प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक

मई 2026 मूल्य ₹ 150.00

प्रतियोगिता दर्पण

हिन्दी मासिक

शिक्षित युवा वर्ग के स्वर्णिम भविष्य के लिये



For e-magazine:
http://emagazine.pdgroup.in

9 770974 639001

प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक

मई 2026

पहला अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, दिल्ली 2026

समसामयिक घटनाएँ

- तीव्र औद्योगिक विकास हेतु 'भव्य' योजना
- राज्यों के लिए नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक
- ऑस्कर पुरस्कार (2026), ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान
- भारत तीसरी बार आईसीसी टी-20 विश्व कप का विजेता
- 2025-26 में देश में प्रमुख कृषिगत उत्पादन : दूसरे अग्रिम अनुमान
- उत्तराखण्ड व झारखण्ड के बजट (2026-27)

फोकस

- सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशें
- भारत के सेवा निर्यात : सम्भावनाएँ और चुनौतियाँ
- आपदा प्रबन्धन : रणनीति से क्रियान्वयन तक

हल प्रश्न-पत्र

- स्टेट बैंक परिवीक्षाधीन अधिकारी (प्रा.), 25

मॉडल हल प्रश्न

- आगामी सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा

लेख

- रचनात्मक अर्थव्यवस्था का उदय : नवाचार और रूपान्तरण
- हाइड्रोजन वैली नवाचार क्लस्टर : भारत का ऊर्जा परिवर्तन
- भारतश्री पहल : देश के ऐतिहासिक शिलालेखों का डिजिटलीकृत भण्डार

साथ में अन्य सारगर्भित सामग्री

मूल्य ₹ 150.00

न्यायिक परीक्षा नोट्स
सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

सिविल सेवा परीक्षा, 2025
टॉपर्स इण्टरव्यू

ebooks.pdgroup.in

एक सम्पूर्ण वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के साथ

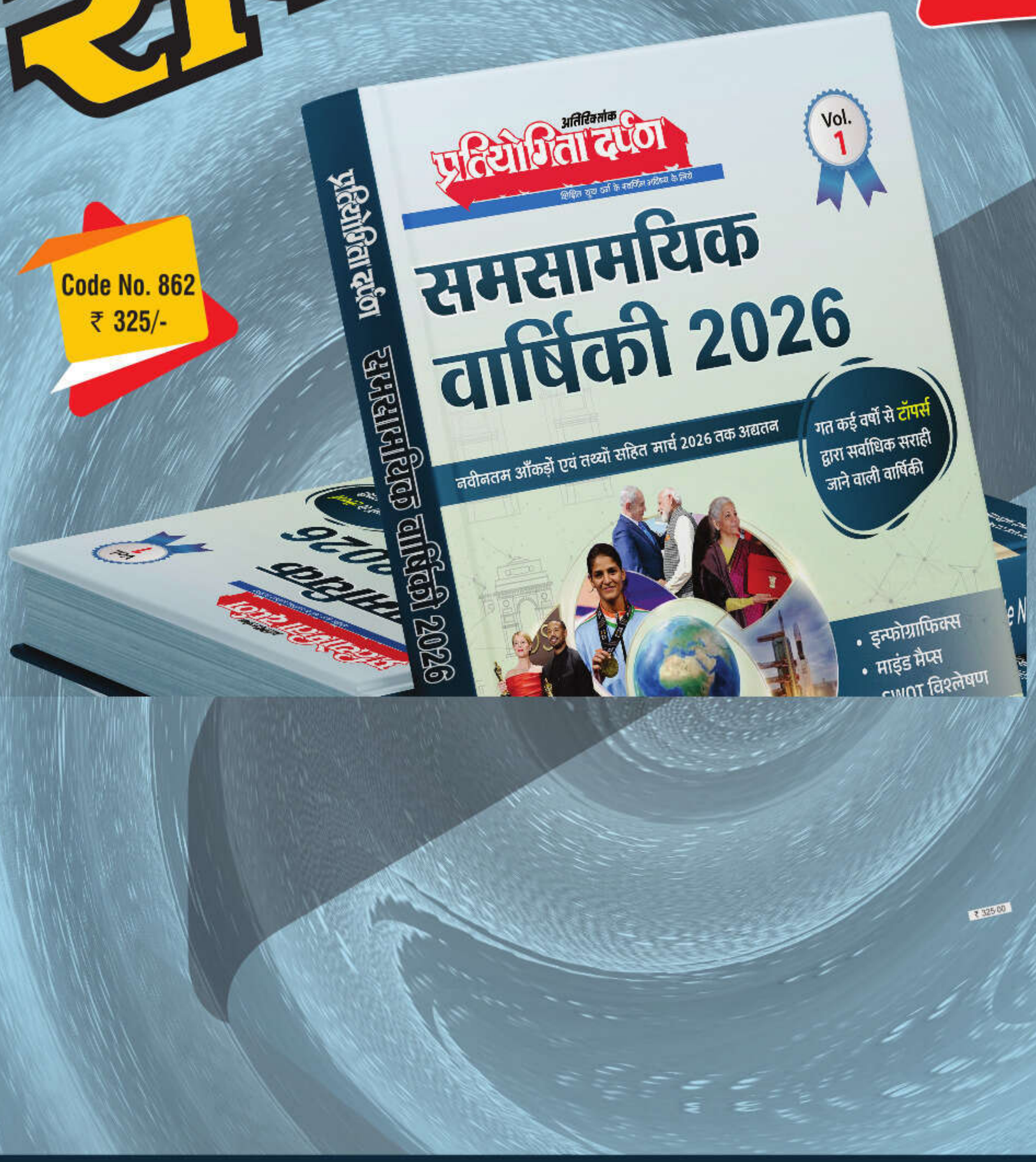
प्रतियोगिता परीक्षाओं में

सफलता

Fresh Arrivals

Vol. 1

मार्च 2026 तक अद्यतन



Code No. 862
₹ 325/-

राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सैन्य, पर्यावरण व जैव-विविधता एवं खेल सम्बन्धी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं तथा प्रमुख नवीनतम योजनाओं व कार्यक्रमों का विवेचन

English Edition : Code No. 800 ₹ 320/-

प्रतियोगिता दर्पण | 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास रोड, आगरा-282 005
फोन : (0562) 2530966, 2531101 • हल्द्वानी मो. 07060421008
• E-mail : sales@pdgroup.in
• Website : www.pdgroup.in

ebooks.pdgroup.in



UPSC NEW BOOKS PDF

2026 EDITION

अब UPSC STANDARD BOOKS 2026 की PDF सीधे टेलीग्राम पर लें सकते है
बस हमारी टेलीग्राम बॉट पर मैसेज करें

Telegram Bot - @pdfhub2026bot

सीधे मैसेज भेजने के लिए MESSAGE NOW पर क्लिक करें

Message Now

1000+ Research & Evidence Based Product Range
5000+ SKUs | Ayurvedic Medicines



देश का
सर्वश्रेष्ठ पतंजलि
गाय का शुद्ध
देशी घी



झूठपेस्ट से बचें, सच्चा टूथपेस्ट दन्त कान्ति ही अपनाएं।
पायरिया, दांतों का पीलापन, दुर्गन्ध,
दर्द आदि से मुक्ति पाएं



पिम्पल–रिंकल मिटाएं,
प्राकृतिक सौन्दर्य पाएं,
पतंजलि एलोवेरा जैल अपनाएं



100 से अधिक
पैरामीटर्स पर खरा
सर्वश्रेष्ठ पतंजलि हनी



हानिकारक रिफाइंड ऑयल छोड़कर सर्वोत्तम पतंजलि कच्ची घानी
सरसों तेल व पतंजलि के नैचुरल एवं फिजिकली रिफाइंड ऑयल
ही घर लायें। अपने परिवार को मिलावट के ज़हर से बचायें



बालों का झड़ना, टूटना एवं असमय
सफेद होना रोके, पतंजलि केश कान्ति
एडवांस हेयर ऑयल व शैम्पू की रेंज



52% प्रोटीन
के साथ न्यूट्रेला
सोया चंक्स



500 से अधिक
औषधीय तत्वों
के साथ
पतंजलि च्यवनप्राश



0% मैदा, **0%** कोलेस्ट्रॉल, पौष्टिक तत्वों
से भरपूर पतंजलि बिस्किट्स



राख, निंबू की शक्ति के साथ पतंजलि डिशवॉश
नीम के गुण के साथ
पतंजलि डिटर्जेन्ट व पवित्र गोमुत्र
से निर्मित गोनाइल



27 ग्राम प्रोटीन
(प्रति स्कूप) पूरे दिन
का प्राकृतिक पोषण



अरहर से लेकर
सभी प्रकार
की नेचुरल दालें



बन्धानी हींग व
100% शुद्ध
पतंजलि मसाले



एलोवेरा, नीम, तुलसी जैसे
प्राकृतिक गुणों वाला
पतंजलि फेशवॉस



हल्दी, चन्दन, एलोवेरा, नीम, केसर
जैसे प्राकृतिक गुणों के साथ



गैस, कब्ज़, पाचन,
त्वचा व बालों
के लिए लाभदायक



100% स्वदेशी, शुद्ध व सेहतमन्द
पतंजलि शर्बत व फ्रूट ड्रिंक्स



अपनी मासूम त्वचा को सिंथेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स
की क्रूरता से बचायें,
पतंजलि से नेचुरल ब्यूटी पायें



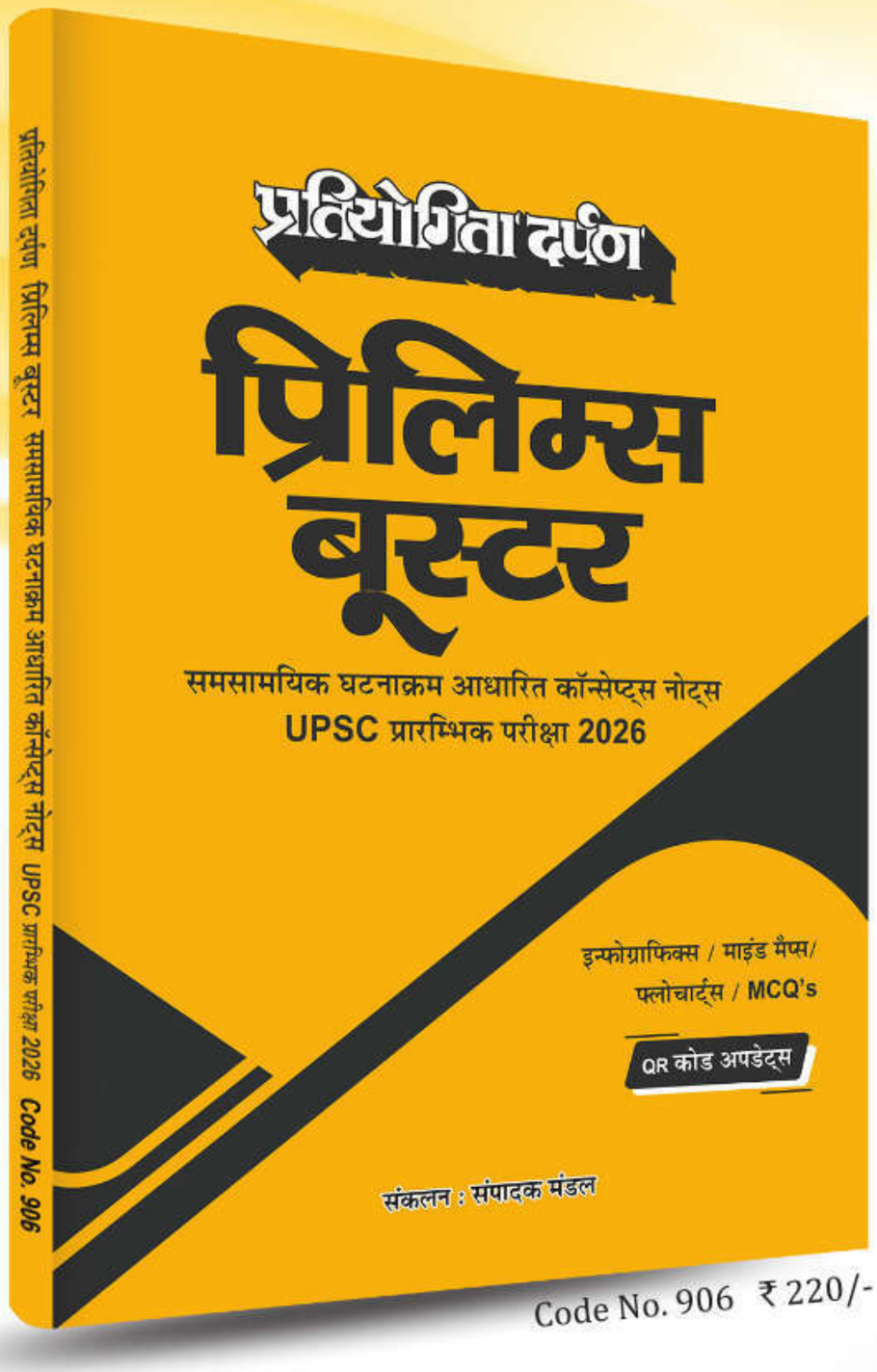
स्वच्छता भी व सौम्यता भी

ebooks.pdgroup.in

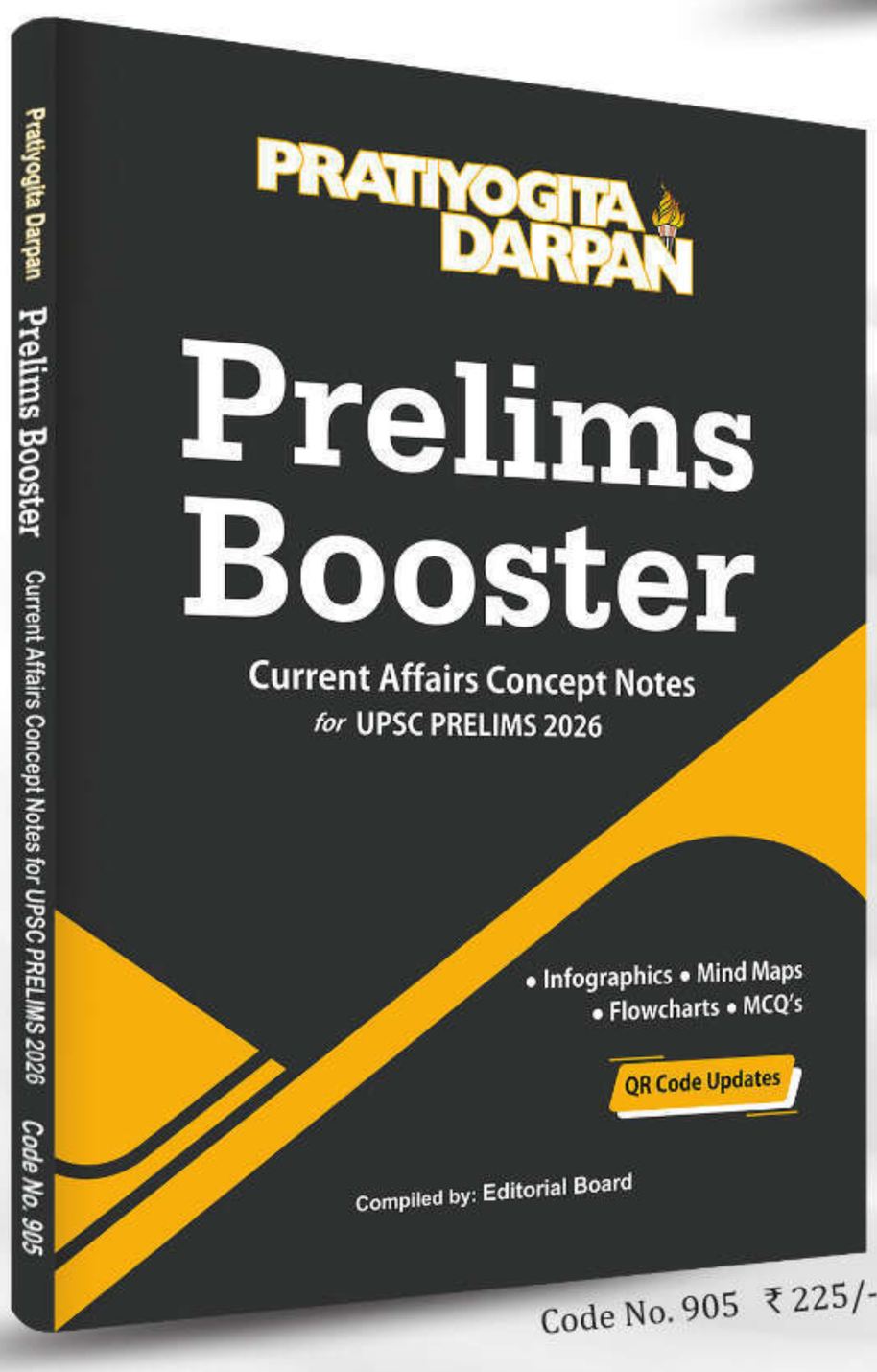
प्रतियोगिता दर्पण

इन्फोग्राफिक्स
माइंड मैप्स
फ्लोचार्ट्स
MCQ's

QR कोड अपडेट्स



Code No. 906 ₹ 220/-



Code No. 905 ₹ 225/-

Infographics
Mind Maps
Flowcharts
MCQ's

QR Code Updates

BUY NOW

Available on :
www.pdgroup.in amazon Flipkart

• आगरा फोन : (0562) 2530966, 2531101 • हल्द्वानी मो. 07060421008 | sales@pdgroup.in | care@pdgroup.in

संस्थापक सम्पादक

स्व. श्री महेन्द्र जैन

सम्पादक

राहुल जैन

प्रधान सलाहकार

डॉ. रवि कान्त

रजिस्टर्ड ऑफिस

2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर,
आगरा–282 002

सम्पादकीय ऑफिस

1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी,
आगरा-मथुरा बाईपास,
आगरा–282 005
फोन : 0562-2531101, 2530966
ई-मेल : सम्पादकीय : publisher@pdgroup.in
कस्टमर केयर : care@pdgroup.in

हल्द्वानी ऑफिस

8-310/1, ए.के. हाउस हीरानगर,
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल–263 139
(उत्तराखण्ड)
मो.–07060421008

प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दी मासिक

के पाठकों से...

प्रिय पाठको !

आपकी सर्वाग्रगण्य एवं लोकप्रिय पत्रिका **'प्रतियोगिता दर्पण'** का **मई 2026 अंक** आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष एवं संतोष की अनुभूति हो रही है. पत्रिका के प्रस्तुत अंक को आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है. प्रकाशन से सम्बन्धित सभी लोगों के सामूहिक प्रयास एवं सहयोग से यह अंक इतना अधिक परीक्षोपयोगी बन पाया है.

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी बनाने की दृष्टि से इस अंक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित एवं विश्लेषणात्मक लेख दिए गए हैं. इनमें से कुछ लेख इस प्रकार हैं—सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशें, भारत के सेवा निर्यात : सम्भावनाएँ और चुनौतियाँ, परिवर्तन के अनुकूल : नया युद्धक्षेत्र और भारतीय सशस्त्र बल, रचनात्मक अर्थव्यवस्था का उदय : नवाचार और रूपान्तरण, AI-आधारित विकास मॉडल : अवसर, नैतिक प्रश्न और नियामकीय चुनौतियाँ, भारत की ज्ञान-आधारित आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ, हाइड्रोजन वैली नवाचार क्लस्टर : भारत का ऊर्जा परिवर्तन, भारतश्री पहल : देश के ऐतिहासिक शिलालेखों का डिजिटलीकृत भण्डार.

पत्रिका के सर्वाधिक विश्लेषणात्मक महत्वपूर्ण भाग में दिव्य दर्पण, चर्चित विभिन्न अवधारणाएँ, ऐतिहासिक व्यक्तित्व. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के चयनित हल प्रश्न-पत्र एवं मॉडल प्रश्न-पत्र आवश्यक व्याख्या एवं संकेतों के साथ दिए गए हैं. इनमें से कुछ प्रश्न-पत्र इस प्रकार हैं—

हल प्रश्न-पत्र

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया परिवीक्षाधीन अधिकारी (प्रा.) परीक्षा, 2025 का हल प्रश्न-पत्र

मॉडल पेपर

आगामी सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा, 2026 हेतु विशेष हल प्रश्न

हमारे सम्मानित पाठकों की माँग पर परीक्षोपयोगी पत्रिकाओं का सार उपलब्ध कराना शुरू किया है, जिसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

हम आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि **"कठिन परिश्रम एवं उचित और सामयिक मार्गदर्शन सफलता प्राप्त करने का मूलमंत्र है." प्रतियोगिता दर्पण** आपका सही एवं सामयिक मार्गदर्शन करने में बेजोड़ है. आप प्रयास कीजिए, आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए प्रतियोगिता दर्पण आपके साथ है.

नियमित रूप से एवं समझदारी के साथ प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए. यह आपको अभीष्ट सफलता दिलाने एवं आपके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने में पूर्णत: सक्षम है.

आपकी चतुर्दिक सफलता एवं स्वर्णिम भविष्य की हार्दिक शुभकामनाओं सहित

राहुल जैन
(सम्पादक)

All rights reserved. No part of this Magazine may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, Electronic, Mechanical, Photocopying, Recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher. While every effort has been made to ensure accuracy of the information published in this edition, neither publisher nor any of its employees accept any responsibility for any error or omission. Articles that cannot be used are returned to the authors if accompanied by a self addressed and sufficiently stamped envelope. But no responsibility is taken for any loss or delay in returning the material. Pratiyogita Darpan assumes no responsibility for statements and opinions advanced by the authors nor for any claims made in the advertisements published in the Magazine. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts and forums in Agra only.

ebooks.pdgroup.in

48 वर्ष | दशम् अंक | मई 2026

प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दी मासिक

571वाँ सफलतम अंक

इस अंक में...

7 सम्पादकीय

9 राष्ट्रीय घटनाक्रम



16 राज्य समाचार

21 अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम



28 आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य

34 नवीनतम सामान्य ज्ञान

43 खेलकूद

51 रोजगार समाचार

52 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

58 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

63 UPSC-CSE : एक जीवन बदलने वाली यात्रा, जो हर समर्पण के लायक है

अनुप्रेरक युवा प्रतिभाएं



67 **राघव झुनझुनवाला**
सिविल सेवा परीक्षा, 2025 में चयनित (चौथा स्थान)



69 **अक्षत सिंघल**
सिविल सेवा परीक्षा, 2025 में चयनित (352वाँ स्थान)

73 **दिव्य दर्पण**

79 स्मरणीय तथ्य

विश्व परिदृश्य



81 विश्व व्यापार की चुनौतियाँ तथा भारत की आर्थिक कूटनीति

83 भारत-कनाडा सम्बन्ध : सुधार की नई पहल

महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार एवं प्रश्नोत्तर

86
- महिलाओं के लिए बजटीय प्रावधान **(योजना)**
- सशक्त और समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली **(कुरुक्षेत्र)**
- सूखे का महासंकट **(डाउन टू अर्थ)**

90 **सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय-फरवरी 2026**

फोकस

94 (1) सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशें

100 (2) भारत के सेवा निर्यात : सम्भावनाएँ और चुनौतियाँ

103 (3) आपदा प्रबन्धन : रणनीति से क्रियान्वयन तक

ebooks.pdgroup.in

विविधा

107 ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं ऐतिहासिक स्थल
112 वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएँ

लेख

117 **रक्षा एवं प्रौद्योगिकी लेख**—परिवर्तन के अनुकूल : नया युद्धक्षेत्र और भारतीय सशस्त्र बल



119 **रचनात्मक अर्थव्यवस्था लेख**—रचनात्मक अर्थव्यवस्था का उदय : नवाचार और रूपान्तरण

122 **कृत्रिम बुद्धिमत्ता लेख**—AI-आधारित विकास मॉडल : अवसर, नैतिक प्रश्न और नियामकीय चुनौतियाँ

123 **ज्ञान सम्पदा एवं विकास लेख**—भारत की ज्ञान-आधारित आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ



125 **हरित ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी लेख**—हाइड्रोजन वैली नवाचार क्लस्टर : भारत का ऊर्जा परिवर्तन



129 **संस्कृति एवं विरासत संरक्षण लेख**—भारतश्री पहल : देश के ऐतिहासिक शिलालेखों का डिजिटलीकृत भण्डार

131 सार संग्रह

हल प्रश्न-पत्र

135 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया परिवीक्षाधीन अधिकारी (प्रा.) परीक्षा, 2025 का हल प्रश्न-पत्र

मॉडल हल प्रश्न

147 आगामी सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा, 2026 हेतु विशेष हल प्रश्न-**सामान्य अध्ययन-I**

वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान

162 उद्योग, व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता

163 समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न

167 आर्थिक घटनाचक्र : वस्तुनिष्ठ प्रश्न

ज्ञानार्जन के नवीन क्षितिज

172 क्या आप जानते हैं ?

173 अपना ज्ञान बढ़ाइए

श्रेष्ठतर प्रतिभागी

174 **प्रथम पुरस्कृत निबन्ध**—"अमेरिकी कूटनीति जनित नव-उपनिवेशवाद से आसन्न संकट"

176 **निबन्ध प्रतियोगिता क्रमांक-560 का परिणाम**

177 **वाद-विवाद प्रतियोगिता**

प्रतियोगिता दर्पण में प्रकाशित किसी भी सामग्री अथवा चित्र के लिए सम्पादक की सहमति होना आवश्यक नहीं है. -सम्पादक

ebooks.pdgroup.in

सम्पादकीय



कर्म में निरत रहकर सफलता प्राप्त कीजिए

भगवान श्रीराम की कथा के संदर्भ में उनके प्रिय अनुज लक्ष्मण जी का यह कथन अत्यन्त प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है–

कादर मन कहुँ एक अधारा।
दैव-दैव आलसी पुकारा।।

कठिनाई अथवा मुसीबत आने पर जो लोग केवल भगवान का नाम लेते हुए, हाय, हाय पुकारते हैं, वे कायर और आलसी हैं, क्योंकि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना, अथवा केवल भाग्य और भगवान को दोष देना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है.

जीवन में कर्म या कर्तव्य-पालन प्रधान है. कर्म के बिना जीवन और जगत का अस्तित्व ही नहीं रह सकता है. चन्द्र, सूर्य सदृश महाशक्तियाँ भी अपने पथ पर निरर्थक चलते रहकर विश्व के प्रति अपने कर्तव्य का पालन अनवरत् रूप से करती रहती हैं. इनका संचालक-परमात्मा या परमतत्व भी यदि कर्म से विरत हो जाए, तो सृष्टि का क्रम ही नष्ट हो जाएगा, इसीलिए कहा गया है–''कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्थात् कर्म करने में तेरा अधिकार हो''– क्योंकि कर्म के अभाव में हमारा अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा ? कर्म के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भी हमें ही दूर करना होगा. हम न कायर कहलाना चाहेंगे और न अकर्मण्य. आपको यदि जीवन में सफल होने की, कुछ बनने की इच्छा है, तो तदर्थ प्रयत्न करना ही होगा. प्रत्येक प्रतियोगिता से सम्बन्धित पाठ्यक्रम होता है, उसके हेतु निर्धारित नियम होते हैं, जिनको लक्ष्य करके आपको अपने कर्तव्य-पथ पर आरूढ़ होना होता है. कठिनाइयाँ उपस्थित होने पर आपको कभी आवश्यक पुस्तकों का सहारा लेना होता है और कभी गुरुजन की सेवा में उपस्थित होना पड़ता है. ऐसा न करने पर आपकी समस्याओं का हल न हो सकेगा. लोक में प्रचलित एक लोकोक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है–स्वयं के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है. हम यदि जीवन में सुख-समृद्धि की इच्छा करते हैं, तो हमें उसके लिए प्राणपन से प्रयत्न करना होगा. इसीलिए कहा जाता है–''कर्म ही पूजा है–Work is worship.'' इस कथन का सीधा-सा तात्पर्य यह है कि भगवान कर्म से प्रसन्न होते हैं. सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ एवं सर्वथा पूर्ण काम होते हुए भी वह प्रतिपल कर्म में निरत रहते हैं. वह जहाँ भी अवतार रूप अथवा पैगम्बर के रूप में प्रकट होते हैं. वहाँ कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं, क्योंकि मानव-जीवन समस्याओं का संघात है और उसका निवारण कर्म द्वारा ही सम्भव है. हिन्दी के कथाकार जैनेन्द्र कुमार का यह कथन ध्यातव्य है–''कर्म अनिवार्य है और मनुष्य नितान्त स्वतंत्र नहीं है, कर्म की परिधि से घिरा है, उस परिधि के भीतर स्वतंत्र है. परिधि से बाहर भागकर नहीं जा सकेगा. वह अपना दुर्भाग्य समझे या सौभाग्य, जग का तंत्र ही ऐसा है.'' कर्म करना हमारी नियति है, क्योंकि समस्याएँ पैदा करना हमारा स्वभाव है. यदि कर्म न किया जाए, तो जीवन की समस्याएँ किस प्रकार सुलझें ? कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार मकड़ी जिस तरह अपने भीतर से जाला प्रकट करती है, उसी प्रकार मनुष्य समस्याएँ उत्पन्न करता रहता है और फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए प्रयास यानी कर्म करता है. जो जितना सटीक एवं सार्थक कर्म करता है वह उतना ही सफल और महान बन जाता है. जो कर्म से विरत होता है, वह निष्क्रिय, निकम्मा, जाहिल आदि कहलाकर समाज के लिए भारस्वरूप होकर जीवित रहता है, जो कर्म से विरत होता है वह कर्महीन होकर जीता है, वह जिस काम से सम्बद्ध होता है, वह चौपट हो जाता है–कर्महीन खेती करे, बैल मरे कि सूखा परे.

युवावर्ग के जो सदस्य अपना समय अध्ययन-मनन करते हुए व्यतीत करते हैं, वे समय और जीवन का सार्थक प्रयोग करते हैं. वे ही परीक्षाओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं, जो कर्म के महत्व को नहीं समझते हैं, वे काल, कर्म और ईश्वर को दोष देते हैं तथा भगवान और भाग्य के नाम पर जीवन भर पश्चाताप करते हैं. ''अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभम्'' सूक्ति के अनुसार शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और प्रत्येक मनुष्य खाने, पीने, श्वास लेने आदि से लेकर बातचीत, अध्ययन-मनन तक कुछ-न-कुछ करने को विवश है. तब फिर हम जो कुछ करें, वह सोच-विचार कर, योजनाबद्ध रूप से क्यों न करें. हम याद रखें कि ''अच्छे कर्म वे कब्जे होते हैं जिन पर स्वर्ग का द्वार टिका रहता है. उन्हीं के सहारे वह द्वार खुलता है.''

(विक्टर ह्यूगो)

हम चाहकर भी कर्म की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वभावतः कर्म को महत्व देते हैं. सामाजिक जीवन में जो लोग केवल बातें बनाते हैं और स्वयं तदनुसार आचरण नहीं करते हैं, यानी जिनकी कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं होता है. उनकी अवज्ञा वे लोग भी करते हैं, जो स्वयं में विश्वास करते हैं. कहा भी गया है कि–

अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम।
दास मलूका कह गए सबके दाता राम।।

लोक में प्रचलित यह कहावत सचमुच युग-युगीन अनुभव की अभिव्यक्ति करने वाली है–Actions speak louder than words अर्थात् कर्म की ध्वनि शब्दों से ऊँची होती है. आप किसी भी संत, महात्मा, भक्त, योगी आदि की वाणी सुनिए अथवा पढ़िए, आपको कर्म की प्रेरणा मिलेगी, आप किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़कर अथवा उसके जीवन में झाँक कर देखिए, आपको अनवरत् कर्म का प्रवाह दृष्टिगत होगा, आप किसी भी सफल प्रतियोगी का साक्षात्कार पढ़िए अथवा उससे व्यक्तिगत साक्षात्कार कीजिए. आपको विदित होगा कि वह अपना अधिकांश समय अपनी पुस्तकों के मध्य व्यतीत करता रहा है. जब तक बच्चा रोता नहीं है, तब तक स्नेह की विग्रह ममतामयी माता भी उसको दूध नहीं पिलाती है, तब यदि आप Burn the midnight-oil–आधी रात तक बिजली की बत्ती जलाकर नहीं पढ़ेंगे, तब तक माता सरस्वती आप पर कृपा क्यों करने लगीं ?

प्रकारान्तर से यह निवेदन करना आवश्यक प्रतीत होता है कि कर्म की सफलता के लिए धर्म की, कर्तव्याकर्तव्य के ज्ञान की, स्थिरता आवश्यक है. किशोरावस्था का धर्म सर्वविदित है. हम पूर्ण कर्मशील रहकर अपने भावी जीवन का निर्माण करने का, भविष्य को स्वर्णिम बनाने का प्रयत्न करें, हो सकता है, हम जितना प्रयास करें, उसके अनुरूप परिणाम या सफलता प्राप्त न हो, परन्तु यह निर्विवाद है कि कर्म या प्रयास के अभाव में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा. विचारक डिजरैली ने ठीक ही कहा है कि–''कर्म सदैव सुख न ला सके, परन्तु कर्म के बिना सुख कहीं मिलता.''

कर्म की महिमा के संदर्भ में आचार्य विनोबा भावे का यह कथन हमारी आँखें खोल देता है–''कर्म वह दर्पण है, जो हमें अपना स्वरूप दिखा देता है. अतएव हमें कर्म का कृतज्ञ होना चाहिए''. हम अथर्ववेद की वाणी से प्रेरणा ग्रहण करें और कर्तव्य कर्म में जुट जाएँ–''मेरे बाएँ हाथ में कर्म है और दाएँ हाथ में जय है.''

ebooks.pdgroup.in

वार्षिक सदस्यता शुल्क

मासिक पत्रिकाएँ »	सामान्य ज्ञान दर्पण	सक्सेस मिरर	प्रतियोगिता दर्पण	PRATIYOGITA DARPAN
एक प्रति मूल्य	₹ 50.00	₹ 30.00	₹ 150.00	₹ 150.00
वार्षिक मूल्य :				
साधारण डाक से	₹ 450.00	₹ 270.00	₹ 1355.00	₹ 1350.00
रजिस्टर्ड डाक से	₹ 710.00	₹ 525.00	₹ 1615.00	₹ 1610.00
द्विवार्षिक मूल्य :				
साधारण डाक से	₹ 840.00	₹ 505.00	₹ 2525.00	₹ 2520.00
रजिस्टर्ड डाक से	₹ 1360.00	₹ 1015.00	₹ 3045.00	₹ 3040.00

वार्षिक सामूहिक सदस्यता शुल्क (Including Registered Post + GST)

प्रतियोगिता दर्पण (हिन्दी) + Pratiyogita Darpan (English)	₹ 3000
प्रतियोगिता दर्पण (हिन्दी) + सामान्य ज्ञान दर्पण	₹ 2100
सामान्य ज्ञान दर्पण + सक्सेस मिरर	₹ 1000
सामान्य ज्ञान दर्पण + प्रतियोगिता दर्पण (हिन्दी) + Pratiyogita Darpan (English)	₹ 3450
प्रतियोगिता दर्पण (हिन्दी) + सामान्य ज्ञान दर्पण + सक्सेस मिरर	₹ 2370
प्रतियोगिता दर्पण (हिन्दी) + Pratiyogita Darpan (English) + सामान्य ज्ञान दर्पण + सक्सेस मिरर	₹ 3725

PRATIYOGITA DARPAN

SCAN TO SUBSCRIBE MAGAZINES

ऑनलाइन आर्डर के लिए हमारी
वेबसाइट www.pdgroup.in पर विजिट करें
या CALL अथवा WHATSAPP करें-

9634167776 | care@pdgroup.in

- सदस्यता शुल्क किसी भी माध्यम से भेजा जा सकता है।
- पुराने ग्राहक अपना सब्सक्रिप्शन RENEW करते समय अपने OLD SUBSCRIPTION NO. का उल्लेख अवश्य करें।
- चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट 'प्रतियोगिता दर्पण' के नाम से आगरा में देय ही स्वीकार किए जाएंगे।

आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएँ

2026

5-6 अप्रैल—राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर/प्लाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा, 2025

7 अप्रैल—एमपीईएसबी वनरक्षक/जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा, 2026

7 अप्रैल—एसएससी जूनियर इंजीनियर (द्वितीय चरण) भर्ती परीक्षा, 2025

9 अप्रैल—उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रधानाचार्य) सेवा परीक्षा, 2025

10 अप्रैल—एसएससी संयुक्त उच्च माध्यमिक (10 + 2) स्तर भर्ती परीक्षा, 2025 (द्वितीय चरण)

11 अप्रैल—एम्स (AIIMS) नॉरसेट (NORCET) 10वीं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा, 2026 (प्रारम्भिक चरण)

11 अप्रैल—आरबीआई बैंक सहायक (प्रारम्भिक चरण) भर्ती परीक्षा, 2026

12 अप्रैल—झारखण्ड सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2026

12 अप्रैल—एनडीए और एनए परीक्षा (I), 2026

12 अप्रैल—सीडीएस परीक्षा (I), 2026

14-21 अप्रैल—बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2025

15 अप्रैल से—एमपीईएसबी स्टाफ नर्स और पैरामेडीकल संयुक्त भर्ती परीक्षा, 2026

18 अप्रैल—आरएसएसबी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा, 2026

19 अप्रैल—आरपीएससी पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2025

25-27 अप्रैल—उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड्स भर्ती परीक्षा, 2025

25-30 अप्रैल—बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा, 2026

26 अप्रैल—मध्य प्रदेश राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारम्भिक परीक्षा, 2026

26 अप्रैल—हरियाणा सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2026

मई-जून—एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा, 2026 (प्रारम्भिक चरण)

8 मई से—एमपीईएसबी प्री. एग्रीकल्चर टेस्ट (PAT), 2026

9-10 मई—उत्तर प्रदेश प्रवक्ता (PGT) भर्ती परीक्षा, 2022

10 मई—आरएसएसबी लैब असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा, 2026

11-31 मई—एनटीए (NTA) सीयूईटी स्नातक प्रवेश परीक्षा, 2026

17 मई—बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा, 2026

17 मई—एमपीपीएससी सहायक कुल सचिव परीक्षा, 2025

17 मई—यूपीपीएससी सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (मुख्य परीक्षा), 2025 (हिन्दी, गणित एवं अंग्रेजी)

21 मई—यूपीएसएसएससी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 2025

24 मई—सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2026

1-16 जून—भारतीय सेना अग्निवीर सीईई भर्ती परीक्षा, 2026

3-4 जून—उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) भर्ती परीक्षा, 2022

7 जून—यूपीपीएससी अपर निजी सचिव (तृतीय चरण) परीक्षा, 2023

8-10 जून—उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल भर्ती परीक्षा, 2025

27-29 जून—हरियाणा सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2026

28 जून—आरएसएसबी फॉरेस्टर या फॉरेस्ट रेंजर भर्ती परीक्षा, 2026

जुलाई—मध्य प्रदेश मिडिल स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026

2-4 जुलाई—उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET), 2026

5-6 जुलाई—आरएसएसबी जूनियर क्लर्क-II/जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा, 2026

12 जुलाई—एमपीपीएससी सहायक प्राध्यापक परीक्षा, 2026 (प्रथम चरण)

12-18 जुलाई—राजस्थान ग्रेड-2 प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, 2025

19 जुलाई—केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2026

जुलाई-सितम्बर—एसएससी संयुक्त उच्च माध्यमिक (10 + 2) स्तर भर्ती परीक्षा, 2026 (प्रारम्भिक चरण)

अगस्त—मध्य प्रदेश प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026

2 अगस्त—एमपीपीएससी सहायक प्राध्यापक परीक्षा, 2026 (द्वितीय चरण)

21 अगस्त (प्रारम्भ)—सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2026

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



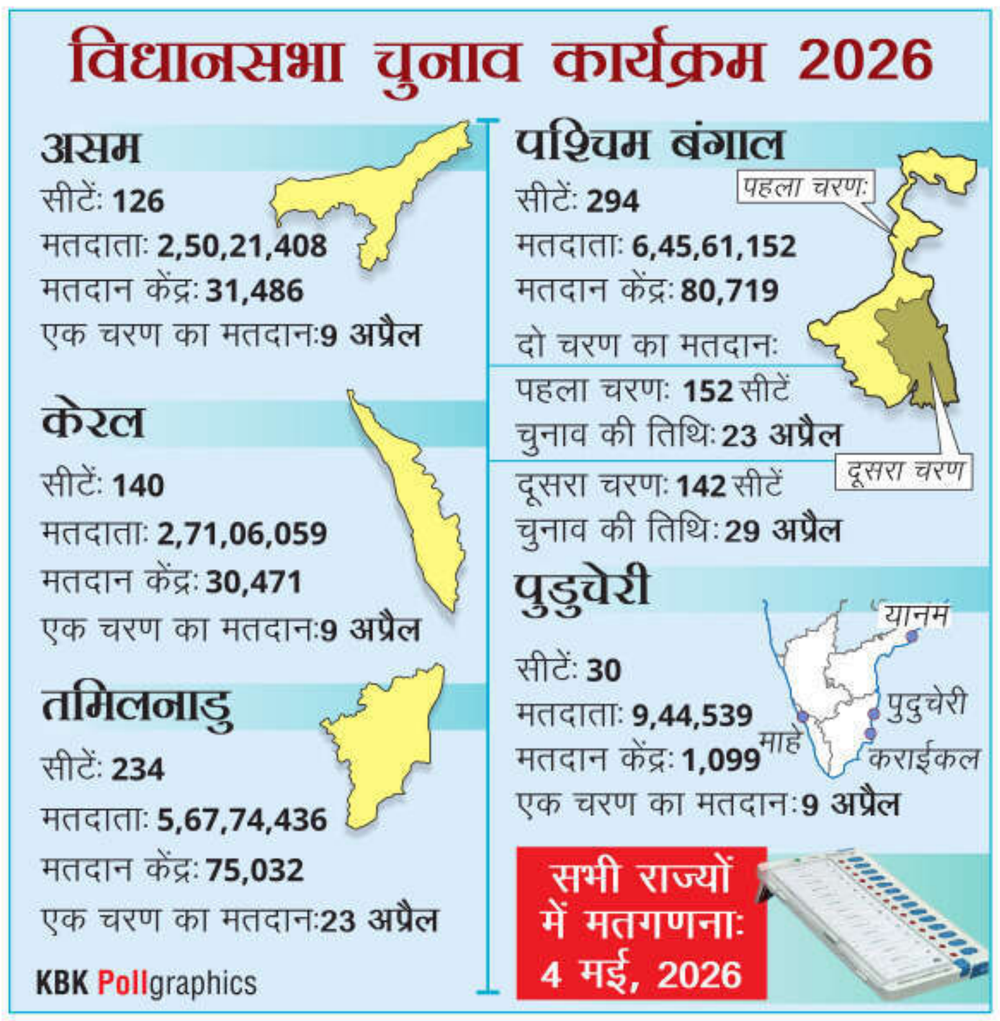
राष्ट्रीय घटनाक्रम

- पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु व केरल तथा केन्द्रशासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए विधान सभा चुनाव कार्यक्रम घोषित
- श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति
- पनडुब्बी रोधी पोत आईएनएस अंजदीप नौसेना में शामिल
- ओमान तक समुद्री यात्रा के पश्चात् भारतीय नौसेना के नौकायन पोत आईएनएसवी कौंडिन्य की सुरक्षित वापसी
- सिविल सेवा परीक्षा-2025 का परिणाम घोषित : सफल अभ्यर्थियों में 31 प्रतिशत महिलाएँ
- गुजरात में समान नागरिक संहिता विधेयक विधान सभा द्वारा पारित
- अनुसूचित जाति के किसी हिन्दू, सिख अथवा बौद्ध द्वारा कोई अन्य धर्म अपनाने से एससी का दर्जा समाप्त : सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
- दंत चिकित्सा व शिक्षा में सुधार के लिए डेंटल काउंसिल के स्थान पर नेशनल डेंटल कमीशन का गठन
- कालिंजर किले का पहाड़ी क्षेत्र राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल घोषित
- नामीबिया व द. अफ्रीका के पश्चात् अब बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते
- देश में संचालित फर्जी विश्वविद्यालयों की यूजीसी की ताजा सूची
- पंजाब में महिलाओं के लिए नई मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु व केरल तथा केन्द्रशासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए विधान सभा चुनाव कार्यक्रम घोषित

निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों— पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु व केरल तथा 1 केन्द्रशासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए विधान सभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 15 मार्च, 2026 को की है. पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में 23 व 29 अप्रैल, 2026 को कराया जाएगा, जबकि असम, केरल, तमिलनाडु व पुदुचेरी में मतदान एक-एक चरण में कराने की घोषणा की गई है. तमिलनाडु विधान सभा की सभी 234 सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल को कराया जाएगा, जबकि असम की सभी 126, केरल की सभी 140 तथा पुदुचेरी विधान सभा की सभी 30 सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल, 2026 को सम्पन्न होगा. पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटों में से 152 सीटों पर मतदान 23 अप्रैल को तथा 142 सीटों के लिए मतदान 29 अप्रैल को कराया जाएगा. इससे पूर्व 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में मतदान 8 चरणों में तथा असम में 3 चरणों में कराया गया था. सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना 4 मई, 2026 को कराई जाएगी. **चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चारों राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है.**

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग की घोषणानुसार गोवा, त्रिपुरा व नगालैण्ड की 1-1 तथा कर्नाटक की 2 रिक्त सीटों सहित कुल 5 सीटों के लिए उपचुनाव 9 अप्रैल को तथा गुजरात की 1 व महाराष्ट्र की 2 रिक्त सीटों सहित 3 सीटों के लिए उपचुनाव 23 अप्रैल को कराया जाएगा.



श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति

जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना ने आधुनिक युद्ध क्षमता एवं तत्परता का प्रदर्शन अभ्यास 'वायुशक्ति 2026' 27 फरवरी, 2026 को किया. राफेल, सुखोई-SU30MKI, तेजस व मिराज 2000 सहित भारतीय वायु सेना के उन्नत लड़ाकू विमानों ने वायु-से-जमीन पर मार करने वाले निर्देशित बमों व मिसाइलों का उपयोग करते हुए सटीक हमले कर निर्धारित लक्ष्यों पर प्रहार इस अभ्यास के तहत् किए. दिन और रात दोनों परिस्थितियों में युद्ध अभियानों के लिए तत्परता इसके तहत् प्रदर्शित की गई.

इस युद्ध अभ्यास के दौरान देश की राष्ट्रपति व सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी इतिहास रचा जब स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड (LCH Prachand) में पायलट यूनीफॉर्म में ही सह-पायलट के रूप में उड़ान उन्होंने भरी. हेलीकॉप्टर को ग्रुप कैप्टेन एन.एस. बहुआ ने उड़ाया तथा वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह साथ उड़ान भर रहे दूसरे हेलीकॉप्टर में मौजूद थे. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (HAL) द्वारा निर्मित इस अत्याधुनिक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए देश की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज तथा परमाणु परीक्षण स्थल का हवाई अवलोकन राष्ट्रपति ने किया. उड़ान के दौरान सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर के रूप

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

में देशवासियों के लिए संदेश भी हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से राष्ट्रपति ने प्रसारित किया तथा हेलीकॉप्टर से सैल्यूट कर उपस्थित जवानों व अधिकारियों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया. लड़ाकू हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में सह-पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली वह देश की पहली राष्ट्रपति हैं. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर वायुसेना के जैसलमेर केन्द्र पर उपस्थित थे.



एलसीए प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने से पूर्व पायलट यूनीफॉर्म में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

पनडुब्बी रोधी पोत आईएनएस अंजदीप नौसेना में शामिल

उथले पानी में चलने वाली पनडुब्बी रोधी नौका (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft – ASW-SWC) श्रेणी के तीसरे पोत अंजदीप (Anjadip) को 27 फरवरी, 2026 को नौसेना की पूर्वी कमान द्वारा चेन्नई बंदरगाह पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से नौसेना में कमीशन किया गया. इस युद्धपोत का उद्देश्य भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं व तटीय निगरानी में वृद्धि करना है. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा निर्मित अंजदीप एक अत्याधुनिक पोत है जिसे विशेष रूप से तटीय युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस पोत की कमीशनिंग से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्धक्षमता व तटीय निगरानी की क्षमता में वृद्धि होगी. डॉल्फिन हंटर (Dolphin Hunter) के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया यह युद्धपोत स्वदेशी, अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी हथियारों व सेंसर पैकेज से सुसज्जित है तथा भारतीय नौसेना में इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना व उन्हें निष्क्रिय करना है. 77 मीटर लम्बा यह पोत 25 समुद्री मील (Knots) प्रति घण्टा की गति प्राप्त करने में सक्षम है तथा इसका यह नामकरण कारवार (Karwar) तट से दूर एक ऐतिहासिक द्वीप के नाम पर किया गया है.

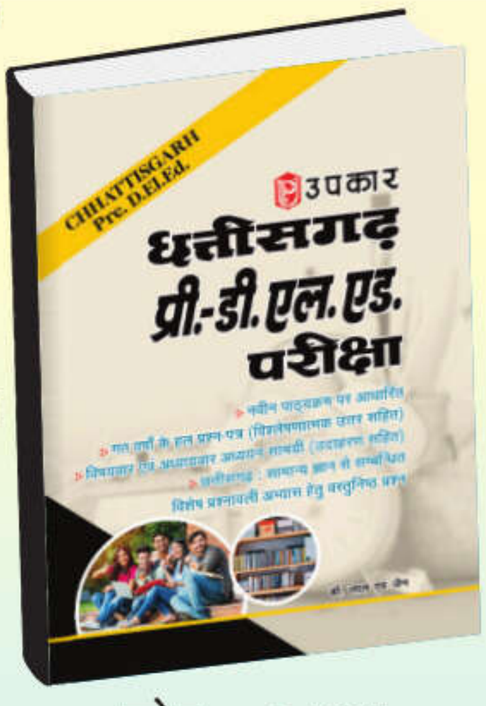
ज्ञातव्य है कि इस श्रेणी के आठ पोतों का निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि. द्वारा किया जाना है. आइएनएस अंजदीप इस श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है. इस श्रेणी का पहला युद्धपोत आईएनएस अरनाला 18 जून, 2025 को तथा दूसरा आईएनएस एंद्रोथ (INS Andarth) 6 अक्टूबर, 2025 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था.

ओमान तक समुद्री यात्रा के पश्चात् भारतीय नौसेना के नौकायन पोत आईएनएसवी कौंडिन्य की सुरक्षित वापसी

पाँचवीं शताब्दी की प्राचीन भारतीय तकनीक का उपयोग करके पाल विधि से बनाया गया भारतीय नौसेना का इंजन रहित नौकायन पोत आईएनएसवी कौंडिन्य (INSV–Indian Naval Sailing Vessel Kaundinya), पोरबंदर से मस्कट (ओमान) की यात्रा कर 2 मार्च, 2026 को मुम्बई वापस पहुँच गया. बिना किसी धातु या कील का इस्तेमाल कर लकड़ी के तख्तों को नारियल के

उपकार

धत्तीसगढ़ प्री-डी.एल.एड. परीक्षा



- नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित
- गत वर्षों के हल प्रश्न-पत्र (विश्लेषणात्मक उत्तर सहित)
- विषयवार एवं अध्यायवार अध्ययन सामग्री (उदाहरण सहित)
- छत्तीसगढ़ : सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित विशेष प्रश्नावली अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न

डॉ. लाल एवं जैन

कोड : 1361
मूल्य : ₹ 410.00

उपकार प्रकाशन, आगरा
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

PRATIYOGITA DARPAN

We are Cordially Inviting You to Visit Our Stalls at

DOON BOOK FESTIVAL 2026

FREE ENTRY

PREPARE YOURSELF ON

Date: 04th To 12th April 2026
Timings: 11:00 am To 08:00 pm
Venue : Parade Ground, Dehradun, Uttarakhand

Bharat Shiksha Expo 2026

FREE ENTRY

Date: 23rd To 25th April 2026
Timings: 10:00 am To 05:00 pm
Venue : India Expo Centre & Mart Greater Noida, Delhi-NCR

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

रेशों की रस्सियों से सिलकर बनाए गए तथा पैडल कपड़े के पाल व हवा के सहारे ही चलने वाले इस इंजन रहित पोत का निर्माण गोवा की एक निजी कम्पनी होडी इनोवेशंस द्वारा केन्द्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना तथा फर्म के त्रिपक्षीय समझौते के तहत् बनाया गया था तथा भारतीय नौसेना में इसे 21 मई, 2025 को कमीशन किया गया था. अजंता की गुफाओं के एक भित्ति चित्र पर आधारित डिजाइन वाले इस नौकायन पोत का यह नामकरण पहली सदी के प्राचीन भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर किया गया है.



नौकायन पोत आईएनएसवी कौंडिन्य

पारम्परिक रूप से निर्मित भारतीय नौसेना के 20 मीटर लम्बे इस नौकायन पोत ने पहली विदेश यात्रा भारत के पोरबन्दर बंदरगाह से ओमान के मस्कट के लिए 29 दिसम्बर, 2025 को प्रारम्भ की थी. भारत के प्राचीन व्यापारिक मार्ग का ही अनुसरण करते हुए 18 दिन में, यह 14 जनवरी, 2026 को मस्कट पहुँच गया था, जहाँ वाटर कैनन सैल्यूट से इसका स्वागत किया गया. आवश्यक रखरखाव के पश्चात् इसकी वापसी यात्रा 7-8 फरवरी, 2026 को प्रारम्भ हुई तथा 2 मार्च को मुम्बई में इसकी वापसी हुई. मुम्बई की नौसेना गोदी में वाटर आर्क सैल्यूट के साथ इसका स्वागत हुआ. बंदरगाह पर इसका स्वागत करने वालों में नौसेना की पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफीसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन व नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी उपस्थित थे.

आईएनएसवी कौंडिन्य की इस विदेश यात्रा का उद्देश्य ओमान के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूत करने के साथ-साथ भारत के उन समुद्री मार्गों का अनुसरण करना था, जो किसी समय भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ते थे तथा जिनके जरिए पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत का मसालों व वस्त्रों आदि का व्यापार होता था आईएनएसवी कौंडिन्य के इस विशेष मिशन का नेतृत्व कमांडर विकास शेओरान व कमांडर वाई. हेमंत कुमार ने किया था. नौसेना की पश्चिमी कमान के वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के अनुसार, आईएनएसवी कौंडिन्य की अगली विदेश यात्रा पुरी से बाली के लिए शीघ्र ही होगी.

सिविल सेवा परीक्षा-2025 का परिणाम घोषित : सफल अभ्यर्थियों में 31 प्रतिशत महिलाएँ

वर्ष 2025 की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम संघ लोक सेवा आयोग ने 6 मार्च, 2026 को जारी किए हैं. देश की इस सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 958 अभ्यर्थियों (659 पुरुष व 299 महिलाओं) की भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा ग्रुप ए व ग्रुप बी की केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु संस्तुति आयोग द्वारा की गई है. इनमें 317 अम्यर्थी सामान्य श्रेणी के हैं, जबकि 104 आर्थिक दृष्टि से कमजोर श्रेणी (EWS) के, 306 अन्य पिछले वर्गों (OBC) के, 158 अनुसूचित जाति (SC) व 73 अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति (ST) के हैं. इनके अतिरिक्त 258 अन्य अभ्यर्थियों की एक समेकित आरक्षित सूची (Consolidated Reserve List) भी आयोग द्वारा तैयार रखी गई है.

6 मार्च को घोषित परीक्षाफल में सफल अभ्यर्थियों के नाम मेरिट के आधार पर ही घोषित किए गए हैं. घोषित मेरिट सूची के अनुसार, जोधपुर से एमबीबीएस की उपाधि प्राप्त डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, जबकि तमिलनाडु की राजेश्वरी सुवे एम व हरियाणा के अकांश ढुल ने क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया है. दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त राघव झुनझुनवाला व राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से लॉ में ऑनर्स की उपाधि प्राप्त ईशान भटनागर इस परीक्षा में क्रमशः चौथे व पाँचवें स्थान पर रहे हैं. इस प्रकार, 1 महिला व 4 पुरुष अभ्यर्थी इस परीक्षा में पहले पाँच स्थानों पर रहे हैं. पहले 25 स्थानों पर सफल रहे अभ्यर्थियों में 11 महिलाएँ व 14 पुरुष शामिल हैं. पहले 10 स्थानों पर रहे अभ्यर्थियों के प्राप्तांक दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं.

इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा (2025) में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले अनुज अग्निहोत्री मूलतः राजस्थान के जोधपुर के एक गाँव के निवासी हैं, किन्तु उनके पिता रावतभाटा में एटोमिक पॉवर प्लांट में काम करते थे जिससे उनकी प्रारम्भिक शिक्षा रावतभाटा से ही हुई.

जोधुपर स्थित 'एम्स' (AIIMS) से एमबीबीएस (स्नातक) उपाधि प्राप्त अनुज ने सिविल सेवा परीक्षा में चिकित्सा विज्ञान (Medical Science) को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था. **2025 में सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष स्थान अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने प्राप्त किया.** अपने पहले ही प्रयास में 2023 की परीक्षा में सिविल सेवा में ही DANICS (Delhi Andman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Services) कैडर में सिलेक्शन के पश्चात् दिल्ली में ही एसडीएम के रूप में वह प्रोबेशनर थे. 2024 की परीक्षा में लिखित परीक्षा में सफलता के पश्चात् साक्षात्कार वह क्लियर नहीं कर सके थे.



अनुज अग्निहोत्री

2025 की परीक्षा में लिखित परीक्षा में 867 तथा साक्षात्कार में 204 अंक प्राप्त करके कुल 1071 प्राप्तांकों के साथ शीर्ष स्थान उन्होंने प्राप्त किया है. **परीक्षा में इस सफलता पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बस दो ही शब्द हैं–'अनुशासन' और 'खुद पर विश्वास', ये दोनों हैं, तो दुनिया जीत सकते हैं.**

सिविल सेवा परीक्षा-2025 : मेरिट सूची में पहले 10 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक

रैंक	अभ्यर्थी	मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक (1750)	साक्षात्कार में प्राप्तांक (275)	कुल प्राप्तांक (2025)
1	अनुज अग्निहोत्री	867	204	1071
2	राजेश्वरी सुवे एम	865	202	1067
3	अकांश ढुल	864	193	1057
4	राघव झुनझुनवाला	847	195	1042
5	ईशान भटनागर	823	215	1038
6	जिनिया अरोरा	822	215	1037
7	एआर राजा मोहिदीन	834	201	1035
8	पाकशाल सचिव	837	198	1035
9	आस्था जैन	835	198	1033
10	उज्ज्वल प्रियांक	846	187	1033

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

सिविल सेवा परीक्षा 2025 में दूसरे स्थान पर तथा महिला अभ्यर्थियों में पहले स्थान पर रही राजेश्वरी सुवे एम मदुरै (तमिलनाडु) की रहने वाली हैं तथा सिविल सेवा परीक्षा 2025 में यह सफलता प्राप्त करने से पूर्व तमिलनाडु राज्य सेवा परीक्षा के जरिए तमिलनाडु में डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यरत थी. **अन्ना यूनीवर्सिटी चेन्नई से इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनिरिंग में बीई की उपाधि प्राप्त राजेश्वरी सुवे ने पाँच प्रयासों में प्रारम्भिक परीक्षा से भी आगे न पहुँच पाने के पश्चात् अपने छठे प्रयास में यह सफलता प्राप्त की है.** सिविल सेवा परीक्षा में समाजशास्त्र को वैकल्पिक विषय के रूप में उन्होंने लिया था. इस परीक्षा में लिखित परीक्षा में 865 तथा साक्षात्कार में 202 अंक प्राप्त करके कुल 1067 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया है तथा इस रैंक के साथ प्रशासनिक सेवा में वह जा सकती हैं, किन्तु मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी इच्छा पुलिस सेवा में जाने की है.


राजेश्वरी सुवे एम

सिविल सेवा परीक्षा 2025 में तीसरे स्थान पर रहे अकांश ढुल मूलतः हरियाणा के निवासी हैं तथा उनके पिता हरियाणा भाजपा के नेता हैं. **दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बी.कॉम. (आनर्स) की उपाधि प्राप्त अकांश ने सिविल सेवा परीक्षा (2025) में यह सफलता अपने चौथे प्रयास में प्राप्त की है.** पहले प्रयास में 2021 की परीक्षा में प्रारम्भिक परीक्षा क्लियर करने के पश्चात् मुख्य परीक्षा वह क्लियर नहीं कर सके थे. **उसके पश्चात् 2023 से लगातार तीनों वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में सफलता उन्होंने प्राप्त की.** 2023 की परीक्षा में उनकी ऑल इंडिया रैंक 342 थी जिसके आधार पर इंडियन ऑडिट एण्ड एकाउंट्स सर्विस (IA & AS) उन्हें एलॉट हुई. इस सेवा में रहते हुए रैंक सुधारने के लिए 2024 की परीक्षा उन्होंने दी तथा 295 रैंक उन्होंने प्राप्त की तथा अब 2025 की परीक्षा में देश में तीसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया है.


अकांश ढुल

सिविल सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में वाणिज्य एवं लेखांकन (Commerce and Accountancy) को वैकल्पिक विषय के रूप में उन्होंने चुना था. परीक्षा में कुल 1057 अंक (लिखित परीक्षा में 864 व सांक्षात्कार में 193) प्राप्त कर अखिल भारतीय स्तर पर तीसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया है.

परीक्षा में चौथे स्थान पर रहे मुजफ्फरपुर (बिहार) के राघव झुनझुनवाला दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बी.ए. (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त हैं. **सिविल सेवा परीक्षा में यह सफलता अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने प्राप्त की है. पहले प्रयास में साक्षात्कार तक न पहुँचे राघव दूसरे प्रयास में साक्षात्कार तक तो पहुँचे, किन्तु मेरिट लिस्ट में स्थान न पा सके.** तीसरे प्रयास में लिखित परीक्षा में 847 तथा साक्षात्कार में 195 अंक सहित कुल 1042 प्राप्तांकों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर चौथा स्थान उन्होंने प्राप्त किया. इस परीक्षा में अर्थशास्त्र को ही वैकल्पिक विषय के रूप में उन्होंने चुना था.


राघव झुनझुनवाला

पाँचवें स्थान पर रहे भोपाल के ईशान भटनागर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से बीए एलएलबी (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त हैं तथा **सिविल सेवा परीक्षा में अपने पहले प्रयास में 276 रैंक के साथ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए वह चयनित हुए तथा दूसरे ही प्रयास में पाँचवीं रैंक उन्होंने प्राप्त की है.** इस परीक्षा के लिए समाजशास्त्र को वैकल्पिक विषय उन्होंने चुना था. इस परीक्षा में कुल 1038 अंक (लिखित परीक्षा में 823 तथा साक्षात्कार में 215) प्राप्त करके पाँचवाँ स्थान उन्होंने प्राप्त किया है.


ईशान भटनागर

सिविल सेवा परीक्षा कुल 3 चरणों वाली परीक्षा है. इसमें 400 अंकों की प्रारम्भिक परीक्षा, 1750 अंकों की मुख्य लिखित परीक्षा तथा 275 अंकों का साक्षात्कार (Personality Test) शामिल रहता है. प्रारम्भिक परीक्षा में 200-200 अंकों के 2 प्रश्न-पत्र होते हैं. इनमें पेपर-II (CSAT), केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है. तथा इसमें 33 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी का पेपर-I चैक ही नहीं किया जाता. पेपर-I में प्राप्तांक ही प्रारम्भिक परीक्षा में अभ्यर्थी की मेरिट निर्धारित करते हैं तथा इसमें कट-ऑफ से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने के पात्र होते हैं. (प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के आधार पर बनने वाली फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते)

- मुख्य परीक्षा में वर्णनात्मक किस्म के 9 प्रश्न-पत्र होते हैं. इनमें अंग्रेजी तथा ऐच्छिक भाषा के 300-300 अंकों के 2 प्रश्न-पत्र केवल क्वालिफाइंग प्रकृति के होते हैं तथा इनमें प्राप्त अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाते.
- मुख्य परीक्षा में मेरिट निर्धारण के लिए 1750 अंकों की लिखित परीक्षा में कुल प्रश्न-पत्र 250-250 अंक के होते हैं. इसमें 250 अंकों का पहला निबन्ध का प्रश्न-पत्र तथा 250-250 अंकों के ही सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न-पत्र सभी के लिए अनिवार्य होते हैं, जबकि ऐच्छिक विषय के 2 प्रश्न-पत्र भी 250-250 अंकों के होते हैं. साक्षात्कार के लिए 275 अंक निर्धारित हैं. इस प्रकार पूरी मुख्य परीक्षा 2025 अंकों की होती है.

वर्ष 2025 की सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न चरणों में कट-ऑफ मार्क्स' निम्नवत् रहे हैं—

सिविल सेवा परीक्षा-2025 में विभिन्न स्तरों पर कट-ऑफ मार्क्स

श्रेणी	प्रारम्भिक परीक्षा (Prelims Cut-off) (सामान्य अध्ययन-I पेपर)	मुख्य परीक्षा (Mains Cut-off) (1750 में से)	योग (Final Cut-off) (2025 में से)
सामान्य	92·66	739	963
ओबीसी	92·00	717	931
ईडब्ल्यूएस	89·34	706	926
एससी	84·00	700	905
एसटी	82·66	694	902

- इससे पूर्व वर्ष 2024 की सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कट-ऑफ मार्क्स प्रारम्भिक परीक्षा में (200 में से) 87·98, मुख्य परीक्षा में (1750 में से) 729 तथा कुल प्राप्तांक के मामले में 947 (2025 में से) रही थी.
- ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए इन चरणों में यह क्रमशः 87·28, 702 व 910 थीं
- ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए यह कट ऑफ क्रमशः 85·92, 696 तथा 917 थी.
- एससी अभ्यर्थियों के लिए 2024 की परीक्षा में यह कट-ऑफ क्रमशः 79·03, 685 व 880 थी.
- एसटी अभ्यर्थियों के मामले में 2024 की परीक्षा में यह कट-ऑफ क्रमशः 74·23, 684 व 884 थी.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

छठा स्थान पाने वाली जिनिया अरोरा (Zinnia Aurora) मूलतः हरियाणा में रोहतक की निवासी हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान विषयों के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त जिनिया ने यह सफलता अपने दूसरे प्रयास में प्राप्त की है. **पहले प्रयास में 2024 की परीक्षा में 156वीं रैंक पाने पर आईपीएस में चयन उनका हुआ था तथा दूसरे ही प्रयास में छठवाँ स्थान उन्होंने प्राप्त किया है.** राजनीति विज्ञान व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (PSIR) इस परीक्षा में उनका वैकल्पिक विषय था. 2025 की परीक्षा में लिखित परीक्षा में 822 तथा साक्षात्कार में 215 अंकों सहित कुल 1037 अंक उन्होंने प्राप्त किए.



जिनिया अरोरा

वर्ष 2025 की सिविल सेवा परीक्षा हेतु कुल 9,37,876 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिनमें से 5,76,793 अभ्यर्थी ही प्रारम्भिक परीक्षा में शामिल हुए थे. प्रारम्भिक परीक्षा 25 मई, 2025 को आयोजित हुई थी जिसमें प्राप्तांकों के आधार पर 14,161 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त की थी. मुख्य परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित की गई थी जिसके आधार पर 2736 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया था. मुख्य लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर परीक्षा का परिणाम 6 मार्च, 2026 को घोषित किया गया है.

इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल रहे कुल 958 अभ्यार्थियों में 659 पुरुष व 299 महिलाएँ हैं. इस प्रकार सफल अभ्यर्थियों में महिलाओं का प्रतिशत इस वर्ष 31·21 प्रतिशत रहा है पिछले वर्ष 2024 की परीक्षा में सफल महिलाओं का प्रतिशत 28·15 प्रतिशत ही था. विगत कुछ वर्षों में सफल अभ्यर्थियों में महिलाओं का प्रतिशत निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है–

परीक्षा वर्ष	सफल अभ्यर्थियों में महिलाओं का प्रतिशत
2016	23
2017	24
2018	24
2019	23
2020	28
2021	26
2022	34
2023	34·6
2024	28·15
2025	31·21

गुजरात में समान नागरिक संहिता पर विधेयक विधान सभा द्वारा पारित

विवाह, तलाक, उत्तराधिकार व लिव-इन जैसे मामलों में सभी के लिए समान नियम लागू करने के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code–UCC) विधेयक गुजरात विधान सभा ने 25 मार्च, 2026 को पारित किया है. विधान सभा द्वारा पारित यूसीसी विधेयक पर यह पंक्तियाँ लिखे जाने तक राज्यपाल की अनुमति लम्बित है. स्वतंत्रता के पश्चात् इस आशय का कानून बनाने वाला उत्तराखण्ड देश पहला राज्य है. गुजरात में समान नागरिक संहिता विधेयक के कानूनी रूप लेने के बाद यह देश का दूसरा राज्य होगा. गौरतलब है कि उत्तराखण्ड में इस आशय का कानून 27 जनवरी, 2025 से लागू किया गया था, जबकि गोवा में पुर्तगाली शासन-काल से ही समान नागरिक संहिता लागू है.

समान नागरिक संहिता का सबसे मजबूत पक्ष 'महिला सशक्तिकरण' कहा जा सकता है. विवाह के लिए कानूनी उम्र तलाक के मामले में सबके लिए समान नियम व बहु-विवाहों पर रोक से यह मुस्लिम महिलाओं को विशेष राहत प्रदान करेगा. लिव-इन में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन को इस विधेयक के तहत् अनिवार्य किया गया है तथा इसके उल्लंघन पर कारावास या जुर्माने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है. लिव-इन में रहने वाले जोड़ों के बच्चों के भविष्य का भी पूरा ध्यान इसमें किया गया है. आदिवासियों की सांस्कृतिक विशिष्टता को बचाए रखने के लिए उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है.

गुजरात का यह समान नागरिक संहिता विधेयक राज्य की भौगोलिक सीमाओं में रहने वाले सभी नागरिकों पर तो लागू होगा ही, साथ ही यह राज्य की सीमाओं के बाहर रहने वाले गुजरातियों पर भी प्रभावी होगा.

अनुसूचित जाति के किसी हिन्दू, सिख अथवा बौद्ध द्वारा कोई अन्य धर्म अपनाने से एससी का दर्जा समाप्त : सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

सामाजिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति के किसी हिन्दू, सिख अथवा बौद्ध धर्म के अनुयायी द्वारा कोई अन्य धर्म अपनाने की स्थिति में सम्बन्धित उसका अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाता है तथा उसे मिलने वाले सभी संवैधानिक एवं वैधानिक लाभ स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं. सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस पी. के. मिश्रा व जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 24 मार्च, 2026 को अपने इस फैसले में कहा कि कोई दलित व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाने के पश्चात् अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत् मिलने वाले किसी भी लाभ और संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है. सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह फैसला आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मई 2025 के एक फैसले के विरुद्ध धर्मान्तरण कर ईसाई पादरी बने चिंथदा आनंद की याचिका पर सुनाया. धर्म परिवर्तन कर ईसाई पादरी बने चिंथदा आनंद ने याचिका लगाई थी उन्हें कुछ लोगों से जातिगत भेदभाव व दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा. **सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि केवल हिन्दू, सिख व बौद्ध धर्म में ही अनुसूचित जातियाँ विद्यमान हैं तथा कोई अन्य धर्म अपनाने पर जन्म के आधार पर मिलने वाला यह दर्जा प्रभावी नहीं रहता.** सर्वोच्च न्यायालय के इस सम्बन्ध में 1950 के एक फैसले का हवाला देते हुए भी पीठ ने कहा कि **कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म का पालन करे तथा एससी होने का लाभ भी ले.**

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में संविधान के तहत् जारी अनुसूचित जाति आदेश के खण्ड 3 के हवाले से कहा गया है कि केवल वे ही व्यक्ति अनुसूचित जाति के माने जाएंगे जो हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म को मानते हों. यदि कोई व्यक्ति ईसाई या अन्य धर्म का पालन करता है तो वह अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आएगा, भले ही उसका जन्म किसी अनुसूचित जाति के समुदाय में हुआ हो.

दंत चिकित्सा व शिक्षा में सुधार के लिए डेंटल काउंसिल के स्थान पर नेशनल डेंटल कमीशन का गठन

मेडिकल शिक्षा के बाद सरकार ने अब दंत चिकित्सा में सुधार के लिए 'डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया' (DCJ) को भंग कर नए नियामक 'नेशनल डेंटल कमीशन' (NDC) का गठन किया है. इसके लिए औपचारिक अधिसूचना 19 मार्च, 2026 को जारी कर दी गई है. इसके साथ ही डीसीआई के स्थान पर एनडीसी की व्यवस्था लागू हो गई है. दंत चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए एनडीसी में तीन बोर्ड गठित किए गए हैं. इनमें से एक अंडर ग्रेजुएट एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एज्यूकेशन बोर्ड दंत शिक्षा की निगरानी करेगा. दूसरा, डेंटल एसेसमेंट एण्ड रेटिंग

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

बोर्ड दंत चिकित्सा एवं दंत शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन व उनकी मान्यता का काम देखेगा, जबकि तीसरा एथिक्स एण्ड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड दंत चिकित्सकों के पंजीकरण व आचार संहिता का काम सँभालेगा. डॉ. संजय तिवारी को नव गठित नेशनल डेंटल कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है. इस परिवर्तन के साथ ही डेंटिस्ट एक्ट 1948, जिसके तहत् डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, को अब निरस्त कर दिया गया है.

ज्ञातव्य है कि मेडिकल एज्यूकेशन में इसी तरह के सुधारों के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन सितम्बर 2020 में ही किया जा चुका है.

कालिंजर किले का पहाड़ी क्षेत्र राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल घोषित

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कांलिंजर किला (Kalinjar Fort) के पहाड़ी क्षेत्र को भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने मार्च 2026 में एक राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल (National Geo-Heritage Site) घोषित किया है. उत्तर प्रदेश में यह पहला भू-विरासत स्थल है. क्षेत्र को भू-विरासत स्थल घोषित करते हुए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अपर महानिदेशक ने 16 मार्च के एक समारोह में इसके भू-वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस क्षेत्र की दुर्लभ भू-वैज्ञानिक संरचना, एपार्चियन अन्कॉन्फॉर्मिटी (Eparchaeean Unconformity) विभिन्न परतों के बीच लम्बे समय के अन्तर को उजागर करती है जो पृथ्वी के भू-वैज्ञानिक इतिहास के एक लम्बे अन्तराल को दर्शाती है. उन्होंने बताया कि कालिंजर क्षेत्र की चट्टानें अरबों वर्ष के अन्तराल पर घटी भू-वैज्ञानिक घटनाओं को दर्शाती हैं. इस सम्बन्ध में जीएसआई की प्रेस-विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस पहाड़ी पर लगभग 2·0-2·5 अरब वर्ष पुराने बुंदेलखण्ड ग्रेनाइट के ऊपर करीब 1·2 अरब वर्ष पुराने कैमूर बलुआ पत्थर (Kaimur Sandstone) की परतें दिखाई देती हैं, जो पृथ्वी के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है. चट्टानों की अलग-अलग काल की परतें पृथ्वी के विकास को समझने में सहायक होती हैं.

भारत में 1851 ई. में स्थापित भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण भू-विरासत स्थलों की पहचान करने व उन पर अनुसंधान करने के लिए प्राथमिक प्राधिकरण है. इसकी संस्तुति के आधार पर भारत में लगभग 70 भू-स्थलों को राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है. मेघालय में स्थित भावमलुह गुफा, तिरुमाला पहाड़ियाँ, केरल स्थित बर्काला चट्टान खण्ड, सैंट मेरी द्वीप समूह व सेंट थामस माउंट पर चाकौनाइट आदि इनमें शामिल हैं.

नामीबिया व द. अफ्रीका के पश्चात् अब बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते

चीता पुनर्वास परियोजना के तहत् नामीबिया व द. अफ्रीका के पश्चात् अब अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 9 चीते 28 फरवरी, 2026 को भारत लाए गए. लगभग 7000 किमी का सफर तय कर इन चीतों को लेकर विशेष विमान पहले ग्वालियर एयरपोर्ट पहुँचा, जहाँ से वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा इन्हें श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुँचाया गया. इन 9 चीतों में 6 मादा और 3 नर चीते हैं. इसके साथ ही भारत में चीतों की संख्या अब 48 हो गई थी बाद में 9 मार्च को नामीबिया से लाई गई एक मादा चीते ने 5 शावकों को जन्म दिया जिससे देश में चीतों की कुल संख्या शावकों सहित 53 हो गई है (मार्च 2026 के अन्त की स्थिति).

बोत्सवाना से लाए गए 9 नए चीतों को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा. 9 नए चीतों को छोड़े जाने तथा 5 नए शावकों के जन्म के पश्चात् कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या 50 हो गई है (3 चीते मंदसौर जिले के गाँधी अभयारण्य में हैं).

ज्ञातव्य है कि 17 सितम्बर, 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो पार्क में छोड़कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परियोजना की शुरुआत की थी. इसके पश्चात् 18 फरवरी, 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते भारत लाए गए. इन 20 चीतों में से 11 चीते जीवित हैं, बोत्सवाना से 9 नए चीते लाए जाने तथा देश में ही प्रजनन से मार्च 2026 के अन्त में इनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है (मार्च 2026 के अन्त की स्थिति). कूनो में अब तक 45 शावकों का जन्म हुआ है, जिनमें से 33 जीवित हैं.

देश में संचालित फर्जी विश्वविद्यालयों की यूजीसी की ताजा सूची

विद्यार्थियों को फर्जी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से आगाह करने के लिए देश के विभिन्न भागों में संचालित फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी की जाती रही है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देश के विभिन्न भागों में संचालित 32 ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची एक बार पुनः अपनी वेबसाइट पर फरवरी 2026 में जारी की है. **यूजीसी की विज्ञप्ति के अनुसार यह विश्वविद्यालय विधिवत् स्थापित नहीं हैं तथा इनके द्वारा प्रदत्त कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा मान्य नहीं है. अतः इनमें प्रवेश लेने से आगाह विद्यार्थियों को किया गया है.** फर्जी विश्वविद्यालयों की इस सूची में सर्वाधिक 12 विश्वविद्यालय दिल्ली में व 3 उत्तर प्रदेश में हैं. यूजीसी की फरवरी 2026 की विज्ञप्ति में उल्लिखित ऐसे फर्जी संस्थानों/विश्वविद्यालयों की प्रदेशवार सूची निम्नलिखित है–

दिल्ली

1. ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एण्ड फिजिकल हैल्थ साइंस (ए.आई.पी.पी.एच.एस.) स्टेट गवर्नमेन्ट यूनिवर्सिटी, आफिस के एच नं. 608-609, प्रथम तल सन्त कृपाल सिंह पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग बी.डी.ओ. कार्यालय के पास अलिपुर, दिल्ली-36.
2. कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरिया गंज, दिल्ली.
3. यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली.
4. वॉकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली.
5. ए.डी.आर. सेन्ट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, ए.डी.आर. हाउस, 8जे, गोपाल टॉवर, 25 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
6. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड इंजीनियरिंग, नई दिल्ली.
7. विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट, इण्डिया, रोजगार सेवा सदन, 672, संजय एंक्लेव, अपोजिट जी.टी.के. डिपो, नई दिल्ली-110033.
8. आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी), 351-352, फेस-1, ब्लॉक-ए, विजय बिहार, रिठाला, रोहिणी, दिल्ली-110085.
9. वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी (डब्लू.पी.यू.एन.यू.), नम्बर-201, द्वितीय तल, बेस्ट बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034.
10. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग, 1810/4, प्रथम तल, कोटला मुबारकपुर, दिल्ली.
11. माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, 109, मधुबन बिल्डिंग, क्रांति की स्थिति कम्युनिकेशंस, 55, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019.
12. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोल्यूशन, बी-1/1, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058.

केरल

13. सेन्ट जॉन यूनिवर्सिटी कृष्णाटम्, केरल.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

14. इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन (आई.आई. यू.पी.एम.), कुन्नामंगलम कोजहिकोदे, केरला 673571.

महाराष्ट्र

15. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर, महाराष्ट्र.
16. नेशनल बैकवर्ड कृषि, विद्यापीठ, तड़वाल, ताल. अक्कलकोट, जिला– सोलापुर, महाराष्ट्र.

पश्चिम बंगाल

17. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसन, 80, चौरंगी रोड, कोलकाता-20.
18. इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसन एण्ड रिसर्च, 8-ए, डायमण्ड हार्बर रोड बिलटेक इन, 2 फ्लोर, ठाकुर, पूकूर, कोलकत्ता-70006

उत्तर प्रदेश

19. महामाया टेक्निकल (प्राविधिक) विश्वविद्यालय, पी.ओ. महर्षि नगर, जिला–गौतम बुद्ध नगर, सैक्टर-110 के पीछे, नोएडा-201304 उत्तर प्रदेश.
20. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश.
21. भारतीय शिक्षा परिषद् भारत भवन, मटियारी चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-227105.
22. गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद.

पुडुचेरी

23. श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, नं. 186, थीलासपेट, वाजुथवर रोड, पुडुचेरी-605009.
24. उषा लात्चुमनन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टी.वी. मलाई रोड, वाझापडियार नगर थिरुक्कनूर, पुडुचेरी-605501.

आन्ध्र प्रदेश

25. क्राइस्ट न्यू टेस्टामेन्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी, #32-23-2003,7वीं लेन, काकुमानुवरिहोट्टा, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश-522002 व फिट नं. 301, ग्रेस विला अपा., 7/5, श्रीनगर, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश-522002.
26. बाईबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इण्डिया, मकान नं. 49-35-26 एन.जी.ओ. कॉलोनी, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश-530016.

अरुणाचल प्रदेश

27. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, 130/A, सेक्रेटेरिएट एस.ओ., अरुणाचल प्रदेश-791111

हरियाणा

28. मैजिक एण्ड आर्ट यूनिवर्सिटी, 308ए, दशमेश प्लाजा, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा-121001.

कर्नाटक

29. सर्व भारतीय शिक्षा पीठ, एस. के. चौल्टरी के पास, देवनूर मेन रोड, विजया नगर, तुमकुर-572102, कर्नाटक.
30. ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी, #1035, चौथा ब्लॉक, गोल्डन हाइट्स के पास, डॉ. राजकुमार रोड, राजाजी नगर, बेंगलुरु-560010 (कर्नाटक)

राजस्थान

31. राजीव गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, मानसा चौक, भिवाड़ी, जिला अलवर (राजस्थान).

झारखण्ड

32. दक्ष यूनिवर्सिटी (वोकेशनल और लाइफ स्किल एजुकेशन), भास्कर पथ, न्यू पुंदाग, मसिबाड़ी, राँची, झारखण्ड-834007.

भारतीय नौसेना का दूसरा आईओएस सागर पहल

हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग सम्वर्धन के लिए भारतीय नौसेना ने अपना दूसरा ***आईओएस सागर*** *(IOS SAGAR–Indian Ocean Ship-Security and Growth for All in the Region) पहल 16 मार्च, 2026 को प्रारम्भ किया है. भारतीय नौसेना ने हिन्द महासागर नौसेना सिम्पोजियम (IONS) की अध्यक्षता फरवरी 2026 में ही ग्रहण की थी (देखें प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2026, पृष्ठ 15). इसलिए IOS SAGAR के दूसरे आयोजन में 16 IONS देशों के नौसैनिक शामिल थे.*

आईओएस सागर एक ऐसा संचालन सहभागिता कार्यक्रम है जो विदेशी मित्र देशों के नौसैनिकों को भारतीय नौसेना के जहाज पर एक साथ प्रशिक्षण और नौकायन में सक्षम बनाता है. *आईओएस पहल के 16 मार्च को शुरू हुए दूसरे आयोजन में 16 मित्र देशों के नौसैनिकों ने भाग लिया है. इस कार्यक्रम का प्रारम्भ भारतीय नौसेना के कोच्चि स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्रों के साथ हुआ, जहाँ प्रतिभागियों को नौसेना संचालन, समुद्री कौशल व समुद्री सुरक्षा से जुड़ी अवधारणाओं के प्रमुख पहलुओं से अवगत कराया गया. इसके अगले चरण में प्रतिभागियों को भारतीय नौसेना के जहाज पर तैनात किया गया जहाँ भारतीय नौसेना कर्मियों के साथ मिलकर समुद्र में संचालन गतिविधियों में उन्हें शामिल किया गया. आईओएस सागर पहल की इस दूसरी पहल के समापन की तिथि यह पंक्तियाँ लिखे जाने तक घोषित नहीं हुई थी.*

भारतीय नौसेना द्वारा आईओएस सागर की पहली पहल का आयोजन अप्रैल 2025 में किया गया था. लगभग एक माह तक आईएनएस सुनयना पर चले इस आयोजन में 9 मित्र देशों के 44 कर्मी शामिल हुए थे.

पंजाब में महिलाओं के लिए नई मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना

अपने एक चुनावी वायदे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पंजाब के भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आप (AAP) सरकार ने राज्य की सभी पात्र महिलाओं को ₹ 1000-1000 प्रतिमाह (अनु. जाति की महिलाओं के मामले में ₹ 1500-1500 प्रतिमाह) की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना 1 अप्रैल, 2026 से लागू करने की घोषणा राज्य के 2026-27 के बजट में की है. इस योजना को मुख्यमंत्री मावां धीयां योजना नाम दिया गया है तथा इसके लिए ₹ 9300 करोड़ का प्रावधान 2026-27 के बजट में किया गया है.

सरकारी कर्मचारी महिलाएँ (वर्तमान एवं पूर्व दोनों ही), आयकर दांता महिलाएँ तथा सांसद एवं विधायक (वर्तमान एवं पूर्व) इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं हैं. इनके अतिरिक्त राज्य की सभी स्थायी निवासी वयस्क महिलाएँ पंजीकरण करा कर इस योजना का लाभ ले सकती हैं. पहले से विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या अन्य कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन पा रही महिलाएँ भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं. योजना के तहत् देय राशि सीधे उनके बैंक खातों में ही जमा की जाएगी. सरकार का मानना है कि इस सहायता राशि से महिलाओं को घर के रोजमर्रा खर्च को पूरा करने तथा बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए मदद मिलेगी. ●●●

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित

उपकार

य.जी.सी. नेट जे.आर.एफ. सेट

शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता

(जनरल पेपर-I)

Code 200 ₹ 465.00

उपकार प्रकाशन, आगरा

• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



राज्य समाचार

झारखण्ड बजट (2026-27)

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए झारखण्ड सरकार का बजट राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 24 फरवरी, 2026 को विधान सभा में प्रस्तुत किया. हेमंत सिंह सोरेन के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट होने के साथ-साथ राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. ₹ 1,58,560 करोड़ के इस बजट को **'अबुआ दिशोम'** बजट नाम दिया गया है. इससे पूर्व इस राज्य के 2022-23 के बजट को **'हमर अपन बजट'**, 2023-24 व 2024-25 के बजट को **हमीन कर बजट** तथा 2025-26 के बजट को **अबुआ बजट** कहा गया था. यह पूर्व वर्ष 2025-26 के बजट से लगभग 9 प्रतिशत अधिक है. बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है.

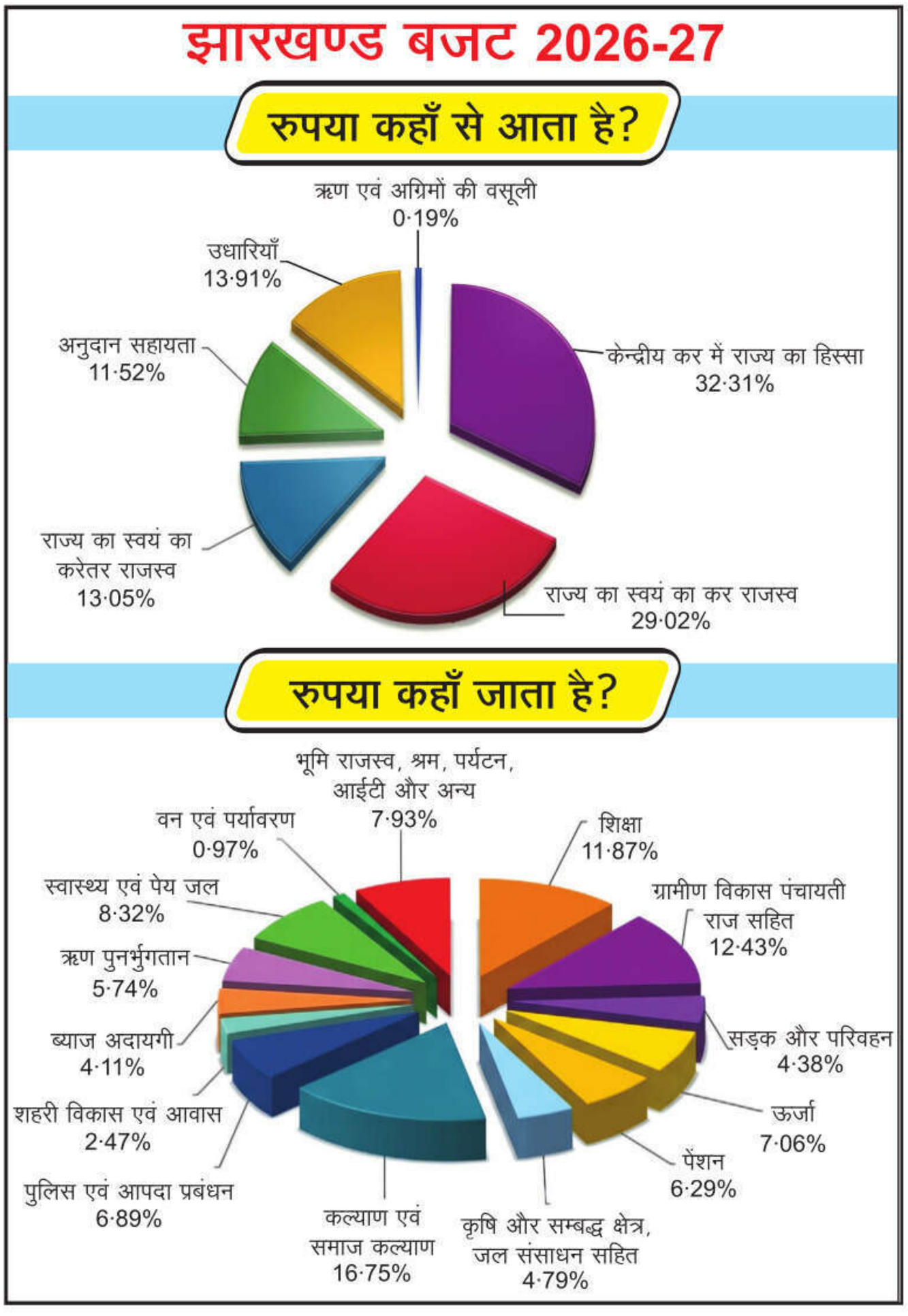
पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजट में सामाजिक क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है. ₹ 1,58,560 करोड़ के इस बजट में इस सेक्टर के लिए सर्वाधिक ₹ 67,460 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए ₹ 59,045 करोड़ का, सामान्य प्रक्षेत्र के लिए ₹ 32,056 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मुफ्त वितरण की योजनाओं पर भी विशेष ध्यान इस बजट में दिया गया है. मइयाँ सम्मान योजना, साबित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, धोती-लुंगी साड़ी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, किसानों के लिए सब्सिडी, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सीएम रोजगार सृजन योजना, कृषि ऋण माफी जैसी योजनाएँ सरकार की प्राथमिकता सूची में हैं. ₹ 14065·57 करोड़ केवल मइयाँ सम्मान योजना के लिए हैं जो कुल बजट का लगभग 8·67 प्रतिशत है.

बजट में इस बार बाल बजट के लिए भी ₹ 10,793 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जेंडर बजट ₹ 34,211 करोड़ का तथा ग्रामीण विकास का कुल बजट ₹ 12,347 करोड़ का



मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बजट की प्रति सौंपते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर

राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने बजट भाषण में बताया कि कोविड के बाद के वर्षों में (2021-22 से 2025-26) प्रचलित मूल्यों पर (At current prices) राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 14·1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. प्रचलित मूल्यों पर राज्य का GSDP 2024-25 में लगभग ₹ 5,16,000 करोड़ अनुमानित किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार का प्रयास अगले 5 वर्षों में इसे दोगुना करने का है. इसके लिए प्रचलित मूल्यों पर लगभग 14 प्रतिशत (स्थिर मूल्यों पर लगभग 9 से 10 प्रतिशत) की दर से विकास करना होगा. उन्होंने बताया कि वह सभी कारक जो एक बड़ी GSDP सुनिश्चित करते हैं, और उच्च विकास दर निर्धारित करते हैं, झारखण्ड में मौजूद है. उन्होंने बताया कि देश का लगभग 40 प्रतिशत खनिज भण्डार झारखण्ड में ही स्थित है तथा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 34 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है, जो कई मूल्यवान लघु वन उत्पादों का स्रोत है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य की आर्थिक विकास दर 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 6·90 प्रतिशत तथा प्रचलित मूल्यों पर 10·03 प्रतिशत रहने का अनुमान वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में व्यक्त किया.



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

झारखण्ड बजट : एक झलक (Budget : At a Glance)

(₹ करोड़ में)

मद	2025-26 बजट अनुमान (Budget Estimates)	2025-26 संशोधित अनुमान (Revised Estimates)	2026-27 बजट अनुमान (Budget Estimates)
1	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**125153·44**	**124932·32**	**136210·04**
2. कर राजस्व	**82240·22**	**84495·22**	**97236·38**
(क) केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	47040·22	46065·55	51236·38
(ख) राज्य का स्व कर-राजस्व	35200·00	38429·67	46000·00
3. कर-भिन्न राजस्व	**42913·22**	**40437·10**	**38973·66**
(क) राज्य का स्व कर-भिन्न राजस्व	25856·12	23380·00	20700·00
(ख) केन्द्र सरकार से अनुदान	17057·10	17057·10	18273·66
4. पूँजी प्राप्तियाँ	**20246·56**	**25342·76**	**22349·96**
(क) ऋणों की वसूली	246·56	357·34	300·00
(ख) अन्य प्राप्तियाँ (विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ)	0.00	0·00	0.00
(ग) उधार एवं अन्य देयताएँ	20000·000	24985·42	22049·96
5. कुल प्राप्तियाँ (1+4)	**145400·00**	**150275·09**	158560·00
6. स्थापना व्यय	**53658·47**	**54460·00**	**57669·00**
7. राजस्व खाते पर जिसमें	**44615·58**	**45291·13**	**48408·17**
(क) ब्याज भुगतान	6354·66	6354.66	6519·96
(ख) वेतन	20254.58	19895·74	21968·33
(ग) पेंशन	10173·12	10173·12	9967·40
8. पूँजी खाते पर जिसमें	**9042·89**	**9168·87**	**9260·83**
(क) राज्य का आंतरिक ऋण	8326·05	8326·05	8027·34
(ख) भारत सरकार से ऋण	420·51	420·51	426·83
(ग) पूँजी व्यय	0·00	0·00	0·00
(घ) ऋण एवं अग्रिम	296.34	422·31	806·66
9. स्कीम	**91741·53**	**95815·09**	**100891·00**
(क) राजस्व खाते पर	66021.12	70240·61	72443·73
(ख) जिसमें पूँजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	9416·35	10829·56	12744·14
(ग) पूँजी खाते पर	25720·41	25574·48	28447·27
10. कुल व्यय (6+9)	**145400**·00	**150275·09**	**158560·00**
(क) राजस्व व्यय (7+9 क)	110636·70	115531·74	120851·90
(ख) पूँजी खाते पर व्यय (8+9 ग)	34763·30	34743·35	37708·10
11. राजस्व घाटा (10क–1)	**–14516·74**	**–9400·58**	**–15358·14**
GSDP का प्रतिशत	**–2·61**	**–1·66**	**–2·46**
12. प्रभावी राजस्व घाटा (11–9ख)	**–23933·09**	**–20230·14**	**–28102·28**
GSDP का प्रतिशत	**–4·30**	**–3·56**	**–4·50**
13. राजकोषीय घाटा {10–(1+4क+4ख+8क+8ख)	**11253·44**	**16238·87**	**13595·79**
GSDP का प्रतिशत	**2·02**	**2·86**	**2·18**
14. प्राथमिक घाटा (13–7क)	**4898·78**	**9884·20**	**7075·83**
GSDP का प्रतिशत	**0·88**	**1·74**	**1·13**

है, जो पिछले वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 9,841 करोड़ का था

बजट पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनका असर आने वाले समय में धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2050 तक झारखण्ड को समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में यह बजट एक मजबूत आधार तैयार करेगा.

प्राप्तियों एवं व्यय का समायोजन

- वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश सरकार का कुल व्यय ₹ 1,58,560 करोड़ रहने का बजट अनुमान है, जो 2025-26 के बजट अनुमान ₹ 1,45,400 करोड़ से लगभग 9 प्रतिशत अधिक है.
- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध (Establishment and Committed Exp.) व्यय का बजट अनुमान ₹ 57,669 करोड़ है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान ₹ 53658·47 करोड़ से 7·5 प्रतिशत अधिक है.
- वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक स्कीम व्यय का कुल बजट अनुमान ₹ 1,00,891 करोड़ का है, वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में यह ₹ 91,741·53 करोड़ था.
- 2026-27 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय ₹ 1,20,851·90 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया है, जो 2025-26 में ₹ 1,10,636·70 करोड़ अनुमानित था.
- 2026-27 में कुल पूँजीगत व्यय ₹ 37,708·10 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो 2025-26 के बजट में ₹ 34,763·30 करोड़ अनुमानित था.
- इस प्रकार 2026-27 में राज्य सरकार के **राजस्व एवं पूँजीगत** व्यय क्रमशः ₹ 1,20,851·90 करोड़ एवं ₹ 37,708·10 करोड़ हैं, जो कुल व्यय ₹ 158,560 करोड़ का क्रमशः 76·22 एवं 23·78 प्रतिशत है.
- 2026-27 में राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,36,210·04 करोड़ अनुमानित हैं, जो 2025-26 के बजट अनुमान (₹ 1,25,153·44 करोड़) की तुलना में 8·8 प्रतिशत अधिक है.
- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के कुल ₹ 97,236·38 करोड़ के कर राजस्व में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में ₹ 46,000 करोड़ अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान ₹ 35,200 करोड़ से 30·7 प्रतिशत अधिक है. कर राजस्व में शेष ₹ 51,236·38 करोड़ केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में अनुमानित है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

- 2026-27 में राज्य को अपने स्रोतों से गैर-कर राजस्व के रूप में ₹ 20,700 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है, जो 2025-26 बजट अनुमान ₹ 25,856·12 करोड़ की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत कम है. इन प्राप्तियों एवं व्यय के यह बजट अनुमान एक दृष्टि में बजट एक झलक बॉक्स में दर्शाए गए हैं.

राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा

- उपर्युक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि 2026-27 में राजस्व घाटा (Revenue Deficit) – ₹ 15,358·14 करोड़ रहने का अनुमान है, जो राज्य के GSDP का – 2·46 प्रतिशत होगी. 2025-26 में राजस्व घाटा – ₹ 14,516·74 करोड़ अनुमानित की गई थी, किन्तु संशोधित आकलन में यह – ₹ 9,400·58 करोड़ रही है.
- 2025-26 में राजकोषीय घाटा ₹ 11,253·44 करोड़ [जीएसडीपी (Gross State Domestic Product) का 2·02 प्रतिशत] पिछले वर्ष बजट में लक्षित था, जो संशोधित आकलन में यह जीएसडीपी का 2·86 प्रतिशत अनुमानित किया गया है. 2026-27 में राजकोषीय घाटा ₹ 13,595·79 करोड़ (जीएसडीपी का 2·18 प्रतिशत) रहने का लक्ष्य बजट में है.

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य/बजटीय घोषणाएँ

- बजट में कोई नया कर नहीं, न ही पहले के किसी कर में वृद्धि.
- ₹ 1,58,560 करोड़ के बजट में राजस्व व्यय ₹ 1,20,851·90 करोड़ (कुल व्यय का 76·22 प्रतिशत) तथा पूँजीगत व्यय ₹ 37,708·10 करोड़ (कुल व्यय का 23·78 प्रतिशत).
- बाल बजट हेतु ₹ 10,793 करोड़ का प्रावधान.
- मइयाँ सम्मान योजना हेतु ₹ 14,065·57 करोड़ (कुल बजट का 8·67 प्रतिशत).
- 2026-27 में राजस्व आधिक्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 2·46 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2·18 प्रतिशत रखने का लक्ष्य.
- 2026-27 में राज्य में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे,
- महिला किसानों के लिए नई महिला खुशहाली योजना शुरू करने की घोषणा.
- चतरा जिले में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी.
- 2026-27 में नए पथों के निर्माण हेतु ₹1000 करोड़ का बजटीय प्रावधान है.
- राँची जिले में दशम् व जोन्हा जलप्रपात में ग्लास ब्रिज व रोप वे का निर्माण 2026-27 में किया जाएगा.
- धनबाद में 2 तथा पलामू, लातेहार व गढ़बा में 1-1 (कुल 5) नए झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा.

उत्तराखण्ड बजट (2026-27)

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखण्ड सरकार का बजट राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण स्थित भराड़ी सैण्ड विधान सभा में 9 मार्च, 2026 को प्रस्तुत किया. चुनावी वर्ष के अपने इस बजट को उत्तराखण्ड के भविष्य का रोडमैप बताते हुए राज्य के समग्र विकास की दिशा तय करने वाला बजट उन्होंने बताया है. राज्य का पिछला 2025-26 का बजट जहाँ ज्ञान (GYAN–गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी सशक्तिकरण) पर फोकस बताया गया था, वहीं 2026-27 के ताजा बजट को ज्ञान के साथ विज्ञान (VIGYAN–Value Based, Inovation Drivin, Good Governance, Youth Powered, Accountability तथा नए उत्तराखण्ड) की धारणा पर बजट अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने बताया है. **इसके साथ ही अलग-अलग वर्गों के लिए किए गए प्रावधानों को संतुलन (SANTULAN) पर आधारित उन्होंने बताया है, जिसमें S–समावेशी विकास, A–आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड, N–नई सोच, T–तीव्र विकास, U–उन्नत शहर एवं गाँव, L–लोक सहभागिता, A–आर्थिक शक्ति तथा N–न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए है. बजटीय प्रावधानों में इन 8 मंत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है.**



विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखण्ड बजट 2026-27 का सार
(Budget At a Glance)

(₹ करोड़ में)

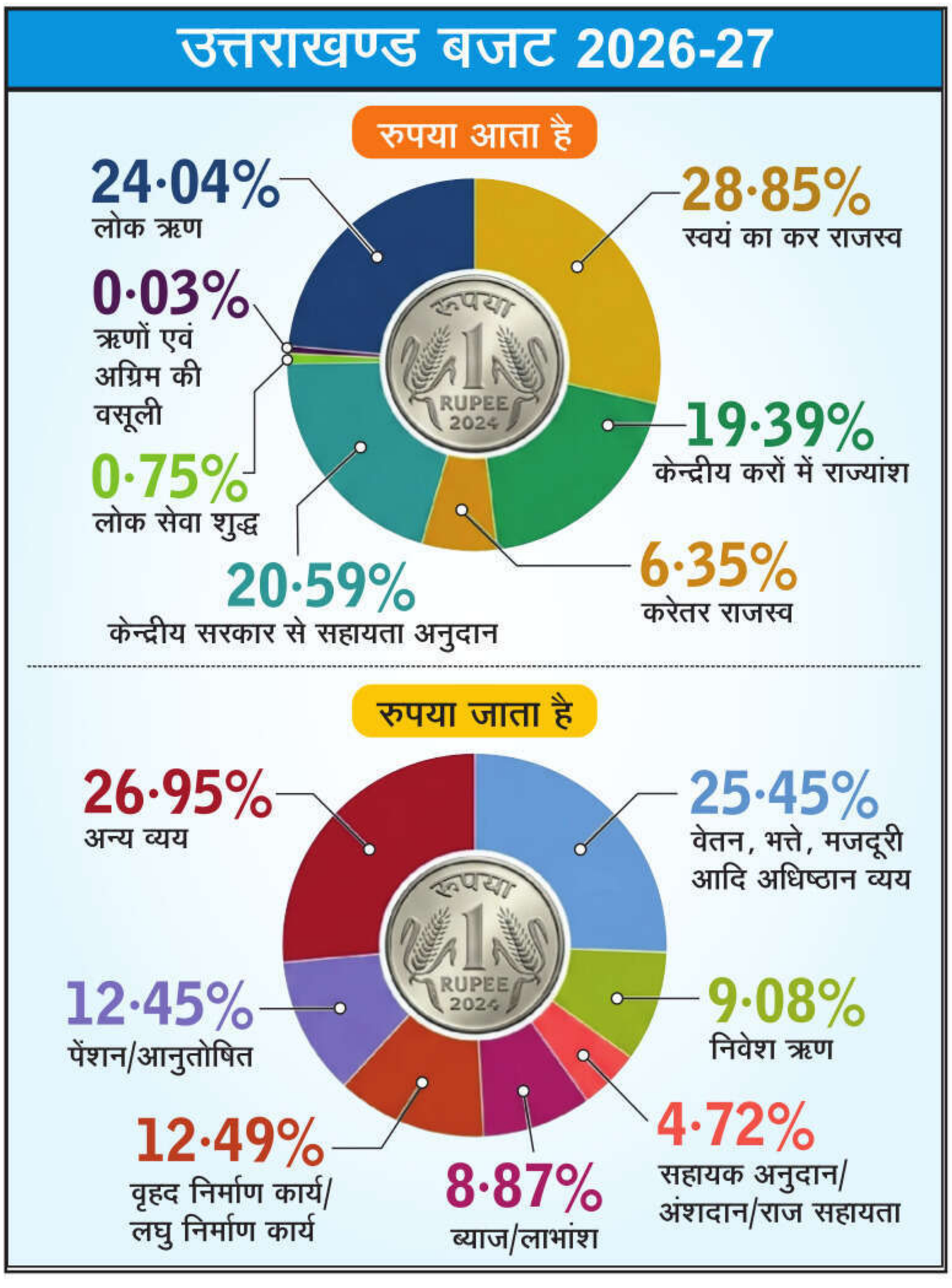
क्र. सं.	विषय (Subject) प्राप्तियाँ	2025-26 बजट अनुमान (Budget Estimates)	2025-26 संशोधित अनुमान (Revised Estimates)	2026-27 बजट अनुमान (Budget Estimates)
1.	राजस्व प्राप्तियाँ	62540·54	62639·45	67525·77
2.	कर राजस्व	39917·74	39253·44	43327·43
3.	करेतर राजस्व	22622·80	23386·01	24198·34
4.	**पूँजी प्राप्तियाँ**	**38494·21**	**39576·36**	**42617·35**
5.	ऋणों की वसूलियाँ	24·21	26·36	27·35
6.	उधार एवं अग्रिम की वसूली	38470·00	39550·00	42590·00
7.	जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	19500·00	19500·00	21000·00
8.	**कुल प्राप्तियाँ (1+4)**	**101034·75**	**102215·81**	**110143·12**
9.	**राजस्व व्यय**	**59954·65**	**60178·38**	**64989·44**
10.	ब्याज अदायगियाँ	6990·14	6625.50	7929·40
11.	**पूँजीगत व्यय जिसमें**	**41220·68**	**41432·66**	**46713·77**
12.	**पूँजीगत परिव्यय**	**14763·13**	**14883·35**	**18152·73**
13.	ऋणों की अदायगियाँ	26005·66	26005·62	28160·63
14.	जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान	19500·00	19500·00	21000·00
15.	ऋण और अग्रिम	451·89	543·69	400·41
16.	**कुल व्यय (9+11)**	**101175·33**	**101611·04**	**111703·21**
17.	**राजस्व अधिशेष (1–9)**	**2585·89**	**2461·07**	**2536·33**
18.	**राजकोषीय घाटा**	**12604·92**	**10639·62**	**12579·70**
19.	**प्रारम्भिक घाटा (18–10)**	**5614·78**	**4014·12**	**4650·30**

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

विधान सभा के मौजूदा कार्यकाल में राज्य के इस अंतिम बजट को राजस्व सरप्लस रखते हुए किसी नए कर का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है तथा न ही किसी कर की दर में कोई वृद्धि की गई है. ₹1,11,703·21 करोड़ के इस बजट में, जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, सरकार के कुल व्यय का 41·8 प्रतिशत भाग पूँजीगत व्यय के रूप में निर्धारित है. इससे अवस्थापना विकास में मदद मिलेगी. समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए समुचित प्रावधान बजट में किए गए हैं. खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति राज्य में लागू की गई है. कृषि विभाग व लोक निर्माण विभाग आदि सहित विभिन्न सरकारी विभागों के लिए प्रावधान बजट में किए गए हैं. महिला कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं, यथा—मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि और निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान आदि के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. केन्द्र द्वारा प्रायोजित 'वीबी-जी राम जी' योजना के लिए ₹ 705 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है.

प्राप्तियाँ एवं व्यय का समायोजन

- बजट में 2026-27 के दौरान प्रदेश सरकार का कुल व्यय ₹1,11,703·21 करोड़ अनुमानित है, जो पूर्व वर्ष 2025-26 के ₹1,01,175·33 करोड़ के व्यय (बजट अनुमान) की तुलना में 10·4 प्रतिशत अधिक है. कुल प्रस्तावित ₹1,11,703·21 करोड़ के प्रस्तावित व्यय में ₹64,989·44 करोड़ राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) तथा ₹46,713·77 करोड़ पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure) के रूप में प्रस्तावित है. राजस्व व्यय में ₹7,929·40 करोड़ ब्याज भुगतान हेतु प्रस्तावित है.



- 2026-27 में प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts) ₹67,525.77 करोड़ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts) ₹42,617·35 करोड़ अनुमानित हैं. ₹67,525·77 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में ₹43,327·43 करोड़ कर राजस्व तथा शेष ₹24,198·34 करोड़ करेतर राजस्व (Non-Tax Revenue) हैं.
- ₹42,617·35 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियों में ₹27·35 करोड़ ऋणों की वसूली (Recoveries of Loans) ₹42,590·00 करोड़ केन्द्र से ऋण के रूप में शामिल हैं.
- प्राप्तियों एवं व्यय के उपर्युक्त आँकड़ों के चलते 2026-27 के दौरान प्रदेश सरकार का राजस्व आधिक्य ₹2,536·33 करोड़ अनुमानित किया गया है.
- बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) ₹12,579·70 करोड़ (जीएसडीपी का 2·94 प्रतिशत) व प्राथमिक घाटा (Primary Deficits) ₹4,650·30 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया है.

अन्य प्रमुख तथ्य/बजटीय घोषणाएँ

- 2026-27 के लिए ₹1,11,703·21 करोड़ का बजट पूर्व वर्ष को तुलना में 10·41 प्रतिशत अधिक.
- बजट में अलग-अलग वर्गों के लिए प्रावधान SANTULAN पर आधारित
- बजट में कोई नया कर नहीं.
- 2026-27 में कुल सरकारी व्यय का 41·8 प्रतिशत भाग पूँजीगत व्यय.
- महिलाओं के जेंडर बजट ₹19,692·02 करोड़ का (पूर्व वर्ष की तुलना में ₹2700 करोड़ अधिक.
- विकसित भारत-जी राम जी योजना के लिए ₹ 705 करोड़ का प्रावधान.
- **अटल आयुष्मान योजना** के लिए ₹600 करोड़.
- हरिद्वार में अर्द्धकुम्भ मेले के लिए ₹1027 करोड़ का प्रावधान.
- किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए घेरबाड़ योजना.
- स्टार्टअप्स व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप वेचर फंड के लिए ₹25 करोड़.
- पॉलीटेक्निक संस्थानों में **इमरजिंग टेक्नोलॉजी** लैब्स की स्थापना.
- नई खेल नीति के तहत् **मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना** के तहत् 8-14 वर्ष आयु वर्ग के प्रति जनपद 300 चयनित छात्र-छात्राओं को ₹1500 प्रति माह तथा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत् 14-23 वर्ष आयु वर्ग के प्रति जनपद

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



UPSC NEW BOOKS PDF

2026 EDITION

अब UPSC STANDARD BOOKS 2026 की PDF सीधे टेलीग्राम पर लें सकते है
बस हमारी टेलीग्राम बॉट पर मैसेज करें

Telegram Bot - @pdfhub2026bot

सीधे मैसेज भेजने के लिए MESSAGE NOW पर क्लिक करें

Message Now

चयनित 200 खिलाड़ियों को ₹2000 प्रति माह की छात्रवृत्ति.

- **अमृत मिशन** के तहत् राज्य में सड़कें, जलापूर्ति व अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार शहरों में किया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश

प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियाँ : 2024-25 के खेल पुरस्कारों का भी वितरण

उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन 24 मार्च, 2026 को लखनऊ में लोक भवन में किया गया. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 खिलाड़ियों को सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति-पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदान किए, जबकि प्रदेश के 5 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार तथा 4 महिला खिलाड़ियों को लक्ष्मीबाई पुरस्कार उन्होंने प्रदान किए.

निम्नलिखित 6 अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति-पत्र दिए गए—

- राजकुमार पाल (हॉकी)—डीएसपी
- प्रवीण कुमार (पैरालम्पिक ऊँची कूद)—डीएसपी
- अजीत सिंह (पैरालम्पिक भाला फेंक)—जिला पंचायत राज अधिकारी
- सिमरन (पैरालम्पिक एथलेटिक्स)—जिला पंचायत राज अधिकारी
- प्रीतिपाल (पैरालम्पिक एथलेटिक्स)—खण्ड विकास अधिकारी
- रिंकू सिंह (क्रिकेट)—क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी

निम्नलिखित खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिए गए—

पुरुष खिलाड़ियों के लक्ष्मण पुरस्कार (2024-25)

- उत्तम सिंह—गाजीपुर-हॉकी
- अभिजीत कुमार—प्रयागराज-जिम्नास्टिक
- जोंटी कुमार—नोएडा-कुश्ती
- यश कुमार—आगरा-पैरा कैनोइंग
- प्रवीण कुमार—नोएडा-पैरा एथलेटिक्स

महिला खिलाड़ियों के रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार (2024-25)

- प्राची—सहारनपुर-एथलेटिक्स
- तान्या चौधरी—बागपत-एथलेटिक्स
- प्रगति केसरवानी—लखनऊ-पैरा टेबल टेनिस
- वंतिका अग्रवाल—नोएडा-शतरंज

लक्ष्मण पुरस्कार व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार विजेताओं को कांस्य प्रतिमा व प्रशस्ति-पत्र के साथ ₹ 3·11-3·11 लाख की राशि पुरस्कार के तहत् प्रदान की गई. कई अन्य खिलाड़ियों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए नकद पुरस्कार मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किए गए.

लक्ष्मण पुरस्कार व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों के तहत् देय राशि को बढ़ा कर अगले वर्ष से ₹ 10-10 लाख करने की घोषणा भी इस समारोह में की गई.

मध्य प्रदेश

भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष

मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व मंत्री व ग्वालियर से लोक सभा के सदस्य रह चुके भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया को मध्य प्रदेश के छठवें वित्त आयोग का अध्यक्ष मार्च 2026 में बनाया गया है. विधान सभा के सेवानिवृत्त अपर सचिव वीरेन्द्र कुमार को आयोग का सदस्य सचिव तथा राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के.के. सिंह इसके सदस्य बनाए गए हैं. आयोग ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों को आवंटित की जाने वाली राशि की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा.

छत्तीसगढ़

महासमुंद जिले में खल्लारी माता मंदिर क्षेत्र में रोपवे का केबल टूटने से कई श्रद्धालु घायल एक की मृत्यु

नवरात्रि के दिनों में दर्शन के लिए महासमुंद जिले में खल्लारी धाम पहुँचा श्रद्धालुओं का एक जत्था रोपवे से नीचे आते समय केबल टूटने से गम्भीर दुर्घटना का शिकार हुआ. केबल टूटने से ट्रॉली तेज गति से नीचे आ टकराई. साथ ही नीचे से ऊपर जा रही ट्रॉली, जिसमें 10 लोग सवार थे, भी अनियंत्रित होकर तेजी से नीचे आई. इस दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए.

खल्लारी माता मंदिर क्षेत्र में यह रोपवे 2 वर्ष पूर्व ही स्थापित किया गया था तथा इसके रखरखाव की जिम्मेदारी कोलकाता स्थित कम्पनी रोपवे एण्ड रिसॉर्ट्स प्रा. लि. को सौंपी गई थी. कम्पनी प्रबन्धन के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है.

राजस्थान

राजस्थान में गाँव ग्वाला योजना

गोवंश को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राजस्थान में एक नई गाँव ग्वाला योजना प्रारम्भ की गई है. इसके तहत् गोवंश को चराने के लिए प्रत्येक गाँव में एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा जो प्रतिदिन गाँव के सभी गोवंश को एकत्रित कर गोचर भूमि में ले जाएगा तथा दिनभर गोवंश को चराने के पश्चात् शाम को उनके मालिक के घर वापस छोड़ेगा. ऐसे प्रत्येक ग्वाला को ₹10 हजार प्रति माह मानदेय प्रदान करने की घोषणा राज्य के पंचायती राज मंत्री ने की है.

राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम अब अबूराज, दो अन्य शहरों के नाम भी बदले

लोगों की स्थानीय भावनाओं का सम्मान करते हुए राजस्थान में माउंट आबू का नाम बदलकर अबूराज करने की घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 27 फरवरी, 2026 को विधान सभा में की. इसके साथ ही डीग जिले में स्थित धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के कस्बे कामाँ (कमान-Kaman) का नाम बदलकर काम वन करने तथा जैन समुदाय के स्वस्तिधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर का नाम यज्ञपुर करने की घोषणा उन्होंने की.

मुख्यमंत्री के अनुसार, इन शहरों के नाम में यह परिवर्तन स्थानीय भावनाओं का सम्मान करने तथा इन शहरों व कस्बों की ऐतिहासिक पहचान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किए गए हैं. ●●●

PRATIYOGITA DARPAN

"Your Feedback, Our Guidance"

SCAN ME!

Scan and Share Your Experience With Us

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

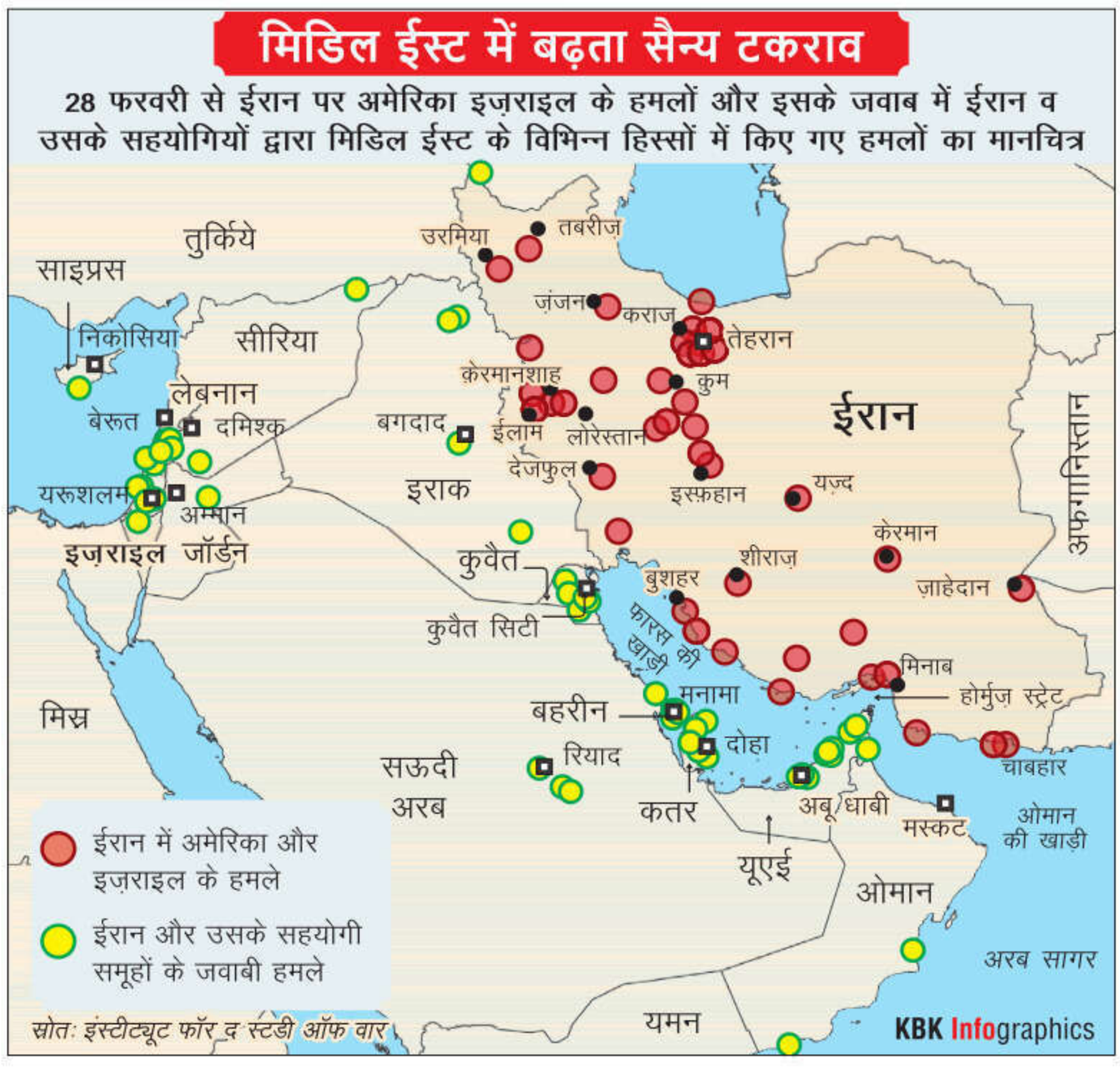
- ईरान पर अमेरिका व इजरायल के हमले से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल
- राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के युवा नेता बालेन्दु शाह नेपाल के नए प्रधान-मंत्री : दिग्गज राजनीतिज्ञों की चुनाव में करारी पराजय
- फिनलैण्ड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की भारत यात्रा
- 11वाँ रायसीना संवाद नई दिल्ली में सम्पन्न
- कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा
- हथियारों की खरीद में भारत का विश्व में यूक्रेन के पश्चात् दूसरा स्थान बरकरार, अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता : स्वीडिश संस्था SIPRI की रिपोर्ट
- इटली में न्यायिक सुधारों के लिए कराए गए जनमत संग्रह में जॉर्जिया मेलोनी सरकार की पराजय

ईरान पर अमेरिका व इजरायल के हमले से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल

विश्व अभी रूस-यूक्रेन युद्ध की विभीषिका से उभरा नहीं था कि एक और बड़े युद्ध ने अमेरिका के साथ-साथ सम्पूर्ण पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे सम्पूर्ण विश्व व वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल छा गए हैं. इस विकराल युद्ध में एक ओर जहाँ अमेरिका व इजरायल हैं, तो दूसरी ओर ईरान इनके हमलों का जवाब अपनी पूरी ताकत से दे रहा है. 28 फरवरी, 2026 से शुरू हुई इस भीषण लड़ाई ने सम्पूर्ण विश्व में खनिज तेल व गैस सहित अधिकांश उत्पादों की आपूर्ति लड़खड़ा दी है.

अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की अमेरिकी चेतावनियों व धमकियों की ईरान द्वारा लगातार उपेक्षा के चलते अमेरिका द्वारा 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' (Operation Epic Fury) तथा इजरायल द्वारा 'ऑपरेशन राइजिंग लायन' (Operation Rising Lion) के तहत् 28 फरवरी, 2026 को ईरानी सैन्य ठिकानों व परमाणु केन्द्रों के साथ-साथ शीर्ष ईरानी नेतृत्व पर भीषण हमले किए, जिनमें ईरान के अनेक सैन्य ठिकानों व परमाणु केन्द्रों के नष्ट होने के साथ-साथ ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की भी मृत्यु हो गई. खामनेई को सुरक्षित ठिकाने पर पहुँचाने का दावा ईरान की ओर से शुरू में यद्यपि किया गया, किन्तु बाद में उनकी मृत्यु की पुष्टि करते हुए उन्हीं के पुत्र मोजतबा खामनेई को ही सर्वोच्च नेता चुने जाने की बात कही गई है.

अमेरिका व इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा है, उसने भी अमेरिका व इजरायल के सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाते हुए सैकड़ों मिसाइलें इन पर दागीं. पश्चिम एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर व बहरीन आदि देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया. इन देशों के तेल केन्द्रों को भी क्षति इन हमलों से पहुँची है. हवाई हमलों की आशं का में अपने हवाई अड्डों को भी इन्होंने शुरू में बन्द कर दिया था जिससे हजारों यात्री विभिन्न हवाई अड्डों पर फँस गए थे. भारत के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए आया एक ईरानी जहाज वापस लौटते समय अमेरिका के एक तारपीडो हमले में डूब गया. उस पर सवार कुछ ईरानी नौसैनिकों को यद्यपि बचा लिया गया, इसके बावजूद 80 से अधिक ईरानी नौसैनिक जहाज पर हुए हमले में मारे गए. **एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए ईरान ने महत्वपूर्ण**



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

तेल मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रास्ते तेल परिवहन लगभग बन्द कर दिया है जिससे भारत सहित अधिकांश देशों में तेल व गैस संकट उत्पन्न हो गया है. ईरानी हमलों को देखते हुए खाड़ी देशों में फँसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए कदम विभिन्न देशों ने उठाए हैं. युद्ध के चलते आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित होने से वैश्विक बाजार बुरी तरह से प्रभावित हैं. उधर लगातार नुकसान उठा रहे ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामनेई ने लम्बे समय तक चलने वाले युद्ध की चेतावनी दी है. इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक साक्षात्कार में कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुँच चुका है तथा ईरान में निशाना बनाने के लिए अब लगभग कुछ नहीं बचा है, इसलिए यह युद्ध अब जल्द ही समाप्त हो सकता है. **युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका की ओर से 15 सूत्रीय प्रस्ताव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की समाप्ति, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निगरानी, ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबन्ध व होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की शर्तें शामिल हैं. अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकराते हुए ईरान की स्पष्ट प्रतिक्रिया यह रही है कि युद्ध विराम उसकी शर्तों पर ही होगा. ईरान की ओर से युद्ध समाप्त करने के लिए कोई तत्परता नहीं दर्शाई गई है. उल्टे उसने इसके लिए 5 शर्तें रखी हैं (25 मार्च की स्थिति). इनमें आक्रमणों व हत्याओं पर पूरी तरह से रोक, युद्ध से हुए नुकसान के लिए हर्जाने का भुगतान तथा होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी अधिकार की सम्प्रभुता की अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता आदि शामिल हैं. युद्ध समाप्ति के लिए शर्तों के आदान-प्रदान के बीच एक-दूसरे के ठिकानों पर गम्भीर हमलों का सिलसिला भी यह पंक्तियाँ लिखे जाने तक जारी था. लगभग एक माह से चल रही इस लड़ाई का फोकस अब होर्मुज स्ट्रेट पर सम्प्रभुता पर आ गया प्रतीत होता है.** यह पंक्तियाँ लिखे जाने तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हमले रोकते हुए होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 10 दिन की डैडलाइन 28 मार्च तक दी थी. उधर ईरानी ठिकानों पर इजरायल के हमले यह पंक्तियाँ लिखे जाने तक जारी थे तथा इजरायल के साथ-साथ अमेरिका के पश्चिम एशिया में स्थित ठिकानों पर ईरानी हमले भी जारी थे. मार्च के अन्त तक 1900 से अधिक लोगों की मौत तथा 20 हजार से अधिक के घायल होने की आशंका व्यक्त की गई थी जबकि अमेरिका के भी 300 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने व 13 सैनिकों की मृत्यु की बात मीडिया रिपोर्टों में कही जा रही थी. ईरान के मिसाइली हमलों से इजरायल में भी काफी तबाही हुई है. वैसे कूटनीतिज्ञों का यह मानना है कि अमेरिका व इजरायल के लिए यह युद्ध उनकी उम्मीद से कहीं अधिक भारी पड़ रहा है. यह युद्ध कब तक चलेगा, इस बारे में अलग-अलग अटकलें ही लगाई जा रही हैं.

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के युवा नेता बालेन्द्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री : दिग्गज राजनीतिज्ञों की चुनाव में करारी पराजय

नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के लिए 5 मार्च, 2026 को कराए गए चुनावों से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है तथा युवाओं व तकनीकी नेतृत्व को बढ़ावा देने तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन के वायदे के साथ उभरी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने नई सरकार का गठन वहाँ मार्च 2026 में किया है.



काठमांडू में बालेन्द्र शाह को नेपाल के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, साथ में हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री सुशीला कार्की

देश के वर्षों तक सत्तारूढ़ रहे कई बड़े राजनीतिक चेहरों को पराजय का सामना समय पूर्व ही कराए गए इस चुनाव में करना पड़ा है. पूर्व वर्षों में प्रधानमंत्री रह चुके शेरबहादुर देउवा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में जहाँ केवल 38 सीटें ही प्राप्त हो सकी हैं, के.पी. शर्मा 'ओली' के नेतृत्व वाली कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल [यूनीफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट–CPN (UML)] को 25 तथा पुष्प कुमार दहल के नेतृत्व वाली नेपाली कम्यूनिस्ट पार्टी (NCP) को 17 सीटें ही इस चुनाव में प्राप्त हुई हैं, जबकि युवा नेता बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने 182 सीटें जीत कर दो-तिहाई बहुमत इस चुनाव में प्राप्त किया है. पार्टी की इन 182 सीटों में 125 सीटें प्रथम मत प्राप्ति प्रणाली (First Past the Post System–FPPS) द्वारा तथा 57 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation System) से जीती हुई हैं. पिछले 2022 के चुनाव में आरएसपी की सीटों की संख्या 20 ही थी, जबकि नेपाली कांग्रेस ने सर्वाधिक 89, सीपीएन (यूएमएल) ने 78 तथा नेपाली कम्यूनिस्ट पार्टी (NCP) ने 45 सीटों पर विजय प्राप्त की थी. चार बार प्रधानमंत्री रहे के.पी. शर्मा ओली (CPN-UML) स्वयं आरएसपी नेता बालेन्द्र शाह से 50 हजार से अधिक मतों से चुनाव में पराजित हुए हैं.

चुनाव के इन परिणामों के चलते राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के युवा नेता बालेन्द्र शाह नए प्रधानमंत्री वहाँ बने है. 35 वर्षीय बालेन्द्र शाह नेपाल के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं. उनके साथ कुछ अन्य मंत्रियों ने भी शपथ 28 मार्च को ग्रहण की है.

ज्ञातव्य है कि सितम्बर 2025 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जेन-जी के हिंसक आन्दोलन ने सीपीएन-यूएमएल के के. पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार का तख्ता पलटा था तथा नए चुनावों तक पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार का गठन वहाँ किया गया था. अन्तरिम सरकार ने संसद भंग करते हुए नए चुनाव 5 मार्च, 2026 को कराने की घोषणा बाद में वहाँ की थी. तदुनुरूप ही 5 मार्च को कराए गए चुनावों के पश्चात् बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में नई निर्वाचित सरकार का गठन वहाँ 28 मार्च, 2026 को हुआ है. 35 वर्षीय बालेन्द्र शाह पूर्व में रैपर व स्ट्रक्चरल इंजीनियर रहे हैं. मई 2022 से जनवरी, 2026 तक काठमांडू के मेयर वह रहे हैं. काठमांडू के मेयर चुने जाने वाले वह पहले निर्दलीय प्रत्याशी थे.

चुनाव परिणाम एक दृष्टि में

पार्टी	सदस्यों की संख्या		
	2026	2022	लाभ/हानि
राष्ट्रीय स्वंतत्र पार्टी	182	20	+160
नेपाली कांग्रेस	38	89	–51
सीपीएन (यूएमएल)	25	78	–53
नेपाली कम्यूनिस्ट पार्टी	17	45	–28
अन्य	12		
निर्दलीय	1	3	–2
योग	**275**		

फिनलैण्ड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की भारत यात्रा

अपने देश के उच्च-स्तरीय शिष्टमण्डल के साथ फिनलैण्ड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब (Alexander Stubb) 4 दिन की राजकीय यात्रा के लिए 4 मार्च, 2026 को नई दिल्ली पहुँचे. उनकी इस यात्रा से कुछ ही दिन पूर्व फिनलैण्ड के प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पो (Petteri Orpo) 18-19 फरवरी को नई दिल्ली

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

में सम्पन्न 'एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए थे. उनकी इस यात्रा के पश्चात् राष्ट्रपति स्टब (4-7 मार्च, 2026) की यह यात्रा राष्ट्रपति के रूप में इनकी पहली ही भारत यात्रा थी, जिसका मुख्य उद्देश्य नई दिल्ली में 5-7 मार्च को रायसीना संवाद (Raisina Dialogue) में भाग लेने के अतिरिक्त प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों पर बात कर इसे नए आयाम प्रदान करना था. रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता (Keynote Speaker) के रूप में वह आमंत्रित थे.



नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ फिनलैण्ड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब

4 दिन की इस यात्रा के लिए 4 मार्च को नई दिल्ली पहुँचने पर 'गार्ड ऑफ ऑनर' के साथ पालम हवाई अड्डे पर उनका स्वागत विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया. 5 मार्च को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउण्डेशन (ORF) द्वारा विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित रायसीना संवाद के उद्घाटन समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेते हुए फिनलैण्ड के राष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि पश्चिमी प्रभुत्व वाला युग अब समाप्त हो रहा है तथा भविष्य की दिशा अब ग्लोबल साउथ तय करेगा, क्योंकि उसके पास ही अब जनसांख्यिकीय एवं आर्थिक शक्ति है. उन्होंने कहा कि अगली विश्व व्यवस्था तय करने में भारत एक निर्णायक शक्ति होगा. वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता का उन्होंने भरपूर समर्थन किया.

5 मार्च को ही प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात् फिनलैण्ड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भेंट की. मेहमान राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए भारतीय राष्ट्रपति ने 'विकसित भारत' की दिशा में भारत की यात्रा में फिनिश कम्पनियों की सराहना करते राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि अनेक भारतीय कम्पनियाँ फिनलैण्ड में सक्रिय हैं तथा हजारों भारतीय, विशेषतः आईटी पेशेवर फिनलैण्ड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. सतत् विकास एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में फिनलैण्ड के नेतृत्व की सराहना भी भारतीय राष्ट्रपति ने की.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ मेहमान राष्ट्रपति स्टब की वार्ता 5 मार्च को ही हुई. हैदराबाद हाउस में वार्ता में पूर्व राजघाट पर महात्मा गाँधी को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की. बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता से दोनों नेताओं ने भारत व फिनलैण्ड की गहरी व स्थायी मित्रता की पुष्टि करते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया. भारत व यूरोपीय संघ (EU) के बीच 27 जनवरी, 2026 को सम्पन्न स्वतंत्र व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसके लाभकारी अवसरों को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया. भारत-फिनलैण्ड द्विपक्षीय सम्बन्धों को 'डिजिटलीकरण व स्थिरता में रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership in Digitalisation and Sustainability) के स्तर तक ले जाने में सहमति दोनों पक्षों में रही. 16 मार्च, 2021 के भारत-फिनलैण्ड वर्चुअल शिखर सम्मेलन तथा 2018 व 2022 में क्रमशः स्टॉकहोम व कोपेनहेगन के भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलनों में तथा फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठकों से प्राप्त गति के आधार पर दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने व गहरा करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता पर बल दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता में दिया. संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार की आवश्यकता स्वीकारते हुए विस्तृत सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए फिनलैण्ड का समर्थन मेहमान राष्ट्रपति ने दोहराया. आतंकवाद व हिंसक अतिवाद के सभी रूपों की दोनों पक्षों ने स्पष्ट व जोरदार निंदा की. यूक्रेन में संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से स्थायी शांति के प्रयासों के लिए समर्थन जारी रखने को दोनों पक्षों में सहमति रही. भारत में अक्टूबर 2026 में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच (World Circular Economy Forum) की सह-मेजबानी के लिए भी सहमति दोनों पक्षों में रही.

विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के तीन समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात् किए गए. आधिकारिक सांख्यिकी (Official Statistics) व नवाचार क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों के प्रवासन व गतिशीलता के क्षेत्र के समझौते इनमें शामिल हैं. पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के नवम्बर 2020 में हस्ताक्षरित समझौते का नवीकरण भी इस अवसर पर किया गया.

नई दिल्ली में इन व्यस्त कार्यक्रमों के पश्चात् 6 मार्च को फिनलैण्ड के राष्ट्रपति मुम्बई रवाना हो गए जहाँ महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल व मुख्यमंत्री से मुलाकात के पश्चात् अग्रणी भारतीय उद्यमियों के साथ भेंट के उनके कार्यक्रम थे. दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत-फिनलैण्ड बिजनेस ईवेंट को भी उन्होंने मुम्बई में सम्बोधित किया. दोनों देशों के बीच एकेडमिक सहयोग के सिलसिले में मुम्बई विश्वविद्यालय के छात्रों को भी 6 मार्च को उन्होंने सम्बोधित किया. अगले दिन 7 मार्च को मुम्बई से ही उनकी स्वदेश वापसी हुई.

11वाँ रायसीना संवाद नई दिल्ली में सम्पन्न

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के तत्वावधान में 11वाँ रायसीना संवाद (Raisina Dia-logue) नई दिल्ली में 5-7 मार्च, 2026 को सम्पन्न हुआ. 110 देशों के लगभग 2700 प्रतिभागी जिनमें मंत्री पूर्व राष्ट्राध्यक्ष/शासन प्रमुख, उद्योगपति, शिक्षाविद् पत्रकार व रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ आदि शामिल थे विश्व के समक्ष विद्यमान राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर मंथन के लिए इसमें उपस्थित थे. **फिनलैण्ड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब इस वर्ष इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के साथ-साथ उद्घाटन सत्र में प्रमुख वक्ता (Keynote Speaker) भी थे.** इस वर्ष इस सम्मेलन का थीम—'संस्कार-अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति' (Samskara-Assertion, Accom-modation, Advancement) था. 5 मार्च को सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया.

5 मार्च को रायसीना संवाद के उदघाटन समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेते हुए फिनलैण्ड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने इस बात पर बल दिया कि पश्चिमी प्रभुत्व वाला युग अब समाप्त हो रहा है तथा भविष्य की दिशा अब ग्लोबल साउथ तय करेगा, क्योंकि उसके पास ही अब जनसांख्यिकीय एवं आर्थिक शक्ति है. उन्होंने कहा कि अगली विश्व व्यवस्था तय करने में भारत एक निर्णायक शक्ति होगा. उन्होंने सुझाव दिया कि जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् 'सेंट फ्रांसिस्को मोमेंट' आया था, वैसे ही विश्व को अब एक 'दिल्ली मोमेंट' की जरूरत है, जहाँ

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

भारत के नेतृत्व में विश्व के नेता मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार करें. वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता का उन्होंने भरपूर समर्थन किया.

रायसीना डायलॉग भू-राजनैतिक (Geopolitics) व भू-आर्थिक (Geo-economics) मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय व दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है. इसका पहला आयोजन 2016 में किया गया था. यह एक ऐसा बहुउद्देशीय सम्मेलन है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, उच्चाधिकारी, राजनेता, पत्रकार एवं उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर अपने विचार रखते हैं. जर्मनी के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (Munich Security Conference) तथा सिंगापुर के शांगरी ला संवाद (Shangri La Dialogue) के समकक्ष माने जाने वाला यह सम्मेलन वैश्विक नेतृत्व, नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों व उद्योग विशेषज्ञों आदि को वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने को मंच प्रदान करता है. इसका यह नाम (रायसीना संवाद) नई दिल्ली की 'रायसीना हिल्स' जहाँ भारत सरकार के मुख्यालय रहे हैं, के नाम पर रखा गया है.

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत का उदय अजेय है, और यह देश अपनी विकास यात्रा अपनी शक्ति के दम पर तय करेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी अन्य देश की मेहरबानी पर निर्भर नहीं है. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि आज विश्व एक 'अस्थिर और अनिश्चित युग' में प्रवेश कर चुका है और इस सन्दर्भ में वैश्विक व्यवस्था को लेकर विभिन्न प्रस्ताव भी साझा किए. इसी के साथ 'ग्लोबल साउथ' को एक भौगोलिक शब्द न मानकर एक 'भावना' उन्होंने बताया.

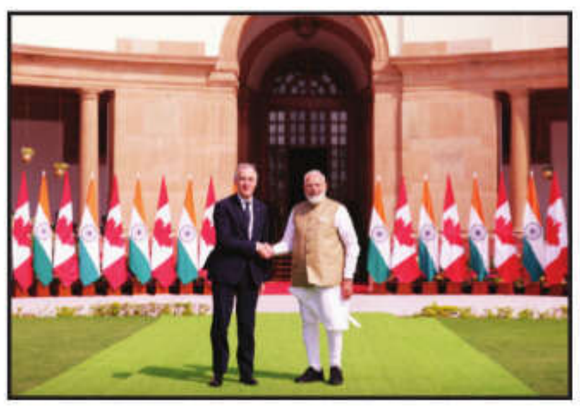
हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका, आत्मनिर्भरता तथा पड़ोसी देशों के साथ विकास आधारित साझेदारी पर उन्होंने बल दिया. श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस व सेशेल्स के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास पर भी चर्चा उन्होंने की. 'समुद्र का हृदय : हिन्द महासागर का भविष्य' सत्र में विदेश मंत्री ने भारत की अहम भूमिका, विश्वसनीय भागीदारी व स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देते हुए कहा कि भारत के विकास से क्षेत्र के सभी देशों को लाभ होगा. संयुक्त राष्ट्र के वीटो पॉवर पर तीखे सवाल करते हुए सुरक्षा परिषद् में सुधार के साथ-साथ भारत की स्थायी सदस्यता की माँग को उन्होंने दोहराया.

सम्मेलन के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका, भूटान, कीनिया, मॉरिशस, माल्टा व रवांडा जैसे कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात कर आर्थिक एवं डिजिटल सहयोग पर चर्चा की.

इन विदेश मंत्रियों व अन्य शिक्षाविदों व प्रतिभागियों ने 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में 6 मुख्य स्तम्भों पर आधारित विभिन्न प्रारूपों में विचार-विमर्श किए— (i) विवादित सीमाएँ : शक्ति, ध्रुवीकरण और परिधि, (ii) साझा संसाधनों का पुनर्निर्माण : नए समूह, नए संरक्षक, नए रास्ते, (iii) ह्वाइट ह्वेल : एजेंडा 2030 की खोज, (iv) अन्तिम समय : जलवायु, संघर्ष और विलम्ब की कीमत, (v) भविष्य की दुनिया : एक तकनीक-प्रधान समाज की ओर, (vi) टैरिफ के दौर में व्यापार : पुनर्प्राप्ति, लचीलापन और पुनर्निर्माण इनमें शामिल थे. इन सभी 6 स्तम्भों के इर्द-गिर्द चर्चाएँ सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में आयोजित हुईं.

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी (Mark Carney) ने अपने देश के उच्च-स्तरीय शिष्टमण्डल के साथ 4 दिन की भारत की आधिकारिक यात्रा 27 फरवरी-2 मार्च, 2026 को की. प्रधानमंत्री के रूप में मार्च 2025 में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् श्री मोदी के साथ इनकी दो मुलाकातें—जून 2025 में कनानास्किस (कनाडा) में जी-7 शिखर सम्मेलन में तथा नवम्बर 2025 में जोहान्सबर्ग (द. अफ्रीका) में जी-20 शिखर सम्मेलन में हो चुकी थी, भारत की उनकी यह पहली ही आधिकारिक यात्रा थी, उनकी यह यात्रा ऐसे समय में सम्पन्न की गई जब पिछले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudearu) के कार्यकाल के दौरान 2023 में दोनों देशों के राजनयिक सम्बन्धों में खटास आई थी.



नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का स्वागत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

इस प्रकार विदेश मंत्रालय ने उनकी भारत की इस यात्रा को द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुधारने की दिशा में एक प्रयास भी करार दिया है. विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत की यह आधिकारिक यात्रा को एक ऐतिहासिक 'परिवर्तन का बिन्दु' बताया जो 2023 में शुरू हुए राजनयिक गतिरोध को प्रभावी रूप से समाप्त करती है.

कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने 4 दिन की भारत की इस यात्रा की शुरुआत मुम्बई से की. 27 फरवरी को मुम्बई पहुँचने पर हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जयकुमार रावल ने की. मुम्बई में ही रिलायंस इण्डस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन मुकेश अंबानी व उनकी पत्नी नीता अंबानी ने 1 मार्च को अपने घर पर उनकी मेजबानी की. मुम्बई में अपने पहले 2 दिन विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग उन्होंने लिया तथा भारतीय उद्यमियों, वित्तीय विशेषज्ञों, नव प्रवर्त्तकों व शिक्षाविदों के साथ मुलाकातें उन्होंने की. बाद में 1 मार्च की सायं नई दिल्ली पहुँचने के पश्चात् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों पर उनकी वार्ता 2 मार्च को हैदराबाद हाउस में हुई. दोनों नेताओं ने कनानास्किस में जून 2025 में तथा जोहान्सबर्ग में नवम्बर 2025 में हुई अपनी मुलाकातों में भारत-कनाडा सम्बन्धों के लिए निर्धारित रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का स्वागत वार्ता में किया तथा सरकार-से-सरकार (Government-to-Government) तथा व्यवसाय-से-व्यवसाय (Business-to-Business) के बीच सम्बन्धों को बढ़ावा देने के इरादे को दोहराते हुए स्वच्छ ऊर्जा, पारम्परिक ऊर्जा, नागरिक परमाणु ऊर्जा व महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके. भारत की पहल वाले अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबन्धन (ISA) व बायोफ्यूल एलायंस में शामिल होने के इरादे की घोषणा कनाडा की ओर से इस अवसर पर की गई. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) में डायलॉग पार्टनर बनने की घोषणा भी कनाडा की ओर से की गई जिसका स्वागत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे हमारे समुद्री सहयोग को नई गहराई मिलेगी.

पूर्ववर्ती कनाडाई सरकार के कार्यकाल में आई खटास को दूर कर द्विपक्षीय सम्बन्धों में पुनः मजबूती लाने के प्रयास द्विपक्षीय वार्ता में किए गए. वस्तुतः द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा, रक्षा व समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक सहमतियाँ दोनों प्रधानमंत्रियों की वार्ता में बनी. द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य वार्ता में

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

तय किया गया तथा इसके लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement–CEPA) को 2026 के अन्त तक अन्तिम रूप देने का निश्चय वार्ता में किया गया. (दोनों देशों के बीच यह बातचीत पहले ही चल रही थी जिसे 2023 में तत्कालीन कनाडा सरकार ने रोक दिया था). दोनों देशों के बीच हुए एक अन्य समझौते के तहत् कनाडा की कैमेको कम्पनी भारत को परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए 2035 तक 2·20 करोड़ पाउण्ड यूरेनियम की आपूर्ति करेगी. महत्वपूर्ण खनिजों, शैक्षणिक आदान-प्रदान नवीकरणनीय ऊर्जा, व सांस्कृतिक सहयोग के समझौतों सहित 8 विभिन्न समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर इस अवसर पर किए गए. रक्षा क्षेत्र में सहयोग संवर्द्धन के लिए इंडो-कनाडा डिफेंस डायलॉग तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को आगे बढ़ाने के लिए इण्डिया-कनाडा पार्लियामेन्ट फ्रैंडशिप ग्रुप की स्थापना की घोषणा भी वार्ता में की गई. साथ ही व्यापारिक सम्बन्धों के लिए इण्डिया-कनाडा सीईओ फोरम का पुनर्गठन भी किया गया.

बाद में स्वदेश वापसी से पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी ने भारत-कनाडा सीईओ फोरम को सम्बोधित किया. भारत मण्डपम में आयोजित इस फोरम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्नी को कार्यभार सँभाले अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ है, जबकि हमारे सम्बन्धों ने एक 'लाइट ईयर' की छलांग लगाई है. भारत में निवेश के अवसरों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कनाडा के पेंशन फण्ड्स ने भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश किया है. भारत की इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी का भाग बनने के लिए कनाडाई निवेशकों को उन्होंने आमंत्रित किया. भारत-कनाडा सीईओ फोरम की बैठक में भाग लेने के पश्चात् मार्क कार्नी अगले चरण की यात्रा के लिए 2 मार्च की ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए.

हथियारों की खरीद में भारत का विश्व में यूक्रेन के पश्चात् दूसरा स्थान बरकरार, अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता : स्वीडिश संस्था SIPRI की रिपोर्ट

विश्व में हथियारों के बड़े क्रेताओं एवं विक्रेताओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट स्वीडन स्थित थिंक टैंक **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट** (SIPRI) द्वारा प्रति वर्ष जारी की जाती है. संस्था की ऐसी वर्ष 2026 की रिपोर्ट मार्च 2026 में जारी हुई है. **रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2021-25 के दौरान 5 वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों के 5 बड़े आयातक देश क्रमशः यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, कतर, व पाकिस्तान रहे हैं, संस्था की इस रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों की इस अवधि में हथियारों के 5 बड़े निर्यातक देश क्रमशः अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी व चीन रहे हैं.** इसमें बताया गया है कि 2016-20 की तुलना में 2021-25 की 5 वर्षों की अवधि में यूक्रेन के हथियारों के आयात में 11 हजार प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है जिससे यूक्रेन ही इस अवधि में विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना रहा है और भारत जो 2015-19 में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था तथा 2020-24 में दूसरे स्थान पर आ गया था, 2021-25 के दौरान आयातों में कमी के बावजूद हथियारों का दूसरा बड़ा आयातक बरकरार रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, 2016-20 की तुलना में 2021-25 में भारत के शस्त्र आयातों में जहाँ 4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, वहीं पड़ोसी देशों में चीन के शस्त्र आयातों में इस अवधि में 72 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि पाकिस्तान के हथियारों के आयात में 66 प्रतिशत की वृद्धि इस अवधि में दर्ज की गई है.

संस्था की पिछली सालाना रिपोर्टों की तर्ज पर वर्ष 2026 की रिपोर्ट में भी विश्व में हथियारों के सभी प्रमुख निर्यातक राष्ट्रों (व उनसे हथियार खरीदने वाले प्रमुख देशों) तथा हथियारों के सभी प्रमुख आयातक राष्ट्रों (व उन्हें हथियारों की आपूर्ति करने वाले प्रमुख राष्ट्रों) के नामों का उल्लेख किया गया है. इनमें अग्रणी देशों के नाम व सम्बन्धित जानकारी दिए गए बॉक्स में दी गई है.

संस्था (SIPRI) की वर्ष 2026 की सन्दर्भित रिपोर्ट के अनुसार

आयात परिदृश्य

- 2021-25 के दौरान विश्व में हथियारों के सबसे बड़े दो आयातक देश क्रमशः यूक्रेन व भारत रहे. सन्दर्भित अवधि में हथियारों के कुल वैश्विक आयात का 9·7 प्रतिशत आयात यूक्रेन ने तथा 8·2 प्रतिशत भारत ने किया. इस मामले में तीसरा, चौथा व पाँचवाँ स्थान क्रमशः सऊदी अरब, कतर व पाकिस्तान का रहा.
- 2021-25 के दौरान भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले पहले 3 देश क्रमशः रूस, फ्रांस व इजरायल रहे. सन्दर्भित अवधि में भारत के हथियारों की कुल खरीद में 40 प्रतिशत आपूर्ति रूस द्वारा, 29 प्रतिशत की फ्रांस द्वारा तथा 15 प्रतिशत भाग की आपूर्ति इजरायल द्वारा की गई.
- रिपोर्ट के अनुसार, 2021-25 के दौरान चीन द्वारा हथियारों की खरीद में भारी गिरावट आई है. 2016-20 के दौरान हथियारों के वैश्विक आयात के 5·2 प्रतिशत भाग का आयात चीन द्वारा किया गया था, जो 2021-25 में 1·3 प्रतिशत ही रहा. इससे चीन, जो 2020-24 में विश्व में हथियारों का 16वाँ बड़ा आयातक राष्ट्र था. 2021-25 में 21वें स्थान पर रहा. 2021-25 की अवधि में उसे हथियारों की आपूर्ति करने वाले तीन प्रमुख देश क्रमशः रूस (66 प्रतिशत), यूक्रेन (15 प्रतिशत) व फ्रांस (13 प्रतिशत) रहे.
- पाकिस्तान का उपर्युक्त अवधि (2021-25) में हथियारों की खरीद में विश्व में पाँचवाँ स्थान रहा. इस अवधि में हथियारों के कुल वैश्विक आयात के 4·2 प्रतिशत भाग का आयात पाकिस्तान ने किया तथा उसे हथियारों की आपूर्ति करने वाले पहले 3 देश क्रमशः चीन (80 प्रतिशत), तुर्किए (7·0 प्रतिशत) व नीदरलैण्ड्स (4·6 प्रतिशत) रहे.
- अमेरिका, जो 2021-25 की अवधि में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र रहा, उसने इस अवधि में हथियारों का आयात भी किया. हथियारों के कुल वैश्विक आयात का 2·9 प्रतिशत उसने आयात किया तथा इस मामले में विश्व में 8वाँ स्थान अमेरिका का रहा. रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के हथियारों के कुल आयात में 17 प्रतिशत भाग की आपूर्ति ब्रिटेन ने की, जबकि फ्रांस (14 प्रतिशत) व इटली (13 प्रतिशत) का इस मामले में क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान रहा.
- जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-25 में यूरोप के देशों ने हथियारों के कुल आयात का 33 प्रतिशत प्राप्त किया, जिसके बाद एशिया और ओशिनिया (31 प्रतिशत), मध्य पूर्व (26 प्रतिशत), अमेरिका (5·6 प्रतिशत) और अफ्रीका (4·3 प्रतिशत) के देश रहे हैं.

निर्यात परिदृश्य

- 2021-25 के 5 वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों के कुल निर्यात में सर्वाधिक 42 प्रतिशत योगदान अमेरिका का रहा. जबकि 9·8 व 6·8 प्रतिशत योगदान के साथ फ्रांस व रूस इस मामले में क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे.
- रिपोर्ट के अनुसार, 2021-25 के दौरान अमेरिका ने अपने हथियार निर्यात का सर्वाधिक 12 प्रतिशत भाग सऊदी अरब को, दूसरे स्थान पर 9·4 प्रतिशत निर्यात यूक्रेन को तथा तीसरे स्थान पर 8·9 प्रतिशत निर्यात जापान को किया.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

2021-25 के दौरान हथियारों के बड़े आयातक राष्ट्र व उन्हें हथियारों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश

क्रमांक	आयातक राष्ट्र	हथियारों के कुल वैश्विक आयात में अंश (प्रतिशत में)		2016-20 की तुलना में 2021-25 में प्रतिशत परिवर्तन	तीन प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश (2021-25) (आयातक राष्ट्र के हथियारों के कुल आयात में आपूर्तिकर्ता देश का अंश) (प्रतिशत में)		
		2021-25	2016-20		I	II	III
1.	यूक्रेन	9·7	0·1	11896	अमेरिका (41)	जर्मनी (14)	पोलैण्ड (9·4)
2.	भारत	8·2	9·3	–4·0	रूस (40)	फ्रांस (29)	इजरायल (15)
3.	सऊदी अरब	6·8	11·0	–31	अमेरिका (77)	स्पेन (9·5)	फ्रांस (4·6)
4.	कतर	6·4	3·4	106	अमेरिका (48)	इटली (21)	यूके (17)
5.	पाकिस्तान	4·2	2·8	66	चीन (80)	तुर्किए (7·0)	नीदरलैण्ड्स (4·6)
6.	जापान	3·9	2·5	76	अमेरिका (95)	यूके (3·4)	नॉर्वे (0·9)
7.	पोलैण्ड	3·6	0·4	852	द. कोरिया (47)	अमेरिका (44)	इटली (2·2)
8.	अमेरिका	2·9	2·1	48	यूके (17)	फ्रांस (14)	इटली (13)
9.	कुवैत	2·8	0·3	805	अमेरिका (62)	इटली (31)	फ्रांस (5·7)
10.	ऑस्ट्रेलिया	2·8	5·0	–39	अमेरिका (85)	स्पेन (6·5)	जर्मनी (4·0)
11.	संयुक्त अरब अमीरात	2·7	3·5	–15	अमेरिका (42)	फ्रांस (18)	द. कोरिया (10)

2021-25 के दौरान हथियारों के बड़े निर्यातक राष्ट्र व उनसे हथियारों के प्रमुख क्रेता

क्रमांक	निर्यातक राष्ट्र	ह थियारों के कुल वैश्विक निर्यात में अंश (प्रतिशत में)		2016-20 की तुलना में 2021-25 में प्रतिशत परिवर्तन	निर्यातक राष्ट्र के हथियारों के तीन प्रमुख क्रेता (निर्यातक के कुल निर्यात में आयातक राष्ट्र का अंश 2021-25 में) (प्रतिशत में)		
		2021-25	2016-20		I	II	III
1.	अमेरिका	42	36	27	सऊदी अरब (12)	यूक्रेन (9·4)	जापान (8·9)
2.	फ्रांस	9·8	8·8	21	भारत (24)	मिस्र (11)	ग्रीस (10)
3.	रूस	6·8	21	–64	भारत (48)	चीन (13)	बेलारूस (13)
4.	जर्मनी	5·7	5·4	15	यूक्रेन (24)	मिस्र (14)	इजरायल (10)
5.	चीन	5·6	5·5	11	पाकिस्तान (61)	सर्बिया (6·8)	थाइलैण्ड (4·7)
6.	इटली	5·1	2·2	157	कतर (26)	कुवैत (17)	इण्डोनेशिया (12)
7.	इजरायल	4·4	3·1	56	भारत (29)	जर्मनी (21)	अमेरिका (7·8)
8.	यूके	3·4	3·3	13	कतर (31)	अमेरिका (14)	यूक्रेन (13)
9.	द. कोरिया	3·0	2·6	24	पोलैण्ड (58)	फिलीपींस (18)	यूएई (9·5)
10.	स्पेन	2·3	2·4	–6·7	सऊदी अरब (28)	तुर्किए (16)	बेल्जियम (12)
11.	तुर्किए	1·8	0·9	122	पाकिस्तान (16)	यूएई (12)	यूक्रेन (8·4)

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

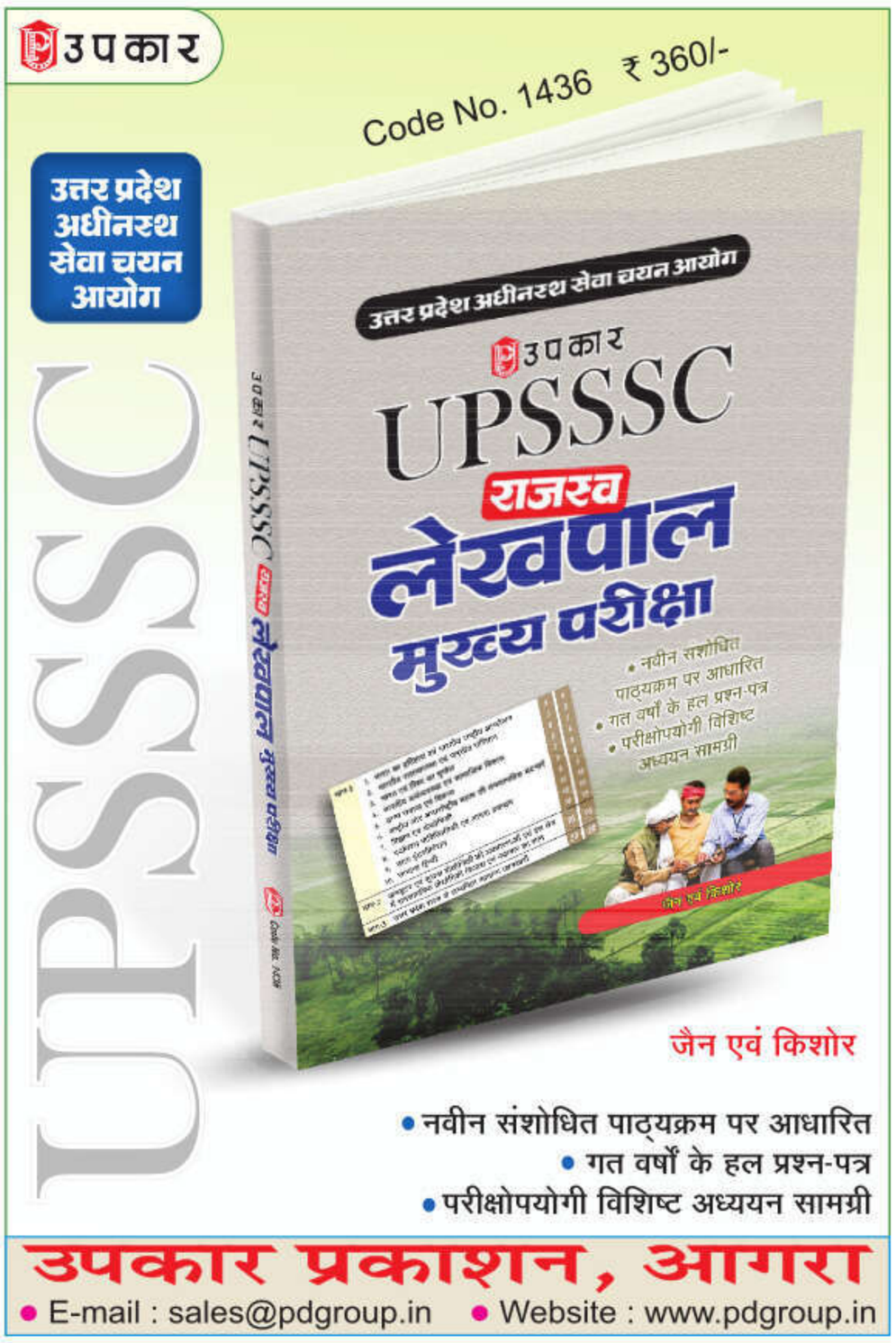
- 2021-25 के दौरान हथियारों का दूसरा बड़ा निर्यातक देश फ्रांस रहा. सन्दर्भित अवधि में फ्रांसीसी हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता भारत रहा. फ्रांस ने अपने हथियारों के निर्यात के 24 प्रतिशत भाग की आपूर्ति भारत को की, जबकि 11 प्रतिशत व 10 प्रतिशत भाग के क्रेता क्रमशः मिस्र व ग्रीस रहे.
- सन्दर्भित अवधि (2021-25) में रूस ने अपने हथियारों के कुल निर्यात के सर्वाधिक 48 प्रतिशत भाग का निर्यात भारत को किया, जबकि चीन को 13 प्रतिशत व बेलारूस को भी 13 प्रतिशत भाग का उसने निर्यात किया.
- 2021-25 के दौरान चीनी हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता पाकिस्तान रहा. चीन ने अपने हथियारों के कुल निर्यात के 61 प्रतिशत भाग का निर्यात पाकिस्तान को किया, जबकि सर्बिया को 6·8 प्रतिशत व थाइलैण्ड को 4·7 प्रतिशत भाग का निर्यात उसने किया. इस प्रकार चीनी हथियारों के 3 बड़े क्रेता क्रमशः पाकिस्तान सर्बिया व थाइलैण्ड रहे.
- रिपोर्ट के अनुसार, हथियारों के वैश्विक बाजार में अमेरिका का ही प्रभुत्व अब बना हुआ है. इसमें बताया गया है कि 2016-20 की तुलना में 2021-25 में अमेरिकी निर्यात में 27 प्रतिशत की वृद्धि जहाँ हुई, वहीं रूस के निर्यात में 64 प्रतिशत की गिरावट इस अवधि में दर्ज की गई. इससे पूर्व 2015-19 की तुलना में 2021-25 में भी अमेरिकी शस्त्र निर्यातों में 24 प्रतिशत की वृद्धि जहाँ हुई थी, रूस के शस्त्र निर्यातों में 64 प्रतिशत की गिरावट ही दर्ज की गई थी. उससे पूर्व 2014-18 की तुलना में 2019-23 में अमेरिकी शस्त्र निर्यातों में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि रूस के निर्यात 53 प्रतिशत घटे थे. इसी तरह 2013-17 की तुलना में 2018-22 में 14 प्रतिशत की वृद्धि अमेरिकी शस्त्र निर्यातों में हुई थी, जबकि रूसी निर्यात 31 प्रतिशत घटे थे.

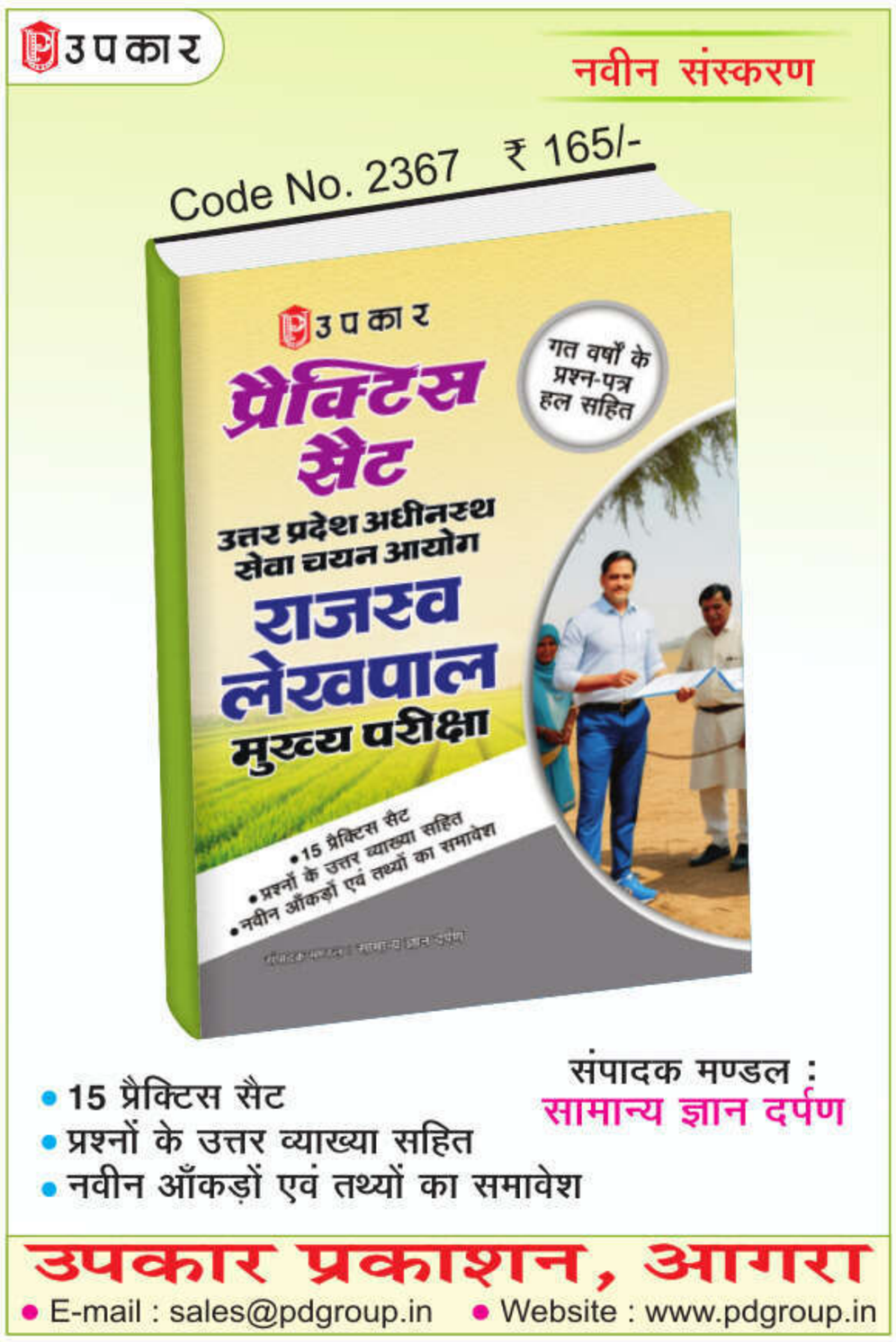
इटली में न्यायिक सुधारों के लिए कराए गए जनमत संग्रह में जॉर्जिया मेलोनी सरकार की पराजय

इटली में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) के नेतृत्व को एक करारा झटका गत मार्च माह में उस समय लगा जब उनके द्वारा कराए गए जनमत संग्रह को जनता ने उनके प्रस्तावित न्यायिक सुधारों को ठुकरा दिया. मेलोनी सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यापक न्यायिक सुधारों के लिए जनमत संग्रह वहाँ 22 व 23 मार्च, 2026 को कराया गया था. सरकार के इस प्रस्ताव के पक्ष में 46 प्रतिशत मत ही पड़े, जबकि 54 प्रतिशत मतदाताओं ने 'No' के लिए मत दिया. 2 दिन तक चले इस मतदान में 59 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

जनमत संग्रह में इस पराजय से मेलोनी सरकार को घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक झटका लगा है तथा इससे आने वाले राष्ट्रीय चुनाव में उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है. वर्ष 2022 में सत्ता में आने के पश्चात् मेलोनी को यह पहला बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. जनमत संग्रह में अपनी पराजय को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है कि जनता के फैसले का वह सम्मान करती हैं, किन्तु त्यागपत्र देने से स्पष्ट इंकार उन्होंने किया है. इटली में अगले आम चुनाव अगले वर्ष (2027 में) ही होने हैं. जनमत संग्रह में जॉर्जिया मेलोनी सरकार की पराजय आगामी चुनावों में उनकी स्थिति को कमजोर कर सकती है.

●●●





PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य

- **2025-26 में देश में खाद्यान्न व अन्य प्रमुख कृषिगत उत्पादन : दूसरे अग्रिम अनुमान**
- **2025-26 के लिए भी कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर 8·25 प्रतिशत ही बरकरार**
- **2025-26 की पहली तीन तिमाहियों में चालू खाते के घाटे में कमी : आरबीआई रिपोर्ट**
- **दिसम्बर 2025 के अन्त में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या व टेलीडेंसिटी आदि के सम्बन्ध में 'ट्राई' की रिपोर्ट**
- **वर्ल्ड हैप्पिनेस इण्डेक्स (2025) में भारत का 147 देशों में 116वाँ स्थान**
- **राज्यों की राजकोषीय स्थिति के आकलन हेतु नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (2026)**
- **आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत् पंजीकृत अस्पतालों का विस्तार**
- **पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी**
- **नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान**

2025-26 में देश में खाद्यान्न व अन्य प्रमुख कृषिगत उत्पादन : दूसरे अग्रिम अनुमान

फसल वर्ष 2025-26 में देश में प्रमुख कृषि उपजों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 मार्च, 2026 को जारी किए गए. **जारी अनुमानों में केवल खरीफ एवं रबी उत्पादन के अनुमान ही शामिल हैं.** विभिन्न जायद फसलों को मई/जून 2026 में जारी किए जाने वाले आगामी तीसरे अग्रिम अनुमानों में शामिल किया जाएगा, (दूसरे अग्रिम अनुमान में केवल खरीफ एवं रबी मौसम का उत्पादन शामिल होता है).

दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत् देश में 2025-26 में—

- खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1741·44 लाख मीट्रिक टन और रबी खाद्यान्न उत्पादन 1745·13 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है (**इस प्रकार जायद के अतिरिक्त कुल खाद्यान्न उत्पादन 348·66 मिलियन टन अनुमानित है**).
- खरीफ चावल का उत्पादन 1239·28 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर होने का अनुमान है, जो पूर्व वर्ष 2024-25 के 1227·72 लाख मीट्रिक टन की तुलना में, 11·56 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्शाता है. रबी चावल का उत्पादन 167·20 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है. गेहूँ का उत्पादन रिकॉर्ड 1202·10 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 1179·45 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 22·65 लाख मीट्रिक टन अधिक है.
- श्रीअन्न (खरीफ) का उत्पादन 123·43 लाख मीट्रिक टन और श्रीअन्न (रबी) का उत्पादन 30·98 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है. इसके अलावा, पोषक/मोटे अनाज (खरीफ) का उत्पादन/425·89 लाख मीट्रिक टन और पोषक/मोटे अनाज (रबी) का उत्पादन 213·41 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है.
- तूर एवं चने का उत्पादन क्रमशः 34·55 लाख मीट्रिक टन एवं 117·92 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है एवं मसूर का उत्पादन 17·33 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है.
- खरीफ एवं रबी मूँगफली का उत्पादन क्रमशः 112·94 लाख मीट्रिक टन एवं 7·97 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है. खरीफ मूँगफली का उत्पादन पिछले वर्ष के 104·12 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 8·82 लाख मीट्रिक टन अधिक है. सोयाबीन का उत्पादन 127·20 लाख मीट्रिक टन एवं रेपसीड और सरसों का उत्पादन 133·31 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है. कपास का उत्पादन 290·91 लाख गाँठें (प्रत्येक गाँठ 170 किग्रा और गन्ने का उत्पादन 5001·97 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है.

कृषिगत उत्पादन के आँकड़े : एक दृष्टि में [10 मार्च, 2026 के दूसरे अग्रिम अनुमान (लाख टन)]

जायद उत्पादन के आँकड़े इनमें शामिल नहीं हैं, वह आँकड़े उपलब्ध होने के पश्चात् 2025-26 में कृषिगत उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान मई/जून 2026 में जारी किए जाएंगे.

- खरीफ खाद्यान्न—1741·44 लाख टन
- रबी खाद्यान्न—1745·13 लाख टन
- खरीफ चावल—1239·28 लाख टन (रिकॉर्ड)
- रबी चावल—167·20 लाख टन
- गेहूँ—1202·10 लाख टन (रिकॉर्ड)
- खरीफ मक्का—302·47 लाख टन (रिकॉर्ड)
- रबी मक्का—159·03 लाख टन
- खरीफ श्रीअन्न—123·43 लाख टन
- रबी श्रीअन्न—30·98 लाख टन
- खरीफ पौष्टिक/मोटे अनाज—425·89 लाख टन
- रबी पौष्टिक/मोटे अनाज—213·41 लाख टन
- तूर—34·55 लाख टन
- चना—117·92 लाख टन
- मसूर—17·33 लाख टन
- सोयाबीन—127·20 लाख टन
- रेपसीड एवं सरसों—133·31 लाख टन
- खरीफ मूँगफली—112·94 लाख टन (रिकॉर्ड)
- रबी मूँगफली—7·97 लाख टन

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

- कुल खरीफ तिलहन—265·33 लाख टन
- रबी तिलहन—144·65 लाख टन
- गन्ना—5001·97 लाख टन
- कपास—290·91 लाख गाँठें (170 किग्रा की प्रत्येक गाँठ)
- जूट—81·27 लाख गाँठें (180 किग्रा की प्रत्येक गाँठ)

2025-26 के लिए भी कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर 8·25 प्रतिशत ही बरकरार

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमाओं पर ब्याज दर पूर्व स्तर 8·25 प्रतिशत ही बरकरार रखने की संस्तुति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation—EPFO) के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने की है. तद्नुरूप इन जमाओं पर कर्मचारियों को पिछले 2 वर्षों की तरह 2025-26 के लिए भी 8·25 प्रतिशत ब्याज ही प्राप्त होगा. रेपो दर में आमतौर पर कटौती के बीच बाजार में ब्याज दरों में गिरावट के बावजूद ईपीएफ जमाओं पर ब्याज दर में कोई कटौती न किए जाने से ईपीएफओ के लगभग 7·5 करोड़ सब्सक्राइबर्स लाभान्वित होंगे. इससे पूर्व 2021-22 में ईपीएफ जमाओं पर देय ब्याज जहाँ 8·10 प्रतिशत थी. 2022-23 में भी 8·15 प्रतिशत रहने के पश्चात् लगातार 3 वर्षों से यह 8·25 प्रतिशत बनी हुई है.

हाल ही के वर्षों में ईपीएफ जमाओं पर ब्याज दरें

वर्ष	ब्याज दर (प्रतिशत)
2015-16	8·80
2016-17	8·65
2017-18	8·55
2018-19	8·65
2019-20	8·50
2020-21	8·50
2021-22	8·10
2022-23	8·15
2023-24	8·25
2024-25	8·25
2025-26	8·25

2025-26 के लिए ब्याज दर को 2023-24 व 2024-25 के स्तर पर ही बनाए रखने के प्रस्ताव को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 2 मार्च, 2026 को सम्पन्न बैठक में मंजूरी प्रदान की गई. **वित्त मंत्रालय की मंजूरी के पश्चात् बढ़ी हुई ब्याज दर को अधिसूचित किया जाएगा.**

कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund–EPF) एक अनिवार्य रिटायरमेन्ट फण्ड है जिसमें कर्मचारी व नियोक्ता हर महीने अनिवार्यतः योगदान करते हैं. इस फण्ड का प्रबन्धन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है. यह प्रावधान 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों के मामले में लागू होता है. कुछ मामलों में 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर भी यह लागू किया जा सकता है.

कर्मचारी भविष्य निधि पर देय ब्याज का निर्धारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बोर्ड ऑफ ट्रस्ट द्वारा वित्त मंत्रालय की मंजूरी से किया जाता है. ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती है, किन्तु कर्मचारी के ईपीएफ खाते में यह वार्षिक रूप से जमा की जाती है. कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जमा सम्पूर्ण राशि, जिसमें उसके स्वयं के योगदान के अतिरिक्त नियोक्ता का भी योगदान तथा प्रति वर्ष जमा होने वाली ब्याज भी शामिल होती है, कर्मचारी के रिटायरमेन्ट पर उसको प्राप्त होती है.

इस प्रकार यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो नौकरी के दौरान थोड़ी-थोड़ी बचाई गई राशि रिटायरमेन्ट के समय एक बड़े फण्ड के रूप में प्राप्त हो जाती है.

2025-26 की पहली तीन तिमाहियों में चालू खाते के घाटे में कमी : आरबीआई रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आँकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तीन तिमाहियों (अप्रैल-दिसम्बर 2025) में भारत के चालू खाते के घाटे (Current Account Deficit–CAD) में काफी कमी दर्ज की गई है तथा सन्दर्भित अवधि में यह घाटा 30·1 अरब डॉलर रहा है, जो पूर्व वर्ष की समान अवधि (अप्रैल-दिसम्बर 2024) में 36·6 अरब डॉलर था. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रैल-दिसम्बर 2024 में यह 1·3 प्रतिशत था, जो अप्रैल-दिसम्बर 2025 में 1·0 प्रतिशत रहा है.

रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2026 में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर 2024 में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Net FDI) 0·6 अरब डॉलर था, जो बढ़कर 2025-26 की समान अवधि में 3·0 अरब डॉलर हो गया था. इसके विपरीत अप्रैल-दिसम्बर 2024 में निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Net Foreign Portfolio Investment) का अन्तर्प्रवाह 9·4 अरब डॉलर था, जो 2025-26 की समान अवधि में 4·3 अरब डॉलर के निवल बाह्य प्रवाह में बदल गया था.

उल्लेखनीय है कि चालू खाते के घाटे का कम होना व्यापार एवं सेवाओं के निर्यात से बेहतर प्राप्तियों को दर्शाता है, तथा इससे विदेशी ऋणों पर देश की निर्भरता कम होती है.

दिसम्बर 2025 के अन्त में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या व टेलीडेंसिटी आदि के सम्बन्ध में 'ट्राई' की रिपोर्ट

दिसम्बर 2025 के अन्त में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या उसके ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण ब्रॉडबैण्ड उपभोक्ताओं की संख्या तथा इसके सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी तथा विभिन्न दूरसंचार मण्डलों में टेलीडेंसिटी (प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या) आदि के सम्बन्ध में विस्तृत आँकड़े दूरसंचार नियामक निकाय, ट्राई (TRAI–Telecom Regulatory Authority of India) द्वारा फरवरी 2026 में जारी किए गए. ट्राई के इन आँकड़ों के अनुसार—

दिसम्बर 2025 के अन्त में टेलीफोन के शहरी उपभोक्ताओं की संख्या 762·44 मिलियन थी. (इनमें 720·15 मिलियन उपभोक्ता वायरलैस टेलीफोन के व 42·29 मिलियन वायरलाइन टेलीफोन के थे). एक वर्ष पूर्व दिसम्बर 2024 की तुलना में यह 14·9 प्रतिशत अधिक थी (दिसम्बर 2024 के अन्त में टेलीफोन के शहरी उपभोक्ताओं की संख्या 663·37 मिलियन थी). दिसम्बर 2025 के अन्त में टेलीफोन के ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या 543·70 मिलियन थी, जो दिसम्बर 2024 में 526·56 मिलियन थी. इस प्रकार दिसम्बर 2025 के अन्त में ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या दिसम्बर 2024 की तुलना में 3·26 प्रतिशत अधिक थी. दिसम्बर 2025 के अन्त में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 1306·14 मिलियन थी. (इनमें 1258·77

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

टेलीफोन परिदृश्य एक दृष्टि में
(31 दिसम्बर, 2025 की स्थिति)

	वायरलैस	वायरलाइन	योग
टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या (करोड़ में)	**1258·77**	**47·37**	**1306·14**
शहरी उपभोक्ता (करोड़ में)	720·15	42·29	762·44
ग्रामीण उपभोक्ता (करोड़ में)	538·62	5·08	543·70
टेलीडेंसिटी (प्रतिशत में) (प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन)	**88·41**	**3·33**	**91·74**
शहरी क्षेत्रों में (प्रतिशत)	140·66	8·26	148·92
ग्रामीण क्षेत्रों में (प्रतिशत)	59·07	0·56	59·63
कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में			
शहरी उपभोक्ताओं का प्रतिशत	57·21	89·27	58·37
ग्रामीण उपभोक्ताओं का प्रतिशत	42·79	10·73	41·63
ब्रॉडबैण्ड उपभोक्ताओं की संख्या (करोड़)	962·07	45·29	1007·36

मिलियन उपभोक्ता वायरलैस टेलीफोन के तथा 47·37 मिलियन वायरलाइन टेलीफोन उपभोक्ता थे). दिसम्बर 2025 के अन्त में टेलीफोन उपभोक्ताओं की यह संख्या पूर्व वर्ष की तुलना में 9·77 प्रतिशत अधिक थी. (दिसम्बर 2024 के अन्त में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 1189·92 मिलियन थी.)

दिसम्बर 2025 के अन्त में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं में शहरी उपभोक्ता 58·37 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता 41·63 प्रतिशत थे.

टेलीडेंसिटी

टेलीफोन कनेक्शनों के उपर्युक्त आँकड़ों के चलते देश में टेलीडेंसिटी प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या दिसम्बर 2025 के अन्त में 91·74 प्रतिशत (दिसम्बर 2024 के अन्त में 84·45 प्रतिशत) थी, जो शहरी क्षेत्रों में 148·92 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्रों में 59·63 प्रतिशत थी. दिसम्बर 2023 के अन्त में देश में टेलीडेंसिटी 85·23 प्रतिशत थी.

दिसम्बर 2025 के अन्त में देश के कुल 22 लाइसेंस्ड सर्विस एरियाज (LSAs) में सबसे कम टेलीडेंसिटी 61·88 प्रतिशत बिहार में, 69·74 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में व 72·33 प्रतिशत मध्य प्रदेश में थी. दिसम्बर 2025 के अन्त में सर्वाधिक टेलीडेंसिटी 359·50 प्रतिशत दिल्ली में, दूसरे स्थान पर 127·85 प्रतिशत कर्नाटक में तथा तीसरे स्थान पर 125·36 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में थी.

विभिन्न क्षेत्रों में टेलीडेंसिटी
(दिसम्बर 2025 की स्थिति)

राज्य/मण्डल	टेलीडेंसिटी
बिहार	61·88
उत्तर प्रदेश	69·74
मध्य प्रदेश	72·33
असम	78·92
ओडिशा	81·52
प. बंगाल	82·32
राजस्थान	82·33
पूर्वोत्तर	83·25
हरियाणा	89·42
जम्मू-कश्मीर	96·89
गुजरात	97·23
आन्ध्र प्रदेश	99·93
तमिलनाडु	106·44
महाराष्ट्र	114·14
पंजाब	116·27
केरल	122·18
हिमाचल प्रदेश	125·36
कर्नाटक	127·85
दिल्ली	359·50
सम्पूर्ण भारत	**91·74**

नोट—उपर्युक्त आँकड़ों में कोलकाता के आँकड़े पश्चिम बंगाल में, मुम्बई के महाराष्ट्र में तथा उत्तर प्रदेश ईस्ट तथा उत्तर प्रदेश वेस्ट के आँकड़े उत्तर प्रदेश में शामिल हैं.

वर्ल्ड हैप्पिनेस इण्डेक्स (2025) में भारत का 147 देशों में 116वाँ स्थान

किसी भी देश में खुशहाली (Happiness) केवल जीडीपी में वृद्धि या आय में वृद्धि से ही नहीं आती. जीडीपी के साथ-साथ अन्य अनेक मानक यथा-खुशी का अहसास, जीवन प्रत्याशा, उदारता व भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति आदि भी खुशहाली के लिए आवश्यक हैं. ऐसे ही कुछ मानकों के आधार पर विभिन्न देशों से खुशहाली (Happiness) की स्थिति के आकलन के लिए **हैप्पिनेस इण्डेक्स की गणना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के Wellbeing Research Centre द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क** (यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क) के सहयोग से जारी की जाती है, जिन्हें वर्ल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट शीर्षक से प्रति वर्ष जारी किया जाता है.

इस वर्ष की ऐसी रिपोर्ट 20 मार्च, 2026 को वर्ल्ड हैप्पिनेस डे के अवसर पर विश्व भर में जारी हुई, जो इस तर्ज की चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट थी. **147 देशों के लिए हैप्पिनेस सूचकांक की गणना इस रिपोर्ट में की गई है, जिनमें भारत का 116वाँ स्थान है.** इससे पूर्व वर्ष 2025 की पिछली रिपोर्ट में भारत का 147 देशों में 118वाँ तथा 2024 की रिपोर्ट में भारत का 143 देशों में 126वाँ स्थान था. इस सूचकांक पर आधारित आकलन के अनुसार, भारत में खुशहाली की स्थिति में प्रति वर्ष सुधार विगत वर्षों में दर्शाया गया है तथापि इस रिपोर्ट के आकलन में भारत में स्थिति काफी चिन्ताजनक ही लगातार बनी हुई है. मार्च 2026 में जारी ताजा रिपोर्ट में भारत के लिए यह इण्डेक्स 4·536 आकलित करते हुए 147 देशों में 116वाँ स्थान उसे दिया गया है. इस प्रकार भारत को इस मामले में नीचे से 32वाँ स्थान इस वर्ष दिया गया है. इससे पूर्व वर्ष 2021, 2022 व 2023 की रिपोर्ट्स में भारत को सबसे निचले 11 देशों में स्थान दिया गया था, जबकि 2024 की रिपोर्ट में नीचे से 17वाँ स्थान भारत को दिया गया था.

- **2026 की रिपोर्ट में विभिन्न देशों के लिए सूचकांक की गणना 2023-25 के आँकड़ों के औसत के आधार पर की गई है.**
- इस वर्ष की रिपोर्ट में खुशहाली के मामले में भारत के पड़ोसी देशों में चीन, नेपाल व पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर बताई गई है. हैप्पिनेस इण्डेक्स की 2026 की रिपोर्ट में चीन को 65वाँ, नेपाल को 99वाँ व पाकिस्तान को 104वाँ स्थान

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

दिया गया है, जबकि भारत का स्थान 116वाँ है.

- 2026 की वर्ल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट में सर्वोच्च हैप्पिनेस सूचकांक (7·764) फिनलैण्ड के लिए आकलित है. इस प्रकार फिनलैण्ड को सर्वाधिक खुशहाल देश (Happiest Country) इस रिपोर्ट में बताया गया है. **यह लगातार नौवाँ वर्ष है जब खुशहाली के मामले में फिनलैण्ड शीर्ष पर है.** उसके पश्चात् क्रमशः आइसलैण्ड (7·540), डेनमार्क (7·539), कोस्टारिका (7·439), स्वीडन (7·255) व नॉर्वे (7·242) के स्थान हैं. सर्वाधिक खुशहाल 10 देशों में इनके बाद क्रमशः नीदरलैण्ड्स, इजरायल, **लक्जेम्बर्ग** व स्विट्जरलैण्ड के स्थान हैं.

विभिन्न देशों के लिए हैप्पिनेस इंडेक्स (2025) व हैप्पिनेस के मामले में वैश्विक रैंक शीर्ष 10 राष्ट्र

रैंक	राष्ट्र	हैप्पिनेस इंडेक्स
1	फिनलैण्ड	7·764
2	आइसलैण्ड	7·540
3	डेनमार्क	7·539
4	कोस्टारिका	7·439
5	स्वीडन	7·255
6	नॉर्वे	7·242
7	नीदरलैण्ड्स	7·223
8	इजरायल	7·187
9	लक्जेमबर्ग	7·063
10	स्विट्जरलैण्ड	7·018
सबसे निचले 10 राष्ट्र		
138	तंजानिया	3·902
139	मिस्र	3·862
140	डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक कांगो	3·761
141	लेबनान	3·723
142	यमन	3·532
143	बोत्सवाना	3·464
144	जिम्बाब्वे	3·346
145	मलावी	3·284
146	सिएरा लियॉन	3·251
147	अफगानिस्तान	1·446

भारत व पड़ोसी देश		
65	चीन	6·074
99	नेपाल	5·147
104	पाकिस्तान	4·868
116	**भारत**	**4·536**
127	बांग्लादेश	4·319
129	म्यांमार	4·287
134	श्रीलंका	4·013
अन्य प्रमुख राष्ट्र		
11	न्यूजीलैण्ड	6·995
15	ऑस्ट्रेलिया	6·916
21	संयुक्त अरब अमीरात	6·821
22	सऊदी अरब	6·817
23	अमेरिका	6·816
29	ब्रिटेन	6·694
35	फ्रांस	6·586
61	जापान	6·130
79	रूस	5·834
97	ईरान	5·151
111	यूक्रेन	4·658

किसी भी देश के लिए यूनाइटेड नेशंस संस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के हैप्पिनेस इण्डेक्स का मान 0–10 के बीच हो सकता है. किसी देश के लिए हैप्पिनेस इण्डेक्स का मान अधिक होना अधिक खुशहाली की स्थिति बताता है. सूचकांक का मान कम होना कम खुशहाली को दर्शाता है. इस सूचकांक की गणना 7 मानकों के आधार पर होती है. इसमें (i) प्रति व्यक्ति जीडीपी (Per Capital GDP), (ii) सामाजिक समर्थन (Social Support), (iii) स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (Healthy Life Expectancy), (iv) उदारता (Generosity), (v) जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता (Freedom to make Life Choices), (vi) भ्रष्टाचार की धारणा (Perception of Corruption) तथा (vii) देश की तबाही की स्थिति (Dystopia) शामिल हैं.

- खुशहाली के मामले में अन्य प्रमुख देशों में न्यूजीलैण्ड का 11वाँ, ऑस्ट्रेलिया का 15वाँ, यूएई का 21वाँ, सऊदी अरब का 22वाँ, अमेरिका का 23वाँ, यूके का 29वाँ, जापान का 61वाँ, रूस का 79वाँ, ईरान का 97वाँ तथा यूक्रेन का 111वाँ स्थान इस रिपोर्ट में बताया गया है.
- खुशहाली की सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की ही इस वर्ष की रिपोर्ट में भी बताई गई है. सबसे नीचे 147वें स्थान पर रहे अफगानिस्तान के लिए हैप्पिनेस इण्डेक्स 1·446 ही आकलित किया गया है. इससे ऊपर 146वें स्थान पर सियरा लियॉन, 145वें स्थान पर मलावी व 144वें स्थान पर जिम्बाब्वे हैं.

युद्ध के साथ-साथ आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान में 1-1 करोड़ रियाल के करेंसी नोट जारी

युद्ध के कारण उत्पन्न हुए तेल एवं गैस संकट तथा आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति पर छाए संकट ने सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है. तेल एवं गैस के मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि ने परिवहन लागतों व विभिन्न वस्तुओं की उत्पादन लागतों में तीव्र वृद्धि की है जिससे अधिकांश देश फिलहाल मुद्रास्फीति का शिकार बने हैं. ईरान की खुद की अर्थव्यवस्था भी ऐसे विकराल संकट में फंसी है जहाँ खाने-पीने की वस्तुओं के मूल्य दोगुना हो गए हैं तथा कई जरूरी चीजें इससे भी अधिक महँगी हो गई हैं. वहाँ बेकाबू हो रही महँगाई के बीच मुद्रा (रियाल) का मूल्य तेजी से घटा है. मौद्रिक संकट से जूझ रहे ईरान में युद्ध से पूर्व ही 50 लाख रियाल का करेंसी नोट 1 फरवरी, 2026 को जारी किया गया था. युद्ध की स्थिति में वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि तथा मुद्रा की कमी के चलते 1-1 करोड़ रियाल के करेंसी नोट वहाँ मार्च 2026 में जारी किए गए हैं. मार्च के मध्य में 1 करोड़ रियाल का मूल्य 6-7 डॉलर के बराबर ही था.

राज्यों की राजकोषीय स्थिति के आकलन हेतु नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (2026)

विभिन्न मानकों के आधार पर राज्यों की राजकोषीय स्थिति के आकलन के लिए नीति आयोग ने इन राज्यों के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (Fiscal Health Index) का दूसरा संस्करण मार्च 2026 में जारी किया. इसका पहला संस्करण जनवरी 2025 में जारी किया गया था जिसमें 18 राज्यों का 2022-23 के लिए मूल्यांकन किया गया था. मार्च 2026 में जारी दूसरे संस्करण में इन 18 राज्यों के साथ-साथ पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्र के 10 छोटे राज्यों के लिए भी अध्ययन किया गया है.

विभिन्न राज्यों के लिए आकलित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI)

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

राजकोषीय स्वास्थ्य के निम्नलिखित 5 स्तम्भों पर आधारित हैं–

(i) **व्यय की गुणवत्ता (Quality of Expenditure)**–यह प्रतिबद्ध व्यय की तुलना में विकासात्मक व पूँजीगत व्यय के अध्ययन पर आधारित हैं.

(ii) **राजस्व जुटाना (Revenue Mobilisation)**–राज्य के स्वयं के स्रोतों से कर राजस्व व करेत्तर राजस्व जुटाने की दक्षता का मूल्यांकन.

(iii) **राजकोषीय विवेक (Fiscal Prudence)**–घाटे के प्रबन्धन के मामले में विवेकशील.

(iv) **ऋण सूचकांक (Debt Index)**–बकाया देन दारियों के सम्बन्ध में स्थिति का मूल्यांकन तथा

(v) **ऋण स्थिरता (Debt Sustainability)**–बकाया ऋण चुकाने की दक्षता का आकलन.

उपर्युक्त 5 स्तम्भों के आधार पर आकलित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का मान किसी भी राज्य के लिए 0–100 के बीच हो सकता है. 2023-24 के लिए सभी प्रमुख 18 राज्यों के लिए आकलित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक निम्नलिखित हैं–

रैंक	राज्य	राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI Score)	
1	ओडिशा	73·1	एचीवर
2	गोवा	54·7	
3	झारखण्ड	50·5	
4	गुजरात	49·9	फ्रंट रनर
5	महाराष्ट्र	45·0	
6	छत्तीसगढ़	44·3	
7	तेलंगाना	44·3	
8	उत्तर प्रदेश	41·9	
9	कर्नाटक	41·7	
10	मध्य प्रदेश	37·8	परफॉर्मर
11	हरियाणा	34·5	
12	बिहार	30·9	
13	तमिलनाडु	29·8	
14	राजस्थान	27·6	
15	केरल	24·8	एस्पिरेशनल
16	प. बंगाल	23·8	
17	आन्ध्र प्रदेश	23·1	
18	पंजाब	12·4	

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के मान के आधार पर सभी 18 राज्यों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में नीति आयोग ने विभाजित किया है–

1. **एचीवर (Achiever)**–इस श्रेणी में वह राज्य हैं जिनमें मजबूत राजकोषीय अनुशासन, उच्च स्व कर एवं करेतर राजस्व, कम राजकोषीय घाटा तथा प्रबंधनीय ऋण हैं. **उपर्युक्त तालिका में पहले तीन राज्यों–ओडिशा, गोवा व झारखण्ड को इस श्रेणी में रखा गया है, इनमें भी ओडिशा की स्थिति सर्वश्रेष्ठ है. नीति आयोग के एफएचआई के 2022-23 के लिए पहले संस्करण में भी ओडिशा की स्थिति को ही सर्वश्रेष्ठ आकलित किया गया था.**
2. **फ्रंट रनर (Frunt Runner)**–इस श्रेणी में वह राज्य हैं, जो आमतौर पर मजबूत राजकोषीय स्थिति बनाए हुए हैं, किन्तु किसी-न-किसी स्तम्भ की कमजोरी के कारण उच्च स्थिति से पीछे हैं. फ्रंट रनर कहे गए इन राज्यों में 6 राज्य–क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक को शामिल किया गया है.
3. **परफॉर्मर (Performer)**–इन राज्यों के स्कोर यह दर्शाते हैं कि एफएचआई के पाँचों स्तम्भों में इनकी स्थिति मिश्रित है. उपर्युक्त तालिका में 10 से 14 रैंक वाले 5 राज्य इस श्रेणी में बताए गए हैं. इनमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु व राजस्थान शामिल हैं.
4. **एस्पिरेशनल (Aspirational)**–सबसे कम स्कोर वाले राज्य इस श्रेणी में हैं. इनका निम्न स्कोर यह प्रदर्शित करता है कि स्व-कर राजस्व, अधिक राजकोषीय घाटे व उच्च ऋण आदि राजकोषीय संकटों से यह जूझ रहे हैं. उपर्युक्त तालिका में 15 से 18 रैंक वाले 4 राज्य इस श्रेणी में हैं. इनमें केरल, प. बंगाल, आन्ध्र प्रदेश व पंजाब शामिल हैं. सूचकांक की दृष्टि से पंजाब की राजकोषीय स्थिति सबसे कमजोर है.

नीति आयोग की इस रिपोर्ट में पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के लिए सूचकांक सर्वाधिक बताया गया है तथा उसके पश्चात् उत्तरखण्ड, त्रिपुरा, मेघालय, असम व मिजोरम के स्थान हैं.

इस प्रकार नीति आयोग की यह रिपोर्ट राज्यों में राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कई नीतिगत प्राथमिकताओं पर जोर देती है. इनमें राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ाना और राज्यों की कर क्षमता को मजबूत करना; राजकोषीय लचीलापन वापस लाने के लिए तय खर्चों को तर्कसंगत बनाना; पूँजीगत खर्च की बनावट और गुणवत्ता में सुधार करना और घाटे और कर्ज के रुझानों को ज्यादा असरदार तरीके से सँभालने के लिए मध्यम-अवधि की राजकोषीय योजना के ढाँचे अपनाना शामिल है. यह रिपोर्ट सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन प्रणालियों को मजबूत करने, सत्यापित राजकोषीय डेटा के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ाने और बजट से बाहर के कर्ज पर ज्यादा बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता पर भी जोर देती है.

अगले 5 वर्षों तक खुदरा मुद्रास्फीति 4 ± 2 प्रतिशत ही बनाए रखने का लक्ष्य

अगले 5 वर्षों तक (2030-31 तक) देश में खुदरा मुद्रास्फीति की दर को 2 प्रतिशत की घट-बढ़ के साथ 4 प्रतिशत ही बनाए रखने को भारतीय रिजर्व बैंक को केन्द्र सरकार ने कहा है. इस प्रकार वह दर 4 ± 2 प्रतिशत (2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक) ही बनाए रखने का लक्ष्य आरबीआई को सौंपा गया है.

ज्ञातव्य है कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने तथा आम लोगों पर महँगाई का असर कम करने के लिए खुदरा मुद्रास्फीति की दर को 31 मार्च, 2021 तक 4 प्रतिशत के आस-पास बनाए रखने का लक्ष्य आरबीआई के लिए सरकार ने पहले 2016 में निर्धारित किया था. बाद में मार्च 2021 में इसी लक्ष्य को मार्च 2026 तक के लिए बरकरार रखा गया था. अब एक बार पुनः अगले 5 वर्ष के लिए (मार्च 2031 तक के लिए) यही 4 प्रतिशत का लक्ष्य सरकार ने बरकरार रखा है जिसमें ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत व निचली सीमा 2 प्रतिशत है.

वित्त मंत्रालय द्वारा इस आशय की अधिसूचना मार्च 2026 में, ऐसे समय में जारी की गई है जब जनवरी 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 2·74 प्रतिशत व फरवरी 2026 के लिए यह 3·21 प्रतिशत (अनंतिम) घोषित की जा चुकी थी.

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के तहत् पंजीकृत अस्पतालों का विस्तार

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) भारत सरकार द्वारा संचालित सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है. सितम्बर 2018 से राँची (झारखण्ड) से

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

शुरू की गई इस योजना का तेजी से विस्तार हुआ है. पहले केवल गरीब व कमजोर परिवारों को ही पंजीकृत अस्पतालों में सालाना ₹ 5 लाख तक का कैशलैस इलाज की सुविधा इस योजना के तहत् उपलब्ध कराई जाती थी, अब सभी परिवारों के 70 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य तथा कुछ अन्य वर्ग भी इस योजना के तहत् लाभ के पात्र हैं.

हाल ही के वर्षों में योजना के विस्तार के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 23 मार्च, 2026 को लोक सभा में बताया कि इस योजना के लिए पंजीकृत अस्पतालों की संख्या 2018-19 में 6917 थी जिसमें 3013 सरकारी व 3904 निजी अस्पताल शामिल थे. योजना के तहत् पात्र लाभार्थियों को कैशलैस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने वाले पंजीकृत अस्पतालों की संख्या फरवरी 2026 के अन्त तक 36,229 हो गई थी. इनमें 19,483 सरकारी व 16,746 निजी अस्पताल शामिल थे. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, योजना के तहत् पंजीकृत अस्पताल पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने से इंकार नहीं कर सकते.

पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी

सभी पात्र भूमिधारक किसानों को कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केन्द्र सरकार द्वारा फरवरी 2019 से ही संचालित है. इस योजना के तहत् पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹ 6,000 की राशि ₹ 2000-2000 की तीन किस्तों में प्रदान की जाती है. **ऐसी पहली किस्त पात्र किसानों के बैंक खातों में 24 फरवरी, 2019 को ट्रांसफर की गई थी तब से यह योजना निरन्तर जारी है.** इस योजना की 22वीं किस्त प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 मार्च, 2026 को पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है. असम के गुवाहाटी में 13 मार्च को एक समारोह में श्री मोदी ने लगभग 9·32 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में कुल मिलाकर लगभग ₹ 18,640 करोड़ की राशि प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) के जरिए जमा कर दी. इन लाभार्थियों में 2·15 करोड़ से अधिक महिलाएँ थीं. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कुल मिलाकर यह 22वीं किस्त जहाँ थी, वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना की यह तीसरी अन्तिम किस्त थी.** यह किस्त जारी होने के बाद इस योजना के तहत् किसानों को ट्रांसफर की गई कुल राशि लगभग ₹ 4·27 लाख करोड़ हो चुकी है.

इस योजना के तहत् 2026-27 की पहली किस्त अब जुलाई/अगस्त 2026 में सम्भावित है, जो पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त होगी.

ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को प्राप्त होता है, जिनके नाम कृषि भूमि है. संस्थागत भूमि धारक इस योजना के तहत् लाभ के पात्र नहीं हैं. किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत अथवा विभाग से सेवानिवृत्त होकर पेंशन पाने वाले किसान की इस योजना के लाभ के पात्र नहीं हैं. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेंट आदि के रूप में पंजीकृत पेशेवरों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता. कृषि भूमि का उपयोग यदि कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु किया जाता है, तो ऐसे भूस्वामी इस योजना के तहत् लाभ के पात्र नहीं हैं.

संवैधानिक पदों के पूर्व एवं वर्तमान धारक पूर्व एवं वर्तमान मंत्री भी इस योजना के तहत् लाभ के पात्र नहीं हैं. पिछले लेखा वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति इस योजना के तहत् लाभ के पात्र नहीं हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के लिए अपना ई-केवाईसी कराना तथा फार्मर आईडी बनवाना आवश्यक है.

नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान

कृषि एवं किसान मंत्रालय की एक ताजा विज्ञप्ति के अनुसार नारियल (Coconut) के कुल वैश्विक उत्पादन में 30·7 प्रतिशत योगदान भारत का है, जिससे नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है. इस सम्बन्ध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में 17 मार्च, 2026 को लोक सभा में बताया गया कि विश्व में नारियल की खेती लगभग 12,390 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है. जिसमें भारत का हिस्सा लगभग 2165 हजार हेक्टेयर है. मंत्रालय के अनुसार भारत में प्रति वर्ष लगभग 21373·62 मिलियन नारियल का उत्पादन होता है जिससे इसकी औसत उत्पादकता लगभग 9871 नारियल प्रति हेक्टेयर है.

विश्व में नारियल का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख देश—इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका व ब्राजील आदि हैं. कुछ वर्ष पूर्व इनमें अग्रणी राष्ट्र इंडोनेशिया था, जो अब भारत माना जाता है. भारत में नारियल उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य—केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु हैं. देश में नारियल उत्पादन में वृद्धि के लिए 2026-27 के बजट में ही 'कोकोनट प्रमोशन स्कीम' की घोषणा केन्द्र सरकार ने की है. इस योजना का उद्देश्य नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल उत्पादन में वृद्धि के लिए पुराने व कम उत्पादक पेड़ों के स्थान पर नए पौधे व किस्में लगाकर उत्पादकता व उत्पादन में वृद्धि करना है.

औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए 'भव्य' योजना

देश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने की दिशा में एक और पहल के तहत् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने एक नई ***भारत औद्योगिक विकास योजना–'भव्य'*** *(Bharat Audyogik Vikas Yojna–BHAVYA) को मंजूरी 18 मार्च, 2026 को प्रदान की है जिसके तहत् देश के विभिन्न भागों में 100 'प्लग एण्ड प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जहाँ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए* ***मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर*** *(Core Infrastructure—आंतरिक सड़कें, जल निकासी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी व प्रशासनिक प्रणालियाँ आदि),* ***मूल्य वर्द्धित इन्फ्रास्ट्रक्चर*** *(Value Added Infrastructure—तैयार कारखाने के शेड, आवश्यकतानुसार निर्मित इकाइयाँ, भण्डारण सुविधाएँ आदि) तथा* ***सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर*** *(Social Infrastructure—श्रमिकों के आवास व अन्य सहायक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी. देश भर में 100 से 1000 एकड़ तक के 100 ऐसे प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए ₹ 33,600 करोड़ केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की 18 मार्च की बैठक में स्वीकृत किए गए हैं.* ***भव्य योजना का मुख्य उद्देश्य देश में विश्व-स्तरीय औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, विनिर्माण की सम्भावना के द्वार खोलना तथा भारत की विकास गाथा को गति प्रदान करना है.*** *इन औद्योगिक पार्कों से एक ओर जहाँ विनिर्माण इकाइयाँ (Manufacturing Units), लघु एवं मध्यम उपक्रम (MSMEs), स्टार्टअप्स तथा 'रैडी टू यूज' इन्फ्रास्ट्रक्चर की तलाश करने वाले वैश्विक निवेशक जहाँ लाभान्वित होंगे, वहीं दूसरी ओर श्रमिक, लॉजिस्टिक प्रदाता, सेवा क्षेत्र के उद्यम व स्थानीय समुदाय आदि इसके द्वितीयक लाभार्थी होंगे. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा लॉजिस्टिक्स व सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा. राज्य सरकारों व निजी क्षेत्र के सहयोग से लागू की जाने वाली यह योजना भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केन्द्र (Global Manufacturing Hub) बनाने में सहायक होगी.*

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

नवीनतम सामान्य ज्ञान

शब्द संक्षेप
(Abbreviation)

????–????

एसवीईईपी (स्वीप)–सिस्टेमैटिक वोटर्स एज्यूकेशन एण्ड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन

????–????

SVEEP–Systematic Voters' Education and Electoral Participation

व्याख्या–भारत में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने व मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए यह चुनाव आयोग का एक कार्यक्रम है. इसका मूल उद्देश्य भारत के सभी पात्र नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें एक जागरूक मतदाता बनाना है.

यह उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा झूठे एवं भ्रामक विज्ञापनों से उपभोक्ताओं का बचाव करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित यह एक वैधानिक प्राधिकरण है. उपभोक्ताओं को गलत संदेश देने वाली प्रथाओं व विज्ञापनों पर रोक लगाकर ऐसा करने वालों को यह दण्डित भी कर सकता है..

नियुक्तियाँ
(Appointments)

9 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में नए राज्यपाल/उपराज्यपाल

- मार्च 2026 में 9 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में नए राज्यपालों/उपराज्यपालों की नियुक्तियाँ व फेरबदल किए गए हैं. इन फेरबदल के तहत्–
- दिल्ली के उपराज्यपाल रहे विनय कुमार सक्सेना को स्थानांतरित करके लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार सौंपा गया है. जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली ने 13 मार्च को लेह में सीआईबीएस ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई है. वह लद्दाख के चौथे उपराज्यपाल हैं.
- अमेरिका में भारत के राजदूत रहे पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है. दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने 11 मार्च को लोक भवन में आयोजित समारोह में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई. इस पद पर विनय कुमार सक्सेना का स्थान उन्होंने लिया है.
- लद्दाख के निवर्तमान उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को अब हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुरमीत सिंह संघवालिया ने 10 मार्च को शिमला में लोक भवन में आयोजित समारोह में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई. वह इस राज्य के 30वें राज्यपाल हैं. इस पद पर शिव प्रकाश शुक्ला, जिन्हें अब तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है, का स्थान कविंदर गुप्ता ने लिया है.
- तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुजॉय पॉल ने 12 मार्च को कोलकाता में लोक भवन में आयोजित समारोह में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई. एन. आर. रवि ने इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त डॉ. सी. वी. आनंद बोस का स्थान लिया है, जिन्होंने 39 माह तक पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहने के पश्चात् अचानक ही 5 मार्च को इस्तीफा दे दिया था.
- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को अब महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है.
- बिहार विधान सभा अध्यक्ष रहे वरिष्ठ भाजपा नेता नन्द किशोर यादव को अब नगालैण्ड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
- रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू ने पटना में लोक भवन में 14 मार्च को आयोजित समारोह में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई. इस पद पर आरिफ मोहम्मद खान का स्थान उन्होंने लिया है.
- केरल के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु के राज्यपाल का कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है. (तमिलनाडु में राज्यपाल रहे आर. एन. रवि को अब प. बंगाल का राज्यपाल मार्च 2026 में ही बनाया गया है.)

विक्रम दोराईस्वामी चीन में भारत के नए राजदूत

भारतीय विदेश सेवा के 1992 बैच के राजनयिक विक्रम दोराईस्वामी अब चीन में भारत के नए राजदूत होंगे. इस पद पर प्रदीप कुमार रावत, जो मार्च 2022 से वहाँ भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं, का स्थान दोराईस्वामी लेंगे. भारतीय विदेश सेवा के 1992 बैच के विक्रम दोराईस्वामी इस नियुक्ति से पूर्व ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त थे. वह इससे पूर्व बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त तथा द. कोरिया व उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके हैं.


विक्रम दोराईस्वामी

नीतीश कुमार जनता दल (यू) के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित

राज्य सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के कुछ ही दिन पश्चात् मार्च 2026 में ही नीतीश कुमार को जनता दल (यूनाइटेड) का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार पुनः निर्विरोध चुना गया. शरद यादव के पद छोड़ने के पश्चात् पहली बार 2016 में उन्हें इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था तथा 2019 में उनकी पुनर्नियुक्ति इस पद पर हुई थी. वर्ष 2020 में उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था तथा 2023 में पुनः पार्टी का अध्यक्ष पद उन्होंने ही सँभाला था. अब मार्च 2026 में पुनः इस पद हेतु उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है.


नीतीश कुमार

पार्थनिल घोष एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबन्ध निदेशक

सामान्य बीमा कम्पनी एचडीएफसी एर्गो (HDFC ERGO) जनरल इंश्योरेंस कम्पनी में कार्यकारी निदेशक रहे पार्थनिल घोष अब इस कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक सह-सीईओ (MD & CEO) होंगे. 'इरडा' (IRDA) के अनुमोदन के पश्चात् वह यह कार्यभार 16 अप्रैल, 2026 से सँभालेंगे. इस पद पर अनुज त्यागी, जो कई वर्षों से यह दायित्व सँभाले हुए हैं, का स्थान पार्थनिल घोष लेंगे. अनुज त्यागी ने इस पद से त्यागपत्र 16 जनवरी, 2026 को दे दिया था.

थल सेना नेतृत्व में व्यापक फेरबदल : लेफ्टि. जन. धीरज सेठ थल सेना के नए उप प्रमुख

भारतीय थल सेना के प्रशासन में व्यापक स्तर पर फेरबदल 1 अप्रैल, 2026 से किए गए

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

हैं. इनके तहत् सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (GOC-in-C) रहे लेफ्टि. जनरल को अब थल सेना का उप प्रमुख (VCOAS–Vice Chief of Army Staff) 1 अप्रैल, 2026 से बनाया गया है. इस पद पर लेफ्टि. जन. पी.पी. सिंह, जिन्हें 1 अप्रैल से ही पश्चिमी कमान का कमांडर बनाया गया है, का स्थान लेफ्टि. जन धीरज सेठ ने लिया है. 1 अप्रैल, 2026 से ही लेफ्टि. जनरल वीएमबी कृष्णन सेना की पूर्वीकमान के कमांडर (COC-in-C) बनाए गए हैं, जबकि दक्षिणी कमान के कमांडर का दायित्व लेफ्टि. जन. संदीप जैन को सौंपा गया है.



लेफ्टि. जन. धीरज सेठ थल सेना के नए उप प्रमुख

पुरस्कार/सम्मान (Awards/Honours)

क्रिकेट के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई के नमन पुरस्कार (2026)

घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय क्रिकेटरों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के वर्ष 2024-25 के नमन पुरस्कारों का वितरण नई दिल्ली में 15 मार्च, 2026 को किया गया. अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ-साथ बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेन्ट्स (रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी आदि) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर्स को भी पुरस्कार इस समारोह में दिए गए.

इस वर्ष के नमन पुरस्कार वितरण समारोह में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 जीतने वाली सीनियर पुरुष टीम, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने वाली सीनियर महिला टीम, आईसीसी अण्डर-19 विश्व कप 2026 जीतने वाली पुरुष अण्डर-19 टीम और आईसीसी अण्डर-19 विश्व कप 2025 जीतने वाली महिला अण्डर-19 टीम को भी सम्मानित किया गया.



सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट (पुरुष) का पुरस्कार लेते हुए शुभमन गिल

भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देने वाला बीसीसीआई का सर्वोच्च सम्मान कर्नल सी. के. नायडू लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार रोजर बिन्नी व राहुल द्रविड़ को संयुक्त रूप से इस समारोह में दिया गया, जबकि महिला क्रिकेट में असाधारण योगदान के लिए बीसीसीआई लाइफटाइम एचीवमेंट अर्वार्ड फॉर विमेन मिताली राज को दिया गया. इस वर्ष के पुरस्कारों में प्रमुख पुरस्कारों की सूची अग्रलिखित है–

पुरस्कार (2024-25)

लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार (कर्नल सी.के. नायडू पुरस्कार)–रोजर बिन्नी व राहुल द्रविड़

बीसीसीआई लाइफ-टाइम एचीवमेंट अवॉर्ड फॉर विमेन– मिताली राज

सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेटर (पुरुष का पॉली उमरीगर पुरस्कार–शुभमन गिल (दूसरी बार यह पुरस्कार)

सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेटर (महिला) – स्मृति मंधाना (पाँचवीं बार यह पुरस्कार)

सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय पदार्पण (पुरुष)–हर्षित राणा

सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय पदार्पण (महिला)– एन. श्री चरणी



सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेटर (महिला) स्मृति मंधाना

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन (महिला)– स्मृति मंधाना

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट (महिला)–दीप्ति शर्मा

घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अम्पायर– उल्लास गाँधी (विदर्भ)

बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (टीम)–मुम्बई क्रिकेट एसोसिएशन

रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर (लाला अमरनाथ पुरस्कार)–हर्ष दुबे (विदर्भ)

सीमित ओवर घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर (लाला अमरनाथ पुरस्कार)– आयुष महात्रे (मुम्बई)

घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (सीनियर) जगमोहन डालमिया ट्रॉफी)– शेफाली वर्मा (हरियाणा)

घरेलू क्रिकेट (जूनियर) में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (जगमोहन डालमिया ट्रॉफी)–इरा जाधव (मुम्बई)

ऑस्कर पुरस्कार (2026)

वर्ष 2025 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एण्ड साइंसेज (AMPAS) के 98वें **एकेडमी अवॉर्ड्स** (प्रचलित नाम ऑस्कर पुरस्कार) का वितरण लॉस एंजेल्स (कैलीफोर्निया) स्थित डॉल्बी थिएटर में 15 मार्च, 2026 को किया गया. कुल मिलाकर 24 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार इस वर्ष दिए गए. सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग का पुरस्कार इस वर्ष से ही शुरू किया गया है.

इस वर्ष सर्वाधिक 6 पुरस्कार पॉल थामस एंडरसन द्वारा निर्देशित फिल्म **वन बैटल आफ्टर अनदर** को मिले, जबकि रयान कूगलर द्वारा निर्देशित सिनर्स (Sinners) ने दूसरे स्थान पर 4 ऑस्कर तथा गुइलेर्मो डेल टोरो द्वारा निर्देशित फिल्म फ्रैंकेन्स्टीन (Frankenstein) को 3 ऑस्कर प्राप्त हुए. फिल्म सिनर्स को रिकॉर्ड सर्वाधिक 16 पुरस्कारों हेतु नामांकित किया गया था. दूसरे स्थान पर 6 पुरस्कार पाने वाली फिल्म वन बैटल ऑफ्टर अनदर 13 पुरस्कारों के लिए नामांकित थी.

अमेरिकी निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा निर्देशित फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर (One Battle After Another) को सर्वाधिक 6 पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत् मिले जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता व सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग के प्रमुख पुरस्कार शामिल हैं. सर्वश्रेष्ठ कॉस्टिंग का पुरस्कार इसी वर्ष से ही प्रारम्भ किया गया है. इस फिल्म को 13 श्रेणियों में पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था.



सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले व सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी. जॉर्डन ट्रॉफियों के साथ

दूसरे स्थान पर 4 पुरस्कार **'सिनर्स'** को प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ संगीत व सर्वश्रेष्ठ ओरिजनल स्क्रीनप्ले के पुरस्कार शामिल थे.

सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पॉल थामस एंडरसन द्वारा निर्देशित फिल्म **वन बैटल आफ्टर अनदर** को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इसके ही निर्देशक पॉल थामस एंडरसन को दिया गया. फिल्म सिनर्स में मुख्य भूमिका के लिए अमेरिकन अभिनेता माइकल बी. जॉर्डन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तथा फिल्म हैमनेट में भूमिका के लिए आयरिश अभिनेत्री जेसी बकले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत् दिया गया.

इन प्रमुख पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है–

सर्वश्रेष्ठ फिल्म–वन बैटल आफ्टर अनदर (निर्देशक–पॉल थामस एंडरसन)

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



सर्वश्रेष्ठ निर्देशक—पॉल थामस एंडरसन (फिल्म—वन बैटल ऑफ्टर अनदर)

मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता—माइकल बी. जॉर्डन (फिल्म—सिनर्स)

मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री—जेसी बकले (फिल्म—हैमनेट)

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता—सीन पैन (फिल्म—वन बैटल आफ्टर अनदर)

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री—एमी मेडिगन (फिल्म—वेपंस)

सर्वश्रेष्ठ एनीमेटेड फीचर फिल्म—केपॉप डेमोन हंटर्स

सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म—सेंटीमेंटल वैल्यू (नॉर्वे)

सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म—मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन

सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म—ऑल द एम्प्टी रूम्स

सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म—द. सिंगर्स तथा टू पीपुल्स एक्सचेंजिंग स्लाइवा

सर्वश्रेष्ठ एनीमेटेड शॉर्ट फिल्म—द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स

सर्वश्रेष्ठ संगीत (ओरिजिनल स्कोर)—सिनर्स

सर्वश्रेष्ठ संगीत (ओरिजिनल साँग)—गोल्डन (फिल्म केपॉप डेमोन हंटर्स)

सर्वश्रेष्ठ साउंड— फिल्म—एफ 1 (F1)

सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग —वन बैटल आफ्टर अनदर

सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन—फिल्म फ्रैंकेन्स्टीन

सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी—सिनर्स

सर्वश्रेष्ठ मेकअप एवं हेयर स्टाइलिंग—फ्रैंकेन्स्टीन

सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन—फ्रैंकेन्स्टीन

सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग—फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर

सर्वश्रेष्ठ विजुअल एफेक्ट्स—अवतार : फायर एण्ड एश

सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल राइटिंग स्क्रीन प्ले—फिल्म सिनर्स

सर्वश्रेष्ठ एडॉप्टेड राइटिंग (स्क्रीन प्ले)—वन बैटल आफ्टर अनदर

उल्लेखनीय है कि करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हिन्दी फिल्म होमबाउंड वर्ष 2026 के (98वें) ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म केटेगरी (Best International Feature Film Category) में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी.

तमिल कवि एवं गीतकार वैरामुथु रामासामी को ज्ञानपीठ पुरस्कार (2025)

भारतीय ज्ञानपीठ ने भारत में साहित्य के क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिष्ठित (60वाँ) ज्ञानपीठ पुरस्कार, वर्ष 2025 के लिए तमिल कवि एवं गीतकार वैरामुथु रामासामी (Vairamuthu Ramasamy) को प्रदान करने की घोषणा 15 मार्च, 2026 को की है. उनके लिखे गीतों ने तमिल साहित्य के साथ-साथ तमिल फिल्मों में भी विशेष पहचान बनाई है जिनके चलते तमिल साहित्य के अनेक पुरस्कारों (साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित) के साथ-साथ तमिल फिल्म जगत के अनेक पुरस्कारों से 73 वर्षीय वैरामुथु सम्मानित हैं. तमिल फिल्मों में उनके गीतों के लिए 7 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 10 बार तमिल फिल्मों का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार व कई बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का तमिलनाडु राज्य-स्तरीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुका है. **भारत सरकार ने 2003 में पद्म श्री से तथा 2014 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया था.**


वैरामुथु रामासामी

ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वह तीसरे तमिल साहित्यकार हैं. तमिल साहित्यकारों में उनसे पूर्व यह पुरस्कार पी. वी. अकिलन्दम (1975) व डी. जयकांतन (2002) को मिल चुका है. इस पुरस्कार के तहत् वागदेवी (विद्या की देवी सरस्वती) की प्रतिमा व प्रशस्ति-पत्र के साथ ₹ 11 लाख की राशि प्रदान की जाती है.

ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भाषा में योगदान के लिए दिया जाता है (किन्तु एक बार 2018 का यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए भी अमिताव घोष को दिया जा चुका है). 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की किसी एकल कृति के लिए ही दिया जाता था, किन्तु उसके पश्चात् लेखक के किसी भाषा में समग्र योगदान के लिए दिया जाता है.

पिछले वर्ष, वर्ष 2024 के लिए (59वाँ) ज्ञानपीठ पुरस्कार हिन्दी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था.

ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार

वर्ष	पुरस्कार विजेता
1965	जी. शंकर कुरूप (मलयालम)
1966	ताराशंकर बंध्योपाध्याय (बांग्ला)
1967	(1) के. वी. पुटप्पा (कन्नड़) (2) उमाशंकर जोशी (गुजराती)
1968	सुमित्रानन्दन पन्त (हिन्दी)
1969	फिराक गोरखपुरी (उर्दू)

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

1970	विश्वनाथ सत्यनारायण (तेलुगू)
1971	विष्णु देव (बांग्ला)
1972	रामधारी सिंह 'दिनकर' (हिन्दी)
1973	(1) डॉ. दत्तात्रेय रामचन्द्र बेन्द्रे (कन्नड़) (2) गोपीनाथ मोहन्ती (ओडिया)
1974	विष्णु सखा खाण्डेकर (मराठी)
1975	पी. वी. अकिलन्दम (तमिल)
1976	श्रीमती आशापूर्णा देवी (बांग्ला)
1977	के. शिवाराम करन्थ (कन्नड़)
1978	एस. एच. वी. अज्ञेय (हिन्दी)
1979	डॉ. वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य (असमिया)
1980	एस. के. पोट्टेकट (मलयालम)
1981	अमृता प्रीतम (पंजाबी)
1982	महादेवी वर्मा (हिन्दी)
1983	मस्ति वेंकटेश आयंगर (कन्नड़)
1984	थकाजी शिवशंकर पिल्लई (मलयालम)
1985	पन्नालाल पटेल (गुजराती)
1986	सच्चिदानन्द राउत्रे (ओडिया)
1987	वि. वा. शिरवाडकर (मराठी)
1988	सी. नारायण रेड्डी (तेलुगू
1989	कुर्रतुल एन. हैदर (उर्दू)
1990	विनायक कृष्ण गोकाक (कन्नड़)
1991	सुभाष मुखोपाध्याय (बांग्ला)
1992	नरेश मेहता (हिन्दी)
1993	डॉ. सीताकान्त महापात्र (ओडिया)
1994	प्रो. यू. आर. अनंतमूर्ति (कन्नड़)
1995	एम.टी. वासुदेवन नायर (मलयालम)
1996	श्रीमती महाश्वेता देवी (बांग्ला)
1997	अली सरदार जाफरी (उर्दू)
1998	गिरीश कर्नाड (कन्नड़)
1999	(1) निर्मल वर्मा (हिन्दी) (2) गुरदयाल सिंह (पंजाबी)
2000	इन्दिरा गोस्वामी (असमिया)
2001	राजेन्द्र केशवलाल शाह (गुजराती)
2002	डी. जयकांतन (तमिल)
2003	विंदा करंदीकर (मराठी)
2004	रहमान राही (कश्मीरी)
2005	कुँवर नारायण (हिन्दी)
2006	(1) रवीन्द्र केलकर (कोंकणी) (2) सत्यव्रत शास्त्री (संस्कृत)
2007	ओ. एन. वी कुरूप (मलयालम)
2008	अखलाख मोहम्मद खान (शहरयार) (उर्दू)
2009	(1) अमरकांत (हिन्दी) (2) श्री लाल शुक्ला (हिन्दी)
2010	चन्द्रशेखर कंवर (कन्नड़)
2011	प्रतिभा राय (ओडिया)
2012	डॉ. रावुरी भारद्वाज (तेलुगू)
2013	प्रो. केदारनाथ सिंह (हिन्दी)
2014	भालचन्द्र नेमाड़े (मराठी)
2015	रघुवीर चौधरी (गुजराती)
2016	शंख घोष (बांग्ला)
2017	कृष्णा सोबती (हिन्दी)
2018	अमिताव घोष (अंग्रेजी)
2019	अक्कीथम अच्युतम नम्बूथिरी (मलयालम)
2021	नीलमणि फूकन (असमिया)
2022	दामोदर मॉऊजो (कोंकणी)
2023	स्वामी रामभद्राचार्य (संस्कृत) व गुलजार (सम्पूर्ण सिंह कालरा) (उर्दू)
2024	विनोद कुमार शुक्ल (हिन्दी)
2025	वैरामुथु रामासामी (तमिल)

बांग्ला साहित्यकार रामकुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान (2025)

के. के. बिड़ला फाउण्डेशन द्वारा भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित (35वाँ) सरस्वती सम्मान वर्ष 2025 के लिए बांग्ला भाषा के लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को उनके उपन्यास 'हर पार्वती कथा' को प्रदान करने की घोषणा की गई है. 21 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् किसी बांग्ला साहित्यकार को यह पुरस्कार दिया गया, इससे पूर्व बांग्ला साहित्यकार सुनील कुमार गंगोपाध्याय को वर्ष 2004 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था. **के. के. बिड़ला फाउण्डेशन के इस पुरस्कार में लेखक को ₹ 15 लाख की सम्मान राशि के साथ प्रशस्ति-पत्र और प्रतीक चिह्न दिया जाता है.**



रामकुमार मुखोपाध्याय

के. के. बिड़ला फाउण्डेशन का साहित्य के क्षेत्र का यह पुरस्कार संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में विगत् 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है रामकुमार मुखोपाध्याय की कृति 'हर पार्वती कथा' का प्रकाशन वर्ष 2020 में हुआ था. 'हर पार्वती कथा' शिव पार्वती की पौराणिक कथा को केन्द्र में रखकर लिखा गया है. इससे पूर्व वर्ष 2024 का यह (34वाँ) सरस्वती सम्मान संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को संस्कृत भाषा की उनकी रचना स्वामी नारायण सिद्धान्त सुधा के लिए दिया गया था. इस पुरस्कार की स्थापना के. के. बिड़ला फाउण्डेशन द्वारा 1991 ई. में की गई थी.

साहित्य के क्षेत्र में के. के. बिड़ला फाउण्डेशन के 2 अन्य पुरस्कार—व्यास सम्मान व बिहारी पुरस्कार हैं. इनमें सरस्वती सम्मान जहाँ भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा में विगत् 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है, वहीं व्यास सम्मान किसी भारतीय साहित्यकार को विगत् 10 वर्षों में हिन्दी में पहली बार प्रकाशित उत्कृष्ट रचना के लिए तथा बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किसी साहित्यकार को विगत् 10 वर्षों में पहली बार हिन्दी/राजस्थानी में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है. सरस्वती सम्मान के तहत् ₹ 15 लाख, व्यास सम्मान के तहत् ₹ 4 लाख तथा बिहारी पुरस्कार के तहत् ₹ 2·50 लाख की राशि अब प्रदान की जाती है.

सरस्वती सम्मान से अब तक सम्मानित सभी साहित्यकारों की सूची

वर्ष	साहित्यकार का नाम	कृति/उपन्यास/काव्य
1991	हरिवंश राय बच्चन	आत्मकथा (हिन्दी)
1992	रमाकांत रथ	श्री राधा (कविता संग्रह), ओडिया
1993	विजय तेंदुलकर	कन्यादान (नाट्य), मराठी
1994	डॉ. हरभजन सिंह	रुख ते ऋषि (कविता संग्रह), पंजाबी
1995	बालमणि अम्मा	निवेद्यम (कविता संग्रह), मलयालम
1996	शमसुर रहमान फारुखी	शेर-ए-शोर अंगेज, उर्दू

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

1997	मनुभाई पंचोली 'दर्शक'	कुरुक्षेत्र, गुजराती
1998	प्रो. शंख घोष	गंधर्व कविता गुच्चा, बांग्ला
1999	इंद्रा पार्थ-सारथी	रामानुजार (नाट्य), तमिल
2000	मनोज दास	अमृताफल (उपन्यास), ओडिया
2001	दलीप कौर तिवाना	कथा कहो उर्वशी (उपन्यास), पंजाबी
2002	महेश अलकुंचवार	युगांत (नाट्य), मराठी
2003	प्रो. गोविन्द चन्द्र पांडे	भागीरथी (कविता), संस्कृत
2004	सुनील गंगोपाध्याय	प्रथम अलो (उपन्यास), बांग्ला
2005	प्रो. के. अय्यप्पा पणिकर	अयप्पा पानुकरुड़े कृति काल (कविता संग्रह), मलयालम
2006	जगन्नाथ प्रसाद दास	परिक्रमा (कविता संग्रह), ओडिया
2007	नैयर मसूद	ताऊस चमन की मैना (लघु कहानी संग्रह), उर्दू
2008	लक्ष्मी नंदन बोरा	कायाकल्प (उपन्यास), असमी
2009	सुरजीत पातर	लफ्जों दी दरगाह, पंजाबी
2010	प्रो. एस.एल. भयरप्पा	उपन्यास 'मंद्रा', कन्नड़
2011	ए.ए. मानवालन	इरामा कथायुम इरामायाकुलम, तमिल
2012	सुगाथा कुमारी	मनालेजुथु (कविता संग्रह), मलयालम
2013	गोविन्द मिश्र	धूल पौधों पर (उपन्यास), हिन्दी
2014	वीरप्पा मोइली	रामायण महान्वेषण (काव्य), कन्नड़
2015	पद्मा सचदेव	चित्त-चेते (आत्मकथा), डोगरी
2016	महाबलेश्वर सैल	हाउटन (उपन्यास), कोंकणी
2017	सितांशु यशचंद्र	वखार (कविता संग्रह), गुजराती
2018	के. शिवा रेड्डी	पक्काकि ओट्टिगिलिते (कविता संग्रह), तेलुगू
2019	वासदेव मोही	चेक बुक (लघु कथा संग्रह), सिंधी
2020	शरण कुमार लिबले	सनातन (उपन्यास), मराठी
2021	रामदरश मिश्र	मैं तो यहाँ हूँ (कविता संग्रह), हिन्दी
2022	शिवशंकरी	सूर्य वामसम (स्मृति ग्रन्थ) (तमिल)
2023	प्रभा वर्मा	रौद्र सात्विकम (मलयालम)
2024	भद्रेश दास	स्वामीनारायण सिद्धान्त सुधा (संस्कृत)
2025	रामकुमार मुखोपाध्याय	हर पार्वती कथा (उपन्यास) (बांग्ला)

टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्र-शेखरन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान

टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चन्द्रशेखरन को भारत-ब्रिटेन व्यापार सम्बन्धों को मजबूत करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन सरकार ने मानद नाइटहुड (Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) से सम्मानित किया गया है. **चन्द्रशेखर को यह सम्मान 18 मार्च, 2026 को नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त के निवास पर ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन द्वारा दिया गया.** उन्हें सम्मानित करते हुए ब्रिटिश उच्चायोग के वक्तव्य में कहा गया कि टाटा समूह ब्रिटेन में एक दीर्घकालिक निवेशक है जिसकी गतिविधियाँ ऑटोमेटिव, स्टील, प्रौद्योगिकी व उपभोक्ता क्षेत्रों में फैली हुई हैं.



एन. चन्द्रशेखरन को नाइटहुड से सम्मानित करती हुई भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन

चन्द्रशेखरन को नाइटहुड से सम्मानित करते हुए 'भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन (Lindy Cameron) ने उन्हें ब्रिटेन के अद्भुत मित्र व भारत की कॉर्पोरेट दुनिया में एक प्रतीकात्मक व्यक्ति (An Iconic Figure in India's Corporate World) बताया.

स्टॉकहोम वाटर प्राइज (2026)

यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर, एन्वायरमेंट एण्ड हैल्थ (UNU-INWEH) के ईरानी मूल के निदेशक काबेह मदानी (Kaveh Madani) को 'जल दिवालियापन' से सम्बन्धित उनके शोध के लिए स्टॉकहोम वाटर फाउण्डेशन के वर्ष 2026 के स्टॉकहोम वाटर प्राइज के लिए चुना गया है. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से दिए जाने वाला यह पुरस्कार उन्हें अगस्त 2026 में 'विश्व जल सप्ताह' के दौरान स्वीडन के राजा कार्ल XVI गुस्ताफ के हाथों दिया जाएगा.



काबेह मदानी

'जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार' कहे जाने वाले इस पुरस्कार के तहत् 10 लाख स्वीडिश क्रोनर (लगभग 1·06 लाख डॉलर) की राशि प्रदान की जाती है.

'भारत के वाटरमैन' कहे जाने वाले राजेन्द्र सिंह को 2015 में यह पुरस्कार दिया गया था.

साहित्य अकादमी पुरस्कार (2025)

साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के अपने मुख्य पुरस्कारों (साहित्य अकादमी पुरस्कार) की घोषणा 16 मार्च, 2026 को की. 24 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार घोषित किए गए हैं. पुरस्कृत 24 कृतियों में 8 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 6 लघु कहानी संग्रह, 2 निबंध संग्रह, 2 संस्मरण, 1 आत्मकथा तथा 1 साहित्यिक आलोचना शामिल हैं.

हिन्दी भाषा के लिए ममता कालिया को उनके संस्मरण.'जीते जी इलाहाबाद' तथा अंग्रेजी के लिए नवतेज सरना को उनके

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

वर्ष 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चुने गए साहित्यकारों व उनकी रचनाओं के नाम

भाषा	पुरस्कृत कृति/रचना	पुरस्कृत लेखक
असमिया	करही खेलर साधु (उपन्यास)	देवब्रत दास
बंगाली	श्रेष्ठ कबिता (कविता)	प्रसून बंद्योपाध्याय
बोडो	द्वंग्वी लामा म्वांसे गाथ्वन (उपन्यास)	सहैसुली ब्रह्मा
डोगरी	ठाकुर सत्सयि (कविता, दोहे)	खजूर सिंह ठाकुर
अंग्रेजी	क्रिमसन स्प्रिंग (उपन्यास)	नवतेज सरना
गुजराती	भट्टखडकी (कविता)	योगेश वैद्य
हिन्दी	जीते जी इलाहाबाद (संस्करण)	ममता कालिया
कन्नड़	दादा सीरीसु टांडे (लघु कहानियाँ)	अमरेश नुगाडोनी
कश्मीरी	नज्दावनेकी पॉट अलाव (कविता)	अली शैदा
कोंकणी	कोंकणी काव्येम : रूपाणी अनी रूपकम (निबंध)	हेनरी मेंडोंका (एच.एम.पर्नल)
मैथिली	धात्री पात सन गाम (संस्मरण)	महेन्द्र
मलयालम	मायामानुष्यर (उपन्यास)	एन प्रभाकरन
मणिपुरी	कंगलमद्रिबा एफुत (लघु कथाएँ)	हाओबम नलिनी
मराठी	कल्याणिल्य रेशा (आत्मकथा)	राजू बाविस्कर
नेपाली	नेपाली परम्परागत संस्कृति रा सभ्यता को डुकुटी (निबंध)	प्रकाश भट्टराई
ओडिया	पादपुराण (काव्य)	गिरिजाकुमार बलियार सिंह
पंजाबी	सुरक्षा किट (कहानियाँ)	जिंदर
राजस्थानी	भरखमा (कहानियाँ)	जितेंद्र कुमार सोनी
संस्कृत	प्रस्थानचतुस्तये ब्रह्मघोषः (कविता)	महामहोपाध्याय साधु भद्रेशदास
संथाली	मिड बिरना चेन्ने साओन इनाग सागाई (लघु कथाएँ)	सुमित्रा-सोरेन
सिंधी	वाघू (कहानियाँ)	भगवान अटलानी
तमिल	थमिज सिरुकाथैयिन थडंगल (साहित्यिक आलोचना)	सा. तमिलसेल्वन
तेलुगू	अनिमेस (कविता)	नंदिनी सिधा रेड्डी
उर्दू	सफर जारी है (कविता)	प्रीतपाल सिंह बेताब

साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं.

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएँ

(i) असमी, (ii) बांग्ला, (iii) गुजराती, (iv) हिन्दी, (v) कन्नड़, (vi) कश्मीरी, (vii) कोंकणी, (viii) मलयालम, (ix) मणिपुरी, (x) मराठी, (xi) नेपाली, (xii) ओडिया, (xiii) पंजाबी, (xiv) संस्कृत, (xv) सिंधी, (xvi) तमिल, (xvii) तेलुगू, (xviii) उर्दू, (xix) बोडो, (xx) संथाली, (xxi) मैथिली तथा (xxii) डोगरी.

उपन्यास 'क्रिमसन स्प्रिंग' के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया है.

पुरस्कार हेतु चुने गए साहित्यकारों को ताम्रपत्र व शॉल के साथ ₹1-1 लाख की राशि 31 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान की गई.

हॉकी इण्डिया के वार्षिक पुरस्कार (2025)

हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को हॉकी इण्डिया के वर्ष 2025 के (8वें) वार्षिक पुरस्कारों का वितरण नई दिल्ली में 27 मार्च, 2026 को किया गया. पिछले वर्ष 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हॉकी खिलाड़ियों के विशेष पुरस्कार समारोह में प्रदान किए गए. हॉकी इण्डिया की 15वीं नेशनल चैम्पियनशिप (2025) में सफलता के लिए 7 इकाइयों–हॉकी झारखण्ड, हॉकी हरियाणा, हॉकी मिजोरम, हॉकी पंजाब, हॉकी मध्य प्रदेश, हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा व हॉकी उत्तर प्रदेश को ₹ 10-10 लाख की प्रोत्साहन राशि हॉकी इण्डिया के समारोह में प्रदान की गई. हॉकी के अन्य विभिन्न टूर्नामेन्ट्स जीतने वाली टीमों को भी खेल मंत्री मनसुख मांडविया व खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से की उपस्थिति में पुरस्कार समारोह में प्रदान किए गए. श्री जफर इकबाल को **हॉकी इण्डिया का सर्वोच्च मेजर ध्यानचन्द लाइफटाइम : एचीवमेंट पुरस्कार दिया गया.** इस पुरस्कार के तहत् ₹ 25 लाख की राशि उन्हें प्रदान की गई.

वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार भारतीय टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह को तीसरी बार तथा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार फॉरवर्ड नवनीत कौर को दिया गया. बलवीर सिंह सीनियर ट्रॉफी के साथ ₹ 20-20 लाख की राशि इस पुरस्कार के तहत् इन्हें प्रदान की गई. अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष अम्पायर नामित किए जाने के लिए रघु प्रसाद आर.वी. को भी पुरस्कार इस समारोह में दिया गया.



सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार लेते हुए हार्दिक सिंह



सर्वोच्च महिला खिलाड़ी का पुरस्कार लेती हुई नवनीत कौर

हॉकी इण्डिया के वर्ष 2025 के प्रमुख पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है–

मेजर ध्यानचन्द लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार (₹ 25 लाख)–जफर इकबाल.

वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार (₹ 20 लाख) –हार्दिक सिंह

वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार (₹ 20 लाख) –नवनीत कौर

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान पुरुष खिलाड़ी (Upcoming Player of the Year) का जुगराज सिंह पुरस्कार (Under 21 पुरुष) (₹ 10 लाख)—प्रिंस दीप सिंह

वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी (Upcoming Player of the Year) का असुंता लाक्रा पुरस्कार (Under 21 महिला) (₹ 10 लाख)—साक्षी राणा

वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर (बलजीत सिंह पुरस्कार ₹ 5 लाख)—बिछू देवी खारिबान

डिफेंडर ऑफ द ईयर (परगट सिंह पुरस्कार) (₹ 5 लाख)—संजय

मिड फील्डर ऑफ द ईयर (अजित पाल सिंह पुरस्कार) (₹ 5 लाख)—सुमित

फॉरवर्ड ऑफ द ईयर (धनराज पिल्लई पुरस्कार) (₹ 5 लाख)—सुखजीत सिंह

विश्व व्यापार संगठन का द्विवार्षिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कैमरून में याउंडे (Yaounde) में 26-29 मार्च, 2026 को सम्पन्न हुआ. विश्व व्यापार संगठन का यह सर्वोच्च नीति निर्धारक सम्मेलन 2-2 वर्ष के अन्तराल पर होता है. ऐसा पिछला 13वाँ सम्मेलन 26 फरवरी-2 मार्च, 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी में हुआ था. संगठन के सभी 166 सदस्य देशों के व्यापार मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी इस नीति निर्धारक सम्मेलन में भाग लेते हैं.

याउंडे में कैमरून के व्यापार मंत्री ल्यूक मैग्लायर म्बार्गा अतांगाना (Luc Magloire Mbarga Atangana) की अध्यक्षता में सम्पन्न इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया. सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में भाग लेने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे. डब्ल्यूटीओ का यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका-इजरायल व ईरान के बीच युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर संकट व अनिश्चितता के बादल छाए हुए थे. व्यापार संगठन में सुधार, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में अनियमिताएँ, खाद्य सुरक्षा के नाम पर कृषिगत उत्पादन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी, मत्स्य पालन सब्सिडी तथा किसानों व मछुआरों की आजीविका की सुरक्षा आदि इस सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख मुद्दे थे.

निधन
(Death)

अयातुल्लाह अली खामनेई

अयातुल्लाह अली खामनेई एक ईरानी राजनीतिज्ञ शिया धर्मगुरु थे. 1981 से 1989 तक ईरान के तीसरे राष्ट्रपति रहने के पश्चात् 1989 से 28 फरवरी, 2026 तक 36 वर्ष से अधिक समय तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे, खामनेई 2026 के ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान पहले ही दिन 28 फरवरी, 2026 को अमेरिकी हमले का शिकार बने. एक सर्वोच्च नेता के रूप में, खामनेई इस्लामी गणराज्य में सबसे शक्तिशाली राजनेता थे. वह ईरान के राष्ट्राध्यक्ष होने के साथ-साथ सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ भी थे. वह ईरान में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विदेश नीति और राष्ट्रीय नियोजन जैसे कई क्षेत्रों में सरकार की मुख्य नीतियों पर अंतिम निर्णय ले सकते थे. सर्वोच्च नेता के रूप में, खामनेई का सरकार की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के साथ-साथ सैन्य और मीडिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण था. उनके शासन काल में अमेरिका के साथ ईरान के कट्टर शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहे थे. अमेरिका व इजरायल के कट्टर विरोधी रहे खामनेई ने इजरायली-फिलिस्तीनी संघर्ष में हमास का तथा रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस का ही पक्ष लिया था.



अयातुल्लाह अली खामनेई

उनके निधन के पश्चात् विश्वभर में शियाओं ने शोक प्रदर्शित किया तथा युद्ध के बीच ही ईरान में 7 दिन का सार्वजनिक अवकाश व 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया.

उनके निधन के पश्चात् उनके ही पुत्र मोजतबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया है.

एच. के. दुआ

वरिष्ठ पत्रकार, राजनयिक व राज्य सभा के पूर्व मनोनीत सदस्य तथा दो प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी व एच. डी. देवगौड़ा के मीडिया सलाहकार रहे हरि कृष्ण दुआ का 88 वर्ष की आयु में 4 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में निधन हो गया. 1987 से 1994 तक हिन्दुस्तान टाइम्स, 1994 से 1996 तक इंडियन एक्सप्रेस तथा 2003-09 के दौरान 'द ट्रिब्यून' के सम्पादक वह रहे थे. 2001 से 2003 तक डेनमार्क में भारत के राजदूत तथा 2009 से 2015 तक राज्य सभा के मनोनीत सदस्य भी वह रहे थे. इससे पूर्व 1998 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था. पंजाब विश्वविद्यालय व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने डी. लिट. की मानद उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया था.

टी. के. ओम्मन

पद्मभूषण से सम्मानित अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाजशास्त्री टी. के. ओम्मन (T. K. Oommen) जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय व जेएनयू में अध्यापन के पश्चात् प्रोफेसर एमेरिट्स के रूप में सेवाएँ दी तथा जो अनेक स्वदेशी विश्वविद्यालयों में भी विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, का 26 फरवरी, 2026 को 88 वर्ष की आयु में गुरुग्राम (हरियाणा) में निधन हो गया. भूदान आन्दोलन पर उनका शोध कार्य काफी महत्वपूर्ण रहा था. समाजशास्त्र से सम्बन्धित अनेक पुस्तकों के रचयिता टी.के. ओम्मन इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन (ISA) के प्रेजीडेंट भी रहे थे

वर्ष/दिवस/सप्ताह
(Year/Days/Week)

मार्च 2026

3 मार्च—विश्व वन्यजीव दिवस

(संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रति वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने का फैसला 20 दिसम्बर, 2013 को अपने 68वें सत्र में किया था.)

4 मार्च—राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस (National Safety Day)

(कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने तथा दुर्घटनाओं से बचाव के लिए)

7 मार्च—जन औषधि दिवस

8 मार्च—अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

9 मार्च—राष्ट्रमण्डल दिवस (मार्च का दूसरा सोमवार)

12 मार्च—मॉरिशस दिवस (मॉरिशस का स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस)

14 मार्च—पाई (π) दिवस

15 मार्च—विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

16 मार्च—राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस

18 मार्च—आयुध कारखाना दिवस (ऑर्डनेन्स फैक्ट्री दिवस)

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

20 मार्च—अन्तर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस (संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 28 जून, 2012 को स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर 20 मार्च को 'इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पिनेस' के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है.)

20 मार्च—विश्व गौरैया दिवस

21 मार्च—विश्व वन दिवस

(प्रति वर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 नवम्बर, 2012 को पारित किया था.)

22 मार्च—बिहार दिवस

(1912 ई. में 22 मार्च को बंगाल प्रेसीडेंसी के विभाजन के परिणामस्वरूप बिहार एक पृथक् राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था.)

22 मार्च—विश्व जल दिवस

23 मार्च—भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु का बलिदान दिवस

23 मार्च—पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस

(23 मार्च, 1940 को ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन में लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसने बाद में पाकिस्तान के गठन के लिए आधार प्रदान किया. **स्वतंत्र पाकिस्तान का पहला संविधान भी बाद में 1956 में 23 मार्च को ही अंगीकृत किया गया था.**)

23 मार्च—विश्व मौसम विज्ञान दिवस

24 मार्च—विश्व क्षय रोग दिवस

26 मार्च—बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस व राष्ट्रीय दिवस

(बांग्लादेश की पाकिस्तान से मुक्ति यद्यपि 16 दिसम्बर, 1971 को हुई थी, इसके राष्ट्रपिता शेख मुजीब उर रहमान ने देश की स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च, 1971 को ही कर दी थी. **इस उपलक्ष्य में 26 मार्च को ही देश के स्वतंत्रता दिवस व राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है.**)

27 मार्च—विश्व रंगमंच दिवस

28 मार्च—अर्थ-ऑवर

(मार्च का अंतिम शनिवार, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन रात्रि 8.30 बजे से 9.30 बजे तक सभी गैर-जरूरी लाइटों व विद्युत् उपकरणों को बंद रखा जाता है.)

30 मार्च—राजस्थान स्थापना दिवस

(तत्कालीन राजपूताना रियासतों के विलय के फलस्वरूप राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च, 1949 को हुई थी.)

पुस्तकें (Books)

क्रिमसन स्प्रिंग (Crimson Spring)
—नवतेज सरना

इट्स ईजी टु बी हैल्दी (It's Eazy to be Healthy)
—मलाइका अरोरा

एन एक्सीडेन्टल लॉयर (An Accidental Lawyer)
—के.के. वेणुगोपाल

दुर्घटना (Accident)

बोलीविया में बैंक नोट ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त

द. अमेरिका के बोलीविया (Bolivia) में एल आल्टो (El-Alto) शहर में वायु सेना का एक हरक्युलिस C-30 विमान 27 फरवरी, 2026 को खराब मौसम में लैंडिंग के दौरान रन वे से फिसल कर पास की व्यस्त सड़क पर जा गिरा जहाँ अनेक कारें भी इसकी चपेट में आ गईं. सेना का यह विमान सेन्ट्रल बैंक से नए छपे हुए 12 टन नोटों के बंडल ले जा रहा था. इस दुर्घटना में कम-से-कम 25 लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई तथा विमान से गिरे नोट सड़क पर इधर-उधर फैल गए. इन्हें लूटने के लिए लोगों की भीड़ भी सड़क पर जमा हो गई. नोटों को बचाने के लिए पानी की बौछारों व आँसू गैस का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा.

भारतीय वायु सेना का सुखोई 30 एमकेआई विमान दुर्घटनाग्रस्त : दोनों चालकों की मृत्यु

भारतीय वायु सेना का एक सुखोई SU-30MKI लड़ाकू विमान असम के पहाड़ी कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में 5 मार्च, 2026 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया. असम के जोरहट से एक प्रशिक्षण अभियान पर उड़ान के दौरान पहाड़ी क्षेत्र में इस विमान के लापता होने का पता चला. बाद में जोरहट से 60 किमी दूर विमान के अवशेष पाए गए. विमान के दोनों चालक स्क्वाड्रन लीडर अनुज तथा फ्लाइट लेफ्टि. पुरवेश दुरागर इस दुर्घटना में मारे गए.

2000 के पहले दशक में ही भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया रूस निर्मित SU-30MKI विमान वायु सेना के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में माना जाता है. भारतीय वायु सेना की रीढ़ कहे जाने वाले ऐसे लगभग एक दर्जन विमान दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं. 5 मार्च, 2026 को हुई ताजा दुर्घटना से पूर्व 4 जून, 2024 को नासिक में एक SU-30MKI दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तथा इससे पूर्व 28 जनवरी, 2023 को ग्वालियर के निकट एक SU-30MKI तथा एक मिराज-2000 आकाश में ही आपस में टकरा गए थे.

कोलंबिया में सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त : 50 से अधिक सैनिकों की मृत्यु

कोलंबिया में सेना का एक हरक्युलिस सी-130 विमान 23 मार्च को उस समय दुर्घटना का शिकार हुआ जब चालक दल के 11 सदस्यों सहित अन्य को लेकर इसने प्युर्टो लेगुइजामो (Puerto Leguizamo) से उड़ान भरी ही थी. यह स्थान कोलंबिया के दक्षिणी अमेजन क्षेत्र में पेरू की सीमा के निकट स्थित है. इस दुर्घटना में 66 लोगों की मृत्यु की बात प्रारम्भिक जानकारी में कही गई है, यद्यपि अपुष्ट सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या अधिक सम्भावित है.

सम्मेलन (Conferences)

जी-7 विदेश मंत्रियों का सम्मेलन

विश्व के औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न 7 देशों के अन्तर्सरकारी समूह G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक फ्रांस के अबाये डेस-वॉक्स-डी-केर्ने (Abbaye des Vaux-de-Carnay) शहर में 26-27 मार्च, 2026 को हुई. जी-7 के सदस्य देशों—अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान व कनाडा के विदेश मंत्रियों के अतिरिक्त भारत, सऊदी अरब, द. कोरिया, ब्राजील व केन्या के विदेश मंत्री भी विशेष आमंत्रितों के रूप में शामिल रहे. जी-7 विदेश मंत्रियों की यह बैठक जून 2026 में फ्रांस में एवियन (Evian) में होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में आयोजित की गई थी. रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में ईरानी हमलों से उत्पन्न स्थिति, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी नियंत्रण व वैकल्पिक समुद्री मार्ग आदि मुद्दों पर चर्चा भी सम्मेलन में हुई.

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कुछ विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी सम्मेलन से इतर सम्पन्न की.

विविध (Miscellaneous)

स्टीडफास्ट डार्ट (2026)

यह 'नाटो' (NATO) का एक वृहद सैन्याभ्यास है, जो इस वर्ष फरवरी 2026 में मुख्य रूप से जर्मनी व बाल्टिक सागर में सम्पन्न हुआ. अमेरिका इस वर्ष इसमें शामिल नहीं था. यूरोप के 13 देशों के लगभग 10 हजार सैनिक इस वर्ष के इस युद्धाभ्यास में शामिल थे.

ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा

अमेरिका व इजरायल तथा ईरान के बीच भीषण युद्ध के बीच समुद्री हमलों के साथ-साथ

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने तथा केवल मित्र राष्ट्रों के लिए ही मार्ग खोलने के दौर में भारत ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से तेल व गैस से भरे अपने टैंकर्स को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकालने के लिए चलाए गए नौसैनिक मिशन को 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा' नाम दिया गया था.

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, दिल्ली

दिल्ली को राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक व फिल्मी गतिविधियों का भी केन्द्र बनाने के उद्देश्य से वहाँ पहले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFD-2026) का आयोजन 25-31 मार्च, 2026 को हुआ. इसका मुख्य केन्द्र भारत मंडपम था जहाँ 25 मार्च को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया. दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा आयोजित इस महोत्सव में ओलिवर लक्से द्वारा निर्देशित फिल्म सिरात (Sirat) उद्घाटन फिल्म थी (इस फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में ज्यूरी का विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ था). एक सप्ताह तक चले इस महोत्सव में 47 देशों की 147 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन विभिन्न केन्द्रों पर किया गया.

भारतीय व अन्तर्राष्ट्रीय फीचर फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन व हाइब्रिड फॉर्मेट इनमें शामिल थीं. गुरुदत्त की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 'प्यासा' सहित अनेक पुरानी फिल्मों के रिस्टोर्ड प्रिंट स्क्रीन पर दिखाए गए, अनेक चर्चाएँ, स्क्रीनिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव के तहत् आयोजित किए गए. भारतीय सिनेमा के भविष्य, ओटीटी (OTT) के प्रभाव व फिल्म निर्माण की बारीकियों पर चर्चा महोत्सव में हुई. अनुपम खेर, विकी कौशल, सुभाष घई, सान्या मल्होत्रा, अरविंद स्वामी, हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर, कंगना रनौत, नंदामुरी बालकृष्ण, बोमन इरानी, आदिल हुसैन, मनोज बाजपेयी, आमिर खान, मधुर भंडारकर, शेखर कपूर व भूमि पेडनेकर आदि ने महोत्सव के उद्घाटन समारोह/विभिन्न सत्रों में उपस्थिति दर्ज की. फिल्म जगत की तीन हस्तियों—नंदामुरी बालकृष्ण, शर्मिला टैगोर व धर्मेन्द्र (मरणोपरांत) को लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार इस महोत्सव में प्रदान किया गया. आयोजकों के अनुसार, यह महोत्सव केवल फिल्में दिखाने तक सीमित नहीं था, यह दिल्ली को वैश्विक सिनेमा का केन्द्र बनाने का प्रयास था.

वज्र प्रहार 2026 : भारतीय सेना व अमेरिकी सैन्य विशेष बल का संयुक्त अभ्सास

भारतीय सेना व अमेरिकी सैन्य विशेष बल (Special Forces Exercise) के संयुक्त अभ्यास 'वज्र प्रहार' का 16वाँ संस्करण हिमाचल प्रदेश में बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण विद्यालय में 24 फरवरी-16 मार्च, 2026 को सम्पन्न हुआ. भारत व अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक रणनीतियों के आदान-प्रदान को सुदृढ़ इस अभ्यास के तहत् किया गया. भारतीय सेना के विशेष बल की टुकड़ी में 45 जवान तथा अमेरिकी विशेष बलों के 12 जवान इस संयुक्त अभ्यास में शामिल थे. इस संयुक्त अभ्यास का पिछला 15वाँ संस्करण अमेरिका में इडाहो (Idaho) में नवम्बर 2024 में सम्पन्न हुआ था.

संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन-2026 : भारतीय सेना व जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स का सैन्याभ्यास

भारतीय सेना व जापान की ग्राउंड सेल्फ फोर्स (JGSDF) के बीच दो सप्ताह के वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का सातवाँ संस्करण उत्तराखण्ड में चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केन्द्र में 24 फरवरी-9 मार्च, 2026 को सम्पन्न हुआ. दोनों पक्षों के 120-120 सदस्यों का दल इस संयुक्त अभ्यास में शामिल था. सामरिक गतिविधियों का संयुक्त अभ्यास इस संस्करण के तहत् किया गया.

धर्म गार्जियन भारत व जापान के सैन्य बलों के बीच होने वाला एक वार्षिक सैन्याभ्यास है. वर्ष 2018 में शुरू हुए इस सैन्याभ्यास का आयोजन वैकल्पिक रूप से भारत व जापान में किया जाता है. इसका पिछला छठवाँ संस्करण जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में 24 फरवरी-9 मार्च, 2025 को सम्पन्न हुआ था. उससे पूर्व इसका पाँचवाँ संस्करण भारत में राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी-9 मार्च, 2024 व चौथा संस्करण जापान में शिगा प्रान्त में 17 फरवरी-2 मार्च, 2023 को सम्पन्न हुआ था.

भारत व सेशेल्स का संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये-2026

भारत व सेशेल्स के सशस्त्र बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये (Lamitiye) 2026 सेशेल्स रक्षा अकादमी में 9-20 मार्च, 2026 को सम्पन्न हुआ. लामितिये, क्रियोल (सेशेल्स की भाषा) भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ मित्रता है. यह 2001 से शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वाँ संस्करण था जिसमें सेना के तीनों अंग शामिल थे.

ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अभ्यास ककाडू- 2026 में भारत की भागीदारी

*ऑस्ट्रेलिया का बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास **ककाडू (Kakadu) 2026** सिडनी के तट पर मार्च 2026 में सम्पन्न हुआ. कई देशों के नौसैनिक पोत इसमें शामिल रहे. भारत की ओर से नौसेना के आधुनिक युद्धपोत आईएनएस नीलगिरि ने इसमें भाग लिया.*

इस नौसैनिक अभ्यास के साथ ही 21 मार्च को सम्पन्न 'इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू' में भी आईएनएस नीलगिरि शामिल रहा. ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की स्थापना के 125वें वर्ष में आयोजित इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में लगभग 20 देशों के 30 से अधिक युद्धपोत शामिल थे.



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



खेलकूद

बैडमिन्टन

भारत के लक्ष्य सेन दूसरी बार ऑल इंग्लैण्ड ओपन बैडमिन्टन खिताब से चूके

भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन बर्मिंघम (इंग्लैण्ड) में 3-8 मार्च, 2026 को सम्पन्न ऑल इंग्लैण्ड ओपन बैडमिन्टन में फाइनल में पराजित होकर खिताब से चूक गए. 8 मार्च को इस टूर्नामेन्ट में फाइनल में उनका मुकाबला ताइवान (चीनी ताइपे) के लिन चुन-यी (Lin Chun-yi) से था, जिसमें 15-21, 20-22 से पराजय का मुँह उन्हें देखना पड़ा. **यह दूसरा अवसर था, जब ऑल इंग्लैण्ड ओपन बैडमिन्टन में फाइनल में पराजित होकर खिताब से वह चूक गए. इससे पूर्व 2022 में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन के हाथों पराजय का मुँह उन्हें फाइनल में देखना पड़ा था.**

इस टूर्नामेन्ट का महिलाओं का एकल खिताब चीन की वांग झीयी (Wang Zhiyi) ने फाइनल में द. कोरिया की आन से यंग को हराकर जीता.

डब्ल्यूबीएफ के लेवल 1000 के इस टूर्नामेन्ट का पुरुषों का युगल किम वोन हो तथा सियो सिंयुग-जाए की द. कोरियाई जोड़ी ने तथा महिला युगल लियु शेंगशू व तान निंग की चीनी जोड़ी ने जीता, जबकि मिश्रित युगल खिताब ये होंग बी व निकाले गोंजालेस चान की चीनी ताइपे की जोड़ी के नाम रहा.

क्रिकेट

जम्मू-कश्मीर टीम ने पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का सत्र 2025-26 का रणजी ट्रॉफी टूर्नामेन्ट अक्टूबर 2025-मार्च 2026 के दौरान विभिन्न शहरों में खेला गया विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों की कुल 38 टीमें इस टूर्नामेन्ट में शामिल थीं जिनमें फाइनल मुकाबला जम्मू-कश्मीर व कर्नाटक की टीमों के बीच हुआ. 8 मार्च, 2026 को हुबली (कर्नाटक) में खेले गए फाइनल में जम्मू-कश्मीर की टीम ने कर्नाटक को पहली पारी की बढ़त के आधार पर हराकर जीतने में सफलता प्राप्त की. **जम्मू-कश्मीर टीम ने पहली बार ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप की यह ट्रॉफी अपने नाम की है, जबकि उपविजेता कर्नाटक टीम इससे पूर्व 8 बार इस ट्रॉफी की विजेता रह चुकी है.**

पारस डोगरा की कप्तानी वाली जम्मू-कश्मीर टीम ने डी. आर. बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम (केएससीए नाम से भी चर्चित) हुबली (कर्नाटक) में खेले गए फाइनल मैच में पहली पारी में 584 रन बनाने के बाद कर्नाटक टीम को 293 रन पर ही समेट कर 291 रनों की बढ़त प्राप्त कर ली थी. इसी बढ़त के आधार पर ड्रॉ रहे मैच में जम्मू-कश्मीर को विजेता घोषित किया गया. जम्मू-कश्मीर टीम ने पहली बार यह ट्रॉफी जीती है. **पिछले 2024-25 सत्र में विदर्भ टीम इस टूर्नामेन्ट में विजेता रही थी.**



ट्रॉफी के साथ जम्मू-कश्मीर की टीम

अक्टूबर 2025 से शुरू हुए इस टूर्नामेन्ट में कुल 38 टीमें शामिल थीं. जम्मू-कश्मीर टीम के आकिब नबी ने सर्वाधिक 60 विकेट टूर्नामेन्ट में लिए. उन्हें ही **'प्लेयर ऑफ द सीरिज'** घोषित किया गया. टूर्नामेन्ट में सर्वाधिक 950 रन कर्नाटक के रविचन्द्रन स्मारन ने बनाए. **इस खिताबी जीत के लिए ₹ 5 करोड़ की राशि जम्मू-कश्मीर टीम को बीसीसीआई द्वारा दी गई. उपविजेता कर्नाटक को ₹ 3 करोड़ मिले.** जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अलग से ₹ 2 करोड़ के इनाम की घोषणा जम्मू-कश्मीर टीम के लिए की.

भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट शृंखलाएँ (2025-26)

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के विरुद्ध 1 टेस्ट मैच, 3 टी-20 व 3 ही एकदिवसीय मैचों की शृंखलाएँ खेलने के लिए भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा फरवरी-मार्च 2026 को किया. इनमें पहले 15-21 फरवरी को खेली गई टी-20 मैचों की शृंखला भारतीय टीम ने 2-1 से जीती, जबकि 24 फरवरी-1 मार्च के दौरान खेली गई एकदिवसीय मैचों की शृंखला ऑस्ट्रेलिया के नाम रही.

अन्त में एकमात्र टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6-8 मार्च को 3 दिन में ही जीत लिया.

इन तीनों ही शृंखलाओं में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी.

पाकिस्तान के विरुद्ध एकदिवसीय मैचों की शृंखला बांग्लादेश ने 2-1 से जीती

बांग्लादेश के दौरे पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने मेजबान टीम के विरुद्ध तीन एकदिवसीय मैचों की शृंखला मार्च 2026 में खेली. इस शृंखला के तीनों मैच मीरपुर में खेले गए थे. उनमें दूसरा मैच ही पाकिस्तानी टीम ने जीता. शृंखला का पहला व तीसरा मैच जीतकर बांग्लादेश ने यह शृंखला 2-1 से जीती. **11 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् बांग्लादेश की पाकिस्तान के विरुद्ध यह ओडीआई शृंखला विजय थी.**

दक्षिण अफ्रीका-न्यूजीलैण्ड टी-20 शृंखला, 2026

मेजबान टीम के विरुद्ध 5 टी-20 मैचों की शृंखला खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैण्ड का दौरा मार्च 2026 में किया. इस शृंखला का दूसरा व तीसरा मैच न्यूजीलैण्ड ने जीता, जबकि शेष तीनों मैच जीत कर दक्षिण अफ्रीका ने यह शृंखला 3-2 से जीती.

भारत की अरुंधति फरवरी 2026 के लिए आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी

फरवरी 2026 में भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला टी-20 शृंखला में शानदार गेंदबाजी के लिए भारत की अरुंधति रेड्डी को अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) ने अपने मासिक पुरस्कारों के तहत् फरवरी 2026 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया है. भारत-ऑस्ट्रेलिया की सन्दर्भित टी-20 शृंखला में अरुंधति रेड्डी ने अच्छे औसत के साथ सर्वाधिक 8 विकेट लिए थे, जिसके चलते भारत ने यह शृंखला 2-1 से जीती थी, जो 2016 के पश्चात् भारत की महिला टीम की ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहली टी-20 शृंखला विजय थी.



अरुंधति रेड्डी

आईसीसी के मासिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार पाने वाली अरुंधति रेड्डी भारत की पाँचवीं महिला खिलाड़ी हैं. इनमें पूर्व यह पुरस्कार भारत की 4 महिला क्रिकेटरों—हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना (दो बार) व शेफाली वर्मा को मिल चुका है.

फरवरी 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का आईसीसी का पुरस्कार साहिब जादा फरहान (पाकिस्तान) को दिया गया है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

आईसीसी द्वारा जनवरी 2021 में शुरू किया गया यह पुरस्कार पुरुष व महिला खिलाड़ियों सहित भारत के कुल 15 खिलाड़ियों को 21 बार दिया जा चुका है.

पुरुष	महिला
ऋषभ पंत (जनवरी 2021)	हरमनप्रीत कौर (सितम्बर 2022)
रविचन्द्रन आश्विन (फरवरी 2021)	दीप्ति शर्मा (दिसम्बर 2023)
भुवनेश्वर कुमार (मार्च 2021)	स्मृति मंधाना (जून 2024)
श्रेयस अय्यर (फरवरी 2022)	स्मृति मंधाना (सितम्बर 2025)
विराट कोहली (अक्टूबर 2022)	शेफाली वर्मा (नवम्बर 2025)
शुभमन गिल (जनवरी 2023)	अरुंधति रेड्डी (फरवरी 2026)
शुभमन गिल (सितम्बर 2023)	
यशस्वी जायसवाल (फरवरी 2024)	
जसप्रीत बुमराह (जून 2024)	
जसप्रीत बुमराह (दिसम्बर 2024)	
शुभमन गिल (फरवरी 2025)	
श्रेयस अय्यर (मार्च 2025)	
शुभमन गिल (जुलाई 2025)	
मोहम्मद सिराज (अगस्त 2025)	
अभिषेक शर्मा (सितम्बर 2025)	



मुम्बई के आरव डेंगला व गुवाहाटी के मयंक चक्रवर्ती भारत के क्रमश: 93वें व 94वें ग्रांड मास्टर

दिल्ली के 21 वर्षीय आर्यन वार्ष्णेय के बाद मुम्बई के 17 वर्षीय आरव डेंगला (Aarav Dengla) भी जनवरी 2026 में ही ग्रांड मास्टर खिताब की सभी आवश्यकताएँ पूरी करके भारत के 93वें ग्रांड मास्टर (GM) बन गए थे. ग्रांड मास्टर खिताब के लिए आरव ने पहला ग्रांड मास्टर नॉर्म 2022 में बिजेलजिना (बोस्निया व हर्जेगोविना) में व दूसरा नॉर्म 2025 में क्रोएशिया में उन्होंने हासिल किया था. जनवरी 2026 में बिजेलजिना में ही तीसरा जीएम नॉर्म व 2500 की आवश्यक रेटिंग प्राप्त करके ग्रांड मास्टर खिताब आरव ने हासिल कर लिया.

आरव डेंगला की इस उपलब्धि के पश्चात् गुवाहाटी के 17 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती ने भी अपना तीसरा ग्रांड मास्टर नॉर्म व 2500 से अधिक की आवश्यक रेटिंग 14 मार्च, 2026 को स्वीडन में एक टूर्नामेन्ट में हासिल की. इसके साथ ही ग्रांड मास्टर खिताब की आवश्यकताओं को उन्होंने पूरा कर लिया.

वर्ष 2026 में ग्रांड मास्टर खिताब हासिल करने वाले आरव डेंगला व मयंक चक्रवर्ती आर्यन वार्ष्णेय के बाद क्रमश: दूसरे व तीसरे खिलाड़ी हैं.



इंडियन ओपन (2026)

मुम्बई में मार्च 2026 में सम्पन्न इंडियन ओपन स्क्वैश (2026) में पुरुष व महिला वर्ग के खिताब भारतीय खिलाड़ियों ने ही जीते. महिला वर्ग में अपने 16वें पीएसए (प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन) खिताब के लिए भारत की अनाहत सिंह ने 22 मार्च को मिस्र की हाना मोअताज (Hana Moataz) को फाइनल में पराजित किया.

पुरुषों के एकल खिताब के लिए भारत के अभय सिंह ने फाइनल में अपने देश के बीर चोंटरानी को पराजित किया.



न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में गुलवीर सिंह का नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ तीसरा स्थान

न्यूयॉर्क सिटी में 15 मार्च, 2026 को सम्पन्न हाफ मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में भारत के लम्बी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया. 21·1 किमी की यह दौड़ 59 मिनट 42 सेकण्ड में पूरी करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी गुलवीर सिंह ने स्थापित किया. हाफ मैराथन में इससे पूर्व राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1 घण्टा 30 सेकण्ड का था, जो अविनाश सांबले ने दिल्ली में 2020 में हाफ मैराथन में बनाया था.


गुलवीर सिंह

न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में पुरुष वर्ग में दक्षिण अफ्रीका के आड्रियान वाइल्डस्कट (Adriaan Wildschutt) 59 मिनट 30 सेकण्ड में दौड़ पूरी करके पहले स्थान पर रहे, जबकि 59 मिनट 41 सेकण्ड के साथ मोरक्को मूल के अमेरिकन जूहेयर तालबी (Zouhair Talbi) का दूसरा स्थान रहा. **तालबी ने गुलवीर सिंह से केवल एक सेकण्ड पहले दौड़ पूरी करके दूसरा स्थान प्राप्त किया.**

ज्ञातव्य है कि लम्बी दूरी की 5000 मीटर व 10,000 मीटर की दौड़ों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड पहले ही गुलवीर सिंह के नाम है.

डुप्लांटिस का पोल वाल्ट में 15वीं बार विश्व रिकॉर्ड

स्वीडिश-अमेरिकन पोल वाल्टर अर्मांड डुप्लांटिस, जिन्हें मोंडो डुप्लांटिस (Mondo Duplantis) नाम से भी जाना जाता है, ने 13 मार्च, 2026 को स्वीडन में एक एथलेटिक्स मीट में पोल वाल्ट में 6·31 मी की छलाँग लगाकर अपने ही विश्व रिकॉर्ड में सुधार किया. 2 बार के ओलम्पिक चैम्पियन (2020, 2024), 3 बार विश्व आउटडोर एथलेटिक्स चैम्पियन (2022, 2023 व 2025) तथा 4 बार के विश्व इनडोर एथलेटिक्स चैम्पियन (2022, 2024, 2025 व 2026) डुप्लांटिस ने 15वीं बार पोल वाल्ट का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है.



मोंडो डुप्लांटिस

पहली राष्ट्रीय इनडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (2026)

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) के तत्वावधान में पहली राष्ट्रीय इनडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप भुवनेश्वर में 24-25 मार्च, 2026 को सम्पन्न हुई. पुरुष व महिला एथलीट्स के लिए 11-11 इनडोर स्पर्द्धाएँ इसमें शामिल थीं. 97 महिला एथलीट्स सहित 278 से अधिक एथलीट्स ने इनमें भाग लिया तथा 8 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनमें बने.

पुरुषों की 60 मीटर दौड़ नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ गुरिंदरवीर सिंह ने जहाँ जीती, महिलाओं की इस दौड़ में महाराष्ट्र की हरिता भद्रा विजेता रहीं.

सभी 11 स्पर्द्धाओं में विजेताओं के नाम तालिका में दर्शाए गए हैं. (तुलना के लिए वर्ल्ड इनडोर एथलेटिक्स में इन्हीं स्पर्द्धाओं के विजेताओं के नाम व उनके प्रदर्शन समय/दूरी भी दूसरी तालिका में प्रस्तुत हैं).

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

पहली राष्ट्रीय इनडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (2026)
(24-25) मार्च, 2026, भुवनेश्वर)
विभिन्न स्पर्द्धाओं के विजेता

	पुरुष वर्ग		महिला वर्ग	
60 मीटर	गुरिंदरवीर सिंह (रिलायंस)	6·60*	हरिता भद्रा (महाराष्ट्र)	7·32
400 मीटर	मोहम्मद सिनान (रिलायंस)	48·27	सलोनी नागर (उत्तर प्रदेश)	53·73*
800 मीटर	मोहम्मद अफसल (एयरफोर्स)	1:47·86*	प्रीति यादव (मध्य प्रदेश)	2:11:83
1500 मीटर	विनोद सिंह (मध्य प्रदेश)	3:46·13	प्रियंका सी (कर्नाटक)	4:34:31
3000 मीटर	शिवाजी परशुराम (रिलायंस)	8:09·88	प्रियंका सी (कर्नाटक)	9:42:05
60 मीटर बाधा	क्रिशिक एम (कर्नाटक)	7·71	अंजलि सी (केरल)	8·32
ऊँची कूद	स्वाधीन कुमार मांझी (ओडिशा)	2·18 मीटर*	पायल जामोड (गुजरात)	1·71 मीटर
लम्बी कूद	सरुन पाया सिंह (ओडिशा)	7·80 मीटर	अनामिका के.ए. (जेएसडब्ल्यू)	6·05 मीटर
तिहरी कूद	विमल मुकेश (नौसेना)	15·41 मीटर	मलाला अनुषा (जेएसडब्ल्यू)	13·20 मीटर
शॉट पुट	रवि कुमार (बीएसएफ)	17·17 मीटर	रेखा (NCOE, पटियाला)	15·63 मीटर
पोल वाल्ट	रीगान जी. (तमिलनाडु)	5·30 मीटर*	बरानिका इलानगोवान (तमिलनाडु)	4·22 मीटर*

(21वीं) वर्ल्ड इनडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (2026)
(20-22 मार्च, 2026, टॉरुन, पोलैण्ड)
विभिन्न स्पर्द्धाओं के विजेता

	पुरुष वर्ग		महिला वर्ग	
60 मीटर	जॉर्डन एंथनी (अमेरिका)	6·41	जायनब डोस्सो (इटली)	7·0
400 मीटर	क्रिस्टोफर विलियम्स (कनाडा)	44·76	लुडैस ग्लोरिया मैन्युएल (चैक गणराज्य)	50·76
800 मीटर	कूपर लुटकेन्हास (अमेरिका)	1:44:24	कीली हॉडकिसन (ब्रिटेन)	1:55·30
1500 मीटर	मारियानो गार्सिया (स्पेन)	3:39·63	जॉर्जिया हंटर बैल (ब्रिटेन)	3:58·53
3000 मीटर	जोशकैर (ब्रिटेन)	7:35·56	नाडिया बोडोक्लेफ्टि (इटली)	8:57·64
60 मीटर बाधा	जेकब जिमांस्की (पोलैण्ड)	7·40	देव्यने चार्टन (बहामास)	7·65**
4×400 मीटर	अमेरिकन टीम	3 : 01·52	अमेरिकन टीम	3:25·81
ऊँची कूद	ओलेह डोरोश्चुक (यूक्रेन)	2·30 मीटर	यारोस्लावा माहुचिख (यूक्रेन)	2·01 मीटर
लम्बी कूद	गेर्सन बाल्डे (पुर्तगाल)	8·46 मीटर	अगाटे डि सूसा (पुर्तगाल)	6·92 मीटर
तिहरी कूद	एंडी डियाज (इटली)	17·47 मीटर	लेयानिस पेरेज (क्यूबा)	14·95 मीटर
शॉट पुट	टॉम वाल्श (न्यूजीलैण्ड)	21·82 मीटर	चेस जैक्सन (अमेरिका)	20·14 मीटर
पोल वाल्ट	अर्मांड डुप्लांटिस (स्वीडन)	6·25 मीटर	मॉली कॉडेरी (ब्रिटेन)	4·85 मीटर
हेप्टाथलन	साइमन एहैमर (स्विट्जरलैण्ड)	6670 अंक**		
पेंटाथलन	—		सोफी डोक्टेर (नीदरलैण्ड्स)	4888 अंक

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

वर्ल्ड इनडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (2026)

21वीं विश्व इनडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप पोलैण्ड में टॉरुन (Torun) में 20-22 मार्च, 2026 को सम्पन्न हुई. 118 देशों के 674 एथलीट इस आयोजन में 27 विभिन्न स्पर्द्धाओं में शामिल थे. भारत का कोई एथलीट इस बार इस आयोजन में शामिल नहीं था. **3 दिन तक चले इस आयोजन में 60 मीटर की दौड़ पुरुष वर्ग में अमेरिका के जॉर्डन एंथनी ने व महिला वर्ग में इटली की जायनाब डोस्सो ने जीतीं. यह दौड़ पूरी करने में क्रमशः 6·41 सेकण्ड व 7·00 सेकण्ड इन धावकों ने लिए.** इस चैम्पियनशिप में पुरुषों में पोल वाल्ट खिताब स्वीडिश-अमेरिकन आर्मंड डुप्लांटिस ने 6·27 मीटर की छलाँग के साथ जीता. पुरुषों के पोल वाल्ट में पहली बार पहले तीन स्थानों पर रहे तीनों एथलीट्स ने 6-6 मीटर से अधिक की छलाँग लगाई. 5 स्वर्ण, 7 रजत व 6 कांस्य सहित कुल 18 पदक जीत कर अमेरिका ने इस मीट की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया जबकि 4 स्वर्ण के साथ ब्रिटेन का दूसरा तथा 3 स्वर्ण व 2 रजत सहित कुल 5 पदकों के साथ इटली का तीसरा स्थान रहा. 32 देश कोई न कोई पदक जीतने में सफल रहे.

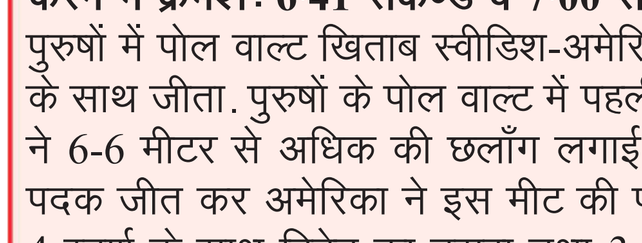
पदक तालिका में पहले 10 राष्ट्र

रैंक	राष्ट्र	स्वर्ण	रजत	कांस्य	योग
1	अमेरिका	5	7	6	18
2	ब्रिटेन	4	0	0	4
3	इटली	3	2	0	5
4	पुर्तगाल	2	1	0	3
5	यूक्रेन	2	1	0	3
6	स्पेन	1	2	2	5
7	नीदरलैण्ड्स	1	2	1	4
8	बेल्जियम	1	2	0	3
9	पोलैण्ड	1	1	2	4
10	स्विट्जरलैण्ड	1	1	1	3
	—	—	—	—	—
	योग (कुल 32 राष्ट्र)	**27**	**29**	**29**	**85**

वर्ल्ड इनडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन 2-2 वर्ष के अन्तराल पर होता है. इसके आगामी 22वें संस्करण का आयोजन भारत में भुवनेश्वर में होगा.

आगामी विश्व इनडोर एथलेटिक्स (2026) का आयोजन भारत में

आगामी (22वीं) विश्व इनडोर एथलेटिक्स (2028) की मेजबानी भारत को सौंपी गई है. इस आशय का निर्णय वर्ष 2026 की 21वीं विश्व इनडोर एथलेटिक्स के आयोजन से पूर्व वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल की पोलैण्ड में टॉरुन (Torun) में 19 मार्च को सम्पन्न बैठक में लिया गया. भारत में यह स्पर्द्धाएं भुवनेश्वर में आयोजित होंगी. वर्ष 2028 की विश्व इनडोर एथलेटिक्स की मेजबानी के लिए एथलेटिक्स फेडेरशन ऑफ इंडिया (AFI) ने दावेदारी इस वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रस्तुत की थी. भारत को यह मेजबानी मिलने को एएफआई ने अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय एथलेटिक्स के बढ़ते कद का संकेत बताया है.



इण्डियन वेल्स ओपन (बीएनपी परिबास ओपन)–2026

एटीपी व डब्ल्यूटीए के लेवल 1000 का इण्डियन वेल्स ओपन, जिसे बीएनपी परिबास ओपन टूर्नामेन्ट भी कहा जाता है, कैलीफॉर्निया में 4-15 मार्च, 2026 को सम्पन्न हुआ. इसमें पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः यानिक सिनर (Jannik Sinner) व आर्यना सबालेंका ने जीते. इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने फाइनल मुकाबले में रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराकर पुरुषों का एकल खिताब जहाँ जीता वहीं महिलाओं के एकल खिताब के लिए कजाखस्तान की एलेना रिबाकिना को फाइनल में बेलारूस की आर्यना सबालेंका (Aryna Sabalenka) ने हराया.


यानिक सिनर

इस प्रतिष्ठित टूर्नामेन्ट का पुरुषों का युगल खिताब गुइडो आन्द्रेयोजी (अर्जेन्टीना) व मैन्युएल गिनार्ड (फ्रांस) की जोड़ी ने तथा महिलाओं का युगल कैटेरिना सिनियाकोवा (चैक गणराज्य) व टेलर टाउनसैंड (अमेरिका) की जोड़ी ने जहाँ जीता वहीं मिश्रित युगल बेलिंडा बेनसिक (स्विट्जरलैण्ड) व फ्लेवियो कोबोली (इटली) की जोड़ी के नाम रहा.


आर्यना सबालेंका

सीनियर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय टेबल टेनिस चैम्पियनशिप (2026)

इंदौर में 14-21 मार्च, 2026 को सम्पन्न 87वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में पुरुष व महिला वर्ग के टीम खिताब क्रमशः पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (PSPB) व भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जीते.

पुरुष वर्ग में टीम खिताब के लिए पीएसपीबी ने फाइनल मुकाबले में पश्चिम बंगाल को 3-0 से पराजित किया, जबकि महिला वर्ग का टीम खिताब आरबीआई ने फाइनल में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (PSPB) को 3-2 से पराजित किया.

इंडियन वेल्स ओपन (बीएनपी परिबास ओपन) 2026 (4-15 मार्च, 2026 (इंडियन वेल्स, कैलीफॉर्निया, अमेरिका) विजेता एवं उपविजेता

पुरुष एकल	**विजेता**	यानिक सिनर (इटली)
	उपविजेता	डेनिल मेदवेदेव (रूस)
महिला एकल	**विजेता**	आर्यना सबालेंका (बेलारूस)
	उपविजेता	एलेना रिबाकिना (कजाखस्तान)
पुरुष युगल	**विजेता**	गुइडो आन्द्रेयोजी (अर्जेन्टीना) व मैन्युएल गिनार्ड (फ्रांस)
	उपविजेता	आर्थर रिंडरकनेक (फ्रांस) व वैलेंटिन वाचेरोट (मोनाको)
महिला युगल	**विजेता**	कैटेरिना सिनियाकोवा (चैक गणराज्य) व टेलर टाउनसैंड (अमेरिका)
	उपविजेता	अन्ना डानिलिना (कजाखस्तान) व अलेक्सांद्रा क्रूनिक (सर्बिया)
मिश्रित युगल	**विजेता**	बेलिंडा बेनसिक (स्विट्जरलैण्ड) व फ्लेवियो कोबोली (इटली)
	उपविजेता	गैब्रिएला डाब्रोव्स्की (कनाडा) व लॉयड ग्लासपूल (ब्रिटेन)

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

87वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय टेबल टेनिस चैम्पियनशिप (2026) (14-21 मार्च, 2026 इन्दौर) विजेता एवं उपविजेता

पुरुष एकल	विजेता उपविजेता	मानव ठक्कर (पीएसपीबी) जीत चन्द्रा (रेलवे)
महिला एकल	विजेता उपविजेता	यशस्विनी घोरपडे (पीएससीबी) सिंड्रेला दास (पीएससीबी)
पुरुष युगल	विजेता उपविजेता	जीत चंद्रा व अनिर्बान घोस (दोनों रेलवे) रोनित भांजा व प्रेयेश राज सुरेश (दोनों रेलवे)
महिला युगल	विजेता उपविजेता	सुतीर्थ मुखर्जी व कॉशानी नाथ (दोनों रेलवे) अविशा कर्माकर व नंदिनी साहा (एयरपोर्ट अथॉरिटी)
मिश्रित युगल	विजेता उपविजेता	अंकुर भट्टाचारजी (पश्चिम बंगाल) व सुहाना सेनी (हरियाणा) अनिकेत बोस व सम्प्रीति रॉय (दोनों पश्चिम बंगाल)
टीम खिताब		
पुरुष वर्ग	विजेता उपविजेता	पीएसपीबी पश्चिम बंगाल
महिला वर्ग	विजेता उपविजेता	आरबीआई पीएसपीबी

वैयक्तिक मुकाबलों में भी पुरुष वर्ग में पीएसपीबी के खिलाड़ियों का ही दबदबा रहा. **पुरुषों के एकल खिताब** के लिए 'पीएसपीबी' के मानव ठक्कर ने फाइनल में रेलवे के जीत चन्द्रा को हराया, जबकि **महिलाओं का एकल** खिताब पीएसपीबी की ही यशस्विनी घोरपडे ने फाइनल में अपने ही संस्थान की सिंड्रेला दास को हराकर अपने नाम किया. **मानव ठक्कर व यशस्विनी के यह पहले ही राष्ट्रीय खिताब है.**

इस चैम्पियनशिप में **पुरुषों के युगल** खिताब के लिए फाइनल मुकाबला रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (RSPB) के खिलाड़ियों के ही बीच रहा. इस मुकाबले में जीत चन्द्रा व अनिर्बान घोष की रेलवे की जोड़ी ने रोनित भांजा व प्रेयेश राज सुरेश की जोड़ी को फाइनल में हराया.

महिलाओं का युगल खिताब सुतीर्थ मुखर्जी व कौशानी नाथ की रेलवे की जोड़ी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की अविशा कर्माकर व नंदिनी साहा की जोड़ी को फाइनल में हरा कर जीता, जबकि **मिश्रित युगल खिताब** अंकुर भट्टाचारजी (पश्चिम बंगाल) व सुहाना सेनी (हरियाणा) की जोड़ी ने अनिकेत बोस व सम्प्रीति रॉय की पश्चिम बंगाल की जोड़ी को फाइनल में हराकर अपने नाम किया.

दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैम्पियनशिप (2026)

दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैम्पियनशिप (2026) के पुरुष वर्ग के मुकाबले दुबई में 23-28 फरवरी को सम्पन्न हुए. एटीपी के लेवल-500 के इस टूर्नामेन्ट में एकल खिताब रूस के डेनिल मेदवेदेव ने फाइनल में नीदरलैण्ड्स के टेल्लोन ग्रीकस्पूर के वाक ओवर के चलते जीता. इस टूर्नामेन्ट के युगल खिताब के लिए हैरी हेलियोवारा (फिनलैण्ड) व हेनरी पैटन (ब्रिटेन) ने मार्सेलो एरेवालो (एल सेल्वेडोर) व मेट पैविक (क्रोएशिया) को फाइनल में पराजित किया.

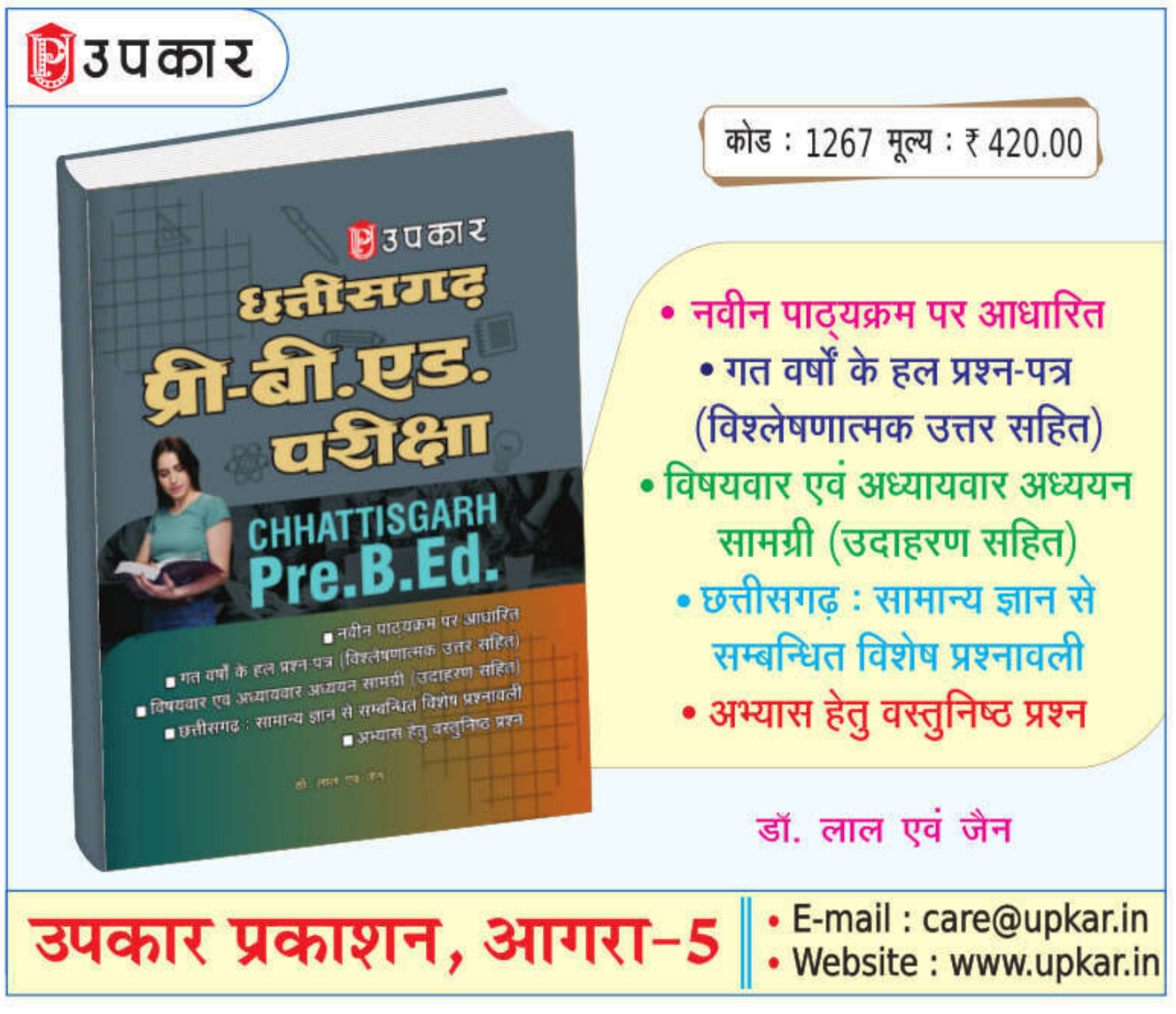


मार्च 2026 में तीन फॉर्मूला-1 रेसों (ऑस्ट्रेलियाई, चीनी व जापानी ग्रांड प्रिक्स) का आयोजन

वर्ष 2026 की पहली तीन फॉर्मूला-1 रेसों का आयोजन मार्च माह में हुआ. इनमें वर्ष की पहली ऑस्ट्रेलियाई ग्रा. प्रि, दूसरी चीनी ग्रांड प्रिक्स तथा तीसरी जापानी ग्रांड प्रिक्स शामिल थीं. 8 मार्च को मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई रेस में मर्सिडीज टीम के ब्रिटिश चालक जार्ज रसेल विजेता रहे, जबकि मर्सिडीज के ही इटेलियन चालक एके एंटोनेलि का इसमें दूसरा स्थान रहा.

15 मार्च को शंघाई में चीनी ग्रांड प्रिक्स में इसका विपरीत परिणाम रहा. चीनी ग्रांड प्रिक्स में एके एंटोनेलि व जार्ज रसेल क्रमशः विजेता व उपविजेता रहे.

मार्च 2026 की तीसरी फॉर्मूला-1 रेस जापानी ग्रां प्रि. थी, 29 मार्च को सुजुका सर्किट में आयोजित इस रेस में पहला व दूसरा स्थान क्रमशः एके एंटोनेलि व ऑस्कर पियास्त्री ने प्राप्त किया. ●●●



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) का टी-20 मैचों का 10वाँ विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेन्ट न्यूजीलैण्ड को 96 रन से फाइनल में हराकर गत विजेता भारत ने जीता है तथा लगातार दो बार व कुल मिलाकर तीन बार यह टूर्नामेन्ट जीतने वाला पहला देश भारत हो गया है.

इस टूर्नामेन्ट में भाग लेने वाले देशों की संख्या 20 थी जिनमें 2 देश (भारत व श्रीलंका) मेजबान होने के नाते टूर्नामेन्ट में जहाँ थे, वहीं 6 टीमें (अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैण्ड, द. अफ्रीका, अमेरिका व वेस्टइंडीज) पिछले 2024 के टूर्नामेन्ट में उच्च रैंक के आधार पर, 4 टीमें (आयरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान व स्कॉटलैण्ड) आईसीसी टी-20 रैंकिंग के आधार पर, 1 टीम (कनाडा) अमेरिका से, 2 यूरोप से (इटली व नीदरलैण्ड्स), 2 अफ्रीका से (नामीबिया व जिम्बाब्वे) तथा 3 टीमें एशिया-ईएपी से (नेपाल, ओमान व संयुक्त अरब अमीरात) क्वालीफायर के रूप में टूर्नामेन्ट में शामिल की गई थीं. (बांग्लादेश की टीम भी चयनित 20 टीमों में शामिल थी, किन्तु उसके द्वारा भाग लेने से इंकार करने के पश्चात् उसके स्थान पर अगली रैंक वाली टीम **स्कॉटलैण्ड को शामिल किया गया था. इनमें सुपर 8 दौर में पहुँचने वाली 8 टीमें—भारत, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज व दक्षिण अफ्रीका (ग्रुप ए) तथा पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैण्ड व न्यूजीलैण्ड (ग्रुप बी) थी, जबकि फाइनल में स्थान बनाने वाली 2 टीमें भारत व न्यूजीलैण्ड थीं.**

टी-20 विश्व कप 2026 के प्रमुख पुरस्कार (आईसीसी के प्रमुख पुरस्कार)		
विजेता टीम	भारत	(26 लाख डॉलर/लगभग ₹ 27·48 करोड़)
उपविजेता	न्यूजीलैण्ड	(14·23 लाख डॉलर/ लगभग ₹ 14·65 करोड़)
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेन्ट	संजू सैमसन (भारत)	
प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच	जसप्रीत बुमराह (भारत)	
टूर्नामेन्ट में सर्वाधिक रन	साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) (7 मैचों में 383 रन)	
टूर्नामेन्ट में सर्वाधिक विकेट	जसप्रीत बुमराह (भारत) व वरुण चक्रवर्ती (भारत) (14-14 विकेट)	

भारत व श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी-8 मार्च, 2026 के दौरान खेले गए इस प्रतिष्ठित टूर्नामेन्ट का फाइनल मैच भारत व न्यूजीलैण्ड के बीच अहमदाबाद स्थित नरेन्द्र मोदी अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 8 मार्च को खेला गया, जिसमें सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने 96 रन से विजय दर्ज कर अपनी धरती पर टी-20 विश्व चैम्पियन बनने वाली पहली टीम होने का गौरव भी प्राप्त किया. **भारत तीसरी बार आईसीसी टी-20 विश्व कप का विजेता बना है. इससे पूर्व 2007 में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर तथा 2024 में द. अफ्रीका को फाइनल में हराकर भारत टी-20 विश्व कप विजेता रहा था.** (आईसीसी विश्व कप में भारत का यह पाँचवाँ खिताब है. 2026 में टी-20 विश्व कप जीतने से पूर्व 2007 में महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी में तथा 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टी-20 विश्व कप भारत ने जीते थे, जबकि 1983 में कपिल देव की कप्तानी में तथा 2011 में महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी में एकदिवसीय क्रिकेट का विश्व कप भारत ने जीता था.)

8 मार्च को नरेन्द्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में 1 लाख से अधिक दर्शकों की उपस्थिति में पहले खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 255 रन भारतीय टीम ने बनाए तथा विजय के लिए 256 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैण्ड को दिया, किन्तु न्यूजीलैण्ड की पूरी टीम 19 ओवर में ही 159 रन बनाकर आउट हो गई. **भारतीय टीम की 255 रनों की पारी विश्व कप के किसी फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है.** इसमें सर्वाधिक 89 रनों का योगदान संजू सैमसन का, 54 रन का योगदान ईशान किशन का तथा 52 रन का योगदान अभिषेक शर्मा का रहा. सैमसन ने 89 रन 46 गेंदों पर 8 छक्कों व 5 चौकों की मदद से बनाए. **फाइनल मैच में न्यूजीलैण्ड के सर्वाधिक 4 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को 'प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच' का तथा लगातार 3 मैचों में 85 से अधिक रन बनाने वाले संजू सैमसन को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेन्ट' का पुरस्कार दिया गया.**



विजय के पश्चात् टीम का उल्लास

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

टी-20 विश्व कप 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी	रन/मैच	उच्चतम पारी
साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)	383/7	100
टिम सीफर्ट (न्यूजीलैण्ड)	326/9	89*
संजू सैमसन (भारत)	321/5	97*
ईशान किशन (भारत)	317/9	77
फिन एलेन (न्यूजीलैण्ड)	298/9	100*

सर्वोच्च व्यक्तिगत पारियाँ (सात शतकों सहित)

खिलाड़ी	पारी/गेंद	विरुद्ध
युवराज सामरा (कनाडा)	110/65	न्यूजीलैण्ड
जैकब बेथेल (इंग्लैण्ड)	105/48	भारत
फिन एलेन (न्यूजीलैण्ड)	100*/33	द. अफ्रीका
हैरी ब्रुक (इंग्लैण्ड)	100/51	पाकिस्तान
पथुम निसांका (श्रीलंका)	100*/52	ऑस्ट्रेलिया
साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)	100*/58	नामीबिया
साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)	100/60	श्रीलंका
संजू सैमसन (भारत)	97*/50	वेस्टइंडीज

सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज

खिलाड़ी	विकेट/मैच
जसप्रीत बुमराह (भारत)	14/8
वरुण चक्रवर्ती (भारत)	14/9
शैडली वान शाल्कविक (अमेरिका)	13/4
ब्लेसिंग मुजारबानी (जिम्बाब्वे)	13/6
आदिल रशीद (इंग्लैण्ड)	13/8

सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ी	छक्के/मैच
संजू सैमसन (भारत)	24/5
फिन एलेन (न्यूजीलैण्ड)	20/9
शिमरॉन हेटमेयर (वेस्टइंडीज)	19/7
साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)	18/7
ईशान किशन (भारत)	18/9

(इस विश्व कप में कुल रिकॉर्ड 780 छक्के लगे. इससे पूर्व 2024 में हुए टी-20 विश्व कप में कुल 517 छक्के लगे थे.)

30 दिन तक चले इस टूर्नामेन्ट में सर्वाधिक 383 रन पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने बनाए, जबकि सर्वाधिक 14-14 विकेट भारत के जसप्रीत बुमराह व वरुण चक्रवर्ती ने लिए. कुल 13·5 मिलियन डॉलर इनामी राशि के इस टूर्नामेन्ट में 26 लाख डॉलर की राशि विजेता टीम को तथा लगभग 14·23 लाख डॉलर की राशि उपविजेता टीम को पुरस्कारस्वरूप प्रदान की गई.

भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपनी ओर से भारतीय टीम व सपोर्टिंग स्टाफ के लिए ₹ 131 करोड़ के नकद पुरस्कार की घोषणा बाद में 10 मार्च को की. विभिन्न राज्य सरकारों व नियोक्ताओं ने भी अपने खिलाड़ियों के लिए अलग से पुरस्कार घोषित किए हैं. **विजेता भारतीय टीम को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है.**

आईसीसी की टीम ऑफ द टूर्नामेन्ट

इस विश्व कप में निष्पादन के आधार पर आईसीसी ने विश्व कप की जो टीम बाद में घोषित की है, उसमें द. अफ्रीका के एडन मरक्राम (Aiden Markram) को कप्तान बनाया गया है. भारत के चार खिलाड़ियों—संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या व जसप्रीत बुमराह को इसमें स्थान दिया गया है.

पूरी टीम इस प्रकार है—

साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान), संजू सैमसन (भारत, विकेट-कीपर), ईशान किशन (भारत), एडन मरक्राम (द. अफ्रीका, **कप्तान**) हार्दिक पांड्या (भारत), विल जैक्स (इंग्लैण्ड), जैसन होल्डर (वेस्टइंडीज), जसप्रीत बुमराह (भारत), लुंगी न्गीडी (द. अफ्रीका), आदिल रशीद (इंग्लैण्ड), ब्लेसिंग मुजारबानी (जिम्बाब्वे) तथा शैडली वान शाल्कविक (अमेरिका, 12वें खिलाड़ी).

टी-20 विश्व कप के विभिन्न आयोजन

क्र.	वर्ष	विजेता	उपविजेता
1.	2007	भारत	पाकिस्तान
2.	2009	पाकिस्तान	श्रीलंका
3.	2010	इंग्लैण्ड	ऑस्ट्रेलिया
4.	2012	वेस्टइंडीज	श्रीलंका
5.	2014	श्रीलंका	भारत
6.	2016	वेस्टइंडीज	इंग्लैण्ड
7.	2021	ऑस्ट्रेलिया	न्यूजीलैण्ड
8.	2022	इंग्लैण्ड	पाकिस्तान
9.	2024	भारत	द. अफ्रीका
10.	2026	भारत	न्यूजीलैण्ड

टी-20 के आगामी 11वें विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड की संयुक्त मेजबानी में 2028 में होगा.



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

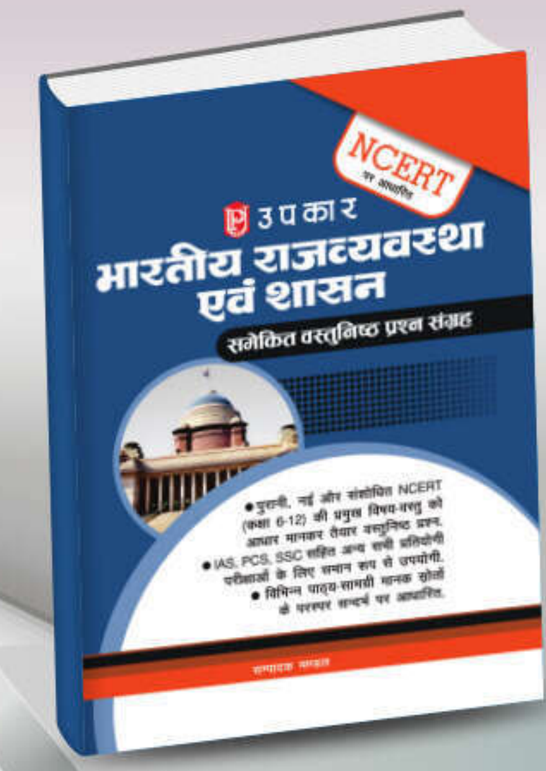
Fresh Arrivals

उपकार

NCERT

पर आधारित

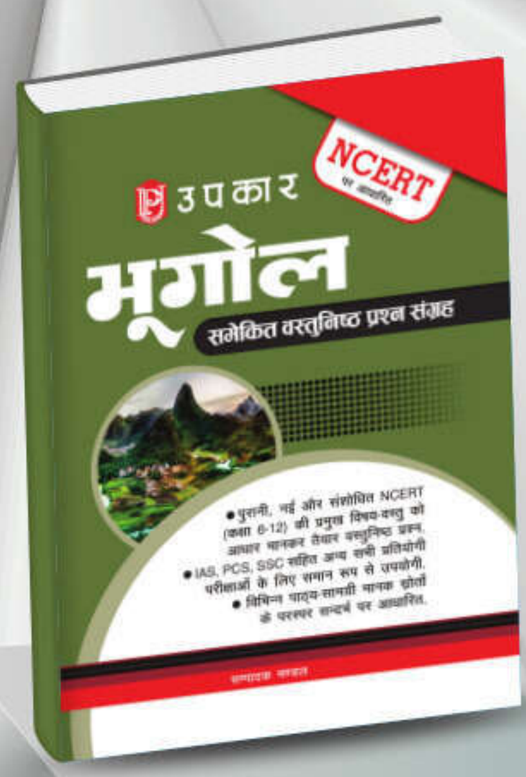
समेकित वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह



Code 2816 ₹ 135.00



Code 2813 ₹ 295.00



Code 2814 ₹ 299.00



Code 2817 ₹ 285.00



Code 2815 ₹ 90.00

मुख्य विशेषताएँ

- पुरानी, नई और संशोधित NCERT (कक्षा 6-12) की प्रमुख विषय-वस्तु को आधार मानकर तैयार वस्तुनिष्ठ प्रश्न.
- IAS, PCS, SSC सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी.
- विभिन्न पाठ्य-सामग्री मानक स्रोतों के परस्पर सन्दर्भ पर आधारित.

English Editions Also Available

उपकार प्रकाशन | 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास रोड, आगरा-282 005
फोन : (0562) 2530966, 2531101 • हल्द्वानी मो. 07060421008 | • E-mail : sales@upkar.in • Website : www.upkar.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



रोजगार समाचार

छत्तीसगढ़ में प्री.डी.एल.एड. (Pre. D.El. Ed.) प्रवेश परीक्षा 2026

छत्तीसगढ़ में विभिन्न विद्यालयों/संस्थानों में संचालित डी.एल.एड. (D. El. Ed.) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु प्री.डी.एल.एड. (Pre. D.El. Ed.) प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम), रायपुर द्वारा 4 जून, 2026 को सम्भावित है. परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर 13 अप्रैल, 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन कर सकते हैं. डी.एल.एड. (D. El. Ed.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन 4 जून, 2026 को अलग-अलग पारियों में राज्य के 33 विभिन्न जिला मुख्यालयों में प्रस्तावित है. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन-पत्र परिषद् की वेबसाइट पर आमंत्रित किए गए हैं. आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने की अन्तिम तिथि 13 अप्रैल, 2026 तथा आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार की अन्तिम तिथि 16 अप्रैल, 2026 तक है.

बिहार स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा-2026 (ITICAT, 2026)

बिहार राज्य में स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) में सत्र 2026-27 व 2026-28 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा-2026 (ITI Competitive Admission Test–ITI CAT 2026) का आयोजन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद द्वारा 17 मई, 2026 को प्रस्तावित है. प्रवेश में विभिन्न वर्गों के लिए नियमानुसार आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है. 300 अकों की वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्नों वाली प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में गणित, सामान्य विज्ञान व सामान्य ज्ञान के 2-2 अकों के 50-50 प्रश्न होंगे.

इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त, 2026 को न्यूनतम 14 वर्ष होनी चाहिए (मोटर व्हीकल मैकेनिक व ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए उक्त तिथि को 17 वर्ष की आयु अनिवार्य है), प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण 14 अप्रैल, 2026 तक कराना होगा, परीक्षा शुल्क नैट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड आदि के जरिए यह 15 अप्रैल, 2026 तक जमा कराया जा सकता है.

इस प्रवेश परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका (Prospectus) पर्षद की वेबसाइट : www.bceceboard.bihar.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं. इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश में सहायक बोरिंग तकनीशियन मुख्य परीक्षा-2025

उत्तर प्रदेश शासन के लघु सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग तकनीशियन के कुल 402 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उपर्युक्त परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा किया जाएगा. इस प्रतियोगिता परीक्षा में वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो आयोग की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2025 (PET-2025) में सम्मिलित हुए हैं तथा जिन्हें इसके लिए स्कोर कार्ड आयोग द्वारा जारी किया गया है.

इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग द्वारा 15 अप्रैल-5 मई, 2026 तक आमंत्रित किए गए हैं. विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता—हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में वांछित प्रमाण-पत्र/निर्दिष्ट ट्रेड्स में से किसी एक में आईटीआई पाठ्यक्रम (इन वांछित योग्यताओं की पूर्ण जानकारी के लिए विस्तृत विज्ञापन देखें).

आयु सीमा—(1 जुलाई, 2026 को) 18-40. वर्ष विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है.

इस भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के भाग-1 में सम्बन्धित ट्रेड सम्बन्धी (आधार सुरक्षा परिचय, इंजी-नियरिंग धातु, पदार्थ विज्ञान, चक्रीय गति आदि) 65 प्रश्न होंगे, जबकि भाग-2 में कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी 15 तथा भाग-3 में उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे. परीक्षा सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in देखें. आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन-पत्र इस वेबसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026

कक्षा एक से आठवीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता प्रदान करने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा 2, 3 व 4 जुलाई, 2026 को किया जाएगा. इस कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल होने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

ऑनलाइन आवेदन परीक्षा से सम्बन्धित वेबसाइट www.upessc.gov.in पर 26 अप्रैल, 2026 तक किए जा सकते हैं. परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु अंतिम तिथि भी 26 अप्रैल, 2026 है.

इस परीक्षा के तहत् पहला प्रश्न-पत्र उन उम्मीदवारों के लिए है, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के शिक्षक के रूप में पात्रता हासिल करना चाहते हैं, जबकि दूसरा प्रश्न-पत्र कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए शिक्षक की पात्रता के लिए है. उम्मीदवार किसी एक परीक्षा में या दोनों में शामिल हो सकते हैं. आवश्यक शैक्षणिक योग्यता धारक इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र हैं, प्राथमिक स्तर (I-V) के लिए UPTET की परीक्षा में बाल विकास तथा शिक्षण विधि (चाइल्ड डेवलपमेंट एण्ड पैडोगॉजी), भाषा प्रथम व भाषा द्वितीय, गणित व पर्यावरण अध्ययन के 30-30 बहुविकल्पीय प्रश्न (कुल 150 प्रश्न) होंगे. 150 अंकों की इस परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा. CTET द्वितीय प्रश्न-पत्र के लिए प्रश्न-पत्र में बाल विकास एवं शिक्षण विधि, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय के 30-30 अंकों के 30-30 प्रश्नों के साथ 60 अंकों का गणित एवं विज्ञान खण्ड (गणित/विज्ञान के शिक्षक के लिए) सामाजिक अध्ययन का खण्ड (सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए) शामिल होगा.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में बढ़ता चयापचय (Metabolic) रोगों का संकट

- हालिया 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज' (GBD) अध्ययन (1990-23) के अनुसार, भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चयापचय सम्बन्धी बीमारियों के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरा है.
- उल्लेखनीय है कि चयापचय रोग उन विकारों का समूह हैं, जो शरीर की ऊर्जा रूपान्तरण प्रक्रिया को बाधित करते हैं, जिनमें टाइप-2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप (Hypertension), मोटापा (उच्च BMI), उच्च LDL कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर (MASLD) प्रमुख हैं. ये रोग मुख्य रूप से गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) की श्रेणी में आते हैं.

प्रमुख चयापचय रोग

- **मधुमेह**—शरीर द्वारा शुगर को ठीक से अवशोषित न कर पाना.
- **मेटाबोलिक सिंड्रोम**—उच्च रक्त-चाप, उच्च रक्त शर्करा और पेट के आस-पास अतिरिक्त वसा का एक समूह.
- **थायरॉइड विकार**—हाइपोथायरायडिज्म (धीमा मेटाबॉलिज्म) या हाइपरथायरायडिज्म (तेज मेटाबॉलिज्म).
- **फेनिलकेटोनुरिया (PKU)**—एक दुर्लभ वंशानुगत विकार.
- **गॉउट (Gout)**—यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से जोड़ों में दर्द.

वर्तमान स्थिति और सांख्यिकीय आँकड़े

- अध्ययन के निष्कर्ष चिंताजनक हैं, क्योंकि भारत दिव्यांगता-समायोजित जीवन वर्ष (Disability-Adjusted Life Year–DALY) के मामले में चीन से भी आगे निकल गया है. गौरतलब है कि DALY रोग के समग्र बोझ को मापने की एक इकाई है, जो असमय मृत्यु के कारण खोए वर्षों (YLL) और दिव्यांगता के साथ जिए गए वर्षों (YLD) का योग है.
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में, भारत में मधुमेह के कारण लगभग 5·8 लाख और उच्च रक्तचाप के कारण 15·7 लाख मौतें दर्ज की गईं. जहाँ उच्च BMI और कोलेस्ट्रॉल में भारत वर्तमान में दूसरे स्थान पर है, वहीं मधुमेह और रक्तचाप

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित हालिया चर्चित प्रमुख शब्दावलियाँ

रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) तकनीक

- बढ़ती जनसंख्या और ताजे पानी के संकट के समाधान हेतु खारे पानी के विलवणीकरण (Desalination) को एक प्रमुख विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.
- उल्लेखनीय है कि रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) इस प्रक्रिया की सबसे प्रचलित विधि है, जिसका उपयोग खारे पानी को शुद्ध करने के अलावा फार्मा, बायोटेक, रेडियोधर्मी अपशिष्ट उपचार और खाद्य उद्योगों में भी किया जाता है. हालाँकि, यह तकनीक ऊर्जा-गहन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के कारण भारी मात्रा में CO_2 उत्सर्जन करती है.
- इसके अतिरिक्त, प्रक्रिया के दौरान निकलने वाला अत्यधिक सांद्रित खारा उप-उत्पाद समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और सूक्ष्म जीवों के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न करता है.

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)

- पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण कच्चे तेल और गैस की कीमतों में अस्थिरता उत्पन्न हुई है. इसका प्रभाव केवल ईंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के कपड़ा, खनन और इस्पात निर्माण जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों पर भी लागत के रूप में दबाव डाल रहा है.
- उल्लेखनीय है कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, जिसमें कम मात्रा में इथेन भी शामिल होती है. इसकी उच्च ऑक्टेन रेटिंग इसे स्पार्क-इग्निशन इंजनों के लिए एक आदर्श ईंधन बनाती है. एलपीजी की संरचना भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करती है; उदाहरण के तौर पर, ठण्डी जलवायु वाले देशों (जैसे—यूके) में 'प्रोपेन' की प्रधानता होती है, जबकि गर्म जलवायु वाले देशों में 'ब्यूटेन' का अधिक उपयोग किया जाता है. हालाँकि, यह शोधन प्रक्रियाओं और कच्चे तेल के गुणों के आधार पर भिन्न हो सकती है.

हेलियोसीस्मोलॉजी (Helioseismology) तकनीक

- नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी (SDO) उपग्रह से हेलियोसीस्मोलॉजी (Helioseismology) तकनीक का उपयोग कर सूर्य के आंतरिक भाग में चुम्बकीय गतिविधियों के नए साक्ष्य खोजे गए हैं.
- उल्लेखनीय है कि हेलियोसीस्मोलॉजी सूर्य की सतह पर होने वाले दोलनों और कम्पनों का अध्ययन करने की विधि है, जो सूर्य की आन्तरिक संरचना को समझने में मदद करती है; यह ठीक उसी प्रकार कार्य करती है, जैसे—भूकम्प विज्ञान (Seismology) पृथ्वी के आन्तरिक भाग का अध्ययन करता है. यह खोज सौर तूफानों और अन्तरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करने में सहायक होगी, जिससे उपग्रह संचार और पावर ग्रिड को सौर विकिरण के खतरों से सुरक्षित रखा जा सकेगा.

वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों (GNSS)

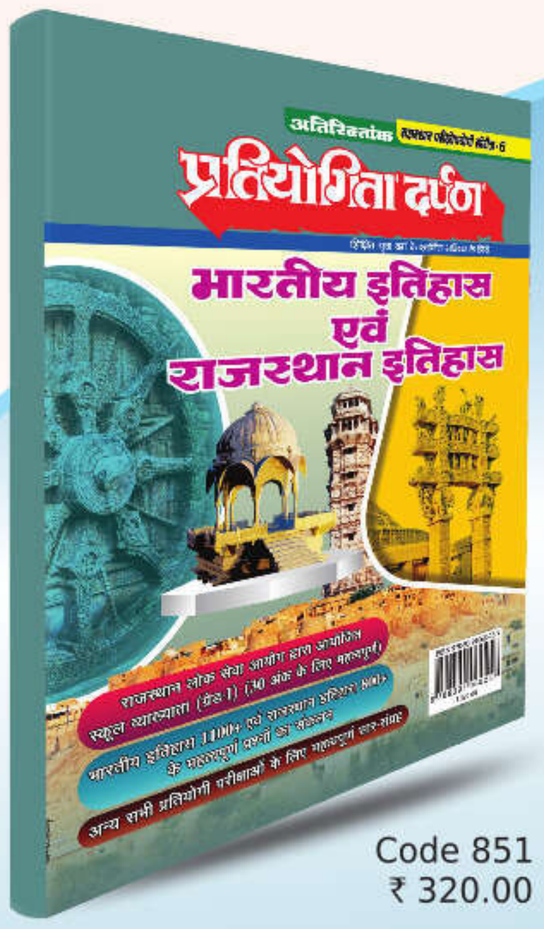
- वैश्विक स्तर पर जहाजों और विमानों की स्थिति, नेविगेशन और समय (PNT) सम्बन्धी जानकारी के लिए GNSS (जैसे—अमेरिका का GPS, भारत का NavIC, रूस का GLONASS) पर निर्भरता बढ़ी है.
- हालाँकि, हाल के दिनों में जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग जैसी साइबर चुनौतियों ने वैश्विक परिवहन सुरक्षा के लिए गम्भीर चिंताएँ भी पैदा की हैं.
- जीपीएस जैमिंग में जैमर द्वारा उसी आवृत्ति पर 'शोर' उत्पन्न कर वास्तविक संकेतों को दबा दिया जाता है, जिससे नेविगेशन बाधित हो जाता है, वहीं जीपीएस स्पूफिंग में फर्जी संकेतों के जरिए रिसीवर को गलत स्थान या ऊँचाई की जानकारी दी जाती है, जिससे पायलट या कप्तान भ्रमित होकर गलत निर्णय ले सकते हैं.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

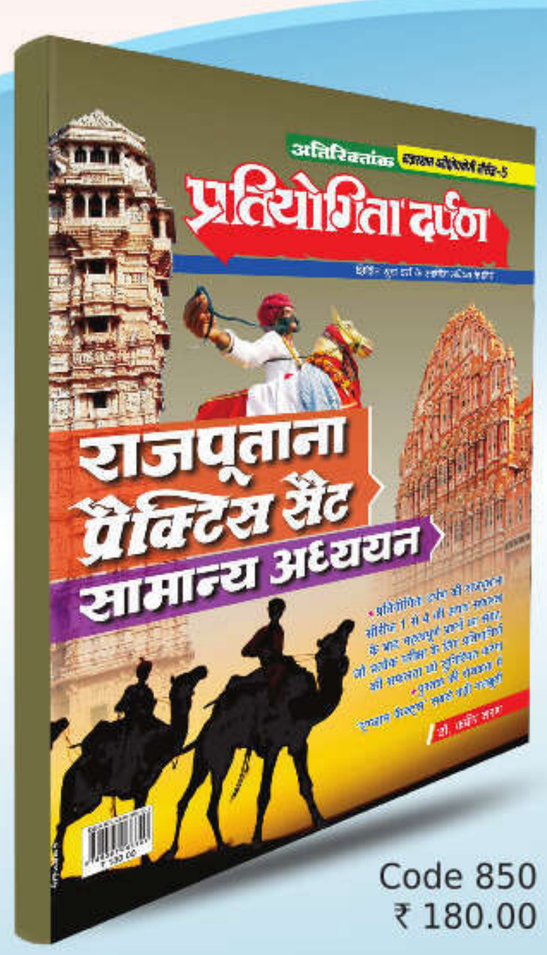
प्रतियोगिता दर्पण

भारतीय इतिहास एवं राजस्थान इतिहास

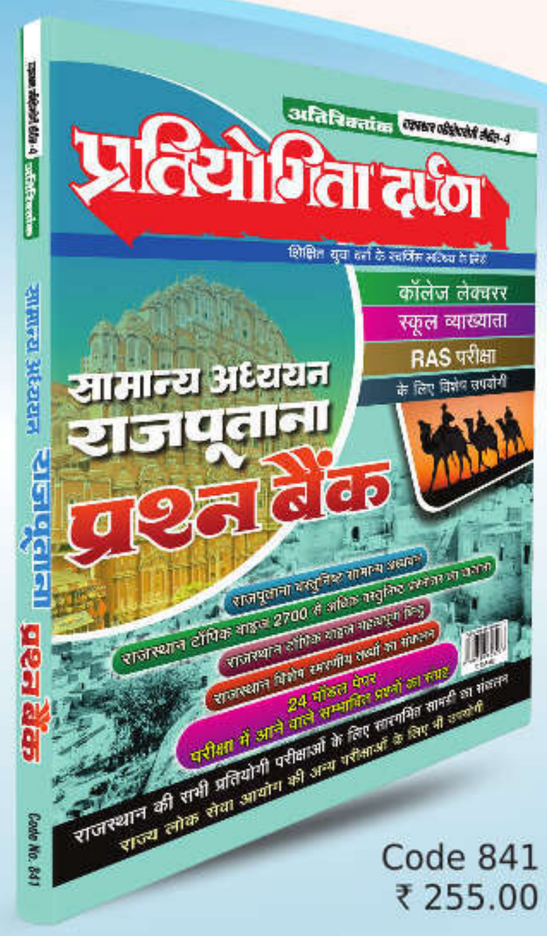




Code 851
₹ 320.00

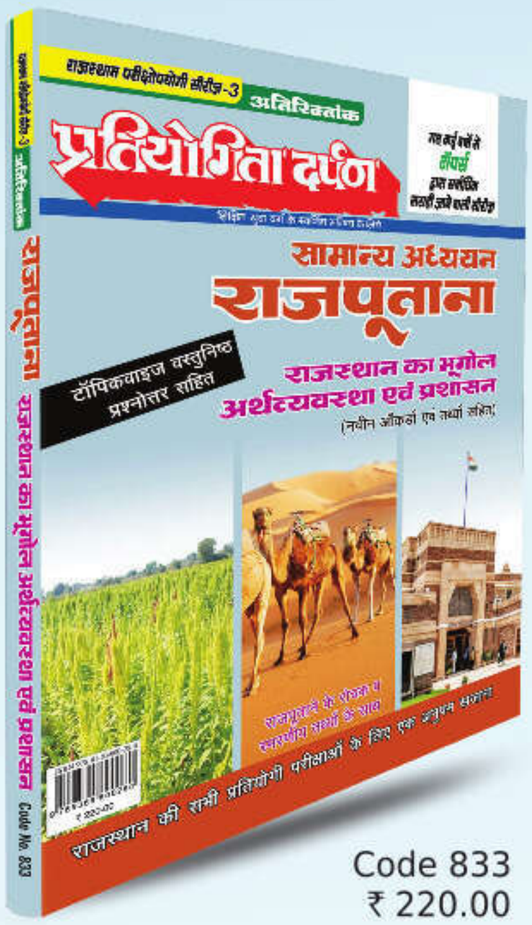


Code 850
₹ 180.00

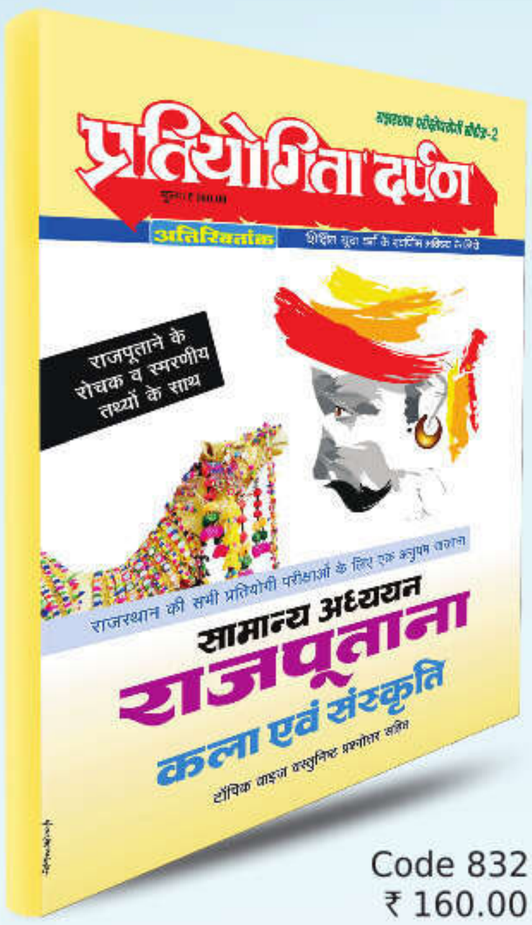


Code 841
₹ 255.00

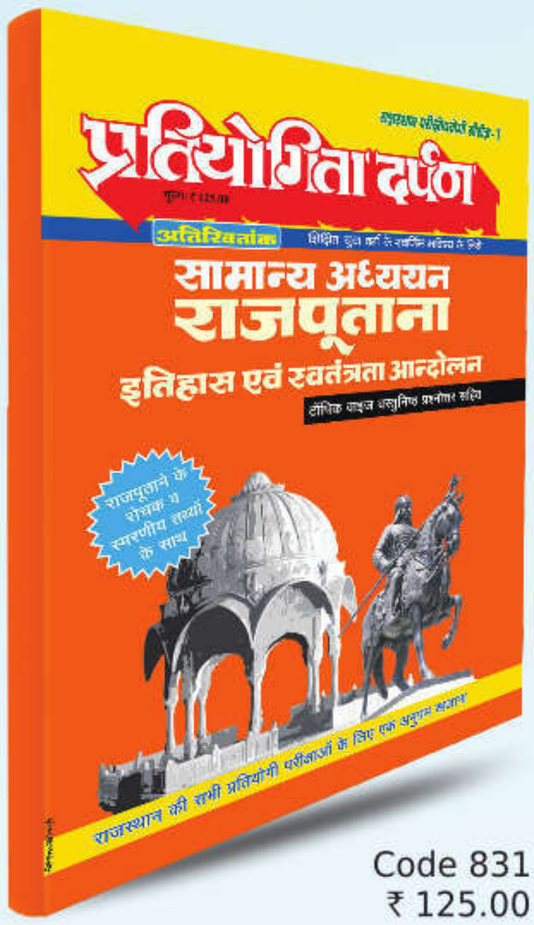
- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता (ग्रेड-I) (30 अंक के लिए महत्वपूर्ण)
- भारतीय इतिहास 1100+ एवं राजस्थान इतिहास 800+ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन
- अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सार-संग्रह
- प्रतियोगिता दर्पण की राजपूताना सीरीज में अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह, जो प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रतिभागियों की सफलता को सुनिश्चित करेगा
- पुस्तक की रोचकता में 'एग्जाम फैक्ट्स' सबसे बड़ी मजबूती



Code 833
₹ 220.00



Code 832
₹ 160.00



Code 831
₹ 125.00

प्रतियोगिता दर्पण | 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास रोड, आगरा-282 005
फोन : (0562) 2530966, 2531101 • हल्द्वानी मो. 07060421008 | • E-mail : sales@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

का कुल भार (Disease Burden) यहाँ सर्वाधिक है.

प्रमुख कारक एवं भविष्य की चुनौतियाँ

- इस संकट के पीछे तीव्र शहरीकरण, गतिहीन जीवनशैली, तनाव और अति-प्रसंस्कृत (Ultra-processed) खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन मुख्य कारण हैं. यदि वर्तमान रुझान जारी रहा, तो 2030 तक इन जोखिम कारकों में और भी भयावह वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे स्वास्थ्य प्रणालियों पर अत्यधिक वित्तीय दबाव पड़ेगा.

डाइमिथाइल ईथर (DME) : भारत की ऊर्जा सुरक्षा हेतु तकनीकी नवाचार

- हालिया पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक संकट और ऊर्जा आयात पर निर्भरता को देखते हुए, CSIR-राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (NCL), पुणे द्वारा विकसित डाइमिथाइल ईथर (DME) तकनीक भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण है.
- डाइमिथाइल ईथर (डीएमई) एक स्वच्छ और बहुमुखी ईंधन है, जिसे घरेलू स्तर पर उपलब्ध स्रोतों जैसे—कोयला, कृषि अपशिष्ट (बायोमास) और कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पादित किया जा सकता है. यह तकनीक न केवल आयात निर्भरता कम करने में सहायक है, बल्कि भारत के 'शुद्ध शून्य' (Net Zero) उत्सर्जन लक्ष्यों की प्राप्ति में भी पूरक है.

तकनीकी नवाचार और अनुप्रयोग

- CSIR-NCL ने एक विशिष्ट उत्प्रेरक और उन्नत इंजीनियरिंग डिजाइन विकसित किया है, जो मेथनॉल को कुशलतापूर्वक डीएमई में परिवर्तित करता है.



- डीएमई की सबसे बड़ी विशेषता इसकी LPG (तरल पेट्रोलियम गैस) के साथ मिश्रण क्षमता है. इसे मौजूदा एलपीजी स्टोव में बिना किसी बड़े बदलाव के इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे उपभोक्ता स्तर पर सुलभ बनाता है.
- यद्यपि वर्तमान में भारत मेथनॉल का आयात करता है, लेकिन भविष्य में स्वदेशी कोयला गैसीकरण और बायोमास के उपयोग से इसे पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है.

डाइमिथाइल ईथर (DME)

यह एक रंगहीन, गैर-संक्षारक और कम विषाक्त गैस है, जो दबाव में तरल बन जाती है. इसे LPG के साथ 20% तक मिलाया जा सकता है. इसकी तापीय क्षमता और कैलोरी मान पारम्परिक ईंधन के समान है. इसका उपयोग एरोसोल, विलायक और प्रशीतक (Refrigerant) के रूप में भी होता है.

उत्पादन प्रक्रिया

- डीएमई का उत्पादन मीथेन (CH_4) को आधार बनाकर किया जाता है. प्रक्रिया के तहत् मीथेन को पहले सिंथेटिक गैस ($CO+H_2$) में और फिर मेथनॉल में बदला जाता है, जो अंततः डीएमई में परिवर्तित होता है.
- यह बहु-चरणीय प्रक्रिया नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय दोनों स्रोतों के उपयोग की अनुमति देती है.

देश की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन

- प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के सानंद में देश की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है. यह अमेरिकी कम्पनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित यह संयंत्र 'इण्डिया सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM) के तहत् एक प्रमुख उपलब्धि है.
- गौरतलब है कि लगभग ₹ 22,516 करोड़ के निवेश से निर्मित यह सुविधा मुख्य रूप से DRAM (रैम टाइप), NAND उत्पाद और SSD (सॉलिड स्टेट ड्राइव) स्टोरेज डिवाइस का निर्माण करेगी, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं.

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)

- भारत सरकार ने दिसम्बर 2021 में 10 अरब डॉलर के वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी. इसका प्राथमिक उद्देश्य विनिर्माण, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) इकाइयों की स्थापना के लिए सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है. हालिया केन्द्रीय बजट 2026-27 में भी भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है.
- यह नया चरण न केवल आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने पर केन्द्रित है, बल्कि पूर्ण-स्टैक भारतीय बौद्धिक सम्पदा (IP) डिजाइन करने, उपकरणों के उत्पादन और उद्योग-नेतृत्व वाले अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से एक कुशल कार्यबल (Skilled Workforce) तैयार करने पर भी बल देता है.

भारत का राष्ट्रव्यापी एचपीवी (HPV) टीकाकरण अभियान

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 फरवरी, 2026 को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर (Cervical Cancer) की रोकथाम हेतु 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए एक व्यापक ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया.
- इस अभियान का उद्देश्य भारत में महिलाओं के बीच होने वाले दूसरे सबसे आम कैंसर के प्रसार को रोकना है. टीकाकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 'U-Win' पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, जो कोविड-19 के दौरान प्रयुक्त CoWIN प्लेटफॉर्म की तर्ज पर काम करेगा.

HPV और सर्वाइकल कैंसर

- ह्यूमन पैपिलोमावायरस 100 से अधिक वायरस का एक समूह है, जिनमें से कम-से-कम 14 प्रकार कैंसरकारी हैं. विशेष रूप से HPV 16 और 18 वैश्विक स्तर पर लगभग 70% सर्वाइकल कैंसर के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं.
- भारत में यह रोग प्रति वर्ष लगभग 1·25 लाख महिलाओं को प्रभावित करता है और करीब 75,000 मौतों का कारण बनता है. अध्ययनों के अनुसार, लगभग 85% सर्वाइकल कैंसर के मामलों का मूल कारण लगातार बना रहने वाला एचपीवी संक्रमण ही है.

टीकाकरण रणनीति और स्वदेशी विकास

- वर्तमान अभियान के तहत् सरकार ने MSD की 'गार्डसिल' (Gardasil) दवा की एकल खुराक (Single dose) उपचार पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया है.
- समानान्तर रूप से, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ICMR) स्वदेशी

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

रूप से विकसित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) की वैक्सीन 'सर्वावैक' (Cervavac) की एकल खुराक की प्रभावकारिता पर शोध कर रही है. स्वदेशी टीकों की उपलब्धता भविष्य में इस कार्यक्रम की लागत कम करने और व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने में गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

'मूनशॉट' परियोजना

- हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और प्रतीक्षा ट्रस्ट ने मिलकर 'मूनशॉट' नामक एक परियोजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क की कार्यक्षमता को सहारा देने वाले उन्नत 'ब्रेन को-प्रोसेसर' विकसित करना है.
- यह तकनीक विशेष रूप से उन लोगों के लिए आशा की किरण है, जो स्ट्रोक या अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण अपने शरीर के अंगों पर नियंत्रण खो चुके हैं.
- यह परियोजना दो तरह के उपकरणों पर काम कर रही है—एक जिन्हें सर्जरी के जरिए शरीर के अन्दर लगाया जा सकता है और दूसरे जिन्हें बिना किसी ऑपरेशन के शरीर के बाहर से ही इस्तेमाल किया जा सकता है.
- ये ब्रेन को-प्रोसेसर साधारण उपकरणों से अलग हैं, क्योंकि ये 'द्विदिशीय' या बिडायरेक्शनल तरीके से काम करते हैं. इसका मतलब है कि ये न केवल मस्तिष्क से निकलने वाले संकेतों को पढ़ते और समझते हैं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से उन्हें संसाधित करके वापस मस्तिष्क तक भेजते हैं.
- उल्लेखनीय है कि पुराने उपकरण सिर्फ दिमाग की बातें सुनने तक सीमित थे, वहीं ये नए को-प्रोसेसर मस्तिष्क की सोचने, समझने, ध्यान लगाने और निर्णय लेने जैसी जटिल प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाते हैं.
- इस तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के हाथों की गतिविधियों को फिर से सामान्य बनाना है, ताकि वे चीजों को पकड़ने और हिलाने में सक्षम हो सके. इसके साथ ही, इस परियोजना में 'नॉन-इनवेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन' (NIBS) तकनीक पर भी जोर दिया गया है. इसमें सिर की त्वचा पर इलेक्ट्रोड या चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करके बिना किसी चीर-फाड़ के मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है.
- टीएमएस (TMS) और टीडीसीएस (tDCS) जैसी पद्धतियों के माध्यम से मानसिक रोगों और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों का इलाज सम्भव हो सकेगा.

भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने 'हरीश राणा *बनाम* भारत संघ' वाद में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 12 वर्षों से 'वेजिटेटिव स्टेट' (चेतनाहीन अवस्था) में पड़े एक मरीज की जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दी. न्यायालय ने 'मरीज के सर्वोत्तम हित के सिद्धान्त' (Best Interest of the Patient Principle) का पालन करते हुए 30 दिनों की अनिवार्य विचार अवधि (Cooling-off period) की शर्त को भी शिथिल कर दिया, क्योंकि मेडिकल बोर्ड और परिवार दोनों ही ठीक होने की किसी भी सम्भावना से असहमत थे.

इच्छामृत्यु के प्रकार और कानूनी प्रावधान

भारत में इच्छामृत्यु के दो मुख्य आयामों पर न्यायिक स्पष्टता दी गई है—

- **सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia)**—इसमें प्राणघातक दवाओं के माध्यम से जीवन का अन्त किया जाता है. भारत में यह पूर्णतः अवैध है.
- **निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)**—इसमें जीवन रक्षक उपचार या पोषण को वापस लेकर रोगी की प्राकृतिक मृत्यु होने दी जाती है.
- **अरुणा रामचंद्र शानबाग मामला (2011)**—न्यायालय ने पहली बार सख्त शर्तों के तहत् निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी.
- **कॉमन कॉज निर्णय (2018)**—इसे संवैधानिक मान्यता मिली. न्यायालय ने घोषित किया कि अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) के तहत् 'गरिमा के साथ मरने का अधिकार' एक मूल अधिकार है. इसी मामले में 'लिविंग विल' (Living Will) या 'एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स' की अवधारणा को भी स्वीकार किया गया.

संशोधित प्रक्रिया और भविष्य की राह

- 2023 के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसी स्थिति में एक प्राथमिक और एक माध्यमिक मेडिकल बोर्ड का गठन अनिवार्य है. वर्तमान निर्णय में न्यायालय ने संसद से 'एण्ड-ऑफ-लाइफ केयर' के लिए एक व्यापक वैधानिक ढाँचा (Comprehensive Law) बनाने का आग्रह किया है. साथ ही, पारदर्शिता के लिए निर्देश दिया गया है कि अस्पतालों द्वारा मेडिकल बोर्ड के निर्णयों की सूचना न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दी जाए.



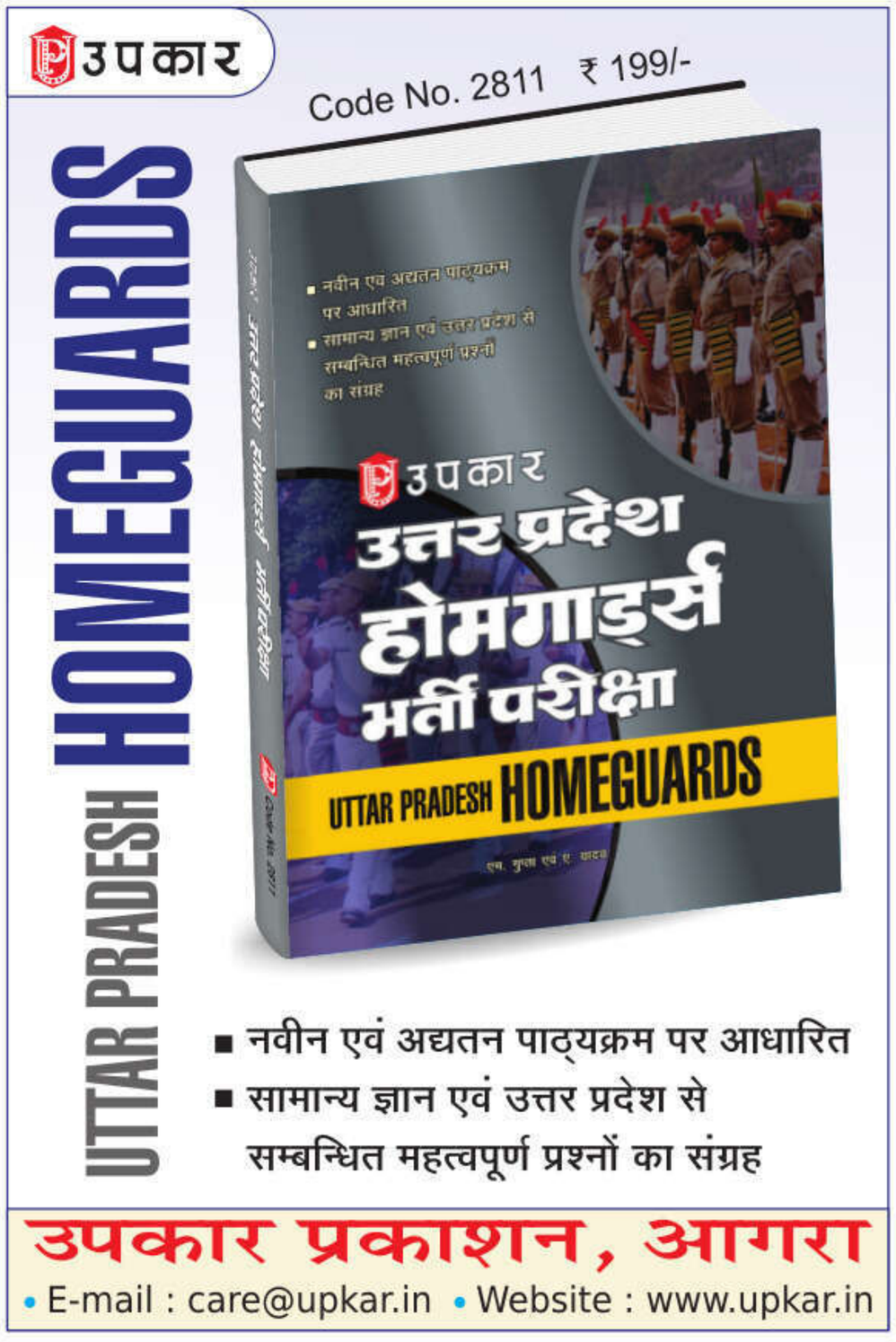
PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अन्य प्रमुख सुर्खियाँ	
एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) Mk-III और श्टिल (Shtil) मिसाइल	• केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 स्वदेशी ALH Mk-III (MR) हेलीकॉप्टरों हेतु HAL के साथ व भारतीय नौसेना के लिए रूस की श्टिल (Shtil) सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों का समझौता किया है.
गौ-टेक 2026	• महाराष्ट्र गोसेवा आयोग और ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ-बेस्ड इण्डस्ट्रीज (GCCBI) के सहयोग से 20-23 मार्च, 2026 के बीच पुणे के कृषि महाविद्यालय में इसका आयोजन किया गया है.
हर्पीस सिम्पलेक्स वायरस (HSV)	• पश्चिम बंगाल के एक सुधार गृह में हर्पीस सिम्पलेक्स वायरस (HSV) के प्रकोप से कई कैदियों की मृत्यु और संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिसका मुख्य कारण अत्यधिक भीड़-भाड़ माना जा रहा है. • यह एक संक्रामक वायरल बीमारी है, जो मुँह या जननांगों पर दर्दनाक छाले पैदा करती है. यह संक्रमण लाइलाज है, क्योंकि वायरस शरीर में आजीवन बना रहता है. • **HSV-1**—मुख्य रूप से ओरल हर्पीस (ठण्डे छाले) का कारण बनता है और लार या त्वचा के सम्पर्क से फैलता है. • **HSV-2**—यह मुख्य रूप से यौन सम्पर्क के माध्यम से फैलता है और जेनिटल हर्पीस का कारण बनता है. दुर्लभ मामलों में, यह प्रसव के दौरान माँ से बच्चे में भी फैल सकता है.
दोहरे उद्देश्य वाली हरित ऊर्जा सामग्री	• IIT गुवाहाटी ने MXene-आधारित सामग्री विकसित की है, जो जल इलेक्ट्रोलिसिस और सौर-संचालित विलवणीकरण (Desalination) दोनों में सक्षम है. • यह सामग्री हाइड्रोजन विकास के लिए केवल 12 mV का अल्ट्रा-लो ओवरपोटेंशियल प्रदर्शित करती है, जो इसे पारम्परिक प्लेटिनम उत्प्रेरकों से अधिक कुशल और किफायती बनाती है. • सौर ऊर्जा का उपयोग करके यह प्रणाली 2 $kg/m^2/h$ की उच्च दर से खारे समुद्री जल को पीने योग्य पानी में बदलती है. इसमें नमक जमा होने की समस्या नहीं होती, जिससे यह लम्बे समय तक प्रभावी रहती है.
विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केन्द्र	• भारत ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर (जुव्वलादिन्ने) में इन्हें स्थापित किया है. इसे सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा 29·58 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है. यहाँ डिजिटल ट्विन और रोबोटिक निर्माण जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग होगा. • यह केन्द्र मानवरहित सतह पोत (USV), स्वायत्त जलमार्ग वाहन (AUV) और इंटेलिजेंट नेविगेशन सिस्टम विकसित करेगा.
भारत की पहली साइबर सुरक्षा सुविधा 'कनेक्टसेफ' लॉन्च	• डेलॉइट (Deloitte) ने भारत की पहली ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी (OT) आधारित साइबर सुरक्षा सुविधा 'कनेक्टसेफ' लॉन्च की है. • यह ऑटोमोटिव, मेडिकल टेक और विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुरक्षा सहायता प्रदान करती है.
लेजिओनेयर्स रोग	• लंदन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में लेजिओनेयर्स रोग (Legionnaires' disease) के मामलों में वृद्धि देखी गई है. • यह रोग 'लेजिओनेला न्यूमोफिला' बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गम्भीर निमोनिया है. यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता. संक्रमण दूषित पानी की बूँदों (जैसे—कूलिंग टावर, AC या फव्वारे) को साँस के साथ अन्दर लेने से होता है.
स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बोया सिस्टम का परीक्षण	• भारत ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) द्वारा विकसित स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बोया (Floating LiDAR Buoy) सिस्टम का तमिलनाडु के मुत्तोम तट पर सफल परीक्षण किया है. • यह LiDAR (Light Detection and Ranging) तकनीक का उपयोग करता है, जो लेजर पल्स के माध्यम से हवा की गति और दिशा का सटीक डेटा एकत्र करती है. • यह समुद्र की सतह से 300 मीटर की ऊँचाई तक वायुमण्डलीय पैटर्न को मापने में सक्षम है. लेजर तरंगें हवा के कणों से टकराकर वापस लौटती हैं, जिससे वास्तविक समय में विश्लेषण किया जाता है.
गांडीवा तकनीक	• हाल ही में, कन्नूर अपराध शाखा ने 55 वर्षीय परवीन बाबू और उनकी 32 वर्षीय बेटी सकीना फातिमा को गिरफ्तार कर एक दशक पुराने हत्या के मामले को सुलझाया है. • अपराध शाखा ने आरोपियों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए NATGRID के अन्तर्गत आने वाले उन्नत एआई-आधारित विश्लेषणात्मक उपकरण गांडीवा का उपयोग किया. गौरतलब है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न सरकारी और निजी डेटाबेस से जुड़ता है.
पूर्ण चन्द्र ग्रहण	• 3 मार्च, 2026 को पूर्ण चन्द्रग्रहण देखा गया, जिसे खगोलविदों ने 'ब्लड मून' का नाम दिया है. यह तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चन्द्रमा के बिल्कुल बीच में आ जाती है, जिससे चन्द्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है. • पूर्ण ग्रहण के दौरान चन्द्रमा काला नहीं होता. पृथ्वी का वायुमण्डल सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित (Refract) करता है, जिससे नीली रोशनी छन जाती है और केवल लम्बी लाल तरंगदैर्ध्य (Red Wavelength) चन्द्रमा तक पहुँचती है.
स्व-प्रतिकृति RNA	• शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने QT45 नामक एक स्व-प्रतिकृति RNA (Self-replicating RNA) अणु विकसित किया है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

	• स्व-प्रतिकृति RNA में स्वयं की प्रतिलिपि बनाने और अपनी रज्जुक शृंखला (टेम्पलेट) में मौजूद जानकारी की भी नकल करने की क्षमता होती है. • यह 'RNA वर्ल्ड हाइपोथीसिस' का समर्थन करता है. इसके अनुसार प्रारम्भिक जीवन DNA और प्रोटीन के विकसित होने से पहले स्व-प्रतिकृति RNA पर आधारित था.
डार्क ऑक्सीजन	• वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की लगभग 4,000 मीटर गहराई पर 'डार्क ऑक्सीजन' उत्पादन की खोज की है. यह ऑक्सीजन प्रकाश-संश्लेषण से स्वतंत्र है, जो सूर्य के प्रकाश के बिना गहरे समुद्र में उत्पन्न होती है. • समुद्र तल पर पाए जाने वाले पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स विद्युत् रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से इसे उत्पादित करते हैं. • गौरतलब है कि यह खोज उस पुरानी धारणा को चुनौती देती है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत केवल प्रकाश-संश्लेषण है.
IMPAct4-Nutrition प्लेटफॉर्म	• नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने IMPAct4Nutrition प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. इसका लक्ष्य आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य सुधार को मजबूत करना है. • IMPAct4Nutrition एक ऐसा मंच है, जो पोषण से जुड़ी जानकारी और संसाधनों का केन्द्रीय हब बनकर काम करता है. यह मंच व्यवसायों को पोषण अभियान पोषण 2.0 से जोड़ता है, ताकि निजी क्षेत्र भी पोषण सुधार की इस मुहिम में भागीदार बन सके. • पोषण 2.0 का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं के लिए जरूरी पोषण मानकों में सुधार करना है, जैसे—बेहतर आहार, एनीमिया में कमी और सन्तुलित भोजन की आदतें.
ग्रेविटी बम : गुरुत्वाकर्षण से चलने वाला मारक हथियार	• ग्रेविटी बम वर्तमान में तब अधिक चर्चा में आया जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध इसे प्रयोग करने की बात कही है. • इसे ऐतिहासिक रूप से 'फ्री-फॉल' बम के नाम से भी जाना जाता है. • इस बम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें क्रूज मिसाइलों की तरह अपना कोई आन्तरिक इंजन या शक्ति स्रोत नहीं होता. एक बार विमान से छोड़े जाने के बाद, यह पूरी तरह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है. इसकी दिशा और प्रहार की सटीकता इसे गिराने वाले विमान की गति, ऊँचाई और हवा के दबाव पर निर्भर करती है.





PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



UPSC NEW BOOKS PDF

2026 EDITION

अब UPSC STANDARD BOOKS 2026 की PDF सीधे टेलीग्राम पर लें सकते है
बस हमारी टेलीग्राम बॉट पर मैसेज करें

Telegram Bot - @pdfhub2026bot

सीधे मैसेज भेजने के लिए MESSAGE NOW पर क्लिक करें

Message Now

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भारत ने नागोया प्रोटोकॉल पर पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की

- केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के सहयोग से 27 फरवरी, 2026 को नागोया प्रोटोकॉल पर अपनी पहली रिपोर्ट जैविक विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) को प्रस्तुत की.
- यह रिपोर्ट नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 29 के तहत् निर्धारित निगरानी और रिपोर्टिंग दायित्वों का हिस्सा है.
- यह रिपोर्ट 1 नवम्बर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2025 तक की अवधि को कवर करती है और भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) के लक्ष्य 13 की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित करती है.



- भारत ने इस रिपोर्ट के माध्यम से अपने अद्वितीय तीन-स्तरीय संस्थागत ढाँचे को प्रदर्शित किया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और स्थानीय स्तर पर निर्वाचित निकायों द्वारा गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC) शामिल हैं.
- जैव विविधता पर सम्मेलन (CBD), जिसकी उत्पत्ति 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई थी, का मुख्य उद्देश्य वैश्विक जैव विविधता की रक्षा, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और संसाधनों से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत वितरण है.
- भारत ने 1994 में इस सम्मेलन की पुष्टि की थी, जिसके तहत् जैविक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को रोकना, उनके सतत् उपयोग को विनियमित करना और इन संसाधनों के संरक्षकों, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों को उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत करना अनिवार्य है.
- CBD के तहत् दो महत्वपूर्ण पूरक समझौते हैं—2003 का कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) की जैव सुरक्षा से सम्बन्धित है और 2014 (लागू होने का वर्ष) का नागोया प्रोटोकॉल, जो विशेष रूप से आनुवंशिक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त लाभों के निष्पक्ष और समान वितरण पर केन्द्रित है. नागोया प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई फार्मास्युटिकल कम्पनी किसी देश के जैविक संसाधनों का उपयोग करती है, तो उसका लाभ वहाँ की स्वदेशी आबादी के साथ साझा किया जाए.
- वैश्विक स्तर पर, CBD के सदस्य देश हर 2 वर्ष में 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज' (COP) के माध्यम से मिलते हैं.
- हाल ही में कोलम्बिया के कैली में आयोजित COP-16 में 'डिजिटल अनुक्रम सूचना' (DSI) के लिए 'कैली फण्ड' की स्थापना की गई और 2030 तक प्रति वर्ष 200 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया.
- इससे पूर्व, 2022 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित COP-15 ने 'कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा' (GBF) को जन्म दिया, जिसमें 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 23 उद्देश्य शामिल हैं.

जैविक विविधता सम्मेलन के दौरान ही भारत द्वारा अपनी सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत

- 26 फरवरी, 2026 को जैविक विविधता सम्मेलन (CBD) के समक्ष प्रस्तुत सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट (NR-7) न केवल भारत की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को दर्शाती है, बल्कि कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचे (KMGBF) के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का भी प्रमाण है.

जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत का कानूनी ढाँचा

- भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए संवैधानिक और वैधानिक दोनों प्रावधान मौजूद हैं. संविधान राज्य को निर्देश देता है और नागरिकों पर मौलिक कर्तव्य लागू करता है.
- अनुच्छेद 48-ए (राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त) राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है.
- अनुच्छेद 51-ए(जी) (मौलिक कर्तव्य) प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य है.
- संवैधानिक निर्देशों के अतिरिक्त, जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन के लिए वैधानिक प्रावधान भी हैं—मत्स्य अधिनियम, 1897; वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972; जैविक विविधता अधिनियम, 2002.
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002; संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता अधिनियम, 1992 में निहित उद्देश्यों को साकार करने के भारत के प्रयास से अस्तित्व में आया, जिसकी भारत ने 1994 में पुष्टि की थी. अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं—जैव विविधता का संरक्षण, इसके संसाधनों का सतत् उपयोग और एक न्यायसंगत प्रक्रिया के माध्यम से आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष और समान वितरण.
- इसी प्रकार, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) 1999 (जिसे बाद में 2008 में अद्यतन किया गया) को सीबीडी के आदेशों को लागू करने के लिए तैयार किया गया था. 2014 में, इस योजना को आइची जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन किए गए, जिन्हें 2010 में नागोया में आयोजित सीबीडी सीओपी-10 में अपनाया गया था.
- इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, भारत ने कोलम्बिया के कैली में आयोजित COP-16 में राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) 2024-30 का शुभारम्भ किया, ताकि इसे COP-15 में अपनाए गए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जैव विविधता ढाँचे के अनुरूप बनाया जा सके, जो आइची लक्ष्यों का स्थान लेता है. इसमें 2030 तक संरक्षण प्रयासों को दिशा देने के लिए 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

- भारत की यह रिपोर्ट 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों (NBTs) के सापेक्ष 142 संकेतकों पर आधारित एक व्यापक मूल्यांकन है. रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि भारत के सभी 23 लक्ष्य वर्तमान में प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हैं. यह सफलता समग्र सरकारी और समग्र सामाजिक दृष्टिकोण का परिणाम है, जिसमें 33 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभिन्न राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी शामिल है.

संरक्षण नेटवर्क और वन्यजीव डेटा

- **वन आवरण**—देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,356·95 वर्ग किमी (25·17%) तक पहुँच गया है.
- **रामसर स्थल**—अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की संख्या 2014 में 26 थी, जो 2026 तक बढ़कर 98 हो गई है.
- **संरक्षित क्षेत्र**—भारत का नेटवर्क अब 58 बाघ अभयारण्य, 33 हाथी अभयारण्य, 106 राष्ट्रीय उद्यान और 574 वन्यजीव अभयारण्यों के साथ अत्यंत विस्तृत है.
- **प्रजाति संख्या**—भारत दुनिया के 70% से अधिक बाघों (3,682) का घर है. इसके अलावा 891 एशियाई शेर, 4,014 गैंडे और पहली बार गणना की गई 6,327 नदी डॉल्फिन व 718 हिम तेंदुए भारत की समृद्ध विविधता को दर्शाते हैं.

कृषि जैव विविधता और सामुदायिक भागीदारी

- भारत ने न केवल जंगली जानवरों बल्कि कृषि विरासत को भी संरक्षित किया है. देश में 22 कृषि जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जहाँ 171 देशी फसलों और 230 पशु नस्लों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है.
- स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण के लिए 2·76 लाख से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC) कार्य कर रही हैं, जो पारम्परिक ज्ञान को 'पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर' (PBR) के माध्यम से सुरक्षित करती हैं.
- नागोया प्रोटोकॉल के तहत् 'पहुँच और लाभ साझाकरण' (ABS) के माध्यम से ₹140 करोड़ का वितरण समुदायों के बीच किया गया है.
- आधुनिक भारत अपनी संरक्षण रणनीति में रिमोट सेंसिंग, उपग्रह टेलीमेट्री और डीएनए आधारित उपकरणों जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहा है.

हाल ही में प्रमुख पादप एवं जीव जंतु प्रजाति

एक्टिनिडिया इंडिका

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में कीवी की एक नई जंगली प्रजाति एक्टिनिडिया इंडिका की खोज की. यह प्रजाति केवल जिरो घाटी के पास 1,725 मीटर ऊँचाई पर समशीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में ही पाई जाती हैं.



Caulocera hollowayi और Asura buxa

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India–ZSI) के वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिमालय क्षेत्र में लाइकेन मॉथ की दो नई प्रजातियों की पहचान की है. इन नई प्रजातियों को कौलोसेरा होलोवाई और असुरा बुक्सा (Caulocera hollowayi तथा Asura buxa) नाम दिया गया है. उल्लेखनीय है कि Caulocera hollowayi प्रजाति की पहचान सिक्किम के गोलितार (Golitar) क्षेत्र के आस-पास एकत्र किए गए नमूनों के अध्ययन से हुई. वही Asura buxa नामक प्रजाति का पता पश्चिम बंगाल के पनिजोरा (Panijhora) क्षेत्र से प्राप्त नमूनों के अध्ययन के दौरान चला.

ओसबेकिया जुबीनगार्गियाना

गौहाटी विश्वविद्यालय के वनस्पति वैज्ञानिकों (बर्नाली दास, नमिता नाथ और प्रसभ पुल्प्रा) ने असम के मानस नेशनल पार्क में Melastomataceae परिवार के अन्तर्गत एक नई पादप प्रजाति ओसबेकिया जुबीनगार्गियाना (Osbeckia zubeengargiana) की खोज की है. उल्लेखनीय है कि इस सुंदर गुलाबी फूल वाले पौधे का नाम प्रसिद्ध असमिया गायक और प्रकृति प्रेमी जुबीन गर्ग के सम्मान में रखा गया है.

वेला कार्ली

शोधकर्ताओं ने केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में वेला कार्ली (Vela carli) मीठे पानी के केकड़े की एक दुर्लभ प्रजाति में गाइनैन्ड्रोमॉर्फी (Gynandromorphy) पाई है. यह केकड़ा एक ही शरीर में नर (प्रजनन अंग) और मादा (गोनोपोर) दोनों लक्षण प्रदर्शित करता है, जो गेकार्सिनुसिडे (Gecarcinucidae) परिवार में पहली बार दर्ज की गई घटना है.

मरुस्थलीय काई सिंट्रिचिया कैनिनर्विस

वैज्ञानिकों ने मरुस्थलीय काई Syntrichia caninervis (सिंट्रिचिया कैनिनर्विस) को मंगल ग्रह पर जीवन बसाने (टेराफॉर्मिंग) के लिए एक सम्भावित 'अग्रणी प्रजाति' (Pioneer species) के रूप में पहचाना है, क्योंकि यह अत्यधिक निर्जलीकरण, तापमान और तीव्र विकिरण के बावजूद जीवित रह सकती है. हाल के अध्ययनों के अनुसार, यह काई कृत्रिम मंगल जैसी स्थितियों में भी पनप सकती है.



ग्लिप्टोथोरेक्स सेंटीमेरेनी और ओरेइचथिस एलियाने

शोधकर्ताओं ने नगालैण्ड के मोकोकचुंग जिले में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों से दो नई मीठे पानी की मछली प्रजातियाँ; ग्लिप्टोथोरेक्स सेंटीमेरेनी और ओरेइचथिस एलियाने; खोजीं, जो पत्रिका जूटैक्सा में प्रकाशित हुई. उल्लेखनीय है कि ग्लिप्टोथोरेक्स सेंटिमेरेनी दिकु नदी में वही ओरेइचथिस एलियान, सुरंग नदी में खोजी गई है.

एम्फीपोड प्रजाति 'स्टेनोथो लोरी'

बरहमपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ओडिशा के गंजाम में भारतीय जल क्षेत्र में पहली बार एक दुर्लभ एम्फीपोड प्रजाति 'स्टेनोथो लोरी' की खोज की है. यह छोटी, झींगा जैसी समुद्री प्रजाति (5·5 मिमी) पहले केवल मलेशिया में रिकॉर्ड की गई थी और यह भारत में इसके मिलने का पहला रिकॉर्ड है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

- शासन में पारदर्शिता लाने के लिए 'परिवेश' (PARIVESH) पोर्टल जैसी एकल-खिड़की प्रणाली विकसित की गई है. साथ ही, 'मिशन लाइफ' और 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसे जन-आन्दोलनों ने नागरिकों को सीधे संरक्षण प्रयासों से जोड़ दिया है.

भारत के 85% से अधिक शहर वायु गुणवत्ता मानकों में विफल : CREA रिपोर्ट

- ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केन्द्र (CREA) द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आँकड़ों के हालिया विश्लेषण ने भारत के शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की गम्भीर स्थिति को उजागर किया है.
- 1 अक्टूबर, 2025 से 28 फरवरी, 2026 के बीच किए गए इस अध्ययन के अनुसार, विश्लेषण किए गए भारत के 238 शहरों में से 204 शहर (लगभग 85%) 40/mu g/m^3 के निर्धारित भारतीय राष्ट्रीय मानक को पूरा करने में विफल रहे.
- इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि भारत का एक भी शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सुरक्षित मानक (5 /mu g/m^3) पर खरा नहीं उतरा.

प्रदूषण के केन्द्र : उत्तर भारत का संकट

- रिपोर्ट के अनुसार, पिछली सर्दियों में गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहाँ PM2·5 की औसत सान्द्रता 172/mu g/m^3 दर्ज की गई. इसके बाद नोएडा (166/mu g/m^3) और दिल्ली (163/mu g/m^3) का स्थान रहा. शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से अधिक शहर, जिनमें ग्रेटर नोएडा, बहादुरगढ़, धारूहेड़ा और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं.
- जारी आँकड़े दर्शाते हैं कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दियों के दौरान प्रदूषकों का जमाव स्वास्थ्य के लिए आपातकालीन स्थिति पैदा कर रहा है.

महानगरों की स्थिति और स्वास्थ्य जोखिम

- भारत के प्रमुख महानगरों में वायु गुणवत्ता का स्तर राष्ट्रीय सीमा से काफी ऊपर बना हुआ है. दिल्ली के बाद कोलकाता (78/mu g/m^3), मुम्बई (48/mu g/m^3) और चेन्नई (44/mu g/m^3) में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक रहा. केवल बेंगलुरु (39/mu g/m^3) राष्ट्रीय मानक सीमा के भीतर रहने में सफल रहा.
- शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि PM2·5 जैसे सूक्ष्म कण सीधे फेफड़ों और रक्तप्रवाह में प्रवेश कर गम्भीर श्वसन रोगों और हृदय सम्बन्धी समस्याओं का कारण बनते हैं.
- उल्लेखनीय है कि प्रदूषण के इस दौर में कर्नाटक का चामराजनगर भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा, जहाँ PM2·5 का स्तर मात्र 19/mu g/m^3 रहा. दिलचस्प बात यह है कि देश के 10 सबसे स्वच्छ शहरों में से 8 अकेले कर्नाटक राज्य से हैं, जबकि मध्य प्रदेश और मेघालय का एक-एक शहर इस सूची में स्थान बनाने में सफल रहा.

संकट में प्रवासी वन्यजीव : वैश्विक रिपोर्ट ने दी विलुप्ति की चेतावनी

- संयुक्त राष्ट्र की 'प्रवासी वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन' (CMS) की हालिया अंतरिम रिपोर्ट ने दुनिया भर के प्रवासी जीवों के अस्तित्व पर गहरा संकट जताया है.
- रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक संधि के तहत् संरक्षित लगभग 49% प्रवासी प्रजातियों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि 24% प्रजातियाँ अब विलुप्ति की कगार पर हैं.
- पिछले 2 वर्षों के भीतर ही इन प्रजातियों पर मंडरा रहा खतरा काफी बढ़ गया है. जनसंख्या में गिरावट का जोखिम 5% और विलुप्त होने का खतरा 2% तक बढ़ा है.
- वर्तमान में, CMS के तहत् सूचीबद्ध 1,189 प्रजातियों में से 582 प्रजातियाँ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं. इनमें पक्षी, जंगली खुर वाले जानवर (जैसे—लामा और गजेल), मीठे पानी की मछलियाँ और समुद्री जीव जैसे—शार्क व कछुएँ शामिल हैं.

संरक्षण की स्थिति और चुनौतियाँ

- IUCN (प्रकृति संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ) के आंकड़ों के आधार पर तैयार यह रिपोर्ट बताती है कि 26 नई प्रजातियाँ अब 'उच्च जोखिम' श्रेणी में आ गई हैं, जिनमें 18 तटीय पक्षी शामिल हैं.
- **भारत में स्थिति**—भारत के तटीय क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट आई है. उत्तरी हिन्द महासागर में शार्क और रे मछलियाँ भी संकट में हैं. हालाँकि, दक्षिण एशिया में गिद्धों की आबादी में सुधार एक सकारात्मक संकेत है.
- उदाहरण के लिए—साइगा मृग, स्किमिटर-हॉर्नड ओरिक्स और भूमध्यसागरीय मोंक सील जैसी सात प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों के बेहतर परिणाम मिले हैं.

एवियन इन्फ्लुएंजा (H5N1)

- रिपोर्ट में बर्ड फ्लू (H5N1) को एक बड़े खतरे के रूप में रेखांकित किया गया है. इसने न केवल पक्षियों (जैसे—अफ्रीकी पेंगुइन और लाल मुकुट वाले सारस) बल्कि समुद्री स्तनधारियों (जैसे—सी लायन और फर सील) को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है. लम्बी आयु वाली प्रजातियों के लिए यह महामारी विशेष रूप से घातक है, क्योंकि वे मृत्यु दर में अचानक वृद्धि को सहने में अक्षम होती हैं.

मानवीय हस्तक्षेप और पर्यावास का विनाश

- CMS की कार्यकारी सचिव एमी फ्रैंकल के अनुसार, अत्यधिक दोहन और पर्यावास का विखण्डन अन्य सबसे बड़े खतरे हैं. मध्य एशिया में रेलवे, सड़कों और बाड़ों के निर्माण से मंगोलियाई गजेल जैसे खानाबदोश जानवरों के प्रवास मार्ग बाधित हुए हैं, जिससे उनकी गतिशीलता में भारी कमी आई है.

संयुक्त राष्ट्र की 'प्रवासी वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन' (CMS)

- 1979 में संयुक्त राष्ट्र के तहत् स्थापित CMS एक बाध्यकारी वैश्विक संधि है. इसकी 'परिशिष्ट I' में शामिल 188 प्रजातियों (जैसे—भारत के एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और समुद्री कछुएँ) के लिए सख्त संरक्षण अनिवार्य है. इसमें शिकार पर प्रतिबंध और उनके प्राकृतिक रास्तों को बहाल करना शामिल है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

पर्यावरण और पारिस्थितिकी से सम्बधित अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ	
एपिस डोर्साटा : मधुमक्खी प्रजाति	• हाल के दिनों में भारत भर में मधुमक्खियों के हमलों की सूचना चिंताजनक रूप से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. उल्लेखनीय है कि अधिकांश घटनाओं के लिए जिम्मेदार मधुमक्खी प्रजाति एपिस डोर्साटा है, जिसे विशाल चट्टानी मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है. यह चट्टानों, किले की दीवारों और ऊँचे पेड़ों पर बड़े, खुले घोंसले बनाती है. • यह समझना महत्वपूर्ण है कि मधुमक्खियाँ आमतौर पर स्वयं हमला नहीं करतीं. इसके पीछे कोई बाहरी बाधा या खतरे का आभास होना आवश्यक है और एक बार डंक मारने पर मधुमक्खी मर जाती है.
दिल्ली में देश का पहला 'माइक्रोएल्गी' आधारित एयर प्यूरीफायर टॉवर	• दिल्ली ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई तकनीक अपनाई है. एयरोसिटी हाईवे के किनारे भारत का पहला 'प्योरएयर टॉवर' लगाया गया है, जो सूक्ष्म शैवाल (Microalgae) की मदद से हवा साफ करता है. यह टॉवर सड़क के बीचों-बीच (डिवाइडर पर) लगा है, जो आम सड़क संरचना को एक जीवित और प्राकृतिक हवा साफ करने वाली मशीन में बदल देता है. • आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले स्मॉग टॉवर मशीनी फिल्टरों पर निर्भर होते हैं जिन्हें बार-बार बदलना पड़ता है, लेकिन यह नया टॉवर पूरी तरह अलग है. यह प्राकृतिक प्रक्रिया (प्रकाश संश्लेषण) का उपयोग करता है. इसमें मौजूद सूक्ष्म शैवाल हवा से प्रदूषित गैसों जैसे—कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धूल के कणों (PM) को सोख लेते हैं. बदले में, यह टॉवर ताजी ऑक्सीजन छोड़ता है और प्रदूषण को 'एल्गी बायोमास' में बदल देता है.
सीओपी-15	• प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन (सीएमएस) के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी-15) की 15वीं बैठक 23-29 मार्च, 2026 तक ब्राजील के माटो ग्रोसो डो सुल के कैम्पो ग्रांडे स्थित बोस्क एक्सपो में आयोजित की गई. इसकी बैठक पहली बार ब्राजील में आयोजित की गई है. सीएमएस सीओपी 15 का विषय 'जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति को जोड़ना' रखा गया है. • उल्लेखनीय है कि प्रवासी वन्यजीवों पर सम्मेलन, जिसे बॉन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, 23 जून, 1979 को अपनाया गया था. सीएमएस एक ढाँचागत सम्मेलन है और इसमें कई समझौते, समझौता ज्ञापन और विशेष प्रजाति सम्बन्धी पहलें शामिल हैं. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में एक पर्यावरण संधि के रूप में, सीएमएस प्रवासी जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण और सतत् उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है.
पशु अनुकूलन	• प्रकृति में जीवित रहने के लिए जानवरों ने कई अनोखे तरीके विकसित किए हैं, जिनमें से 'खड़े होकर सोना' एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक रणनीति है. यह अनुकूलन मुख्य रूप से शाकाहारी जीवों में देखा जाता है. • उदाहरण के लिए—घोड़ों और हाथियों जैसे भारी शरीर वाले जीवों के लिए जमीन से तुरन्त उठना कठिन और ऊर्जा खपत वाला कार्य होता है, इसलिए उनके शरीर में 'स्टे अपरेटस' (Stay Apparatus) जैसी विशेष शारीरिक संरचना होती है, जो माँसपेशियों पर दबाव डाले बिना जोड़ों को लॉक कर देती है. • वहीं, फ्लेमिंगो जैसे पक्षी एक पैर पर सोकर अपने शरीर की गर्मी को बचाते हैं. यह व्यवहार पशुओं को गहरी नींद के दौरान भी सतर्क रहने और खतरे की स्थिति में तुरन्त भागने में सक्षम बनाता है, जो उनके अस्तित्व के लिए अनिवार्य है.
प्रकृति 2026 सम्मेलन व भारतीय कार्बन मार्केट पोर्टल	• अन्तर्राष्ट्रीय कार्बन मार्केट सम्मेलन 'प्रकृति' 2026 का आयोजन नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट के तहत् किया गया. इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा आयोजित किया गया है. • इसका विषय 'एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक साझेदारी और डिजिटल समाधान पर जोर देना है'. • इसी सम्मेलन के दौरान भारतीय कार्बन मार्केट पोर्टल को भी लॉन्च किया गया, जो कार्बन ट्रेडिंग को सुव्यवस्थित करेगा.
भारतीय बाइसन महोत्सव 2026	• ओडिशा के देब्रिगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में दूसरे भारतीय बाइसन महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया. उल्लेखनीय है कि देब्रिगढ़-हीराकुड क्षेत्र में लगभग 848 बाइसन (गौर) दर्ज किए गए थे. • यह आईयूसीएन रेड लिस्ट में संकटग्रस्त; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अन्तर्गत सूचीबद्ध (संरक्षण का उच्चतम स्तर) और CITES परिशिष्ट I में सम्मिलित है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

पर्यावरण लेखा परीक्षा एजेंसी	• राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एनपीसी) ने हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के साथ पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी (ईएडीए) के रूप में कार्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है. • उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की स्थापना 1958 में एक स्वायत्त और गैर-लाभकारी संगठन के रूप में हुई थी. यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधीन कार्य करता है.
प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा	• मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए आक्रामक पौधा प्रजाति प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा को व्यवस्थित रूप से हटाने के निर्देश जारी किए हैं. • उल्लेखनीय है कि यह प्रजाति दक्षिण अमेरिकी देशों में उत्पन्न हुई और उपनिवेशीकरण के प्रारम्भिक दिनों में जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग के लिए अन्य महाद्वीपों में लाई गई थी. हालाँकि, वर्तमान में यह हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए एक आपदा साबित हो रही है. अदालत ने अनुसार प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा ने उपजाऊ भूमि, घास के मैदानों और जंगलों की काईदार व स्पंजी मिट्टी को नष्ट कर दिया है और इन पेड़ों के नीचे की भूमि बंजर भूमि में बदल गई है.
जोहा चावल	• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने असम के GI टैग प्राप्त जोहा चावल की पहली निर्यात खेप यूनाइटेड किंगडम और इटली भेजी है. उल्लेखनीय है कि असम और पूर्वोत्तर भारत की विशिष्टता, जोहा चावल एक सुगंधित और छोटे दानों वाली शीतकालीन धान की प्रजाति है. जोहा चावल की 22 किस्मों में कोला जोहा, कुड्कुनी जोहा और केतेकी जोहा सबसे लोकप्रिय हैं.
नागौरी पान मेथी	• राजस्थान की नागौरी पान मेथी को 'सामुदायिक किसान किस्म' की श्रेणी के तहत् पादप किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) द्वारा आधिकारिक तौर पर पेटेंट/पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है.

●●●



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

UPSC-CSE : एक जीवन बदलने वाली यात्रा, जो हर समर्पण के लायक है

—अतुल कपूर

हमारे जीवन में ऐसे बहुत कम पल आते हैं, जो सचमुच हमारे जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं और UPSC-CSE को पास करना उन्हीं में से एक है. 6 मार्च, 2025 को, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के फाइनल परिणाम घोषित किए.

कुल 958 उम्मीदवारों (659 पुरुष और 299 महिलाएँ) ने दुनिया की सबसे कठिन चयन प्रक्रियाओं में से एक की अंतिम बाधा को पार किया. इनमें से हर व्यक्ति न केवल बधाई का, बल्कि सच्ची प्रशंसा का भी हकदार है, क्योंकि उन्होंने जो हासिल किया है, वह असाधारण रूप से दुर्लभ है.

UPSC-CSE 2025 परीक्षा के चरण	पंजीकृत छात्रों की संख्या	परीक्षा में सम्मिलित छात्र	मुख्य परीक्षा के लिए चयनित छात्र
प्रारम्भिकी	937876	576793	14161

	सम्मिलित छात्र	साक्षात्कार के लिए चयनित छात्र
मुख्य परीक्षा	14161	2736

	सम्मिलित छात्र	अन्तिम घोषित परिणाम में चयनित
साक्षात्कार	2736	958

लाखों उम्मीदवारों में से, जिन्होंने इस कठिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की हिम्मत दिखाई, ये वे भाग्यशाली लोग हैं जिनके नाम इस अंतिम मेरिट-लिस्ट में आए हैं. यह केवल एक अकादमिक उपलब्धि नहीं है; यह वर्षों के अथक त्याग और अकेले में की गई पढ़ाई द्वारा इस कठिन चक्र से बाहर निकलने की सच्ची संतुष्टि का परिणाम है.

UPSC-CSE में सफलता तब मिलती है जब आप संघर्ष के माध्यम से अपने मन के संदेह पर जीत पाते हैं और जिनमें आंतरिक विश्वास होता है कि यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, यह आपकी पहुँच में है.

जब एक सपना हकीकत बन जाता है

हाँ, यह इन सफल उम्मीदवारों की अटूट प्रतिबद्धता ही है, जो उन्होंने इस भीषण प्रतियोगिता का सामना करने में दिखाई और उन्होंने सामान्य जीवन से कहीं बड़ी चीज का मुकाबला करने के लिए खुद को अकादमिक और मानसिक, दोनों तरह से तैयार किया.

UPSC-CSE में सफलता पाना कोई छोटी बात नहीं है, यह परीक्षा आपकी बुद्धि, आपके चरित्र और आपकी मानसिक सहनशक्ति की परख करती है और इसके लिए, UPSC बधाई का पात्र है कि वह दशकों से इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक निभा रहा है.

भारत को उसके सर्वोच्च प्रशासनिक स्तरों पर सेवा देने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करना इतना आसान नहीं है और एक बार जब ये लोग इस खूबसूरती से डिजाइन की गई परीक्षा-प्रणाली को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं, तो ये युवा IAS, IPS, IFS, IRS और अन्य 'ग्रुप A' और 'B' केन्द्रीय सेवाओं में शामिल हो जाते हैं.

प्रति वर्ष, CSE के नतीजों के साथ, हमारी नौकरशाही और मजबूत होती है. ये युवा जिलों का प्रशासन सँभालेंगे, पुलिस बलों का नेतृत्व करेंगे, विदेश नीति को आकार देंगे और उन निर्णयों को प्रभावित करेंगे जो लाखों आम नागरिकों के जीवन को छूते हैं. इस परीक्षा के पुरस्कारों को केवल वेतन या पद-प्रतिष्ठा के रूप में नहीं मापा जाता इन्हें विरासत, प्रभाव और सार्वजनिक सेवा के उस दुर्लभ विशेषाधिकार के रूप में मापा जाता है, जिसमें चीजों को बदलने की वास्तविक शक्ति होती है.

शीर्ष 5 सफल उम्मीदवारों की प्रोफाइल

UPSC-CSE 2025 में शीर्ष स्थान (Top Rank) अनुज अग्निहोत्री ने प्राप्त किया है. AIIMS, जोधपुर से मेडिकल की पढ़ाई (MBBS) करने वाले अनुज ने अपने विषय पर पूरा भरोसा दिखाया और 'चिकित्सा विज्ञान' (Medical Science) को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना. अगर पीछे मुड़कर देखें, तो पिछली बार 'चिकित्सा विज्ञान' को वैकल्पिक विषय (दूसरा वैकल्पिक विषय—मनोविज्ञान था) के रूप में चुनने वाली और पहला स्थान पाने वाली उम्मीदवार शेना अग्रवाल थीं (AIR 1; CSE 2011). इंजीनियरिंग स्नातक राजेश्वरी सुवे एम (अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में B.E.) ने इस वर्ष दूसरा स्थान हासिल किया है. उन्होंने 'समाजशास्त्र' (Sociology) को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है.

दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य (Commerce) में स्नातक अकांश ढुल ने तीसरा स्थान हासिल किया है और उन्होंने 'वाणिज्य और लेखाशास्त्र' (Commerce & Accountancy) को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था. चौथी रैंक राघव झुनझुनवाला को मिली है, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से B.A. Economics (Hons.) किया है. उन्होंने अपने ही विषय–Economics को अपने वैकल्पिक विषय के तौर पर चुना.

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली से B.A. LLB (Hons.) करने वाले ईशान भटनागर ने समाजशास्त्र को अपने वैकल्पिक विषय के तौर पर चुनकर पाँचवीं रैंक हासिल की.

मेरे लिए टॉप 5 रैंक से सबसे बड़ी सीख यह है कि 5 में से 3 टॉपर्स ने अपने ही विषय चुने थे और यह निर्णय शायद वर्ष 2013 के बाद आए परीक्षा-प्रणाली में बदलावों के मद्देनजर यह एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है.

आइए, और गहराई से पड़ताल करें और कुछ और काम की बातें जानें.

टॉप 25 उम्मीदवारों द्वारा हासिल किए गए अंक

एक बात जो ध्यान खींचती है, वह है पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) के स्कोर और यह एक सुखद आश्चर्य है. लिस्ट में 200+ अंक पाने वाले कई उम्मीदवार दिख रहे हैं.

टॉप 25 उम्मीदवारों में, पहली रैंक पाने वाले अनुज अग्निहोत्री को मिलाकर, कुल 13 उम्मीदवारों ने 200+ अंक हासिल करके मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की की है.

इंटरव्यू में सबसे ज्यादा अंक पाने वाली उम्मीदवार हैं तेजस्विनी सिंह (AIR 62), जिन्होंने 275 में से 225 अंक हासिल किए हैं. हालाँकि, इंटरव्यू में इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद, Mains (लिखित परीक्षा) में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 62वीं रैंक से ही संतोष करना पड़ा.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

हमें 2 उम्मीदवार–ईशान भटनागर (AIR 5) और जिनिया अरोड़ा (AIR 6)–ऐसे मिले, जिन्होंने इंटरव्यू में 215 अंक हासिल किए और तीन उम्मीदवार (यशस्वी राज वर्धन, निसार दिशांत अमृतलाल और इफरा शम्स अंसारी) ऐसे मिले, जिन्होंने 209 अंक हासिल किए.

CSE 2024 में हमने देखा था कि पहली रैंक पाने वाले के स्कोर एक नए निचले स्तर पर पहुँच गए थे (शक्ति दुबे–1043 अंक), और अब, CSE 2025 में, पहली रैंक पाने वाले के अंकों (अनुज अग्निहोत्री–1071 अंक) में थोड़ा सुधार देखने को मिला है.

UPSC-CSE 2025 में शीर्ष 25 उम्मीदवारों के अंक

क्र.स.	नाम	मुख्य परीक्षा	साक्षात्कार	कुल अंक
1	अनुज अग्निहोत्री	867	204	1071
2	राजेश्वरी सुवे एम	865	202	1067
3	अकांश ढुल	864	193	1057
4	राघव झुनझुनवाला	847	195	1042
5	ईशान भटनागर	823	215	1038
6	जिनिया अरोड़ा	822	215	1037
7	ए.आर. राजाह मोहिदीन	834	201	1035
8	पक्षाल सेक्रेटरी	837	198	1035
9	आस्था जैन	835	198	1033
10	उज्ज्वल प्रियांक	846	187	1033
11	यशवंत राजवर्धन	823	209	1032
12	अक्षित भारद्वाज	841	190	1031
13	अनन्या शर्मा	822	206	1028
14	सुरभि यादव	862	165	1027
15	सिमरनदीप कौर	825	201	1026
16	मोनिका श्रीवास्तव	819	206	1025
17	चितवन जैन	850	175	1025
18	श्रुति आर	825	200	1025
19	निसार दिशांत अमृतलाल	815	209	1024
20	रवि राज	823	201	1024
21	शुभम सिंह	837	187	1024
22	गीतिका अरोडा	831	192	1023
23	जीनू श्री जसवंत चंद्र	832	191	1023
24	इफरा शम्स अंसारी	813	209	1022
25	भाविका चोपड़ा	829	193	1022

महिला उम्मीदवारों की परफॉर्मेंस लगातार शानदार बनी हुई है. हाल के वर्षों–CSE 2021 (श्रुति शर्मा), 2022 (इशिता किशोर) और 2024 (शक्ति दुबे) में हमने देखा है कि लड़कियों ने टॉप रैंक हासिल की है. इस बार, राजेश्वरी सुवे एम (1067 अंक) ने टॉप रैंक से सिर्फ 4 अंकों से चूकते हुए मेरिट-लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया. यह एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन है और महिला उम्मीदवारों का कुल प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है.

अगर हम Mains (लिखित) अंकों के प्रभाव की बात करें, तो सुरभि यादव (AIR 14) 862 अंकों के साथ और चितवन जैन (AIR 17) 850 अंकों के साथ, सिर्फ Mains (लिखित) परीक्षा में अपनी मजबूती के दम पर टॉप 20 में अपनी जगह पक्की कर पाई.

जैसे-जैसे हम मेरिट-लिस्ट में नीचे की ओर बढ़ते हैं, ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं, जो हमारा ध्यान खींचते हैं.

टॉप 25 की लिस्ट पर एक नजर डालें और उनके प्रदर्शन से संकेत लेकर अपने लक्ष्य तय करें; आपकी योजना किस तरह की होगी, यह आपके अंतिम परिणामों में साफ दिखाई देगा.

CSE 2025 के लिए कट-ऑफ अंक न्यूनतम अर्हक अंक

सिविल सेवा परीक्षा 2025 में, विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत विभिन्न चरणों में अन्तिम अनुशंसित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम अर्हक मानक/अंक निम्नलिखित हैं–

इसे समझाने के लिए, मैं जनरल कैटेगरी के अंकों को आधार मान रहा हूँ.

प्रीलिम्स का कट-ऑफ GS पेपर 1 के प्रदर्शन पर आधारित होता है, लेकिन GS पेपर 2 कई लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर देता है और कट-ऑफ कम रहने के मुख्य कारणों में से एक यह भी है.

यह कट-ऑफ दिखाता है कि जिस उम्मीदवार के 92·66 या उससे ज्यादा अंक आए होंगे, उसे मुख्य परीक्षा 2025 में बैठने की पात्रता मिल गई होगी.

परीक्षा चरण	सामान्य	ईडब्ल्यूएस	ओबीसी	एससी	एसटी	पीडब्ल्यू श्रेणी-1	पीडब्ल्यू श्रेणी-2	पीडब्ल्यू श्रेणी-3	पीडब्ल्यू श्रेणी-5
प्रारम्भिकी *	92·66	89·34	92·00	84·00	82·66	76·66	54·66	40·66	40·66
मुख्य परीक्षा #	739	706	717	700	694	703	708	536	451
अन्तिम परिणाम	963	926	931	905	902	917	944	804	631

*Cut-off marks on the basis of GS Paper-I only. GS Paper-II was of qualifying nature with 33% marks.
Subject to 10% marks in each of the seven competitive papers *i.e.*, Essay, GS-I, GS-II, GS-III, GS-IV, Optional-I and Optional-II.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

कुल 1750 अंकों में से 739 अंकों का मुख्य परीक्षा कट-ऑफ यह दिखाता है कि जिस उम्मीदवार के 739 या उससे ज्यादा अंक आए होंगे, उसे पर्सनैलिटी टेस्ट 2025 में बैठने का मौका मिल गया होगा.

सीधे-सीधे हिसाब-किताब की बात करें तो, 963 का फाइनल कट-ऑफ यह बताता है कि जिस उम्मीदवार के 739 अंक आए थे, उसे मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए कम से कम 224 अंक और लाने की जरूरत थी.

यह बहुत ज्यादा माँग है और 200 से ज्यादा अंक लाना इतना आसान नहीं होता. इसके अलावा, इंटरव्यू में बैठने वाले हर उम्मीदवार का चयन नहीं होता और जाहिर है, फायदा हमेशा उन उम्मीदवारों को मिलता है जिनका प्रदर्शन मुख्य परीक्षा (लिखित) में अच्छा रहा हो.

लेकिन UPSC-CSE एक ऐसा मैदान है, जहाँ उम्मीदवारों को आखिरी चरण, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करके अपनी किस्मत बदलने का पूरा मौका मिलता है.

इस परिणाम की बारीकी से जाँच करने पर पता चलता है कि AIR 456 पर रहीं रितिका भान ने मुख्य परीक्षा (लिखित) में 776 अंक और इंटरव्यू में 187 अंक लाकर मेरिट लिस्ट में जगह बना ली.

सानिया सेरवी (AIR 450) ने मुख्य परीक्षा (लिखित) में 757 अंक और इंटरव्यू में 206 अंकों का अच्छा स्कोर करके मेरिट लिस्ट में जगह बनाई.

इंटरव्यू में इतना शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद, मुख्य परीक्षा (लिखित) में अपेक्षाकृत कम अंकों के कारण वह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) में किसी पद की उम्मीद नहीं कर सकतीं.

हम कुछ भी कहें, मेरे हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हर कोई बधाई और तारीफ का हकदार है.

तो अगर आप IAS बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए?

आपको मुख्य परीक्षा (लिखित) में 780-860 अंक लाने का लक्ष्य रखना चाहिए.

IAS में जगह बनाने के सम्भावित परिदृश्य

- अगर आप CSE 2025 के कट-ऑफ के हिसाब से देखें और आपका Mains का स्कोर इस रेंज के निचले सिरे पर है, तो आपको Interview में 220+ अंक लाने होंगे.
- अगर आपके Mains के अंक ऊपरी बैंड को छूते हैं और आप Interview में औसतन 160+ अंक भी ले आते हैं.
- अगर आप ऊपरी सिरे के आस-पास कहीं स्कोर कर पाते हैं, और Interview में भी 200+ अंकों का अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आप टॉप रैंक में अपना नाम आने की उम्मीद कर सकते हैं.

इसी तरह, दूसरी कैटेगरी के उम्मीदवार भी अपने लक्ष्य तय कर सकते हैं और आने वाले Mains के लिए उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं.

हालाँकि, नतीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन समझदारी भरे लक्ष्यों के साथ, आप हमेशा अपनी उम्मीदें जिन्दा रख सकते हैं.

कट-ऑफ 2023-2025 : 3 वर्ष की तुलना (सामान्य कैटेगरी)

प्रीलिम्स 2023 में अब तक के सबसे कम कट-ऑफ (200 में से 75·41 अंक) को देखते हुए, ऐसा लगता है कि कट-ऑफ धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है.

प्रारम्भिक परीक्षा का कट-ऑफ

CSE 2023 – 75·41 अंक

CSE 2024 – 87·98 अंक

CSE 2025 – 92·66 अंक

कोई कह सकता है कि Cut-off में हर बीतते वर्ष सुधार हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि CSE 2023 में सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र 1 काफी मुश्किल था और उसके अगले वर्ष CSE 2024 के प्रीलिम्स में चौंकाने वाली बातें अपेक्षाकृत कम थीं और CSE 2025 में यह काफी हद तक सन्तुलित था; यह बात कट-ऑफ के रुझानों में साफ तौर पर झलकती है.

जब हम कट-ऑफ का विश्लेषण करते हैं, तो कभी-कभी हम बारीकियों पर ध्यान नहीं देते और किसी भी हाल में हम प्रीलिम्स के रुझानों के आधार पर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि मुख्य परीक्षा (लिखित) और अंतिम परिणाम के कट-ऑफ भी रुझान वैसे ही रहेंगे.

जरा उस स्थिति के बारे में सोचिए, जहाँ कोई उम्मीदवार पिछले वर्ष के कट-ऑफ को ही अपना पैमाना मानकर चलता है; ऐसी स्थिति में, कट-ऑफ में महज 4-5 अंकों का बदलाव भी उस उम्मीदवार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. एक अभ्यर्थी के तौर पर, आपको यह समझना होगा कि यह केवल आपकी योग्यता के स्तर का सवाल नहीं है, जिसे किसी 1 वर्ष का कट-ऑफ तय कर सके. बल्कि हर वर्ष, यह आपकी 'सापेक्षिक प्रदर्शन' (Relative Performance) ही होती है, जो कट-ऑफ का निर्धारण करती है और यह सापेक्षिक प्रदर्शन उस वर्ष परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन से उभरकर सामने आता है.

कट-ऑफ एक ऐसा आँकड़ा है, जो अंतिम परिणाम तैयार होने के साथ ही निर्धारित होता है; यह कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे पहले से ही तय कर दिया गया हो.

CSE प्रीलिम्स 2025 में प्रश्न-पत्रों के अपेक्षाकृत आसान होने के बावजूद, यह बात साफ है कि उम्मीदवारों की तैयारी का स्तर एक जैसा नहीं है. यह बात सुनने में भले ही थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन कोचिंग संस्थानों, विशेषज्ञों और मार्गदर्शकों की मदद से की गई तथा कथित 'बेहतरीन तैयारी' भी उम्मीदवारों को सफलता की इस दहलीज को पार करवाने में मददगार साबित नहीं हो रही है.

जी हाँ, CSE प्रीलिम्स 2026 से ठीक पहले, यह एक तरह की 'जागने की चेतावनी' (Wake-up call) है. आप इस बात का पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि CSE प्रीलिम्स 2026 में आपको किस तरह के प्रश्न-पत्र का सामना करना पड़ेगा; लेकिन यदि आप कट-ऑफ से काफी ऊँचा लक्ष्य निर्धारित करके अपनी तैयारी करते हैं, तो आपके निरन्तर प्रयास निश्चित रूप से आपको प्रीलिम्स के कट-ऑफ से काफी ऊपर सुरक्षित स्थिति में पहुँचा देंगे भले ही कट-ऑफ के अंक कुछ और बढ़ ही क्यों न जाएँ.

मुख्य परीक्षा कट-ऑफ

CSE 2023 – 741 अंक

CSE 2024 – 729 अंक

CSE 2025 – 739 अंक

इससे साफ पता चलता है कि जहाँ प्रीलिम्स कट-ऑफ में लगातार सुधार दिख रहा है, वहीं CSE 2024 में मेन्स कट-ऑफ में भारी गिरावट आई थी और अब, CSE 2025 कट-ऑफ में थोड़ा सुधार दिख रहा है. फिर भी, कट-ऑफ CSE 2023 में देखे गए स्तर से कम ही है.

यह एक और संकेत है कि मुख्य परीक्षा स्तर पर, आपकी प्रतिस्पर्धा प्रीलिम्स स्तर की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन होती है. जो व्यक्ति 1 वर्ष से ज्यादा समय तक पढ़ाई करता है और प्रीलिम्स पास कर लेता है, यह इस बात का संकेत है कि उसने लगन से तैयारी की है और अपनी तैयारी की यात्रा के दौरान, उसने अपने ज्ञान के आधार को धीरे-धीरे बढ़ाया है; और यह चीज तब बहुत काम आती है जब वह अगले स्तर—मुख्य परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार होता है.

अंतिम परिणाम का कट-ऑफ मुख्य परीक्षा के कट-ऑफ रुझानों को ही दर्शाता है,

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि CSE 2025 में कट-ऑफ में जबरदस्त सुधार हुआ है और यह CSE 2023 के कट-ऑफ से पूरे 10 अंक ज्यादा हैं.

अंतिम परिणाम कट-ऑफ

CSE 2023 – 953 अंक
CSE 2024 – 947 अंक
CSE 2025 – 963 अंक

जब मैं कहता हूँ कि मुख्य परीक्षा में आपका प्रदर्शन ही आपके अंतिम परिणाम को निर्धारित करता है, तो इसका मतलब यह है कि मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्राप्त उच्च अंक आपको एक सुरक्षा कवच (Cushion) प्रदान करते हैं और यदि आप इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करने में सफल रहते हैं, तो इंटरव्यू में प्राप्त आपके उच्च अंक अंतिम मेरिट-सूची में आपका नाम सुनिश्चित करने में यहाँ तक कि उच्च रैंक के साथ भी एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं.

अंतिम कट-ऑफ का लगभग स्थिर रहना एक स्पष्ट संदेश देता है आपकी प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है और UPSC की रचनात्मक तथा नवीन प्रकृति ने इसे वास्तव में और भी कठिन बना दिया है.

यह प्रत्येक चरण के महत्व को उजागर करता है और यह भी बताता है कि UPSC-CSE की तैयारी करते समय आपको प्रत्येक चरण प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू को किस नजरिए से देखना चाहिए.

आपको यह समझना होगा कि प्रीलिम्स केवल एक छँटनी परीक्षा (Screening test) है, लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होती है; और प्रीलिम्स के प्रश्न-पत्रों में किसी भी अप्रत्याशित तत्व (Surprise element) के शामिल हो जाने से यह परीक्षा और भी ज्यादा अनिश्चित हो जाती है.

इसे स्वीकार करें या इनकार करते रहें Prelims असल में 'बचने' (Survival) का एक इम्तिहान है और आपको इसकी तैयारी ठीक उसी तरह करनी होगी जैसी इसकी जरूरत है और यह सिर्फ GS Paper-1 की बात नहीं है; यह 'बचने' की भावना GS Paper-2 में भी जिन्दा रहनी चाहिए. अगर आपकी तैयारी काफी अच्छी है, और आप GS Paper-1 और 2, दोनों में 2-2 घण्टे तक टिके रह पाते हैं, तो पूरी सम्भावना है कि आप ऐसा प्रदर्शन करेंगे जिससे आप कट-ऑफ से ऊपर बने रहेंगे.

एक बार जब आप Prelims पास कर लेते हैं, तो सही योजना के साथ पढ़ाई करने पर चीजें काफी व्यवस्थित हो जाती हैं; लगातार अच्छा प्रदर्शन करने से आप निश्चित रूप से इस सफर को आसानी से पार कर लेंगे और आपको मनचाहे नतीजे मिलेंगे.

अगर आप UPSC-CSE 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि आप इन सफल उम्मीदवारों से प्रेरणा लें और अपना हौसला बनाए रखें.

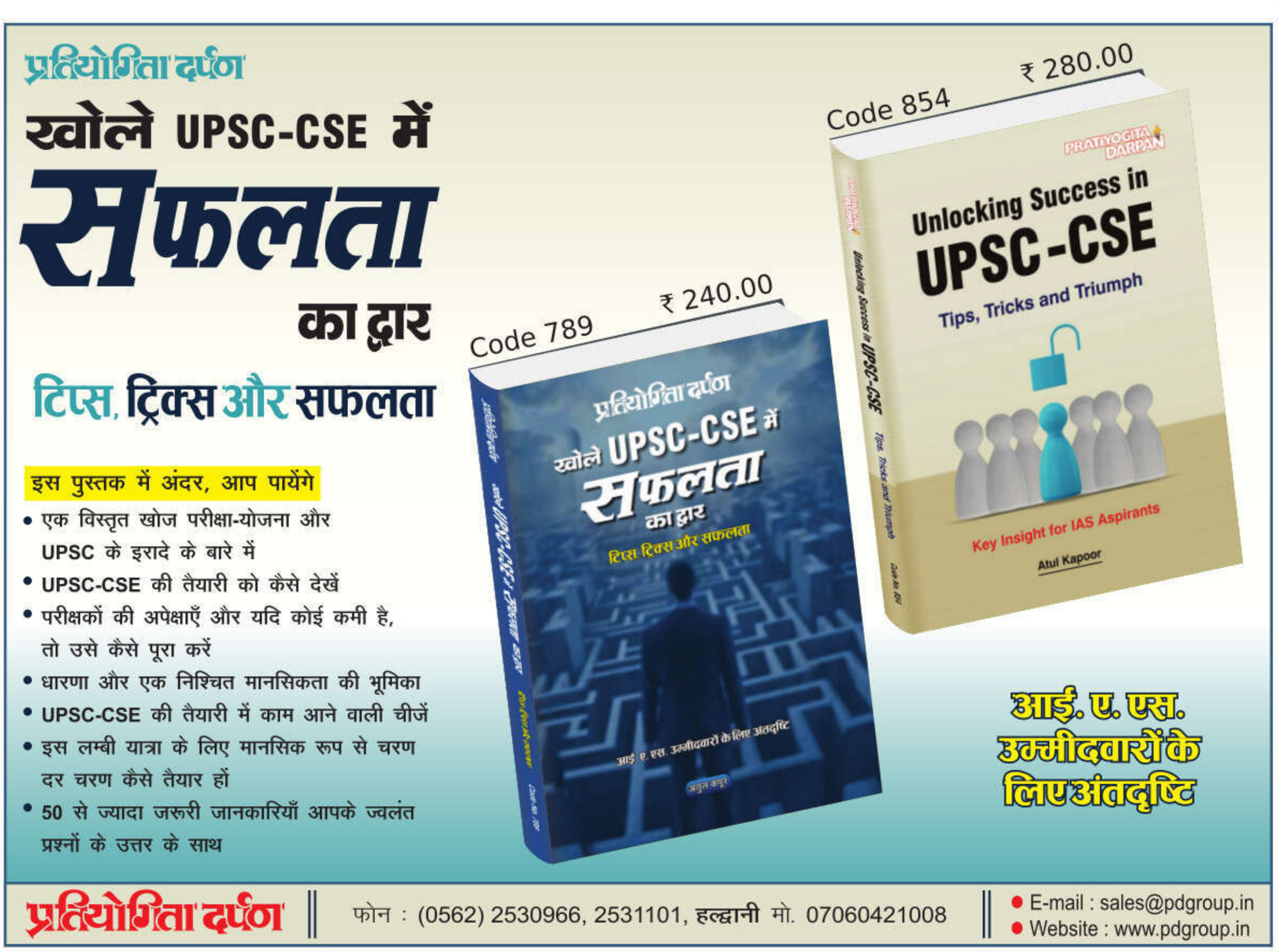
Prelims 2026 में अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं; यह आपको अपनी चीजों को फिर से व्यवस्थित करने और आपके पास मौजूद संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने का एक मौका देता है. अपनी योजनाओं के अनुसार काम करें और अपनी पूरी जान लगा दें.

Prelims में आपकी सफलता, अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा और अंतिम नतीजों के लिए आपकी उम्मीदों को जिन्दा रखेगी.

इसलिए, तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, हर एक दिन कीमती है !

मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं !

●●●



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

"मेरी सफलता के मुख्य कारक, ईमानदारी से लक्ष्य के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत मेरे माता-पिता का विश्वास व समर्थन रहा है"

—राघव झुनझुनवाला

सिविल सेवा परीक्षा, 2025 में चयनित (चौथा स्थान)

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, 2025 में चयनित होकर श्री राघव झुनझुनवाला ने एक गौरवपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, जिसके लिए वह प्रशंसा एवं हमारी हार्दिक बधाई के पात्र हैं. प्रतियोगिता दर्पण के साथ उनकी महत्वपूर्ण भेंटवार्ता यहाँ मूलरूप में प्रस्तुत है.



प्र. द.—सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता पर प्रतियोगिता दर्पण परिवार की ओर से हार्दिक बधाई.

श्री राघव—जी, बहुत-बहुत धन्यवाद !

प्र. द.—इन सेवाओं में आपने क्या सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी ?

श्री राघव—मेरी पहली प्राथमिकता आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) व दूसरी आईएफएस (भारतीय विदेश सेवा) थी.

प्र. द.—सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने का विचार कब आया; कोई ऐसी प्रेरणा जिसने आपको सिविल सेवा की ओर आकर्षित किया ?

श्री राघव—सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने का निर्णय मैंने कॉलेज के अन्तिम वर्ष लिया. हालाँकि, यह विचार किसी एकाएक प्रेरणा का परिणाम नहीं था. अपने कॉलेज के प्रारम्भिक वर्षों से ही मैं कॉलेज की एक सोसाइटी 'वित्त शाला' से जुड़ा रहा हूँ, जो समाज के गरीब तबके, समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीय समावेशन के लिए कार्यरत है. इस संस्था के कार्यक्रमों में भाग लेने के दौरान मेरे अन्दर बार-बार समाज के इन पिछड़े तबकों के लिए बड़े स्तर पर कार्य करने की प्रेरणा आती रहती थी. अतः सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अन्य कारणों के साथ उपर्युक्त वर्णित प्रेरणा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

प्र. द.—यह आपका कौनसा प्रयास था ?

श्री राघव—यह मेरा तीसरा प्रयास था. पहले प्रयास में प्रारम्भिक परीक्षा पास करने के बाद कुछ स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्या के कारण मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ. दूसरे प्रयास में साक्षात्कार तक पहुँचने के बाद अन्तिम परिणाम सूची में मेरा नाम नहीं आया. अन्ततः इस तीसरे प्रयास में मुझे अन्तिम रूप से सफलता प्राप्त हुई है.

भाषा माध्यम—अंग्रेजी
प्रयास—तीसरा
वैकल्पिक विषय—अर्थशास्त्र

प्र. द.—आपकी राय में तैयारी की शुरुआत के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार कौनसे हैं ?

श्री राघव—सर्वप्रथम, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी की योजना बना रहे हैं, उसके लिए स्वप्रेरणा सबसे आवश्यक है. किसी दूसरे के कहने या अन्य दबाव में आप तैयारी तो प्रारम्भ कर सकते हैं, लेकिन स्वप्रेरणा के बिना आप कभी भी शत-प्रतिशत अपना आउटकम नहीं दे पाते हैं.

प्र. द.—आपका वैकल्पिक विषय क्या था. साथ ही इसके चुनाव का आधार क्या रहा ?

श्री राघव—मेरा वैकल्पिक विषय अर्थशास्त्र था. वैकल्पिक विषय चुनाव का सर्वप्रमुख आधार मेरी व्यक्तिगत रुचि थी. दूसरा यह विषय मेरा स्नातक विषय भी रहा है.

वैकल्पिक विषय के चुनाव का आधार

- व्यक्तिगत रुचि (सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक)
- सही मार्गदर्शन, सिविल सेवा परीक्षा के अन्य विषयों में उपयोगिता
- उपलब्ध स्रोत सामग्री व मानक पुस्तकों की उपलब्धता

प्र. द.—क्या आप इस प्रयास में अपनी तैयारी एवं परीक्षा में निष्पादन से सन्तुष्ट थे और उच्च सफलता के प्रति आशावान थे ? सफलता के इस समाचार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री राघव—ईमानदारी से कहूँ तो अन्तिम परिणाम के प्रति इस वर्ष भी मैं अधिक आश्वस्त नहीं था. ऐसा इसलिए, क्योंकि इस वर्ष मैं अपने साक्षात्कार में प्रदर्शन से अधिक संतुष्ट नहीं था. अतः पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अन्तिम परिणाम में चयन को लेकर एक संशय था. हालाँकि, अन्तिम रूप से चयन मेरी मेहनत, ईश्वर, माता-पिता व परिवारजनों का आशीर्वाद है कि मैं यह स्थान हासिल कर सका. सफलता के समाचार पर स्वाभाविक रूप से एक संतुष्टि का भाव आया.

प्र. द.—क्या तैयारी के शुरू में आपने अपने लिए इस परीक्षा का सामना करने के लिए कोई समय-सीमा या प्रयासों की संख्या सम्बन्धी सोच बनाई थी ?

श्री राघव—जी हाँ, मैंने निश्चय किया था कि मैं अपने सभी प्रयासों को देने की बजाय लगभग तीन प्रयास ही दूँगा. हालाँकि, मुझे यह विश्वास था कि इन निर्धारित प्रयासों में भी समर्पण और कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है. यही कारण है कि पहले दो प्रयासों में असफलता के बाद भी मैं निराश नहीं हुआ, बल्कि अपने अगले प्रयास के लिए तैयारी शुरू की.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

प्र. द.—प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी की क्या रणनीति रही ?

श्री राघव—

प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
सामान्य अध्ययन (प्रश्न-पत्र-I) ● सर्वप्रथम पाठ्यक्रम को गहनता से समझना. ● सभी विषयों पर किसी मानक पुस्तक से अध्ययन. ● अपने स्वयं के संक्षिप्त नोट्स, उनका अपडेशन व बार-बार रिवीजन. ● अभ्यास के लिए PYQs को हल करना व उनकी प्रकृति के आधार पर भविष्य हेतु तैयारी योजना बनाना व PYQs प्रकृति को मैच करते हुए टेस्ट पेपर को हल करना. **सामान्य अध्ययन (प्रश्न-पत्र-II)** ● वर्तमान समय में यह सबसे चुनौतीपूर्ण पेपर रहा है, इसलिए प्रारम्भिक परीक्षा से कुछ माह पूर्व से ही इस प्रश्न-पत्र हेतु अध्ययन व टेस्ट पेपर के माध्यम से निरन्तर अभ्यास. ● दूसरा इस पेपर के अन्तर्गत अपने सबसे मजबूत सब्जेक्ट को स्कोरिंग बनाए.	● मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए वर्तमान में चर्चित समसामयिक मुद्दों के साथ उनके स्टेटिक भाग को भी कवर करना. ● अत्यधिक लेखन अभ्यास. ● विश्वसनीय टेस्ट सीरीज व मूल्यांकन के आधार पर कमियों को दूर करना. ● लेखन अभ्यास के समय उत्तरों को डायग्राम और पॉइंटर्स के साथ लिखने का अभ्यास. ● उत्तर लेखन के लिए अपने कन्टेंट को चैट जीपीटी या अन्य सहायक स्रोतों से मूल्यवर्धन करते रहना.

प्र. द.—साक्षात्कार के दौरान आपसे किन टॉपिक्स पर सवाल पूछे गए थे ?

श्री राघव—साक्षात्कार के दौरान मेरे वैकल्पिक विषय अर्थशास्त्र से सवाल पूछे गए जैसे—अर्थव्यवस्था में रेगुलेशन और डिरेगुलेशन से तात्पर्य, करेंसी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी आदि. इसके अतिरिक्त मेरी व्यक्तिगत रुचि व अन्य विषयों से सम्बन्धित भी प्रश्न पूछे गए थे.

प्र. द.—सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में भाषा माध्यम का क्या फर्क पड़ता है ?

श्री राघव—व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि भाषा एकमात्र अभिव्यक्ति का माध्यम है. आप जिस भाषा में सर्वाधिक सहज रहें, आपको अपना भाषा माध्यम वही रखना चाहिए. दूसरा, UPSC की परीक्षा बहुत ही पारदर्शी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि भाषा के माध्यम से कोई भेदभाव सम्भव है. ऐसा इसलिए, क्योंकि हिन्दी माध्यम से भी अभ्यर्थी शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं. अतः भाषा माध्यम को लेकर मेरा सुझाव यही है कि किसी माध्यम में आप स्वयं को तैयारी के लिए फोर्स न करें. आप जिस भाषा में सर्वाधिक सहज हैं, उसी का चुनाव करें.

प्र. द.—सिविल सेवा केवल यही एकमात्र लक्ष्य था या किसी और कॅरियर विकल्प के लिए साथ-साथ तैयारी कर रहे थे ?

श्री राघव—प्राथमिकता सिविल सेवा ही मेरा लक्ष्य था. हालाँकि, अन्य कॅरियर विकल्प के रूप में मैं किसी गैर-लाभकारी संगठन के साथ काम करने की भी योजना बना रहा था अर्थात् बहुत स्पष्ट कहूँ तो अगर मेरी यूपीएससी यात्रा सफल नहीं होती तो मैं एक प्रभावशाली परामर्श फर्म में काम करने की योजना बना रहा था.

प्र. द.—अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे ?

श्री राघव—इस सफलता के पीछे कोई एक व्यक्ति या कारक नहीं है. यह मेरी, मेरे परिवार, मेरे करीबी दोस्तों और मेरे शुभचिन्तकों द्वारा किए गए संचयी प्रयासों की सफलता है. मेरा यह मानना है कि जब आप कोई प्रयास पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलती है.

प्र. द.—प्रारम्भिक परीक्षा में ऋणात्मक अंकन (नेगेटिव मार्किंग) से बचने के लिए क्या सावधानी बरती ?

श्री राघव—प्रारम्भिक परीक्षा में ऋणात्मक अंकन से बचने के लिए मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से बचता था, जहाँ मेरे अनुसार सवाल के 50 प्रतिशत से अधिक गलत होने की सम्भावना है. दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं अक्सर ऐसे सवालों को स्किप कर देता था जिसमें मुझे अधिक संदेह रहता था.

व्यक्ति परिचय

नाम—राघव झुनझुनवाला
पिता का नाम—स्व. नवीन झुनझुनवाला
माता का नाम—अंजू देवी
शैक्षिक योग्यता—
स्नातक (अर्थशास्त्र ऑनर्स)—श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (नई दिल्ली)

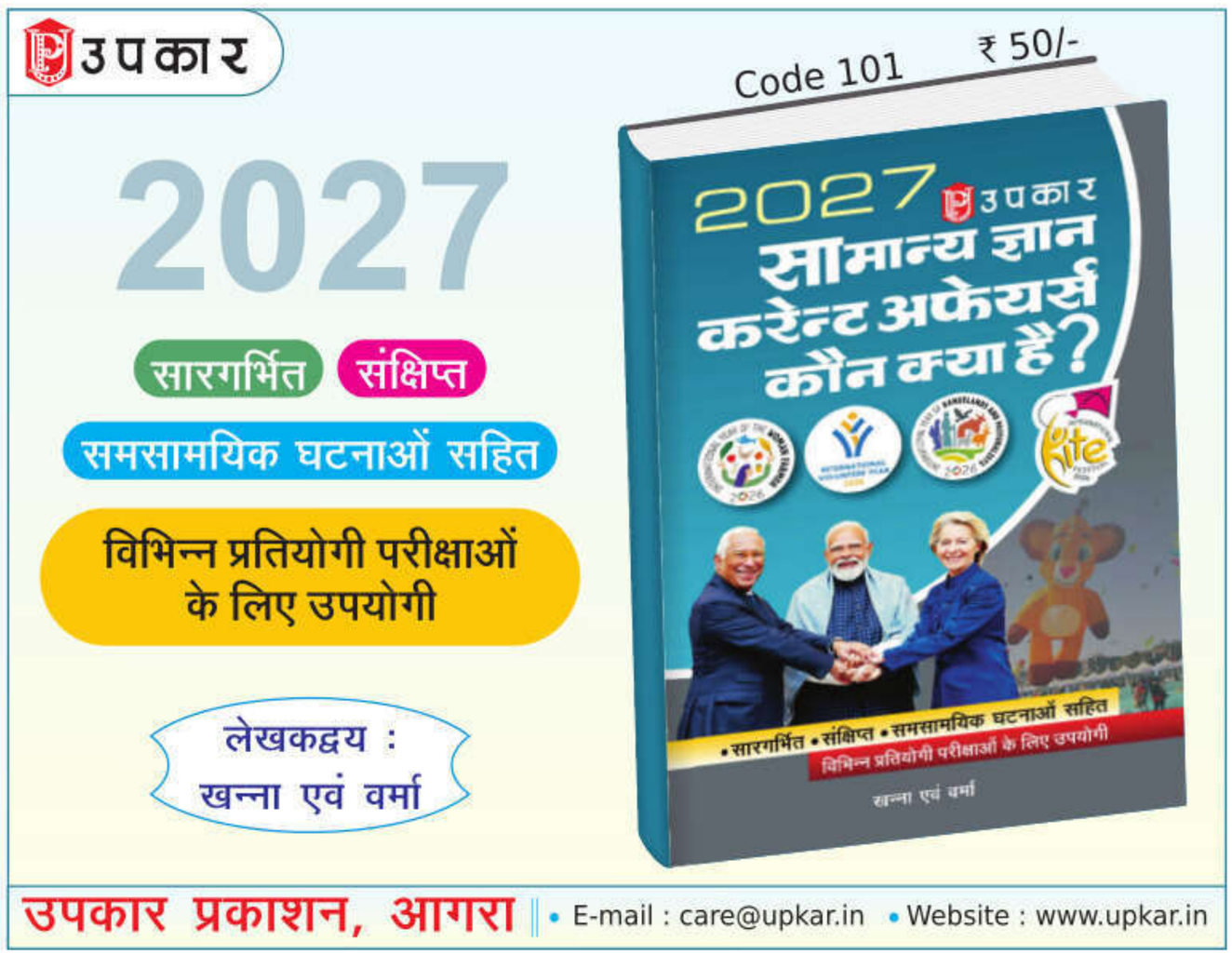
प्र. द.—कोई सुझाव या संदेश अभ्यर्थियों को देना चाहेंगे ?

श्री राघव—ऐसे अभ्यर्थी जो सिविल सेवा में आना चाहते हैं, सर्वप्रथम स्वयं पर विश्वास रखें कि आप कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं. दूसरा ईमानदारी-पूर्वक अपने निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पण रखे.

व्यक्तिगत विशेषताएँ

पसंदीदा व्यक्तित्व—मेरे परिवारजन
सबल पक्ष—स्वयं पर विश्वास
दुर्बल पक्ष—कुछ विशेष नहीं.
रुचियाँ—फोटोग्राफी, स्थानीय गाइड के रूप में गूगल मानचित्र में योगदान देना, यात्रा ब्लॉग देखना आदि.

प्र. द.—आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ. ●●●



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

मेरी सफलता का मूलमंत्र है, "धैर्य, संकल्प और दृढ़-निश्चय"

—अक्षत सिंघल

सिविल सेवा परीक्षा, 2025 में चयनित (352वाँ स्थान)

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, 2025 में चयनित होकर श्री अक्षत सिंघल ने एक गौरवपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, जिसके लिए वह प्रशंसा एवं हमारी हार्दिक बधाई के पात्र हैं. प्रतियोगिता दर्पण के साथ उनकी महत्वपूर्ण भेंटवार्ता यहाँ मूलरूप में प्रस्तुत है.



प्र. द.—सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता पर प्रतियोगिता दर्पण परिवार की ओर से हार्दिक बधाई.

श्री अक्षत—बहुत-बहुत धन्यवाद सर !

प्र. द.—इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको मन में सर्वप्रथम विचार कब आया व इसके लिए सही सलाह कहाँ से मिली ?

श्री अक्षत—सिविल सेवा के लिए तैयारी का विचार कॉलेज के बाद मेरी पहली जॉब के दौरान आया. वर्ष 2019 में 'भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (आईईएस)' में चयन के बाद वर्ष 2023 में मेरे मन में यह विचार आया कि मुझे प्रशासनिक सेवा के लिए ट्राई करना चाहिए. इस विचार के लिए स्वप्रेरणा के साथ-साथ मेरे ही गृह जिले से चयनित आईएएस हिमांशु मंगल व मेरे मित्र मोहित मंगल (सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे) से सलाह लेकर मैंने अपनी जॉब के साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की भी तैयारी प्रारम्भ कर दी थी.

प्र. द.—प्रशासनिक सेवाओं की किन खूबियों ने आपको इस ओर कॅरियर के लिए अत्यधिक प्रेरित किया ?

श्री अक्षत—सर, मेरा इस सन्दर्भ में मानना है कि सिविल सेवा आपको ऐसे विविध अवसर प्रदान करती है, जहाँ आपको भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अपनी सर्विस के दौरान कार्य करने व सुधारों का अवसर मिलता है. आपको प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी के साथ जमीनी स्तर पर लोगों के लिए कार्य करने का अवसर भी मिलता है. उपर्युक्त कार्य व विस्तार ही प्रशासनिक सेवा को अन्य सेवाओं से अलग करती है.

प्र. द.—यह आपका कौनसा प्रयास था ?

श्री अक्षत—यह मेरा चौथा प्रयास था. मैं अपने पहले व दूसरे प्रयास में जहाँ प्रारम्भिक परीक्षा में असफल रहा, वहीं अपने तीसरे प्रयास में साक्षात्कार पास नहीं कर सका. अपने इस चौथे प्रयास में, मैंने पुनः साक्षात्कार दिया और अन्तिम रूप से सफलता मुझे मिली है.

प्र. द.—क्या आप इस प्रयास में अपनी तैयारी एवं परीक्षा में निष्पादन से सन्तुष्ट थे ?

श्री अक्षत—जी हाँ, मुझे विश्वास था, ऐसा इसलिए, क्योंकि पिछले प्रयास में साक्षात्कार तक पहुँचने के बाद मुझे अपनी तैयारी सही दिशा में लग रही थी. अतः इस प्रयास में मैंने अपनी छोटी-छोटी गलतियों में सुधार कर उसे पूरा किया.

भाषा माध्यम—अंग्रेजी
प्रयासों की संख्या—4
वैकल्पिक विषय—नृविज्ञान (एंथ्रोपोलॉजी)

प्र. द.—अपना परिणाम जानने से पहले आप टॉपर्स के बारे में क्या सोचते थे ? क्या इनमें से किसी टॉपर्स से आप प्रभावित हुए ?

श्री अक्षत—बचपन में ऐसा विचार आता था कि यूपीएससी बहुत कठिन परीक्षाओं में से एक है, अतः जो भी विद्यार्थी इसमें सफल होते हैं वह अत्यधिक मेधावी छात्र ही होते होंगे, इसके साथ टॉपर्स में कुछ स्पेशल होता होगा या फिर वह 18-20 घण्टे पढ़ते होंगे. हालाँकि, जब इस परीक्षा की तैयारी मैंने शुरू की तो मुझे यह समझ आया कि यह परीक्षा बहुत ही प्रबंधकीय प्रकृति की है. अतः जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी के दौरान सही प्रबंधकीय रणनीति अपनाता है वह सफलता प्राप्त कर सकता है. यहाँ प्रबंधकीय रणनीति से तात्पर्य परीक्षा तैयारी के लिए सही रणनीति, अध्ययन स्रोतों का सही चुनाव व अन्य ऐसे ही कारकों से हैं.

प्र. द.—ऐसे विद्यार्थी जो प्रशासनिक सेवाओं को कॅरियर बनाना चाहते है, हालाँकि वह अभी इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं. अतः इसके लिए सही रणनीति व सलाह क्या हो सकती है ?

श्री अक्षत—सर, मुझे लगता है जो भी विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं को अपना कॅरियर बनाना चाहता है, उसे सबसे पहले स्वयं से यह सवाल पूछना चाहिए कि 'यही क्यों' ? दूसरा इसे किसलिए प्राप्त करना है ? और तीसरा इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ? जब उपर्युक्त तीनों सवालों के बहुत स्पष्ट जबाव आपके पास होते हैं, तो सफलता तक लगने वाले समय, परीक्षा के किसी भी चरण में असफलता, आदि से आप निराश नहीं होंगें.

तैयारी के लिए सही सलाह व रणनीति के सम्बन्ध में मेरा मानना है कि यह व्यक्तिगत होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि सभी की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं. हालाँकि, तैयारी शुरुआत में आप किसी सफल अभ्यर्थी, कोचिंग संस्थान या अन्य माध्यमों से सलाह लेकर तैयारी प्रारम्भ कर सकते हैं.

प्र. द.—प्रारम्भिक, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई ?

श्री अक्षत—जॉब के साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए मेरे अधिकांश स्रोत ऑनलाइन ही थे. इसके अतिरिक्त मैंने प्रारम्भिक परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले वर्षों के टॉपर्स के नोट्स में कुछ एड ऑन करके उनका अध्ययन सामग्री के रूप में उपयोग किया. मुख्य परीक्षा के लिए मैंने अधिक-से-अधिक उत्तर लेखन का अभ्यास किया. कोचिंग संस्थाओं के टेस्ट पेपर लिखे व पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों के आधार पर प्रश्नों की प्रकृति व वर्तमान में पूछे

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

जा सकने वाले प्रश्नों का विश्लेषण किया. साक्षात्कार के लिए अपने ऐसे मित्र जो सिविल सेवा की तैयारी में लगे हुए थे, एक ऑनलाइन ग्रुप बनाकर मॉक इंटरव्यू की तैयारी की. इस ग्रुप के माध्यम से हम सारे मित्र किसी ज्वलंत व महत्वपूर्ण टॉपिक पर विचार-विमर्श करते थे.

प्र. द.—प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु क्या रणनीति रही, क्या इसे आपने एक साथ किया या फिर अलग-अलग ?

श्री अक्षत—प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी मैंने एक साथ ही की.

प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
● सर्वप्रथम इस बहुतायत इन्फॉर्मेशन के दौर में अपने मानक अध्ययन स्रोतों की पहचान करना व उन्हें सीमित रखना.	● परीक्षा पाठ्यक्रम व वर्तमान पैटर्न के अनुरूप तैयारी.
● सभी विषयों के लिए किसी एक मानक पुस्तक का चयन.	● सम्पादकीय या किसी समसामयिक मुद्दे पर बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए उत्तर लेखन का अभ्यास करना.
● पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों (PYQs) के आधार पर प्रश्नों की प्रकृति समझना व तैयारी करना.	● ऐसे विषय जहाँ आप स्वयं को कमजोर पाते हैं, किसी विशेषज्ञ या अन्य सीनियर्स की मदद से तैयारी कर सकते हैं.
● टॉपर्स नोट्स आदि का अपने इनपुट जोड़कर तैयारी में सहायता लेना.	● विश्वसनीय टेस्ट सीरीज से निरन्तर लेखन अभ्यास व मूल्यांकन के आधार पर सुधार का प्रयास करते रहना आदि.
● समसामयिक मुद्दों पर किसी मानक मासिक पत्रिका से तैयारी करना..	

प्र. द.—प्रारम्भिक परीक्षा में ऋणात्मक अंकन (नेगेटिव मार्किंग) के लिए क्या सावधानी बरती ?

श्री अक्षत—सर, मेरा मानना है कि प्रारम्भिक परीक्षा एक विद्यार्थी के माइंडसैट का परीक्षण है. ऐसा इसलिए, क्योंकि जब आप किसी भी वर्ष का प्रारम्भिक परीक्षा का प्रश्न-पत्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि 30-35 सवाल ही ऐसे है जिनका आप शत-प्रतिशत उत्तर दे पाने की स्थिति में है. शेष प्रश्नों के सम्बन्ध में आपको थोड़ा बहुत तार्किक अनुमान (Intelligent guessing), एलिमिनेट पद्धति आदि से उत्तर निकालना होता है. तार्किक अनुमान व एलिमिनेट पद्धति के समय एक अभ्यर्थी का पॉजिटिव माइंडसैट ही उसे विश्वास (Belief) दिलाता है कि उसने जो पढ़ा है और वह जिस उत्तर का चयन कर रहा है वह सही है.

प्रारम्भिक परीक्षा में ऋणात्मक अंकन से बचने के लिए मैंने ऐसे प्रश्नों का ही उत्तर दिया जिसमें या तो मैं शत-प्रतिशत कन्फर्म हूँ या लॉजिकल अनुमान से उनका उत्तर निकाल पा रहा हूँ. अन्य प्रश्नों को मैंने स्किप कर दिया था.

प्र. द.—मुख्य परीक्षा की तैयारी की योजना में क्या विशेष परिवर्तन किया ?

श्री अक्षत—सर, मुख्य परीक्षा के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन विषयों की बात करें तो उत्तर लिखते समय प्रश्न की माँग को समझना और उसके अनुसार उत्तर लिखना सबसे महत्वपूर्ण है. ऐसा इसलिए, क्योंकि जो भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होता है उसके पास Knowledge की कमी तो नहीं होती है. अतः ऐसे में अन्तर प्रश्न की माँग के अनुरूप उत्तर लेखन ही करता है.

तैयारी के दौरान आप बार-बार पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों को देखकर उनकी माँग के अनुरूप उत्तर लेखन का अभ्यास कीजिए. मूल्यांकन के लिए इसे आप अपनी कोचिंग, सीनियर्स या ग्रुप आदि में भेजकर कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए.

दूसरा निर्धारित समय में उत्तर लेखन अभ्यास, ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्य परीक्षा के प्रश्न-पत्र का निर्धारित समय में उत्तर लेखन बहुत चुनौतीपूर्ण होता है. अतः पूर्व में निर्धारित समय में उत्तर लेखन अभ्यास इस समस्या के समाधान में सहायक होता है.

प्र. द.—क्या तैयारी के शुरू में आपने अपने लिए इस परीक्षा का सामना करने के लिए कोई समय-सीमा या प्रयासों की संख्या सम्बन्धी सोच बनाई थी ?

श्री अक्षत—जी हाँ, प्रारम्भ में इसके लिए 0 2-3 वर्षों का समय मैंने निर्धारित किया था. हालाँकि, अंतिम सफलता में मुझे कुछ अतिरिक्त वर्षों का समय लगा.

प्र. द.—आपने वैकल्पिक विषय का चुनाव किस आधार पर किया व इसकी तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनाई ?

श्री अक्षत—मेरा वैकल्पिक विषय नृविज्ञान (एंथ्रोपोलॉजी) था. इस विषय के चुनाव का सर्वप्रमुख आधार यह रहा कि मुझे यह काफी रुचिकर लगता है.

वैकल्पिक विषय : तैयारी रणनीति

- सर्वप्रथम सही विषय का चुनाव (सही चुनाव से तात्पर्य आपके पसंदीदा व रुचिकर विषय से है).
- एक बार विषय चयन के बाद पूरे विश्वास के साथ तैयारी अर्थात् बार-बार परिवर्तन की प्रवृत्ति से बचना.
- पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों व वर्तमान पैटर्न के अनुरूप संक्षिप्त नोट्स व अधिक-से-अधिक लेखन अभ्यास करना आदि.

प्र. द.—साक्षात्कार हेतु किस प्रकार की तैयारी की. साक्षात्कार में आपसे कैसे प्रश्न पूछे गए ?

श्री अक्षत—सर, साक्षात्कार की तैयारी के लिए हमारा एक सिविल सेवा की तैयारी कर रहे दोस्तों का ऑनलाइन ग्रुप था, जहाँ हम सभी वर्तमान में चल रहे मुद्दों पर गहन विश्लेषण करते थे.

मेरे साक्षाकार के समय अमेरिका-भारत ट्रेड डील से सम्बन्धित मुद्दा अधिक चर्चा में था, अतः साक्षात्कार बोर्ड ने भी इसी से सम्बन्धित प्रश्न से शुरुआत की.

अन्य साक्षात्कार प्रश्न मेरे बी.टेक., इंडिगो फ्लाइट मुद्दा, गृह जिला व गृह राज्य से सम्बन्धित थे.

साक्षात्कार के दौरान पूछे गए प्रश्नों की बात करू तो सर्वप्रथम अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर साक्षात्कार बोर्ड की चेयरपर्सन ने पूछा कि यदि आप भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और आपको इस डील के सम्बन्ध में भारतीय प्रधानमंत्री को सुझाव देना है, तो आप इस सम्बन्ध में क्या सुझाव देंगे ? दूसरा यदि आप अमेरिका को इसी पद पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को क्या सुझाव देंगे ?

अन्य प्रश्न जैसे इंडिगो फ्लाइट समस्या को कैसे हल किया जा सकता था, या उसके

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

सम्बन्ध में क्या-क्या चुनौतियाँ थी ? आपके गृह राज्य जैसे राजस्थान में क्या समस्याएँ हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है ? आदि.

प्र. द.—परीक्षा की तैयारी के लिए सम-सामयिक पत्रिकाओं विशेषतः प्रतियोगिता दर्पण के सम्बन्ध में आपकी क्या राय है ? तैयारी की शुरुआत कर रहे परीक्षार्थियों को इस सम्बन्ध में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ?

श्री अक्षत—समसामयिक पत्रिकाएँ जैसे—प्रतियोगिता दर्पण की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह है कि आपकी तैयारी से सम्बन्धित अधिकांश समसामयिक कंटेट यहाँ सम्मिलित रूप से मिल जाता है. व्यक्तिगत रूप से प्रतियोगिता दर्पण में आने वाले लेखों का नियमित रूप से अध्ययन करने से मुझे मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में अत्यधिक सहायता मिली.

प्र. द.—वर्तमान समय में किसी विद्यार्थी के चयन में कोचिंग संस्था या ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का क्या महत्व है ?

श्री अक्षत—सामान्यतः विद्यार्थियों में यह रूझान रहता है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए किसी कोचिंग संस्था की आवश्यकता रहती है. इस सम्बन्ध में मेरा मानना है कि कोचिंग संस्थाओं की अनिवार्यता जैसी कोई आवश्यकता नहीं है. आप बिना किसी कोचिंग संस्था के भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं. वर्तमान में हमें बहुत सारे ऐसे टॉपर्स देखने को मिले हैं जिन्होंने कोचिंग की अनिवार्यता को अस्वीकार किया है.

ऑनलाइन अध्ययन सामग्री के सम्बन्ध में मेरा मानना है कि यह आपकी तैयारी के लिए वरदान और अभिशाप दोनों सिद्ध हो सकती हैं. अतः आप इस सम्बन्ध में उन्हीं अध्ययन सामग्री का चयन कीजिए जो मानक है, अत्यधिक भ्रामक नहीं. अपनी तैयारी के दौरान मैंने भी अधिकांश तैयारी ऑनलाइन स्रोतों से ही की है. अतः सही ऑनलाइन सामग्री आपकी सफलता का भी रास्ता तय करा सकती है.

प्र. द.—सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में भाषा माध्यम का क्या फर्क पड़ता है ?

श्री अक्षत—सर, मुझे नहीं लगता भाषा माध्यम का कोई फर्क पड़ता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि सफलता आपके व्यक्तित्व परीक्षण, उत्तर लेखन और प्रशासनिक मुद्दों पर सोचने-समझने की क्षमता पर निर्धारित होता है. भाषा, अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है.

प्र. द.—सिविल सेवा परीक्षा बहुत अप्रत्याशित है. अनेकों बार कई मेधावी छात्र भी इसमें अंतिम सफलता से वंचित रह जाते हैं. ऐसे में अभ्यर्थियों को क्या कोई अन्य कॅरियर विकल्प रखना चाहिए. इस सम्बन्ध में आपकी क्या राय है ?

श्री अक्षत—इस सम्बन्ध में मेरा मानना है कि प्रारम्भ में कम-से-कम दो प्रयास विद्यार्थियों को बिना किसी संशय के पूर्ण समर्पण से देना चाहिए. तत्पश्चात् यदि कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आता है तब आप तैयारी के साथ ही अन्य विकल्प पर विचार कर सकते हैं. सिविल सेवा परीक्षा की प्रकृति, सब्जेक्टिविटी और थोड़ा सफलता के लिए लक फैक्टर बहुत बार आपको अन्य जॉब को करते हुए भी इसमें सफलता दिला सकता है.

व्यक्तिगत विशेषताएँ

पसंदीदा व्यक्तित्व—*मेरे आदरणीय चाचा जी व परिवारजन*

सबल पक्ष—*आत्म-विश्वास व समय-प्रबन्धन*

दुर्बल पक्ष—*कुछ विशेष नहीं.*

रुचियाँ—*खेलों (क्रिकेट, बैडमिंटन व अन्य) के प्रति अधिक रुझान*

प्र. द.—क्या अभ्यर्थी के आर्थिक और सामाजिक स्थिति का प्रभाव तैयारी पर पड़ता है ? यदि हाँ, तो कैसे ?

श्री अक्षत—सर, इस सम्बन्ध में मेरा मानना है कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए आर्थिक पृष्ठभूमि का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है. जहाँ तक सामाजिक पृष्ठभूमि की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि इस आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है. आप किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आकर यहाँ सफलता प्राप्त कर सकते हैं. प्रत्येक वर्ष टॉपर्स लिस्ट में भी हमें अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्र सफल होते दिखते हैं.

प्र. द.—अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे ?

श्री अक्षत—सर्वप्रथम माता-पिता व परिवार जन के अन्य सदस्यों के साथ अपने दोस्तों को.

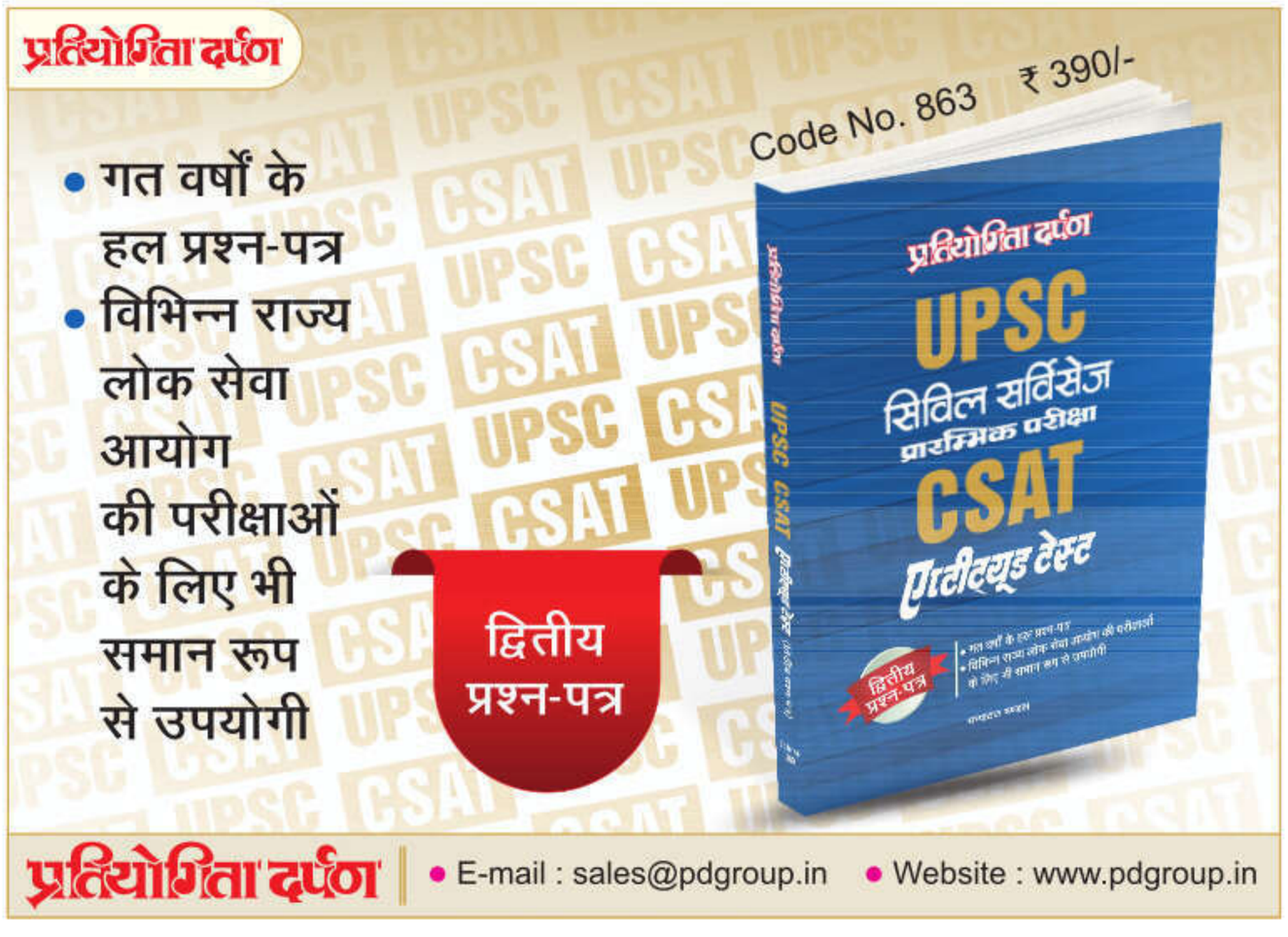
प्र. द.—कोई सुझाव या सन्देश अभ्यर्थियों को देना चाहेंगे ?

श्री अक्षत—सर्वप्रथम यही कि जो भी इसकी तैयारी करना चाहता है, उसको क्लियर होना चाहिए कि वह इस सेवा में क्यों आना चाहता है ? यदि उसका लक्ष्य क्लियर होगा तो वह आने वाले व्यवधानों से सुरक्षित रहेगा. तत्पश्चात् तैयारी के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सही रणनीति व दिशा अपनाना आदि.

व्यक्ति परिचय

नाम—अक्षत सिंघल
पिता का नाम—श्री दिनेश चंद सिंघल
माता का नाम—श्रीमती रेखा सिंघल
शैक्षिक योग्यता—
10th—विवेकानन्द संस्कार सीनियर सेकण्डरी स्कूल, गंगापुर सिटी–92 प्रतिशत
12th—डीएस साइंस एकेडमी – गंगापुर सिटी–94 प्रतिशत
बी.टेक. (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)—एमएनआईटी जयपुर—80 प्रतिशत
पूर्व चयन—भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (2019)

प्र. द.—आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ. ●●●



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

NTA यू.जी.सी.

नेट जेआरएफ सेट परीक्षा

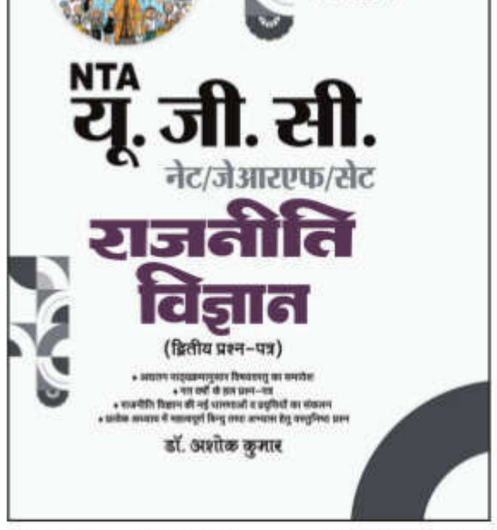
‖ नवीन संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित ‖

गत वर्षों के हल प्रश्न-पत्र सहित

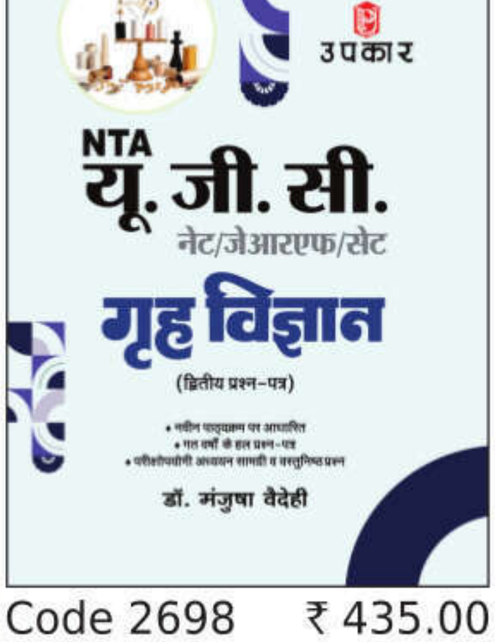
उपकार प्रकाशन की उपयोगी पुस्तकें



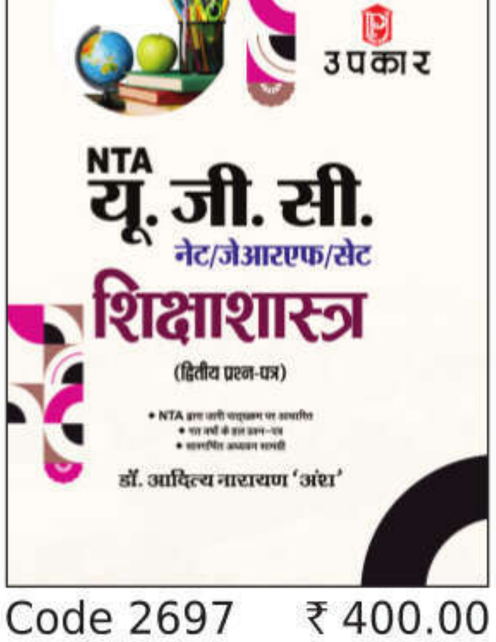
Code 200 ₹ 465.00



Code 2258 ₹ 580.00



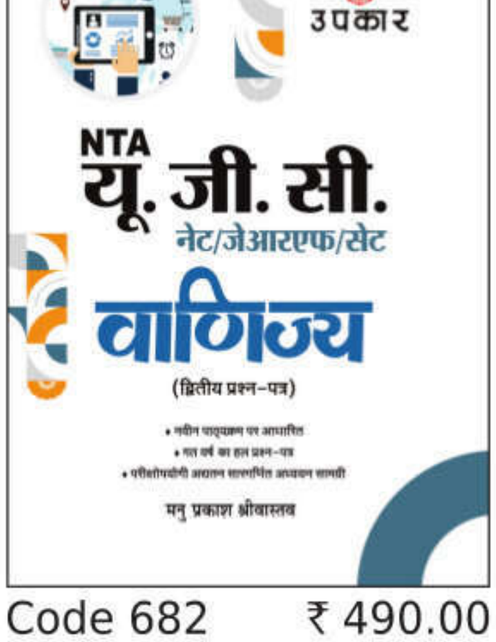
Code 2328 ₹ 515.00



Code 2558 ₹ 899.00



Code 2459 ₹ 490.00



Code 2711 ₹ 625.00

Code 2698 ₹ 435.00

Code 2697 ₹ 400.00

Code 2270 ₹ 735.00

Code 682 ₹ 490.00

उपकार प्रकाशन ‖ 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास रोड, आगरा-282 005
फोन : (0562) 2530966, 2531101 • हल्द्वानी मो. 07060421008 ‖ • E-mail : sales@upkar.in • Website : www.upkar.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



दिव्य दर्पण

संघ एवं राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण

अधूरेपन से पूर्णता का सफर

नेल्सन मंडेला का एक प्रसिद्ध कथन कि "जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव लगता है." जीवन के एक बड़े यथार्थ को उजागर करता है. यह अधूरापन अक्सर हमारे मन में किसी कार्य के प्रति सन्देह और कभी-कभी डर पैदा करता है. जब हम किसी बड़े लक्ष्य की शुरुआत करते हैं, तो वह एक ऊँचे पहाड़ जैसा दिखता है. रास्ते की कठिनाइयाँ और बीच में आने वाली बाधाएँ हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद हम इसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन याद रखिए, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से कदम और 'अधूरेपन' के उसी अहसास से होती है.

काम के अधूरा लगने के पीछे मुख्य कारण हमारा नजरिया है. हम अक्सर परिणाम पर इतना ध्यान केन्द्रित कर देते हैं कि प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं.

अधूरापन नकारात्मक नहीं है; यह इस बात का प्रमाण है कि आप प्रयास कर रहे हैं. धैर्य रखें, क्योंकि कोई भी महान कृति रातों-रात तैयार नहीं होती. किसी भव्य इमारत की पहली ईंट रखने पर वह महल नहीं, बल्कि सिर्फ एक गड्ढा ही लगा होगा. जब काम अधूरा लगे और थकान होने लगे, तब अनुशासन ही वह शक्ति है, जो आपको अन्तिम छोर तक ले जाती है. खुद पर भरोसा रखें कि जो शुरू किया है, उसे पूरा करने की क्षमता भी आप में ही है.

अधूरापन केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं. जिस क्षण आप हार न मानने का संकल्प लेकर आखिरी कदम बढ़ाते हैं, वही अधूरा काम आपकी सफलता की कहानी बन जाता है. इसलिए, अधूरेपन से घबराएँ नहीं, बल्कि इसे पूरा करने के जुनून में बदल दें. याद रखें, पूर्णता की चमक केवल उन्हीं को मिलती है, जो अधूरेपन के अँधेरे से गुजरने का साहस रखते हैं.

अन्तर्राष्ट्रीय

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न–"होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसी भू-राजनीतिक चोकपॉइंट्स में व्यवधान न केवल वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच रणनीतिक पुनर्गठन को भी मजबूर करता है. हालिया पश्चिम एशियाई संकट के सन्दर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए और भारत पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए."

चर्चा में क्यों ?

फरवरी-मार्च 2026 में इजरायल/अमेरिका संघर्ष के कारण उत्पन्न तनाव से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं और वैकल्पिक सुरक्षित मार्गों की खोज तेज हो गई है उल्लेखनीय है कि होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे चोकपॉइंट्स में व्यवधान वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक गम्भीर खतरा है, क्योंकि यहाँ से विश्व के लगभग 25-30% समुद्री तेल और 20% एलएनजी का व्यापार होता है.

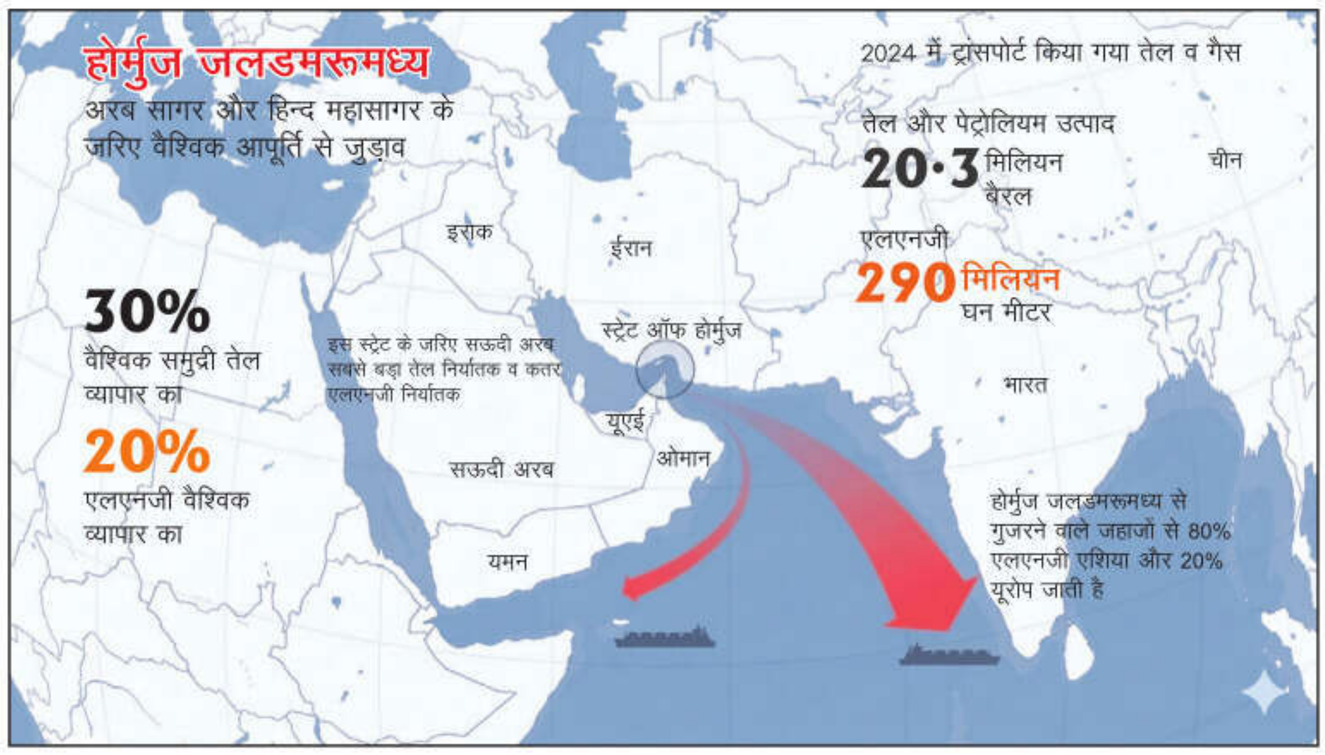
उत्तर–फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण 'धमनी' है. मात्र 33 किमी की संकीर्ण चौड़ाई वाला यह मार्ग विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग 25-30% वहन करता है. हाल ही में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण इस मार्ग का अवरुद्ध होना वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर एक 'सिस्टम शॉक' की तरह है, जिसने शक्ति सन्तुलन और आर्थिक प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित कर दिया है.

ऊर्जा की भू-राजनीति और आपूर्ति का संकट

- होर्मुज जलडमरूमध्य का बंद होना केवल एक परिवहन बाधा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक संकट है.
- उदाहरण के लिए, विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का 50% से अधिक हिस्सा तेल और गैस से आता है. पश्चिम एशियाई देश (सऊदी अरब, यूएई, ईरान और कतर) इसके मुख्य स्रोत हैं, जबकि चीन और भारत जैसे उभरते देश इसके मुख्य उपभोक्ता हैं.
- दूसरा आपूर्ति में अचानक कमी या बाधा से कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार पहुँच गई हैं. यह निर्भर देशों में मुद्रास्फीति को बढ़ाने के साथ वैश्विक विकास दर को भी बाधित करता है.

प्रमुख वैश्विक शक्तियों का रणनीतिक पुनर्गठन

- इस संकट ने अमेरिका, रूस और वेनेजुएला जैसे देशों की ऊर्जा आपूर्ति के सन्दर्भ में भूमिका को बदल दिया है.
- गौरतलब है कि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक (शेल गैस सहित) होने के बावजूद, वैश्विक बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है. होर्मुज के बंद होने से राष्ट्रपति ट्रम्प की आर्थिक गणनाएँ प्रभावित हुई हैं, जिससे अमेरिका को वैकल्पिक कूटनीति अपनाने पर मजबूर होना पड़ा है.
- **रूस : अनपेक्षित लाभार्थी–**2022 के यूक्रेन युद्ध के बाद अलग-थलग पड़ा रूस अचानक 'अनिवार्य' हो गया है. पश्चिम एशिया में उत्पादन बाधित होने



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

से रूसी तेल (जिसके पास बड़ा व्यापार योग्य अधिशेष है) वैश्विक कीमतों को स्थिर करने का एक विकल्प बनकर उभरा है.

- **पश्चिम देशों की नीति में बदलाव**—तेल की कमी को देखते हुए, पश्चिम अब चुपचाप उन रूसी और वेनेजुएला के तेल टैंकरों को बाजार में अनुमति देने के लिए विवश है, जिन्हें पहले प्रतिबंधित किया गया था.

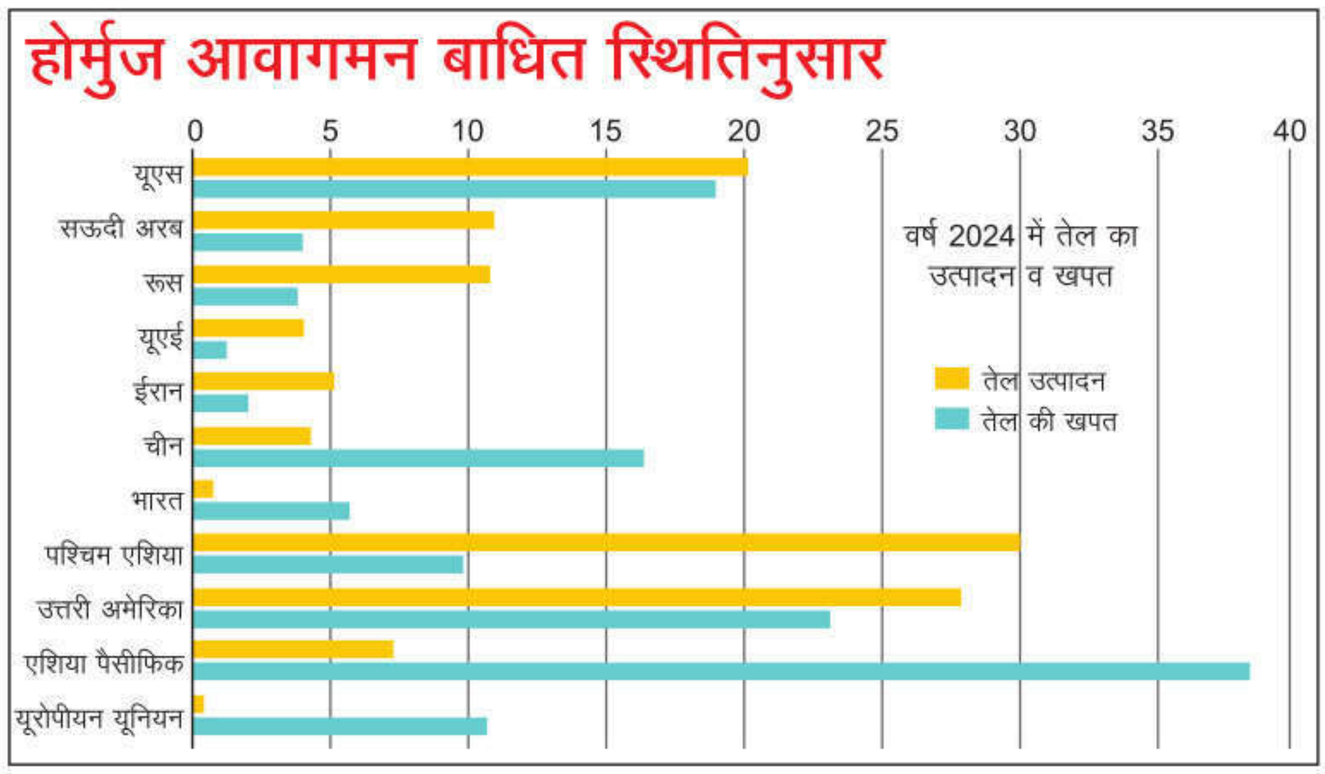
भारत के लिए निहितार्थ और प्रतिक्रिया

- भारत, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, भारत का लगभग 40% कच्चा तेल आयात और लगभग 54% एलएनजी आयात इसी मार्ग से होकर गुजरता है. अतः इस व्यवधान से भारत भी सीधे प्रभावित हुआ है. हालाँकि, भारत ने पूर्व में ही अपनी प्रो एक्टिव नीति से इस व्यवधान को संतुलित किया है.
- उदाहरण—भारत ने अपनी निर्भरता को पूर्व में ही स्थानांतरित करना प्रारम्भ कर दिया था. 2021 में रूस से होने वाला आयात जो मात्र 2-5% था, 2023-24 तक बढ़कर 39% हो गया है.
- भारत ने न केवल रियायती रूसी तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि अपनी विशाल शोधन (Refining) क्षमता का उपयोग करके परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर लाभ भी कमाया.
- भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूसी तेल की खरीद जारी रखी, जिसे अब वैश्विक बाजार में कीमतों को स्थिर रखने वाले एक कारक के रूप में (भले ही अनौपचारिक रूप से) स्वीकार किया जा रहा है.

तेल, शक्ति और व्यवधान की राजनीति

- तेल का नियंत्रण अब केवल आर्थिक संसाधन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक भू-राजनीतिक हथियार बन गया है. वेनेजुएला और ईरान के पास विश्व के 39% सिद्ध तेल भण्डार हैं, जो उन्हें भविष्य की राजनीति का केन्द्र बनाते हैं.
- होर्मुज का संकट यह दर्शाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में "स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं." कल का 'अछूत' रूस आज ऊर्जा संकट का तारणहार बन रहा है.

सारांशतः होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट यह स्पष्ट करता है कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत नाजुक है. भारत जैसे देशों के लिए, यह संकट ऊर्जा आत्मनिर्भरता (Renewables) की दिशा में तेजी से बढ़ने और सामरिक तेल भण्डार (Strategic Petroleum Reserves) को मजबूत करने की चेतावनी है. अंततः, तेल की राजनीति में शक्ति का केन्द्र वहीं झुकता है, जहाँ आपूर्ति सुरक्षित और अबाधित होती है. पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है, जहाँ गठबंधन विचारधारा के बजाय 'आपूर्ति की अनिवार्यता' पर आधारित होंगे.



Source: Statistical Review of World Energy 2025. The Energy Institute

2024 में तेल का व्यापार (मिलियन बैरल में)

	कच्चे तेल व आयात उत्पाद	निर्यात कच्चा तेल	उत्पाद	कुल निर्यात
सऊदी अरब	0·4	6·4	1·2	7·2
रूस	0·0	4·9	2·2	7·0
यूएई	0·8	3·7	2·0	4·9
कनाड़ा	1·0	4·4	0·7	4·2
इराक	0·1	3·6	0·5	4·0
यूएस	8·4	4·0	5·9	1·4
भारत	6·0	0·0	1·9	– 4·1
चीन	13·4	0·0	1·2	– 12·2
विश्व	**69·4**	**43·2**	**26·2**	**0·0**

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न—भारत की तेल आयात निर्भरता और होर्मुज जलडमरूमध्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

I. भारत के कुल कच्चे तेल आयात में से लगभग 2·5-2·7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल युद्ध पूर्व होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता था.

II. भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है.

III. भारत अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 85-88% हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?

(A) केवल I
(B) केवल I और III
(C) केवल III
(D) I, II और III

उत्तर—(D)

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न—"1927 का महाड सत्याग्रह केवल पानी के लिए एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारतीय संवैधानिकवाद और 'समानता' के लिए एक बुनियादी क्षण था." इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और स्वतंत्रता के बाद के कानूनी ढाँचे तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर इसके प्रभाव पर विचार कीजिए.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

चर्चा में क्यों ?

महाड सत्याग्रह (जिसे चवदार तालाब सत्याग्रह भी कहा जाता है) वर्तमान में अपनी 99वीं वर्षगाँठ और शताब्दी वर्ष में प्रवेश के कारण चर्चा में है. गौरतलब है कि 20 मार्च, 2026 को इस ऐतिहासिक आन्दोलन के 99 वर्ष पूरे हुए है.

उत्तर–20 मार्च, 1927 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने एक बड़ा आन्दोलन किया. उन्होंने महाराष्ट्र के महाड में हजारों लोगों के साथ 'चवदार तालाब' से प्रतीकात्मक विरोध के रूप में पानी पिया. पानी पीना हर इंसान की जरूरत है, लेकिन उस समय 'अछूत' समझे जाने वाले लोगों को इस तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता था. कानून होने के बावजूद, समाज के ऊँचे तबके के लोग उन्हें रोकते थे. यह आन्दोलन सिर्फ तालाब से पानी के लिए नहीं, बल्कि मानवीय सम्मान और समानता के लिए लड़ाई थी, आन्दोलन से पूर्व दलितों को पानी देना एक 'दान' या 'दया' माना जाता था. अम्बेडकर जी ने इसे एक 'अधिकार' बना दिया. उल्लेखनीय है कि गाँधी जी के नेतृत्व में 1930 का नमक सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ था. लेकिन महाड सत्याग्रह भारतीय समाज की अंदरूनी बुराई (छुआछूत) के खिलाफ था. यह भारत में अपने हक के लिए लड़ा गया अपनी तरह का पहला बड़ा सामाजिक आन्दोलन था.

पानी से परे : प्रतीकात्मक और आमूलचूल उद्देश्य

- महाड सत्याग्रह अद्वितीय था, क्योंकि इसका लक्ष्य कोई विदेशी उत्पीड़क नहीं, बल्कि एक सामाजिक भेदभाव के प्रति संघर्ष था.
- **गरिमा का अधिकार–**पानी पीना एक प्रतीकात्मक कार्य था जिसका उद्देश्य यह साबित करना था कि 'दबे-कुचले वर्ग' सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँचने के लिए "पर्याप्त रूप से हकदार" हैं.
- **धार्मिक कुरूतियों का विरोध–**दिसम्बर 1927 में इस आन्दोलन के दूसरे चरण के दौरान, अम्बेडकर जी ने सार्वजनिक रूप से धार्मिक कुरूतियों व उनसे सम्बन्धित ग्रन्धों का विरोध यह कहते हुए किया कि भारत का भविष्य किसी 'धार्मिक संहिता' के बजाय एक 'नागरिक संहिता' द्वारा शासित होना चाहिए.

संवैधानिकवाद और विधि का शासन

- **कानूनी लड़ाई–**जब उच्च-जाति के हिंदुओं ने सत्याग्रहियों के खिलाफ मौजूदा अदालत से निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली, तो अम्बेडकर ने आन्दोलन को स्थगित कर दिया और एक कानूनी लड़ाई लड़ी जो 10 वर्ष तक चली.
- आगे 1937 में, नरहरि दामोदर वैद्य *बनाम* भीमराव रामजी अम्बेडकर मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले ने इस बात की पुष्टि की कि सार्वजनिक तालाब सभी नागरिकों के लिए खुले हैं. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक जगहों से जुड़े स्थानीय रीति-रिवाज, बुनियादी मानवाधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते.
- **महाड *बनाम* दांडी–**नमक सत्याग्रह (दांडी) का मुख्य उदेश्य जहाँ बाहरी ताकतों से अधिकार हासिल करना था, वहीं महाड का मकसद समाज के भीतर ही समता (बराबरी) कायम करना था.
- दांडी में माँग थी कि अंग्रेज नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर समाप्त करें, वही महाड में माँग थी कि अभिजात वर्ग, दलितों का सम्मान व उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित न करें.
- नमक कर को कानून बनाकर खत्म किया जा सकता था, लेकिन छुआछूत को मिटाने के लिए 'सोच बदलने' और सामाजिक ताने-बाने में आमूल-चूल बदलाव की जरूरत थी. महाड ने 'बराबरी का सन्देश' दिया, जिसने समाज के हाशिए पर पड़े तबकों के लिए सामाजिक व राजनीतिक आजादी को सार्थक बनाया.

भारतीय संविधान पर प्रभाव

- महाड आन्दोलन से आए परिवर्तन की 'छाप' स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग III में साफ तौर पर दिखाई देती है.
- **अनुच्छेद 15(2)–**यह खास तौर पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों में जाने और कुओं, तालाबों और नहाने के घाटों के इस्तेमाल के मामले में किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है. यह चावदार तालाब पर हुए संघर्ष व माँग को स्पष्ट करता सीधा कानूनी रूप है.
- **अनुच्छेद 17–**छुआछूत का खात्मा उसी मशाल की अन्तिम परिणति है, जिसे महाड में जलाया गया था.
- **एक मूल्य के रूप में गरिमा–**संविधान की प्रस्तावना में 'बंधुत्व' और 'व्यक्ति की गरिमा' पर जो जोर दिया गया है, उसकी जड़ें अम्बेडकर जी की इस समझ में हैं कि सामाजिक बराबरी के बिना, राजनीतिक लोकतंत्र भारतीय जमीन पर महज एक 'ऊपरी दिखावा' बनकर रह जाता है.

सारांशतः 2027 में महाड़ सत्याग्रह की शताब्दी वर्षगाँठ इस गणतंत्र के लिए एक प्रकार के 'संवैधानिक दीक्षा-संस्कार' के रूप में काम करेगी. यह हमें याद दिलाता है कि भारत का संघर्ष केवल अंग्रेजों के खिलाफ एक आन्दोलन नहीं था, बल्कि मूल रूप से मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना के लिए एक आन्दोलन था. अतः वर्तमान में भी महाड़ आन्दोलन के उदेश्यों को जमीनी हकीकत देने के लिए, केवल प्रतीकात्मक समारोहों से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करना होगा कि 'समानता का अधिकार' प्रत्येक भारतीय नागरिक के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाए; हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि केवल जन्म के संयोग के कारण, पानी की मौजूदगी में कोई भी व्यक्ति फिर कभी प्यासा न रहे.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–निम्नलिखित कथनों में से कौनसा सही सुमेलित नहीं है ?

I. महाड सत्याग्रह – 1927
II. नमक सत्याग्रह (दांडी) – 1922
III. नरहरि दामोदर वैद्य *बनाम* भीमराव रामजी अम्बेडकर मामला – 1937

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल III
(D) केवल I और III

उत्तर–(D)

राजव्यवस्था

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न–"क्या भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में 'अनिवार्य मतदान' को लागू करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है ? अनिवार्य मतदान की चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए मतदाता भागीदारी बढ़ाने के अन्य वैकल्पिक उपायों पर चर्चा कीजिए."

चर्चा में क्यों ?

चुनाव आयोग ने अप्रैल-मई 2026 में होने वाले 5 विधान सभा चुनावों का मतदान कार्यक्रम घोषित कर दिया है. चुनाव से सम्बन्धित एक मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनावों में अनिवार्य मतदान के सम्बन्ध में चर्चा के कारण यह विषय सुर्खियों में रहा है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

उत्तर–भारतीय लोकतंत्र की नींव 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' पर टिकी है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत् मान्यता प्राप्त है. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य मतदान पर उठाए गए प्रश्न और 2026 के विधान सभा चुनावों की घोषणा ने इस बहस को पुनः जीवित कर दिया है. जहाँ एक ओर अनिवार्य मतदान को लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक बताया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रशासनिक व्यवहार्यता के चश्मे से भी देखा जाना अनिवार्य है.

अनिवार्य मतदान : संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य

- भारत में मतदान का अधिकार वर्तमान में एक 'वैधानिक अधिकार' (Statutory Right) है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत् पंजीकृत मतदाताओं को वोट देने का अधिकार है, लेकिन यह कोई कानूनी बाध्यता नहीं है.
- **अनुच्छेद 19(1)(a)**–अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 'मौन रहने का अधिकार' भी शामिल है. अनिवार्य मतदान को इस मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि मतदान न करना भी एक प्रकार का राजनीतिक विरोध या अरुचि की अभिव्यक्ति हो सकता है.
- **विधि आयोग की दृष्टि**–255वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने स्पष्ट किया था कि मतदान को अनिवार्य बनाना न तो वांछनीय है और न ही व्यावहारिक.

अनिवार्य मतदान की चुनौतियाँ (भारतीय सन्दर्भ में)

- **प्रशासनिक और वित्तीय बोझ**–भारत जैसे 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले देश में गैर-मतदाताओं की पहचान करना, उन्हें नोटिस भेजना और दंडित करना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी.
- **दंडात्मक प्रकृति**–ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील जैसे देशों में जुर्माना लगाने का प्रावधान है, लेकिन भारत की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है. उन पर आर्थिक दंड लगाना या सरकारी सेवाओं से वंचित करना सामाजिक न्याय के विरुद्ध होगा.
- **नोटा (NOTA) की उपस्थिति**–सर्वोच्च न्यायालय ने नोटा का विकल्प इसलिए दिया था ताकि मतदाता अपनी असहमति दर्ज कर सकें. यदि हम किसी को मतदान केन्द्र तक आने के लिए 'मजबूर' करते हैं, तो यह लोकतांत्रिक चयन की स्वैच्छिक भावना को समाप्त कर देता है.
- **प्रवासी श्रमिकों की समस्या**–करोड़ों श्रमिक अपने गृह राज्य से दूर काम करते हैं. बिना 'रिमोट वोटिंग' (Remote Voting) के उनके लिए मतदान अनिवार्य करना उनके रोजगार और आर्थिक स्थिति पर प्रहार होगा.

भागीदारी बढ़ाने के अन्य वैकल्पिक उपाय

- अनिवार्य मतदान के स्थान पर 'प्रोत्साहन' और 'सुविधा' पर आधारित मॉडल अधिक प्रभावी हो सकता है.
- **तकनीकी हस्तक्षेप**–चुनाव आयोग को 'रिमोट वोटिंग मशीन' (RVM) और सुरक्षित डिजिटल माध्यमों पर काम करना चाहिए ताकि प्रवासी भारतीय और आंतरिक प्रवासी कहीं से भी वोट दे सकें.
- **जागरूकता अभियान**–'स्वीप' (SVEEP) जैसे कार्यक्रमों को सोशल मीडिया और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों (Influencers) के माध्यम से और अधिक सघन बनाने की आवश्यकता है.
- **रसद और परिवहन**–मतदान के दिन वैधानिक अवकाश का कड़ाई से पालन हो. साथ ही, दूर-दराज के क्षेत्रों और श्रमिकों के लिए विशेष परिवहन (बस/ट्रेन) की व्यवस्था भागीदारी बढ़ा सकती है.
- **पंजीकरण का सरलीकरण**–मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल और बाधा रहित बनाया जाना चाहिए.

सारांशतः लोकतंत्र की सफलता 'जबरदस्ती' में नहीं, बल्कि 'जन-भागीदारी' में निहित है. अनिवार्य मतदान भले ही कागजों पर भागीदारी के आँकड़े बढ़ा दे, लेकिन यह नागरिकों के 'चुनने के अधिकार' की मूल भावना को आहत कर सकता है. जैसा कि दिनेश गोस्वामी समिति ने भी सुझाव दिया था, भारत को दंडात्मक उपायों के बजाय मतदाता शिक्षा, चुनावी सुधारों और तकनीकी सुगमता पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए. एक जागरूक और स्वेच्छा से मतदान करने वाला नागरिक ही वास्तविक रूप से सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करता है.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–भारत में मतदान के अधिकार के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

I. भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्रदान करता है.

II. भारत में मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है.

III. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्रदान करता है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?

(A) केवल 2 और 3
(B) 1, 2 केवल 3
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 1 और 2

उत्तर–(C)

संवैधानिक एवं सामाजिक मुद्दा

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न–"हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा 'हंसानंदिनी नंदूरी *बनाम* भारत संघ' मामले में दिया गया निर्णय केवल श्रम कानून का सुधार नहीं है, बल्कि यह 'मातृत्व' की पारंपरिक जैविक परिभाषा से परे एक संवैधानिक विस्तार है." चर्चा कीजिए. क्या आपको लगता है कि यह निर्णय भारत में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया और लैंगिक न्याय को सुदृढ़ करने में सहायक होगा ?

चर्चा में क्यों ?

उच्चतम न्यायालय ने 17 मार्च, 2026 को फैसला सुनाया कि कानून के तहत् मातृत्व अवकाश, गोद लेने के समय बच्चे की उम्र पर निर्भर नहीं हो सकता. न्यायालय ने अपने निर्णय में 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश से वंचित करने वाले नियम को रद्द कर दिया.

उत्तर–हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने 'हम्सानंदिनी नंदूरी *बनाम* भारत संघ' मामले में 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' की धारा 60(4) के उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली माताओं को

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

ही प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) का पात्र मानता था. न्यायालय का यह निर्णय न केवल समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) को सुदृढ़ करता है, बल्कि मातृत्व को केवल 'जैविक प्रक्रिया' के बजाय 'देखभाल और भावनात्मक जुड़ाव' के रूप में पुनः परिभाषित करता है.

निर्णय का संवैधानिक और कानूनी आधार

- न्यायालय ने इस मामले में 'उचित वर्गीकरण' (Reasonable Classification) के सिद्धांत का प्रयोग किया.
- **अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार)**—न्यायालय के अनुसार, 3 महीने की आयु सीमा एक कृत्रिम और मनमाना वर्गीकरण था. जैविक माता और दत्तक माता के बीच अवकाश के मामले में भेदभाव करना 'बोधगम्य अन्तर' (Intelligible Differentia) की कसौटी पर खरा नहीं उतरता.
- **अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार)**—न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मातृत्व का अधिकार और बच्चे की देखभाल का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा है. प्रजनन स्वायत्तता में केवल जन्म देना ही नहीं, बल्कि गोद लेना भी शामिल है.

मातृत्व की अवधारणा का विस्तार

न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव किया है—

- **जैविक *बनाम* सामाजिक मातृत्व**—अब तक कानून केवल प्रसव के बाद शरीर को मिलने वाले आराम पर केन्द्रित था. न्यायालय ने कहा कि मातृत्व केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक 'मनोवैज्ञानिक अवस्था' है.
- **भावनात्मक बंधन (Bonding)**—दत्तक बच्चों को, विशेषकर जो संस्थागत देखभाल (Orphanages) से आते हैं, नए वातावरण में ढलने और माता-पिता के साथ जुड़ाव बनाने के लिए अधिक समय और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है. उम्र की सीमा इस प्रक्रिया में बाधक थी.

दत्तक ग्रहण और लैंगिक न्याय पर प्रभाव

- **प्रक्रियात्मक बाधाओं का समाधान**—दत्तक ग्रहण नियमों (CARA) के अनुसार, एक बच्चे को 'कानूनी रूप से मुक्त' घोषित करने में अक्सर समय लगता है, जिससे बच्चा 3 महीने से बड़ा हो जाता है. पुराने नियम के कारण अधिकांश माताएँ अवकाश से वंचित रह जाती थीं. यह निर्णय गोद लेने की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक और आकर्षक बनाएगा.
- **लैंगिक समानता**—कार्यस्थल पर दत्तक माताओं को 'दोयम दर्जे' का मानने की प्रवृत्ति समाप्त होगी. यह महिलाओं के कॅरियर की निरन्तरता और उनकी व्यक्तिगत पसन्द (गोद लेने का निर्णय) के बीच सन्तुलन स्थापित करेगा.
- **संस्थागत विकल्प *बनाम* व्यक्तिगत देखभाल**—सरकार के इस तर्क को कि 'क्रेच (Creche)' प्रसूति अवकाश का विकल्प हो सकते हैं, न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया. यह स्पष्ट किया गया कि संस्थान कभी भी माँ के व्यक्तिगत स्पर्श और देखभाल का स्थान नहीं ले सकते.

चुनौतियाँ एवं आगे की राह

यद्यपि यह निर्णय ऐतिहासिक है, लेकिन अभी भी कुछ सुधारों की आवश्यकता है—

- **पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)**—देखभाल की जिम्मेदारी केवल महिला पर न रहे, इसके लिए लिंग-तटस्थ (Gender-neutral) नीतियों की आवश्यकता है.
- **निजी क्षेत्र में कार्यान्वयन**—असंगठित और निजी क्षेत्रों में इन नियमों को सख्ती से लागू करना एक बड़ी चुनौती है.
- **जागरूकता की कमी**—समाज में अभी भी गोद लिए गए बच्चों और उनके कानूनी अधिकारों को लेकर रूढ़िवादिता मौजूद है.

सारांशतः उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय 'देखभाल-आधारित मातृत्व' (Care-based Motherhood) की ओर एक प्रगतिशील कदम है. 3 महीने की आयु सीमा को समाप्त करके न्यायालय ने न केवल कानून की विसंगति को दूर किया है, बल्कि यह भी स्थापित किया है कि परिवार का गठन जैविक सम्बन्धों से कहीं अधिक भावनात्मक प्रतिबद्धता पर आधारित होता है. यह निर्णय समावेशी विकास, बाल कल्याण और कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न—'हम्सानंदिनी नंदूरी *बनाम* भारत संघ' मामले में उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. न्यायालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की उस धारा को रद्द कर दिया है, जो केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली माताओं को प्रसूति अवकाश की अनुमति देती थी.
2. न्यायालय के अनुसार, गोद लेने वाली माताओं के लिए आयु सीमा का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है.
3. इस निर्णय में स्पष्ट किया गया कि 'मातृत्व' का अर्थ केवल जैविक प्रसव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बच्चे की भावनात्मक देखभाल और पालन-पोषण भी शामिल है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

उत्तर—(D)

विश्व इतिहास

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न—"औपनिवेशिक सीमाएँ और प्रशासनिक संरचनाएँ अक्सर आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय सीमाओं से आगे तक फैली हुई थीं." इस सन्दर्भ में परीक्षण कीजिए कि ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य ने मध्य-पूर्व पर राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव कैसे डाला ?

चर्चा में क्यों ?

वर्तमान में खाड़ी देशों में युद्ध और वर्षों से इन देशों के बीच सीमा विवाद के कारण इसके ऐतिहासिक कारणों की चर्चा सुर्खियों में बनी रहती है.

उत्तर—आधुनिक मानचित्रों में ब्रिटिश राज को केवल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक सीमित दिखाया जाता है, किन्तु वास्तव में इसका प्रभाव क्षेत्र यमन से लेकर ओमान और कुवैत तक फैला था.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

जैसा कि सैम डेलरिम्पल ने अपनी पुस्तक 'द शैटर्ड लैंड्स' (2025) में रेखांकित किया है, 1928 तक एशिया का एक विशाल हिस्सा एक ही साम्राज्यवादी ध्वज (ब्रिटिश राज) के अन्तर्गत एकजुट था.

प्रशासनिक और कानूनी एकीकरण

- ब्रिटिश भारत ने खाड़ी देशों को प्रत्यक्ष उपनिवेश बनाने के बजाय 'संरक्षण की प्रणाली' (System of Protection) के माध्यम से नियंत्रित किया. इंटरप्रिटेशन एक्ट, 1889 के तहत् ये क्षेत्र कानूनी रूप से भारत का हिस्सा माने जाते थे.
- **नियंत्रण**—इन क्षेत्रों का प्रशासन 'इंडियन पॉलिटिकल सर्विस' द्वारा चलाया जाता था और इनकी सुरक्षा 'इंडियन आर्मी' के हाथों में थी.
- **रियासतों का दर्जा**—आधिकारिक सूची में भारतीय रियासतों का नाम 'अबू धाबी' से शुरू होता था. लॉर्ड कर्जन ने तर्क दिया था कि ओमान भी साम्राज्य की उतनी ही महत्वपूर्ण 'नेटिव स्टेट' है जितनी कि केलत.

रणनीतिक और आर्थिक कारण

- **समुद्री सुरक्षा**—ब्रिटेन का प्राथमिक हित फारस, इराक और भारत के बीच समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करना था. 1797-1819 के बीच 'पाइरेट कोस्ट' (वर्तमान UAE) के समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए ब्रिटिश भारत ने कड़े हस्तक्षेप किए.
- **स्वेज नहर का प्रभाव**—1869 में स्वेज नहर खुलने से भारत और ब्रिटेन के बीच की दूरी कम हो गई, जिससे इस क्षेत्र का भू-राजनीतिक महत्व और अधिक बढ़ गया.

संचालन का केन्द्र

- खाड़ी क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखने के लिए लंदन, भारत और स्थानीय अरब शासकों के बीच समन्वय था. 1858 तक इन क्षेत्रों का संचालन बॉम्बे प्रेसीडेंसी के अधीन था और उसके बाद सीधे भारत सरकार (Viceroy) के नियंत्रण में आ गया. बुशहर (फारस) में 1763 में स्थापित 'रेजीडेंसी' इस नियंत्रण का मुख्य केन्द्र थी.

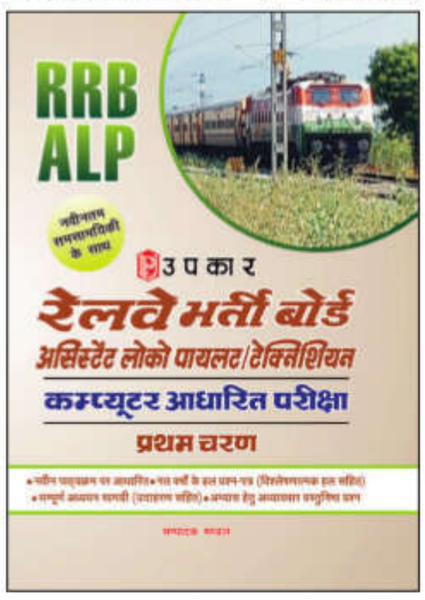
सारांशतः मार्च 1947 तक फारस की खाड़ी का प्रशासन 'इंडियन पॉलिटिकल सर्विस' द्वारा ही प्रबंधित किया जाता था. हालाँकि, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत् अदन (यमन) को भारत से अलग कर 'क्राउन कॉलोनी' बना दिया गया. स्वतंत्रता के समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि स्वतंत्र भारत को खाड़ी देशों पर शासन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अंततः, 1971 तक ब्रिटिश प्रभाव के हटने के साथ ही यह 'विस्तारित राज' आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ.

सि. से. प्रा. परीक्षा

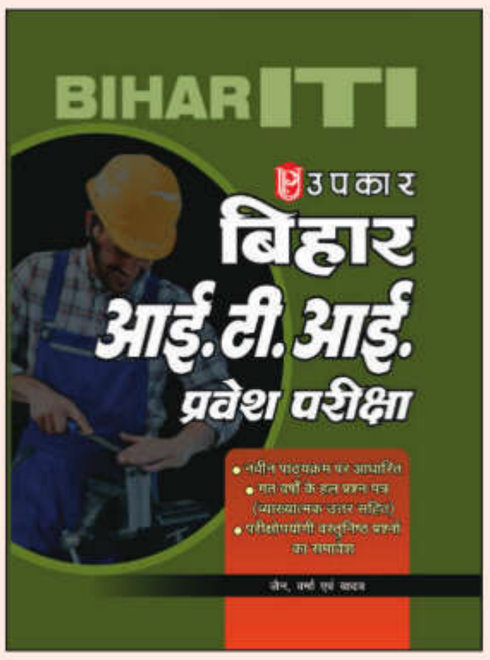
प्रश्न—19वीं सदी के अन्त में किस ब्रिटिश अधिनियम के तहत् खाड़ी देशों (Gulf States) के संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी रूप से 'ब्रिटिश भारत' का हिस्सा माना गया था ?

(A) रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
(B) भारत सरकार अधिनियम, 1858
(C) इंटरप्रिटेशन एक्ट, 1889
(D) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909

उत्तर—(C)

RRB/ALP
उपकार
रेलवे भर्ती बोर्ड
असिस्टेंट लोको पायलट/टेक्निशियन
Code : 2554 ₹ 480.00


सम्पादक मण्डल
प्रथम चरण
कम्प्यूटर आधारित परीक्षा
नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित
गत वर्षों के हल प्रश्न-पत्र (विश्लेषणात्मक हल सहित)
सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री (उदाहरण सहित)
अभ्यास हेतु अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न
English Edition
Code 1968 ₹ 390.00
उपकार प्रकाशन, आगरा
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

उपकार बिहार
आई.टी.आई.
प्रवेश परीक्षा
(पूर्णतः पाठ्यक्रमानुसार)


प्रमुख आकर्षण
• नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित
• गत वर्षों के हल प्रश्न-पत्र (व्याख्यात्मक उत्तर सहित)
• परीक्षोपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश
Code 725 ₹ 485.00
लेखकगण
जैन, वर्मा एवं यादव
सॉल्वड् पेपर्स Code 1443 ₹ 170.00
उपकार प्रकाशन, आगरा
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



स्मरणीय तथ्य

राष्ट्रीय

1. हाल ही में 18वीं लोक सभा के गठन के लगभग 2 वर्ष बाद, लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विशेषाधिकार समिति के लिए 15 सदस्यों को मनोनीत किया है. इसकी अध्यक्षता किसे प्रदान की गई है ? ***–रवि शंकर प्रसाद (भाजपा के वरिष्ठ नेता)***

☞ विशेषाधिकार समिति एक स्थायी समिति है, जो सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जाँच करती है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है. इसकी लोक सभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्य सभा समिति में 10 सदस्य होते हैं. उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 105 और 122 संसद के विशेषाधिकारों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं. अनुच्छेद 105 के अनुसार, संसद में बोलने की स्वतंत्रता होगी. संसद या उसकी किसी समिति में किसी भी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी भी मत के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी.
अनुच्छेद 122 के अनुसार, संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रक्रिया में कथित अनियमितता के आधार पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा.

2. 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धित घोषणा किस भारतीय राज्य द्वारा की गई है ? ***–कर्नाटक***

☞ वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया और स्पेन अपने देशों में ऐसे प्रतिबन्ध लगा चुके हैं. ब्रिटेन, डेनमार्क और ग्रीस भी इस संवेदनशील मुद्दे का अध्ययन कर रहे हैं और इसी तरह के विचार भारत में भी आकार ले रहे हैं, जो विश्व के सबसे बड़े सोशल मीडिया बाजारों में से एक है. उल्लेखनीय है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है, जहाँ 75 करोड़ स्मार्टफोन डिवाइस और 1 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं. भारत के केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2019-20 में किए गए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक की एक-चौथाई से भी कम आबादी 15 वर्ष से कम आयु की है. नीति आयोग द्वारा 2025 के लिए जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की जनसंख्या लगभग 67·6 करोड़ है.

3. फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है ***– 7·5%***

☞ फिच रेटिंग्स ने अपना 'वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण-मार्च 2026' जारी किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 7·5% रहने का अनुमान लगाया गया है. वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी पूर्वानुमान को दिसम्बर 2025 में अनुमानित 7·4% से थोड़ा बढ़ाकर 7·5% कर दिया गया है, जिसका मुख्य कारण मजबूत घरेलू माँग और स्थिर आर्थिक संकेतक हैं.

4. हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 'ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025' से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है ?
– प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार आर. वैरामुथु को

☞ प्रतिष्ठित तमिल गीतकार और लेखक आर. वैरामुथु को 60वें (वर्ष 2025 के लिए) ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है. वैरामुथु यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल लेखक (इससे पूर्व यह पुरस्कार तमिल लेखक अकिलन (1975) और जयकांतन (2002) को प्रदान किया जा चुका है) हैं. वैरामुथु को इससे पूर्व उपन्यास 'कल्लिकट्टू इतिहासम' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार (2003) भी मिल चुका है. वर्ष 2003 में पद्म श्री और वर्ष 2014 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया था. ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना भारतीय ज्ञानपीठ परिषद् द्वारा 1961 ई. में संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं (2013 में अंग्रेजी भाषा के लिए भी) के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए की गई थी. गौरतलब है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में जी. शंकर कुरुप (मलयालम) को प्रदान किया गया था. वर्ष 1976 में आशापूर्णा देवी (बंगाली) इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला थीं. अंग्रेजी भाषा के लिए पहले विजेता अमिताव घोष (वर्ष 2018 में) थे.

5. आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्ययुगीन शिलालेख की खोज की गई है, यह किस राजवंश से सम्बन्धित मानी जा रही है ? ***– गजपति राजवंश***

☞ 15वीं शताब्दी का यह शिलालेख पुरुषोत्तम देव के अधिकारी कुमारगुरु महापात्रा का उल्लेख करता है. उल्लेखनीय है कि गजपति साम्राज्य की स्थापना कपिलेंद्र देव ने की थी. अपने उत्कर्ष के दौरान यह साम्राज्य वर्तमान पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से लेकर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी कटक (आधुनिक कटक) थी.

6. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, गोद लेने वाली सभी महिला कर्मचारी, बच्चे की आयु की किसी भी शर्त के बिना, कितने सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की समान रूप से हकदार हैं ? ***– 12 सप्ताह***

☞ भारत में कामकाजी महिलाओं के हितों की रक्षा हेतु मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 मुख्य वैधानिक ढाँचा है. वर्ष 2017 के संशोधन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रगति की गई, जिसमें पहली बार गोद लेने वाली (Adopting) और कमीशनिंग (Commissioning) माताओं को 12 सप्ताह के सवैतनिक अवकाश का अधिकार दिया गया. हालाँकि, इसमें एक 'प्रतिबंधात्मक शर्त' थी कि यह लाभ तभी मिलेगा जब गोद लिया गया बच्चा 3 महीने से कम उम्र का हो. इसी प्रावधान को बाद में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 60(4) में भी शामिल किया गया था. हालिया ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस आयु सीमा को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. न्यायालय का तर्क है कि उम्र के आधार पर ऐसा वर्गीकरण भेदभावपूर्ण है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) व अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन) का उल्लंघन करता है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि 'गोद लेना' माता-पिता बनने का एक पूर्णतः वैध मार्ग है और इसे जैविक जन्म से अलग या कमतर नहीं माना जा सकता. यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी माँ का स्नेह और देखभाल प्राप्त हो, चाहे उसका आगमन किसी भी माध्यम से हुआ हो.

7. भारत विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक नारियल उत्पादन में इसका कितना योगदान है ? ***– लगभग 30·37%***

☞ नारियल, एरेकेसी कुल से सम्बन्धित एकबीजपत्री ताड़ का पौधा है, जो एक बारहमासी बागान फसल है. इसकी उत्पत्ति आमतौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया से मानी जाती है. नारियल के विकास के लिए गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु आवश्यक है. यह 25°C से 30°C के बीच तापमान वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह उगता है और इसे पर्याप्त और समान रूप से वितरित वर्षा की आवश्यकता होती है. भारत में यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा और पश्चिम बंगाल में उगता है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

8. हाल ही में सुर्खियों में रही गाइनांड्रोमॉर्फी जैविक स्थिति किससे सम्बन्धित है ? – ***मीठे पानी के केकड़े की एक प्रजाति वेला कार्ली से***

☞ साइलेंट वैली नेशनल पार्क में वेला कार्ली (Vela Carli) केकड़े में गाइनांड्रोमॉर्फी (Gynandromorphy) का दुर्लभ मामला मिला है. यह एक ऐसी जैविक स्थिति है जिसमें एक ही जीव के शरीर में नर और मादा दोनों के ऊतक और लक्षण मौजूद होते हैं. यह मुख्य रूप से प्रारम्भिक विकास के दौरान कोशिका विभाजन (Mitosis/Meiosis) में त्रुटियों या गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण होता है. यह उभयलिंगिता (Hermaphroditism) से भिन्न है, जहाँ जीव में दोनों लिंगों के कार्यात्मक अंग होते हैं.

9. हाल ही में किस राज्य विधान सभा द्वारा अशांत क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी विधेयक पारित किया गया है ? – ***राजस्थान विधान सभा द्वारा***

☞ गुजरात के बाद राजस्थान भारत का दूसरा राज्य बन गया है जिसने इस तरह का विधेयक लागू किया है. राजस्थान विधान सभा द्वारा प्रस्तावित कानून के तहत् धारा 3(1,2) में कहा गया है कि राज्य सरकार राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर सकती है यदि वह मानती है कि साम्प्रदायिक हिंसा, दंगे या सार्वजनिक अव्यवस्था मौजूद है या होने की सम्भावना है.

10. किस भारतीय पैरा-एथलीट ने नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री की मेन्स जंप टी63 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है ? – ***शैलेश कुमार ने***

☞ बिहार के जमुई के पैरा-एथलीट शैलेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स (2026) में पुरुषों की टी63 हाई जंप (ऊँची कूद) स्पर्धा में 1·84 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है.

अन्तर्राष्ट्रीय

1. 4 मार्च, 2026 को विश्व मोटापा दिवस के अवसर पर जारी 'विश्व मोटापा एटलस 2026' का विषय रखा गया है ? – ***मोटापे से निपटने के लिए 8 अरब कारण***

☞ 'विश्व मोटापा महासंघ' ने इसका दूसरा संस्करण जारी किया है. विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार, मोटापे से ग्रस्त और अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या के मामले में भारत अब चीन के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है. एटलस 2025 से 2040 की अवधि के लिए बचपन के मोटापे के प्रसार के अनुमानों की एक शृंखला भी प्रस्तुत करता है. अनुमान बताते हैं कि इस अवधि में, भारत में 20 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त होंगे और 56 मिलियन बच्चे या तो अधिक वजन वाले होंगे या मोटापे से ग्रस्त होंगे. भारत में, 2025 में 5-9 आयु वर्ग के कुल 14·9 मिलियन बच्चे और 10-19 आयु वर्ग के 26 मिलियन से अधिक बच्चे अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं.

2. हाल ही में किस देश ने पार्किंसंस रोग के लिए विश्व की पहली आईपीएस सेल-आधारित थेरेपी 'एमचेप्री' को मंजूरी प्रदान की है ? – ***जापान***

☞ जापान ने सुमितोमो फार्मा द्वारा विकसित 'एमचेप्री' (Amchepry) नामक विश की पहली आईपीएस (iPS) सेल-आधारित थेरेपी को पार्किंसंस रोग के लिए मंजूरी दी है. यह तकनीक प्रयोगशाला में विकसित डोपामाइन-उत्पादक कोशिकाओं को मस्तिष्क में प्रत्यारोपित कर रोग का इलाज करती है. यह उपलब्धि क्योटो विश्वविद्यालय के नैदानिक परीक्षणों पर आधारित है.

3. हाल ही में सुर्खियों में रहा खर्ग द्वीप (Kharg Island) किस खाड़ी में स्थित है ? – ***फारस की खाड़ी में***

☞ अमेरिका द्वारा ईरान की आर्थिक जीवन रेखा माने जाने वाले खर्ग द्वीप (Kharg Island) पर हमले के कारण यह चर्चा का विषय रहा है. यह द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित है. यह ईरान के तट पर होर्मुज जलडमरूमध्य के उत्तर-पश्चिम में स्थित है. गौरतलब है कि ईरान के लगभग 90% तेल का निर्यात इसी द्वीप से किया जाता है.

4. हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर 14वीं सदी के एक जहाज के मलबे से युआन वंश काल के नीले-सफेद चीनी-मिट्टी के बर्तनों का बड़ा भण्डार मिला है ? – ***सिंगापुर के***

☞ युआन वंश काल के नीले-सफेद चीनी-मिट्टी के बर्तनों का बड़ा भण्डार, मंगोल साम्राज्य के दौर में समुद्री व्यापार के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है. माना जा रहा है कि यह जहाज चीन से तेमासेक की ओर जा रहा था, जो आधुनिक सिंगापुर के स्थान पर स्थित एक ऐतिहासिक व्यापारिक केन्द्र था.

5. हाल ही में भारत ने 29 देशों के साथ मिलकर किस देश में शांति-स्थापना सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की माँग की है ? – ***लेबनान में***

☞ भारत ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शान्ति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है, जो ईरान युद्ध के बाद इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच बढ़ते टकराव के बीच तैनात हैं. उल्लेखनीय है कि लेबनान भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित क्षेत्र की एक संकीर्ण पट्टी है. यह उत्तर और पूर्व में सीरिया, दक्षिण में इजरायल और पश्चिम में भूमध्य सागर से अपनी सीमाएँ साझा करता है.

6. हाल ही में किस देश ने मेनिन्जाइटिस-मस्तिष्क ज्वर के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है ? – ***ब्रिटेन ने***

☞ ब्रिटेन के केंट में घातक मेनिन्जाइटिस-मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप के बाद तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई है. उल्लेखनीय है कि मेनिंगोकोकल रोग कई प्रकार के जीवाणुओं के कारण होता है. इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, तेज साँस लेना, सुस्ती, कँपकँपी, उल्टी और हाथों-पैरों का ठण्डा पड़ना शामिल हैं.

7. हाल ही में किस देश ने भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लम्बे बेली पुल का उद्घाटन किया है ? – ***श्रीलंका***

☞ भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लम्बे बेली पुल का श्रीलंका के चिलाव-थोडुवावा मार्ग पर उद्घाटन किया गया. हाल ही में आए दित्वाह चक्रवात से यह क्षतिग्रस्त हो गया था.

8. भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) की प्रोफेसर ने 'नेवाडो ओजोस डेल सलाडो' (Nevado Ojos del Salado) शिखर पर पहुँचकर की. र्तिमान स्थापित किया है. यह शिखर कहाँ स्थित है ? – ***एंडीज पर्वत श्रेणी में चिली-अर्जेंटीना सीमा पर***

☞ भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) की कम्प्यूटर साइंस और ऑटोमेशन विभाग की प्रोफेसर अर्पिता पात्रा ने 6 मार्च, 2026 को विश्व के सबसे ऊँचे सक्रिय ज्वालामुखी, नेवाडो ओजोस डेल सलाडो (Nevado Ojos del Salado) पर तिरंगा फहराया है. यह 6,879 मीटर ऊँचा पर्वत दक्षिण अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है.

9. संयुक्त राष्ट्र ने 'सहमति निष्कर्ष' (Agreed Conclusions) नामक एक नया वैश्विक फ्रेमवर्क अपनाया है. इसका उद्देश्य न्याय प्राप्ति में सुधार लाना है – ***विश्व भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए***

☞ 'सहमति निष्कर्ष' को 'महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW)' के 70वें सत्र के दौरान व्यापक सहमति से अपनाया गया. यह सत्र न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में आयोजित किया गया है.

10. भारत ने मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से अपने किस पड़ोसी देश को 5,000 मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति की है ? – ***बांग्लादेश को***

☞ भारत ने मार्च 2026 में, बांग्लादेश को अपनी मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से 5,000 मीट्रिक टन हाई-स्पीड डीजल की पहली खेप आपूर्ति की है. यह आपूर्ति असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से की गई है. ●●●

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



विश्व परिदृश्य

✍ डॉ. अरुणोदय बाजपेयी

विश्व व्यापार की चुनौतियाँ तथा भारत की आर्थिक कूटनीति

वर्तमान में वैश्वीकरण की प्रक्रिया भले ही शिथिल हो गई हो, लेकिन देशों की विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति का महत्व बढ़ गया है. वैश्वीकरण के आरम्भ से ही व्यापार तथा निवेश देशों के आर्थिक विकास का एक प्रमुख आधार बना हुआ है. चीन के तीव्र आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार तथा निवेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है तथा प्रत्येक देश अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए प्रभावी व कारगर आर्थिक कूटनीति को अपनाने का प्रयास कर रहा है. इस सम्बन्ध में वैश्विक व्यापार व्यवस्था में 4 चुनौतियाँ प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर हैं—

पहली यह कि विश्व के प्रमुख देश वर्तमान में व्यापार के क्षेत्र में संरक्षणवादी नीतियाँ अपना रहे हैं. संरक्षणवादी नीतियों के अन्तर्गत देश दूसरे देशों से आने वाले आयात पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्धों का सहारा लेते हैं. इन प्रतिबन्धों के कारण वैश्विक स्तर पर व्यापार तथा निवेश बाधित होता है. वर्ष 2025 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने जनवरी से ही दूसरे देशों पर एकतरफा टैरिफ लगाने की प्रक्रिया आरम्भ की थी. इससे भारत सहित कई देश प्रभावित हुए हैं. उल्लेखनीय है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार देश है. भारत के विरुद्ध अमेरिका ने अगस्त 2025 में 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. इससे अमेरिका को होने वाला भारत का निर्यात कम हो गया है तथा भारत के निर्यात में कमी आ गई है. यद्यपि 2 फरवरी, 2026 को भारत व अमेरिका के बीच आपसी सहमति के अन्तर्गत हुई बातचीत में अमेरिका ने भारत के आयात पर टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया, लेकिन 20 फरवरी, 2026 के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले (राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा भारत सहित अन्य देशों पर लगाए गए रेसीप्रोकल टैरिफ को असंवैधानिक करार दिया) के बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने 1977 के आपातकालीन आर्थिक शक्ति कानून का प्रयोग करते हुए भारत सहित सभी देशों से आयात पर पहले 10 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की व बाद में इसे बढ़ाकर 15% कर दिया. ईरान में चल रहे युद्ध के कारण अमेरिकी टैरिफ पर कोई भी समझौता अनिश्चितता का शिकार हो गया है.

दूसरी प्रमुख चुनौती व्यापार व आपूर्ति श्रृंखला के राजनीतिकरण की है अर्थात् बड़े देश व्यापार तथा महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति को गैर-व्यापारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं. इसे व्यापार के हथियारीकरण (Weaponization of Trade) के नाम से जाना जाता है. उदाहरण के लिए, अमेरिका ने भारत के विरुद्ध अगस्त 2025 में 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ इसलिए लगाया था कि भारत रूस से तेल का आयात कर रहा है. अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर कई प्रकार के आर्थिक तथा सैनिक प्रतिबन्ध लगा रखे हैं. इसके पहले अमेरिका द्वारा ईरान के विरुद्ध 2018 में लगाए गए नए प्रतिबन्धों के कारण भारत को ईरान से अपना तेल आयात बन्द करना पड़ा था. ईरान से यह तेल आयात अभी भी बन्द है. अमेरिका अभी भी इसी नीति पर चल रहा है. व्यापार के राजनीतिकरण में चीन भी अमेरिका से पीछे नहीं है. चीन ने अप्रैल 2025 में भारत तथा अन्य देशों को अपने यहाँ से होने वाले चुम्बकों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था. चीन का चुम्बकों के उत्पादन में एकाधिकार है तथा भारत चुम्बकों के आयात के लिए लगभग पूरी तरह चीन पर निर्भर है. उल्लेखनीय है कि ऑटोमोबाइल उद्योग तथा बिजली उपकरणों के अलावा कई आधुनिक उद्योगों में चुम्बकों का उपयोग एक आवश्यक तत्व है. चीन के प्रतिबन्धों के कारण भारत में चुम्बक का प्रयोग करने वाली वस्तुओं का उत्पादन व व्यापार प्रभावित हुआ. इसी तरह क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन व आपूर्ति में भी चीन का प्रभुत्व बना हुआ है. क्रिटिकल मिनरल्स के प्रसंस्करण में विश्व में चीन की हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत है. क्रिटिकल मिनरल्स जैसे—लिथियम, सिलकॉन, जिरकोनियम आदि का प्रयोग भी कई आधुनिक उद्योगों जैसे—क्लीन इनर्जी उत्पादन व भण्डारण तथा सेमी-कंडक्टर आदि में होता है. चीन ने कई बार क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति को बाधित कर अपने कूटनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया है. इसीलिए भारत तथा अन्य देश क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत व लोचशील बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं. अमेरिका तथा 9 देशों ने दिसम्बर 2025 में पैक्स सिलिका नामक पहल की घोषणा की है जिसका एक प्रमुख उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को लोचशील तथा विश्वसनीय बनाना है. भारत भी 20 फरवरी, 2026 को पैक्स सिलिका पहल में शामिल हो गया है.

विश्व व्यापार में **तीसरी** चुनौती विश्व में लगातार चल रहे क्षेत्रीय संघर्षों के कारण वैश्विक व्यापार का बाधित होना है. वर्तमान में विश्व में कई क्षेत्रीय संघर्ष चल रहे हैं. उदाहरण के लिए, यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व व्यापार प्रभावित हो रहा है. यूक्रेन तथा रूस खाद्य उत्पादों तथा तेल व गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं. इस युद्ध के कारण खाद्य पदार्थों तथा तेल का व्यापार प्रभावित हो रहा है. भारत ने कई वैश्विक मंचों पर विश्व में खाद्य सुरक्षा का मामला जोर-शोर से उठाया है. अमेरिका का तथा यूरोपियन यूनियन ने इस युद्ध के कारण रूस के विरुद्ध कई तरह के आर्थिक व सैनिक प्रतिबन्ध लगा रखे है. इससे रूस के साथ भारत तथा अन्य देशों का व्यापार प्रभावित हुआ है. अमेरिकी प्रतिबन्धों के कारण भारत को रूस से अपना तेल आयात कम करना पड़ा है. इसी प्रकार 7 अक्टूबर, 2023 से चल रहे गाजा संघर्ष तथा वर्तमान में 28 फरवरी, 2026 से चल रहे ईरान युद्ध के कारण विश्व व्यापार विशेषकर तेल व गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है. उल्लेखनीय है कि ये दोनों संघर्ष पश्चिम एशिया में चल रहे हैं तथा पश्चिम एशिया विश्व में तेल व गैस का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है. अफ्रीका में चल रहे कई स्थानीय संघर्षों के कारण भी विश्व का व्यापार प्रभावित हो रहा है.

विश्व व्यापार की **चौथी** चुनौती विश्व व्यापार संगठन का निरन्तर कमजोर होना है. वैश्वीकरण के युग में मुक्त विश्व व्यापार के प्रोत्साहन के लिए 1 जनवरी, 1995 को 'विश्व व्यापार संगठन' की स्थापना की गई

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

थी. उल्लेखनीय है कि विश्व व्यापार को उदार तथा मुक्त बनाने का दायित्व विश्व व्यापार संगठन का है, लेकिन विश्व व्यापार संगठन प्रमुख देशों के सहयोग के बिना प्रभावी नहीं हो सकता है. कई प्रमुख देशों की संरक्षणवादी नीतियों के कारण विश्व व्यापार संगठन की भूमिका कमजोर हो रही है. उदाहरण के लिए, अमेरिका के असहयोग के कारण विश्व व्यापार संगठन की विवाद समाधान प्रणाली निष्क्रिय हो गई है. अमेरिका ने 2025 में विश्व व्यापार संगठन को अपना वित्तीय योगदान बन्द कर दिया है तथा उसने विश्व व्यापार संगठन से अलग होने के लिए अपनी संसद अर्थात् कांग्रेस में एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है. विश्व व्यापार संगठन की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था इसका मंत्रिमण्डलीय सम्मेलन है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के वाणिज्य मंत्री भाग लेते हैं तथा इसकी बैठकें प्रति 2 वर्ष के अन्तराल पर होती हैं. आम सहमति के अभाव में ये बैठकें प्रभावी नहीं हो पा रही हैं. उदाहरण के लिए, 13वाँ मंत्रिमण्डलीय सम्मेलन फरवरी-मार्च 2024 में आबूधाबी में हुआ था जिसमें प्रमुख विचारणीय विषयों जैसे—विवाद समाधान प्रणाली को पुनर्जीवित करना, खाद्य सुरक्षा तथा मछली सब्सिडी आदि में कोई आम सहमति नहीं बन पाई. कुल मिलाकर विश्व व्यापार संगठन वर्तमान में मुक्त व्यापार के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहा है.

भारत की आर्थिक कूटनीति : मुक्त व्यापार समझौते

विश्व अर्थव्यवस्था की वर्तमान अनश्चितताओं तथा संरक्षणवाद के माहौल में अपने व्यापारिक व आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारत ने अपनी आर्थिक कूटनीति को नई दिशा प्रदान की है. इनमें विश्व आपूर्ति श्रृंखला को लोचशील बनाने के साथ-साथ भारत ने अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए मुक्त व्यापार समझौतों की नीति अपनाई है. मुक्त व्यापार समझौते में शामिल देश एक-दूसरे के निर्यात में टैरिफ शुल्क को या तो समाप्त कर देते हैं अथवा बहुत कम कर देते हैं. इससे उन देशों के बीच व्यापार में तेजी आती है. उल्लेखनीय है कि विश्व व्यापार संगठन ने भी मुक्त व्यापार समझौतों को अपवाद-स्वरूप मान्यता दे रखी है. मुक्त व्यापार समझौतों की नीति भारत के निर्यात गंतव्यों के विविधीकरण के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझीदार अमेरिका ने भारत के विरुद्ध सबसे अधिक 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. इससे भारत का व्यापार प्रभावित हो रहा था. इस समस्या का समाधान करने तथा भारतीय व्यापार के लिए अन्य बाजारों को तलाशने की प्रक्रिया में भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों की नीति आपनाई है. वैसे तो भारत ने पूर्व में भी कई देशों के साथ इस प्रकार के व्यापार समझौते किए हैं, लेकिन गत 1 वर्ष में इसमें अधिक गतिशीलता दिखाई देती है.

भारत के मुक्त व्यापार समझौते

भारत ने फरवरी 2026 के अन्त तक कुल 18 मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, इनमें से 14 समझौते द्वि पक्षीय हैं तथा 4 समझौते (आसियान, सार्क, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ तथा यूरोपीय संघ) बहुपक्षीय हैं. इनका विवरण निम्नलिखित है–

1. भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता-1998—यह भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है.
2. भारत-थाइलैण्ड मुक्त व्यापार समझौता, 2003.
3. भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, 2005.
4. दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता-2006, इसे साफ्टा के नाम से भी जाना जाता है. यह समझौता दक्षेस के देशों के साथ है.
5. व्यापार तथा पारगमन पर भारत-भूटान समझौता, 2006.
6. भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता 2009.
7. भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, 2011.
8. भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, 2011
9. भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, 2011
10. भारत-नेपाल व्यापार समझौता, 2009.
11. भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौता, 2021.
12. भारत-यू.ए.ई. व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, 2022.
13. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक व्यापार तथा सहयोग समझौता, 2022.
14. भारत-मुक्त व्यापार संघ व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौता, 10 मार्च, 2024.
15. भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता, 24 जुलाई 2025.
16. भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, 18 दिसम्बर, 2025.
17. भारत-न्यूजीलैण्ड मुक्त व्यापार समझौता, 22 दिसम्बर, 2025.
18. भारत-यूरोपियन संघ मुक्त व्यापार समझौता, 27 जनवरी, 2026.

वरीयता व्यापार समझौतों (Preferential Trade Agreements)

इसके अलावा भारत ने 6 वरीयता व्यापार समझौतों (Preferential Trade Agreements) पर भी हस्ताक्षर किए हैं– एशिया-पैसिफिक व्यापार समझौता, 1975; ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रिफेरेंसेज (Global System of Trade Preferences), 1988; भारत अफगानिस्तान वरीयता व्यापार समझौता, 2003; भारत-मर्कोसुर वरीयता व्यापार समझौता, 2004; भारत-चिली वरीयता व्यापार समझौता, 2006 तथा भारत-दक्षेस वरीयता व्यापार समझौता, 2003.

मुक्त व्यापार समझौतों तथा वरीयता व्यापार समझौतों में मुख्य अन्तर यह है कि जहाँ मुक्त व्यापार समझौते में पक्षकारों के बीच होने वाले व्यापार की सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, वहीं वरीयता व्यापार समझौतों में किसी वस्तु विशेष के व्यापार में पक्षकारों के बीच आयात-निर्यात में वरीयता प्रदान की जाती है. अतः वरीयता व्यापार समझौता सीमित प्रकृति का होता है.

भारत द्वारा सम्पादित कतिपय प्रमुख मुक्त व्यापार समझौते

भारत द्वारा सम्पादित प्रमुख समझौतों में दो समझौते दूरगामी परिणाम वाले हैं, क्योंकि भारत ने ये समझौते यूरोप के विकसित देशों के साथ किए हैं. इन देशों के साथ व्यापारिक व निवेश सम्बन्धी सहयोग से भारत की वस्तुओं, सेवाओं के व्यापार तथा कुशल कामगारों को नए अवसर प्राप्त होंगे. इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है–

(अ) भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement–CETA)

जुलाई 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत तथा ब्रिटेन के बीच सम्पन्न यह एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता है. 3 वर्ष की गहन बातचीत के बीच 6 मई, 2025 को इस समझौते को अन्तिम रूप दिया गया था. इस समझौते के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1. इस समझौते में कुल 26 अध्याय हैं, जिनमें समझौते में शामिल सभी प्रमुख प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है.
2. इस समझौते के अन्तर्गत भारत से ब्रिटेन को होने वाला 99 प्रतिशत निर्यात जीरो शुल्क वाला अर्थात् शुल्क मुक्त होगा. इससे भारत की कई

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

वस्तुओं; जैसे–टेक्सटाइल, समुद्री उत्पाद, लेदर वस्तुएँ, खेलकूद का सामान, खिलौने, रत्न तथा गहने, इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटोपार्ट्स आदि के निर्यात में वृद्धि होगी. दूसरी तरफ ब्रिटेन से भारत आने वाली 90 प्रतिशत वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. ब्रिटेन की महँगी वस्तुओं जैसे–स्कॉच ह्विस्की पर वर्तमान में लगने वाला 150 प्रतिशत टैक्स अगले 10 वर्षों में घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा. इसी प्रकार ब्रिटेन की कारों में वर्तमान में भारत में लगने वाला 100 प्रतिशत टैक्स घटकर 10 प्रतिशत रह जाएगा.

3. इस समझौते में भारत से ब्रिटेन जाने वाले व्यावसायिक कॉर्मिकों के जाने को भी सुविधाजनक बनाया गया है.
4. एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन ने भारत की शर्त को मानते हुए कृषि क्षेत्र को इस मुक्त व्यापार समझौते से अलग रखा है.
5. मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार व निवेश में इजाफा होगा. 2025 में भारत व ब्रिटेन के बीच 47 बिलियन पाउण्ड का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था. अनुमान है कि इस मुक्त व्यापार समझौते के बाद 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार 75 बिलियन तक पहुँच जाएगा. इसके अतिरिक्त मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच निवेश व रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी.

(ब) भारत-यूरोपियन संघ मुक्त व्यापार समझौता

इस समझौते पर 27 जनवरी, 2026 को उस समय हस्ताक्षर किए गए, जब यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष तथा यूरोपीय परिषद् के अध्यक्ष ने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा की थी. यह समझौता अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोपीय संघ में यूरोप के 27 देश शामिल हैं.

इस समझौते की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं–

1. इस समझौते के अन्तर्गत यूरोपीय संघ द्वारा भारत से आयात होने वाली 99 प्रतिशत वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त हो जाएगा तथा भारत में यूरोप से आने वाली 96·6 प्रतिशत वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त हो जाएगा.
2. इस समझौते में दोनों के बीच होने वाले सेवाओं के व्यापार तथा डिजिटल व्यापार को शामिल किया गया है.
3. भारतीय किसानों के हितों को देखते हुए इस समझौते में कृषि उत्पादों तथा दुग्ध उत्पादों को शामिल नहीं किया गया है. अतः उक्त उत्पादों में टैरिफ की व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगी.
4. दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वे व्यापार को और सुविधाजनक बनाने के उपाय अपनाएंगे तथा बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था लागू करेंगे.
5. इस समझौते में दोनों के बीच व्यापार सम्बन्धी विवादों के समाधान की भी व्यवस्था की गई है.

दोनों के बीच 2024 में कुल व्यापार 120 बिलियन यूरो था. सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा जनसंख्या की दृष्टि से दोनों पक्षों की विश्व में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

निष्कर्ष

उक्त समझौतों के बाद भारत के व्यापार तथा विदेशी निवेश का तेजी से विस्तार होगा तथा भारत को अमेरिका की बजाय यूरोप में निर्यात के नए स्रोत प्राप्त होंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृषि तथा दुग्ध उत्पादों को इस समझौते से अलग रखा है. भारत ने अन्य समझौतों में भी इसी नीति का पालन किया है. इस प्रकार हाल के वर्षों में मुक्त व्यापार समझौते भारत की आर्थिक कूटनीति का महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं.

भारत-कनाडा सम्बन्ध : सुधार की नई पहल

करीब 3 वर्ष बाद भारत व कनाडा अपने आपसी तनावों व खराब सम्बन्धों को सुधारने के लिए प्रयासरत दिखाई दे रहे है. इस दिशा में कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की 27 फरवरी-2 मार्च, 2026 के बीच सम्पन्न 4 दिवसीय यात्रा का विशेष महत्व है. इस यात्रा से दोनों देशों ने अपने सम्बन्धों में आए तनावों को दूर कर आर्थिक व सामरिक क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है. वर्ष 2023 से ही दोनों देशों के सम्बन्ध खराब चल रहे थे. कार्नी की यात्रा से दोनों के बीच सम्बन्धों को दोबारा से मजबूत करने में मदद मिलेगी. यह यात्रा 2018 के बाद कनाडा के किसी प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है. इसके पहले कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वर्ष 2018 में भारत की यात्रा की थी.

भारत-कनाडा सम्बन्ध : एक पृष्ठभूमि

भारत तथा कनाडा के बीच वैसे तो गम्भीर तनाव 2023 में उपन्न हुए, लेकिन इसकी नींव 2018 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री ट्रूडो की यात्रा के समय ही पड़ गई थी, जब भारत की इच्छा के विपरीत ट्रूडो ने अमृतसर व पंजाब की भी यात्रा की थी. बात यह है कि कनाडा में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग निवास करते हैं तथा उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए ट्रूडो ने उस समय पंजाब की यात्रा की थी, लेकिन कनाडा में स्थित कतिपय अतिवादी सिख समूह खालिस्तान की माँग उठाते रहते है. भारत के आग्रह के बावजूद ट्रूडो सरकार ने इन अतिवादी समूहों पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की. भारत और कनाडा के सम्बन्ध 2023 में उस समय ज्यादा खराब हो गए थे जब कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितम्बर 2023 में भारत पर आरोप लगाया कि भारतीय सुरक्षा एजेन्सियाँ कनाडा में सिख उग्रवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि 18 जून, 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलम्बिया प्रान्त के सुरे (Surrey) शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर उग्रवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई थी. इतना ही नहीं प्रतिक्रियास्वरूप कनाडा ने भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को कनाडा छोड़ने के लिए भी कहा. भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक बचकाना आरोप बताया. इसके साथ ही भारत ने भी दिल्ली स्थित कनाडा दूतावास के एक वरिष्ठ राजनयिक को भारत छोड़ने का आदेश दिया था. प्रतिक्रिया-स्वरूप भारत ने अपने कनाडा स्थित दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए कनाडा के नागरिकों को वीजा देने पर भी रोक लगा दी थी. विवाद यहीं तक सीमित नहीं रहा. अक्टूबर 2023 में भारत ने कनाडा के दूतावास में कार्यरत अतिरिक्त स्टाफ को भी कनाडा से वापस बुला लिया था. कनाडा ने भारतीय दूतावास से अपने अतिरिक्त स्टाफ को मलेशिया तथा सिंगापुर में शिफ्ट कर दिया था. इसके साथ ही भारत ने कनाडा में निवास कर रहे अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने की एडवाइजरी जारी की. इसका एक तात्कालिक कारण यह था कि कनाडा में स्थित कतिपय खालिस्तानी अतिवादी समूहों ने भारतीय नागरिकों व राजनयिकों को धमकी दी थी.

तनाव के प्रभाव–भारत व कनाडा के बीच आए तनावों के कारण दोनों देशों के सम्बन्ध नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए–

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

पहला, इस घटना के कारण भारत व कनाडा के बीच चल रहे आर्थिक सहयोग में खासा गतिरोध उत्पन्न हो गया. दोनों देश अपने आर्थिक सम्बन्धों का विस्तार करने के लिए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (Comprehensive Economic Cooperation Agreement–CEPA) को अन्तिम रूप देने के लिए बातचीत कर रहे थे. इससे दोनों देशों के बीच यह सम्भावित व्यापार समझौता अनिश्चितता का शिकार हो गया है. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिरोध के कारण वर्तमान व्यापार भी प्रभावित हुआ. दोनों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 20 मिलियन डॉलर था जिसमें बाद में गिरावट आई.

दूसरा, भारत व कनाडा के बीच कूटनीतिक गतिरोध का प्रभाव कनाडा में निवास कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा व उनके कामकाज पर भी पड़ा है. कनाडा के कतिपय अतिवादी नेताओं द्वारा हिन्दुओं को धमकाने का प्रयास किया गया. इस घटना का प्रभाव भारत में सामजिक सद्भाव को तनावयुक्त कर सकता है.

तीसरा, इससे कनाडा स्थित सिख अलगाववादी ताकतों को बल मिला. सिख समुदाय के करीब 60 लाख लोग भारत के बाहर विश्व के विभिन्न देशों में निवास करते है. इनमें सबसे ज्यादा 7,70000 सिख कनाडा में निवास करते हैं. कनाडा में सिखों की आबादी वहाँ की जनसंख्या का 2 प्रतिशत है. अतः कनाडा के राजनीतिक दल इनका समर्थन प्राप्त करने के लिए इनके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं. उल्लेखनीय है कि भारत ने 2020 में हिंसात्मक गति-विधियों के कारण हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया था तथा हरदीप सिंह को भारत लाने की अपील कनाडा से की थी, लेकिन कनाडा ने इसके बावजूद निज्जर का प्रत्यर्पण नहीं किया. कनाडा भारत विरोधी व खालिस्तान समर्थक गतिविधियों का गढ़ रहा है. जून 1985 में कनाडा से भारत आ रहे एक यात्री विमान को कनाडा स्थित सिख आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था, जिसमें 329 भारतीय नागरिक मारे गए थे. इस घटना के लिए दोषी तीन में से दो आतंकवादियों को पहले ही छोड़ दिया गया था तथा अन्तिम अभियुक्त को 2016 में मुक्त कर दिया गया था. खालिस्तान सम्बन्धित अलगाववादी गतिविधियों को लेकर भारत व कनाडा के बीच पहले से मनमुटाव था, लेकिन 2023 के बाद यह तनाव बहुत अधिक बढ़ गया था.

नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा, फरवरी-मार्च, 2026

भारत व कनाडा के खराब सम्बन्धों के बीच कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने 27 फरवरी-2 मार्च, 2026 तक 4 दिनों की भारत यात्रा की है. मार्क कार्नी 14 मार्च, 2025 को ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने थे. प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने भारत व कनाडा के सम्बन्धों में सुधार की पहल करना आरम्भ कर दिया था. कार्नी ने कनाडा में 17-18 जून, 2025 को सम्पन्न हुए जी-7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था. प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2025 में कनाडा की यात्रा भी की थी तथा इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी सम्बन्धों को पुनः पटरी पर लाने की सहमति बनी थी. इसके बाद दोनों नेताओं के बीच 22 नवम्बर, 2025 को दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहन्सबर्ग में जी-20 सम्मेलन के दौरान भी अनौपचारिक बातचीत हुई थी.

उक्त पृष्ठभूमि में भारत के आमंत्रण पर कार्नी ने भारत की वर्तमान यात्रा की है. उनके साथ इस यात्रा के दौरान मंत्रियों, शीर्ष अधिकारियों तथा व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमण्डल भी भारत आया था. दोनों पक्षों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय व बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत के बाद दोनों देशों ने यात्रा के अन्त में 2 मार्च, 2026 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों व कार्यक्रमों का उल्लेख है.

इस संयुक्त वक्तव्य के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं–

(अ) दोनों नेताओं ने अपने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा 79 वर्ष से चले आ रहे घनिष्ठ सम्बन्धों को रेखांकित किया. दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि वर्तमान विश्व की अनिश्चित तथा जटिल परिस्थितियों के आलोक में दो लोकतांत्रिक देशों के बीच एक मजबूत व भविष्यगामी साझेदारी का विकास आवश्यक है. इस साझेदारी से अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा यह साझेदारी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में सहायक सिद्ध होगी. उक्त साझे दृष्टिकोण के आधार पर दोनों नेताओं ने वसुधैव कुटुम्बकम अथवा वन अर्थ वन फेमिली तथा वन फ्यूचर (One Earth One Family One Future) से प्रेरित फ्रेमवर्क के आधार पर भारत-कनाडा सामरिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की. दोनों देशों के बीच भविष्य की साझेदारी का रोडमैप 'वन अर्थ वन फेमिली तथा वन फ्यूचर' के फ्रेमवर्क पर ही आधारित है.

(ब) वन अर्थ अर्थात् एक पृथ्वी

इसके अन्तर्गत क्लीन इनर्जी सहयोग, क्रिटिकल मिनरल, जलवायु परिवर्तन तथा कृषि क्षेत्र में साझेदारी को शामिल किया गया है–

1. इनर्जी साझेदारी के अन्तर्गत दोनों देशों ने भारत-कनाडा इनर्जी पार्टनरशिप का आरम्भ किया है, जिसमें दोनों देशों के बीच इनर्जी के क्षेत्र में दीर्घकालीन साझेदारी को आगे बढ़ाया जाएगा.
2. क्लीन इनर्जी के क्षेत्र में कार्बन कैप्चर तथा उपयोग व भण्डारण में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई. क्लीन इनर्जी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भी दोनों देशों के बीच एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
3. इनर्जी व्यापार के अन्तर्गत दोनों देशों ने कनाडा द्वारा भारत को यूरेनियम आपूर्ति के लिए 2·6 बिलियन डॉलर का समझौता भी सम्पन्न हुआ है.
4. वर्तमान में क्रिटिकल मिनरल आधुनिक तकनीकी विकास, विशेषकर क्लीन इनर्जी स्टोरेज तथा ऑटोमोबाइल के लिए अत्यन्त आवश्यक है. अतः दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए है. इसके अन्तर्गत दोनों देश क्रिटिकल मिनरल्स की एक-एक सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला के विकास का प्रयास करेंगे.
5. भारत व कनाडा दोनों ही देश प्रमुख कृषि उत्पादक देश हैं. दोनों देशों ने कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है. दोनों देशों ने भारत के सोनीपत (हरियाणा) में **भारत-कनाडा दाल उत्कृष्टता** केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया है. उल्लेखनीय है कि कनाडा दालों का बड़ा उत्पादक देश है तथा भारत 2023 के पहले कनाडा से बड़ी मात्रा में मसूर दाल का आयात करता रहा है.

(स) वन फेमिली फ्रेमवर्क

इसके अन्तर्गत आपसी सहयोग के लिए शिक्षा, वैज्ञानिक शोध, कौशल विकास, नवोन्मेष, टेलेन्ट विकास, सांस्कृतिक सहयोग तथा जनता के बीच आदान-प्रदान को शामिल किया गया है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

1. दोनों देशों ने टेलेन्ट, विद्यार्थियों तथा शिक्षाविदों के बीच आपसी गतिशीलता बढ़ाने पर बल दिया. इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच रिसर्च इन्टर्नशिप की सुविधा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं. इसके अन्तर्गत प्रति वर्ष 300 भारतीय विद्यार्थी अमेरिका की संस्थाओं में इन्टर्नशिप के लिए जा सकेंगे.
2. नवोनन्मेष के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त टेलेन्ट व नवोन्मेष रणनीति की भी घोषणा की गई है. इसके अन्तर्गत दोनों देशों के बीच शोध व नवोन्मेष के क्षेत्र में सहयोग व आदान-प्रदान पर बल दिया गया है.
3. दोनों देशों के बीच जनता के ऐतिहासिक सम्बन्धों के आलोक में सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने पर बल दिया गया है. सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
4. दोनों नेताओं ने भारत-कनाडा ट्रैक-2 सामरिक वार्ताओं की शुरुआत का स्वागत किया तथा इन्हें आगे बढ़ाने का निर्णय लिया.

(द) वन फ्यूचर (One Future)

इसके अन्तर्गत विज्ञान व तकनीकी, अन्तरिक्ष तकनीकी तथा डिजिटल तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग को शामिल किया गया है.

1. आर्थिक विकास में विज्ञान व तकनीकी के महत्व को देखते हुए दोनों ने विज्ञान व तकनीकी तथा नवोन्मेष के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया. इसके लिए भारत-कनाडा विज्ञान व तकनीकी सहयोग समिति को पुनर्जीवित किया गया है.
2. यह निर्णय लिया गया कि दोनों देश निजी व सरकारी अन्तरिक्ष संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाएंगे. इसके अन्तर्गत दोनों देश संयुक्त अन्तरिक्ष कार्यक्रमों का भी संचालन करेंगे.
3. डिजिटल तकनीकी के अन्तर्गत संयुक्त रूप से ए.आई. टूल्स के विकास में सहयोग का निर्णय लिया गया.
4. दोनों देशों ने भारत-कनाडा-ऑस्ट्रेलिया तकनीकी व नवोन्मेष साझेदारी का स्वागत किया. तीनों देशों द्वारा नवम्बर 2025 में जी-20 की बैठक के समय उक्त साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए थे.

(य) आधारभूत संरचना (Foundational Layers)

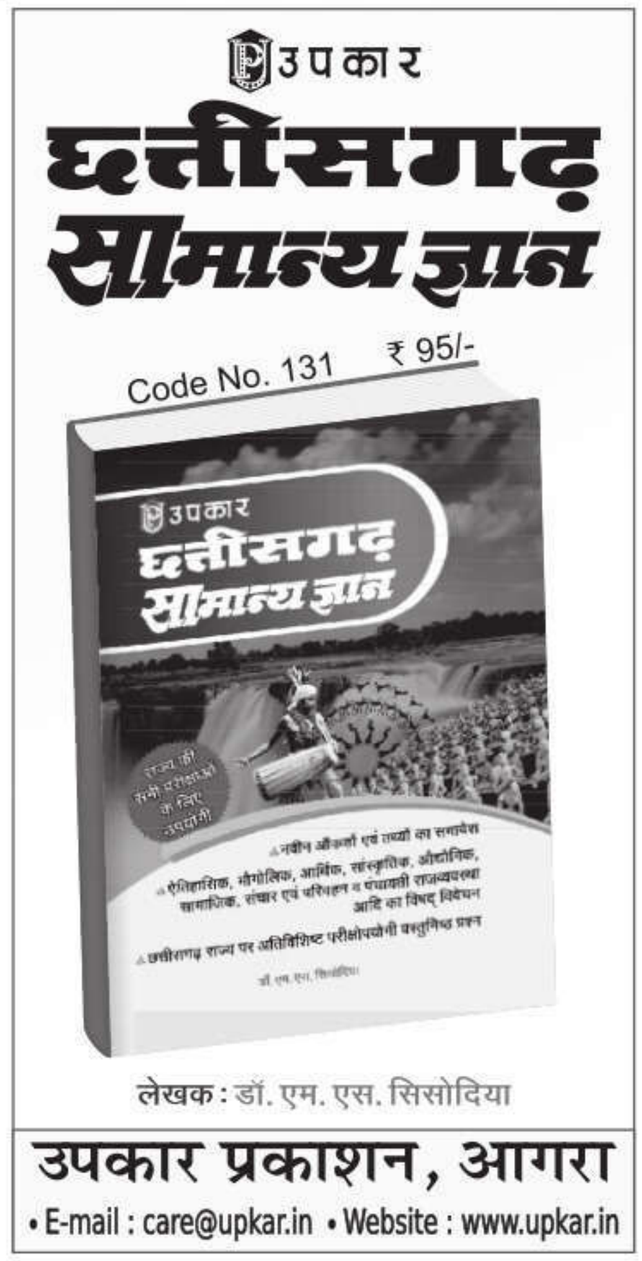
वन अर्थ, वन फैमिली तथा वन फ्यूचर के फ्रेमवर्क पर आधारित उक्त सामरिक साझेदारी को व्यावहारिक रूप देने के लिए दोनों देशों ने इस यात्रा के दौरान सम्बन्धों की 2 आधारभूत संरचनाओं को चिह्नित किया है. इसका तात्पर्य यह कि भारत व कनाडा की सामरिक साझेदारी में ये दोनों संरचनाएँ नींव का काम करेंगी.

1. **सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सहयोग–** सुरक्षा सहयोग को दोनों देशों द्वारा अपनी साझेदारी की आधारभूत संरचना माना गया है. इस सम्बन्ध में दोनों देशों ने हिंसक उग्रवाद, आतंकवाद, नशीली दवाओं का अवैध व्यापार तथा साइबर अपराधों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की.
   प्रतिरक्षा सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों ने स्थायी प्रतिरक्षा वार्ताओं की व्यवस्था करने पर सहमति व्यक्त की. इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई.
   इसी के साथ ही हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में सुरक्षा व स्थायित्व के लिए भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया.
2. **व्यापारिक सहयोग–**दोनों देशों ने व्यापार व निवेश में सहयोग को अपनी साझेदारी का दूसरा आधारभूत स्तम्भ माना है.
   इसके अन्तर्गत दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते की वार्ताओं को पुन: गति प्रदान कर इस वर्ष के अन्त तक इस समझौते के समापन का निर्णय लिया है. इस समझौते को व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement–CEPA) का नाम दिया गया है.
   इसके साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक अपने वर्तमान व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
   व्यापार व निवेश की साझेदारी को गति प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रियों की वार्ताओं तथा सी.ई.ओ. फोरम को पुन: स्थापित किया गया है.

निष्कर्ष

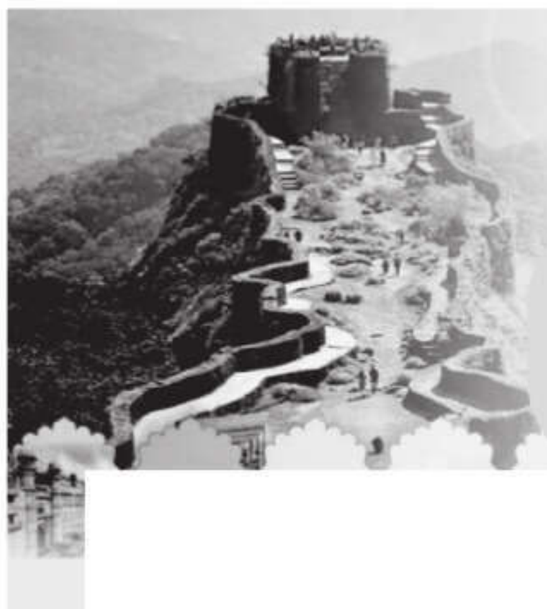
भारत व कनाडा ने 79 वर्ष पहले अपने कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना की थी. कनाडा में निवास कर रहे भारतीयों के कारण दोनों देशों के बीच कतिपय मुद्दों को छोड़कर सामान्य सम्बन्ध रहे हैं. तनाव का एक मुद्दा कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को शरण मिलना रहा है. भारत ने इस विषय पर कनाडा से अपनी चिन्ताएँ भी कई बार व्यक्त की हैं. सितम्बर 2023 में दोनों देशों के सम्बन्धों में तीव्र गिरावट आई जब कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत की सुरक्षा एजेन्सियों पर कनाडा में निज्जर नामक आतंकवादी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया. भारत द्वारा इस सम्बन्ध में साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात कही गई, लेकिन कनाडा ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया. इसके बाद से 3 वर्ष तक दोनों के सम्बन्धों में गिरावट का क्रम चलता रहा. मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सम्बन्धों को पुन: पटरी पर लाने की पहल की. इस पहल के अन्तर्गत कार्नी की भारत यात्रा से दोनों के सम्बन्धों में तेजी से सुधार का क्रम आरम्भ हुआ है. यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अन्य कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, तथा मुक्त व्यापार समझौते को यथाशीघ्र सम्पन्न करने पर सहमति व्यक्त की है. इसके अलावा भारत को यूरेनियम की आपूर्ति तथा क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं. उल्लेखनीय है कि विश्व की वर्तमान व्यवस्था की अनिश्चितता तथा दोनों देशों के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की एकतरफा टैरिफ नीतियाँ भी दोनों देशों को सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हैं. उक्त तथ्यों के आलोक में कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी की वर्तमान यात्रा दोनों देशों के सम्बन्धों के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध होगी.

●●●



लेखक : डॉ. एम. एस. सिसोदिया
उपकार प्रकाशन, आगरा
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



योजना पर आधारित प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1. केन्द्रीय बजट 2026-27 में मध्यम वर्ग के लिए किए गए प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए. क्या ये प्रावधान आर्थिक गतिविधियों और उपभोग को बढ़ाने में सहायक होंगे ? (150 शब्द)

उत्तर—मध्यम वर्ग किसी भी अर्थव्यवस्था की खपत, निवेश और कर राजस्व का महत्वपूर्ण आधार होता है. केन्द्रीय बजट 2026-27 में मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं.

मुख्य प्रावधान

1. आय कर में राहत—नई कर व्यवस्था में आय कर स्लैब को यथावत और कर दरों को सरल बनाने का प्रयास किया गया हैं.

- **उदाहरण**—कम आय कर भार से मध्यम वर्ग की बचत और उपभोग बढ़ सकता है.

2. आवास क्षेत्र को प्रोत्साहन—सस्ते आवास और गृह ऋण योजनाओं को बढ़ावा दिया गया है.

3. डिजिटल और सेवा क्षेत्र में अवसर—डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सृजित करने का प्रयास किया गया है.

- **उदाहरण**—आईटी, ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं में रोजगार के नए अवसरों के लिए प्रयास.

4. शिक्षा और कौशल विकास—तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है.

- **उदाहरण**—एआई, क्लाउड और डिजिटल स्किल से युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी.
- सारांशतः उपर्युक्त प्रावधान मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाकर उपभोग और निवेश को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलने की सम्भावना है.

प्रश्न 2. "विकसित भारत के निर्माण में युवा, महिलाएँ, किसान और गरीब चार प्रमुख स्तंभ हैं." बजट 2026-27 के सन्दर्भ में स्पष्ट कीजिए. (250 शब्द)

उत्तर—समावेशी विकास का अर्थ है कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे. बजट 2026-27 में युवा, महिलाएँ, किसान और गरीब को विकास के चार प्रमुख स्तंभ माना गया है.

1. युवा—कौशल विकास पर जोर-नई तकनीकी स्किल (AI, डिजिटल, क्लाउड) पर प्रशिक्षण.

- **उदाहरण**—औद्योगिक क्षेत्रों के पास नए विश्वविद्यालय/स्किल सेंटर स्थापित करना.

स्टार्टअप व नवाचार—युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन.

- **उदाहरण**—स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इनोवेशन मिशन.

2. महिलाएँ : महिला उद्यमिता को बढ़ावा—स्वयं सहायता समूह (SHGs) को समर्थन.

- **उदाहरण**—लखपति दीदी योजना से ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना.

कौशल व रोजगार—देखभाल सेवाओं (Care economy) में अवसर.

- **उदाहरण**—आंगनवाड़ी, हेल्थ केयर और सेवा क्षेत्र में प्रशिक्षण.

3. किसान—डिजिटल कृषि और एग्रीटेक-खेती को तकनीक से जोड़ना.

- **उदाहरण**—डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और भारत-कृषि प्लेटफॉर्म.

मूल्य शृंखला और भण्डारण—फसल के बाद नुकसान कम करना.

- **उदाहरण**—कोल्ड-स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी/मत्स्य क्षेत्र का विस्तार.

4. गरीब : सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ—भोजन, आवास और स्वास्थ्य पर ध्यान.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

- **उदाहरण**—प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना.

रोजगार अवसर : ग्रामीण रोजगार व कौशल कार्यक्रम.

- **उदाहरण**—विकसित भारत-जी राम जी और ग्रामीण आजीविका मिशन.

निष्कर्ष—यदि इन चार स्तम्भों—युवा, महिलाएँ, किसान और गरीब को सशक्त किया जाए, तो आर्थिक वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित होगा और 'विकसित भारत 2047' का लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव होगा.

कुरुक्षेत्र पर आधारित प्रश्नोत्तर



प्रश्न 1. केन्द्रीय बजट 2026-27 में आर्थिक सुधारों के माध्यम से रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों का विश्लेषण कीजिए. (150 शब्द)



उत्तर—केन्द्रीय बजट 2026-27 का उद्देश्य आर्थिक सुधारों के माध्यम से रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है. यह बजट 'विकसित भारत 2047' की दिशा में संरचनात्मक बदलावों पर जोर देता है.

1. रोजगार और कौशल विकास—युवाओं के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाए गए.

- उद्योगों की जरूरत के अनुसार तकनीकी कौशल पर जोर.
- **उदाहरण**—टेक्सटाइल और एमएसएमई क्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्र.

2. एमएसएमई और उद्योग को बढ़ावा—एमएसएमई क्लस्टर और वित्तीय सहायता बढ़ाई गई.

- तकनीकी उन्नयन और बाजार तक पहुँच को प्रोत्साहन.
- **उदाहरण**—MSME के लिए क्रेडिट गारंटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म.

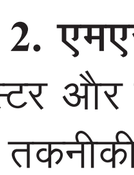
3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती—कृषि, ग्रामीण उद्योग और बुनियादी ढाँचे में निवेश.

- किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार बढ़ाने पर जोर.
- **उदाहरण**—फूड प्रोसेसिंग, डेयरी और मत्स्य पालन का विस्तार.

4. अवसंरचना और निवेश—परिवहन, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाया गया.

- इससे उद्योगों की लागत कम और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.
- **उदाहरण**—सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाएँ.

निष्कर्ष—अतः बजट 2026-27 के सुधार रोजगार, उद्योग और ग्रामीण विकास को गति देकर भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.



प्रश्न 2. केन्द्रीय बजट 2026-27 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर और डेटा अवसंरचना को भविष्य-उन्मुख अर्थव्यवस्था की नींव के रूप में कैसे प्रस्तुत किया गया है ? इसके सम्भावित लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए. (250 शब्द)



उत्तर—केन्द्रीय बजट 2026-27 में भारत को भविष्य-उन्मुख तकनीकी अर्थव्यवस्था बनाने पर विशेष जोर दिया गया है. AI, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर भारत को वैश्विक तकनीकी उत्पादन और नवाचार का केन्द्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा अवसंरचना—राष्ट्रीय AI डेटा केन्द्रों और डिजिटल अवसंरचना के निर्माण पर जोर.

- इससे शोध, स्टार्टअप और उद्योगों को डेटा व कम्प्यूटिंग क्षमता मिलेगी.
- **उदाहरण**—स्वास्थ्य क्षेत्र में AI आधारित रोग पहचान और स्मार्ट कृषि में AI द्वारा फसल पूर्वानुमान.

2. सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण—इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत् चिप निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा.

- इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उद्योग को मजबूत करना है.
- **उदाहरण**—मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए भारत में चिप निर्माण इकाइयाँ.

3. बायोटेक और वैक्सीन अनुसंधान—बायोमैन्युफैक्चरिंग और जैव-प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देकर स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र को मजबूत करना.

- **उदाहरण**—mRNA वैक्सीन और नई दवाओं के विकास के लिए अनुसंधान संस्थानों को समर्थन.

4. स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा—तकनीकी स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता और नीति समर्थन.

- **उदाहरण**—AI, रोबोटिक्स और फिनटेक स्टार्टअप को निवेश व इनक्यूबेशन समर्थन.

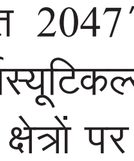
चुनौतियाँ—उच्च पूँजी निवेश और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी.

- डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ.
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति शृंखला जोखिम.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

निष्कर्ष—इस प्रकार, बजट 2026-27 में तकनीकी अवसंरचना और नवाचार को बढ़ावा देकर भारत को डिजिटल और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को साकार करने में सहायक होंगे.

डाउन टू अर्थ पर आधारित प्रश्नोत्तर



प्रश्न 1. हालिया केन्द्रीय बजट 2026-27 में घोषित प्रावधानों के सन्दर्भ में बताइए कि यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों का किस हद तक समाधान प्रस्तुत करता है ? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए. (150 शब्द)



उत्तर—केन्द्रीय बजट 2026-27 ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया है जब वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, निवेश में सुस्ती और ग्रामीण माँग की कमजोरी जैसी चुनौतियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद हैं.

बजट की प्रमुख प्राथमिकताएँ

1. दीर्घकालिक विकास दृष्टि—बजट को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य से जोड़ा गया है, जिसमें जैव-फार्मास्यूटिकल्स, शहरी आर्थिक क्षेत्र और भण्डारण तकनीकों जैसे क्षेत्रों पर निवेश का प्रस्ताव है.

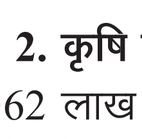
2. कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र—कृषि क्षेत्र के लिए लगभग ₹ 1·62 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा कृषि उन्नति योजना में वृद्धि की गई है, जिससे उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया गया है.

3. महिला सशक्तिकरण व ग्रामीण आजीविका—स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया गया है.

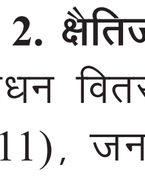
सीमाएँ व चुनौतियाँ—कुल सरकारी व्यय GDP के 13·6% तक सीमित है, जो पिछले वर्षों से कम है.

- ग्रामीण मजदूरी और माँग में गिरावट के बावजूद पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया गया.
- कुछ सामाजिक योजनाओं (जैसे—फसल बीमा, उज्ज्वला) में कटौती देखी गई.

निष्कर्ष—अतः बजट दीर्घकालिक विकास और संरचनात्मक सुधारों पर केन्द्रित है, किन्तु अल्पकालिक माँग और रोजगार सृजन को पर्याप्त बढ़ावा देने की आवश्यकता बनी हुई है.



प्रश्न 2. 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों में आए प्रमुख परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए. साथ ही बताइए कि ये परिवर्तन सहकारी संघवाद और जलवायु चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं ? (250 शब्द)



उत्तर—वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत् गठित एक संवैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य कार्य केन्द्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बँटवारे तथा अनुदानों के सिद्धांत तय करना है. 16वें वित्त आयोग ने बदलती आर्थिक और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की है.

मुख्य परिवर्तन

1. करों के ऊर्ध्वाधर वितरण की निरन्तरता—आयोग ने राज्यों को केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में 41% हिस्सेदारी बनाए रखने की सिफारिश की है, जिससे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को स्थिरता मिलती है.

2. क्षैतिज वितरण के नए मानदंड—राज्यों के बीच संसाधन वितरण के लिए आय का अन्तर, जनसंख्या (2011), जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, क्षेत्रफल, वन एवं पारिस्थितिकी और कर-प्रयास जैसे मानदंडों को महत्व दिया गया है. पहली बार राष्ट्रीय जीडीपी में राज्यों के योगदान को भी एक संकेतक के रूप में शामिल किया गया है.

3. राज्य घाटा अनुदान समाप्त करने की सिफारिश—इससे राज्यों को अपने संसाधन बढ़ाने और राजस्व सृजन की दिशा में अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.

4. स्थानीय निकायों को अधिक अनुदान—पंचायतों और शहरी निकायों के लिए 2026-31 के दौरान लगभग ₹ 7·9 लाख करोड़ के अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिससे विकेन्द्रीकरण और स्थानीय शासन को मजबूती मिलेगी.

5. जलवायु और पर्यावरण पर ध्यान—वन क्षेत्र तथा पारिस्थितिक सेवाओं को मानदंड बनाकर राज्यों को पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया है.

महत्व—ये सिफारिशें राज्यों को राजस्व बढ़ाने, स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देकर सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करती हैं.

निष्कर्ष—हालाँकि, इन सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों की प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय अनुशासन आवश्यक है, परन्तु 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें भारत की संघीय वित्तीय व्यवस्था को अधिक संतुलित, उत्तरदायी और भविष्य उन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

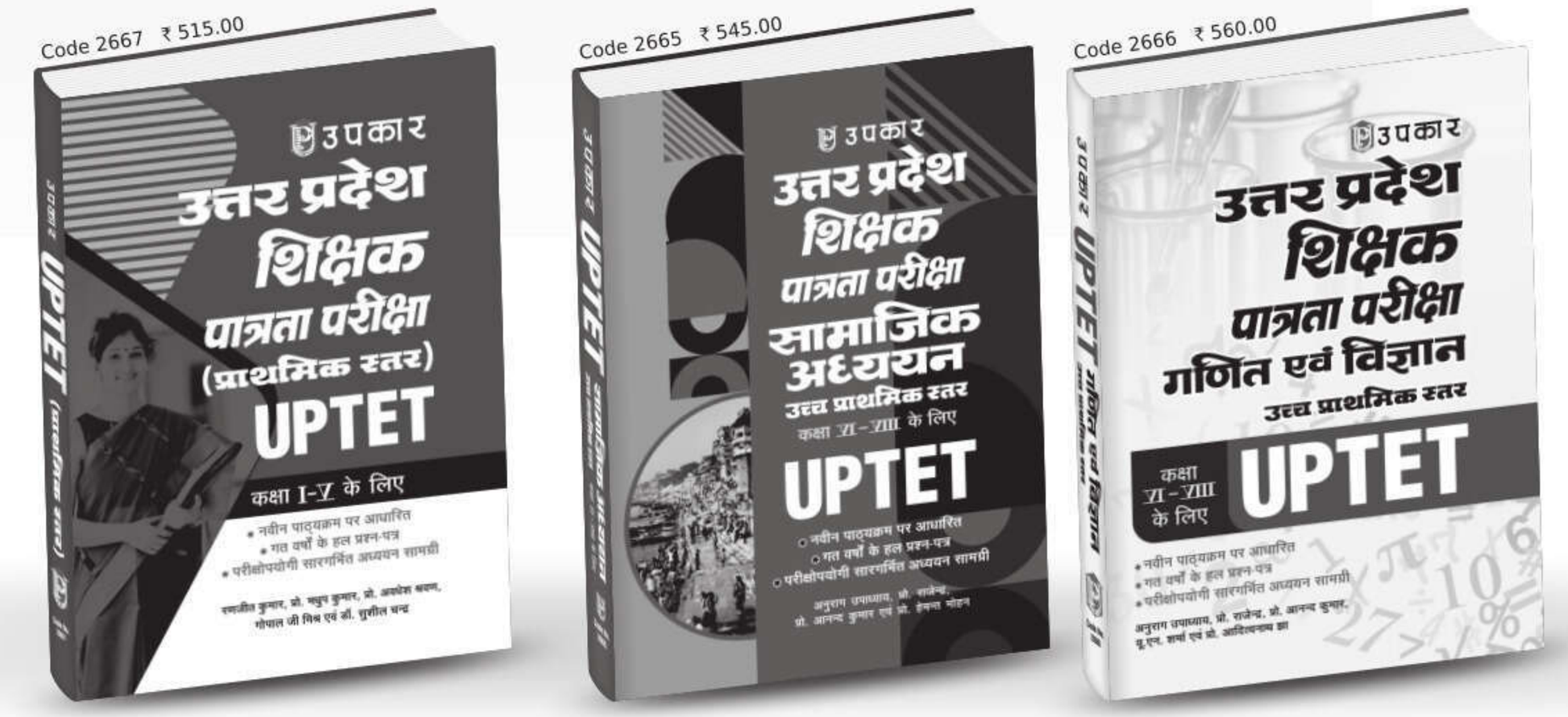
उपकार

उत्तर प्रदेश

शिक्षक पात्रता परीक्षा

कक्षा I-V के लिए

कक्षा VI-VIII के लिए







UPTET

* नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित * गत वर्षों के हल प्रश्न-पत्र
* परीक्षोपयोगी सारगर्भित अध्ययन सामग्री

Available on : upkar.in | amazon | Flipkart

उपकार प्रकाशन | 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास रोड, आगरा-282 005
फोन : (0562) 2530966, 2531101 • हल्द्वानी मो. 07060421008 | • E-mail : sales@upkar.in • Website : www.upkar.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय – फरवरी 2026

फोटोकॉपी मूल दस्तावेज का स्थान नहीं ले सकती : सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में 'सर्वोत्तम साक्ष्य नियम' की पुनः पुष्टि की गई

- **मामले का नाम एवं सन्दर्भ–** थरम्मेल पी. थंबरन *बनाम* टी. उषाकृष्णन, 2026 INSC 134, भारत का सर्वोच्च न्यायालय.

संक्षिप्त तथ्य

यह मामला केरल में एक सम्पत्ति विवाद से उत्पन्न हुआ, जो पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) के माध्यम से किए गए एक विक्रय लेन-देन की वैधता से सम्बन्धित था. वादी ने कुछ अचल सम्पत्ति पर अपना स्वामित्व होने का दावा किया और आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने जाली पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करके धोखाधड़ी-पूर्वक विक्रय विलेख निष्पादित किया.

वादी के अनुसार, उसने प्रतिवादी के पक्ष में ऐसा कोई पावर ऑफ अटॉर्नी कभी निष्पादित नहीं किया था.

इसलिए, उस दस्तावेज के आधार पर सम्पत्ति का बाद का हस्तांतरण शून्य और अवैध था.

विचारण (ट्रायल) की कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी ने मूल दस्तावेज के स्थान पर केवल उसकी फोटोकॉपी प्रस्तुत करके पावर ऑफ अटॉर्नी के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया. प्रतिवादी ने तर्क दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत् इस फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए.

विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और कहा कि प्रतिवादी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा है तथा द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ स्थापित नहीं कर सका. परिणामस्वरूप, न्यायालय ने उक्त लेन-देन को अमान्य घोषित कर दिया.

हालाँकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निर्यण को पलट दिया, फोटोकॉपी को ग्राह्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया और सम्पत्ति के लेन-देन को वैध ठहराया.

वादी ने इस निर्णय को केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को पुनर्स्थापित करते हुए यह निर्णय दिया कि साक्ष्य अधिनियम के तहत् निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना फोटोकॉपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

इस निर्णय से असंतुष्ट होकर, प्रतिवादी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की.

विचारण हेतु मुद्दे

1. क्या किसी दस्तावेज की फोटोकॉपी को, मूल दस्तावेज के खो जाने या अनुपलब्ध होने को सिद्ध किए बिना, द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ?
2. क्या न्यायालय सिविल विवादों में सम्पत्ति अधिकारों का निर्धारण करने के लिए फोटोकॉपी पर निर्भर कर सकते हैं ?
3. साक्ष्य अधिनियम के तहत् द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य बनाने से पहले किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है ?

सम्बन्धित विधिक प्रावधान

न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधान का परीक्षण किया, विशेष रूप से–

- धारा 61–दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत (BSA, 2023 की धारा 56)
- धारा 62–प्राथमिक साक्ष्य (BSA, 2023 की धारा 57)
- धारा 63–द्वितीयक साक्ष्य (BSA, 2023 की धारा 58)
- धारा 65–वे परिस्थितियाँ जिनमें द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है (BSA, 2023 की धारा 60)

न्यायालय ने 'सर्वोत्तम साक्ष्य नियम' (Best Evidence Rule) के सिद्धान्त का भी सन्दर्भ दिया, जिसके अनुसार जहाँ तक सम्भव हो, मूल दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है.

न्यायालय का अन्तिम निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया. न्यायालय ने यह माना कि कथित पावर ऑफ अटॉर्नी की फोटोकॉपी को ग्राह्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए आवश्यक शर्तें पूर्ण नहीं की गई थीं.

न्यायालय का तर्क

न्यायालय ने यह बल दिया कि प्राथमिक साक्ष्य नियम (Primary Evidence Rule) के अनुसार किसी दस्तावेज अन्तर्वस्तु का सबूत सिद्ध करने के लिए पक्षकारों को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है.

फोटोकॉपी जैसे द्वितीयक साक्ष्य केवल उन असाधारण परिस्थितियों में स्वीकार किए जा सकते हैं, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में वर्णित हैं.

द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले, जिस पक्ष ने उस पर निर्भर होना है, उसे यह सिद्ध करना आवश्यक है कि–

- मूल दस्तावेज खो गया है या नष्ट हो गया है, या
- मूल दस्तावेज विरोधी के पास है, जो इसे प्रस्तुत करने से इंकार कर रहा है, या
- वैध कानूनी कारणों से मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सकता.

वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने ऐसी कोई परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं कीं. यह साबित भी नहीं हुआ कि मूल पावर ऑफ अटॉर्नी खो गया था या अनुपलब्ध था.

न्यायालय ने चेतावनी दी कि बिना सख्त जाँच के फोटोकॉपी स्वीकार करने से धोखाधड़ी और दस्तावेजों में जालसाजी का जोखम बढ़ जाएगा, विशेषकर उन सम्पत्ति विवादों में जहाँ दस्तावेजी साक्ष्य निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

"रियल एस्टेट परियोजनाओं में दिवालियापन : सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक संस्थाओं के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाहियों की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया"

मामले का नाम एवं सन्दर्भ–सतिंदर सिंह भसीन *बनाम* कर्नल गौतम मुल्लिक, 2026 SCC OnLine SC, भारत का सर्वोच्च न्यायालय.

संक्षिप्त तथ्य

यह मामला एक रियल एस्टेट विकास परियोजना से उत्पन्न हुआ, जिसमें कई गृह खरीदारों ने आवासीय इकाइयाँ खरीदने के लिए पर्याप्त राशि निवेश की थी. परियोजनाओं में हालाँकि, निर्माण में गम्भीर देरी हुई और डेवलपर वादे के अनुसार फ्लैट्स का कब्जा देने में विफल रहा.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

पीड़ित गृह खरीदारों का आरोप था कि डेवलपर ने अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया और परियोजना प्रभावी रूप से ठप हो गई थी. परिणामस्वरूप, कुछ आवंटियों ने दिवालियापन और दिवालापन संहिता, 2016 (IBC) की धारा 7 के तहत् राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की, यह दावा करते हुए कि डेवलपर ने वित्तीय देनदारी का उल्लंघन किया. मामले में जटिलता इस कारण उत्पन्न हुई कि रियल एस्टेट परियोजना को कई कॉर्पोरेट संस्थाओं के माध्यम से संरचित किया गया था, जो परियोजना से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों जैसे भूमि स्वामित्व निर्माण या वित्तीय प्रबंधन को सँभालती थीं. याचिकाकर्ताओं ने परियोजना से जुड़े कई कॉर्पोरेट संस्थाओं को शामिल करते हुए संयुक्त दिवालियापन याचिका दायर की.

प्रतिवादियों की याचिका की योग्यता (Maintainability) पर आपत्ति जताई, यह तर्क देते हुए कि दिवालियापन और दिवालापन संहिता केवल एकल कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कार्यवाही की अनुमति देती है और इसलिए कई संस्थाओं के खिलाफ संयुक्त याचिका वैध नहीं है.

यह विवाद अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा, जिसे यह तय करना था कि क्या एक ही रियल एस्टेट परियोजना में शामिल कई संस्थाओं के खिलाफ सामूहिक दिवालियापन कार्यवाही शुरू की जा सकती है.

विचारण हेतु मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कानूनी मुद्दों का परीक्षण किया—

1. क्या एक ही रियल एस्टेट परियोजना में शामिल कई कॉर्पोरेट संस्थाओं के खिलाफ संयुक्त दिवालियापन याचिका दायर की जा सकती है ?
2. क्या गृह खरीदारों को परियोजना में शामिल प्रत्येक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ अलग-अलग याचिका दायर करनी आवश्यक है ?
3. धारा 7 के तहत् गृह खरीदारों द्वारा दिवालियापन कार्यवाही शुरू करने के लिए मूल आवश्यक शर्तें (Threshold requirement) को किस प्रकार व्याख्यायित किया जाना चाहिए ?

सम्बन्धित विधिक प्रावधान

इस मामले में दिवालियापन और दिवालापन संहिता, 2016 (IBC) के प्रावधानों की व्याख्या शामिल थी, जिनमें विशेष रूप से—

- **धारा 7**—वित्तीय लेनदारों कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया की शुरुआत.
- **धारा 5(8)**—वित्तीय देनदारी की परिभाषा (जिसमें गृह खरीदारों से प्राप्त राशि शामिल है)
- सम्बन्धित NCLT प्रक्रियात्मक नियम

न्यायालय ने IBC के पीछे विधायी उद्देश्य पर भी विचार किया, विशेष रूप से यह कि यह संहिता दिवालियापन विवादों के समयबद्ध समाधान को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है.

न्यायालय का अन्तिम निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ कई कॉर्पोरेट संस्थाएँ आपस में निकटता से जुड़ी हैं और एक ही रियल एस्टेट परियोजना के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हों, संयुक्त दिवालियापन याचिका दायर की जा सकती है.

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि प्रक्रियात्मक तकनीकी बाधाएँ गृह खरीदारों को राहत प्राप्त करने से नहीं रोक सकतीं, जब परियोजना जटिल कॉर्पोरेट संरचनाओं के माध्यम से संचालित की जा रही हो.

न्यायालय का तर्क

न्यायालय ने यह माना कि आधुनिक रियल एस्टेट परियोजनाएँ प्रायः कॉर्पोरेट संरचनाओं के माध्यम से विकसित की जाती हैं, जहाँ विभिन्न कम्पनियाँ भूमि अधिग्रहण, निर्माण, विपणन और वित्तीय प्रबन्धन जैसे अलग-अलग कार्य सँभालती हैं.

यदि न्यायालय यह अनिवार्य कर दें कि गृह खरीदार प्रत्येक कॉर्पोरेट संस्था के खिलाफ अलग-अलग दिवालियापन कार्यवाही दायर करें, तो यह अनावश्यक प्रक्रियात्मक जटिलताएँ उत्पन्न करेगा और न्याय की देरी करेगा. ऐसा दृष्टिकोण IBC के उद्देश्य को भी कमजोर करेगा, जिसका मुख्य लक्ष्य दिवालियापन विवादों का कुशल और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है.

न्यायालय ने बल दिया कि लेन-देन की वास्तविकता (Substance) उसके आकार-प्रकृति (Form) पर प्राथमिक होनी चाहिए. यदि कई कॉर्पोरेट संस्थाएँ वास्तव में एक एकीकृत परियोजना का हिस्से के रूप में कार्य कर रही हैं, तो अलग-अलग कार्यवाही की आवश्यकता रखना अवास्तविक और अन्यायपूर्ण होगा.

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि गृह खरीदारों को IBC के तहत् वित्तीय लेनदार (Financial Creditors) के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसलिए उनके हितों की सुरक्षा आवश्यक है. कानूनी ढाँचा कॉर्पोरेट डेवलपर्स को केवल जटिल कॉर्पोरेट संरचनाएँ बनाने के माध्यम से जिम्मेदारी से बचने की अनुमति नहीं दे सकता.

अतः न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दिवालियापन कार्यवाहियों की व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिए कि IBC के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके और लेनदारों के अधिकार, विशेषकर गृह खरीदारों के अधिकार, जिनकी अक्सर परियोजनाओं में सबसे अधिक संवेदनशील स्थिति होती है, सुरक्षित रहें.

"फरार अभियुक्त अग्रिम जमानत नहीं ले सकता: सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया में जवाबदेही को पुनः पुष्ट किया"

मामले का नाम व सन्दर्भ—बाल मुकुंद सिंह गौतम *बनाम* राज्य मध्य प्रदेश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, फरवरी 2026 में निर्णय.

संक्षिप्त तथ्य

यह मामला मध्य प्रदेश में एक आपराधिक जाँच से उत्पन्न हुआ, जिसमें अभियुक्त बाल मुकुंद सिंह गौतम के खिलाफ गम्भीर आरोप थे. जाँच के दौरान, पुलिस ने अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास किया ताकि उससे पूछताछ की जा सके. हालाँकि, अभियुक्त ने जाँच में सहयोग नहीं किया और कथित रूप से फरार बना रहा.

अभियुक्त ने जाँच अधिकारियों के सामने समर्पण करने या अदालत में हाजिर होने के बजाय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए याचिका दायर की. उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी, यह देखते हुए कि अभियुक्त ने जाँच में सहयोग नहीं किया और गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा था.

इस निर्णय से असंतुष्ट होकर, अभियुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, यह तर्क देते हुए कि अग्रिम जमानत कानूनी अधिकार है, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त है जिसे गिरफ्तारी का भय हो और उच्च न्यायालय ने केवल इसलिए राहत देने से इन्कार किया कि अभियुक्त ने समर्पण नहीं किया.

वहीं, राज्य पक्ष ने तर्क दिया कि अग्रिम जमानत अनुशासनात्मक (Discretionary) उपाय है और इसे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जो जान-बूझकर कानूनी प्रक्रिया से बचता हो.

विचारण हेतु मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर विचार किया—

1. क्या ऐसा अभियुक्त जो फरार है या जाँच से बच रहा है, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है ?
2. क्या अभियुक्त जिसने जाँच अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया, उसे अग्रिम जमानत दी जा सकती है ?

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



UPSC NEW BOOKS PDF

2026 EDITION

अब UPSC STANDARD BOOKS 2026 की PDF सीधे टेलीग्राम पर लें सकते है
बस हमारी टेलीग्राम बॉट पर मैसेज करें

Telegram Bot - @pdfhub2026bot

सीधे मैसेज भेजने के लिए MESSAGE NOW पर क्लिक करें

Message Now

3. अग्रिम जमानत के प्रावधानों के तहत् न्यायालय को विवेकाधिकार (Discretion) का प्रयोग करते समय किन कारकों पर नवाचार करना चाहिए?

सम्बन्धित विधिक प्रावधान

न्यायालय ने अग्रिम जमानत से सम्बन्धित आपराधिक प्रक्रिया कानून के प्रावधानों का परीक्षण किया—

- **धारा 438, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—** अग्रिम जमानत देने के लिए निर्देश.
- **धारा 482, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023—**गिरफ्तारी से पूर्व जमानत (Pre-arrest bail) से सम्बन्धित प्रावधान.

न्यायालय ने अग्रिम जमानत के दायरे और उद्देश्य की व्याख्या करते हुए पूर्व के निर्णयों (Precedents) का भी सन्दर्भ लिया.

न्यायालय का अन्तिम निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा.

न्यायालय ने यह नियम दिया कि अग्रिम जमानत ऐसे अभियुक्त को नहीं दी जा सकती जो फरार है या जान-बूझकर जाँच से बच रहा है. अभियुक्त को पहले अपनी सच्ची ईमानदारी और जाँच में सहयोग करने की इच्छा प्रदर्शित करनी होगी.

न्यायालय का तर्क

सर्वोच्च न्यायालय ने यह जोर दिया कि अग्रिम जमानत एक असाधारण विवेकाधिकार (Extraordinary Discretionary Relief) है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को मनमानी गिरफ्तारी या उत्पीड़िन से बचाना है. हालाँकि, यह प्रावधान उन व्यक्तियों को बचाने के लिए नहीं है, जो जान-बूझकर कानून से बचते हैं.

न्यायालय ने यह भी देखा कि जो अभियुक्त फरार रहता है, वह कानूनी प्रक्रिया का सम्मान नहीं करता. ऐसी परिस्थितियों में अग्रिम जमानत देने से आपराधिक जाँच की प्रभावशीलता कमजोर होती है और अभियुक्तों को गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रोत्साहन मिलता है.

अभियुक्त का जाँच में सहयोग करना अग्रिम जमानत पर विचार करते समय एक महत्वपूर्ण कारक है. न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह उपाय उन लोगों द्वारा दुरुपयोग न हो जो आपराधिक कार्यवाहियों को अवरुद्ध या विलम्बित करने का प्रयास कर रहे हैं.

इसलिए, न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि अभियुक्त का जाँच अधिकारियों के सामने उपस्थित न होना अग्रिम जमानत को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त कारण था.

प्रतियोगिता दर्पण/मई/2026/92

"सार्वजनिक रोजगार में समानता : समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता"

मामले का नाम व सन्दर्भ—पवन कुमार *बनाम* भारत संघ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय.

संक्षिप्त तथ्य

यह मामला केन्द्र सरकार के तहत् कार्यरत कर्मचारियों के सेवा शर्तों और नियमितीकरण से सम्बन्धित विवाद से उत्पन्न हुआ. याचिकाकर्ता पवन कुमार एक सरकारी प्रतिष्ठान में अनुबंधित या अस्थायी पद पर लम्बे समय तक कार्यरत थे.

यद्यपि उन्होंने वही कर्तव्य निभाए जो अन्य कर्मचारियों ने किए और जिनका बाद में नियमितीकरण किया गया, उन्हें नियमित नियुक्ति और सम्बन्धित सेवा लाभों से वंचित रखा गया.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कई अन्य कर्मचारी, जो कर्तव्यों, योग्यताओं और सेवा अवधि के सन्दर्भ में समान स्थिति में थे, उन्हें नियमितीकरण प्रदान किया गया. इसके बावजूद उनके मामले को पर्याप्त न्यायसंगत कारण बताए बिना अस्वीकार कर दिया गया. याचिकाकर्ता के अनुसार, ऐसा भेदभाव मनमाना और अनुचित था.

अधिकारियों के निर्णय से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया. उच्च न्यायालय ने अनुरोधित राहत देने से इंकार किया और कहा कि नियमितीकरण कोई स्वचालित अधिकार नहीं है और सार्वजनिक रोजगार के मामलें में सरकार को विवेकाधिकार प्राप्त है.

इसके बाद याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की. यह तर्क देते हुए कि भले ही नियमितीकरण स्वचालित अधिकार न हो, राज्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पास वैध और न्यायसंगत आधार न हो.

विचारण हेतु मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कानूनी मुद्दों पर विचार किया—

1. क्या राज्य एक कर्मचारी को नियमितीकरण से वंचित कर सकता है, जबकि अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों को यह लाभ दिया गया हो ?
2. क्या ऐसा भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत् समानता की गारंटी का उल्लंघन है ?
3. क्या सार्वजनिक रोजगार में प्रशासनिक विवेकाधिकार मनमानी तरीके से प्रयोग किया जा सकता है ?

सम्बन्धित विधिक प्रावधान

इस मामले में मुख्य रूप से निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या शामिल थी—

- **अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान—**कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा.
- **अनुच्छेद 16(1), भारतीय संविधान—** सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों में समानता.

न्यायालय ने प्रशासनिक कानून और सेवा न्यायशास्त्र (Service Jurisprudence) के स्थापित सिद्धान्तों पर भी भरोसा किया, विशेष रूप से उस सिद्धान्त (Doctrine) पर कि राज्य को रोजगार के मामलों में निष्पक्ष और न्यायसंगत ढंग से कार्य करना चाहिए.

न्यायालय का अन्तिम निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया और यह माना कि समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ सेवा लाभ और नियमितीकरण के मामलों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए.

न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के मामले पर पुनर्विचार किया जाए और इसे उसी प्रकार से किया जाए जैसे अन्य कर्मचारियों को यह लाभ प्रदान किया गया था.

न्यायालय का तर्क

न्यायालय ने यह देखा कि अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता का सिद्धान्त राज्य से यह अपेक्षा करता है कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए. प्रशासनिक प्राधिकरण कर्मचारियों के बीच मनमाना भेदभाव नहीं कर सकते, जब तक कि वे तर्कसंगत और न्यायसंगत कारण प्रस्तुत न करें.

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि नियमितीकरण अनुबंधित या अस्थायी कर्मचारियों का स्वाभाविक अधिकार नहीं है, जब सरकार किसी विशेष श्रेणी में कुछ कर्मचारियों को नियमित करती है, तो उसे सभी समान श्रेणी के कर्मचारियों पर समान मानदण्ड लागू करने होंगे.

किसी भी उद्देश्यपूर्ण मापदण्ड के बिना चयनात्मक नियमितीकरण शत्रुतापूर्ण भेदभाव (Hostile Discrimination) के रूप में देखा जाएगा, जो संविधान के तहत् स्वीकार्य नहीं है.

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी जोर दिया कि सार्वजनिक प्राधिकरणों को पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर-मनमाने ढंग से कार्य करना चाहिए. सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाले निर्णय मनमाने विवेकाधिकार पर नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ विचारों पर आधारित होने चाहिए.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

"स्व-अर्जित या संयुक्त ? साक्ष्य सम्बन्धी कसौटी निर्धारित"

मामले का नाम एवं सन्दर्भ

दुरईसामी *बनाम* दोराईराज C.A. No.-002129-002130-2012, सर्वोच्च न्यायालय

संक्षिप्त तथ्य

यह विवाद एक हिन्दू परिवार के सदस्यों के बीच कुछ अचल सम्पत्तियों के वर्गीकरण को लेकर उत्पन्न हुआ. एक पक्ष (Duraisamy) ने दावा किया कि सम्बन्धित सम्पत्तियाँ उसकी स्व-अर्जित (Self-Acquired) हैं, जिन्हें उसने अपनी स्वतंत्र आय से खरीदा है, इसलिए अन्य सहभाजकों (Coparceners) में उनका बँटवारा नहीं हो सकता.

दूसरी ओर, दोराईराज ने तर्क दिया कि ये सम्पत्तियाँ संयुक्त परिवार की हैं, जिन्हें हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) की पैतृक निधि (Ancestral Nucleus) से प्राप्त धन से खरीदा गया है. यह भी कहा गया कि भले ही सम्पत्ति किसी एक व्यक्ति (सहभाजक/कर्ता) के नाम पर हो, लेकिन धन के स्रोत से उसका संयुक्त पारिवारिक स्वरूप सिद्ध होता है.

निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने सम्पत्ति की प्रकृति पर अलग-अलग निष्कर्ष दिए, विशेषकर साक्ष्य का भार (Burden of Proof) और पर्याप्त पैतृक निधि की उपलब्धता के प्रश्न पर.

अन्ततः मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा ताकि निम्नलिखित कानूनी मुद्दों को स्पष्ट किया जा सके–

- HUF सम्पत्ति के सम्बन्ध में अनुमान (Presumption).
- सम्पत्ति विवादों में साक्ष्य का भार.
- सम्पत्ति के स्वरूप निर्धारण में पैतृक निधि की भूमिका.

विचारणीय मुद्दे

- क्या सहभाजक/कर्ता के नाम पर दर्ज सम्पत्ति को स्वतः संयुक्त परिवार की सम्पत्ति माना जाएगा ?
- यह सिद्ध करने का साक्ष्य भार किस पर है कि सम्पत्ति स्व-अर्जित है या HUF की ?
- क्या केवल पैतृक निधि की उपस्थिति से संयुक्त स्वामित्व का अनुमान लगाया जा सकता है ?
- दस्तावेजी साक्ष्य *बनाम* परिस्थिति जन्य वित्तीय क्षमता–किसे कितना महत्व दिया जाए ?

सम्बन्धित विधिक प्रावधान

- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
- पारम्परिक हिन्दू विधि के अन्तर्गत HUF के सिद्धान्त.
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (धारा 101-103 और धारा 104-106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम)
- सम्पत्ति और स्वामित्व से सम्बन्धित सामान्य विधि सिद्धान्त

न्यायालय का अंतिम निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि–

- किसी सहभाजक के नाम पर दर्ज सम्पत्ति को स्वतः संयुक्त परिवार की सम्पत्ति मानने का कोई नियम नहीं है.
- परन्तु यदि यह सिद्ध हो जाए कि परिवार के पास पर्याप्त पैतृक निधि थी, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्पत्ति संयुक्त परिवार की हो सकती है.
- ऐसी स्थिति में साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर स्थानांतरित हो जाता है, जो इसे स्व-अर्जित बताता है.

न्यायालय ने पैतृक निधि के महत्व को स्वीकार करते हुए HUF विवादों में साक्ष्य के भार के स्थानांतरण (Shifting Burden of Proof) के सिद्धान्त को स्पष्ट किया.

न्यायालय का तर्क

न्यायालय ने पारम्परिक हिन्दू विधि और पूर्व निर्णयों का गहन विश्लेषण किया और बताया कि HUF सम्पत्ति की अवधारणा विशेष है, जहाँ स्वामित्व केवल दस्तावेजों से ही नहीं बल्कि धन के स्रोत और पारिवारिक संरचना से भी निर्धारित होता है.

मुख्य तर्क

(i) **स्वतः संयुक्त होने का कोई अनुमान नहीं**–केवल यह तथ्य कि परिवार संयुक्त है, यह सिद्ध नहीं करता कि उसकी सभी सम्पत्तियाँ संयुक्त हैं. प्रत्येक सम्पत्ति का अलग-अलग मूल्यांकन आवश्यक है.

(ii) **पैतृक निधि का सिद्धान्त (Doctrine of Ancestral Nucleus)**–यदि परिवार के पास ऐसी पैतृक सम्पत्ति या निधि है जो आय उत्पन्न करने में सक्षम है, और वह आय नई सम्पत्ति खरीदने के लिए पर्याप्त है, तो बाद में खरीदी गई सम्पत्तियों को संयुक्त माना जा सकता है.

(iii) **साक्ष्य के भार का स्थानांतरण**–प्रारम्भ में साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर होता है जो संयुक्त सम्पत्ति का दावा करता है. एक बार पैतृक निधि और उसकी क्षमता सिद्ध हो जाए, तो भार दूसरे पक्ष पर चला जाता है कि वह स्व-अर्जन सिद्ध करे.

(iv) **वित्तीय क्षमता का महत्व**–न्यायालय ने यह जोर दिया कि यह देखा जाना चाहिए कि सम्बन्धित व्यक्ति के पास सम्पत्ति खरीदने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय थी या नहीं, केवल दावा करना पर्याप्त नहीं है.

(v) **पूर्व निर्णयों पर निर्भरता**–न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों की पुष्टि की–

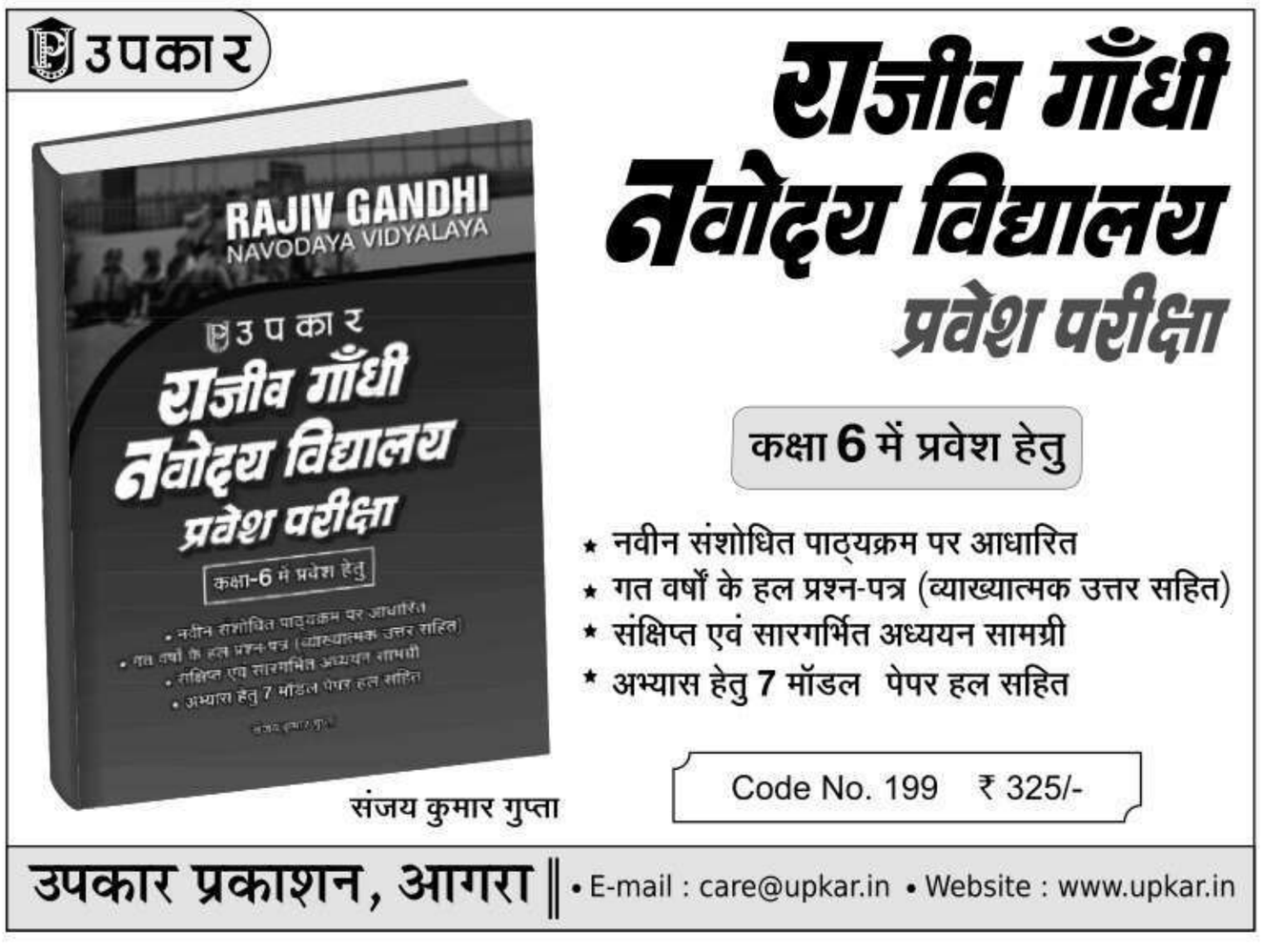
- के. वी. नारायणस्वामी अय्यर *बनाम* के. वी. रामकृष्ण अय्यर
- मल्लेसप्पा बांडेप्पा देसाई *बनाम* देसाई मल्लप्पा

इन मामलों में यह स्थापित किया गया था कि पैतृक निधि का अस्तित्व और उसकी पर्याप्तता अत्यंत महत्वपूर्ण है.

साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण

न्यायालय ने कहा कि अदालतों को दस्तावेजी साक्ष्य, आय के स्रोत और परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, केवल अनुमानों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.

●●●



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

फोकस 1

सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशें

✍ डॉ. श्याम सुन्दर सिंह चौहान

भारत में केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों को आकार देने में वित्त आयोग (एफसी) की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 की धारा (1) और वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से सोलहवें वित्त आयोग का गठन किया गया. आयोग को 1 अप्रैल, 2026 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2031 को समाप्त होने वाले 5 वर्ष की अवधि (2026-27 से 2030-31) के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.

डॉ. अरविंद पनगढ़िया, (पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग) को सोलहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और ऋत्विक रंजन पांडे को वित्त आयोग (एफसी) के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया. 30 जनवरी, 2024 की अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त किया गया—

(i) श्री अजय नारायण झा, पूर्व सदस्य, पन्द्रहवें वित्त आयोग और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पूर्व सचिव पूर्णकालिक सदस्य. अजय नारायण झा ने 8 अप्रैल, 2025 से प्रभावी अपने पद से इस्तीफा दिया. इसके बाद टी. रबी शंकर, उप-गवर्नर, आरबीआई, को 7 जून, 2025 को आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया.

(ii) श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, पूर्व विशेष सचिव, व्यय विभाग पूर्णकालिक सदस्य.

(iii) डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, अर्था ग्लोबल पूर्णकालिक सदस्य. चूँकि डॉ. निरंजन राजाध्यक्षा ने पद ग्रहण नहीं किया, अतः राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल, 2024 को डॉ. मनोज पांडा, पूर्व निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान, को आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया.

(iv) डॉ. सौम्या कांती घोष, समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय स्टेट बैंक अंशकालिक सदस्य.

सन्दर्भ की शर्तें (ToR)

सोलहवें वित्त आयोग के गठन के आदेश के अनुसार, इसको सन्दर्भित मुद्दे निम्नलिखित थे—

(i) संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण, जो संविधान के भाग XII, अध्याय I के तहत् उनके बीच बाँटी जानी है या हो सकती है और उन राज्यों के बीच उस आय के सम्बन्धित हिस्सों का आवंटन.

(ii) उन सिद्धान्तों का निर्धारण करना जो राज्यों की राजस्व सहायता के रूप में भारत के समेकित कोष से दी जाने वाली अनुदानों को नियंत्रित करेंगे और अनुच्छेद 275 के तहत् उनके राजस्व की सहायता के रूप में राज्यों को दी जाने वाली राशियाँ, उन उद्देश्यों के लिए सिवाय जो उक्त अनुच्छेद की उपधारा (1) के प्रावधानों में निर्दिष्ट नहीं हैं.

(iii) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर उन उपायों को अपनाना जो राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं ताकि राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति बढ़ाई जा सके.

सोलहवें वित्त आयोग को 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक की अवॉर्ड अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपनी थी. बाद में रिपोर्ट जमा करने की अवधि बढ़ाकर 30 नवम्बर, 2025 कर दी गई. आखिरकार, सोलहवें वित्त आयोग ने 17 नवम्बर, 2025 को भारत के राष्ट्रपति को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी. यह रिपोर्ट 1 फरवरी, 2026 को केन्द्रीय बजट 2026-27 के साथ संसद में पेश की गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में घोषणा की कि XVI FC की सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है.

सम्बन्धित लेख को इस आकर्षक वीडियो के द्वारा संक्षेप में समझें

QR कोड को स्कैन करें

2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय वित्त : एक मूल्यांकन

सोलहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीकृत प्रायोजित योजनाओं की भूमिका को स्वीकार किया, उसने महसूस किया कि संसाधनों के

सकल कर राजस्व (GTR) के ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण में रुझान

- पहले तीन आयोगों (1952-66) की पुरस्कार अवधि के दौरान सकल कर राजस्व में वित्त आयोग द्वारा संस्तुत हस्तांतरण का अनुपात काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन इसके बाद इसमें बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई.
- सातवें वित्त आयोग की शुरुआत में, यह 1978-79 में सकल कर राजस्व का 24·6 प्रतिशत से बढ़कर 1979-80 में सकल कर राजस्व का 30·7 प्रतिशत हो गया.
- चौदहवें वित्त आयोग की शुरुआत में भी इसी तरह की वृद्धि देखी गई, जो 2014-15 में सकल कर राजस्व का 32·2 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में सकल कर राजस्व का 40·6 प्रतिशत हो गया.
- विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत् 29·5 प्रतिशत से बढ़कर बारहवें वित्त आयोग के तहत् 30·5 प्रतिशत, तेरहवें वित्त आयोग के तहत् 32 प्रतिशत और चौदहवें वित्त आयोग के तहत् 42 प्रतिशत हो गया.
- 2019 में, पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से पहले, जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके इसे जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केन्द्रशासित प्रदेश (UTs) में बदल दिया गया. ध्यान दिया गया कि केन्द्रशासित प्रदेशों का हिस्सा विभाज्य पूल का लगभग 1 प्रतिशत होगा.
- सोलहवें वित्त आयोग ने ऊर्ध्वाधर वितरण पर प्रभावी ढंग से स्थिति को बनाए रखा, यानी 41 प्रतिशत.
- गैर-वित्त आयोग स्थानांतरणों सहित, राज्यों को राजस्व संसाधनों का कुल स्थानांतरण उससे भी अधिक रहा है. पहले चार वित्त आयोगों के पुरस्कार अवधि के दौरान, यह औसतन सकल कर राजस्व का 33·4 प्रतिशत था. चौदहवें वित्त आयोग और पन्द्रहवें वित्त आयोग के पुरस्कार अवधि के दौरान, औसत स्थानांतरण सकल कर राजस्व का 55·8 प्रतिशत तक पहुँच गया था.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

कुशल उपयोग के लिए उनके कार्यान्वयन को मापने योग्य, वास्तविक समय के आउटपुट संकेतकों से जोड़कर उनकी संरचना को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है. केन्द्रीय सरकार को एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त करनी चाहिए जो इन योजनाओं का नया मूल्यांकन करें और उन योजनाओं को बन्द करने की सिफारिश करें जो संसाधनों का उत्पादक ढंग से उपयोग नहीं कर रही हैं.

कर राजस्व का वितरण : ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण

केन्द्रीय सरकार से राज्यों तक संसाधनों के प्रवाह के तीन मुख्य चैनल हैं.

पहला, संविधान के अनुच्छेद 270(1) के तहत् संघ का कर राजस्व, जिसमें उप कर (CESS), अधिभार, संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) को मिलने वाले कर और संग्रहण की लागत शामिल नहीं है, को संघ और राज्यों के बीच वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर साझा किया जाता है.

दूसरा, अनुच्छेद 275(1) के तहत् वित्त आयोग राज्यों के समेकित कोष को सहयोग देने के लिए विशेष अनुदान की सिफारिश करता है.

तीसरा, अनुच्छेद 282 के तहत् संघीय सरकार राज्यों को विवेकाधीन अनुदान प्रदान करती है, मुख्य रूप से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से. यद्यपि वित्त आयोग की उनकी प्रकृति या मात्रा निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं है, चूँकि वे राज्यों के कुल राजस्व संसाधनों में योगदान करते हैं, इसलिए इसे पहले दो चैनलों के माध्यम से हस्तांतरण की सिफारिश करते समय ध्यान में रखना चाहिए.

सोलहवें वित्त आयोग ने, विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 41 प्रतिशत पर रखा.

कर राजस्व का वितरण : क्षैतिज वितरण

क्षैतिज वितरण में विभिन्न राज्यों के बीच विभाज्य पूल में राज्यों के कुल हिस्से का आवंटन शामिल है, जैसा कि ऊर्ध्वाधर वितरण प्रक्रिया में निर्धारित किया गया है, ऐतिहासिक रूप से, यह आवंटन एक ऐसी मानदंड श्रृंखला पर आधारित रहा है, जो समानता और दक्षता पर विचार करती है. प्रत्येक मानदण्ड को एक भार प्रदान किया जाता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्यों के कुल हिस्से में से कौनसा प्रतिशत उस मानदंड के अनुसार साझा किया जाएगा.

छठे वित्तीय आयोग तक, विभाजनीय कोष का 80 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा राज्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया जाता था. इसका मतलब यह था कि विभाजनीय कोष का 80 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा प्रति व्यक्ति के बराबर आवंटित किया जाता. इन आयोगों ने विभाजनीय कोष के शेष हिस्से को कर राजस्व में योगदान या ऐसे मानदंडों के आधार पर आवंटित किया जो समानता के पक्ष में अधिक झुकाव रखते थे, जैसे—प्रति व्यक्ति आय का प्रतिलोम, प्रति व्यक्ति आय का किसी मानक प्रति व्यक्ति आय से दूरी, या किसी विकास सूचकांक. सातवें वित्त आयोग से, समानता-उन्मुख मानदंडों का महत्व बढ़ गया. दसवें वित्त आयोग ने कर प्रयास और क्षेत्र को मानदंड के रूप में पेश किया. ग्यारहवें वित्त आयोग ने वित्तीय अनुशासन जोड़ा, चौदहवें वित्त आयोग ने वन (Forest) को और पन्द्रहवें वित्त आयोग ने कुल प्रजनन दर (TFR) के प्रतिलोम को जोड़ा.

राज्यों के बीच आपसी हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए, सोलहवें वित्त आयोग ने मानदंड के रूप में जनसंख्या (2011 जनगणना : 17·5%), जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (10%), क्षेत्रफल (10%), वन क्षेत्र (10%), प्रति व्यक्ति आय अंतराल (42·5%) और राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान (10%) का उपयोग किया. क्षैतिज हस्तांतरण के लिए सूत्र और विभिन्न मानदंडों को आवंटित किए गए भार तालिका-1 में दिए गए हैं. सोलहवें वित्त आयोग की पारस्परिक अवधि के लिए राज्यों के क्षैतिज हस्तांतरण में हिस्सेदारी तालिका-2 में दी गई है.

तालिका-1 : क्षैतिज हस्तांतरण का सूत्र

मानदंड	निर्दिष्ट भार (प्रतिशत में)
जनसंख्या (2011)	17·5
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन	10
क्षेत्रफल	10
वन आवरण	10
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अंतराल	42·5
सकल घरेलू उत्पाद में योगदान	10
कुल	**100**

तालिका-2 : राज्यों का पारस्परिक हिस्सा

राज्य	हिस्सा (प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश	4·217
अरुणाचल प्रदेश	1·354
असम	3·258
बिहार	9·948
छत्तीसगढ़	3·304
गोवा	0·365
गुजरात	3·755
हरियाणा	1·361
हिमाचल प्रदेश	0·914
झारखण्ड	3·357
कर्नाटक	4·131
केरल	2·382
मध्य प्रदेश	7·347
महाराष्ट्र	6·441
मणिपुर	0·626
मेघालय	0·631
मिजोरम	0·564
नगालैण्ड	0·481
ओडिशा	4·420
पंजाब	1·996
राजस्थान	5·926
सिक्किम	0·335
तमिलनाडु	4·097
तेलंगाना	2·174
त्रिपुरा	0·641
उत्तर प्रदेश	17·619
उत्तराखण्ड	1·141
पश्चिम बंगाल	7·215
कुल	**100**

राज्यों और अनुदानों का आकलन

सोलहवें वित्त आयोग को राज्यों की वित्तीय स्थिति के आकलन में पता चला कि राज्यों के राजस्व घाटे का कारण प्रतिबद्ध व्यय और विवेकाधीन व्यय में निहित था और राजस्व बढ़ाने और व्यय को तर्कसंगत बनाने की पर्याप्त सम्भावना थी. राज्यों द्वारा राजस्व घाटे के अनुदानों की अपेक्षा करने से कठिन लेकिन आवश्यक वित्तीय सुधार करने की प्रेरणा कमजोर हो जाती है, जैसे कि सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, कर प्रशासन में सुधार करना या राजस्व व्यय को कम करना. पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए राजस्व घाटे के अनुदानों की घटती प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, जो 2025-26 तक लगभग शून्य स्तर तक घट जाएगी, सोलहवें वित्त आयोग ने राज्यों को राजस्व घाटे को पाटने के लिए किसी भी प्रकार के अनुदान की सिफारिश नहीं की. सोलहवें वित्त आयोग ने किसी भी क्षेत्र-विशेष या राज्य-विशेष अनुदान की भी सिफारिश नहीं की.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

स्थानीय निकाय अनुदान

- सोलहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि राज्यों को नागरिक-मैत्रीपूर्ण जीआईएस आधारित सम्पत्ति कर आईटी प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि सम्पत्ति कर की प्रभावी गणना, मूल्यांकन और संग्रहण सुनिश्चित हो सके.
- राज्यों को सभी स्थानीय निकायों को होने वाले हस्तांतरण, जिनमें वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत के समेकित कोष से होने वाले हस्तांतरण, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत हस्तांतरण, राज्य वित्त आयोग के अनुदान और राज्य सरकार के अन्य अनुदान शामिल हैं, अपने बजट में पारदर्शी रूप से दर्शाए जाने चाहिए और इसे शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) और ग्रामीण स्थानीय निकाय (RLBs) के लिए अलग-अलग दिखाना चाहिए.
- अनुच्छेद 280(3)(bb) और 280(3)(c) में, संविधान वित्त आयोग को ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) पर अपनी सिफारिशें 'राज्यों के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर' करने का निर्देश देता है. सोलहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि सम्बन्धित अनुच्छेदों से यह उद्धृत शब्द हटा दिए जाएँ, जिसके लिए संवैधानिक संशोधन किया जाना चाहिए.
- सोलहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए अनुदान को बुनियादी और निष्पादन घटकों में वर्गीकृत किया जाए और शहरी स्थानीय निकाय के लिए अनुदान को बुनियादी, निष्पादन, शहरी अवसंरचना और शहरीकरण प्रीमियम घटकों में वर्गीकृत किया जाए. बुनियादी और निष्पादन घटकों के लिए कुल राष्ट्रीय अनुदान आवंटन, जिसे एक साथ रखा गया है, ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकाय के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया गया है. ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकाय दोनों के लिए बुनियादी और निष्पादन घटकों के बीच विभाजन 80:20 के अनुपात में सुझाया गया है.
- सोलहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि के लिए (2026-27 से 2030-31 तक), विधिवत गठित ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकाय के लिए कुल ₹ 7,91,493 करोड़ के अनुदान का आवंटन संस्तुत किया गया है.
- ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए, राज्य के भीतर वितरण 2026 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या और क्षेत्र के 90:10 अनुपात पर आधारित है. शहरी स्थानीय निकाय के लिए, राज्यों का हिस्सा 2026 के अनुमानित शहरी जनसंख्या और शहरी स्थानीय निकाय के अपने राजस्व स्रोत (OSR) के 90:10 अनुपात से निर्धारित किया गया है.
- प्रत्येक राज्य के भीतर, सभी स्तरों के उचित रूप से गठित ग्रामीण स्थानीय निकाय और उचित रूप से गठित शहरी स्थानीय निकाय को अनुदानों का वितरण सम्बन्धित राज्य वित्त आयोगों (SFCs) की नवीनतम स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार किया जा सकता है. यदि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें उपलब्ध नहीं हैं, तो ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए स्तरवार वितरण निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप हो सकता है. ग्रामीण स्थानीय निकाय के एक स्तर के भीतर, वितरण नवीनतम स्वीकृत राज्य वित्त आयोग सिफारिशों के अनुसार किया जा सकता है या राज्य वित्त आयोग सिफारिशों की अनुपस्थिति में, जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर 90:10 के अनुपात में किया जा सकता है. शहरी स्थानीय निकाय के लिए, वितरण नवीनतम स्वीकृत राज्य वित्त आयोग सिफारिशों के अनुसार किया जा सकता है या राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की अनुपस्थिति में, शहरी जनसंख्या और शहरी स्थानीय निकाय के अपने राजस्व स्रोत के आधार पर 90:10 के अनुपात में किया जा सकता है.
- सम्बन्धित राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुक्त क्षेत्रों के लिए आवंटन करना चाहिए.
- स्थानीय निकाय अनुदान का दावा करने के लिए पार्ट IX और पार्ट IXA के अनुसार उचित रूप से गठित निकाय मौजूद होना चाहिए. यह प्रवेश स्तर की पहली शर्त होगी.
- किसी राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त वर्ष T-2 के ऑडिटेड खाता और वित्त वर्ष T-1 के अस्थायी खातों की वर्ष T में सार्वजनिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्धता स्थानीय निकाय अनुदान प्राप्त करने की प्रवेश स्तर की दूसरी शर्त होगी.
- सभी राज्यों को संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है, जो नियमित रूप से राज्य वित्त आयोग के गठन से सम्बन्धित हैं, जैसा कि संवैधानिक प्रावधान में उल्लिखित है, अर्थात् पिछले राज्य वित्त आयोग के गठन की समाप्ति के 5 वर्षों के बाद और यह सुनिश्चित करना कि राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 6 माह के भीतर ATRs (अनुसंशोधित रिपोर्ट) राज्य विधानमण्डल में रखी जाए, ताकि वे अपने स्थानीय निकाय अनुदान का दावा कर सकें. यह पहले वर्ष से, यानी 2026-27 से, स्थानीय निकाय अनुदान का दावा करने के लिए प्रवेश स्तर का तीसरी शर्त होगा.
- शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान को मूल (80 प्रतिशत) और निष्पादन (20 प्रतिशत) घटकों में विभाजित किया गया है, जिसमें निष्पादन घटक को दो समान भागों में बाँटा गया है—ग्रामीण स्थानीय निकाय/शहरी स्थानीय निकाय निष्पादन घटक और राज्य निष्पादन घटक-मूल घटक राज्यों को प्रवेश स्तर की (अर्हता) तीन शर्तों को पूरा करने पर प्राप्त होगा.
- ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष T में ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान के ग्रामीण स्थानीय निकाय निष्पादन घटक को प्राप्त करने हेतु, सोलहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि ग्राम पंचायतें वर्ष T-1 में वर्ष T-2 के अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों (OSR) का न्यूनतम 1·025 गुना या 2025-26 के अपने राजस्व स्रोत पर प्रति वर्ष 2·5 प्रतिशत यौगिक वृद्धि प्राप्त करें, जिसमें जो भी कम हो उसे लागू किया जाए, न्यूनतम ₹ 1200 प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि के अधीन. यह अनुशंसा अवधि के तीसरे वर्ष से लागू होगा, यानी 2028-29 से.
- ब्लॉक पंचायतों के लिए, सोलहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि वे ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान के ग्रामीण स्थानीय निकाय प्रदर्शन घटक के लिए तभी पात्र होंगे, जब उनके अधिकार क्षेत्र की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतें इसके लिए योग्य हों.
- जिला पंचायतों के लिए, सोलहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि वर्ष T में अनुदान के लिए पात्र होने हेतु, जिला पंचायतें वर्ष T-1 में वर्ष T-2 के अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों (OSR) का न्यूनतम 1·025 गुना या 2025-26 के अपने राजस्व स्रोत पर प्रति वर्ष 2·5 प्रतिशत यौगिक वृद्धि प्राप्त करें,

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

जिसमें जो भी कम हो उसे लागू किया जाए. इनमें से दोनों तीसरे वर्ष से लागू होंगे, यानी 2028-29 से उपलब्ध कराया जा सकता है.

- किसी शहरी स्थानीय निकाय को वर्ष T में शहरी स्थानीय निकाय निष्पादन घटक अनुदान के लिए योग्य होने के लिए, सोलहवें वित्त आयोग ने वर्ष T-1 में इसे वर्ष T-2 में इसके अपने राजस्व स्रोत के न्यूनतम 1·05 गुना या 2025-26 के अपने राजस्व स्रोत पर लागू वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर 5 प्रतिशत में से जो भी कम हो, बढ़ाने की सिफारिश की. यह पुरस्कार अवधि के दूसरे वर्ष, यानी 2027-28 से लागू होगा.
- सोलहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि वर्ष T में ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकाय अनुदानों के राज्य प्रदर्शन घटकों की रिलीज इस शर्त पर निर्भर हो कि राज्य वर्ष T-1 में अपने स्वयं के संसाधनों से स्थानीय निकायों को हमारे द्वारा वर्ष T-1 के लिए सिफारिश किए गए मूल वित्त आयोग अनुदान का 20 प्रतिशत या उससे अधिक राशि हस्तांतरित करे और यह दूसरी वर्ष से लागू होगा.
- मूल घटक का 50 प्रतिशत कतिपय कार्यों से सम्बद्ध होना चाहिए और मूल घटक का शेष 50 प्रतिशत तथा पूरे निष्पादन घटक मुक्त रहने चाहिए.
- सम्बन्धित घटक को 'सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' और/या 'जल प्रबंधन' की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए.
- सोलहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि किसी भी स्थानीय निकाय को सड़क निर्माण और रखरखाव पर अनबद्ध आवंटन का 20 प्रतिशत से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए.
- ग्रामीण से शहरी बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए शहरीकरण प्रीमियम की कुल राशि पूरी अनुशंसा अवधि के लिए ₹10,000 करोड़ होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति एक बार की पात्रता राशि ₹ 2,000 होगी (2011 की जनगणना की आबादी के आधार पर). शहरीकरण प्रीमियम घटक की रिलीज की माँग राज्य द्वारा तब ही की जा सकती है जब उपनगरीय गाँवों को आसन्न बड़े शहरी स्थानीय निकाय (ULB) में मिला दिया जाए, जिसकी मौजूदा जनसंख्या कम-से-कम 1 लाख हो और एक उपयुक्त ग्रामीण से शहरी बदलाव नीति का निर्माण किया गया हो.
- चयनित शहरी स्थानीय निकाय के लिए विशेष बुनियादी ढाँचा घटक, जिसका बजट ₹ 56,100 करोड़ है, शहरी विकास केन्द्रों में व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन में निर्णायक हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करने के लिए आवंटित किया गया है.

राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान उनकी सम्बन्धित स्थानीय निकायों को 10 कार्य दिवसों के भीतर हस्तांतरित किए जाएँ. इस हस्तांतरण में निर्दिष्ट 10 कार्यदिवसों से अधिक किसी भी देरी की स्थिति में, राज्य सरकारों को पिछले वित्तीय वर्ष के बाजार उधार/राज्य विकास ऋण पर लागू प्रभावी ब्याज दर के अनुसार ब्याज के साथ फंड जारी करना अनिवार्य होगा.

आपदा प्रबंधन का वित्तपोषण

- राज्यों के लिए आपदा प्रबंधन कोष का आवंटन पिछले खर्च और आपदा जोखिम सूचकांक (जोखिम, संवेदनशीलता और जोखिम की सम्भावना) के आधार पर किया जाता है. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और राज्य आपदा शमन कोष के लिए 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए कुल ₹ 2,04,401 करोड़ के कोष की सिफारिश की गई है.
- इस कोष को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) के बीच 80:20 के अनुपात में विभक्त किया जाना चाहिए. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का आवंटन ₹ 1,63,521 करोड़ है और राज्य आपदा शमन कोष का ₹ 40,880 करोड़ है. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अन्तर्गत प्रतिक्रिया और राहत तथा पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के बीच पुनर्वितरण का लचीलापन होना चाहिए. आपदाओं से निपटने की तैयारियाँ और क्षमता निर्माण अब राज्य आपदा शमन कोष और राष्ट्री आपदा शमन कोष (NDMF) के अन्तर्गत आएंगे. संचित निधि को अस्थायी रूप से रोक दिया जा सकता है. यदि राज्यों का शेष कोष पिछले 3 वर्षों के वार्षिक आवंटन की सीमा से नीचे चला जाता है, तो रोक ली गई निधि जारी कर दी जाएगी.
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत् संचयी शेष राशि को इस सीमा तक सीमित रखा जाना चाहिए कि यदि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत् अव्ययित शेष राशि पिछले 3 वर्षों के वार्षिक आवंटन के योग से अधिक हो जाए, तो आगे के रिलीज को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है. अगर राज्यों का शेष राशि पिछले 3 वर्षों के वार्षिक आवंटन की सीमा से नीचे आ जाती है, तो रोकी गई धनराशि जारी कर दी जाएगी.
- राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए पिछले खर्चों के आधार पर कुल ₹ 79,406 करोड़ आवंटन की सिफारिश की गई है (एनडीआरएफ और एनडीएमएफ के लिए).
- राज्यों को एसडीआरएफ और एसडी एमएफ के फंड का 25 प्रतिशत योगदान देना होगा, सिवाय उत्तर-पूर्व और पर्वतीय (NEH) राज्यों के, जो 10 प्रतिशत योगदान देंगे और बाकी राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी. केन्द्र सरकार का कुल हिस्सा ₹ 1,55,915·85 करोड़ होता है.
- एनडीआरएफ (रिस्पांस और राहत को छोड़कर) और एनडीएमएफ के माध्यम से केन्द्रीय सहायता का क्रमिक लागत साझा करना बनाए रखना चाहिए. राज्यों को ₹ 250 करोड़ तक की सहायता के लिए 10 प्रतिशत, ₹ 500 करोड़ तक की सहायता के लिए 20 प्रतिशत और ₹ 500 करोड़ से अधिक की सभी सहायता के लिए 25 प्रतिशत योगदान देना होगा. हालाँकि, NEH राज्यों को एनडीआरएफ और एनडीएमएफ के तहत् सभी केन्द्रीय सहायता में 10 प्रतिशत योगदान देना चाहिए.
- हीटवेव (लू) और बिजली गिरना को राष्ट्रीय स्तर पर सूचित आपदाओं की सूची में जोड़ा जाना चाहिए.

बृहत् और राजकोषीय स्थिरता की ओर मार्ग

- राज्यों के राजकोषीय घाटे को उनके सम्बन्धित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3 प्रतिशत पर सीमित रखा जाए. राज्य सरकार के ऋण की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, इस सीमा को संविधान के अनुच्छेद 293 की उपधारा (3) के अनुसार सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.
- यह माना जाता है कि पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) के तहत् संघ सरकार द्वारा वित्तीय सहायता इसकी सीमा से ऊपर होगी, जैसा कि वर्तमान में प्रचलन में है.
- संघ सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को अनुशंसा अवधि के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3·5 प्रतिशत तक कम कर देना चाहिए.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

- राज्यों को बजटीय से इतर स्रोतों से ऋण लेने की प्रथा को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और सभी ऐसे ऋणों को अपने बजट में शामिल करना चाहिए. यदि किसी कारणवश बजटीय बाहर के ऋण लिए जाते हैं, तो नियमित वार्षिक रिपोर्टिंग के लिए एक ढाँचा होना चाहिए, जो प्राथमिकता के आधार पर बजट का हिस्सा हो.
- एक ऐसा ढाँचा तैयार किया जाना चाहिए जिसके तहत् ऋण देने वाले संस्थान समय-समय पर उस ऋण की जानकारी रिपोर्ट करें जो राज्य-स्वामित्व वाली संस्थाओं को दिया गया है, जहाँ सरकार ने ऋण सेवा के लिए सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता ली है.
- सरकारें आवश्यक कदम उठाएँ ताकि FRL को हमारे द्वारा सुझाए गए वित्तीय समेकन रोडमैप के अनुरूप संशोधित किया जा सके. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (FRBM) अधिनियमों के तहत् सरकारों को यह रिपोर्ट करने की बाध्यता हो कि यदि विधायी ढाँचे के तहत् निर्धारित घाटा या ऋण सीमा का उल्लंघन होता है.
- वित्तीय घाटा और ऋण की परिभाषा को समान रूप से सभी बजट बाहरी उधारों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए.
- संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत् यह तंत्र यह अनिवार्य करता है कि राज्यों को अपने सम्मिलित कोषों की सुरक्षा के खिलाफ उधार लेने से पहले संघ की सहमति प्राप्त करनी होगी, जब तक कि उनके पास संघ सरकार से कोई बकाया ऋण है. यह तंत्र प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए अत्यंत उपयोगी रहा है. सोलहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि यह संवैधानिक प्रावधान जारी रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों के उधार लेने की गतिविधियाँ सुझाए गए वित्तीय रोडमैप के अनुरूप हों.
- सार्वजनिक खाता से वित्तीय घाटे की वित्तपोषण की सटीकता का अनुमान लगाने के लिए तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि वित्तीय घाटे की सीमा को प्रभावी ढँग से लागू किया जा सके.
- वार्षिक उधारी सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, सोलहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि वास्तविक जीएसडीपी डेटा उपलब्ध नवीनतम 3 वर्षों के दौरान देखी गई वास्तविक जीएसडीपी की वार्षिक औसत वृद्धि दर को लागू करके जीएसडीपी का अनुमान लगाने का अभ्यास जारी रखा जाना चाहिए.
- राज्यों को अपनी विशिष्ट वर्षों में पुनर्भुगतान दबाव को प्रबंधित करने के लिए स्विच नीलामी और बायबैक जैसी रणनीतियों को अपनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए.

विद्युत् क्षेत्र में सुधार

- राज्यों को डिस्कोम (DISCOMs) के निजीकरण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए.
- जैसे कि DISCOMs का निजीकरण ऋण और बचाव योजना के पुनरावर्ती चक्रों का अधिक निश्चित और स्थायी समाधान प्रदान करता है, यदि सार्वजनिक स्वामित्व ढाँचे के भीतर समाधान खोजा जाता है, तो राज्यों को गुजरात और हरियाणा की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना चाहिए जो अनुकरण करने योग्य हैं.

सब्सिडी को नियंत्रित करना और उसे प्रभावी बनाना

- सोलहवें वित्त आयोग ने यह स्वीकार किया है कि कई राज्यों में राजस्व संतुलन ऋणात्मक हो गया है, जबकि उनमें से कई बड़े पैमाने पर स्थानांतरण योजनाओं को भी एक साथ लागू कर रहे थे. सब्सिडी और स्थानांतरण योजनाओं पर खर्च के लिए उधार लेना वित्तीय दृष्टि से सही नीति नहीं है.
- सोलहवें वित्त आयोग ने राज्यों से यह सिफारिश की कि वे अपनी सब्सिडी योजनाओं की समीक्षा और सुव्यवस्था करें और केवल उन योजनाओं को बनाए रखें जो गरीबों को प्रभावी रूप से लक्षित करती हैं.
- सोलहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि सरकारें लाभार्थी आधार को सुव्यवस्थित करने के लिए तुरन्त कदम उठाएँ, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित बहिष्करण मानदंड और कड़ा समीक्षा प्रक्रिया शामिल हो, ताकि लाभ सबसे कमजोर लोगों तक पहुँच सके.
- राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजनाओं और लाभार्थी आधार के तर्कसंगत पुनर्विन्यास के माध्यम से राजस्व घाटे को कम किया जाए और अंततः उसे समाप्त किया जा सके.
- सोलहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि सरकारें सब्सिडी और अंतरणों की समीक्षा करने के लिए तंत्र स्थापित करें और उनके कार्यान्वयन तंत्र में समाप्ति या निकासी क्लॉज शामिल करें. बजट के बाहर उधारी, गारंटी या राजस्व के असाइनमेंट के माध्यम से सब्सिडी और अंतरणों के वित्तपोषण की ओर रुझान रखना वित्तीय रूप से अनुचित है और उनके लेखांकन में अस्पष्टता लाता है. सब्सिडी के वित्तपोषण के लिए बजट के बाहर उधारी की ऐसी प्रथाओं को बंद किया जाना चाहिए और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं.

सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सुधार

- निष्क्रिय सार्वजनिक उद्यमों पर संघ और राज्य सरकारों पर वित्तीय दबाव कम करने के लिए तत्काल बंद करने पर विचार किया जाना चाहिए. निष्क्रिय सार्वजनिक उद्यमों की भूमि और इमारतें महत्वपूर्ण सम्पत्तियाँ हैं जिन्हें वैकल्पिक उत्पादक उपयोग में लगाया जा सकता है.
- संघ सरकार और राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभाग को अनिवार्य रूप से किसी भी सार्वजनिक उद्यम को, जो लगातार 4 वर्षों में से 3 वर्षों में नुकसान में है, बंद करने, निजीकरण करने या चलाए रखने के लिए कैबिनेट के समक्ष विचार हेतु लाना चाहिए. इसके बाद कैबिनेट उद्यम की रणनीतिक महत्वता के आधार पर उचित कार्रवाई का निर्णय ले सकती है.

सोलहवें वित्त आयोग को अपना कार्य ऐसे समय में करना पड़ा है, जब केन्द्र और राज्य सरकारें विशेष रूप से गैर-एनडीए शासित–अनेक वित्तीय, राजकोषीय और गैर-राजकोषीय मुद्दों पर आमने-सामने हैं जैसे कि राज्यपालों की भूमिका, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन (SIR), कुल कर राजस्व में राज्य के योगदान के सन्दर्भ में कर राजस्व का असमान वितरण आदि. इन कारकों ने देश की संघीय संरचना पर दबाव डाला है.

इन परिस्थितियों में, वित्त आयोग को यह कठिन कार्य सौंपा गया था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कर राजस्व का वितरण केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में और अधिक तनाव पैदा न करे. सोलहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसने संतुलन बनाए रखने का एक संतुलित कार्य किया है. सोलहवें वित्त आयोग ने उस सूत्र की पुनः समीक्षा की है जिसके

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

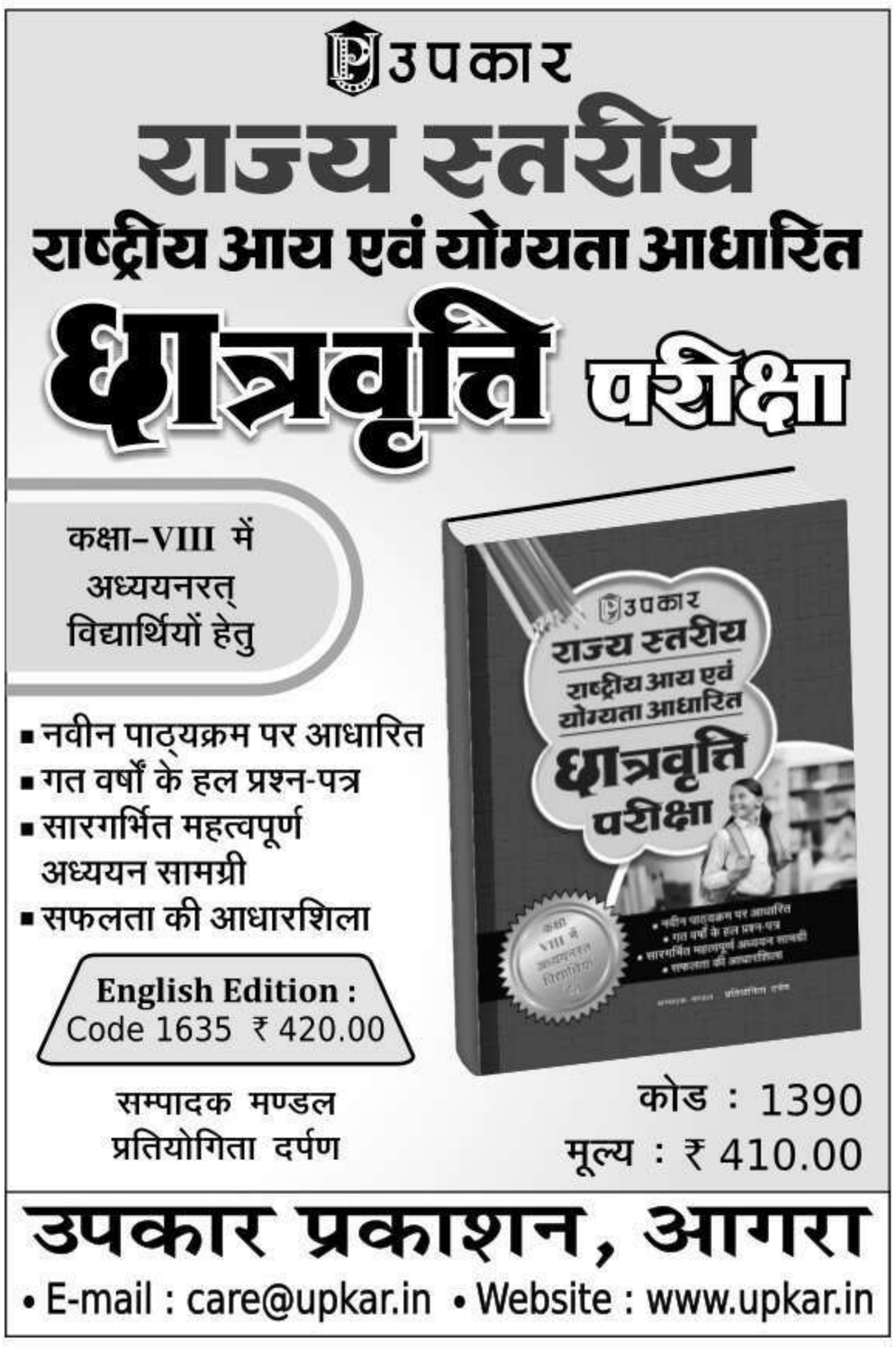
द्वारा विभाज्य पूल के अन्तर्गत करों की गणना की जाती है और इसमें 'सकल घरेलू उत्पाद में योगदान' को एक कारक के रूप में शामिल किया है. इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि कुछ दक्षिणी राज्यों, विशेष रूप से विपक्ष शासित राज्य–तमिलनाडु और कर्नाटक, साथ ही पश्चिमी तट के अधिक विकसित राज्यों, जैसे– गुजरात का हिस्सा वास्तव में बढ़ गया है.

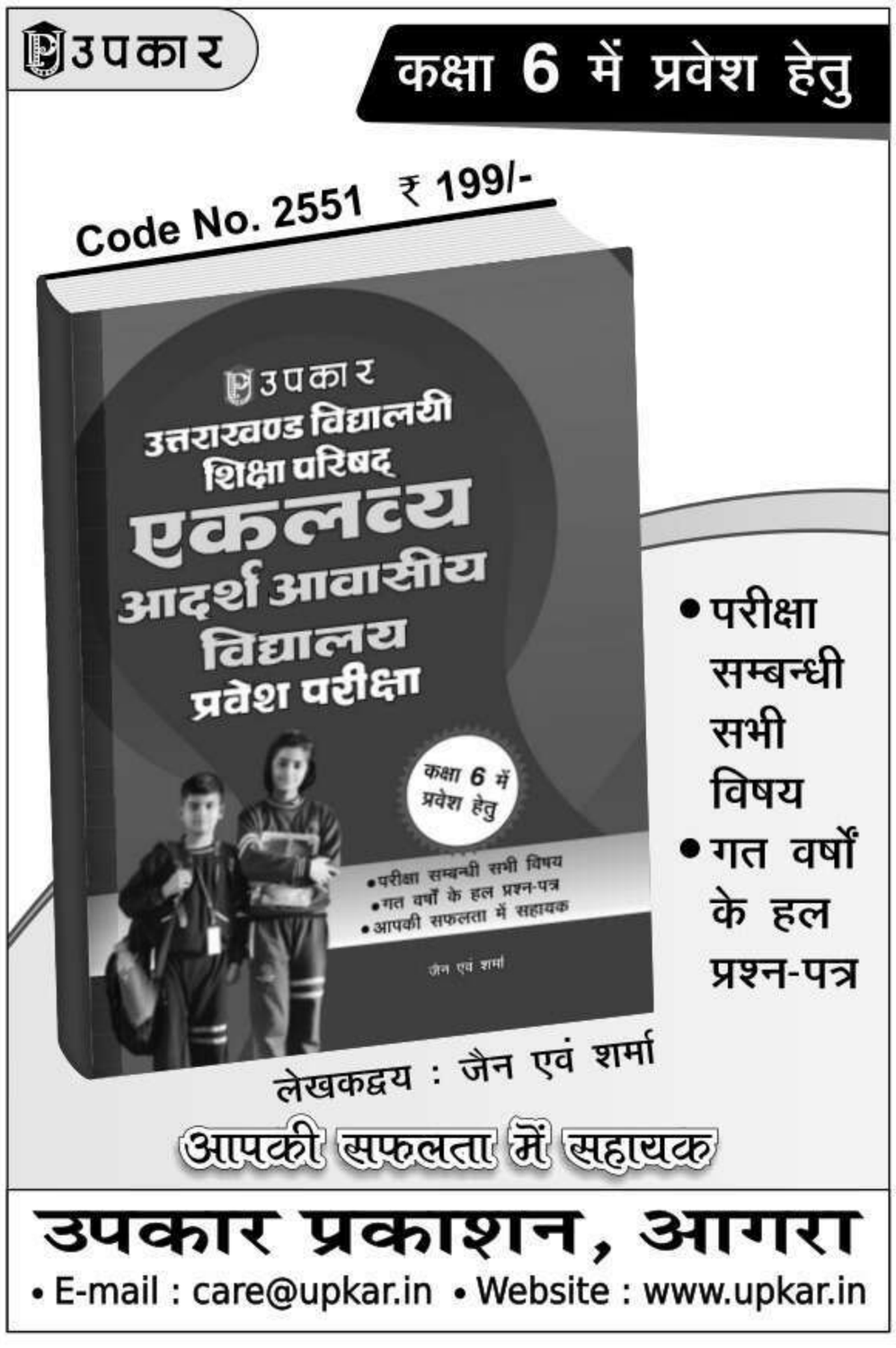
राज्य सरकारों ने लम्बे समय से तर्क दिया है कि नीति प्रयोग और स्वायत्तता के लिए उनका स्थान सिकुड़ता जा रहा है. जीएसटी-1 और जीएसटी-2 सुधार सही दिशा में कदम थे, लेकिन इन्होंने निःसंदेह राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को घटा दिया. राज्य अक्सर शिकायत करते रहे कि जिन राजस्वों तक उन्हें पहुँच थी, उसका एक बड़ा और बड़ा हिस्सा ऐसी योजनाओं के वित्तपोषण और कार्यान्वयन में इस्तेमाल हो जाता था, जो संघीय सरकार द्वारा विकसित और चुनी गई थीं और जिनके लिए स्थानीय राजनेताओं को कोई राजनीतिक क्रेडिट नहीं मिलता था, लेकिन उसी समय, अधिकांश राज्यों की सत्तारूढ़ सरकारें हस्तांतरण भुगतानों (तथाकथित रेवड़ियाँ वितरण) पर भारी निर्भर रही हैं, जिससे उनकी विकास गतिविधियों के लिए इच्छित संसाधनों का आवंटन करने की क्षमता कम हो गई है.

सोलहवें वित्त आयोग ने राज्यों के भाग को विभाज्य कर 41 प्रतिशत पर बनाए रखा है, यह वही अनुपात है जिसे पन्द्रहवें वित्त आयोग ने संस्तुत किया था, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि यह भाग जितना होना चाहिए उससे छोटा है, क्योंकि केन्द्र सरकार विभिन्न उपकर/अधिभार का सहारा लेने की विधि को विगत कई वर्षों से अपना रही है, जो कर के रूप में गिने जाते हैं, लेकिन जिन्हें विभाज्यनीय पूल में शामिल नहीं किया जाता, वास्तविकता यह है कि उपकरों/अधिभारों से प्राप्त कर राजस्व केन्द्र की प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा है. इतना ही नहीं करारोपण की अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र सरकार के पास हैं अर्थात् जिस किसी कर का उल्लेख सातवीं अनुसूची के संघीय सूची, राज्य सूची और अनुवर्ती सूची में उसे लगाने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार के पास है. पूरी सम्भावना है कि सोलहवीं वित्त आयोग की सिफारिशें राज्यों की अधिक हिस्से की माँगों को समाप्त न करें, लेकिन यह अन्याय के आरोपों को पहले ही रोक सकती हैं.

राज्यों की सीमित संचालन क्षमता शायद इसके कारणों में से एक हो सकती है कि उनका कर्ज फिर से एक व्यापक स्तर पर चिन्ता का विषय बनने लगा है. सोलहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारों द्वारा बजट से बाहर उधारी को रोक दिया जाना चाहिए. राज्य वित्तीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के लगभग 3 प्रतिशत के स्तर पर नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण सुधार था और इसके इर्द-गिर्द कोई शॉर्टकट अपनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. बजट से बाहर की उधारी अधिक जटिलताएँ उत्पन्न करती है. एक तो, इससे कई सरकारों की देनदारियों के बारे में पारदर्शिता में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है.

राज्यों के लिए ही, भारी कर्ज का भुगतान करना एक प्रमुख कारण हो सकता है कि वे नए खर्च वाली नीतियाँ लागू करने में असमर्थ महसूस करते हैं. सोलहवें वित्त आयोग ने राजस्व-घाटे अनुदान को बन्द करने की सिफारिश करके भी अच्छा काम किया है, जो वित्तीय अनुशासन को सुधारने में मदद करेगा. सोलहवें वित्त आयोग की सराहना की जानी चाहिए कि उसने राजनीतिक धारा के खिलाफ जाकर सुनिश्चित किया कि अधिक उत्पादक राज्यों के पास संसाधन होंगे और वित्तीय ईमानदारी और विकास-उत्साहजनक नीतियों के लिए प्रोत्साहन बहाल होंगे.●●●





PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

फोकस 2

भारत के सेवा निर्यात : सम्भावनाएँ और चुनौतियाँ

डॉ. बी. के. अग्रवाल

वैश्विक व्यापार में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर भारत का लगातार बढ़ता कद, वैश्विक माल निर्यात और कमर्शियल सेवाओं के निर्यात, दोनों में उसकी बढ़ती हिस्सेदारी से स्पष्ट होता है. वर्ष 2005 और वर्ष 2024 के बीच, वैश्विक माल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई है, जो वर्ष 2005 में 1 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 1·8 प्रतिशत हो गई है; इसी तरह, वैश्विक कमर्शियल सेवाओं के निर्यात में उसकी हिस्सेदारी दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है, जो वर्ष 2005 में 2 प्रतिशत से दोगुना से भी अधिक बढ़कर 2024 में 4·3 प्रतिशत हो गई है. वित्त वर्ष 2026 में, भारत के 'सकल मूल्य संवर्धन' (GVA) में सेवा क्षेत्र का हिस्सा स्थिर कीमतों (2022-23) पर 52·64 प्रतिशत तथा प्रचलित कीमतों पर 54·35 प्रतिशत है. देश में सेवा क्षेत्र निर्यात और रोजगार महत्वपूर्ण तरीके से योगदान देता है. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात (वस्तु निर्यात एवं सेवा निर्यात) 824·9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थे जिसमें से सेवा निर्यात 387·5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थे यह न सिर्फ घरेलू विकास को लगातार मजबूती देता है, बल्कि सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का सबसे स्थिर और मजबूत हिस्सा भी बनकर उभरा है; यह एक ऐसे आधार के तौर पर काम करता है जिसमें विकास की दर ऊँची होती है और उतार-चढ़ाव कम होता है जैसा कि पूरे विश्व में देखा जाता है. इस क्षेत्र ने साल-दर-साल औसतन लगभग 7-8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जो कृषि और उद्योग क्षेत्रों में देखे जाने वाले ज्यादा बड़े चक्रीय उतार-चढ़ावों के बिल्कुल विपरीत है. भारत विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है. यह क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रवाह को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है.

भले ही सेवा क्षेत्र विकास का मुख्य आधार बना हुआ है, लेकिन तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति, जिसने सेवा क्षेत्र को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने में मदद की थी, अब कम्पनियों और कर्मचारियों के अनुकूलन की गति से आगे निकल रही है, जिससे कौशल में अन्तर और व्यवधान पैदा हो रहे हैं. इसके साथ ही, सख्त आव्रजन नियम, डेटा सुरक्षा/स्थानीयकरण के मानक और प्रेषण (Remittance) सम्बन्धी नियमों के कारण, 'स्थिरता लाने वाली शक्ति' बनने का इसका वादा अब चुनौतियों का सामना कर रहा है.

भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक बनकर उभरा है, जो विकास, उत्पादकता और वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा देने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. विश्व बैंक के अनुसार, 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 49·9% हो गई, जो महामारी से पहले के औसत से लगभग 1·5 प्रतिशत अंक अधिक है; यह वृद्धि वैश्विक औसत और अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक है. इस विस्तार को डिजिटल तकनीक को तेजी से अपनाने और भारतीय फर्मों के वैश्विक मूल्य शृंखला में और अधिक गहराई से जुड़ने के कारण हुई उत्पादकता में सुधार से बल मिला है.

सेवा व्यापार

भारत का सेवा व्यापार देश के समग्र व्यापार निष्पादन को बेहतर बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है. वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बावजूद इस क्षेत्र ने मजबूती दिखाई है, जिसका प्रमाण इसके निर्यात में लगातार हो रही वृद्धि है.

वित्त वर्ष 2025 में, सेवाओं का निर्यात अब तक के सबसे ऊँचे स्तर 387·5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया, जिसमें 13·6 प्रतिशत (YoY) की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई. इससे टेक्नोलॉजी, बिजनेस और प्रोफेशनल सेवाओं के लिए एक वैश्विक केन्द्र के तौर पर भारत की स्थिति और मजबूत हुई है. इसी अवधि में सेवाओं के आयात में 11·4 प्रतिशत (YoY) की वृद्धि दर्ज की गई और यह 198·7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया. आयात में यह वृद्धि बिजनेस और वित्तीय सेवाओं के लिए बढ़ती सीमा-पार माँग का संकेत है. इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के व्यापार अधिशेष में वृद्धि हुई और यह 188·8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है. वास्तविकता तो ये रही कि सेवाओं के व्यापार अधिशेष ने माल व्यापार घाटे के दो-तिहाई हिस्से की भरपाई कर दी.

वित्त वर्ष 2026 में सेवाओं का व्यापार मजबूत बना रहा; अप्रैल-दिसम्बर 2025 के दौरान सेवा निर्यात 6·5 प्रतिशत बढ़कर 304·0 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 1·5 प्रतिशत बढ़कर USD 152·2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया. सेवाओं के व्यापार में 151·7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिशेष रहा, जो माल व्यापार घाटे का

सम्बन्धित लेख को इस आकर्षक वीडियो के द्वारा संक्षेप में समझें

QR कोड को स्कैन करें

61·1 प्रतिशत था. यह सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (BPM), कंसल्टिंग और फिनटेक क्षेत्रों की मजबूती को दिखाता है. ऐतिहासिक रूप से, सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात देश के कुल सेवा निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है, जबकि हाल के समय में व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है. यह बढ़ोतरी देश की वैश्विक क्षमता केन्द्रों (Global Capability Centres–GCCs) के लिए एक वैश्विक केन्द्र के रूप में मिली सफलता के कारण हुई है; वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 के बीच GCCs में लगभग 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ोतरी हुई. इस बढ़ोतरी के मुख्य कारण प्रतिभा की उपलब्धता और विविधता हैं.

वैश्विक अनिश्चितता के बीच सेवाओं का निर्यात एक सुरक्षा कवच के रूप में

वैश्विक रुझानों के अनुरूप, सेवाओं का निर्यात भारत के बाह्य क्षेत्र का एक मुख्य आधार और विकास का एक प्रमुख चालक बन गया है. वित्त वर्ष 2023, वित्त वर्ष 2025 के दौरान जीडीपी में इनकी औसत हिस्सेदारी 9·7 प्रतिशत रही, जो महामारी से पहले की अवधि के 7·4 प्रतिशत से अधिक है. नीतिगत अनिश्चितता और भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण वैश्विक माल व्यापार में आई सुस्ती के बीच, सेवाओं के निर्यात ने एक महत्वपूर्ण सहारा प्रदान किया है. वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में यह भूमिका और भी मजबूत हुई है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं के निर्यात की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही के 9·7 प्रतिशत से बढ़कर 10·0 प्रतिशत हो गई है.

भारत के सर्विस एक्सपोर्ट्स की बढ़ती भूमिका, हाल के वर्षों में इसकी ग्रोथ में आई तेजी से साफ झलकती है. सर्विस एक्सपोर्ट्स की औसत ग्रोथ, महामारी से पहले के समय (वित्त वर्ष 2016, वित्त वर्ष 2020) के 7·6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 वित्त वर्ष 2025 के दौरान 14·0 प्रतिशत हो गई है, जो भारतीय सर्विसेज के लिए मजबूत और बड़े पैमाने पर मौजूद ग्लोबल माँग को दिखाता है. ग्लोबल

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

सर्विस मार्केट में बढ़ती कड़ी प्रतिस्पर्धा और पॉलिसी से जुड़ी बढ़ती अनिश्चितता के बीच, वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान सर्विस एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ थोड़ी धीमी होकर 8·0 प्रतिशत पर आ गई. इस थोड़ी-सी गिरावट के बावजूद, ग्रोथ महामारी से पहले के स्तर से ऊपर बनी हुई है, जो इस बात का संकेत है कि सर्विस एक्सपोर्ट्स में अंदरूनी तेजी अभी भी बनी हुई है.

सॉफ्टवेयर सेवाएँ, जो कुल सेवा निर्यात का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं, विकास की मुख्य चालक बनी हुई हैं. डिजिटल सेवाओं की मजबूत वैश्विक माँग के चलते, वित्त वर्ष 2016, वित्त वर्ष 2020 के 4·7 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2023, वित्त वर्ष 2025 के दौरान इनमें औसतन 13·5 प्रतिशत की दर से विस्तार हुआ है. पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाएँ दूसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में उभरी हैं; इनकी विकास दर दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 25·9 प्रतिशत हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2016, वित्त वर्ष 2020 के 10·5 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2023 वित्त वर्ष 2025 में इनका हिस्सा बढ़कर 18·3 प्रतिशत हो गया है. ये दोनों खण्ड मिलकर सेवा निर्यात का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनाते हैं, जो सीमा-पार और ज्ञान-गहन गतिविधियों में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाता है. सेवा निर्यात में वृद्धि को बनाए रखना, सेवाओं के भीतर निरन्तर विविधीकरण और मूल्य शृंखला में आगे बढ़ने पर निर्भर करेगा, जो बदलती वैश्विक माँग के पैटर्न और नियामक वातावरण के अनुरूप हो. इस सन्दर्भ में, भारत के सेवा निर्यात प्रदर्शन को आकार देने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका की जाँच करता है; यह विभिन्न सेवा खण्डों में AI को अपनाने के अलग-अलग प्रभावों और डिजिटल रूप से प्रदान की जा सकने वाली, ज्ञान-गहन निर्यात वस्तुओं में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता पर इसके प्रभावों को रेखांकित करता है.

सेवाओं के व्यापार हेतु विशिष्ट पहलें

केन्द्रीय बजट 2026-27 में, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए लक्षित कर सुधारों, क्लाउड और डेटा केन्द्रों के लिए प्रोत्साहनों, सरल अनुपालन तंत्रों और व्यापार को सुगम बनाने वाले उपायों के माध्यम से इस दिशा को और मजबूत करने की पहल की गई है; इन उपायों का उद्देश्य सेवाओं के व्यापार में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना है. यह भारत को सेवाओं के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी देश बनाने की भी परिकल्पना करता है, जिसका लक्ष्य 2047 तक वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढाकर 10% करना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, **'विकसित भारत' हेतु एक उच्च-स्तरीय 'शिक्षा-से-सशक्तिकरण और उद्यम' स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है.**

यह समिति उन उच्च-संभावित सेवा उप-क्षेत्रों की पहचान करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी जो विकास और रोजगार पैदा करने में सक्षम हैं. यह विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नीतिगत और नियामक मुद्दों को भी सम्बोधित करेगी, जिसमें मानक और मान्यता (Accreditation) ढाँचे शामिल हैं और भारत के सेवा निर्यात को और अधिक विस्तार देने के तरीकों की खोज करेगी. यह समिति कृत्रिम मेधा (AI) और उभरती हुई तकनीकों के नौकरियों और कौशलों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करेगी, साथ ही शिक्षा में कृत्रिम मेधा (AI) के एकीकरण, कार्यबल के कौशल-उन्नयन (Upskilling) और पुनः कौशलन (Reskilling), कृत्रिम मेधा (AI) सक्षम रोजगार मिलान, अनौपचारिक कार्य के औपचारीकरण तथा वैश्विक प्रतिभा और कुशल प्रवासी भारतीयों को आकर्षित करने के लिए उपायों का प्रस्ताव भी देगी. जैसे-जैसे सेवा क्षेत्र विकसित हो रहा है, सेवाओं का व्यापार भारत के बाह्य क्षेत्र के निष्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरा है; बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच बढ़ता हुआ निर्यात समग्र व्यापार वृद्धि को समर्थन प्रदान कर रहा है.

डेटा सेंटर प्रोत्साहनों के जरिए क्लाउड सर्विस एक्सपोर्ट को बढ़ावा—केन्द्रीय बजट 2026-27 की सर्वाधिक प्रमुख पहलों में से एक है, भारत में मौजूद डेटा सेंटर अधोसंरचना के जरिए काम करने वाले ग्लोबल क्लाउड सर्विस सेवा प्रदाताओं को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन शुरू करना. जरूरी अधोसंरचना को सक्षम बनाने और डेटा सेंटर्स में निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत को पहचानते हुए, बजट में उन विदेशी कम्पनियों के लिए 2047 तक टैक्स छूट का प्रस्ताव है, जो भारत में मौजूद अधोसंरचना का इस्तेमाल करके ग्लोबल क्लाइंट्स को क्लाउड सर्विस देती हैं. इसके अलावा, भारत से डेटा सेंटर सर्विस देने वाली सम्बन्धित संस्थाओं को लागत पर 15% के सेफ हार्बर मार्जिन से लाभ मिलने का प्रस्ताव है.

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सुधार—अनुपालन को आसान बनाने के लिए, केन्द्रीय बजट 2026-27 में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (KPO) सेवाओं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी कॉन्ट्रैक्ट अनुसंधान एवं विकास (R&D) सेवाओं को 'सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं' की एक ही श्रेणी के तहत् लाने का प्रस्ताव किया गया है. इसके लिए 15·5% का एकसमान 'सेफ हार्बर मार्जिन' निर्धारित किया गया है और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर की सीमा को ₹ 300 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 2,000 करोड़ कर दिया गया है. सेफ हार्बर व्यवस्था को एक स्वचालित (Automated) और नियमों पर आधारित प्रक्रिया के जरिए मंजूरी दी जाएगी, जिसमें किसी टैक्स अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी. एक बार इस विकल्प को चुनने के बाद, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कम्पनियाँ स्वेक्षा से लगातार 5 वर्षों तक उन्हीं सेफ हार्बर प्रावधानों के तहत् काम जारी रख सकेंगी.

अग्रिम कीमत निर्धारण समझौता [एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (APA)] में सुधार—सूचना प्रौद्योगिकी सर्विस कम्पनियों के लिए, जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (APA) करना चाहती हैं, बजट में सूचना प्रौद्योगिकी सर्विस कम्पनियों के लिए एकतरफा अग्रिम कीमत निर्धारण समझौता प्रक्रिया को तेज करने का भी प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य 2 वर्ष के अन्दर एग्रीमेंट पूरे करना है. टैक्सपेयर के अनुरोध पर, इस 2 वर्ष की अवधि को 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है. अग्रिम कीमत निर्धारण समझौता करने वाली संस्थाओं को उपलब्ध संशोधित रिटर्न फाइल करने की

भारत के वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं के नेतृत्व का सुदृढ़ीकरण

क्लाउड और डिजिटल अधो-संरचना	सेफ हार्बर सुधार	अग्रिम कीमत निर्धारण समझौता और विवादों का निपटारा
2047 तक टैक्स करावकाश (होली डे)	एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग	फास्ट ट्रक मार्ग से एपीए पूरा करना
भारत से वैश्विक क्लाउड सेवाएँ प्रदान करना	15·5% का एकसमान 'सेफ हार्बर मार्जिन'	टैक्सपेयर के अनुरोध पर, इस 2 वर्ष की अवधि को 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है.
डेटा सेंटर प्रदातों को 15% का सेफ हार्बर	सेफ हार्बर की सीमा को ₹ 300 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 2,000 करोड़	
	स्वचालित अनुमोदन 5 वर्षों के लिए वैध	

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

सुविधा को उनकी सम्बन्धित संस्थाओं तक भी बढ़ाने का प्रस्ताव है.

सेवा निर्यात के क्षेत्रीय चालक

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं (ITES) पर किए गए सर्वे से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024 में 2·3 प्रतिशत (YoY) की बढ़ोतरी के बाद, वित्त वर्ष 2025 में सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात 7·3 प्रतिशत (YoY) बढ़ गया है. वित्त वर्ष 2025 में, कम्प्यूटर सेवाओं का निर्यात भारत के कुल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात का दो-तिहाई से ज़्यादा हिस्सा है, जबकि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग (BPO) सेवाएँ सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं (ITES) निर्यात का सबसे अहम हिस्सा बनी हुई हैं. इसके अलावा, जहाँ अमेरिका भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए सबसे बड़ा गंतव्य स्थल बना हुआ है, वहीं वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 के बीच उसका हिस्सा 54·1 प्रतिशत से घटकर 52·9 प्रतिशत हो गया है. साथ ही, इसी दौरान यूरोप का हिस्सा 30·8 प्रतिशत से बढ़कर 32·8 प्रतिशत हो गया है.

यह मजबूत निष्पादन भारत के सेवा क्षेत्र की व्यापक मजबूती को दिखाता है, जिसे सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट (BPM), कंसल्टिंग और फिनटेक प्रखण्ड के लगातार विस्तार से समर्थन मिला है; ये प्रखण्ड कुल सेवा निर्यात को आगे बढ़ा रहे हैं. डिजिटल सेवाओं की मजबूत वैश्विक माँग के समर्थन से, सॉफ्टवेयर सेवाएँ सबसे बड़ा घटक बनी हुई हैं. यह कुल सेवा निर्यात का 40% से ज्यादा हिस्सा है और वित्त वर्ष 2023, वित्त वर्ष 2025 के दौरान इसकी औसत वृद्धि दर 13·5% रही, जबकि वित्त वर्ष 2016 वित्त वर्ष 2020 में यह 4·7% थी. इसके साथ ही, हाल के वर्षों में व्यावसायिक सेवा निर्यात में भी तेजी आई है, जिससे भारत के बाहरी क्षेत्र की मजबूती में इस क्षेत्र का बढ़ता योगदान और भी पुख्ता हुआ है. वित्त वर्ष 2023, वित्त वर्ष 2025 में, पेशेवर और प्रबंधन कंसल्टिंग दूसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में उभरा है; इसकी वृद्धि दर 25·9% रही, जिससे वित्त वर्ष 2016 वित्त वर्ष 20 में इसका हिस्सा 10·5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 वित्त वर्ष 2025 में 18·3% हो गया.

भारत के सेवा निर्यात में उच्च वृद्धि के प्रमुख चालक निम्नलिखित रहे हैं—

- कुल सेवा निर्यात में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सॉफ्टवेयर सेवाएँ सेवा निर्यात का सबसे बड़ा घातक है.
- सॉफ्टवेयर निर्यात में कम्प्यूटर सेवाओं की हिस्सेदारी दो-तिहाई से अधिक है.
- बिजनेस प्रोसेसिंग आउट सोर्सिंग सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का सबसे बड़ा घातक है.
- पेशेवर और प्रबंधकीय परामर्शदात्री सेवाओं ने वित्त वर्ष 2023 व वित्त वर्ष 2025 के बीच 25·9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है.
- ये सभी प्रखण्ड मिलकर सेवाओं के निर्यात का 65% से अधिक हिस्सा बनाते हैं, जो सीमा-पार और ज्ञान-आधारित गतिविधियों में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाता है.

सेवा निर्यात प्रतिस्पर्धा के नए चालक

वैश्विक क्षमता केन्द्रों (GCCs) की बढ़ती उपस्थिति—

- वित्त वर्ष 2020 व वित्त वर्ष 2025 के बीच 7% की यौगिक वार्षिकी वृद्धि दर हासिल की.
- वित्त वर्ष 2024 तक 1700 से अधिक वैश्विक क्षमता केन्द्र कार्यरत.
- उत्पाद विकास, कृत्रिम मेधा सक्षम डिजिटल सेवाएँ, साइबर सिक्योरिटी, एनालिटिक्स इंजीनियरिंग जैसी उच्च मूल्य सेवाएँ.

भारत का तेजी से विकसित होता कृत्रिम मेधा एवं डिजिटल अर्थतंत्र

- कृत्रिम मेधा पेनीट्रेशन (स्टैनफोर्ड एआई सूचकांक रिपोर्ट 2025) में विश्व में भारत दूसरे स्थान पर.
- UNCTAD की फ्रंटियर प्रौद्योगिकी रेडीनेस सूचकांक 2024 भारत विश्व में 36वें स्थान पर.
- भारत से संचालित डेटा क्षमता केन्द्रों की क्षमता 2025 में 1·4 GW से बढ़कर 2030 तक 8·0 GW होने का अनुमान.
- विश्व में सर्वाधिक तेजी के साथ जनरेटिव कृत्रिम मेधा पेटेंट प्राप्त करने में.

सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में वैश्विक व्यापार समझौतों की भूमिका

भारत द्वारा विश्व के अनेक देशों के साथ किये गए व्यापार समझौतों के बढ़ते नेटवर्क ने वैश्विक बाजारों में भारत के सेवा क्षेत्र के लिए बाजार तक पहुँच को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ये समझौते पेशेवरों के लिए अधिक गतिशीलता और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं.

भारत के सेवा निर्यात क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

भारत के सेवा निर्यात को यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों में वैश्विक आर्थिक मंदी से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे माँग में कमी आती है. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए विश्व भर में अपनाई जा रही सख्त मौद्रिक नीतियाँ एक चुनौतीपूर्ण माहौल पैदा कर रही हैं. इसके अलावा, कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भरता और सेवाओं की सीमित टोकरी (बास्केट) जो मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक सेवाओं पर निर्भर है, भी जोखिम पैदा करती है.

भारत के सेवा निर्यात के लिए मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं—

- **वैश्विक आर्थिक मंदी—**प्रमुख निर्यात स्थलों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ में माँग में कमी.
- **कठोर मौद्रिक नीतियाँ—**महँगाई को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में वृद्धि, जिससे निवेश और उपभोग में कमी आ सकती है.
- **सीमित सेवा क्षेत्रों पर निर्भरता—**सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेसिंग आउट सोर्सिंग सेवाओं पर अत्यधिक निर्भरता

भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA)	137 उप क्षेत्रों तक बाजार पहुँच; सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA)	144 सेवाओं के उप-क्षेत्रक आच्छादित
भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता	127 सेवाओं के उप-क्षेत्रक आच्छादित
भारत-न्यूजीलैण्ड मुक्त व्यापार समझौता	118 सेवाओं के उप-क्षेत्रकों को शामिल करने के प्रति प्रतिबद्धता
भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA)	EFTA के प्रस्तावों में स्विट्जरलैण्ड से 128, नॉर्वे से 114, आइसलैण्ड से 110 और लिकटेंस्टीन से 107 शामिल हैं.
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक और व्यापार समझौता	135 सेवाओं के उप-क्षेत्रक आच्छादित
भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता	115 सेवाओं के उप-क्षेत्रक आच्छादित

शेष पृष्ठ 106 पर

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

फोकस 3

आपदा प्रबन्धन : रणनीति से क्रियान्वयन तक

स्वदेशी 2.0 : वैश्विक संकटों से आत्मनिर्भर समाधानों की ओर

✍ डॉ. दीपांकर सिंह

भारत, अपनी विशाल और विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना के कारण, प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रति संवेदनशील है जिसमें भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, सुनामी, भूस्खलन औद्योगिक दुर्घटनाएँ और आतंकवादी घटनाओं में होने वाले गम्भीर विस्फोट आदि शामिल हैं. 27 से अधिक राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को आपदा-सम्भावित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है और 58% से अधिक भू-भाग भूकम्पीय घटनाओं के प्रति संवेदनशील है, इसलिए आपदा की तैयारी एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है.

आपदा से आशय

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार, 'आपदा' से आशय किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से या दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना, विपत्ति या गम्भीर घटना है, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल की भारी क्षति होती है या मानव पीड़ा होती है या सम्पत्ति की क्षति और विनाश होता है या पर्यावरण को नुकसान या क्षरण होता है और यह ऐसी प्रकृति या परिमाण का होता है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे हो. संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा को "किसी समाज या समुदाय के कार्य करते रहने की दशा में गम्भीर रुकावटें खड़ी करना" के रूप में परिभाषित किया गया है .

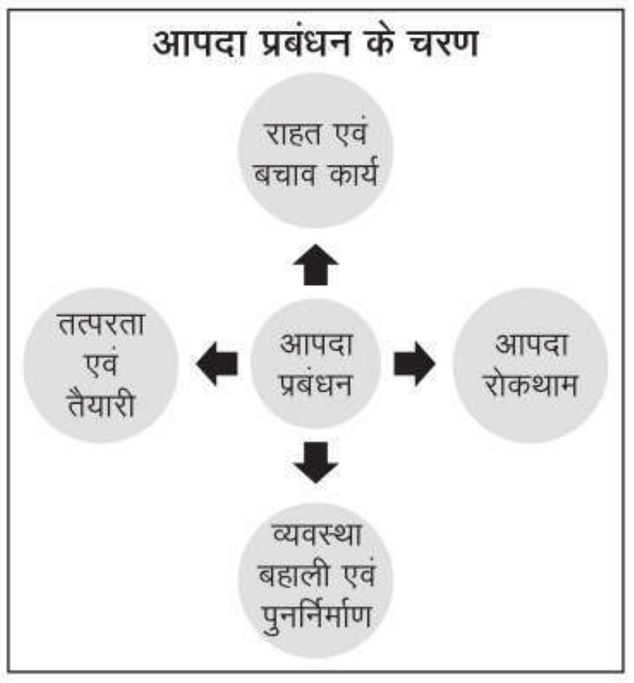
आपदा/जोखिम का प्रकार—भारत निम्नलिखित दैवीय/मानवकृत आपदाओं से समय-समय पर प्रभावित होता रहता है—भूकम्प, बाढ़ (शहरी/नदी) और सुनामी; शहरी बाढ़; चक्रवात और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ)—भूस्खलन और हिमस्खलन; सूखा; लू, शीत लहर और पाला; गरज, बिजली, धूल, ओलावृष्टि, तेज हवाएँ; जैविक आपदाएँ; रासायनिक आपदाएँ; परमाणु/रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियाँ; सामूहिक दुर्घटना और चिकित्सा तैयारी; शहरी बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा; भूकम्पीय रेट्रोफिटिंग; आतंकवादी जनित विस्फोट आदि.

आपदा प्रबन्धन

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार, 'आपदा प्रबन्धन' एक सतत् और एकीकृत प्रक्रिया है जिसमें आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक या समीचीन उपायों की योजना, आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन शामिल है. इसमें किसी भी आपदा के खतरे या खतरे की रोकथाम, सम्बन्धित जोखिमों और परिणामों का शमन या कमी, और आवश्यक क्षमताओं का निर्माण शामिल है. इसमें आपदाओं से निपटने की तैयारी, किसी भी परिसंकटमय स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया और आपदा के प्रभावों की गम्भीरता या परिमाण का आकलन भी शामिल है. इसके अलावा, आपदा प्रबन्धन में निकासी, बचाव और राहत कार्यों के साथ-साथ दीर्घकालिक पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयास भी शामिल हैं.

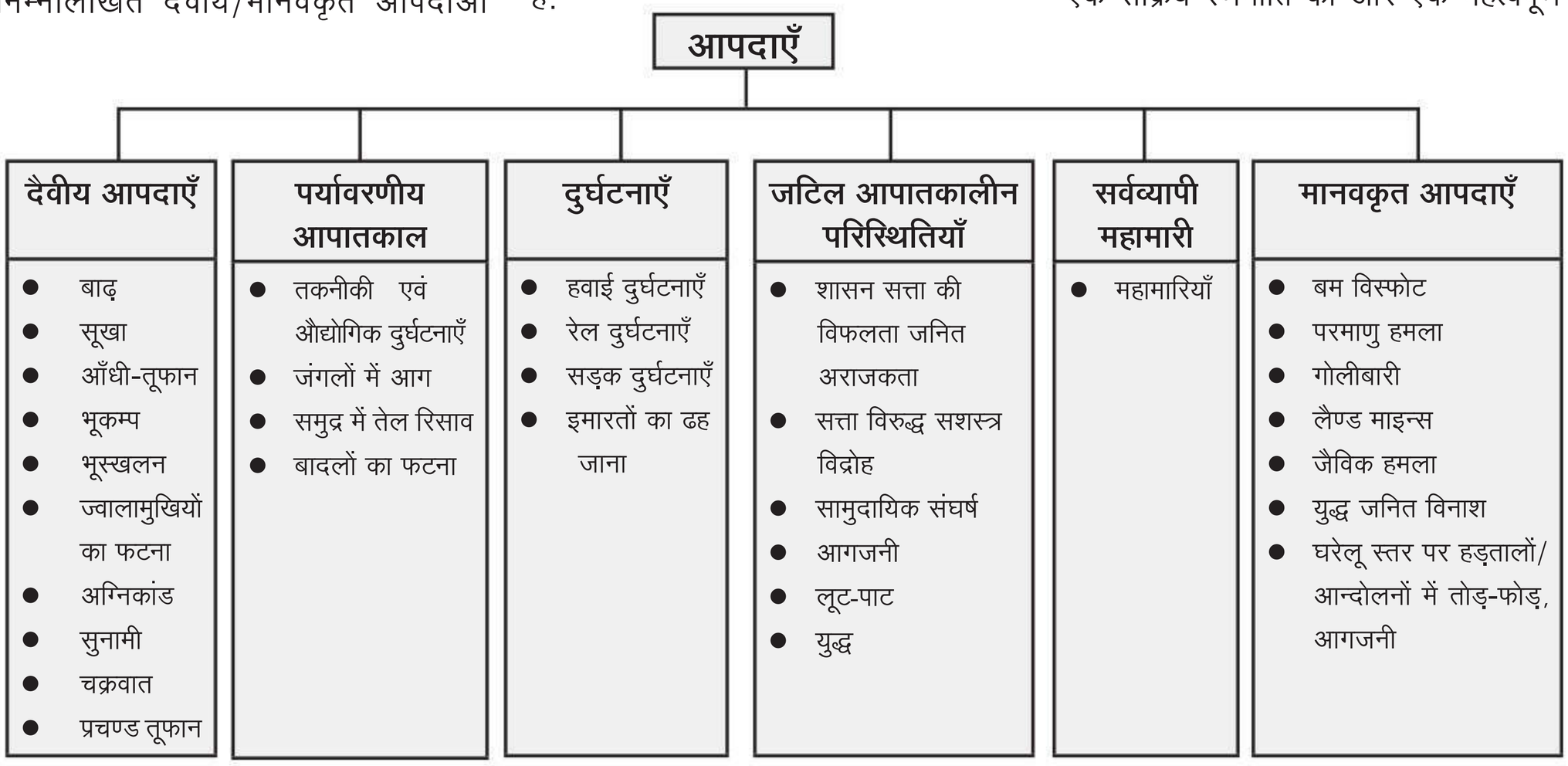
सम्बन्धित लेख को इस आकर्षक वीडियो के द्वारा संक्षेप में समझें

QR कोड को स्कैन करें



राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति (एनपीडीएम), 2009

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति (एनपीडीएम) 2009, भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रतिक्रिया के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है. इस नीति को 22 अक्टूबर, 2009 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था. यह नीति राहत-केन्द्रित दृष्टिकोण से इतर आपदाओं की रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रभावी कार्रवाई पर जोर देने वाली एक सक्रिय रणनीति की ओर एक महत्वपूर्ण



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

बदलाव का प्रतीक है. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 पर आधारित, इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर कानूनी, वित्तीय और समन्वय ढाँचों द्वारा समर्थित संस्थागत तंत्र स्थापित करके एक सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी राष्ट्र का निर्माण करना है.

दृष्टिकोण—यह नीति आपदाओं की रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रत्युत्तर की संस्कृति के माध्यम से एक सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी भारत का निर्माण करने पर केन्द्रित है.

प्रमुख उद्देश्य—राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति (एनपीडीएम) 2009 के उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार हैं—

- आपदा प्रबन्धन के सभी स्तरों पर आपदा जागरूकता और सशक्तता को बढ़ावा देना.
- विकास योजना में आपदा प्रबन्धन को एकीकृत करना.
- आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत और तकनीकी-कानूनी ढाँचे स्थापित करना.
- आपदा की पूर्व चेतावनी प्रणालियों और संचार नेटवर्क को मजबूत करना.
- आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित कमजोर समूहों की समस्याओं का समाधान करते हुए समावेशी प्रत्युत्तर सुनिश्चित करना.

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना (एनडीएमपी) वर्ष 2016 में तैयार और जारी की गई. इस योजना को 2019 में संशोधित किया गया. संशोधित योजना आपदा प्रबन्धन से जुड़े सभी मुद्दों पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों तथा जिला-स्तरीय अधिकारियों को एक मंच पर लाकर आपदा जोखिम घटाने में उनकी भूमिकाओं और दायित्वों पर केन्द्रित है.

एनडीएमपी की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित प्रकार हैं—

- यह योजना आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2025 और आपदा प्रबन्धन पर राष्ट्रीय नीति (एनपीडीएम) 2009 जैसे राष्ट्रीय विधिक अधिदेशों के अनुरूप है.
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के लिए भारत द्वारा हस्ताक्षरित सेंडाई फ्रेमवर्क, सम्पोषणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित पेरिस समझौता (COP-21) के वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाने पर केन्द्रित है.
- डीआरआर के लिए प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा जिसमें मौजूदा समय की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया गया है.
- यह निति सर्वव्यापी और समग्र सिद्धांत के रूप में सामाजिक समावेशन से युक्त है.

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवम्बर 2016 में नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु 10 सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया था. इस सर्व-समावेशी एजेंडे में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तथा सामुदायिक तैयारी से लेकर प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तक सभी मुद्दों पर समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है. डीआरआर पर प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा इस प्रकार है—

1. विकास के सभी क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबन्धन के सिद्धांतों को अंगीकार करना.
2. जोखिम आच्छादन में निर्धन परिवारों से लेकर छोटे और मझोले उद्यमों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा राष्ट्रीयताओं तक सभी को शामिल करना.
3. महिलाओं के नेतृत्व और वृहत् भागीदारी की आपदा जोखिम प्रबन्धन में केन्द्रीय भूमिका लाना.
4. प्रकृति और आपदा जोखिमों की वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए विश्वभर में जोखिम का पता लगाने और उनको कम-से-कम करने में निवेश बढ़ावा देना.
5. आपदा जोखिम प्रबन्धन प्रयासों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का सतत् अनुप्रयोग.
6. आपदा से सम्बन्धित विषयों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों के नेटवर्क की स्थापना.
7. सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों से मिले अवसरों का आपदा जोखिम घटाने में उपयोग करना.
8. आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु स्थानीय क्षमता और पहलों का निर्माण करना.
9. आपदाओं से सीख लेने के प्रत्येक अवसर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसके लिए प्रत्येक आपदा से मिले सबक पर अध्ययन किए जाएँ.
10. आपदाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में सामंजस्य बढ़ाया जाना.

सेंडाई फ्रेमवर्क

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा जोखिम और नुकसान को कम करने हेतु अपनाया गया एक वैश्विक समझौता है. यह 2015 के बाद के विकास एजेंडे का पहला प्रमुख समझौता था और सदस्य देशों को विकास सम्बन्धी लाभों को आपदा के जोखिम से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने का प्रावधान करता है. यह मानता है कि आपदा जोखिम को कम करने में राज्य की प्राथमिक भूमिका है और यह जिम्मेदारी स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों सहित अन्य हितधारकों के साथ साझा की जानी चाहिए.

भारत में आपदा प्रबन्धन से जुड़े निकाय

भारत ने आपदा प्रबन्धन के लिए धीरे-धीरे एक मजबूत कानूनी, संस्थागत और प्रशासनिक ढाँचा तैयार किया है. आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत् राष्ट्रीय, राज्य और जिला-स्तर पर प्रमुख संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया; प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA), मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMAs), और जिला कलेक्टरों/उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMAs).

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए)—भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) भारत में आपदा प्रबन्धन के लिए सर्वोच्च निकाय है. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत् एनडीएमए की स्थापना और राज्य एवं जिला-स्तर पर संस्थागत तंत्रों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण अनिवार्य है. एनडीएमए को आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है. भारत आपदाओं की रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया की संस्कृति विकसित करने की परिकल्पना करता है.

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्न-लिखित हैं—

- आपदा प्रबन्धन पर नीतियाँ निर्धारित करना.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

- राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन करना.
- राष्ट्रीय योजना के अनुसार, भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन करना.
- राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित करना.
- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम या उसके प्रभावों के शमन के उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित करना.
- आपदा प्रबन्धन के लिए नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना.
- शमन के उद्देश्य से धन के प्रावधान की सिफारिश करना.
- प्रमुख आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सहायता प्रदान करना.
- आपदा की रोकथाम या शमन या सम्भावित आपदा स्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण हेतु ऐसे अन्य उपाय करना जिन्हें वह आवश्यक समझे.
- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान के कामकाज के लिए व्यापक नीतियाँ और दिशा-निर्देश निर्धारित करना.

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)—राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारत का एक प्रमुख विशिष्ट बल है जिसका गठन आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत् प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किया गया है. वर्ष 2006 में स्थापित एनडीआरएफ आपात स्थितियों के दौरान विशिष्ट खोज, बचाव और राहत सेवाएँ प्रदान करने का कार्य करता है. एनडीआरएफ कई राष्ट्रीय अभियानों में अग्रणी रहा है, जिनमें कोसी बाढ़ (2008), जम्मू-कश्मीर बाढ़ (2014), नेपाल भूकम्प (2015) और बालासोर रेल त्रासदी (2023) के दौरान किए गए प्रमुख बचाव प्रयास शामिल हैं. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एनडीआरएफ ने जापान (2011) और तुर्की-सीरिया (2023) जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों में अपनी मानवीय सहायता प्रदान की है, जो वैश्विक आपदा राहत प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

एनडीआरएफ के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

- **विशिष्ट आपदा प्रत्युत्तर**—भूकम्प, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खोज, बचाव, निकासी और राहत अभियान चलाना.
- **सीबीआरएन आपातकालीन प्रबन्धन**—यह निकाय रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु घटनाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित है.
- **सक्रिय तैनाती**—पूर्वानुमानित आपदाओं से पहले तत्काल प्रत्युत्तर के लिए टीमों की पूर्व-स्थिति सुनिश्चित करना.
- **क्षमता निर्माण**—आपदा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों, स्थानीय पुलिस और राज्य आपदा मोचन बलों को प्रशिक्षित करना.
- **शहरी खोज और बचाव (यूएसएआर)**—शहरी परिवेश में इमारत ढहने और औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसी जटिल आपात स्थितियों से निपटना.
- **सहयोग और समन्वय**—बड़े संकटों के दौरान स्थानीय अधिकारियों, सशस्त्र बलों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल से काम करना.

वर्तमान में, एनडीआरएफ की कुल 1,149 कर्मियों वाली बटालियन में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, अर्थात् सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स से ली गई 16 बटालियनें शामिल हैं. प्रत्येक बटालियन में 18 आत्मनिर्भर विशिष्ट खोज और बचाव दल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 47 सदस्य होते हैं, जिनमें संरचनात्मक इंजीनियर, तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन, श्वान दस्ता और चिकित्सा/पैरामेडिक कर्मी शामिल होते हैं.

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन में कृत्रिम मेधा (AI) का एकीकरण

तेजी से बढ़ता शहरीकरण बड़े शहरी समूहों के शहरी क्षेत्रों में नई और कतिपय विशिष्ट प्रकार की चुनौतियों को जन्म दे रहा है. इसलिए, शहरी आपदा जोखिम प्रबन्धन के मुद्दे को सम्बोधित करने और शहरी मुद्दों के प्रति केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में संशोधन के माध्यम से धारा '41A' जोड़ी गई है, जो राज्य सरकारों को राज्य की राजधानियों और सभी नगर निगम वाले शहरों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को छोड़कर) में शहरी आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (यूडीएमए) गठित करने का अधिकार प्रदान करती है, ताकि शहर-विशिष्ट आपदाओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सके. यूडीएमए शहरी-विशिष्ट कमजोरियों जैसे बाढ़ और लू (हीट वेव्स) को सम्बोधित करने वाली शहरी योजना की तैयारी और उसके कार्यान्वयन के समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं. आपदा प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2025, राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस के निर्माण का आदेश देता है, जिसमें जोखिम मूल्यांकन, हानि न्यूनीकरण की योजनाएँ और आपदाओं पर वास्तविक समय का डेटा शामिल है.

आपदा प्रबन्धन अधिनियम ने आपदा प्रबन्धन में समन्वय, तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने वाले एक सुदृढ़ कानूनी और संस्थागत ढाँचे की स्थापना करके आपदा प्रबन्धन में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के तौर पर भारत की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया है. अधिनियम के कार्यान्वयन के माध्यम से, भारत ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर सक्रिय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रभावी प्रबन्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है. भारत ने निम्नलिखित उपायों के माध्यम से आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है—

I. आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (Community Disaster Resilience) का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से 23 सितम्बर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में किया गया था. अब तक 53 देश और 12 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इसके सदस्य बन चुके हैं.

II. भारत सरकार आपदा प्रभावित देशों को मानवीय मदद और आपदा राहत प्रदान करती रहती है. 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना से प्रेरित होकर, भारत सरकार ने तुर्की और सीरिया में 'ऑपरेशन दोस्त', म्यांमार में 'ऑपरेशन ब्रह्म' आदि जैसी पहलें कीं, जिससे आपदा पीड़ितों को तत्काल मानवीय मदद और आपदा राहत (एचएडीआर) प्रदान की जा सकी, 18 मार्च, 2026 तक, भारत ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए ईरान को अपनी चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है. यह खेप तेहरान में 'ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी' को सौंपी गई.

आपदा प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत् राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस का

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

निर्माण अनिवार्य किया गया है, जिसमें जोखिम आकलन, शमन योजनाएँ और आपदाओं से सम्बन्धित त्वरित समय का डेटा शामिल होगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) जैसी सतर्कता एजेंसियों ने मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में कृत्रिम मेधा (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) मॉडल्स को एकीकृत किया है, जो 7 दिनों तक की अवधि के अग्रिम पूर्वानुमान लगा सकते हैं. इसमें मिशन मौसम के हिस्से के रूप में बाढ़ पूर्वानुमान (7 दिनों पहले तक) और चक्रवात ट्रैकिंग के लिए एआई संचालित सिमुलेशन शामिल हैं. उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (The National Disaster Mitigation Fund–NDMF) से राज्यों को वित्तीय सहायता को मंजूरी देती है. एचएलसी का गठन यद्यपि आपदा प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अधिनियमन से पहले हो चुका था और यह आपदा प्रबन्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2025 में संशोधन के माध्यम से एचएलसी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है. इसके अलावा, गृह मंत्रालय गम्भीर आपदा के बाद तत्काल फर्स्ट हैंड क्षति मूल्यांकन के लिए अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीम (आईएमसीटी) के समय पर गठन और प्रतिनियुक्ति की सुविधा प्रदान करता है.

एचएलसी ने 2025-26 के दौरान विभिन्न राज्यों को बाढ़/फ्लैश बाढ़/चक्रवात/आग सेवा के आधुनिकीकरण/पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं आदि के लिए एनडीआरएफ से ₹ 4576·7 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है.

भारत में आपदा प्रबन्धन का वित्तीयन 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में

16वें वित्त आयोग द्वारा 2026-31 की अवधि के लिए आपदा प्रबन्धन [राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)/राज्य आपदा शमन कोष (SDMF)] हेतु ₹ 2,04,401 करोड़ की एक बड़ी राशि की सिफारिश की गई है, जिसमें केवल राहत देने के बजाय सक्रिय रूप से आपदा को कम करने पर जोर दिया गया है. 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में क्षेत्रों में जलवायु-सम्बन्धी आपदाओं, जैसे कि लू और शहरी बाढ़ के लिए वित्तीयन भी शामिल है, इसमें हिमालयी/पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 75:25 का लागत-बँटवारा अनुपात निर्धारित किया गया है. 16वें वित्त आयोग की आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित प्रकार हैं–

- राज्यों के लिए आपदा प्रबन्धन निधियों का आवंटन पिछले खर्चों और आपदा जोखिम सूचकांक (खतरा, जोखिम और संवेदनशीलता) पर आधारित है. वर्ष 2026-27 से 2030-31 की पुरस्कार अवधि के लिए, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) को मिलाकर कुल ₹ 2,04,401 करोड़ की राशि की अनुशंसा की गई है.
- इस कोष को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) के बीच 80:20 के अनुपात में बाँटा जाना चाहिए. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के लिए ₹ 1,63,521 करोड़ और राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) के लिए ₹ 40,880 करोड़ आवंटित किए गए हैं. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत् प्रतिक्रिया और राहत तथा बहाली और पुनर्निर्माण के बीच संसाधनों के पुनर्वितरण में लचीलापन होना चाहिए. तैयारी और क्षमता निर्माण अब राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) के अन्तर्गत आएंगे.
- राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबन्धन [राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) के लिए] पर किए गए पिछले खर्चों के आधार पर, ₹ 79,406 करोड़ के कुल आवंटन की सिफारिश की गई है.
- पूर्वोत्तर और हिमालयी (NEH) राज्यों को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF और राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) के फण्ड में 25 प्रतिशत का योगदान देना होगा; पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य 10 प्रतिशत का योगदान देंगे और शेष राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी. केन्द्र सरकार का कुल हिस्सा ₹ 1,55,915·85 करोड़ बनता है.
- NDRF (रिस्पॉन्स और राहत को छोड़कर) और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) के जरिए केन्द्र की मदद में लागत की हिस्सेदारी का मौजूदा सिस्टम जारी रहना चाहिए. राज्यों को ₹ 250 करोड़ तक की मदद के लिए 10%, ₹ 500 करोड़ तक की मदद के लिए 20% और ₹ 500 करोड़ से ज्यादा की सभी मदद के लिए 25% का योगदान देना होगा. हालाँकि, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) के तहत् केन्द्र की सभी मदद का 10% योगदान देना चाहिए.
- लू और बिजली गिरने की घटनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल किया जाना चाहिए.
- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (NDMIS) को केन्द्र और राज्यों, दोनों के लिए एक व्यापक आपदा प्रबन्धन प्रणाली में बदला जाना चाहिए. इस प्रणाली को वास्तविक समय के लेन-देन स्तर के आपदा डेटा को दर्ज करना चाहिए, जो आपदा सम्बन्धी जानकारी के लिए एक एकल स्रोत के रूप में कार्य करे और राज्यों पर अनुपालन के बोझ को कम करे. ●●●

शेष पृष्ठ 102 का

इस क्षेत्र को इन उद्योगों में होने वाले उतार-चढ़ावों के प्रति संवेदनशील बनाती है.

- **वैश्विक नीतियों का विलम्बित प्रभाव–** साझेदार अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि का भारत के निर्यात प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव पड़ता है.
- **बुनियादी ढाँचा और कौशल अंतराल–** हालाँकि, डिजिटल बुनियादी ढाँचे में सुधार हो रहा है, फिर भी उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए कौशल अंतराल को पाटना एक चुनौती बना हुआ है.

हाल के वर्षों में, भारत के सेवा निर्यात में मजबूत और लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, और यह क्षेत्र देश के बाह्य क्षेत्र के निष्पादन को आगे बढ़ाने वाले सबसे मजबूत कारकों में से एक बनकर उभरा है. अपने 'कर्तव्य' की भावना को आगे बढ़ाते हुए, केन्द्रीय बजट 2026-27 लक्षित कर सुधारों, डिजिटल बुनियादी ढाँचे के लिए प्रोत्साहन, कौशल विकास की पहलों और भारत के सेवा क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों के माध्यम से सेवा निर्यात में बढ़ोतरी को और अधिक मजबूती प्रदान करता है. प्रतिभा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक साझेदारियों के मेल से, भारत का सेवा क्षेत्र देश की विकास गाथा को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. ●●●

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

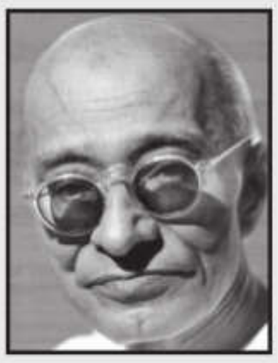
ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं ऐतिहासिक स्थल

ऐतिहासिक व्यक्तित्व

सी. राजगोपालाचारी (1878-1972 ई.)

चर्चा में क्यों ?

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में भारत के उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया. गौरतलब है कि महात्मा गाँधी की प्रतिमा के सामने अशोक मंडप के पास स्थित भव्य सीढ़ी पर स्थापित सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा ने एडविन लुटियंस की प्रतिमा का स्थान लिया है.

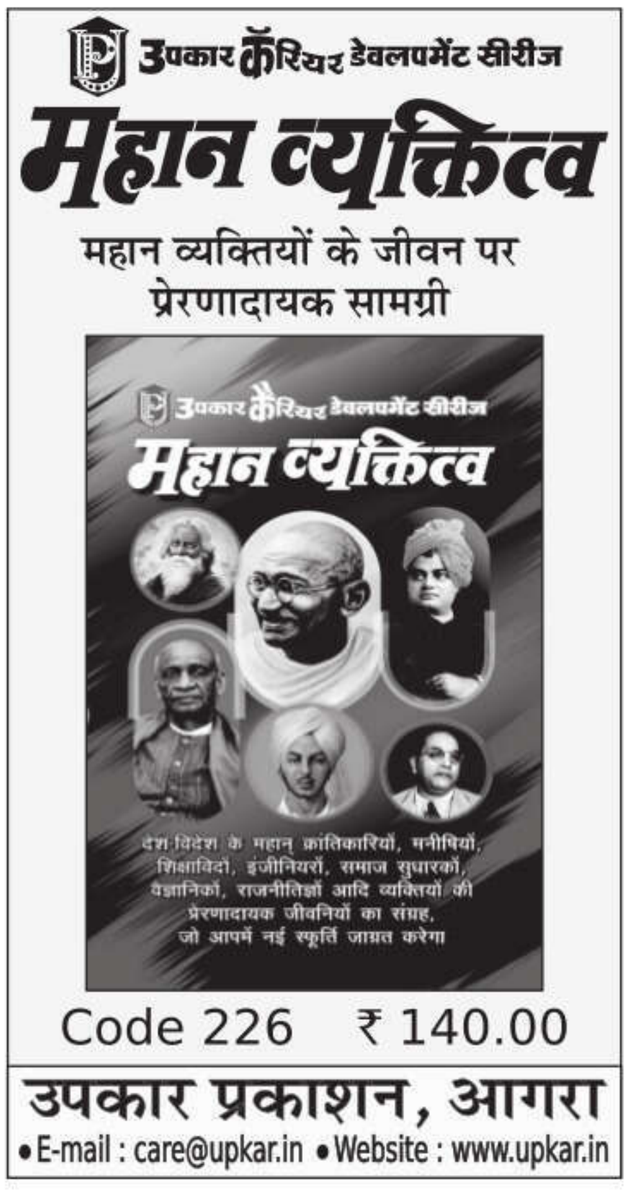


जीवन परिचय

- चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिन्हें प्यार से उनके प्रशंसक और सहयोगी 'राजाजी' कहते हैं का जन्म 10 दिसम्बर, 1878 को मद्रास प्रांत (वर्तमान तमिलनाडु) के सेलम जिले के थोरापल्ली गाँव में हुआ था. उनके पिता चक्रवर्ती अयंगर, जिन्हें वेंकट आर्य के नाम से भी जाना जाता था, होसूर तालुका के मुंसिफ थे.
- राजगोपालाचारी की प्रारम्भिक शिक्षा उनके गाँव के स्कूल में ही हुई. उन्होंने सेंट्रल हिन्दू कॉलेज, बंगलौर (वर्तमान बेंगलुरु) से स्नातक डिग्री प्राप्त की और मद्रास के लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया. वर्ष 1899 में उन्होंने विधि स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सेलम में वकालत प्रारम्भ की.
- लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का साम्प्रदायिक विभाजन राजगोपालाचारी के लिए एक परिवर्तनकारी आघात था. इससे आहत होकर और लोकमान्य तिलक के 'पूर्ण स्वराज' के आह्वान से प्रभावित होकर, उन्होंने तिलक को अपना गुरु मान लिया. तिलक के त्याग और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर राजगोपालाचारी ने भौतिक सुखों का मोह छोड़ दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग चुन लिया.
- जुलाई 1917 में राजगोपालाचारी को सेलम नगरपालिका का चेयरमैन मनोनीत किया गया. फरवरी 1925 में तिरुचेन्गोड में स्थापित आश्रम राजगोपालाचारी के ग्रामीण सुधारों का मुख्य केन्द्र बना. उन्होंने यहाँ अस्पताल, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया. आश्रम से दो पत्रिकाएँ प्रकाशित होती थीं–तमिल में 'विमोचनम्' (मुक्ति) और अंग्रेजी में 'प्रोहिबिशन'. 'विमोचनम्' ग्रामीणों की आवश्यकता की पूर्ति करती थी. राजगोपालाचारी ने ग्रामीणों को शराब की बुराइयों से अवगत कराया और कुटीर उद्योगों, मधुमक्खी पालन तथा साबुन-निर्माण जैसे कार्यों से उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया.
- गाँधी जी की 12 मार्च, 1930 की दांडी यात्रा के समर्थन में मद्रास प्रेसीडेंसी में सी. राजगोपालाचारी ने वेदारण्यम नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया. यह यात्रा 13 अप्रैल, 1930 को तिरुचिरापल्ली (तिरुची) से शुरू होकर वेदारण्यम तक चली, जिसे तंजौर और कुम्भकोणम जैसे क्षेत्रों में व्यापक जनसमर्थन मिला. 16 दिनों की यात्रा के बाद वेदारण्यम पहुँचकर नमक कानून तोड़ने पर राजाजी को गिरफ्तार कर 6 माह के कारावास की सजा दी गई. इस आंदोलन ने दक्षिण भारत में नागरिक अवज्ञा को तीव्र किया और राजगोपालाचारी को एक कद्दावर राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया.
- 14 जुलाई, 1937 को सी.राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रेसीडेंसी के 'प्रधानमंत्री'

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- **एडविन लुटियंस**–1869 ई. में लंदन में जन्मे एडविन लुटियंस एक प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार थे, जिन्होंने नई दिल्ली के बड़े हिस्से को डिजाइन किया था. उल्लेखनीय है कि राजधानी को कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद, 1912 ई. में उन्हें शहर की प्रमुख इमारतों के डिजाइन का काम सौंपा गया. इनमें राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आदि शामिल थे. उन्होंने लंदन में स्थित सेनोटैफ का भी डिजाइन तैयार किया और 1918 ई. में उन्हें 'नाइट' की उपाधि से सम्मानित किया गया था.
- **राष्ट्रपति भवन**–एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन की गई इस इमारत को पहले गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था और दिसम्बर 1929 में, जब वायसराय इरविन वहाँ रहने लगे तो इसे वायसराय हाउस के नाम से जाना जाने लगा.
- **हैदराबाद और अन्य निर्माण**–इंडिया गेट के आसपास विभिन्न 'राजकुमारों' के घर बनाए गए थे और हैदराबाद हाउस और बड़ौदा हाउस के वास्तुकार एडविन लुटियंस थे. 1928 ई. में हैदराबाद हाउस और बीकानेर हाउस का उद्घाटन हुआ.
- पिछले वर्ष जुलाई में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दो सबसे महत्वपूर्ण हॉल दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखने की घोषणा की.
- जनवरी 2024 में, मुगल उद्यानों के सीजन के लिए जनता के लिए खुलने से एक दिन पहले, राष्ट्रपति भवन ने घोषणा की कि इसे 'अमृत उद्यान' का 'सामान्य नाम' दिया जा रहा है.
- 2022 में, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के रास्ते का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था.



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

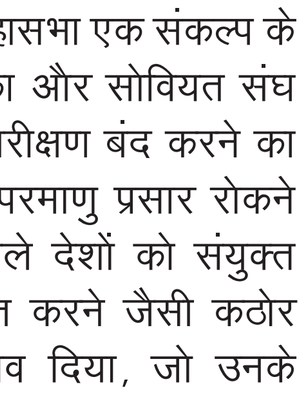
(मुख्यमंत्री) का पद सँभाला. उनका कार्यकाल प्रशासनिक समन्वय और प्रगतिशील सुधारों के लिए जाना जाता है. उन्होंने ब्रिटिश सिविल सेवकों और भारतीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच विश्वास का सेतु बनाया. सामाजिक क्षेत्र में, उन्होंने एक दलित सदस्य को मंत्रिमण्डल में शामिल किया और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किया. उनके शासन के प्रमुख एजेंडे में खादी प्रचार, ग्रामीण उद्योग, निषेध (Prohibition) और स्कूलों में अनिवार्य हिन्दी की शिक्षा शामिल थी. गवर्नर लॉर्ड इसकाइन के सहयोग से उन्होंने प्रभावी सामाजिक-आर्थिक सुधार लागू कर एक कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई.

- स्वतंत्रता पश्चात् चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल नियुक्त हुए, जहाँ अपनी सादगी और प्रशासनिक समन्वय से उन्होंने एक आदर्श राज्याध्यक्ष की मिशाल पेश की. वर्ष 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के बाद वे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर-जनरल बने. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राष्ट्रव्यापी भ्रमण कर जन-समस्याओं का समाधान किया और विभाजन के बाद साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया. उन्होंने विशेष रूप से मुसलमानों से राष्ट्र की मुख्यधारा और धर्मनिरपेक्ष समाज का अभिन्न अंग बनने की अपील की.
- दिसम्बर 1950 में सरदार पटेल के निधन के बाद सी. राजगोपालाचारी भारत के गृह मंत्री नियुक्त किए गए. उनके कार्यकाल की सबसे चर्चित घटना विवादित निवारक निरोध अधिनियम (Preventive Detention Act) को संसद में प्रस्तुत करना था, जिसका विपक्ष और कुछ कांग्रेसियों ने अधिनायकवाद कहकर विरोध किया. उन्होंने इसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक 'आवश्यक न्यूनतम शक्ति' बताकर इसका बचाव किया. इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूपण, कश्मीर मुद्दे के समाधान और स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव (1951-52) की तैयारियों में महत्वपूर्ण रणनीतिक सलाह दी. दिसम्बर 1951 में उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया.
- वर्ष 1952 के प्रथम आम चुनावों में मद्रास प्रांत में कांग्रेस की पराजय के बाद, सी. राजगोपालाचारी को विधायक दल का नेता चुना गया. खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में नेतृत्व सँभाला.
- राजगोपालाचारी को राष्ट्र के प्रति उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सन् 1954 में 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया. वह इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे.
- राजाजी ने सन् 1959 में 'स्वतंत्र' पार्टी बनाई जिसने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हेतु सक्रिय अभियान चलाया. मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके सर्वप्रथम कार्यों में से एक था–खाद्यान्नों के वितरण और उनके मूल्यों को नियंत्रणमुक्त करना.
- वर्ष 1962 में सी. राजगोपालाचारी ने परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की माँग को लेकर गाँधी शान्ति न्यास के तहत् संयुक्त राज्य अमेरिका गए शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया.
- सी. राजगोपालाचारी ने परमाणु निरस्त्रीकरण के वैश्विक अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने 1962 में 'गाँधी शान्ति फाउण्डेशन' के प्रतिनिधिमण्डल के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी से भेंट कर परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने का प्रभावी आग्रह किया. इसके पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) में महासचिव यू. थांट के समक्ष उन्होंने प्रस्ताव रखा कि महासभा एक संकल्प के माध्यम से अमेरिका और सोवियत संघ को सभी परमाणु परीक्षण बंद करने का निर्देश दे. उन्होंने परमाणु प्रसार रोकने में विफल रहने वाले देशों को संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित करने जैसी कठोर चेतावनी का सुझाव दिया, जो उनके वैश्विक शान्ति और मानवाधिकारों के प्रति समर्पण को दर्शाता है.
- 25 दिसम्बर, 1972 को इस विख्यात राजनेता और भारत के महान सपूत का देहावसान हो गया.

सावित्रीबाई फुले (1831-1897 ई.)

चर्चा में क्यों ?

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 मार्च, 2026 को भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की.



जीवन परिचय

- सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले की खंडाला तहसील के नायगाँव नामक स्थान पर 3 जनवरी, 1831 को हुआ. उनके पिता का नाम खण्डोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था.
- सतारा के माली समाज में इनके कुल को श्रेष्ठ गिना जाता था. उस दौर में दलितों के साथ भेदभाव के कारण उनका शिक्षा प्राप्त करना अत्यधिक कठिन था. दलित महिलाओं के लिए शिक्षा को बुरा माना जाता था.
- सावित्रीबाई फुले बाल्यकाल से ही पठन-पाठन में रुचि रखती थी. कहा जाता है कि गाँव के एक मेले में एक पादरी ने यीशु के जीवन चरित्र छपी एक पुस्तक सावित्रीबाई को यह कहकर दी कि यह भगवान की पुस्तक है. तुम पढ़ तो नहीं पाओगी पर चित्र देखकर तुम्हारे चित्त को बहुत आनंद आएगा. सावित्रीबाई फुले जब यह पुस्तक अपने घर लाई तो उनके पिताजी ने इसे फेंक देने को कहा. सावित्रीबाई ने यह कहकर किताब फेंकने से मना कर दिया कि "यह मुझे भगवान के नाम पर दी गई है. मैं भगवान का निरादर नहीं करूँगी, भले ही समाज मुझे फाँसी पर लटका दे".
- सन् 1840 में मात्र 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह 12 वर्ष के ज्योतिबा फुले से हुआ. महात्मा ज्योतिबा फुले स्वयं एक महान शिक्षक, विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, सम्पादक और क्रांतिकारी थे.
- महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी मौसी सगुणाबाई और पत्नी सावित्रीबाई को लेकर अस्पृश्य नारी शिक्षा की पहली पाठशाला प्रारम्भ की.

प्रमुख कृतियाँ

- सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन काल में दो काव्य पुस्तकों की रचना की, जिनमें उनका पहला 'काव्य-फुले' 1854 में तब छपा जब वे मात्र 23 वर्ष की ही थीं.
- दूसरा काव्य-संग्रह 'बावनकशी सुबोध-रत्नाकर' 1891 में आया, जिसे सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के परिनिर्वाण प्राप्ति के बाद उनकी जीवनी के रूप में लिखा था.

- नारी शिक्षा का शुभारम्भ करने हेतु ज्योतिबा द्वारा सहृदय ब्राह्मण तात्यासहब भिड़े के सहयोग से 1 जनवरी, 1848 को पुणे, महाराष्ट्र में पहला विधिवत विद्यालय खोला गया जिसमें गिनती की 6 छात्राओं ने पहले दिन प्रवेश लिया.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

सत्यशोधक समाज

- समाजोत्थान के अपने मिशन पर कार्य करते हुए ज्योतिबा फुले ने 24 सितम्बर, 1873 को अपने अनुयायियों के साथ 'सत्यशोधक समाज' नामक संस्था का निर्माण किया. वे स्वयं इसके अध्यक्ष थे और सावित्रीबाई फुले महिला विभाग की प्रमुख.
- इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शूद्रों और अति शूद्रों को उच्च जातियों के शोषण से मुक्त कराना था. ज्योतिबा के कार्य में सावित्रीबाई ने बराबर का योगदान दिया. ज्योतिबा फुले ने जीवन भर निम्न जाति, महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया.
- 28 नवम्बर, 1890 को महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के साथ ही सावित्रीबाई फुले ने भी सत्य शोधक समाज को दूर-दूर तक पहुँचाने, अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के अधूरे कार्यों को पूरा करने व समाज सेवा का कार्य जारी रखा.

- इस प्रथम विद्यालय में सावित्रीबाई प्रथम स्त्री शिक्षिका बनी. धीरे-धीरे पुणे में इस विद्यालय की चर्चा हुई और छात्राओं की संख्या में वृद्धि होती गई.
- इसके अतिरिक्त उन्होंने देश के पहले किसान स्कूल की भी स्थापना की थी. 1852 ई. में उन्होंने दलित बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की.

महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष

- स्त्री शिक्षा के साथ ही विधवाओं की शोचनीय दशा को देखते हुए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की भी शुरुआत की. 1854 ई. में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने एक अनाथ आश्रम खोला, यह भारत में किसी व्यक्ति द्वारा खोला गया पहला अनाथ आश्रम था. साथ ही अनचाही गर्भावस्था की वजह से होने वाली शिशु हत्या को रोकने के लिए उन्होंने बालहत्या प्रतिबंधक गृह भी स्थापित किया.
- विधवाओं की स्थिति को सुधारने और सती प्रथा को रोकने व विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किए. सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर काशीबाई नामक एक गर्भवती विधवा महिला को न केवल आत्महत्या करने से रोका अपितु उसे अपने घर पर रखकर उसकी देखभाल की और समय पर प्रसव कराया. बाद में उन्होंने उसके पुत्र यशवंत को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया.

पुरस्कार व सम्मान

- वर्ष 2014 में, उनके सम्मान में पुणे विश्वविद्यालय का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर 'सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय' (SPPU) कर दिया गया.
- इंडिया पोस्ट ने 10 मार्च, 1998 को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर, उनकी तस्वीर वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी किया.
- उनके जीवनकाल के दौरान, 1852 ई.में, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व पहलों के लिए उन्हें 'बॉम्बे प्रेसीडेंसी की सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका' घोषित किया था.
- वर्ष 2025 में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने आधुनिक शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया.
- उनकी जयंती के अवसर पर 3 जनवरी को, शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाने के उनके प्रयासों को सम्मानित करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में 'बालिका दिन' (लड़की दिवस) के रूप में मनाया जाता है.

- वर्ष 1890 में जब पति का निधन हो गया तब सामाजिक मान्यताओं को तोड़ते हुए उन्होंने स्वयं अपने पति का अंतिम संस्कार किया.
- वर्ष 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग बीमारी फैलने के कारण वे लोगों की मदद के लिए आगे आईं. हालाँकि, इस दौरान वे स्वयं इस बीमारी से संक्रमित हो गईं और 10 मार्च, 1897 को उनका निधन हो गया.

अन्य प्रमुख चर्चित ऐतिहासिक व्यक्तित्व

भगत सिंह (1907-1931 ई.)



- प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का शहादत (शहीद) दिवस मनाया जाता है.
- 28 सितम्बर, 1907 को बंगा (अब पाकिस्तान) में जन्मे भगत सिंह एक क्रांतिकारी सिख परिवार से थे. 1919 ई. के जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया. उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की.
- वे समाजवाद, मार्क्सवाद और अराजकतावाद के प्रबल समर्थक थे. 1928 ई. में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' का नाम बदलकर 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HSRA) किया, जिसका लक्ष्य भारत में समाजवादी गणराज्य की स्थापना था. उन्होंने 'मैं नास्तिक क्यों हूँ?' (Why I am an Atheist) लिखकर तार्किक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया.

प्रमुख गतिविधियाँ

- **नौजवान भारत सभा (1926)**—युवाओं में क्रांतिकारी भावना भरने हेतु स्थापना.
- **सांडर्स की हत्या (1928)**—लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने हेतु राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर की.
- **सेंट्रल असेम्बली बम कांड (8 अप्रैल, 1929)**—बटुकेश्वर दत्त के साथ 'पब्लिक सेफ्टी बिल' और 'ट्रेड डिस्प्यूट बिल' के विरोध में खाली बेंचों पर बम फेंके. उद्देश्य हत्या नहीं, बल्कि 'बहरों को सुनाना' था.
- लाहौर षड्यंत्र केस के तहत् 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फाँसी दी गई.
- **साहित्यिक कृतियाँ—**
  जेल डायरी, मैं नास्तिक क्यों हूँ?, The Ideal of Socialism

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

गोविन्द बल्लभ पंत (1887-1961 ई.) 	● प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि मनाई जाती है. ● पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितम्बर, 1887 को अल्मोड़ा के निकट खूंट गाँव में हुआ था. ● वर्ष 1916 में उन्होंने कुमाऊँ परिषद् की स्थापना की और 1923 ई. में स्वराज पार्टी के टिकट पर संयुक्त प्रांत विधान परिषद् के सदस्य चुने गए. ● वर्ष 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिसिया लाठीचार्ज में वे गम्भीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके कारण वे स्थायी रूप से शारीरिक रूप से अक्षम हो गए. प्रशासनिक स्तर पर उनकी उपलब्धियाँ अद्वितीय रहीं; वे 1937 से 1939 तक ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बने और स्वतंत्रता के ठीक पूर्व 1946 में पुनः इसी पद पर आसीन हुए. 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने और संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश होने के पश्चात् वे स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और इस पद पर 1954 ई. तक रहे. ● मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बाद, उन्होंने 1955 से 1961 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में देश की सेवा की.
	● भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में उनका योगदान अविस्मरणीय है, जिसके परिणामस्वरूप 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया. उन्हीं के कार्यकाल के दौरान 26 जनवरी, 1950 को संविधान में हिन्दी सहित 14 भाषाओं को आधिकारिक सूची में शामिल किया गया था. ● राष्ट्र के प्रति उनकी निःस्वार्थ सेवा के सम्मान में उन्हें वर्ष 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से विभूषित किया गया. ● 7 मार्च, 1961 को गृह मंत्री के पद पर रहते हुए मस्तिष्क आघात के कारण 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया.
लाला हरदयाल (1884-1939 ई.) 	● प्रति वर्ष 4 मार्च को महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल की पुण्यतिथि मनाई जाती है. ● लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर, 1884 को दिल्ली में हुआ था. लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, वी.डी. सावरकर और मैडम कामा के सम्पर्क में आने के बाद उनके जीवन की दिशा पूर्णतः क्रांतिकारी हो गई. ● वर्ष 1911 में वे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुँचे, जहाँ उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संगठित करना शुरू किया. उन्होंने 1913 ई. में 'पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन' की नींव रखी, जो आगे चलकर 'गदर पार्टी' के रूप में विख्यात हुई. ● इस संगठन के महासचिव के रूप में उन्होंने 'युगांतर आश्रम' मुख्यालय से 'गदर' पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसके मुखपृष्ठ पर स्पष्ट रूप से 'अंग्रेजी राज का दुश्मन' अंकित होता था. ● प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाला हरदयाल और उनके साथियों, जैसे—सोहन सिंह भकना, ने सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई. हालाँकि, अमेरिकी सरकार द्वारा गिरफ्तारी और बाद में जर्मनी व स्वीडन प्रवास के कारण वे प्रत्यक्ष संघर्ष से दूर हो गए, लेकिन उनके द्वारा बोए गए क्रांतिकारी विचारों ने भविष्य में भगत सिंह जैसे राष्ट्रभक्तों को प्रेरित किया. लाला हरदयाल एक प्रखर लेखक भी थे, जिनकी 'द बोधिसत्व डॉक्ट्रिन' और 'सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिन्दू रेस' जैसी रचनाएँ उनके बौद्धिक कौशल को दर्शाती हैं. ● 4 मार्च, 1939 को फिलाडेल्फिया में उनका निधन हो गया.

ऐतिहासिक स्थल

कालिंजर दुर्ग

चर्चा में क्यों ?

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के आस-पास के पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल (National Geo-Heritage Site) घोषित किया है.



मुख्य तथ्य

● कालिंजर दुर्ग का इतिहास 1500 वर्षों से भी अधिक पुराना है. ऐतिहासिक दस्तावेजों और शिलालेखों के अनुसार, इसकी स्थापना गुप्त काल (4वीं-6वीं शताब्दी) के दौरान हुई थी.

● कालांतर में यह चंदेल राजवंश (9वीं-13वीं शताब्दी) के अधीन आया और उनकी राजधानियों में से एक बना. चंदेल शासकों के समय यह दुर्ग एक सैन्य किले के साथ-साथ एक प्रमुख धार्मिक केन्द्र के रूप में भी विकसित हुआ.

अतिरिक्तांक
प्रतियोगिता दर्पण
सामान्य अध्ययन
भारतीय इतिहास
Code 795 ₹ 170.00
संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षाओं हेतु
अन्य विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी
अन्य उपयोगी पुस्तकें
प्राचीन इतिहास Code 837 ₹ 175.00
मध्यकालीन इतिहास Code 838 ₹ 195.00
आधुनिक भारत Code 839 ₹ 255.00
प्रतियोगिता दर्पण • E-mail : sales@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

- महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूँ जैसे शासकों ने इस पर आक्रमण किए, परन्तु वे इसे जीतने में सफल नहीं हो सके. अन्ततः 1569 ई. में अकबर ने इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की और इसे बीरबल को उपहारस्वरूप दे दिया.
- बीरबल के पश्चात् यह किला बुंदेल राजा छत्रसाल और फिर पन्ना के हरदेव शाह के नियंत्रण में रहा, जिसके बाद 1812 ई. में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया.
- दुर्ग परिसर में मस्जिदों, महलों और बावड़ियों के साथ-साथ प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर भी स्थित है. चंदेल शासक परमादित्य देव द्वारा निर्मित इस मन्दिर में नीले पत्थर का शिवलिंग और 18 भुजाओं वाली एक विशाल प्रतिमा मुख्य आकर्षण हैं.

बलिराजगढ किला

चर्चा में क्यों ?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा बिहार के मधुबनी जिले में स्थित बलिराजगढ़ किला (प्राचीन गढ़ के अवशेष) में नए सिरे से वैज्ञानिक उत्खनन के लिए मंजूरी प्रदान करने के बाद यह चर्चा में बना हुआ है. पटना सर्कल के तहत् आने वाला यह स्थल बिहार के 71 राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों में से एक है.



मुख्य तथ्य

- ऐतिहासिक दृष्टि से यह किला लगभग 200 ई. पू. के शुंग काल का माना जाता है, हालाँकि साक्ष्यों से इसके लौह युग तक पुराने होने के संकेत मिलते हैं.
- पूर्व में किए गए उत्खनन से यहाँ निरन्तर मानव निवास के प्रमाण मिले हैं, जिनमें उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड (NBPW) चरण से लेकर शुंग, कुषाण, गुप्त और पाल काल (12वीं शताब्दी ईस्वी तक) के सांस्कृतिक अनुक्रम शामिल हैं.
- उल्लेखनीय है कि इस स्थल की पहचान सर्वप्रथम 1884 ई. में मधुबनी के तत्कालीन उप-विभागीय मजिस्ट्रेट जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने की थी. इसके बाद 1962-63, 1972-73 और 2013-14 में व्यवस्थित उत्खनन किए गए, हालाँकि अंतिम प्रयास को उच्च जल स्तर और पर्यावरणीय बाधाओं के कारण बीच में ही रोक दिया गया था.
- वर्तमान में मिल रही मंजूरी से उम्मीद है कि प्राचीन मिथिला की रक्षा प्रणाली और उसके प्रारम्भिक ऐतिहासिक से लेकर पूर्व मध्यकालीन इतिहास के अनछुए पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी.

होयसल मन्दिर

चर्चा में क्यों ?

कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 11वीं से 13वीं शताब्दी के कई प्रसिद्ध होयसल कालीन मंदिर अपनी जटिल सोपस्टोन की नक्काशी और विशिष्ट सितारा आकार की वास्तुकला के कारण चर्चा में रहे हैं.



मुख्य तथ्य

- होयसल वास्तुकला एक विशिष्ट मिश्रित शैली का प्रतिनिधित्व करती है जिसे अक्सर 'वेसर शैली' कहा जाता है, जो उत्तर भारतीय नागर और दक्षिण भारतीय द्रविड़ मंदिर स्थापत्य परम्पराओं के तत्वों का एक अनूठा मिश्रण है.
- होयसल वास्तुकारों ने निर्माण के लिए क्लोरिटिक शिस्ट या सोपस्टोन को प्राथमिकता दी, जो खदान से निकालते समय कोमल होता है, लेकिन समय के साथ कठोर हो जाता है.
- पत्थर की इसी लचीली प्रकृति के कारण पत्थर में आभूषण, नाखून और बालों की लटों जैसे सूक्ष्म विवरणों को उकेरने में सहजता हुई, जो देखने में सजीव प्रतीत होते हैं.
- इन मंदिरों की एक अन्य प्रमुख विशेषता इनका जगती या ऊँचा उठा हुआ मंच है, जो अक्सर तारे के आकार (Stellate) का होता है.
- मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को क्षैतिज पट्टियों में दर्शाया गया है. होयसल शिल्पकला में परिष्कार का स्तर इतना ऊँचा था कि कई शिल्पी अपनी कलाकृतियों पर अपने हस्ताक्षर भी अंकित करते थे, जो प्राचीन भारतीय कला के इतिहास में एक विरल उदाहरण है.

●●●

उपकार

हिन्दी साहित्य का तथ्यपरक अध्ययन

यू.जी.सी. नेट/जे.आर.एफ./सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, के.वी.एस., एन.वी.एस., डी.एस.एस.एस.बी., पी.जी.टी., टी.जी.टी., राजभाषा निदेशक, हिन्दी अधिकारी, संघ/राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं और विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए हिन्दी साहित्य की अनुपम पुस्तक

लेखक : ओंकार नाथ वर्मा



कोड 2129 ₹ 405/-

विभिन्न परीक्षाओं के विगत् 15 वर्ष के प्रश्नों का भी समावेश.

प्रमुख आकर्षण

➠ आदिकाल ➠ भक्तिकाल ➠ रीतिकाल आधुनिककाल ➠ नाटक ➠ निबंध ➠ कहानी ➠ उपन्यास ➠ आलोचना ➠ हिन्दी गद्य की अन्य विधाएँ ➠ हिन्दी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियाँ ➠ हिन्दी के पत्र और पत्रिकाएँ ➠ विविध

उपकार प्रकाशन, आगरा
• E-mail : sales@upkar.in
• Website : www.upkar.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएँ

ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रिक कुकिंग को अपनाना (Adopting Electric Cooking)

सुर्खियों में क्यों ?

ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध के बाद ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले अधिकांशतः जहाजों पर प्रतिबंध के कारण भारत सहित अन्य देशों में एलपीजी की कमी के कारण कुकिंग के वैकल्पिक साधनों पर चर्चा सुर्खियों में बनी हुई है.

- भारत खाना पकाने की गैस आयात पर सालाना लगभग 26·4 अरब डॉलर खर्च करता है, जिसका अधिकांश आयात हॉर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते होता है.
- उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार भारत में 332 मिलियन एलपीजी कनेक्शन हैं, फिर भी 37% परिवार अभी भी लकड़ी और गोबर का इस्तेमाल करते हैं.
- जानकारों का मानना है कि वर्तमान में उपलब्ध इलेक्ट्रिक कुकिंग साधनों से स्थिति में बदलाव आया है.

गैस कनेक्शन में वृद्धि व उपलब्धता में कठिनाई

- घरेलू एलपीजी कनेक्शन 2015 में 15 करोड़ से बढ़कर 2025 तक लगभग 33 करोड़ हो गए, लेकिन भारत अपनी एलपीजी का 60% और प्राकृतिक गैस का 50% आयात करता है. ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान (IEEFA) का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024-25 में संयुक्त आयात बिल 26·4 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो 6 वर्षों में 50% की वृद्धि दर्शाता है.
- पश्चिम एशिया में होने वाले किसी भी व्यवधान का सीधा असर भारतीय रसोई की कीमतों पर पड़ता है.

क्या लागत, दक्षता और रोजमर्रा के खाना पकाने के मामले में बिजली, गैस से बेहतर विकल्प है ?

- अक्टूबर 2025 में आईईईएफए द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में 4 लोगों के परिवार के लिए इलेक्ट्रिक कुकिंग बिना सब्सिडी वाली एलपीजी की तुलना में 37% और पाइप लाइन वाली प्राकृतिक गैस की तुलना में 14% सस्ती है. इस सम्बन्ध में केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत् मिलने वाले सब्सिडी युक्त सिलेण्डर ही इलेक्ट्रिक कुकिंग की अपेक्षा सस्ता पड़ता है. हालाँकि, इस सब्सिडी पर सरकारी खजाने से प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं.

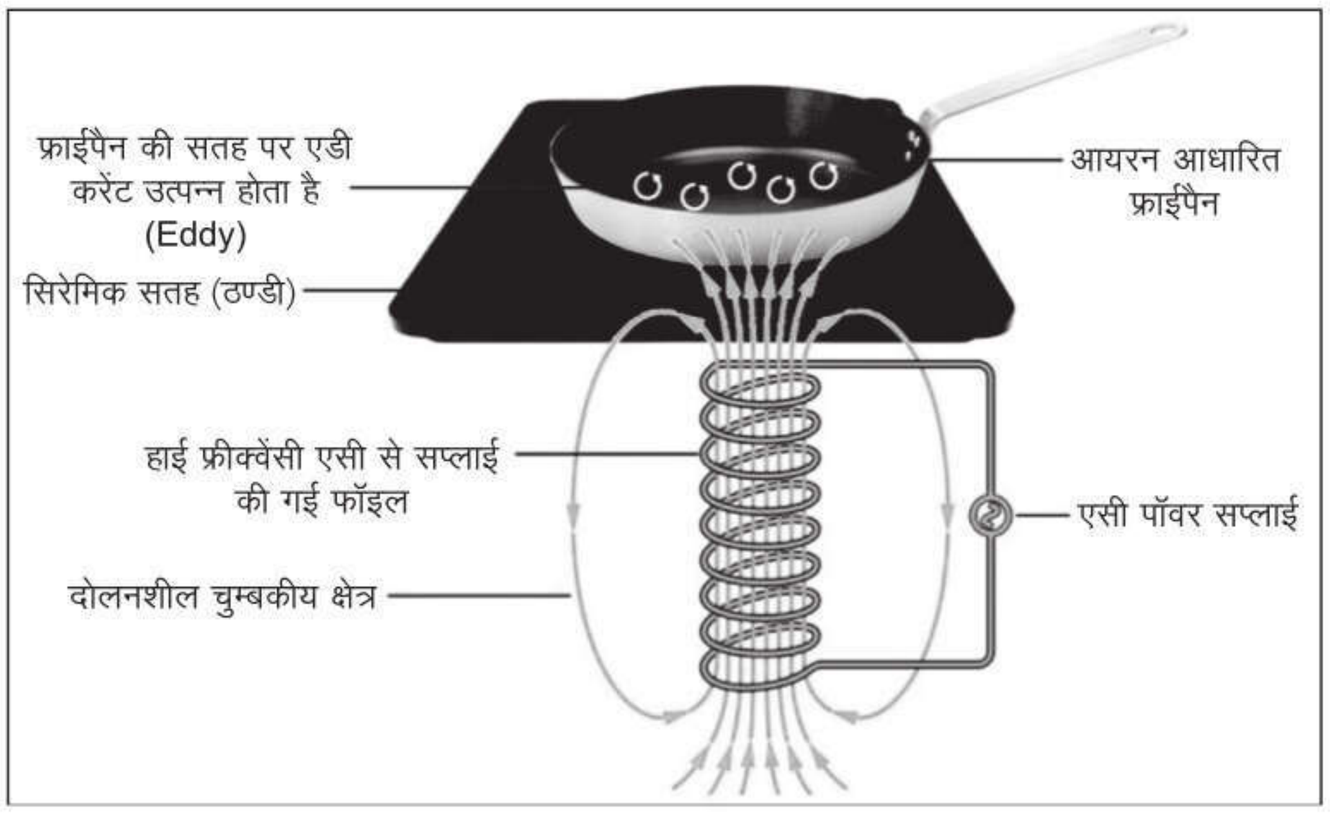
इंडक्शन कुकटॉप

- यह आधुनिक रसोई का एक विज्ञान-आधारित चमत्कार है. पारम्परिक गैस स्टोव के विपरीत, जो खुली लौ का उपयोग करते हैं, इंडक्शन विद्युत् चुम्बकत्व (Electromagnetism) के सिद्धान्त पर काम करता है. इसकी काँच की सतह के नीचे ताँबे की एक कुंडली (Coil) होती है, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा (AC) प्रवाहित होने पर एक तेजी से बदलता चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है.
- जब इस पर लोहे या स्टील जैसे फेरोमैग्नेटिक (Ferromagnetic) बर्तन रखे जाते हैं, तो फैराडे के प्रेरण नियम के अनुसार, बर्तन के तल में विद्युत् धाराएँ उत्पन्न होती हैं, जिन्हें एड़ी धाराएँ (Eddy Currents) कहा जाता है.

- दक्षता में अन्तर भी उतना ही स्पष्ट है. इंडक्शन कुकटॉप अपनी लगभग 85% ऊर्जा बर्तन में स्थानान्तरित करते हैं, जबकि एलपीजी बर्नर लगभग 40% ही स्थानान्तरित कर पाता है.
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आईईईएफए दोनों ही शहरी रसोई से शुरुआत करने की सलाह देते हैं, जिससे आयातित एलपीजी उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हो सकेगी जहाँ अभी भी बिजली या इससे सम्बन्धित वैकल्पिक कुकिंग साधनों की कमी है.
- उपर्युक्त तर्कों के सम्बन्ध में एक सवाल यह है कि अगर एक करोड़ शहरी रसोई प्रत्येक शाम को इंडक्शन कुकटॉप चालू कर दें, तो बिजली ग्रिड का क्या होगा ?

बिजली माँग में उतार-चढ़ाव

- दिनभर में बिजली की माँग में उतार-चढ़ाव होता रहता है. सामान्यतः दोपहर 3 बजे के आस-पास और फिर रात 9 से 11 बजे के बीच यह माँग बढ़ जाती है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि सभी घरों में एक ही समय पर लाइट, पंखे, टीवी और एसी चालू हो जाते हैं. इस अचानक वृद्धि को 'पीक' कहा जाता है.
- भारत की चरम माँग 2014 में 148 गीगावाट से बढ़कर दिसम्बर 2025 में रिकॉर्ड 242·5 गीगावाट हो गई. अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, औसत दैनिक तापमान में प्रत्येक डिग्री की वृद्धि के साथ, चरम माँग में अब 7 गीगावाट से अधिक की वृद्धि होती है.
- इस चरम माँग की पूर्ति के लिए किसी वितरण कम्पनी जैसे—(डिस्कॉम) के पास कुछ विकल्प होते हैं, जैसे—
- यह स्पॉट मार्केट से बिजली खरीद सकता है, आमतौर पर इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से, जहाँ सामान्य समय में



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

कीमतें ₹ 3·50 प्रति यूनिट से लेकर पीक टाइम में ₹ 9-10 तक पहुँच सकती हैं.

- यह महँगे गैस-आधारित पीकिंग प्लांट चालू कर सकता है या संगृहीत जलविद्युत् का उपयोग कर सकता है.
- यह ग्रिड-स्केल बैटरी भी संचालित कर सकता है—दिल्ली स्थित बीएसईएस राजधानी ने इसी प्रकार के ऊर्जा लाभ के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक बैटरी भण्डारण प्रणाली शुरू की है.
- अन्तिम उपाय के रूप में, यह नियोजित बिजली कटौती लागू कर सकता है, विभिन्न क्षेत्रों में बारी-बारी से ब्लैकआउट कर सकता है, जिसे लोड शेडिंग के रूप में जाना जाता है, जो आजीविका को बाधित करता है, औद्योगिक उत्पादन को नुकसान पहुँचाता है और नियामकों द्वारा इसे तेजी से दण्डित किया जा रहा है.
- उपलब्ध विकल्प के सम्बन्ध में पुनः प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रिक कुकिंग अपनाने पर जब शाम के पहले से व्यस्त समय में लाखों इंडक्शन कुकटॉप और जुड़ जाएँ तो इससे बिजली आपूर्ति संकट और बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति में बाजार में बिजली कीमतें बढ़ जाएंगी और बिजली कटौती का खतरा भी बढ़ जाएगा.
- सवाल यह नहीं है कि खाना पकाने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि ग्रिड पर अत्यधिक दबाव डाले बिना ऐसा कैसे किया जाए. यहीं पर स्वचालित माँग प्रतिक्रिया की भूमिका सामने आती है.

क्या स्मार्ट तकनीक इस माँग को सन्तुलित कर सकती है ?

- ओपनएडीआर (Open Automated Demand Response) एक दो-तरफा संचार मानक है, जो स्मार्ट थर्मोस्टेट्स, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर, वॉटर हीटर और कुकटॉप्स को माँग प्रतिक्रिया, सहायक सेवाओं (आवृत्ति/वोल्टेज) और डीईआर समन्वय में स्वचालित रूप से भाग लेने में सक्षम बनाता है. ये उपकरण बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी खपत को स्वचालित रूप से समायोजित कर सकते हैं.
- कैलिफोर्निया के 2002 के ऊर्जा संकट के बाद जन्मा, इसका नवीनतम संस्करण मानक वेब प्रोटोकॉल का उपयोग करके आधुनिक ऊर्जा प्रणालियों से जुड़ता है.
- भारत ने इसका उपयोग शुरू कर दिया है. टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ने देश का पहला ओपनएडीआर पायलट प्रोजेक्ट 167 वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर चलाया, जिसमें पीक वोल्टेज में औसतन 14% की कमी हासिल हुई. पायलट प्रोजेक्ट के एक अध्ययन में कहा गया है कि अगर इस तकनीक को भारत भर की इमारतों में लागू किया जाए, तो पीक वोल्टेज में लगभग 7% की कमी की जा सकती है.
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, दक्षिण कोरिया के ऑटोडीआर पायलट प्रोजेक्ट ने बिजली की खपत में 24% की कमी की; इस तरह के कार्यक्रम आमतौर पर नए ग्रिड बुनियादी ढाँचे की लागत को स्थगित करके 4 वर्षों के भीतर अपनी लागत की भरपाई कर लेते हैं.
- वितरण कम्पनियों के पास अभी भी सम्पूर्ण प्रणाली की कमी है—ओपनएडीआर-अनुरूप सर्वर, स्मार्ट मीटर-एम्बेडेड रिसीवर और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जो वितरित लोड को वर्चुअल पॉवर प्लांट में व्यवस्थित कर सकें.
- इस तरह का ढाँचा तैयार करना आवश्यक है, लेकिन यह समाधान का केवल आधा हिस्सा है. दूसरा आधा हिस्सा घरों को निष्क्रिय उपभोक्ताओं से सक्रिय ग्रिड भागीदार बनाने में निहित है, साथ ही ट्रांसफार्मर और फीडर बुनियादी ढाँचे में निवेश के माध्यम से घरेलू लोड क्षमता को 3 किलोवाट से 5 किलोवाट तक उन्नत करना भी आवश्यक है.

रूफटॉप सोलर पैनल का उपयोग

- एक छत पर लगा सौर पैनल और बैटरी का संयोजन किसी घर को 'प्रोसुमर' में बदल सकता है यानी, वह उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बन सकता है. सौर पैनल दिन में बिजली उत्पन्न करता है; बैटरी अतिरिक्त ऊर्जा संगृहीत करती है और उस संगृहीत ऊर्जा का उपयोग शाम को इंडक्शन कुकटॉप चलाने के लिए किया जा सकता है. यह बड़े पैमाने पर ई-कुकिंग से उत्पन्न होने वाली बिजली की खपत में अचानक वृद्धि को सन्तुलित करता है.
- ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय ग्रिड के 2025 के एक अध्ययन में कहा गया है कि जब आवासीय विद्युतीकरण को रूफटॉप सोलर, बैटरी और ऑफ-पीक शेड्यूलिंग के साथ जोड़ा जाता है, तो पीक लोड में आधी कमी और ग्रिड सुदृढ़ीकरण लागत में 75% की कमी आती है.
- भारत की रूफटॉप सोलर क्षमता 2026 में 24 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 41 गीगावाट से अधिक होने का अनुमान है, जिससे 'पीएम-सूर्य घर' योजना से बढ़ावा मिलेगा, जिसका उद्देश्य 10 मिलियन घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है.
- इसका वास्तविक प्रभाव तब सामने आता है जब अतिरिक्त सौर ऊर्जा को न केवल संगृहीत किया जाता है, बल्कि उसका व्यापार भी किया जाता है.
- पीयर-टू-पीयर (पी2पी) ऊर्जा व्यापार घरों को डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से पड़ोसियों को सीधे अतिरिक्त बिजली बेचने की अनुमति देता है, जिससे पारम्परिक वितरण कम्पनी के मार्ग को दरकिनार किया जा सकता है.
- भारत ने उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित नियामक सैंडबॉक्स के तहत् इण्डिया स्मार्ट ग्रिड फोरम और ऑस्ट्रेलिया की पावरलेजर के नेतृत्व में, लखनऊ में दक्षिण एशिया का पहला ब्लॉकचेन-आधारित पी2पी सौर ऊर्जा व्यापार पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया है. प्रोस्यूमर्स ने कीमतें निर्धारित कीं, वास्तविक समय में ट्रेडों पर नजर रखी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से लेन-देन का निपटान किया. इसका परिणाम यह हुआ कि खुदरा टैरिफ की तुलना में ऊर्जा खरीद मूल्य में 43% की कमी आई.
- न्यूयॉर्क के ऑल-इलेक्ट्रिक बिल्डिंग्स एक्ट के अनुसार, जनवरी 2026 से 7 मंजिलों से कम ऊँचाई वाली अधिकांश नई इमारतों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य है और 2029 से इससे ऊँची इमारतों को भी इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य है.
- भारत ने आधारभूत कार्य शुरू कर दिए हैं. 'गो इलेक्ट्रिक' अभियान और राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम का लक्ष्य 20 लाख इंडक्शन स्टोव उपलब्ध कराना है. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इंडक्शन हॉब्स के लिए स्टार लेबलिंग शुरू की है; पीएम-सूर्य घर योजना के तहत् छत पर सौर पैनल लगाने से घरेलू बचत को जोड़ा गया है, लेकिन एक व्यापक ढाँचा आवश्यक है: अनुमानित ₹ 40,000 करोड़ की वार्षिक एलपीजी सब्सिडी का एक हिस्सा इंडक्शन कुकटॉप के लिए एकमुश्त पूँजीगत सहायता के रूप में पुनर्निर्देशित किया जाए.
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के थोक खरीद मॉडल को ई-कुकिंग उपकरणों तक विस्तारित किया जाए. ई-कुकिंग के लिए समय-

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

आधारित टैरिफ अनिवार्य किया जाए और नए उपकरणों और स्मार्ट मीटरों में ओपन एडीआर की अनुकूलता अनिवार्य की जाए. भारतीय खाना पकाने के लिए डिजाइन की गई मल्टी-पॉट इंडक्शन तकनीक पर अनुसंधान एवं विकास के लिए निधि प्रदान की जाए और टियर-1 शहरों में नए आवासीय भवनों के लिए पूर्णतः विद्युत् निर्माण अनिवार्य किया जाए. इसकी तात्कालिकता भू-राजनीतिक होने के साथ-साथ आर्थिक भी है.

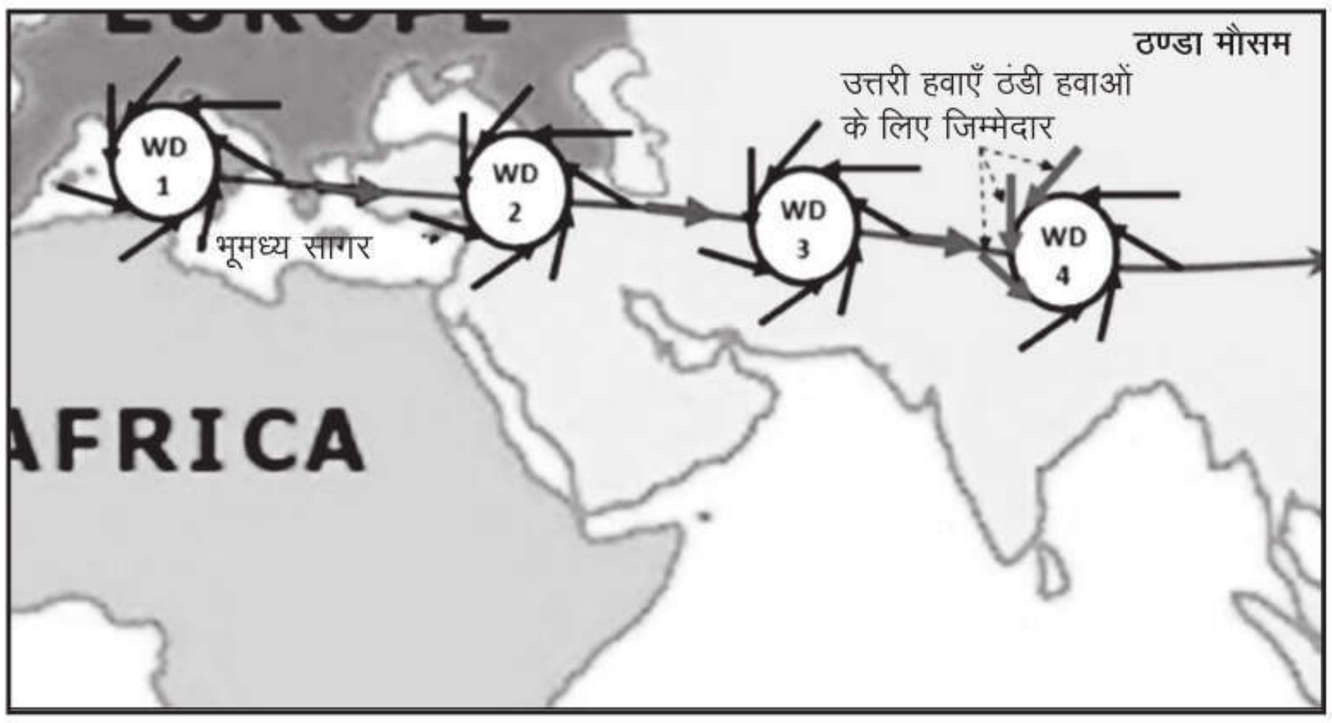
भूगोल

पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance

सुर्खियों में क्यों ?

इस वर्ष मार्च की शुरुआत असामान्य रूप से थोड़ा गर्म रही. हालाँकि, मार्च के तीसरे सप्ताह में गर्मी की जगह आँधी-तूफान, ओलावृष्टि और बारिश के कारण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन के पीछे के कारणों में पश्चिमी विक्षोभ को मुख्य कारक माना जा रहा है. उल्लेखनीय है कि पश्चिमी विक्षोभ के सन्दर्भ में एक परम्परागत दृष्टिकोण यह है कि ये मुख्य रूप से सर्दियों के दौरान आते हैं. हालाँकि, हालिया शोध और मौसम सम्बन्धी अवलोकन इसके सम्बन्ध में एक अधिक जटिल तस्वीर पेश करते हैं. हाल के वर्षों में, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सर्दियों के अन्त और गर्मियों के महीनों में भी देखा जा रहा है. यही कारण है मार्च के महीने में इस अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन के पीछे भी पश्चिमी विक्षोभ को मुख्य कारक माना जा रहा है.

- मार्च के दूसरे-तीसरे सप्ताह में आने वाले मौसम परिवर्तन को समझने के लिए, हमें सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ को समझना होगा. ये वर्षा लाने वाली पवन प्रणालियाँ हैं, जो अफगानिस्तान और ईरान से परे उत्पन्न होती हैं और भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर से नमी ग्रहण करते हुए पूर्व की ओर भारत की तरफ बढ़ती हैं. पिछले वर्ष नवम्बर से, भारत को प्रभावित करने वाली पश्चिमी विक्षोभ धाराओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में कमी आई थी, लेकिन यह प्रवृत्ति तब टूट गई जब दो लगातार, तीव्र पश्चिमी विक्षोभ (13 और 18 मार्च) उत्तर-पश्चिम, उत्तर और पूर्वी भारत से गुजरे.
- पश्चिमी हिमालय, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में भीषण मौसम का प्रकोप रहा, जिसमें आँधी, बिजली, ओलावृष्टि, कम समय में लेकिन तीव्र बारिश (24 घण्टे में 115 मिमी से अधिक) और हिमपात शामिल थे. पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले भीषण मौसम का सामना करना पड़ा था.
- 'भारतीय मौसम विज्ञान विभाग' (आईएमडी) के अधिकारियों ने इसका कारण न केवल पश्चिमी विक्षोभ बताया, बल्कि निचले क्षोभमण्डल में चक्रवाती परिसंचरण की लम्बे समय तक मौजूदगी को भी बताया. इसके अलावा, दक्षिण-



पश्चिम या दक्षिणी दिशा से चलने वाली तेज हवाओं ने बंगाल की खाड़ी से नमी को इस क्षेत्र में पहुँचाया. इससे मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत के क्षेत्रों में हवाओं का संगम हुआ. आईएमडी के मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि मार्च 2023 में भी इसी तरह का मौसम देखा गया था.

- मार्च के मध्य में मौसम सम्बन्धी कई कारकों के संयोजन से पूरे देश में ओलावृष्टि हुई. सबसे पहले, पश्चिमी विक्षोभ मानसून के महीनों (जून-सितम्बर) के दौरान उत्तर-पश्चिम, उत्तर, उत्तर-पूर्व और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश (और अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात) लाते हैं. यह स्थिति मार्च की शुरुआत में भी बनी रहती है, जब सर्दियों का प्रभाव अभी भी बना रहता है.
- मार्च ओलावृष्टि और गरज के साथ बारिश के लिए सबसे अनुकूल महीना होता है. मार्च के मध्य के बाद तापमान बढ़ने लगता है और अनुकूल मौसम की स्थिति में गरज, बिजली और भारी बारिश हो सकती है.
- पूर्वी भारत में, इस दौरान नॉरवेस्टर (पश्चिम बंगाल में कालबैसाखी) के नाम से जानी जाने वाली स्थानीय हवाएँ अचानक तीव्र तूफान, भारी बारिश और गरज के साथ तूफान का कारण बन सकती हैं.
- लू की लहर मूलतः किसी स्थान पर असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि होती है. इसलिए, लू घोषित करने की सीमा उस क्षेत्र में वर्ष के उस समय के दौरान सामान्य रूप से देखे जाने वाले तापमान पर निर्भर करती है.
- आईएमडी के अनुसार, लू की घोषणा तब की जाती है जब मैदानी क्षेत्रों में किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान कम-से-कम 40°C या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में कम-से-कम 30°C या उससे अधिक हो जाता है.
- सामान्य तापमान से विचलन के आधार पर, लू तब कहलाती है जब विचलन 4·5°C से 6·4°C के बीच होता है और भीषण लू तब घोषित की जाती है जब विचलन 6·4°C से अधिक होता है.

भारतीय कला एवं संस्कृति

जनजातीय आर्ट फेस्ट (Tribes Art Fest)

सुर्खियों में क्यों ?

ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 में 75 से अधिक आदिवासी कलाकार, 1,000 से अधिक कलाकृतियाँ और 30 कला परम्पराएँ एक मंच पर एकत्रित की गई हैं. इसका उद्घाटन 2 मार्च को त्रावणकोर पैलेस में केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा किया गया. यह आदिवासी उत्सव भारत की आदिवासी दृश्य संस्कृति के सबसे बड़े और केन्द्रित प्रदर्शनों में से एक है, जिसमें वारली, गोंड, भील, डोकरा, सोहराई, सौरा, बोडो और कोया जैसी परम्पराएँ और अन्य शामिल हैं.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

- हाल ही में आयोजित 'ट्राइब्स आर्ट फेस्ट' ने जनजातीय कला को केवल एक प्रदर्शन वस्तु से हटाकर एक संरचित बाजार पारिस्थितिकी तंत्र (Market Ecosystem) के रूप में स्थापित किया है. यह फेस्ट कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के अन्तर्सम्बन्धों को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है.
- यह फेस्ट कलाकारों को सीधे संग्राहकों, दीर्घाओं और डिजाइन संस्थानों से जोड़कर 'बिचौलियों' की भूमिका को समाप्त करता है. यह सांस्कृतिक विरासत को एक स्थायी आजीविका में बदलने का एक सफल मॉडल है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा को पुष्ट करता है.
- प्रदर्शनी में भारत की समृद्ध विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख कलाओं का प्रदर्शन किया गया.
- **मध्य भारत**—गोंड (म.प्र.), भील (म.प्र., राजस्थान, गुजरात), ओरांव (झारखण्ड, छत्तीसगढ़) और सोहराई कला (झारखण्ड).
- **पश्चिम भारत**—वारली कला (महाराष्ट्र)—जो प्रकृति और समुदाय के बीच आध्यात्मिक सम्बन्ध को दर्शाती है.
- **पूर्वी भारत**—डोकरा धातु शिल्प (ओडिशा, छत्तीसगढ़, प. बंगाल), सौरा चित्रकला (ओडिशा) और मधुबनी/गोदना (बिहार).
- **दक्षिण भारत**—कोया कला (तेलंगाना/आंध्र प्रदेश) और कुरुम्बा कला (तमिलनाडु).
- **उत्तर-पूर्व**—बोडो कला (असम) और बांस शिल्पकला.
- जनजातीय समुदायों में महिलाएँ 'सांस्कृतिक स्मृति की संरक्षक' रही हैं. मिट्टी की दीवारों को सजाने से लेकर कैनवास तक का सफर उनकी रचनात्मकता और नेतृत्व को दर्शाता है.
- **प्रोजेक्ट खुम**—त्रिपुरा की 'कोकबोरोक' भाषा में 'खुम' का अर्थ फूल है. यह सामूहिक कला निर्माण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है.
- कलाकार अब पारम्परिक रंगों (मिट्टी, पत्थर) के स्थान पर ऐक्रेलिक जैसे आधुनिक माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं, जो कला के समकालीन अनुकूलन (Modern Adaptation) को दर्शाता है. 12 दिवसीय इस कार्यक्रम में 'सतत् भविष्य' और 'बाजार सम्बन्ध' जैसे विषयों पर चर्चा ने जनजातीय कला के वैश्विक फलक पर विस्तार की नींव रखी है.

डिजिटल अधिकार एवं कानून

डिजिटल निर्वासन (Digital Exile)

सुर्खियों में क्यों ?

मार्च 2026 में, सोशल मीडिया अकाउंट्स के सस्पेंशन (निलम्बन) में अचानक आई तेजी ने भारत में डिजिटल अधिकार पर चर्चा को पुनः छेड़ दिया है. केन्द्र सरकार ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत् आपातकालीन ब्लॉकिंग आदेश जारी किए थे.

- डिजिटल सेंसरशिप के तहत् जब विशिष्ट URLs को हटाने के साथ-साथ व्यक्तियों से सम्बन्धित प्लेटफॉर्म को भी हटाया जाता है तो आलोचकों द्वारा इसे 'डिजिटल निर्वासन' का नाम दिया जाता है.
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल *बनाम* भारत संघ (2015) मामले में IT एक्ट की धारा 69A की संवैधानिकता को बरकरार रखा था, लेकिन उसने ऐसा सख्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की शर्त पर किया था; इन उपायों में तर्कसंगत और लिखित आदेशों की अनिवार्यता तथा प्रभावित पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार शामिल था.
- आलोचकों का मानना है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षा उपायों का सुचारु क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है. आलोचकों के अनुसार 2009 के ब्लॉकिंग नियमों के नियम 16 (जो ब्लॉकिंग की कार्यवाही के लिए सख्त गोपनीयता अनिवार्य करता है) के तहत् 'गोपनीय' सेंसरशिप व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है.
- उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, 2014 और 2021 के बीच, ब्लॉकिंग आदेशों की संख्या वार्षिक लगभग 470 से बढ़कर लगभग 9,800 तक पहुँच गई, और 2025-26 में 'सहयोग' प्लेटफॉर्म के कारण इसमें भारी उछाल देखा गया.
- यह प्लेटफॉर्म न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय (MeitY) को, बल्कि निचले स्तर के अधिकारियों और पुलिस विभागों को भी सामग्री हटाने (टेकडाउन) के आदेश जारी करने की अनुमति देता है.
- आलोचकों के अनुसार, यह विकेन्द्रीकरण उस विशेष निगरानी व्यवस्था को दरकिनार कर देता है, जिसका मूल उद्देश्य IT एक्ट के तहत् सुनिश्चित किया गया था.
- इसके अलावा, 2026 के संशोधन नियम मध्यस्थों (Intermediaries) के लिए 3 घण्टे में सामग्री हटाने का एक अनिवार्य आदेश लागू करते हैं. ऐसी कम समय-सीमाओं के कारण वास्तविक समीक्षा लगभग नामुमकिन हो जाती है, जिससे प्लेटफॉर्म्स को ऑटोमेटेड एल्गोरिद्म इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ता है.
- आलोचकों का तर्क है कि इन आदेशों की समीक्षा के लिए बना संस्थागत ढाँचा अभी भी पूरी तरह से कार्यपालिका के पक्ष में झुका हुआ है. ब्लॉकिंग के फैसलों पर नजर रखने वाली समीक्षा समिति में सिर्फ कार्यपालिका के सदस्य ही होते हैं.
- उल्लेखनीय है कि कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा हाल ही में इन आदेशों के खिलाफ दायर चुनौतियों को खारिज कर दिया था.
- डिजिटल निर्वासन पर आलोचकों का मानना है कि यह 'सहकारी नियमन' से हटकर 'कमांड-एण्ड-कंट्रोल' वाली डिजिटल शासन व्यवस्था को बढ़ावा देता है.
- तत्पश्चात् ऐसी व्यवस्था में नागरिक और मीडिया संस्थान डिजिटल सार्वजनिक मंच से हटाए जाने से बचने के लिए खुद ही अपनी बातों पर सेंसरशिप लगाने लगते हैं.
- राष्ट्रीय सुरक्षा और बोलने की आजादी के बीच सन्तुलन फिर से बनाने के लिए, भारत को एक 'आनुपातिकता ढाँचा' (Proportionality Framework) अपनाना होगा. इसमें सभी ब्लॉकिंग आदेशों के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक निगरानी वाली व्यवस्था की ओर बढ़ना शामिल है, जैसा कि यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम (Digital Services Act) में है.
- दूसरा पारदर्शिता के साथ सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन करते हुए उपयोगकर्ताओं को 'अपनी बात रखने का अधिकार' (Right to be Heard) सुनिश्चित करना, ये ऐसे जरूरी कदम हैं जिनसे यह विश्वास होगा कि डिजिटल अधिकार भारतीय लोकतंत्र की एक स्थायी विशेषता है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

न्यायपालिका एवं अधिकार

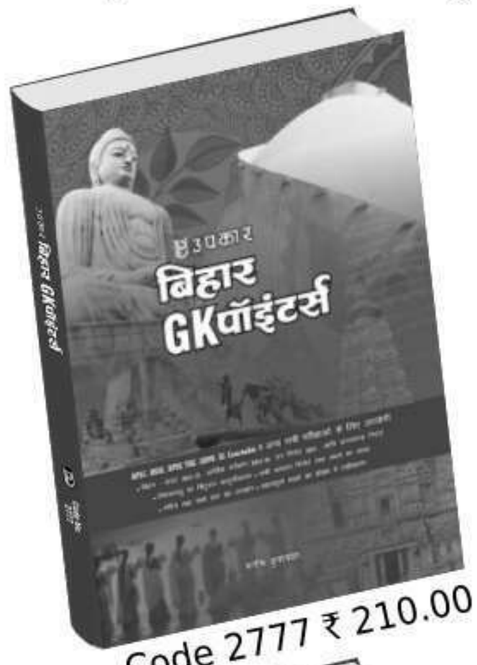
न्यायिक गरिमा और शैक्षणिक स्वतंत्रता (Judicial Dignity and Academic Freedom)

सुर्खियों में क्यों ?

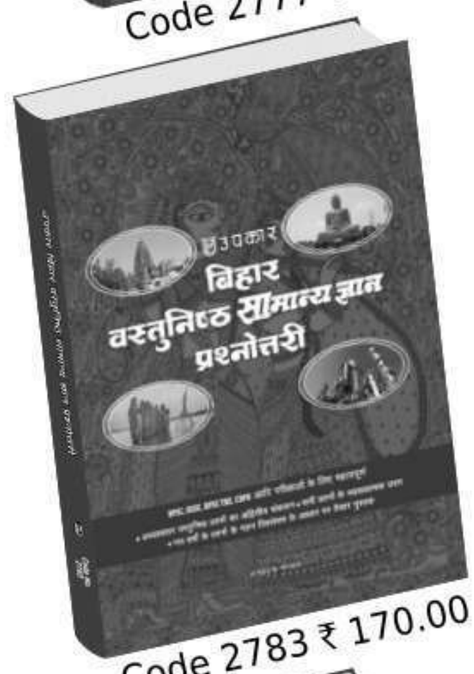
भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले दिनों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के कुछ अंशों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया. न्यायालय का यह आदेश मुख्य रूप से उन सन्दर्भों पर केन्द्रित था जिनमें न्यायिक विलम्ब और न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों का उल्लेख किया गया था. इस विषय ने भारतीय लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तम्भों न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा, नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [अनुच्छेद 19(1a)] और उचित प्रतिबन्ध [अनुच्छेद 19(2)] के मध्य सन्तुलन पर एक नई बहस को जन्म दिया है.

- न्यायिक प्रशासन और संवैधानिक मर्यादा के दृष्टिकोण से, न्यायपालिका की छवि और सार्वजनिक विश्वास उसकी कार्यप्रणाली के आधार स्तम्भ होते हैं.
- फरवरी 2026 के इस प्रकरण में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह मत व्यक्त किया कि पाठ्यपुस्तक में दी गई जानकारी 'चयनात्मक' (Selective) थी, जिससे संस्थान की प्रासंगिकता और गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी.
- न्यायालय का मानना था कि यदि शैक्षणिक सामग्री में केवल नकारात्मक पहलुओं को ही स्थान दिया जाता है और न्यायपालिका द्वारा किए गए सुधारों की अनदेखी की जाती है, जो युवा मस्तिष्क में संस्था के प्रति अविश्वास उत्पन्न कर सकता है.
- इसी आधार पर, न्यायालय ने न केवल पुस्तक के उन हिस्सों पर प्रतिबन्ध लगाया, बल्कि सामग्री तैयार करने वाले विशेषज्ञों की जवाबदेही भी तय करने का निर्देश दिया.
- संविधान के परिप्रेक्ष्य में, यह मुद्दा अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19(2) (उचित प्रतिबन्ध) के बीच के सूक्ष्म अन्तर को स्पष्ट करता है.
- जहाँ एक ओर नागरिकों को सूचना प्राप्त करने और रचनात्मक आलोचना करने का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर संविधान का अनुच्छेद 129 और 215 क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को 'अभिलेख न्यायालय' के रूप में अपनी अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति प्रदान करते हैं.
- न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत् ऐसी किसी भी सामग्री को प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप करती हो या न्यायालय की छवि को धूमिल करती हो.
- इस मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उसकी अन्तर्निहित शक्ति (Inherent Power) का हिस्सा माना जा सकता है.
- विधिक सिद्धान्तों के अनुसार, नरेश श्रीधर मिराजकर *बनाम* महाराष्ट्र राज्य (1966) जैसे ऐतिहासिक मामलों में यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक आदेशों का उद्देश्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना नहीं, बल्कि न्याय के प्रशासन को सुचारू बनाना होता है.
- वैश्विक स्तर पर भी, न्यायपालिका की पारदर्शिता के लिए विभिन्न मॉडल अपनाए गए हैं. उदाहरण के तौर पर, केन्या में 'न्यायिक लोकपाल' और 'प्रदर्शन प्रबंधन समितियों' के माध्यम से जनता के विश्वास में भारी वृद्धि देखी गई.
- भारत में भी, न्यायपालिका ने के. वीरास्वामी *बनाम* भारत संघ मामले में यह स्वीकार किया है कि न्यायाधीश 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' के तहत् 'लोक सेवक' की श्रेणी में आते हैं.
- यह दर्शाता है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली स्वयं सुधार और आत्म-निरीक्षण (Self-introspection) के प्रति सदैव तत्पर रही है.
- अतः एक जीवंत लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम सन्तुलित हो. जहाँ न्यायपालिका की कमियों, जैसे—'लम्बित मामले' और 'न्यायिक सुधार की आवश्यकता' पर चर्चा करना शैक्षणिक जागरूकता का हिस्सा है, वहीं यह भी अनिवार्य है कि छात्रों को न्यायपालिका द्वारा किए गए 'प्रगतिशील निर्णयों' और 'लोकहित याचिकाओं' (PIL) के माध्यम से समाज में आए सकारात्मक बदलावों से अवगत कराया जाए.
- लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि आलोचना तथ्यात्मक हो और उसका उद्देश्य संस्थान को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना हो. अंततः, एक जागरूक नागरिकता और एक सम्मानित न्यायपालिका ही संविधान की प्रस्तावना में निहित 'न्याय' के आदर्श को साकार कर सकते हैं. ●●●

बिहार सामान्य ज्ञान के लिए
उपकार प्रकाशन की उपयोगी पुस्तकें



Code 2777 ₹ 210.00



Code 2783 ₹ 170.00



Code 3096 ₹ 330.00



Code 3098 ₹ 165.00

उपकार प्रकाशन
• E-mail : sales@upkar.in • Website : www.upkar.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

रक्षा एवं प्रौद्योगिकी लेख

परिवर्तन के अनुकूल : नया युद्धक्षेत्र और भारतीय सशस्त्र बल

इक्कीसवी सदी में युद्ध का स्वरूप अभूतपूर्व गति से परिवर्तित हो रहा है. अब यह केवल पारम्परिक युद्धक्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज का युद्धक्षेत्र साइबर हमलों, बाह्य अन्तरिक्ष और संज्ञानात्मक क्षेत्र तक विस्तृत है. भविष्य के युद्ध केवल मानवशक्ति और टैंकों द्वारा नहीं, बल्कि क्वांटम आधारित संचार-सुरक्षा, स्वायत्त प्रणालियाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन, एन्टी-ड्रोन सिस्टम और निर्देशित ऊर्जा हथियारों, उपग्रह-नियंत्रित निगरानी-नेटवर्क आदि हथियारों से परिभाषित होंगे. भारत के लिए, जो जटिल सुरक्षा चुनौतियों से घिरा हुआ है, इस नए युद्ध युग की तैयारी रणनीतिक आवश्यकता होने के साथ-साथ अपनी तकनीकी और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को सिद्ध करने का अवसर भी है.

युद्ध का बदलता स्वरूप

आधुनिक युद्धक्षेत्र बहुआयामी हो गया है. पारम्परिक सैन्य शक्ति के मानक—संख्या, तोपखाना और बख्तरबंद डिवीजन अब रणनीतिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. आज संघर्षों का परिणाम सूचना, साइबर नेटवर्क और स्वायत्त प्रणालियों पर नियंत्रण से निर्धारित होता है. हाइब्रिड युद्ध, जिसमें पारम्परिक बलों, साइबर हमलों, भ्रामक सूचना अभियानों और आर्थिक दबाव का एक साथ उपयोग होता है, वैश्विक स्तर पर प्रमुख खतरे के रूप में उभरा है.

भारत का रणनीतिक वातावरण ऐसी शक्ति की माँग करता है जो सभी क्षेत्रों में संचालन करने में सक्षम हो. एआई-सक्षम निगरानी प्रणाली नेटवर्क कमाण्ड-एण्ड-कन्ट्रोल संरचनाएँ और स्वायत्त हथियार प्लेटफॉर्म को अपनाना अब आवश्यक हो गया है. वर्तमान युद्ध का मुख्य ध्येय मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स पर है, जहाँ भूमि, समुद्र, वायु, अन्तरिक्ष और साइबर क्षमताएँ मिलकर सटीक और तेज प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती हैं.

रक्षा में आत्मनिर्भरता : निर्भरता से आत्मविश्वास की ओर

भारत का रक्षा रूपान्तरण आत्मनिर्भरता (Aatmanirbharta) के लक्ष्य से अविभाज्य है. पिछले दशक में सरकार ने घरेलू डिजाइन, विकास और उन्नत रक्षा प्रणालियों के उत्पादन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है. इसे स्वदेशी खरीद और नवाचार के लिए बढ़ते आवंटनों द्वारा समर्थन प्राप्त है.

घरेलू स्रोतों से रक्षा पूँजीगत अधिग्रहण ₹ 74,000 करोड़ (FY 2021-22) से बढ़कर ₹ 1·2 लाख करोड़ (FY 2024-25) हो गया है, जो केवल सांख्यिकीय बदलाव नहीं, बल्कि "निर्भरता से आत्मविश्वास की मानसिकता में बदलाव" को दर्शाता है.

इसके अलावा, भारत की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत् वार्षिक रक्षा खरीद का 25% सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए आरक्षित किया गया है, और 350 से अधिक वस्तुओं को उनके लिए नामित किया गया है.

यह दृष्टिकोण एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करता है, जहाँ स्टार्टअप, MSMEs और सार्वजनिक एवं निजी उद्यम मिलकर उन्नत रक्षा तकनीकों का उत्पादन करते हैं. यह बदलाव दर्शाता है कि भारत की रक्षा में आत्मनिर्भरता सिर्फ कथन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आन्दोलन, नीति से क्रियान्वयन और नवाचार से प्रभाव में परिवर्तित हो रही है.

iDEX और रक्षा नवाचार का उदय

इनोवेशन्स फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) पहल भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को सशस्त्र बलों की तकनीकी आवश्यकताओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण रही है. 2018 में इसकी शुरुआत के बाद से 650 से अधिक iDEX विजेता उभरे हैं, और उनके प्रोटोटाइप की खरीदारी ₹ 3,000 करोड़ से अधिक सुनिश्चित की गई है. यह रक्षा तैयारी के लिए उद्यमशील प्रतिभा का लाभ उठाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

रक्षा मंत्रालय स्टार्टअप्स को उच्च लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है. भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स होने के साथ, अब लक्ष्य है देश का पहला रक्षा यूनीकॉर्न बनाना—एक ऐसा मील का पत्थर जो भारत की स्वदेशी नवाचार क्षमता और उन्नत सैन्य तकनीकों के पैमाने पर उत्पादन को दर्शाए. ये उपाय सरकार की

सम्बन्धित लेख को इस आकर्षक वीडियो के द्वारा संक्षेप में समझें

QR कोड को स्कैन करें

रणनीति को दर्शाते हैं, जो तकनीकी रूप से सशक्त और नवाचार-संचालित रक्षा क्षेत्र का निर्माण कर रही है.

तकनीकी श्रेष्ठता: भविष्य का युद्धक्षेत्र

उभरती तकनीकें भारत की सैन्य आधुनिकीकरण का केन्द्र हैं—

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग**—एआई को इंटेलिजेंस, निगरानी, खोज, लॉजिस्टिक्स और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में एकीकृत किया जा रहा है. नेटवर्क प्रणाली रीयल-टाइम खतरा मूल्यांकन और ऑपरेशनल निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं.
- **स्वायत्त प्रणाली और ड्रोन**—मानव रहित वायु और जल वाहन, साथ ही ड्रोन स्वार्म्स, निगरानी और लड़ाकू रणनीतियों को बदल रहे हैं.
- **साइबर और अन्तरिक्ष क्षमताएँ**— रक्षा साइबर एजेंसी और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी भारत की डिजिटल और अन्तरिक्ष सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाते हैं.
- **क्वान्टम कम्प्यूटिंग और निर्देशित ऊर्जा हथियार**—ये तकनीकें सुरक्षित संचार, एन्क्रिप्शन और सटीक हमले में नई उपलब्धियों का वादा करती हैं.

सामूहिक रूप से, ये क्षमताएँ सशस्त्र बलों को सूचना में श्रेष्ठता, तेज प्रतिक्रिया और ऑपरेशनल सटीकता प्रदान करती हैं,



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

जो आधुनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हैं.

रक्षा उत्पादन और निर्यात : क्षमता का प्रदर्शन

भारत के रक्षा औद्योगिक क्षेत्र ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्ज की हैं. घरेलू रक्षा उत्पादन ₹ 1·5 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जबकि निर्यात ₹ 23,000 करोड़ से अधिक रहा, जो राष्ट्रीय आत्मविश्वास और वैश्विक मान्यता दोनों को दर्शाता है. प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) और रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS) जैसी पहलें नवप्रवर्तकों को वित्तीय सहायता, परीक्षण सुविधाओं तक पहुँच और सुनिश्चित खरीद प्रदान करती हैं.

रक्षा खरीद नियमावली, 2025 (DPM-2025) अब 5 वर्षों के ऑर्डर (जिसे 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है) की गारंटी देता है, जो नवप्रवर्तकों को पूर्वानुमान और पारम्परिक रक्षा उद्यमिता से जुड़े जोखिमों में कमी प्रदान करता है. ये सुधार यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत की रक्षा पारिस्थितिकी नीति-प्रधान दृष्टिकोण से नवाचार-संचालित औद्योगिक आन्दोलन की ओर विकसित हो.

संगठनात्मक सुधार और थिएटर कमांड

तकनीकी आधुनिकीकरण के साथ-साथ, भारत ने संचालनात्मक तत्परता सुधारने के लिए संरचनात्मक सुधार शुरू किए हैं. चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (CDS) और सैन्य मामलों का विभाग (DMA) की स्थापना से सेना, नौसेना और वायु सेना में संयुक्तता बढ़ी है, जिससे सामंजस्यपूर्ण योजना, संसाधन अनुकूलन और त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलती है.

थिएटर कमांड्स को लागू करने के प्रयास यह दर्शाते हैं कि आधुनिक युद्ध भौगोलिक और कार्यात्मक क्षेत्रों में समेकित संचालन की माँग करता है. ऐसे सुधार भारत की रणनीतिक लचीलापन और संचालनात्मक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे बल परम्परागत और असमान खतरों दोनों पर तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं.

मानव संसाधन और कौशल विकास

तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन सैन्य-कर्मी किसी भी सेना का आधार होते हैं. भारत के सशस्त्र बल उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश कर रहे हैं, जो AI, साइबर संचालन और बहु-डोमेन युद्ध पर केन्द्रित हैं. सिमुलेशन आधारित अभ्यास, वर्चुअल रियलिटी और डेटा एनालिटिक्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल किए जा रहे हैं.

इसके अतिरिक्त, अग्निपथ जैसी पहलें तकनीकी रूप से कुशल, चुस्त और अनुशासित बल तैयार करने का लक्ष्य रखती हैं, जो तकनीकी रूप से गहन वातावरण में काम करने में सक्षम हों. महिलाओं की युद्ध और नेतृत्व भूमिकाओं में भागीदारी संचालनात्मक क्षमता को और मजबूत करती है और आधुनिक, समावेशी सैन्य संस्कृति को दर्शाती है.

रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक जुड़ाव

रक्षा में आत्मनिर्भरता का अर्थ अलगाव नहीं है. भारत रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है और मित्र राष्ट्रों के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग ले रहा है, ताकि अन्तर-संचालन क्षमता मजबूत हो सके. सागरीय सुरक्षा, रक्षा कूटनीति और तकनीकी सहयोग जैसी पहलें भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाती हैं और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विश्वास स्थापित करती हैं.

यह आत्मनिर्भरता और वैश्विक जुड़ाव का सन्तुलन सुनिश्चित करता है कि भारत स्वतंत्र रूप से अपने हितों की सुरक्षा कर सके और क्षेत्रीय व वैश्विक स्थिरता में योगदान दे सके.

चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा

उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं. भारत को उन्नत प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता और क्वान्टम तकनीकों के विकास को तेज करना होगा. नौकरशाही बाधाएँ, लम्बी परीक्षण अवधि और उच्च-स्तरीय अनुसंधान अवसंरचना तक सीमित निजी क्षेत्र की पहुँच अपनाने की गति को धीमा करती है.

साथ ही, तकनीकी परिष्कार और मानव अनुकूलन क्षमता के बीच सन्तुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है. मानसिक लचीलापन, नेतृत्व प्रशिक्षण और संज्ञानात्मक युद्ध कौशल में निवेश नए हथियारों की तरह ही भविष्य के संघर्षों के लिए सेना को तैयार करने में महत्वपूर्ण होंगे.

भविष्य-तैयार बल की ओर

भारत का सशस्त्र बलों के लिए दृष्टिकोण स्पष्ट है—एक तकनीकी रूप से उन्नत, चुस्त और आत्मनिर्भर बल तैयार करना, जो सभी डोमेन में सम्भावित खतरों का सामना करने में सक्षम हो. इसके लिए आवश्यक है—

- स्वदेशी R&D और उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि.
- AI, स्वायत्त प्रणालियों और नेटवर्केड संचालन का एकीकरण.
- संयुक्तता और थिएटर आधारित कमांड संरचनाओं को सुनिश्चित करना.
- मानव संसाधन, समावेशी नेतृत्व और कौशल विकास में निवेश.
- स्टार्टअप्स, MSMEs और अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना.

ये तत्व मिलकर भारत के सशस्त्र बलों को दक्ष, लचीला और अनुकूलनीय सैन्य शक्ति बनाएंगे, जो भविष्य के जटिल संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार होंगे.

साराशंतः युद्धभूमि बदल गई है, लेकिन भारत की सम्प्रभुता की रक्षा करने की दृढ़ता नहीं बदली है. iDEX के तहत् स्वदेशी रक्षा नवाचार से लेकर रिकॉर्ड उत्पादन और निर्यात तक, सशस्त्र बल बहु-डोमेन युद्ध के नए मॉडल को अपनाने लगे हैं. निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर यह परिवर्तन एक रणनीतिक जागरूकता को दर्शाता है, जिसमें तकनीकी आत्मनिर्भरता, संचालनात्मक चुस्ती और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता शामिल हैं.

भारत के सैनिक, गतिशील रक्षा उद्योग और नवाचारी युवाओं के समर्थन से, आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं. जैसे-जैसे एल्गोरिदम, AI, स्वायत्त प्रणालियाँ और अत्याधुनिक तकनीकें युद्ध के स्वरूप को पुनर्परिभाषित कर रही हैं, भारतीय सशस्त्र बल त्वरित रूप से अनुकूलित हो रहे हैं, जिससे राष्ट्र सुरक्षित, लचीला और रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहे.

●●●



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

रचनात्मक अर्थव्यवस्था का उदय : नवाचार और रूपान्तरण

—मनीष कुशवाहा

संक्षिप्त विवरण—रचनात्मक अर्थ-व्यवस्था आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था का तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें मूल्य मुख्यतः रचनात्मकता, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और बौद्धिक सम्पदा से उत्पन्न होता है. भारत में यह क्षेत्र मीडिया और मनोरंजन, एनीमेशन, गेमिंग, डिजाइन, डिजिटल कंटेन्ट, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक उद्योगों के माध्यम से तेजी से विस्तार कर रहा है. वर्तमान में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 30 बिलियन डॉलर आँका गया है. भारत सरकार डिजिटल इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया, स्किल इण्डिया जैसी पहलों के साथ-साथ WAVES 2025, AVGC-XR को बढ़ावा, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) की स्थापना, आईटी नियम 2021 और हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम जैसी नीतियों के माध्यम से इस क्षेत्र को मजबूत कर रही है. हालाँकि, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का उल्लंघन, वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, कौशल प्रशिक्षण की कमी और बाजार तक सीमित पहुँच जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं. इसके बावजूद रचनात्मक अर्थव्यवस्था रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

भारत का 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना आर्थिक विस्तार के लिए नवाचार-उन्मुख दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ा हुआ है. इस लक्ष्य को पाने में भारत सरकार रचनात्मक उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है, जिससे रचनात्मक अर्थव्यवस्था का महत्व तेजी से बढ़ रहा है. भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा और हस्तशिल्प ने इस क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है. भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार लगभग 30 बिलियन डॉलर है और इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है.

पृष्ठभूमि

इक्कीसवीं सदी में रचनात्मकता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है. आर्थिक शक्ति का मापन अब केवल कारखानों और माल ढुलाई मार्गों से नहीं, बल्कि बौद्धिक सम्पदा, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सांस्कृतिक प्रभाव से किया जाता है. विचार वस्तुओं से भी अधिक तेजी से फैलते हैं, कथाएँ बाजारों को प्रभावित करती हैं और रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से यह निर्धारित कर रहे हैं कि राष्ट्रों को वैश्विक स्तर पर कैसे देखा, सुना और उनके साथ साझेदारी की जाती है. इस परिवेश में, रचनात्मक अर्थव्यवस्था विकास और रणनीतिक उपस्थिति के एक निर्णायक क्षेत्र के रूप में उभरी है. सरकार ने संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थानों की स्थापना कर सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया. भारतीय फिल्म उद्योग और दूरदर्शन के विस्तार ने भी रचनात्मक उद्योगों को मजबूत आधार प्रदान किया.

विशेष रूप से वर्ष 2000 के बाद डिजिटल क्रांति के साथ रचनात्मक अर्थव्यवस्था में तेजी से विस्तार हुआ. इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के प्रसार ने डिजिटल कन्टेंट, एनीमेशन, गेमिंग और ऑनलाइन मीडिया जैसे नए क्षेत्रों को बढ़ावा दिया. सरकार की डिजिटल इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया और स्किल इण्डिया जैसी पहलों ने युवाओं को रचनात्मक क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता के लिए प्रेरित किया. हाल के वर्षों में ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया और गेमिंग उद्योग के विकास ने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है, जिससे यह क्षेत्र रोजगार और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत बनता जा रहा है.

रचनात्मक (क्रिएटिव) अर्थव्यवस्था क्या है ?

रचनात्मक अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत वे उद्योग शामिल हैं, जो मूल रूप से रचनात्मकता, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और बौद्धिक सम्पदा आदि पर आधारित हैं. इसमें मीडिया और मनोरंजन, एनिमेशन और दृश्य प्रभाव, गेमिंग, लाइव सांस्कृतिक अनुभव और व्यापक स्तर पर सीमाओं के पार संचालित होने वाले डिजिटल सामग्री प्लेटफॉर्म शामिल हैं. ये केवल हाशिए पर मौजूद सांस्कृतिक गतिविधियाँ नहीं हैं, बल्कि प्रौद्योगिकी-

सम्बन्धित लेख को इस आकर्षक वीडियो के द्वारा संक्षेप में समझें

QR कोड को स्कैन करें

प्रधान, वैश्विक स्तर पर व्यापार योग्य क्षेत्र हैं जो आधुनिक सेवा अर्थव्यवस्थाओं और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य शृंखलाओं में अन्तर्निहित हैं. वैश्विक स्तर पर, रचनात्मक उद्योग सांस्कृतिक हाशिये से निकलकर आर्थिक मुख्यधारा में आ गए हैं. विभिन्न देशों में, इनका योगदान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2 से लेकर 7 प्रतिशत से अधिक तक है और लाइव मनोरंजन से पर्यटन और शहरी सेवाओं पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. इस वैश्विक परिवर्तन के सन्दर्भ में, भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था विकास, रोजगार और मूल्य सृजन के एक प्रमुख स्तम्भ के रूप में उभर रही है.

रचनात्मक अर्थव्यवथा का व्यापक स्वरूप—मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का मूल्य 2024 में लगभग 2·5 ट्रिलियन था. डिजिटल मीडिया इस क्षेत्र के राजस्व का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है, जो उत्पादन और वितरण मॉडल को नया आकार दे रहा है. उच्च विकास वाले क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहे हैं—

- **एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स**—लगभग 103 बिलियन.
- **गेमिंग**—लगभग 232 बिलियन.
- **लाइव मनोरंजन**—लगभग 100 बिलियन से अधिक
- यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का समर्थन करता है.
- वार्षिक उत्पादन लगभग ₹ 3 लाख करोड़ है.

वर्तमान स्थिति—विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WEO) द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इण्डेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर पहुँच गया है. पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) में भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है, भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र लगातार विस्तार के पथ पर अग्रसर है, और अनुमान है कि 2027 तक राजस्व में सालाना लगभग

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

7 प्रतिशत की वृद्धि होगी. कुल क्षेत्र का आकार 2024 में 2,502 बिलियन से बढ़कर 2027 में 3,067 बिलियन होने का अनुमान है, जो सेवा अर्थव्यवस्था के भीतर एक टिकाऊ विकास इंजन के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है.

रचनात्मक अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र

- **मीडिया और मनोरंजन उद्योग**—फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, लाइव संगीत, नृत्य, थिएटर और सर्कस जैसे क्षेत्र रचनात्मक उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी, जिन्हें सामूहिक रूप से AVGC-XR कहा जाता है, रचनात्मक अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्र है.
- **सांस्कृतिक और विरासत आधारित क्षेत्र**—इसमें पुरातात्विक स्थल, संग्रहालय, पुस्तकालय और प्रदर्शनियाँ शामिल होती हैं, जो किसी देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करती हैं.
- **कला और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ**—इसमें पारम्परिक कला, शिल्प, त्योहार तथा लोक संस्कृति से जुड़ी गतिविधियाँ आती हैं, जो समाज की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती हैं.
- **डिजिटल और नई मीडिया गतिविधियाँ**—इसमें सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम, डिजिटल कन्टेंट और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं. गेमिंग भारत के डिजिटल परिवर्तन की सबसे प्रमुख अभिव्यक्तियों में से एक बन गया है.
- **डिजाइन और रचनात्मक सेवाएँ**—फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, आभूषण निर्माण, विज्ञापन तथा रचनात्मक अनुसंधान और विकास इसके अन्तर्गत आते हैं.
- **प्रकाशन और दृश्य कला**—इसमें पुस्तक प्रकाशन, प्रेस, अन्य प्रकाशन गतिविधियाँ तथा पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी जैसी दृश्य कलाएँ शामिल हैं.

विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन **शिखर सम्मेलन (वेव्स) 2025** का आयोजन प्रधानमंत्री के भारत को कंटेन्ट निर्माण के वैश्विक केन्द्र बनाने के विजन के अनुरूप था. वेव्स का प्रमुख उद्देश्य कंटेन्ट, रचनात्मकता और संस्कृति को आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव के संरचित इंजन में एकीकृत करके भारत की ऑरेंज अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था.

रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लाभ

- **रोजगार के नए अवसरों का सृजन**—रचनात्मक अर्थव्यवस्था कला, संगीत, फिल्म, डिजाइन, मीडिया, एनीमेशन, गेमिंग और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है. इससे विशेष रूप से युवाओं और कलाकारों को रोजगार मिलता है.
  उदाहरण—भारत की फिल्म और ओटीटी इण्डस्ट्री (जैसे—वेब सीरीज और डिजिटल कंटेन्ट) ने हजारों लोगों को रोजगार दिया है.
- **आर्थिक विकास में योगदान**—रचनात्मक उद्योग किसी भी देश की जीडीपी और आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये उद्योग निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा भी अर्जित करते हैं.
  उदाहरण—भारत का हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग (जैसे—बनारसी साड़ी, कश्मीरी शॉल) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात होकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं.
- **नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा**—रचनात्मक अर्थव्यवस्था नए विचारों, तकनीकी नवाचार और डिजिटल विकास को प्रोत्साहित करती है. इससे नए उत्पाद और सेवाएँ विकसित होती हैं.
  उदाहरण—भारत में गेमिंग और एनीमेशन उद्योग में नई तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है.
- **सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रसार**—रचनात्मक उद्योगों के माध्यम से किसी देश की संस्कृति, परम्पराओं और कला का संरक्षण और प्रचार होता है. इससे सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है.
  उदाहरण—भारत के शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत और हस्तशिल्प को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है.
- **पर्यटन को बढ़ावा**—रचनात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ पर्यटन उद्योग को भी प्रोत्साहित करती हैं. कला, त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ऐतिहासिक विरासत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.
  उदाहरण—जयपुर साहित्य महोत्सव और खजुराहो नृत्य महोत्सव जैसे कार्यक्रमों से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है.

रचनात्मक अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **बौद्धिक सम्पदा अधिकार का उल्लंघन**— रचनात्मक अर्थव्यवस्था का आधार कलाकारों और रचनाकारों की मौलिक कृतियाँ होती हैं, लेकिन अक्सर इन कृतियों की नकल, पायरेसी और अवैध उपयोग देखने को मिलता है, जिससे रचनाकारों को आर्थिक नुकसान होता है.
  उदाहरण—भारत में फिल्मों और संगीत की ऑनलाइन पायरेसी एक बड़ी समस्या है. कई नई फिल्में रिलीज होते ही अवैध वेबसाइटों पर उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे फिल्म निर्माताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.
- **वित्तीय संसाधनों और निवेश की कमी**—रचनात्मक उद्योगों में कई बार कलाकारों, डिजाइनरों और स्टार्टअप्स को पर्याप्त वित्तीय सहायता और निवेश नहीं मिल पाता. इससे नए विचारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने में कठिनाई होती है.
  उदाहरण—भारत में कई हस्तशिल्प कलाकार और लोक कलाकार आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक नहीं पहुँचा पाते.
- **तकनीकी परिवर्तन और बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा**—डिजिटल तकनीक और इंटरनेट के विकास ने रचनात्मक उद्योगों में अवसर बढ़ाए हैं, लेकिन इसके साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है. स्थानीय कलाकारों को अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों और प्लेटफॉर्मों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है.
  उदाहरण—भारतीय एनीमेशन और गेमिंग उद्योग को अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की उन्नत तकनीक और बड़े बजट वाले प्रोजेक्ट्स से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है.
- **कौशल और प्रशिक्षण की कमी**—रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता के लिए विशेष कौशल, तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है. लेकिन कई देशों में इन क्षेत्रों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण संस्थान और अवसर उपलब्ध नहीं हैं.
  उदाहरण—भारत में कई युवा फिल्म, एनीमेशन, डिजाइन और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, लेकिन उन्हें उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण और संसाधन आसानी से नहीं मिल पाते.
- **बाजार तक सीमित पहुँच**—कई रचनाकार और छोटे उद्यम अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने में असफल रहते हैं. उचित विपणन और वितरण प्रणाली की कमी उनके विकास में बाधा बनती है.
  उदाहरण—भारत के वाराणसी के बुनकर और कारीगर उत्कृष्ट बनारसी साड़ी बनाते हैं, लेकिन कई बार उन्हें उचित बाजार और सही मूल्य नहीं मिल पाता.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

भारत सरकार के प्रयास

- विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स 2025), का आयोजन भारत को कंटेन्ट निर्माण के वैश्विक केन्द्र बनाने के विजन के अनुरूप था. वेव्स का प्रमुख उद्देश्य कंटेन्ट, रचनात्मकता और संस्कृति को आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव के संरचित इंजन में एकीकृत करके भारत की ऑरेंज अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था.
- वेव एक्स , एम एण्ड ई क्षेत्र में स्टार्टअप-नेतृत्व वाले नवाचार के लिए प्लेटफॉर्म है. इसमें दो दिन का लाइव पिचिंग कार्यक्रम शामिल था, जहाँ स्टार्टअप्स ने निवेशकों के सामने अपने विचार प्रस्तुत किये. इसने 30 स्टार्टअप्स को उद्योग के नेताओं के सामने अपने विचार/प्रदर्शन रखने का अवसर दिया और स्टार्टअप पवेलियन में 100 से अधिक स्टार्टअप्स के प्रदर्शन की सुविधा प्रदान की.
- वेव्स बाजार स्क्रिप्ट्स, संगीत, कॉमिक्स और एवी अधिकारों के लिए एक मार्केटप्लेस के रूप में कार्य करता है, जिससे रचनाकारों के लिए नए राजस्व स्रोत बनते हैं. चार महाद्वीपों में 10 से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भागीदारी के माध्यम से, वेव्स बाजार ने बी2बी बैठकों की सुविधा दी.
- भारत में निर्माण प्रतियोगिता (सीआईसी) से एनीमेशन, गेमिंग, एआर/वीआर और संगीत जैसी 33 रचनात्मक श्रेणियों में अगली पीढ़ी की रचनात्मक प्रतिभाओं की राष्ट्रीय स्तर पर खोज की जाती है. इसमें दुनिया भर के रचनाकारों के 1 लाख से अधिक पंजीकरण आए.
- भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) कौशल विकास और नवाचार को संस्थागत रूप देने के लिए, सरकार ने मुम्बई में आईआईसीटी की स्थापना एवीजीसी-एक्सआर के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में की है.
- सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत् सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम) अधिसूचित किए हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है,
- बजट 2026-27 में मुम्बई के भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान को 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेन्ट क्रिएटर लैब स्थापित करने में समर्थन देने का उल्लेख किया गया है.
- सरकार ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) मुम्बई में पहला वेवएक्स इनक्यूबेशन सेन्टर स्थापित किया है और अतिरिक्त केन्द्र देश भर में संचालन में हैं.
- सरकार राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (NHDP) जैसी योजनाओं के जरिए कारीगरों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराती है. साथ ही ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम के माध्यम से भारतीय कला और संस्कृति को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाता है.
- संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र देश की लोक कला, परम्पराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व प्रचार का कार्य करते हैं.
- भारत सरकार रचनात्मक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्रिएटर्स पुरस्कार जैसे कार्यक्रम आयोजित करती है, जिनके माध्यम से डिजिटल कंटेन्ट और रचनात्मक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है.
- इसके अतिरिक्त इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) को AVGC-XR और गेमिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया है.

आगे की राह

रचनात्मक अर्थव्यवस्था भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ बनती जा रही है. इसे सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले बौद्धिक सम्पदा अधिकार की मजबूत व्यवस्था आवश्यक है, ताकि कलाकारों और रचनाकारों की कृतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इसके साथ ही सरकार को रचनात्मक उद्योगों में निवेश और वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे नए उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स को अपने विचारों को विकसित करने का अवसर मिल सके. कौशल विकास और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. स्कूलों और विश्वविद्यालयों में एनीमेशन, डिजाइन, गेमिंग, डिजिटल मीडिया और फिल्म निर्माण जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए. इससे युवाओं को आधुनिक तकनीक और रचनात्मक कौशल प्राप्त होंगे.

डिजिटल तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है. डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया के माध्यम से कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने का अवसर मिल सकता है. इसके अतिरिक्त, पारम्परिक कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उन्हें आधुनिक बाजार से जोड़ना भी महत्वपूर्ण है. सरकार, निजी क्षेत्र और समाज के संयुक्त प्रयासों से रचनात्मक उद्योगों को मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी.

सारांशत: यह कहा जा सकता है कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था केवल आर्थिक विकास का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह नवाचार, सांस्कृतिक संरक्षण और रोजगार सृजन का भी महत्वपूर्ण आधार है. वर्तमान डिजिटल युग में इसकी सम्भावनाएँ और अधिक बढ़ गई हैं. यदि सरकार मजबूत नीतियाँ बनाए, बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा सुनिश्चित करे और कौशल विकास तथा तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करे, तो यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो सकता है. भारत जैसी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले देश के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करती है.

प्रारम्भिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौनसा/से कदम भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था ए.वी.जी.सी.-जेड.आर. को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित है/हैं ?
   1. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021.
   2. बजट 2026-27 में ए.वी.जी.सी. कंटेन्ट क्रिएटर लैब की स्थापना का प्रस्ताव.
   3. भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान को ए.वी.जी.सी.-जेड.आर. और गेमिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में स्थापित करना.

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए—
   (A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
   (C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 और 3
   उत्तर—(D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न

1. भारत में उभरती हुई रचनात्मक अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौनसे हैं ? इसके आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करते हुए बताइए कि भारत सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौनसे प्रमुख कदम उठा रही है ?

●●●

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

AI-आधारित विकास मॉडल : अवसर, नैतिक प्रश्न और नियामकीय चुनौतियाँ

— मनीष प्रियदर्शी

21वीं सदी के तीसरे दशक में मानवता एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है, जहाँ 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence) विकास के नए प्रतिमान गढ़ रही है. जिस प्रकार 18वीं सदी में भाप के इंजन ने शारीरिक श्रम को प्रतिस्थापित किया था, उसी प्रकार आज AI 'मानसिक श्रम' और 'निर्णय लेने की क्षमता' को नई ऊँचाइयों पर ले जा रहा है. इसे 'चौथी औद्योगिक क्रान्ति' (Industry 4.0) का हृदय माना जाता है. AI आधारित विकास मॉडल का अर्थ केवल स्वचालन (Automation) नहीं है, बल्कि एक ऐसी डेटा-संचालित व्यवस्था है, जो उत्पादकता को उच्चतम स्तर तक पहुँचाती है और उन जटिल वैश्विक समस्याओं का समाधान करती है, जो पहले असम्भव मानी जाती थीं.

1. AI आधारित विकास मॉडल के अवसर

AI की शक्ति उसकी 'स्व-शिक्षण' (Self-learning) क्षमता में निहित है. इसके प्रभाव अनेक क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला रहे हैं—

(क) स्वास्थ्य सेवा : 'उपचार' से 'पूर्व-सूचना' तक

- **सटीक निदान (Precision Diagnostics)**—AI एल्गोरिद्म अब रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी जैसे क्षेत्रों में कई मामलों में मानव डॉक्टरों के समान या उससे अधिक सटीक परिणाम दे रहे हैं. उदाहरण के लिए, DeepMind का Health AI आँखों की बीमारियों का पता लगाने में विशेषज्ञों के बराबर सटीकता दिखा चुका है.
- **महामारी विज्ञान**—AI मॉडल विशाल डेटा का विश्लेषण करके भविष्य में होने वाले वायरस के प्रकोप की भविष्यवाणी कर सकते हैं.
- **मानसिक स्वास्थ्य**— AI-आधारित चैटबॉट्स (जैसे— Wysa) उन लोगों को प्रारम्भिक मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, जो सामाजिक संकोच या अन्य कारणों से डॉक्टर के पास नहीं जा पाते.

(ख) कृषि और खाद्य सुरक्षा

- **स्मार्ट फार्मिंग**—भारत जैसे देशों में जहाँ मानसून अनिश्चित रहता है, AI आधारित मौसम पूर्वानुमान और मृदा विश्लेषण (Soil Analysis) फसलों की बर्बादी को 30% तक कम कर सकते हैं.
- **कीट नियंत्रण**—ड्रोन और AI कैमरों की सहायता से केवल प्रभावित पौधों पर ही कीटनाशक छिड़कना सम्भव है, जिससे रासायनिक उपयोग और पर्यावरण प्रदूषण दोनों में कमी आती है.

(ग) सुशासन और सार्वजनिक सेवा (AI for Good)

- सरकारें AI का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) में होने वाली धोखाधड़ी को रोक सकती हैं.
- स्मार्ट यातायात प्रबंधन (Smart Traffic Management) के माध्यम से शहरों में प्रदूषण और यातायात जाम की समस्या का प्रभावी समाधान किया जा सकता है.

2. नैतिक दुविधा (The Ethical Dilemma)

तकनीक कभी भी 'तटस्थ' नहीं होती; वह अपने निर्माता के मूल्यों और डेटा में निहित पूर्वाग्रहों को साथ लेकर चलती है.

(क) एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias)

AI प्रायः उन्हीं पूर्वाग्रहों को दोहराता है, जो समाज में पहले से मौजूद होते हैं. यदि किसी न्याय प्रणाली का AI पिछले 50 वर्षों के डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है, तो वह अनजाने में किसी विशेष समुदाय के प्रति अधिक कठोर निर्णय दे सकता है. इसे **'कोडित भेदभाव'** (Coded Bias) कहा जाता है.

(ख) 'डीपफेक' और गलत सूचना (Deepfakes & Misinformation)

AI का उपयोग करके किसी का भी फर्जी वीडियो या ऑडियो बनाया जा सकता है. यह न केवल व्यक्तिगत गरिमा के विरुद्ध है, बल्कि चुनावों को प्रभावित करने और सामाजिक तनाव या दंगों को भड़काने का एक गम्भीर माध्यम भी बन सकता है.

सम्बन्धित लेख को इस आकर्षक वीडियो के द्वारा संक्षेप में समझें

QR कोड को स्कैन करें

(ग) ब्लैक बॉक्स समस्या और जवाबदेही

जब एक 'डीप लर्निंग' मॉडल कोई निर्णय लेता है, तो उसके पीछे के तर्क को समझना मुश्किल होता है. यदि AI किसी व्यक्ति का लोन रिजेक्ट कर दे या किसी को अपराधी घोषित कर दे, तो वह व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि उसे किस आधार पर नकारा गया है. यह स्थिति पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े गम्भीर प्रश्न उत्पन्न करती है.

3. नियामकीय और भू-राजनीतिक चुनौतियाँ

AI का प्रभावी नियमन करना 'हवा को मुट्ठी में कैद करने' जैसा कठिन कार्य है.

- **कानूनी उत्तरदायित्व**—यदि एक AI-संचालित सर्जिकल रोबोट से गलती हो जाए, तो क्या वह 'चिकित्सा लापरवाही' (Medical Negligence) की श्रेणी में आएगा ? कानून को यहाँ 'इकाई' (Entity) और 'उपकरण' (Tool) के बीच की परिभाषा स्पष्ट करनी होगी.
- **डेटा उपनिवेशवाद (Data Colonialism)**—वैश्विक उत्तर (Global North) की बड़ी प्रौद्योगिकी कम्पनियाँ वैश्विक दक्षिण (Global South) का विशाल डेटा एकत्र कर रही हैं. इससे एक नया आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है, जहाँ डेटा हमारा है, लेकिन उसका लाभ और नियंत्रण विदेशी कम्पनियों के पास है. **शेष पृष्ठ 130 पर**

प्रतियोगिता दर्पण
सामान्य अध्ययन
भूगोल
(भारत एवं विश्व)
Code 792 ₹ 265.00
प्रतियोगिता दर्पण | • E-mail : sales@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

ज्ञान सम्पदा एवं विकास लेख

भारत की ज्ञान-आधारित आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ

— अजय प्रताप तिवारी

सम्बन्धित लेख को इस आकर्षक वीडियो के द्वारा संक्षेप में समझें

QR कोड को स्कैन करें

21वीं सदी में आर्थिक विकास की संरचना में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं. पहले जहाँ भूमि, श्रम और पूँजी जैसे पारम्परिक संसाधन अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार माने जाते थे, वहीं अब ज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद आर्थिक प्रगति के मुख्य चालक बनते जा रहे हैं. वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्धारण केवल भौतिक संसाधनों से नहीं, बल्कि ज्ञान-सम्पदा, अनुसंधान क्षमता और तकनीकी दक्षता से हो रहा है. वर्तमान अर्थव्यवस्था में ज्ञान-आधारित उत्पादन और नवाचार की भूमिका निरन्तर बढ़ती जा रही है. ज्ञान-आधारित आर्थिक विकास एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मुख्य रूप से ज्ञान-आधारित गतिविधियों पर निर्भर करता है. यह पूरी तरह से बौद्धिक क्षमता पर निर्भर है. ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन, सेवाओं, व्यापार और शासन की प्रक्रियाएँ ज्ञान, सूचना, तकनीक, अनुसंधान एवं नवाचार पर आधारित होती हैं. इसमें मानव पूँजी सबसे बड़ा संसाधन होती है. सूचना प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय तकनीक, स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल सेवाएँ इस अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तम्भ हैं. आज जिस राष्ट्र के पास ज्ञान-सम्पदा, नवाचार क्षमता, अनुसंधान संस्थान और डिजिटल अवसंरचना तथा डाटा भण्डारण क्षमता अधिक होगी वही विश्व अर्थव्यवस्था में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निर्वाहन करेगा.

भारत में ज्ञान-आधारित आर्थिक विकास स्थिति

भारतीय आर्थिक विकास का मॉडल पारम्परिक संसाधनों से परिवर्तित होकर ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है. भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ज्ञान-आधारित उत्पाद की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है. भारत ज्ञान-आधारित उत्पाद के माध्यम से आर्थिक विकास पर जोर दे रहा है. केन्द्रीय बजट 2026-27 में अनुसंधान और नवाचार पर विशेष जोर दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुसंधान, नवाचार और डीप-टेक को बढ़ावा देने के लिए ₹ 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो ₹ 1 लाख करोड़ के 'डीप-टेक फण्ड ऑफ फण्डस' को सक्रिय करेगा. फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भारत के ज्ञान-आधारित विकास की सम्भावनाओं को रेखांकित करता है. एआई इकोसिस्टम में 200 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की गई है जिससे आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी. भारत का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय जीडीपी का 0·6-0·7 प्रतिशत है. वैश्विक नवाचार सूचकांक-2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर पहुँच गया है, जबकि 2015 में यह 81वें स्थान पर था. यह सुधार भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, स्टार्ट-अप और डिजिटल अवसंरचना के विस्तार को दर्शाता है.

भारत विश्व का सबसे बड़े स्टार्ट-अप पारिस्थितिक तंत्रों में से एक बन चुका है. वर्ष-2025 में देश में 1·59 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप मौजूद हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक, बायोटेक और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं. इसके साथ ही भारत का आईटी क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है और इसका बाजार आकार लगभग 138 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है. ब्राण्ड फाइनेंस रिपोर्ट-2026 के अनुसार, विश्व के शीर्ष 25 आईटी सेवा ब्राण्डों का कुल 167·2 बिलियन डॉलर है जिसमें से आठ भारतीय आईटी सेवा प्रदाताओं की कुल ब्राण्ड वैल्यू में 36 प्रतिशत की हिस्सेदारी है.

भारत के ज्ञान आधारित रचनात्मक अर्थव्यवस्था का कुल आकार 30 बिलियन डालर के करीब है. इसका सकल घरेलू उत्पादन में 2·5 प्रतिशत की भागीदारी तथा कुल कार्यबल जनसंख्या को 8 प्रतिशत रोजगार मुहैया करती है. वैश्विक स्तर पर 2027 तक ज्ञान आधारित रचनात्मक अर्थव्यवस्था का कुल आकार 480 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है. भारत में डिजिटल उत्पाद में लगातार वृद्धि हो रही है वर्ष-2025 में 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. भारत के कुल निर्यात में ज्ञान-आधारित उत्पादों की हिस्सेदारी में लगभग 20 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके परिणामस्वरूप 11 बिलियन डॉलर से अधिक का अतिरिक्त निर्यात मूल्य सृजित हुआ है. ज्ञान-आधारित क्षेत्र न केवल आर्थिक दृष्टि से तीव्र गति से विस्तृत हो रहा है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का भी एक महत्वपूर्ण प्रेरक बनकर उभर रहा है. आने वाले वर्षों में नवाचार, कौशल-विकास और ज्ञान-सृजन की प्रक्रियाएँ और अधिक सशक्त होंगी, जो समग्र आर्थिक संरचना के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को भी प्रभावित करेंगी.

वैश्विक स्तर पर ज्ञान-आधारित विकास

वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास का स्वरूप तेजी से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है. विश्व के सभी देश अनुसंधान-विकास, नवाचार, सूचना-प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और बौद्धिक सम्पदा को विस्तार दे रहे हैं. विश्व बैंक की रिपोर्टों के अनुसार वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आधार पारम्परिक संसाधनों के बजाय ज्ञान और तकनीक बन चुका है. विश्व के 149 देशों के आँकड़ों पर आधारित नॉलेज इकोनॉमी इंडेक्स-2025 में भारत का 66वाँ स्थान है, जबकि जापान-19, अमेरिका- 15, चीन-36, स्विट्जरलैण्ड और सिंगापुर का क्रमशः पहला और दूसरा स्थान है. ज्ञान आधारित विकास के आधार शोध-नवाचार और विकास के सन्दर्भ को देखें तो विश्व के 175 देशों में भारत का स्थान-61वाँ है, जबकि अमेरिका-13, जापान-27 और डेनमार्क का प्रथम स्थान है. आने वाले दिनों में ज्ञान आधारित विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था का संवाहक होगा.

ज्ञान-आधारित आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ

- भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है. यह जनसंख्या ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी पूँजी है. यदि इस युवा शक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तो यह देश की आर्थिक वृद्धि को कई गुना बढ़ा सकती है.
- भारत की आईटी क्षमता विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है. सॉफ्टवेयर विकास, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कम्प्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों की माँग बढ़ रही है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

- भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है. मोबाइल इंटरनेट और डिजिटल भुगतान प्रणाली ने आर्थिक गतिविधियों को अधिक सुलभ बना दिया है. डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के क्षेत्र में नई सम्भावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं.
- भारत में नवाचार का विस्तार तेजी से हो रहा है. विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में इनोवेशन लैब और इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं. यह नए विचारों को व्यवसाय में बदलने के अवसर प्रदान करता है. जिससे रोजगार सृजन क्षमता और अर्थव्यवस्था को बल मिलता है.
- वैश्विक बाजार में तेजी से बदल रहा है, जहाँ ज्ञान और तकनीक की माँग तेजी से बढ़ रही है. भारत अपनी तकनीकी क्षमता और प्रतिभा के बल पर वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सकता है.

ज्ञान-आधारित विकास की प्रमुख चुनौतियाँ

- किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक विकास का आधार शिक्षा होता है. भारत में शिक्षा पर कम निवेश, गुणवत्ता और कौशल युक्त शिक्षा का अभाव विकास को बाधित करते हैं. भारत अपनी जीडीपी का 2·9-3·2 प्रतिशत खर्च करता है जो अमेरिका और चीन की तुलना में काफी कम है. हालाँकि, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ी है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय संस्थानों की संख्या बहुत कम है. शिक्षा में नवाचार, अनुसंधान और व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी भी एक प्रमुख समस्या है.
- ज्ञान आधारित विकास की निर्भरता शोध, अनुसंधान और नवीन कल्पनाओं पर होती है. भारत में अनुसंधान पर व्यय बहुत कम है. भारत अपने जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है. जबकि अमेरिका लगभग 3·5 प्रतिशत, चीन लगभग 2·4-2·6 प्रतिशत जापान लगभग 3·4 और दक्षिण कोरिया लगभग 5 प्रतिशत खर्च करता है. वैश्विक स्तर पर भारत 7वें स्थान पर है. विकसित देशों की तुलना में भारत में अनुसंधान के लिए पर्याप्त संसाधन और सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, जिससे नवाचार और विकास की गति प्रभावित होती है.
- भारत में शिक्षा प्राप्त युवाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन युवाओं में कौशल अंतराल एक गम्भीर आर्थिक चुनौती है. भारत में 51 प्रतिशत युवा ही रोजगार युक्त कौशल रखते हैं. पारम्परिक शिक्षा प्रणाली अक्सर व्यावहारिक और तकनीकी कौशल पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती. वैश्विक स्तर पर भारत का कौशल अंतराल लगभग 20 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में 13 प्रतिशत, चीन में 15 और जर्मनी में लगभग 8 प्रतिशत है. भारत में लगभग 75 प्रतिशत कम्पनियों में उपयुक्त कौशल वाले कर्मचारियों का अभाव है. चालू वर्ष-2026 के अंत तक टेक क्षेत्र में लगभग 14-19 लाख विशेषज्ञों की कमी होने का अनुमान है. परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार या अल्परोजगार की स्थिति में रहते हैं, जो ज्ञान-आधारित विकास की गति को प्रभावित करता है.
- भारत की सबसे बड़ी समस्या ब्रेन ड्रेन है. भारत के कई प्रतिभाशाली छात्र और वैज्ञानिक बेहतर अवसरों की खोज में विदेश चले जाते हैं. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2023 में लगभग 13 लाख भारतीय छात्रों ने विदेशों में अध्ययन के लिए प्रस्थान किया, जिसमें से अधिकांश वहीं पर विभिन्न पेशों से जुड़ गए. आईटी, चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्र में कुशल पेशेवरों का पलायन देश की मानव पूँजी और आर्थिक विकास को कमजोर करता है.
- भारत में डिजिटल अवसंरचना की कमी ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ी बाधा है. ज्ञान-आधारित विकास के लिए मजबूत डिजिटल अवसंरचना की आवश्यक होती है. भारत के कई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट, डिजिटल उपकरण और तकनीकी संसाधनों की कमी है. इससे डिजिटल विभाजन बढ़ता है और ज्ञान तक समान पहुँच नहीं बन पाती. जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और नीतिगत अस्पष्टता नवाचार और निवेश को प्रभावित करती हैं. जब तक डिजिटल संसाधनों का व्यापक विस्तार नहीं होगा, तब तक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था का लाभ सीमित ही रहेगा.

आगे की राह

ज्ञान-आधारित आर्थिक विकास की दिशा में भारत अग्रसर है, किन्तु वैश्विक नेतृत्व और लक्ष्य-2047 को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक एवं समावेशी नीतियों की आवश्यकता है.

- डिजिटल अवसंरचना, समावेशन और डिजिटल साक्षरता का विस्तार और ग्रामीण में हाई-स्पीड इंटरनेट तथा साइबर सुरक्षा के ढाँचे को मजबूत करना होगा साथ ही डिजिटल इंडिया 2.0 के अन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और क्लाउड अवसंरचना को प्राथमिकता देनी होगी.
- इसके अतिरिक्त अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने के साथ निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना होगा. विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे संस्थानों को वैश्विक शोध केन्द्र के रूप में विकसित करना होगा चाहिए. दीर्घकालिक एवं सरल नीतियों को लक्ष्य बनाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट इनोवेशन, ऊर्जा दक्षता, सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के साथ भारत को टेक्नोलॉजी उपभोक्ता से टेक्नोलॉजी निर्माता बनाना चाहिए.
- नवीन तकनीक एआई, डेटा एनालिटिक्स और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्र में प्रशिक्षण को बढ़ाने से रोजगार सृजन की क्षमता बढ़ेगा एवं ग्रामीण उद्योग में इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देकर ज्ञान आधारित विकास को बढ़ाया जा सकता है.
- भारत को वैश्विक सहयोग और तकनीकी कूटनीति का विस्तार करते हुए रिवर्स ब्रेन ड्रेन नीतियों के माध्यम से बौद्धिक पलायन को रोकना होगा. बौद्धिक सम्पदा और नवाचार संरक्षण पेटेंट प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना होगा शोधकर्ताओं को कानूनी सहायता और वित्तीय सहयोग तथा विश्वविद्यालयों में बौद्धिक सम्पदा अधिकार सेल स्थापित किया जाना चाहिए.
- ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था का आधार शिक्षा है. शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता मानव पूँजी निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है. अनुसंधान-आधारित और कौशल-उन्मुख पाठ्यक्रमों को शामिल करने से नवाचार और ज्ञान-सृजन को बढ़ावा मिलेगा. उच्च शिक्षा संस्थानों और उद्योगों के बीच अनुसंधान सहयोग से ज्ञान और उद्योगों की व्यावहारिक आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित होगा, जो उत्पादन को प्रोत्साहित करता है.

सारतत्व

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश, बढ़ती उद्यमशीलता, डिजिटल विस्तार, शोध एवं नवाचार की प्रगति से ज्ञान-आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है; साथ ही शिक्षा, नवाचार, डिजिटल समावेशन और अनुसंधान

शेष पृष्ठ 128 पर

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

हरित ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी लेख

हाइड्रोजन वैली नवाचार क्लस्टर : भारत का ऊर्जा परिवर्तन

—अनुज कुमार

भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत् जोधपुर, ओडिशा, पुणे और केरल में 4 हाइड्रोजन वैली नवाचार क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की है. इनका उद्देश्य उत्पादन से उपयोग तक ग्रीन हाइड्रोजन की पूरी मूल्य श्रृंखला का प्रदर्शन कर भारत को वैश्विक हाइड्रोजन हब बनाना है.

प्रस्तावना

विश्व ऊर्जा प्रणाली तेजी से जीवाश्म ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था से स्वच्छ ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है. जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन में कमी की आवश्यकता ने नए ऊर्जा स्रोतों की खोज को बढ़ावा दिया है.

इसी सन्दर्भ में ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है. भारत ने इस क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है. इसके तहत् हाइड्रोजन वैली नवाचार क्लस्टर (Hydrogen Valley Innovation Clusters–HVICs) विकसित किए जा रहे हैं, जो उत्पादन से लेकर उपयोग तक हाइड्रोजन की पूरी मूल्य श्रृंखला का प्रदर्शन करेंगे. हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स स्वच्छ ऊर्जा (SDG-7) एवं औद्योगिक नवाचार (SDG-9) के माध्यम से **'ऊर्जा आत्मनिर्भरता'** सुनिश्चित करते हुए जलवायु कार्यवाही (SDG-13) और समावेशी आर्थिक विकास (SDG-8) को एकीकृत करने की रणनीतिक पहल हैं.

हाइड्रोजन ऊर्जा का परिचय

हाइड्रोजन पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर रासायनिक तत्व है और इसे भविष्य के स्वच्छ एवं टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है. यह रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ऊर्जा-समृद्ध गैस है, जो जल (H_2O) तथा विभिन्न कार्बनिक यौगिकों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है. ऊर्जा के क्षेत्र में हाइड्रोजन का महत्व इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि इसके उपयोग से ऊर्जा उत्पादन के दौरान कार्बन उत्सर्जन बहुत कम या लगभग शून्य हो सकता है. जब हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में जलाया जाता है या फ्यूल सेल में उपयोग किया जाता है, तब इसका मुख्य उप-उत्पाद केवल जल (पानी) होता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प बन जाता है.

हाइड्रोजन के उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर इसे सामान्यतः तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है.

I. **ग्रे हाइड्रोजन**—ग्रे हाइड्रोजन वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक उत्पादित हाइड्रोजन है. इसका उत्पादन मुख्यतः प्राकृतिक गैस या कोयले से स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग (Steam Methane Reforming) प्रक्रिया द्वारा किया जाता है. हालाँकि, इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का उत्सर्जन होता है, इसलिए यह पूरी तरह पर्यावरण-अनुकूल नहीं माना जाता.

II. **ब्लू हाइड्रोजन**—ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन भी ग्रे हाइड्रोजन की तरह ही किया जाता है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसे कार्बन कैप्चर, उपयोग और भण्डारण (CCUS) कहा जाता है. इस तकनीक के माध्यम से उत्पादन के दौरान निकलने वाली CO_2 को पकड़कर सुरक्षित रूप से संगृहीत किया जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है.

III. **ग्रीन हाइड्रोजन**—ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन का सबसे स्वच्छ और टिकाऊ रूप माना जाता है. इसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे—सौर और पवन ऊर्जा की सहायता से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है. इस प्रक्रिया में पानी को विद्युत् धारा की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है. चूँकि इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं होता, इसलिए इसमें लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है.

नोट—भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मानकों के अनुसार, विद्युत् अपघटन से निर्मित हाइड्रोजन 'ग्रीन' तभी माना जाएगा, जब इस प्रक्रिया से होने वाला उत्सर्जन प्रत्येक 1 किग्रा हाइड्रोजन उत्पादित करने में 2 क्रिग्रा CO_2 समतुल्य से अधिक न हो.

सम्बन्धित लेख को इस आकर्षक वीडियो के द्वारा संक्षेप में समझें

QR कोड को स्कैन करें

हाइड्रोजन वैली की अवधारणा

हाइड्रोजन वैली (Hydrogen Valley) ऐसी परिकल्पना है जिसमें किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में हाइड्रोजन ऊर्जा की पूरी मूल्य श्रृंखला (Value Chain) को एकीकृत रूप से विकसित किया जाता है. इसमें हाइड्रोजन का उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, वितरण तथा अन्तिम उपयोग सभी गतिविधियाँ एक ही क्षेत्र में आपस में जुड़ी होती हैं. इस मॉडल के तहत् उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे—उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन (बस, ट्रक, ट्रेन) और रसायन उद्योग में किया जाता है. हाइड्रोजन वैली का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर एक समग्र हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिले, कार्बन उत्सर्जन में कमी आए और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिले.

हाइड्रोजन वैली नवाचार क्लस्टर (HVIC) क्या है ?

हाइड्रोजन वैली नवाचार क्लस्टर (Hydrogen Valley Innovation Cluster –HVIC) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य हाइड्रोजन आधारित स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली के विकास, परीक्षण

PRATIYOGITA DARPAN EXTRA ISSUE
UPSC IAS / STATE PSC
GENERAL STUDIES
Environment And We
A book that provides a comprehensive coverage of Ecology and Environment constituent of the syllabus.
Code No. 846 ₹ 215.00
PRATIYOGITA DARPAN • E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

और व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना है. इसे एक ऐसे मॉडल के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ हाइड्रोजन ऊर्जा से सम्बन्धित सभी गतिविधियाँ एकीकृत रूप से संचालित की जाती हैं.

प्रमुख विशेषताएँ

- **पूरी हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला का प्रदर्शन**—HVIC के अन्तर्गत हाइड्रोजन के उत्पादन से लेकर भण्डारण, परिवहन, वितरण और अन्तिम उपयोग तक पूरी मूल्य श्रृंखला को एक ही क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है.
- **उद्योग और शोध संस्थानों के बीच सहयोग**—इस क्लस्टर में उद्योग, वैज्ञानिक संस्थान, स्टार्ट-अप और सरकारी एजेंसियाँ मिलकर काम करती हैं, जिससे तकनीकी नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है.
- **नई तकनीकों का परीक्षण और विकास**—HVIC के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइजर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, भण्डारण तकनीक जैसी नई तकनीकों का परीक्षण किया जाता है.
- **बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी**—इन क्लस्टरों का उद्देश्य भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन के वाणिज्यिक स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपयोग के लिए आधार तैयार करना है.
- **संस्थागत पहल**—भारत में इस अवधारणा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा विकसित किया गया है.
- **सरकारी वित्तीय सहायता**—सरकार ने प्रत्येक हाइड्रोजन वैली नवाचार क्लस्टर के विकास के लिए लगभग ₹ 50 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है.
- **ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन योजना (2025)**—यह सुनिश्चित करती है, कि भारत में उत्पादित हाइड्रोजन निर्धारित उत्सर्जक मानकों पर खरी उतरे, जिससे घरेलू और निर्यात बाजारों में विश्वसनीयता बढ़ेगी.

भारत में हाइड्रोजन वैली की आवश्यकता

- **ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भरता**—भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है. वर्तमान में देश लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है और ऊर्जा सुरक्षा भी प्रभावित होती है. हाइड्रोजन वैली के विकास से स्वदेशी स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. इससे दीर्घकाल में ऊर्जा आयात बिल में कमी आएगी और भारत की ऊर्जा आत्म-निर्भरता तथा ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी.
- **जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति**—भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं. इनमें 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना और 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता स्थापित करना शामिल है. हाइड्रोजन वैली इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ और कम कार्बन उत्सर्जन वाला ऊर्जा स्रोत है.
- **औद्योगिक क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन**—भारत के कई भारी उद्योग जैसे—इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग और पेट्रोलियम रिफाइनरी बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन करते हैं. इन क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने से पारम्परिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी. इससे औद्योगिक उत्पादन अधिक पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ बन सकेगा.

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2023 में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से की गई यह मिशन भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

प्रमुख लक्ष्य

- **ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में वृद्धि**—मिशन के अन्तर्गत 2030 तक लगभग 5 मिलियन टन (MMT) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
- **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार**—ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए लगभग 125 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने की योजना है.
- **निवेश को प्रोत्साहन**—इस मिशन से लगभग ₹ 8 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करने की सम्भावना है.
- **रोजगार सृजन**—ग्रीन हाइड्रोजन से सम्बन्धित उद्योगों और अवसंरचना के विकास से 6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है.
- **वैश्विक हाइड्रोजन हब बनने का लक्ष्य**—इस मिशन का दीर्घकालिक उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केन्द्र बनाना है.

भारत में विकसित हो रहे हाइड्रोजन वैली क्लस्टर

भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से चार प्रमुख Hydrogen Valley Innovation Clusters (HVICs) स्थापित किए जा रहे हैं. इन क्लस्टरों का उद्देश्य उत्पादन से लेकर उपयोग तक हाइड्रोजन की पूरी मूल्य श्रृंखला का विकास करना है.

जोधपुर हाइड्रोजन वैली (राजस्थान)

- यह क्लस्टर सौर ऊर्जा आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर केन्द्रित है.
- राजस्थान के विशाल सौर ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा.
- उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग मुख्य रूप से परिवहन क्षेत्र और विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों में किया जाएगा.

ओडिशा हाइड्रोजन वैली

- इस परियोजना का नेतृत्व IIT भुवनेश्वर द्वारा किया जा रहा है.
- इसका मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन तकनीक का अनुसंधान एवं विकास करना है.
- विशेष रूप से इस्पात उद्योग में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे हरित औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा.

पुणे हाइड्रोजन वैली (महाराष्ट्र)

- इस क्लस्टर का नेतृत्व CSIR–National Chemical Laboratory (CSIR-NCL) कर रहा है.
- इसमें इलेक्ट्रोलिसिस और बायो-रूट तकनीकों के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की योजना है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

- इसका लक्ष्य लगभग 0·7 KTPA (हजार टन प्रति वर्ष) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है.
- इसका उपयोग मुख्यतः रसायन उद्योग और विशेष रसायनों के उत्पादन में किया जाएगा.

केरल हाइड्रोजन वैली

- यह क्लस्टर मुख्यतः बंदरगाह आधारित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केन्द्रित है.
- इसमें हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन क्षेत्र, विशेषकर समुद्री परिवहन और वैकल्पिक समुद्री ईंधन के रूप में किया जाएगा.
- यह पहल हरित बंदरगाह और स्वच्छ समुद्री परिवहन को बढ़ावा देने में सहायक होगी.

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत

विश्व स्तर पर कई देश हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा अर्थव्यवस्था के विकास पर तेजी से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इसे भविष्य के स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है. इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है.

प्रमुख अग्रणी देश

- **जापान**—हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक और परिवहन क्षेत्र में व्यापक उपयोग को बढ़ावा दे रहा है.
- **जर्मनी**—यूरोप में ग्रीन हाइड्रोजन अवसंरचना और औद्योगिक डीकार्बो-नाइजेशन पर विशेष ध्यान दे रहा है.
- **अमेरिका**—उन्नत हाइड्रोजन तकनीक, अनुसंधान और बड़े निवेश के माध्यम से इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है.
- **ऑस्ट्रेलिया**—ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाएँ विकसित कर रहा है.

भारत के प्रमुख लाभ

- **सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धता**—भारत में सौर और पवन ऊर्जा की लागत अपेक्षाकृत कम है.
- **विशाल घरेलू बाजार**—ऊर्जा की बढ़ती माँग ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देती है.
- **औद्योगिक माँग**—इस्पात, उर्वरक और रिफाइनरी जैसे क्षेत्रों में हाइड्रोजन की बड़ी माँग है.

इन कारकों के आधार पर भारत भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश बन सकता है.

आर्थिक महत्व

- **निवेश की सम्भावनाएँ**—भारत में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र तेजी से उभर रहा है. विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में 80 अरब डॉलर से अधिक निवेश की सम्भावना है, जिससे ऊर्जा अवसंरचना और उद्योगों का विस्तार होगा.
- **रोजगार सृजन**—ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग के विकास से उत्पादन इकाइयों, इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण तथा ऊर्जा अवसंरचना विकास जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे.
- **निर्यात क्षमता**—स्वच्छ ऊर्जा की वैश्विक माँग को देखते हुए भारत भविष्य में यूरोप, जापान और अन्य विकसित देशों को ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात करने की क्षमता विकसित कर सकता है.

पर्यावरणीय महत्व

- **कार्बन उत्सर्जन में कमी**—ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में CO_2 उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है.
- **स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा**— हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित वाहन पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इनके उपयोग से प्रदूषणकारी गैसों का उत्सर्जन बहुत कम होता है.
- **औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन**— इस्पात, उर्वरक और रिफाइनरी जैसे क्षेत्रों में हाइड्रोजन का उपयोग जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है.
- **वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में योगदान**— इससे पेरिस समझौते के अन्तर्गत निर्धारित जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है.

उद्योगों में उपयोग

- **इस्पात उद्योग**—इस्पात उत्पादन में पारम्परिक रूप से कोयले का व्यापक उपयोग होता है, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है. ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग डायरेक्ट रिडक्शन प्रक्रिया में करके कोयला आधारित उत्पादन को कम किया जा सकता है, जिससे उद्योग अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनता है.
- **उर्वरक उद्योग**—उर्वरक उद्योग में हाइड्रोजन का उपयोग मुख्यतः अमोनिया उत्पादन के लिए किया जाता है, जो नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रमुख घटक है.
- **रिफाइनरी उद्योग**—पेट्रोलियम रिफाइनरियों में हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन शोधन (Refining) तथा अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रियाओं में किया जाता है.

परिवहन क्षेत्र में उपयोग

- **बस और ट्रक परिवहन**—हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित बसों और ट्रकों का उपयोग स्वच्छ सार्वजनिक और माल परिवहन के लिए किया जा सकता है. इससे डीजल पर निर्भरता कम होती है और प्रदूषण में कमी आती है.
- **रेल परिवहन**—हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों को पारम्परिक डीजल इंजनों के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे रेलवे क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सकता है.
- **समुद्री परिवहन (जहाज)**— हाइड्रोजन का उपयोग वैकल्पिक समुद्री ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जिससे जहाजों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है.
- **भारत में पहल**—भारत में हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाहनों और परिवहन प्रणालियों के पायलट प्रोजेक्ट और अनुसंधान परियोजनाएँ शुरू की जा चुकी हैं.

बंदरगाह आधारित हाइड्रोजन हब

- **ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात केन्द्र**—भारत सरकार ने प्रमुख समुद्री बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भण्डारण और निर्यात केन्द्र के रूप में विकसित करने की पहल की है.
- **प्रमुख उदाहरण**—
  - दीनदयाल पोर्ट (गुजरात)
  - पारादीप पोर्ट (ओडिशा)
  - वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट (तमिलनाडु)
- **उद्देश्य**—इन हबों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और भारत को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन निर्यातक के रूप में स्थापित करना है.

निजी क्षेत्र की भूमिका

- **निवेश और परियोजनाओं का विकास**—भारत में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है. कई बड़ी कम्पनियाँ इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं.
- **प्रमुख कम्पनियाँ**—
  - रिलायंस इंडस्ट्रीज
  - अदानी समूह

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

- JSW समूह
- NTPC

अनुसंधान एवं नवाचार

- **शोध संस्थानों की भूमिका**—भारत में ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के विकास के लिए कई प्रमुख वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान सक्रिय रूप से अनुसंधान कर रहे हैं.
- **प्रमुख संस्थान**—
  - **IIT मद्रास**—हाइड्रोजन नवाचार केन्द्र की स्थापना.
  - **CSIR की विभिन्न प्रयोगशालाएँ**—हाइड्रोजन उत्पादन और भण्डारण तकनीकों पर अनुसंधान.
  - भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के विकास पर कार्य.
- **महत्वपूर्ण पहल**—IIT मद्रास में हाइड्रोजन वैली नवाचार हब स्थापित किया जा रहा है, जो अनुसंधान, तकनीकी विकास और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देगा.

प्रमुख चुनौतियाँ

- **उच्च लागत**—वर्तमान समय में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत पारम्परिक ईंधनों की तुलना में अधिक है, जिससे इसका बड़े पैमाने पर उपयोग अभी सीमित है.
- **अवसंरचना की कमी**—हाइड्रोजन के सुरक्षित उपयोग के लिए पाइप-लाइन नेटवर्क, भण्डारण सुविधाएँ और परिवहन व्यवस्था जैसी विशेष अवसंरचना की आवश्यकता होती है.
- **तकनीकी सीमाएँ**—इलेक्ट्रोलाइजर की उच्च लागत और ऊर्जा दक्षता से जुड़ी चुनौतियाँ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के विस्तार में बाधा उत्पन्न करती हैं.
- **ग्रिड सम्बन्धी समस्याएँ**—नवीकरणीय ऊर्जा की नियमित आपूर्ति नहीं हो पाती है.
- **जल की कमी**—संकटग्रस्ट क्षेत्रों में जल की व्यापक आवश्यकता.
- **नीतिगत आवश्यकताएँ**—रूपरेखाओं, प्रोत्साहनों और मानकों की जरूरत होगी.

नीति उपाय

- **उत्पादन प्रोत्साहन योजना (Production Incentive Schemes)**—सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी योजनाएँ लागू कर रही है, जिससे निजी निवेश और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिले.
- **हाइड्रोजन हब का विकास**—देश के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन हब और हाइड्रोजन वैली क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे उत्पादन, भण्डारण और उपयोग का एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सके.
- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) परियोजनाएँ**—सरकार वैज्ञानिक संस्थानों और उद्योगों के सहयोग से नई हाइड्रोजन तकनीकों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित कर रही है.

भविष्य की सम्भावनाएँ

- **वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन केन्द्र**— पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों और सरकारी नीतिगत समर्थन के कारण भारत के पास ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केन्द्र बनने की क्षमता है.
- **ऊर्जा निर्यातक देश**—ग्रीन हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन से भारत भविष्य में यूरोप, जापान और अन्य देशों को स्वच्छ ऊर्जा निर्यात कर सकता है.
- **स्वच्छ औद्योगिक अर्थव्यवस्था**— हाइड्रोजन के उपयोग से उद्योगों का डीकार्बोनाइजेशन होगा, जिससे पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

सारांशतः हाइड्रोजन वैली नवाचार क्लस्टर भारत के ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर रहा है. यह मॉडल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास जैसे कई लक्ष्यों को एक साथ साधने की क्षमता रखता है. हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा प्रणाली के विकास से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकेगी. यदि भारत तकनीकी नवाचार, अनुसंधान, निवेश और प्रभावी नीतिगत समन्वय को और मजबूत करता है, तो आने वाले दशकों में वह न केवल स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता भी बन सकता है.

●●●

शेष पृष्ठ 124 का

निवेश को लेकर एक एकीकृत नीति लागू करने पर साथ ही तो भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष देशों में शामिल हो सकता है. गौरतलब है कि ज्ञान आधारित विकास केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि रोजगार सृजन क्षमता और सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी भी करते हैं. यदि नीतिगत प्रतिबद्धता, संस्थागत सुधार और सामाजिक सहभागिता के साथ ज्ञान को विकास का केन्द्र बनाया जाए, तो भारत केवल उपभोक्ता-आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित न रह कर नवाचार-प्रेरित वैश्विक आर्थिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका का निर्वाहन कर सकता है. किसी भी राष्ट्र की आर्थिक विकास दर उसके मानव पूँजी (शिक्षा, कौशल और नवाचार क्षमता) की गुणवत्ता पर निर्भर करती है. जिस देश की शिक्षा व्यवस्था, नवा. चार तंत्र और कौशल विकास जितना सुदृढ़ होगा, उसकी आर्थिक प्रगति और उत्पादकता वृद्धि उतनी ही तेज होगी.

प्रारम्भिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न

1. भारत की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
   1. अनुसंधान एवं विकास में निवेश ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था का प्रमुख संकेतक है.
   2. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे आधार और यूपीआई आर्थिक समावेशन में योगदान करते हैं.
   3. ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था केवल सेवा क्षेत्र पर निर्भर करती है.

उपर्युक्त में से कौनसे कथन सही हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

उत्तर—(A)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न

1. ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था 21वीं सदी में राष्ट्रीय शक्ति का नया आधार बन चुकी है. उपर्युक्त कथन को भारत के सन्दर्भ में विभिन्न सम्भावनाओं के साथ चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए.

●●●

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

संस्कृति एवं विरासत संरक्षण लेख

भारतश्री पहल: देश के ऐतिहासिक शिलालेखों का डिजिटलीकृत भण्डार

— रितु चतुर्वेदी

कुछ वर्ष पूर्व, केन्द्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने भारतश्री (BharatSHRI -Bharat Shared Repository of Inscriptions) नामक एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की थी. इसका उद्देश्य भारत के प्राचीन अभिलेखों का राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित डिजिटल भण्डार तैयार करना तथा एक आभासी संग्रहालय की स्थापना करना है. इस पहल के माध्यम से शिलालेखों को सुरक्षित, प्रलेखित एवं आमजन के लिए सुलभ बनाया जाएगा.

आधुनिक तकनीक (उच्च रिजॉल्यूशन स्कैनर्स के माध्यम से डिजिटल प्रारूप में बदलना) की सहायता से यह योजना देश की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण, प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोतों तक पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित करने तथा युवाओं को भारत के इतिहास और विरासत से सक्रिय रूप से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. इसके प्रथम चरण में देश के एक लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा.

पहल के अंतर्गत 76 हजार शिलालेख प्रतिलिपि के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया जारी है. इसी क्रम में पुरालेख निदेशालय ने क्षतिग्रस्त एवं लुप्त शिलालेख प्रतिलिपि की पुनः प्रतिलिपि तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया है.

वर्तमान में कुल 18 तकनीकी टीमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में शिलालेखों की पुनः प्रतिलिपि के कार्य में संलग्न हैं.

उल्लेखनीय है कि इन शिलालेखों की मूल प्रतिलिपियाँ **1887, 1889, 1892, 1894, 1896, 1900** तथा **1915** के दौरान तैयार की गई थीं.

वर्तमान सन्दर्भ

हाल ही में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के निदेशक (एपिग्राफी) के. मुनिरत्नम रेड्डी ने बताया कि ASI ने मैसूर स्थित पुरालेख निदेशालय के कार्यालय में संरक्षित सभी शिलालेख प्रतिलिपि के डिजिटलीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है. इन डिजिटीकृत शिलालेख प्रतिलिपि को भारतश्री परियोजना के अन्तर्गत ऑनलाइन अपलोड कर शीघ्र ही शोधकर्ताओं तथा आमजन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. अनुमानतः अब तक लगभग 1,000 शिलालेख प्रतिलिपि का सफलतापूर्वक डिजिटलीकरण किया जा चुका है, जबकि शेष कार्य आगामी 6 महीनों के अन्दर पूर्ण किए जाने की सम्भावना है.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)—एक परिचय

- **स्थापना वर्ष**—1861
- **संस्थापक**—अलेक्जेंडर कनिंघम (प्रथम महानिदेशक)
- **स्वरूप**—भारत सरकार की प्रमुख पुरातात्त्विक संस्था

भूमिका एवं दायित्व :

- देश में पुरातात्विक अनुसंधान का संचालन
- ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्मारकों का संरक्षण
- प्राचीन स्थलों, अभिलेखों और धरोहरों का वैज्ञानिक अध्ययन
- राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की देखरेख
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन में केन्द्रीय भूमिका निभाने वाली प्रमुख संस्था है.

अवसर

सांस्कृतिक विरासत का दीर्घकालिक संरक्षण—शिलालेख भारत के इतिहास के प्राथमिक स्रोत हैं. इनका डिजिटलीकरण प्राकृतिक क्षरण, मानवीय उपेक्षा तथा आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करेगा. इससे सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत निरन्तरता की भावना सुदृढ़ होगी.

इतिहास लेखन में पारदर्शिता और प्रामाणिकता—डिजिटल भण्डार के माध्यम से शोधकर्ताओं को मूल स्रोतों तक प्रत्यक्ष पहुँच मिलेगी, जिससे इतिहास लेखन में पक्षपात और त्रुटियों की सम्भावना कम होगी. यह निश्चित रूप से अकादमिक गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है.

डिजिटल इंडिया और सुशासन—यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन, ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता के सिद्धान्तों को सांस्कृतिक क्षेत्र में लागू करती है. सार्वजनिक डेटा की उपलब्धता नागरिकों के सूचना के अधिकार और ज्ञान-साझेदारी को प्रोत्साहित करती है.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग—उच्च-रिजॉल्यूशन स्कैनिंग, डेटा आर्काइविंग, मेटाडेटा टैगिंग तथा क्लाउड स्टोरेज जैसी तकनीकों का उपयोग भारत में डिजिटल हेरिटेज मैनेजमेंट के नए मानक स्थापित कर सकता है.

अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कूटनीति—डिजिटल संग्रह के माध्यम से भारत अपनी प्राचीन सभ्यता और अभिलेखीय परम्परा को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित कर सकता है, जिससे 'सॉफ्ट पावर' को मजबूती मिलेगी.

युवाओं और शोधार्थियों की भागीदारी—विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और विद्यार्थियों के लिए यह एक समृद्ध स्रोत सिद्ध होगा, जिससे ऐतिहासिक अनुसंधान में नई पीढ़ी की रुचि बढ़ेगी.

भारतश्री पहल के प्रमुख उद्देश्य

संरक्षण • डिजिटलीकरण • इतिहास का लोकतंत्रीकरण

- शिलालेखों का व्यवस्थित प्रलेखन—देशभर के अभिलेखों का वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध दस्तावेजीकरण.
- डिजिटलीकरण एवं सार्वजनिक पहुँच—प्राचीन शिलालेखों को डिजिटल रूप में संरक्षित कर ऑनलाइन उपलब्ध कराना.
- शैक्षणिक अनुसंधान एवं व्याख्या—इतिहास, पुरातत्व एवं भाषाविज्ञान के शोध को प्रोत्साहन.
- राष्ट्रीय डिजिटल पुरालेख भण्डार—एक केन्द्रीकृत डिजिटल रिपॉजिटरी और आभासी संग्रहालय की स्थापना.
- शिक्षा, जागरूकता एवं जनसम्पर्क—युवाओं और आमजन को भारत की ऐतिहासिक विरासत से जोड़ना.

सम्बन्धित लेख को इस आकर्षक वीडियो के द्वारा संक्षेप में समझें

QR कोड को स्कैन करें

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

चुनौतियाँ

प्रौद्योगिकीय जटिलता—प्राचीन, क्षतिग्रस्त और विभिन्न लिपियों में लिखे शिलालेखों को सटीक रूप से डिजिटाइज करना अत्यन्त जटिल प्रक्रिया है. त्रुटिपूर्ण स्कैनिंग या गलत मेटाडेटा से ऐतिहासिक व्याख्या प्रभावित हो सकती है.

वित्तीय एवं संस्थागत सीमाएँ—बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण हेतु निरन्तर वित्तपोषण, प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा संस्थागत समन्वय की आवश्यकता होगी.

डेटा सुरक्षा और दीर्घकालिक संरक्षण—साइबर हमलों, डेटा हानि या तकनीकी विफलता से डिजिटल भण्डार की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है. डिजिटल संरक्षण भी नियमित अपडेट और रखरखाव की माँग करता है.

भाषायी एवं लिपिकीय विविधता—ब्राह्मी, खरोष्ठी, नागरी, तमिल-ब्राह्मी आदि विविध लिपियों की विशेषज्ञता सीमित है. अनुवाद और व्याख्या में त्रुटियाँ विवाद उत्पन्न कर सकती हैं.

डिजिटल विभाजन—ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण इस पहल का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाएगा.

सन्दर्भ का अभाव—केवल डिजिटल प्रतिलिपि पर्याप्त नहीं; उसके ऐतिहासिक सन्दर्भ, विश्लेषण और प्रमाणिक व्याख्या भी आवश्यक है. इसके आभाव में अर्थ का अनर्थ हो सकता है.

सुझाव

समग्र राष्ट्रीय नीति का निर्माण—भारतश्री को केवल एक सीमित परियोजना के रूप में न देखकर इसे राष्ट्रीय डिजिटल हेरिटेज मिशन का स्वरूप दिया जाना चाहिए. इसके अन्तर्गत शिलालेखों के साथ-साथ ताम्रपत्र, पांडुलिपियाँ, अभिलेखागार सामग्री और पुरातात्विक प्रतिवेदन भी क्रमबद्ध रूप से शामिल किए जा सकते हैं. स्पष्ट समय-सीमा, चरणबद्ध क्रियान्वयन और निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना आवश्यक है.

संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं विशेषज्ञ सहयोग

विश्वविद्यालयों, IITs, भारतीय भाषा संस्थानों, पुरातत्व विभागों तथा अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक ढाँचा विकसित किया जाए. पुरालेख, प्राचीन लिपियों, संरक्षण विज्ञान तथा डिजिटल आर्काइविंग में विशेषज्ञ मानव संसाधन का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण सुनिश्चित किया जाए.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग

- AI आधारित Script Recognition, मशीन लर्निंग, 3D स्कैनिंग और डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन जैसी तकनीकों का प्रयोग कर क्षतिग्रस्त शिलालेखों की पुनर्संरचना की जा सकती है. इससे अनुवाद, लिप्यंतरण और विश्लेषण की प्रक्रिया तेज एवं सटीक होगी.

सार्वजनिक सहभागिता एवं जन-जागरूकता

- स्कूल एवं विश्वविद्यालय स्तर पर डिजिटल प्रदर्शनी, व्याख्यान शृंखला, इंटर्नशिप कार्यक्रम और शोध प्रतियोगिताएँ आयोजित कर युवाओं को इस पहल से जोड़ा जाए. इससे इतिहास के प्रति जागरूकता और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी.

सुदृढ़ साइबर सुरक्षा एवं डेटा संरक्षण

- डिजिटल रिपॉजिटरी की सुरक्षा हेतु मल्टी-लेयर एन्क्रिप्शन, नियमित बैकअप, क्लाउड स्टोरेज और समय-समय पर साइबर ऑडिट अनिवार्य किए जाएँ. डेटा की प्रामाणिकता और अखण्डता बनाए रखना दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है.

बहुभाषीय एवं समावेशी पोर्टल

- पोर्टल को हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में विकसित किया जाए. साथ ही, दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के लिए भी अनुकूल इंटरफेस तैयार किया जाए, ताकि यह पहल वास्तव में समावेशी बन सके.
- **एकीकृत पोर्टल**—एक ऐसा पोर्टल विकसित हो जहाँ उपयोगकर्ता न केवल डेटा देख सके, बल्कि उस पर अपनी शोध टिप्पड़ियाँ भी साझा कर सकें.

निजी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) मॉडल

- तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है, बशर्ते कि डेटा की स्वामित्व एवं सुरक्षा सरकारी नियंत्रण में रहे.



सारांशतः भारतश्री पहल परिप्रेक्ष्य में केवल सांस्कृतिक संरक्षण की परियोजना नहीं, बल्कि इतिहास, प्रौद्योगिकी और सुशासन के संगम का उदाहरण है. यह भारत के 'विजिलेंट आर्काइविस्ट' (सतर्क पुरालेखपाल) के रूप में कार्य करेगा. यदि इसे प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और तकनीकी सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए उसे डिजिटल युग के अनुरूप सशक्त बना सकती है. ●●●

शेष पृष्ठ 122 का

- **हथियारों की नई दौड़ (Lethal Autonomous Weapons)**—AI आधारित स्वायत्त घातक हथियार या 'किलर रोबोट्स' का विकास युद्ध के स्वरूप को बदल रहा है, जिससे भविष्य में बिना मानवीय हस्तक्षेप के युद्ध होने का खतरा बढ़ गया है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए गम्भीर चिंता का विषय है.

आगे की राह

AI-आधारित विकास मॉडल अब लगभग अपरिहार्य है. हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन इसे 'मानवीय मूल्यों' के अनुरूप ढाल जरूर सकते हैं. एक संतुलित मार्ग अपनाने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं—

- **जिम्मेदार AI (Responsible AI)**—विकास के केन्द्र में 'नैतिकता' होनी चाहिए. एल्गोरिद्म का नियमित ऑडिट होना चाहिए ताकि पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सके.
- **मानव-इन-द-लूप Human-in-the-loop)**—महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतिम नियंत्रण हमेशा मनुष्य के हाथ में होना चाहिए.
- **कौशल पुनर्विकास (Re-skilling)**—सरकारों और कॉर्पोरेट्स को बड़े पैमाने पर शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना होगा ताकि कार्यबल को AI के साथ काम करने के योग्य बनाया जा सके.
- **पारदर्शी नियामक व्यवस्था**—एक ऐसी नियामकीय व्यवस्था की आवश्यकता है, जो नवाचार (Innovation) का गला न घोंटे, लेकिन सुरक्षा और निजता से समझौता भी न करे.

सारांशतः AI एक अत्यन्त शक्तिशाली साधन है. यह हमारे लिए एक 'अलादीन का चिराग' साबित हो सकता है, जो गरीबी, बीमारी और अज्ञानता को मिटा दे, बशर्ते हम इसके 'जीन' को नैतिकता और कानून की सीमाओं के भीतर रखना सीख लें. भविष्य उसी समाज का है, जो तकनीक के साथ अपनी मानवीय संवेदनाओं को भी बचाए रखेगा. ●●●

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



सार संग्रह

भारतीय इतिहास एवं संस्कृति

1. मजूमदार, दबीर, वाकनीस और सुरनीस किसके दरबार में अष्टप्रधान के अधिकारी थे ? ***– शिवाजी महाराज***
2. शेरशाह का मकबरा, हुमायूँ का मकबरा, जहाँगीरी महल, बुलन्द दरवाजा और बीबी का मकबरा कहाँ अवस्थित हैं ?
– क्रमशः सासाराम (बिहार), नई दिल्ली, आगरा (उत्तर प्रदेश), फतेहपुर सीकरी (उत्तर प्रदेश), औरंगाबाद (अब छत्रपति संभाजीनगर) महाराष्ट्र
3. कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, निष्काम कर्म योग और अस्पर्श योग में से कौन एक भागवत गीता की मुख्य शिक्षा है ?
– निष्काम कर्म योग (बिना फल की इच्छा के कर्म)
4. तबकति नासिरी, किताबुल हिन्द, तहकीक ए हिन्द, मज्ज्मउल बहनैन और सिर्र-ए-अकबर में से कौन एक दाराशिकोह की रचना है ? ***– मज्ज्मउल बहनैन***
5. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भक्ति में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है ? ***– काम (इन्द्रिय सुख या भोग)***
6. नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारम्भिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं ? ***– मेहरगढ़***
7. कौन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, जिसने 'प्रयाग-प्रशस्ति' की भी रचना की थी ? ***– हरिसेन***
8. 'क्षणिकवाद' का प्रतिपादन और 'अनात्मवाद सिद्धान्त' किस धर्म/दर्शन से सम्बन्धित है ? ***– बौद्ध धर्म/दर्शन से***
9. समुद्रगुप्त के 'प्रयाग-प्रशस्ति' में कोसल के शासक का क्या नाम मिलता है ? ***– राजा महेन्द्र***
10. महानदी का पौराणिक नाम 'नीलोत्पला' बताया गया है
– वायु पुराण में

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन

11. किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार (चाय और चीनी को छोड़कर) समाप्त किया गया था ? ***– 1813 का चार्टर एक्ट***
12. वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन और आजाद हिन्द फौज पर मुकदमा किस वर्ष हुईं प्रमुख घटनाएँ थी ? ***– वर्ष 1945***
13. संथाल विद्रोह, नील क्रान्ति, दक्खन कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा विद्रोह में से कौनसा आन्दोलन 1857 के विद्रोह से पूर्व हुआ था ? ***– संथाल विद्रोह (1855-56 ई.)***
14. 1857 की क्रान्ति के दो महान नेता कौन थे, जो नेपाल चले गए थे ? ***– नाना साहब एवं बेगम हजरत महल***
15. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए कौनसा बंगाली समाचार-पत्र रातोंरात में अंग्रेजी समाचार-पत्र में परिवर्तित हो गया था ? ***– अमृत बाजार पत्रिका***
16. सन् 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन की हड़ताल की थी, इसका नेतृत्व किसने किया था ?
– ठाकुर प्यारेलाल सिंह
17. महात्मा गाँधी ने नवम्बर 1933 में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग (छत्तीसगढ़) का दौरा किया था ?
– घनश्याम सिंह गुप्त
18. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का गठन 1885 में हुआ था. इसके पहले अधिवेशन [दिसम्बर 1885 में बम्बई (अब मुम्बई) में आयोजित] की अध्यक्षता की थी ? ***– व्योमेश चन्द्र बनर्जी***
19. पुर्तगाली हैडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला जाना और ब्लू वाटर पॉलिसी से सम्बन्धित पुर्तगाली गवर्नर थे
– क्रमशः अल्फांसो डी अल्बुकर्क और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा
20. यह लड़ाई 3 अगस्त, 1749 को लड़ी गई, इस युद्ध में, मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवर-उद्-दीन का मुकाबला किया जिसमें अनवर-उद्-दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा था ***– अंबुर का युद्ध***

भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान

21. किसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाते हुए संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300-A के तहत् विधिक अधिकार बना दिया गया था ?
– सम्पत्ति के अधिकार को
22. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जाँच एजेन्सी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में से कौन संवैधानिक निकाय हैं ?
– राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
23. भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरित कर दिया गया था ?
– 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा
24. नगरपालिका समितियाँ, वार्ड समितियाँ, महानगर आयोजना समिति व जिला आयोजना समिति का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था ?
– 74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992
25. राज्यों में विधायिका का गठन, विधान सभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और 'वित्त विधेयक' की परिभाषा किस अनुच्छेद से सम्बन्धित है ?
– क्रमशः अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 178 और अनुच्छेद 199
26. सन् 1989 में मतदान करने के अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत् की गई ? ***– 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम***
27. मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अन्तर्गत सम्मिलित हैं ? ***– क्रमशः अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23-24 और अनुच्छेद 14-18***
28. केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है ?
– अनुच्छेद 282

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

29. यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधान मण्डल के लिए निर्वाचित होता है, तो उसे कितने दिनों के अन्दर राज्य के विधान मण्डल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी ? ***– 14 दिन***

30. गुजरात, कर्नाटक, केरल और ओडिशा में राज्य सभा की सीटों की संख्या कितनी-कितनी हैं ? ***– क्रमश: 11, 12, 9 और 10***

पर्यावरण एवं जैव विविधता

31. आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है ***– समूह प्रजाति (Species)***

32. प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है ?
– उष्णकटिबंधीय प्रदेश

33. पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप हैं
– प्राथमिक उत्पादक (Primary Producers) या स्वपोषी (Autotrophs)

34. मीथेन, क्लोराफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में से कौनसी ग्रीनहाउस गैस नहीं है ? ***– नाइट्रोजन***

35. जमीन से वायुमण्डल के शीर्ष तक हवा के एक स्तम्भ में ओजोन की मोटाई को किस रूप में मापा जाता है ? ***– डॉब्सन इकाइयाँ***

36. भारत वर्तमान में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है ? ***– चौथे स्थान***

37. किन परिस्थितियों में एक कन्टेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी ?
– कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर

38. प्रति वर्ष 'विश्व वानिकी दिवस' मनाया जाता है ? ***– 21 मार्च***

39. 'मसाई मारा' राष्ट्रीय रिजर्व किस देश में अवस्थित है ?
– केन्या

40. 'पेरियार वन्यजीव अभयारण्य' भारत के किस राज्य में अवस्थित है ?
– केरल

भारत एवं विश्व का भूगोल

41. पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं ?
– नीलगिरि की पहाड़ियों

42. बैगा, कादर, मुरिया और खारिया में से कौनसी मध्य भारतीय भू-भाग की जनजाति नहीं है ?
– कादर (मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में)

43. कामेत, धौलागिरि, नामचा बरवा और नंगा पर्वत हिमालय की चोटियों में से कौनसी भारत में पूर्णत: स्थित नहीं हैं ?
– धौलागिरि (नेपाल में)

44. शिवालिक, कुमाऊँ हिमालय और कश्मीर हिमालय में से हिमालय की सबसे बाहरी शृंखला को क्या कहा जाता है ?
– शिवालिक

45. अल्टीसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स और एरिडिसोल्स मिट्टियों का आई.सी.ए. आर. द्वारा यू.एस.डी.ए. मृदा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम है
– एंटीसोल > एल्फीसोल > एरिडिसोल > अल्टीसोल

46. यह दर्रा जम्मू-कश्मीर में स्थित है, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है ***– जोजीला दर्रा***

47. तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है ? ***– म्यांमार से***

48. कपिलधारा व धुआँधार, शिवसमुद्रम और गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ?
– क्रमश: नर्मदा, कावेरी और घाटप्रभा नदी पर

49. चिनाब, व्यास, रावी और सतलज में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है ?
– सतलज (तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर-राकस झील से)

50. किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों के संचलन से होता है ? ***–विवर्तनिक झीलें***

भारतीय अर्थव्यवस्था

51. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है ?
– ₹20 लाख (तरुण प्लस श्रेणी)

52. बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)–(अप्रत्यक्ष कर–सब्सिडी) से निकाली जाती है ***– राष्ट्रीय आय (NI)***

53. अर्थशास्त्र में 2025 के स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार (नोबेल पुरस्कार) से किसे सम्मानित किया गया ?
– जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को

54. कैसी जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है ? ***– नाममात्र (Nominal) जीडीपी का***

55. व्यक्तिगत प्रयोज्य आय (पीडीआई) का सही सूत्र है
– पीडीआई = व्यक्तिगत आय–व्यक्तिगत कर भुगतान–गैर-कर भुगतान

56. मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका समन्वय होता है ?
–सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का

57. किसी अर्थव्यवस्था में छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है ?
–सीमान्त भौतिक उत्पादकता शून्य होती है

58. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है ?
–हैदराबाद में

59. 'उचित और लाभकारी मूल्य' किस फसल से सम्बन्धित है ?
– गन्ना

60. 'पेपर गोल्ड' पद का आशय है
– अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) का विशेष अधिकार (एस.डी.आर.)

सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी

61. ध्वनि की तीव्रता और विद्युत् धारा नापने की इकाई है
– क्रमश: डेसीबल और ऐम्पियर में

62. यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है ***– न्यूटन/मी^{2}***

63. SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है ? ***–डायोप्टर***

64. किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिम्ब के प्रतिबिम्ब की प्रकृति क्या होगी ?
– आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से छोटा

65. प्रकाश-संश्लेषण की प्रक्रिया में ए.टी.पी. के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं ?
– 18 ATP (एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट) और 12 NADPH के अणु

66. उर्ध्वाधर तल (एलिवेशन) एवं क्षैतिज तल (एजिमथ) में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है ***– थियोडोलाइट***

67. तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है ?
– समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



UPSC NEW BOOKS PDF

2026 EDITION

अब UPSC STANDARD BOOKS 2026 की PDF सीधे टेलीग्राम पर लें सकते है
बस हमारी टेलीग्राम बॉट पर मैसेज करें

Telegram Bot - @pdfhub2026bot

सीधे मैसेज भेजने के लिए MESSAGE NOW पर क्लिक करें

Message Now

68. लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है. इस परिघटना का कारण है ***–पृष्ठ तनाव***

69. चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है ? ***– पैन्थेरा टाइग्रिस***

70. मायोपिया से क्या तात्पर्य है ? ***–निकट दृष्टि दोष***

बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

71. बाल विकास में 'आनुवंशिकता' को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है ?
– स्थिर (Static) सामाजिक संरचना

72. पियाजे के अनुसार, संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चा 'वस्तु स्थायित्व' (Object Permanence) प्रदर्शित करता है ?
– संवेदी-प्रेरक अवस्था (Sensory-Motor Stage)

73. 'सीखने का सिद्धान्त' (Trial and Error Theory) किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ?
– एडवर्ड एल. थार्नडाइक द्वारा

74. कोहलबर्ग के अनुसार, नैतिक विकास के किस स्तर पर नैतिक निर्णय 'दण्ड और आज्ञाकारिता' पर आधारित होते हैं ?
– पूर्व-पारम्परिक स्तर (Pre-conventional Level)

75. समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
– सभी बच्चों को उनकी भिन्नताओं के बावजूद एक ही छत के नीचे नियमित स्कूल में शिक्षा देना

76. वाइगोत्सकी के अनुसार, बच्चे अपने से अधिक ज्ञानवान व्यक्ति की सहायता से जो कार्य कर पाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं ?
– समीपस्थ विकास का क्षेत्र (Zone of Proximal Development)

77. बुद्धि का 'बहुबुद्धि सिद्धान्त' (Theory of Multiple Intelligences) किसने दिया था ? ***– हावर्ड गार्डनर ने***

78. वह बालक जिसकी बुद्धि लब्धि (IQ) 140 से अधिक होती है, उसे किस श्रेणी में रखा जाता है ?
– प्रतिभाशाली (Gifted) श्रेणी में

79. 'प्रगतिशील शिक्षा' (Progressive Education) की अवधारणा के मुख्य समर्थक कौन थे ? ***– जॉन ड्यूवी (John Dewey)***

80. अधिगम अक्षमता (Learning Disability) के अन्तर्गत पढ़ने से सम्बन्धित विकार को क्या कहा जाता है ?
– डिस्लेक्सिया (Dyslexia)

सम्प्रेषण/संचार

81. वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें सन्देश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों ही अर्थों को साझा करते हैं ?
– प्रभावी सम्प्रेषण

82. संचार प्रक्रिया में 'डिकोडिंग' (Decoding) का मुख्य कार्य किसके द्वारा किया जाता है ? ***– संदेश प्राप्तकर्ता (Receiver) द्वारा***

83. किसी संगठन में उच्चाधिकारियों से अधीनस्थों की ओर होने वाला सूचना प्रवाह क्या कहलाता है ?
– अधोगामी सम्प्रेषण (Downward Communication)

84. अशाब्दिक संचार (Non-verbal Communication) में शारीरिक हाव-भाव और भंगिमाओं का अध्ययन क्या कहलाता है ? ***– काइनेसिक्स (Kinesics)***

85. सम्प्रेषण के दौरान आने वाली वह बाधा जो शब्दों के अलग-अलग अर्थ निकालने के कारण उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है ? ***– शब्दार्थ सम्बन्धी बाधा (Semantic Barrier)***

86. संचार में 'फीडबैक' (Feedback) या प्रतिपुष्टि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ?
– यह सुनिश्चित करना कि संदेश सही ढंग से समझा गया है

87. अनौपचारिक सम्प्रेषण जाल (Informal Communication Network) को अक्सर किस अन्य नाम से जाना जाता है ?
– ग्रेपवाइन (Grapevine) संचार

88. संचार प्रक्रिया के दौरान होने वाला कोई भी व्यवधान जो संदेश को विकृत कर देता है, क्या कहलाता है ? ***– शोर (Noise)***

89. स्वयं से बात करना या स्वयं को निर्देशित करना किस प्रकार का सम्प्रेषण है ?
– अंत:वैयक्तिक सम्प्रेषण (Intrapersonal Communication)

90. सम्प्रेषण के 7Cs सिद्धान्तों में 'Clarity' का क्या अर्थ है ? ***– संदेश का स्पष्ट और बोधगम्य होना***

कम्प्यूटर ज्ञान

91. आधुनिक कम्प्यूटर की खोज सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी ? ***– 1946 ई. में***

92. कम्प्यूटर की उस हार्डवेयर डिवाइस को क्या कहते हैं, जिसे सामान्यत: कम्प्यूटर का ब्रेन कहा जाता है ?
– CPU (सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट)

93. वह कम्प्यूटर हार्डवेयर जो बहुत बड़ी मात्रा में आँकड़ों को सुरक्षित रख सकता है, क्या कहलाता है ? ***– चिप***

94. किसी भी कम्प्यूटर प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि या एरर को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं ? ***– बग (Bug)***

95. किसी वेबसाइट के उस मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं, जो बाकी पृष्ठों के लिए प्रवेश मार्ग का कार्य करता है ? ***– होमपेज***

96. विज्ञान और गणना के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक कम्प्यूटर भाषा कौनसी है ? ***– FORTRAN***

97. दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कम्प्यूटर (Electronic Digital Computer) में मुख्य रूप से क्या लगा था ?
– वाल्व

98. वह कौनसी भाषा है, जो दुनिया के सभी कम्प्यूटरों में अनिवार्य रूप से लागू होती है ? ***– मशीनी भाषा***

99. तकनीकी क्षेत्र में एप्पल (APPLE) शब्द का क्या अर्थ है ?
– यह चौथी पीढ़ी का एक कम्प्यूटर है

100. सूचना और तकनीक के क्षेत्र में आँकड़ों के भण्डारण की सबसे छोटी और प्रभावी इकाई क्या मानी जाती है ? ***– चिप***

कृषि

101. भारत में रबी की फसलों की बुवाई मुख्य रूप से किन महीनों में की जाती है ? ***– अक्टूबर से नवम्बर के महीनों में***

102. खरीफ की फसलें जैसे—धान और मक्का किस ऋतु के आगमन पर बोई जाती हैं ?
– मानसून के आगमन (जून-जुलाई) के समय

103. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) का मुख्यालय कहाँ स्थित है ? ***– नई दिल्ली में***

104. 'कल्याण सोना' और 'सोनालिका' किस मुख्य खाद्य फसल की उन्नत किस्में हैं ? ***– गेहूँ की***

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

105. 'केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान' (CAZRI) राजस्थान के किस शहर में स्थित है ? ***– जोधपुर में***

106. भारत में 'पीली क्रांति' (Yellow Revolution) का सम्बन्ध किसके उत्पादन से है ? ***– तिलहन उत्पादन से***

107. जया, पद्मा और रत्ना किस अनाज की अधिक उपज देने वाली प्रमुख किस्में हैं ? ***– धान (चावल) की***

108. जायद की फसलों (जैसे–तरबूज, खीरा) का मुख्य समय-अन्तराल क्या होता है ? ***– मार्च से जून के बीच***

109. 'राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान' (NDRI) भारत के किस राज्य में स्थित है ? ***– करनाल, हरियाणा में***

110. कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाने वाली मिट्टी कौनसी है ? ***– काली मिट्टी (रेगुर मिट्टी)***

खेलकूद

111. प्रथम ओलम्पिक खेल कब आयोजित हुए थे ? ***– 776 ई. पू. में***

112. आधुनिक ओलम्पिक खेल का प्रथम आयोजन किस वर्ष हुआ था ? ***– 1896 ई. में***

113. ओलम्पिक ध्वज पर अंकित पाँच छल्ले (Rings) किसका प्रतिनिधित्व करते हैं ? ***– दुनिया के पाँच महाद्वीपों का***

114. ओलम्पिक खेलों का लेटिन भाषा में आदर्श वाक्य (Motto) क्या है ? ***– Citius, Altius, Fortius***

115. ओलम्पिक के आदर्श वाक्य 'Citius, Altius, Fortius' का अर्थ क्या होता है ? ***– और तेज, और ऊँचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन***

116. अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संस्था (IOC) का मुख्यालय कहाँ स्थित है ? ***– लॉसाने (स्विट्जरलैण्ड) में***

117. ओलम्पिक खेलों का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अन्तराल पर किया जाता है ? ***– प्रत्येक 4 वर्ष के अन्तराल पर***

118. 'ओलम्पिक' शब्द की उत्पत्ति 'ओलम्पस' से हुई है, यह किसका नाम है ? ***– एक पर्वत का***

119. भारत ने किस वर्ष ओलम्पिक खेलों में हॉकी का अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था ? ***– 1928 ई. के एमस्टर्डम ओलम्पिक में***

120. ओलम्पिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष और कहाँ से शुरू हुई ? ***– 1900 ई. के पेरिस ओलम्पिक से***

विविध

121. संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है ? ***– 24 अक्टूबर को***

122. संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक या मान्यता प्राप्त भाषाएँ कौन-कौनसी हैं ? ***– अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश और चीनी***

123. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं ? ***– 15***

124. खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का मुख्यालय कहाँ स्थित है ? ***– रोम (इटली) में***

125. यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन) की स्थापना किस वर्ष हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है ? ***– स्थापना 1946 में और मुख्यालय पेरिस (फ्रांस)***

126. भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार 'भारत रत्न' की शुरुआत किस वर्ष की गई थी ? ***– 1954 ई. में***

127. 'भारत रत्न' पुरस्कार का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते के समान बनाया गया है ? ***– पीपल के पत्ते की तरह***

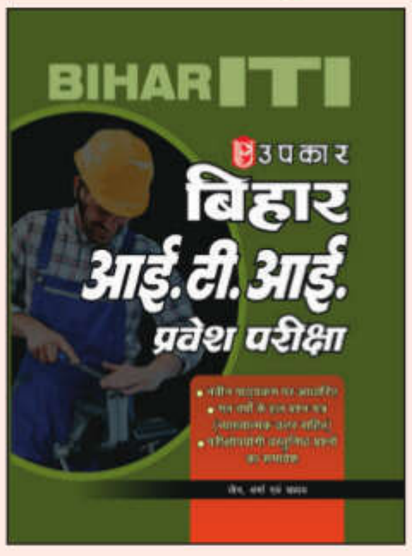
128. विश्व प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं ? ***– फिल्मों के क्षेत्र में***

129. भारत सरकार द्वारा अन्तरिक्ष आयोग और अन्तरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी ? ***– वर्ष 1972 में***

130. इण्डियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है ? ***– बेंगलुरु (कर्नाटक) में***

●●●

उपकार



Code 725 ₹ 485.00
लेखकगण
जैन, वर्मा एवं यादव

प्रमुख आकर्षण

- नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित
- गत वर्षों के हल प्रश्न-पत्र (व्याख्यात्मक उत्तर सहित)
- परीक्षोपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश

सॉल्वड् पेपर्स

Code 1443 ₹ 170.00

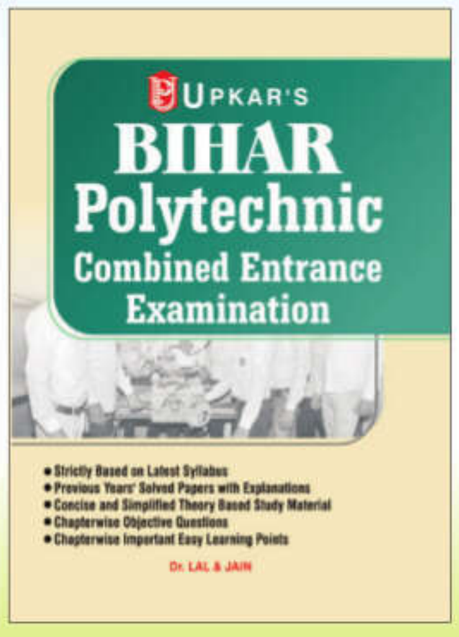
उपकार प्रकाशन, आगरा

• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

उपकार

गत वर्षों के प्रश्न-पत्र हल सहित





Code 282 ₹ 450.00 Code 477 ₹ 455.00

उपकार प्रकाशन, आगरा

• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया परिवीक्षाधीन अधिकारी (प्रा.) परीक्षा, 2025 (4-8-2025) का हल प्रश्न-पत्र

(प्रथम पाली)

Directions—(Q. 1 to 6) In the following passage, there are blanks, each of which has been denoted by a letter. For each blank, five options are given. Choose the most appropriate word from the options that fits the blank appropriately.

The controlled use of fire represents one of humanity's most …(1)… technological breakthroughs. Anthropologists believe our ancestors first …(2)… fire naturally caused by lightning strikes or volcanic activity. This accidental discovery eventually led to the …(3)… of techniques for creating and maintaining flames.

Early humans likely noticed how wildfires …(4)… their environment, both frightening and fascinating them. The first intentional use of fire for warmth and protection marked a …(5)… moment in human evolution. Over millennia, our ancestors developed increasingly sophisticated methods to …(6)… this powerful element, fundamentally changing the course of civilization.

1. Which of the following words will fit in the given blank (1) ?
   (A) trivial (B) seminal
   (C) negligible (D) redundant
   (E) derivative

2. Which of the following words will fit in the given blank (2) ?
   (A) extinguished
   (B) harnessed
   (C) squandered
   (D) circumvented
   (E) deprecated

3. Which of the following words will fit in the given blank (3) ?
   (A) dissolution
   (B) revocation
   (C) culmination
   (D) prohibition
   (E) inception

4. Which of the following words will fit in the given blank (4) ?
   (A) pacified (B) transmute
   (C) stabilized (D) sterilized
   (E) obliterated

5. Which of the following words will fit in the given blank (5) ?
   (A) perfunctory
   (B) pivotal
   (C) arbitrary
   (D) nominal
   (E) sporadic

6. Which of the following words will fit in the given blank (6) ?
   (A) manipulate
   (B) suppress
   (C) relinquish
   (D) contaminate
   (E) dismantle

Directions—(Q. 7 to 11) The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error.

7. Neither the supervisor nor the
   (A)
   workers / has received / the
   (B)
   updated safety manuals / from
   (C)
   the administration yet. /
   (D)
   No error
   (E)

8. Had she studied / more attenti-
   (A) (B)
   vely, she / will have cleared /
   (C)
   the entrance test. / No error
   (D) (E)

9. The manager insisted / that the
   (A)
   reports be submitted / before
   (B)
   noon, as punctuality / was some-
   (C)
   thing he considered to be. / No
   (D) (E)
   error

10. The officer was unaware / that
    (A)
    his assistant had / already sub-
    (B)
    mitted the documents / before
    (C)
    he reach the office. / No error
    (D) (E)

11. He was neither interested in the
    (A)
    opera / nor he wanted / to spend
    (B) (C)
    money / on the concert tickets. /
    (D)
    No error
    (E)

Directions—(Q. 12 to 15) Select the most appropriate option that can substitute the highlighted segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select 'No replacement required'.

12. **Were she to disclose the truth,** the entire committee would be in disarray.
    (A) If she discloses the truth
    (B) If she will disclose the truth
    (C) If she was to disclose the truth
    (D) If she had disclosed the truth
    (E) No replacement required

13. It is essential that every athlete **completes their registration before the deadline.**
    (A) completed their registration before the deadline
    (B) complete their registration before the deadline
    (C) completes his registration before the deadline

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

(D) should be completing their registration before the deadline
(E) No replacement required

14. He narrowly escaped **to be arrested by the border guards** while crossing the checkpoint.
(A) being arrested by the border guards
(B) to being arrested by the border guards
(C) to have been arrested by the border guards
(D) having arrested by the border guards
(E) No replacement required

15. Despite initial resistance, the village elders eventually **came round the proposal.**
(A) came across the proposal
(B) came around to the proposal
(C) came towards the proposal
(D) came about the proposal
(E) No replacement required

Directions—(Q. 16 to 23) Read the following passage and answer the given questions.

The strength of a nation is often measured not only by its economic output but by the stability, resilience, and well-being of its people. Economic growth stems from a combination of natural resources, infrastructure, governance and, most critically, investments in human capital. Countries that prioritize education and healthcare lay the foundation for long-term prosperity.

A **glaring** truth in today's global economy is that wealth alone cannot secure sustainable growth. Natural resource rich nations may enjoy short-term revenue surges, but without strong institutions and a skilled, healthy workforce, such progress risks becoming fragile. Education equips individuals with the skills needed for innovation, adaptability and competitiveness. Healthcare, in turn, ensures that citizens can contribute productively over the long term, reducing absenteeism and lowering the economic burden of disease.

For example, some resource-dependent nations have taken steps to diversify their economies by..... revenue into schools, training centers, hospitals and public health programs. Angola, in recent years, has made efforts to invest in education and healthcare to reduce its dependency on oil exports. By enhancing human capital, it aims to strengthen productivity and attract investment in sectors beyond its primary industries. While challenges remain, such measures show the potential for transforming short-term gains into lasting national strength.

However, the global economic environment remains uncertain. Trade disruptions, fluctuating commodity prices and geopolitical tensions can **stall** development plans, even in countries with ambitious social investment strategies. A **grim** example is when external shocks force governments to cut back on essential public spending, undermining years of progress in education and health sectors. The capacity to withstand such shocks depends heavily on diversified economies and robust fiscal planning.

National strength, therefore, is not built overnight. It requires consistent policies, transparent governance and the vision to balance immediate economic needs with long-term development goals. By fostering a population that is educated, healthy, and capable of innovation, nations can ensure resilience in the face of global uncertainty.

In conclusion, economic growth flourishes when it rests on a solid social foundation. Investments in human capital through education and healthcare are not only moral imperatives but strategic economic decisions. Whether resource-rich or resource-poor, nations that prioritize these areas strengthen their position in the world and secure prosperity for future generations.

16. According to the passage, what is a *key limitation* of relying solely on natural resource wealth ?
(A) It encourages overproduction and causes consistent price hikes in international markets
(B) It results in the neglect of rural populations who rely on agriculture
(C) It provides short-term gains but fails to build institutional and human capital strength
(D) It reduces the need for governance reforms and hinders diplomatic relations
(E) It ensures that countries focus excessively on education and ignore industrial growth

17. Which of the following is a *primary benefit* of investing in healthcare, as described in the passage ?
(A) Reducing population size through better family planning and urban migration
(B) Ensuring long-term productivity by lowering disease burden and absenteeism
(C) Increasing competitiveness in manufacturing exports and international tourism
(D) Redirecting public funding from education to disease surveillance
(E) Achieving better diplomatic ties through global medical collaborations

18. Which of the following is not a factor contributing to national strength as per the passage ?
1. Investment in human capital such as education and healthcare.
2. Strong governance that ensures consistent and transparent policy-making.
3. High dependence on a single export-oriented sector for economic growth.
(A) Only 1
(B) Both 2 and 3
(C) Only 3
(D) Both 1 and 2
(E) All 1, 2, 3

19. Identify the correct statements based on the passage :
1. Angola has been attempting to reduce dependence on oil by investing in people.
2. Global uncertainties make social investment in education and health risky and unwise.
3. Healthcare and education play both moral and economic roles in national development.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

(A) Only 1
(B) Both 1 and 3
(C) Both 2 and 3
(D) Both 1 and 2
(E) All 1, 2, 3

20. Choose the most appropriate **synonym** for the word **'glaring'** as used in the passage.
(A) Obvious (B) Hidden
(C) Subtle (D) Dismissible
(E) Moderate

21. Choose the most appropriate **synonym** for the word **'stall'** as used in the passage.
(A) Delay (B) Promote
(C) Encourage (D) Finalize
(E) Guarantee

22. Choose the most suitable word for the given filler.
(A) Hoarding
(B) Diverting
(C) Exhausting
(D) Concealing
(E) Channeling

23. Choose the most appropriate **antonym** for the word **'grim'** as used in the passage.
(A) Harsh (B) Bright
(C) Serious (D) Gloomy
(E) Bleak

Directions—(Q. 24 to 27) Select the most appropriate option to fill in the blanks.

24. The monk's teachings, though ancient, still ..... relevance today and continue to ..... seekers across the globe.
(A) retain, inspire
(B) attain, infuse
(C) detain, revive
(D) reclaim, console
(E) preserve, enlighten

25. The army commander's decision was ....., made without full information, and it ..... the entire mission.
(A) abrupt, jeopardized
(B) trivial, confirmed
(C) relevant, intensified
(D) delayed, fortified
(E) reckless, determine

26. The writer's latest novel is a ..... of realism and fantasy, carefully..... to challenge the reader's perception.
(A) paradox, hindered
(B) portrayal, composed
(C) blend, crafted
(D) dream, illustrated
(E) merger, dictated

27. The environmental report ..... that the region will face severe drought unless urgent steps are ..... .
(A) assures, neglected
(B) foresees, taken
(C) proposes, eliminated
(D) advocates, dismissed
(E) predicts, resplendent

Directions—(Q. 28 to 30) In the following questions, a sentence is divided into few parts. Rearrange these parts and identify the correct sequence making the sentence grammatically and contextually correct.

28. 1. for improving
2. student discipline
3. announced a new policy
4. the school principal
(A) 2, 1, 4, 3 (B) 4, 1, 2, 3
(C) 4, 3, 1, 2 (D) 2, 3, 1, 4
(E) No rearrangement required

29, 1. levels in the city
2. on reducing pollution
3. the new law had
4. a significant effect
(A) 1, 4, 2, 3 (B) 1, 3, 2, 4
(C) 2, 4, 1, 3 (D) 3, 4, 2, 1
(E) No rearrangement required

30. 1. the teacher's question
2. thoughtful answers
3. was designed to elicit
4. from the students
(A) 1, 4, 2, 3 (B) 1, 3, 2, 4
(C) 2, 4, 1, 3 (D) 3, 4, 2, 1
(E) No rearrangement required

Directions—(Q. 31 to 35) Rearrange the following sentences in the proper sequence to form a meaningful paragraph; then answer the questions given below them.

1. Coffee prices have shown signs of stabilization as new harvests approach, while orange juice supplies continue to struggle with long-term tree health issues.
2. Although both beverages were affected by supply shocks, the nature of disruptions and recovery timelines varied.
3. Meanwhile, orange juice prices spiked as Florida and Brazil, two major producers, battled diseases like citrus greening and hurricane damage.
4. Over the past year, global prices of both coffee and orange juice have surged significantly due to climate-related disruptions.
5. This comparative trend highlights how different agricultural vulnerabilities can cause varied price trajectories in global commodities.
6. Coffee-producing regions in Brazil faced severe droughts and unexpected frosts, leading to lower crop yields and higher prices.

31. Which of the following should be the FIRST sentence after rearrangement ?
(A) 4 (B) 1
(C) 3 (D) 5
(E) 2

32. Which of the following should be the SECOND sentence after rearrangement ?
(A) 2 (B) 5
(C) 6 (D) 1
(E) 4

33. Which of the following should be the THIRD sentence after rearrangement ?
(A) 4 (B) 3
(C) 6 (D) 5
(E) 1

34. Which of the following should be the FIFTH sentence after rearrangement ?
(A) 1 (B) 2
(C) 4 (D) 5
(E) 6

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

35. Which of the following should be the LAST sentence after rearrangement ?

(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 2
(E) 1

Directions—(Q. 36 to 38) In the following questions, a sentence is given with a few highlighted words that may be incorrectly placed. Rearrange these words to form a sentence that is both grammatically correct and contextually meaningful. Then, choose the option that represents the correct sequence of the highlighted words.

36. The stock **sector** (a) closed higher today, driven by **gains** (b) in the banking **market** (c).

(A) bac (B) cab
(C) acb (D) cba
(E) No rearrangement required

37. Heavy **rainfall** (a) caused delays in several **airport** (b) departing from the city **flights** (c).

(A) bac (B) cab
(C) acb (D) cba
(E) No rearrangement required

38. The new policy **areas** (a) to **improve** (b) traffic congestion and **reduce** (c) air quality in urban **aims** (d).

(A) bdac (B) cabd
(C) dcba (D) badc
(E) No rearrangement required

Directions—(Q. 39 to 40) A word has been given in the question and used in the sentences below. Identify the statements where the word has been used in a contextually and grammatically correct manner.

39. **COUNSEL**

1. The psychiatrist offered counsel to help the patient cope with anxiety and emotional distress.
2. The municipal counsel session lasted over four hours as members debated the proposed zoning changes.
3. She sought legal counsel before signing the complex contract to ensure her interests were protected.

(A) Only 1
(B) Only 2
(C) Both 1 and 2
(D) None of these
(E) Both 1 and 3

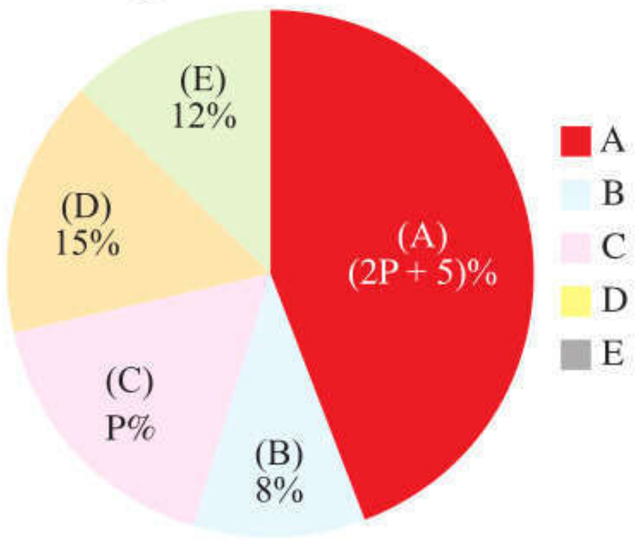
40. **GAIT**

1. The security guard stood at the **school** gait to check the identity cards of visitors.
2. The doctor assessed the patient's **gait** to check for any signs of mobility issues.
3. The **entrance gait** to the park was decorated with colourful lights for the festival.

(A) Only 1
(B) Only 2
(C) Both 1 and 2
(D) None of these
(E) Both 2 and 3

निर्देश—(प्रश्न 41 से 45 तक) नीचे दिया गया पाई-चार्ट पाँच शहरों (A, B, C, D, E) की कुल जनसंख्या को दर्शाता है.

कुल जनसंख्या = 1200



41. शहर F में, पुरुषों की जनसंख्या D की कुल जनसंख्या से 50% अधिक है और महिलाओं की जनसंख्या B और E की औसत जनसंख्या से 20% कम है. F की कुल जनसंख्या (पुरुष + महिला) C की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ?

(A) 152·5% (B) 118·46%
(C) 122·22% (D) 134·30%
(E) 142·29%

42. B और C की कुल जनसंख्या का योग तथा E की कुल जनसंख्या के बीच अन्तर ज्ञात कीजिए.

(A) 290 (B) 119
(C) 120 (D) 192
(E) 129

43. C में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 2 : 5 है और महिलाओं का बच्चों से अनुपात 1 : 1 है. C में बच्चों का E की कुल जनसंख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए.

(A) 36 : 11 (B) 21 : 19
(C) 22 : 21 (D) 23 : 36
(E) 25 : 36

44. शहर D और E की जनसंख्या शहर A और C की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक/कम है ?

(A) 53·20% (B) 58·46%
(C) 52·22% (D) 54·30%
(E) 42·29%

45. सभी शहरों की कुल जनसंख्या में से 35% महिलाएँ हैं और शहर D की कुल जनसंख्या का 55% महिलाएँ हैं. D को छोड़कर सभी शहरों में महिलाओं की कुल संख्या, शहर A की कुल जनसंख्या से कितनी अधिक/कम है ?

(A) 200 (B) 219
(C) 220 (D) 230
(E) 229

निर्देश—(प्रश्न 46 से 49 तक) जानकारी को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए–

दी गई जानकारी में तीन प्रकार के पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी और दूध पीने वाले लोगों (अर्थात् 100) की संख्या दर्शाती है. केवल चाय और कॉफी पसन्द करने वाले लोगों का अनुपात 5 : 3 है. केवल दूध पसन्द करने वाले लोगों की संख्या, केवल चाय और कॉफी दोनों पसन्द करने वाले लोगों के बराबर है. तीनों पेय पदार्थों को पसन्द करने वाले लोगों की संख्या 16 है. केवल दूध और चाय दोनों पसन्द करने वाले लोगों की संख्या, केवल कॉफी और दूध दोनों पसन्द करने वाले लोगों की संख्या से 30% अधिक है. केवल कॉफी और दूध दोनों पसन्द करने वाले लोगों की संख्या 20 है, जो केवल चाय पसन्द करने वाले लोगों की संख्या का दोगुना है.

46. केवल एक पेय पदार्थ पसन्द करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए.

(A) 27 (B) 22
(C) 21 (D) 25
(E) 20

47. कॉफी पसन्द करने वाले लोगों की संख्या, तीनों पेय पदार्थों को एक साथ पसन्द करने वाले लोगों का कितना प्रतिशत है ?

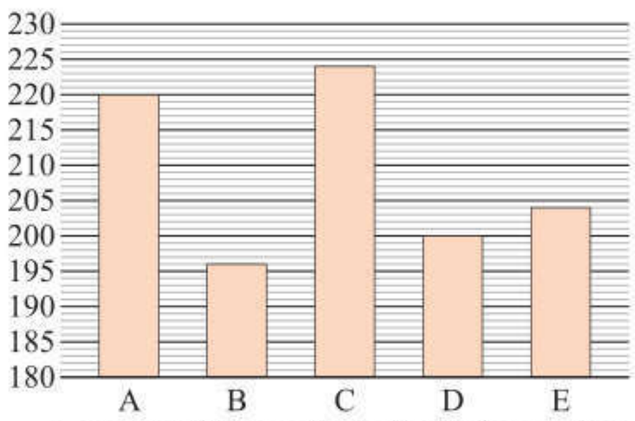
PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

(A) 314·25% (B) 331·25%
(C) 321·21% (D) 315·22%
(E) 310·12%

48. केवल दो पेय पदार्थ पसन्द करने वाले व्यक्तियों का, केवल कॉफी पसन्द करने वाले व्यक्तियों से अनुपात ज्ञात कीजिए.
(A) 14 : 11 (B) 7 : 10
(C) 2 : 19 (D) 19 : 2
(E) 10 : 7

49. दूध और चाय पसन्द करने वाले व्यक्तियों के बीच अन्तर ज्ञात कीजिए.
(A) 14 (B) 12
(C) 21 (D) 15
(E) 10

निर्देश—(प्रश्न 50 से 55 तक) नीचे दिया गया दण्ड-आरेख पाँच अलग-अलग कम्पनियों में स्नातक और स्नातकोत्तर कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाता है. तालिका स्नातक और स्नातकोत्तर कर्मचारियों के बीच अन्तर दर्शाती है.



■ स्नातक और स्नातकोत्तर कर्मचारी की कुल संख्या

कम्पनी	कम्पनियों के स्नातक-स्नातकोत्तर की कुल संख्या
A	4
B	2
C	36
D	90
E	96

नोट—कुल कर्मचारी = स्नातक + स्नातकोत्तर कर्मचारी

स्नातक कर्मचारी स्नातकोत्तर कर्मचारियों से अधिक होते हैं.

50. B और D में स्नातक कर्मचारियों की औसत संख्या तथा A और E में स्नातकोत्तर कर्मचारियों की औसत संख्या के बीच अन्तर ज्ञात कीजिए.
(A) 41 (B) 31
(C) 43 (D) 33
(E) 32

51. कम्पनी A में प्रबन्धक और सहयोगी का अनुपात 7 : 4 है. कम्पनी A में महिला प्रबन्धक पुरुषों की तुलना में 16·67% है. A में पुरुष प्रबन्धक और A में कुल सहयोगियों के बीच अन्तर ज्ञात कीजिए.
(A) 30 (B) 31
(C) 22 (D) 39
(E) 40

52. कम्पनी X में, कुल कर्मचारी A, C और E में कर्मचारियों की औसत संख्या है. A और X में स्नातक कर्मचारियों का अनुपात 1 : 1 है. X में स्नातकोत्तर कर्मचारियों और E में स्नातक कर्मचारियों का अनुपात ज्ञात कीजिए.
(A) 30 : 31 (B) 57 : 31
(C) 22 : 57 (D) 52 : 75
(E) 75 : 52

53. सभी कम्पनियों में स्नातक कर्मचारियों और स्नातकोत्तर कर्मचारियों के बीच अन्तर ज्ञात कीजिए.
(A) 230 (B) 232
(C) 222 (D) 233
(E) 228

54. C में स्नातक महिलाओं की कुल संख्या 50 है. स्नातक पुरुषों की संख्या स्नातकोत्तर महिलाओं की संख्या से 20 अधिक है. C में स्नातकोत्तर पुरुषों की संख्या D में स्नातकोत्तर कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक/कम है ?
(A) 13·30% (B) 31·31%
(C) 22% (D) 38·18%
(E) 32%

55. कम्पनी F में, कुल स्नातक कर्मचारी B में स्नातक कर्मचारियों की तुलना में 121 अधिक है. F में कुल कर्मचारी A में स्नातक कर्मचारियों की तुलना में 125% अधिक है. F में कुल स्नातकोत्तर कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए.
(A) 30 (B) 31
(C) 22 (D) 39
(E) 32

56. एक बर्तन में दूध और पानी का 139·96 लीटर मिश्रण है, जिसमें 80% दूध है. यदि मिश्रण का 24·96% निकाल दिया जाए और 19 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत (लगभग) कितना है ?
(A) 48 (B) 24
(C) 36 (D) 32
(E) 40

57. A और B मिलकर एक काम को 2T दिनों में कर सकते हैं और A अकेले उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है. यदि B अकेले उस काम को 5T दिनों में कर सकता है, तो T का मान ज्ञात कीजिए.
(A) 8 (B) 5
(C) 6 (D) 3
(E) 4

58. एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 12% शिक्षा पर और 7% किराए पर खर्च करता है. वह अपने वेतन का ₹ 10,250 SIP में निवेश करता है और अपने वेतन का $4x\%$ बचाता है. यदि उसका कुल मासिक वेतन ₹ 25,000 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए.
(A) 5 (B) 15
(C) 12 (D) 10
(E) 6

निर्देश—(प्रश्न 59 से 61 तक) नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं. आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उत्तर देना है.
(A) यदि $x > y$
(B) यदि $x \geq y$
(C) यदि $x < y$
(D) यदि $x \leq y$
(E) यदि $x = y$ या x और y के बीच कोई सम्बन्ध नहीं किया जा सकता है

59. I. $x^2 - 20x + 91 = 0$
II. $y^2 - 28y + 195 = 0$

60. I. $x^2 - 24x + 143 = 0$
II. $y^2 - 13y + 22 = 0$

61. I. $3x^2 - 15x + 18 = 0$
II. $y^2 - y - 6 = 0$

62. Y की वर्तमान आयु 28 वर्ष है और चार वर्ष बाद X की आयु का Y से अनुपात 7 : 8 होगा. यदि Z की वर्तमान आयु X की वर्तमान आयु से 25% अधिक है, तो छह वर्ष पहले Z की आयु ज्ञात कीजिए.
(A) 26 वर्ष (B) 22 वर्ष
(C) 20 वर्ष (D) 24 वर्ष
(E) 28 वर्ष

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

63. नाव A और B की स्थिर जल में गति का अनुपात क्रमशः 5 : 4 है. धारा की गति 15 किमी/घण्टा है. नाव A को धारा के अनुकूल 180 किमी की दूरी तय करने में 4·5 घण्टे लगते हैं. नाव B को धारा के प्रतिकूल 120 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ?
(A) 20 घण्टे (B) 36 घण्टे
(C) 24 घण्टे (D) 12 घण्टे
(E) 8 घण्टे

64. A और B एक साझेदारी व्यवसाय में 3 : 4 के अनुपात में निवेश करते हैं और A को ₹ 5,100 के कुल लाभ में से ₹ 2,700 लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त होते हैं. A और B के बीच समय अवधि का अन्तर 3 महीने हैं, तो ज्ञात कीजिए कि A में अपना निवेश कितने महीनों तक रखा ?
(A) 6 (B) 3
(C) 9 (D) 12
(E) 15

65. क्रमशः 400 मीटर और $(400 + x)$ मीटर लम्बी दो ट्रेनें A और B समान गति से चल रही हैं. यदि ट्रेन A और B क्रमशः 16 सेकण्ड और 24 सेकण्ड में एक खम्भे को पार करती हैं, तो ट्रेन 'B' 400 मीटर लम्बे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी ?
(A) 32 सेकण्ड (B) 40 सेकण्ड
(C) 45 सेकण्ड (D) 54 सेकण्ड
(E) 24 सेकण्ड

66. A ने योजना A में ₹ x का निवेश किया, जो चार वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है और उसे ₹ 2,160 का ब्याज प्राप्त होता है. यदि वह ₹ $(x + 500)$ योजना B में निवेश करता है, जो 10% प्रति वर्ष की दर से दो वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है, तो योजना B से उसे प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए.
(A) ₹ 1,090 (B) ₹ 1,205
(C) ₹ 1,120 (D) ₹ 870
(E) ₹ 1,050

67. एक कक्षा में 'x' लड़कों का औसत वजन 40 किग्रा है और उसी कक्षा में 18 लड़कियों का औसत वजन 25 किग्रा है. यदि कक्षा का कुल वजन 1410 किग्रा है, तो $2{\cdot}5x$ का मान ज्ञात कीजिए.
(A) 54 (B) 48
(C) 36 (D) 72
(E) 60

68. वृत्त P और वृत्त Q की परिधि का अन्तर 132 सेमी है. यदि वृत्त Q की त्रिज्या वृत्त P की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो वृत्त Q का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए (वर्ग सेमी में).
(A) 2404 (B) 2464
(C) 2214 (D) 2004
(E) 2124

69. एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर ₹ 96 कमाता है. यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य से 15% की छूट पर बेचता है, तो एक वस्तु बेचने पर खुदरा विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए.
(A) 118 (B) 177
(C) 236 (D) 214
(E) 154

70. यदि एक बेलन के आयतन और गोले के आयतन के बीच का अनुपात 3 : 1 है, तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है.
(A) 2 : 1 (B) 5 : 2
(C) 4 : 1 (D) 3 : 2
(E) 7 : 2

निर्देश—(प्रश्न 71 से 75 तक) निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए.

नौ बॉक्स–A, B, C, D, E, F, G, H और I को एक के ऊपर एक करके एक ही स्टैक में रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों. बॉक्स E और बॉक्स G के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है. बॉक्स I को बॉक्स G से तीन बॉक्स ऊपर रखा गया है. बॉक्स E को बॉक्स H से चार बॉक्स नीचे रखा गया है. बॉक्स H और बॉक्स I के बीच उतने ही बॉक्स रखे गए हैं जितने बॉक्स D और बॉक्स E के बीच में रखे गए हैं. बॉक्स E को बॉक्स D के ऊपर रखा गया है. बॉक्स F को बॉक्स C के ठीक नीचे रखा गया है. बॉक्स A और बॉक्स F के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं. बॉक्स B को बॉक्स A के ऊपर रखा गया है.

71. निम्नलिखित में से कौनसा बॉक्स, बॉक्स C से पाँच बॉक्स नीचे रखा गया है ?
(A) बॉक्स I (B) बॉक्स E
(C) बॉक्स H (D) बॉक्स B
(E) बॉक्स G

72. बॉक्स A के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं ?
(A) दो (B) चार
(C) छः (D) तीन
(E) पाँच

73. यदि सभी बॉक्स को नीचे से ऊपर तक वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने बॉक्स अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे ?
(A) दो (B) चार
(C) एक (D) तीन
(E) पाँच

74. निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सत्य है/हैं ?
1. बॉक्स C के नीचे चार से अधिक बॉक्स रखे गए हैं.
2. बॉक्स G को बॉक्स H के नीचे नहीं रखा गया है.
3. बॉक्स B को सबसे ऊपरी स्थान पर रखा गया है.
(A) 1 और 3 दोनों
(B) केवल 1
(C) केवल 3
(D) 1 और 2 दोनों
(E) सभी 1, 2 और 3

75. यदि बॉक्स F बॉक्स A से उसी प्रकार सम्बन्धित है जिस प्रकार बॉक्स C बॉक्स E से सम्बन्धित है, तो निम्नलिखित में से कौनसा बॉक्स बॉक्स I से सम्बन्धित है ?
(A) बॉक्स D (B) बॉक्स H
(C) बॉक्स G (D) बॉक्स E
(E) बॉक्स B

निर्देश—(प्रश्न 76 से 78 तक) नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद I और II से अंकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं. आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों. सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौनसा निष्कर्ष सर्वज्ञात तथ्यों को नज़रअंदाज़ करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है. उत्तर दीजिए–

(A) यदि केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है

(B) यदि केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

(C) यदि या तो निष्कर्ष I या II अनुसरण करता है
(D) यदि न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है
(E) यदि निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं

76. **कथन :** केवल कुछ प्रकाशन रोल्स हैं.
कुछ रोल खाते हैं.
कुछ खाते माँग हैं.

निष्कर्ष :
I. कोई रोल माँग नहीं है.
II. कुछ प्रकाशनों का माँग होना एक सम्भावना है.

77. **कथन :** केवल कुछ परिसम्पत्तियाँ राजस्व हैं.
कुछ राजस्व इक्विटी हैं.
कोई भी इक्विटी राजकोषीय नहीं है.

निष्कर्ष :
I. कुछ राजस्व राजकोषीय नहीं हैं.
II. सभी परिसम्पत्तियों का राजकोषीय होना एक सम्भावना है.

78. **कथन :** केवल कुछ लाभ नोटिस हैं.
कुछ नोटिस व्यय हैं.
सभी व्यय सब्सिडी हैं.

निष्कर्ष :
I. कुछ नोटिस सब्सिडी हैं.
II. कोई लाभ व्यय नहीं है.

79. शब्द 'NOSTALGIA' में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला शृंखला में होते हैं (आगे और पीछे दोनों दिशाओं में) ?
(A) एक (B) तीन
(C) कोई नहीं (D) दो
(E) चार

80. यदि हम 'FABRICATING' शब्द के बाएँ छोर से तीसरे, छठे, सातवें, नौवें और दसवें अक्षरों का प्रयोग करके एक पाँच अक्षरों का सार्थक शब्द बनाएँ, तो उस सार्थक शब्द के बाएँ छोर से चौथा अक्षर क्या होगा ? यदि कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है, तो उत्तर को X से चिह्नित करें. यदि एक से अधिक सार्थक शब्द बनते हैं, तो उत्तर को Z से चिह्नित करें.
(A) C (B) I
(C) A (D) X
(E) Z

निर्देश—(प्रश्न 81 से 85 तक) दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर दीजिए.

सात व्यक्ति–P, Q, R, S, T, U और V सात अलग-अलग महीनों यानी जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त और नवम्बर में अलग-अलग गतिविधियाँ करते हैं. ये गतिविधियाँ हैं–योग, ध्यान, नृत्य, लम्बी पैदल यात्रा, साइकिल चलाना, कैंपिंग और पढ़ना.

साइक्लिंग 30 दिनों वाले महीनों में की जाती है. S और साइक्लिंग करने वाले व्यक्ति के बीच तीन व्यक्ति हैं. S और T के बीच एक व्यक्ति है. T के बाद व्यक्तियों की संख्या योग करने वाले व्यक्ति से पहले वाले व्यक्तियों के समान है. P, नृत्य करने वाले व्यक्ति से ठीक पहले है. P और ध्यान करने वाले V के बीच तीन से अधिक व्यक्ति हैं. लम्बी पैदल यात्रा R से 30 दिन पहले वाले महीने में की जाती है. पढ़ाई Q से पहले की जाती है, जो लम्बी पैदल यात्रा नहीं करता है.

81. निम्नलिखित में से कौन जून में अपना कार्यकलाप करता है ?
(A) U (B) T
(C) R (D) S
(E) V

82. अगस्त में कौनसी गतिविधि की जाती है ?
(A) नृत्य (B) योग
(C) पढ़ना (D) कैम्पिंग
(E) ध्यान

83. निम्नलिखित में से कौनसा संयोजन गलत है ?
(A) P–पढ़ना (B) S–योग
(C) T–कैम्पिंग (D) V–ध्यान
(E) U–साइकिलिंग

84. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
(A) P और T के बीच दो व्यक्ति हैं
(B) ध्यान नवम्बर में किया जाता है
(C) आप जून में लम्बी पैदल यात्रा करते हैं
(D) R, S से पहले साइकिल चलाता है
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

85. T किस महीने में कैम्पिंग करता है ?
(A) जून (B) अगस्त
(C) जनवरी (D) जुलाई
(E) मार्च

निर्देश—(प्रश्न 86 से 90 तक) दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए.

14 व्यक्ति दो समानान्तर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में सात व्यक्ति हैं. A, B, C, D, E, F और G पंक्ति-1 में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, जबकि P, Q, R, S, T, U और V पंक्ति-2 में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों. पंक्ति-1 के व्यक्ति पंक्ति 2 के व्यक्तियों के सम्मुख हैं. B और D के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं. D एक छोर पर बैठा है. Q और B के सम्मुख व्यक्ति के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं. Q और T के बीच एक व्यक्ति बैठा है. U, S के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, लेकिन D के विपरीत नहीं बैठा है. A और S के सम्मुख व्यक्ति के बीच एक व्यक्ति बैठा है. G, C के ठीक दाईं ओर बैठा है. P, C के सम्मुख नहीं है. F और V के दाईं ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है.

86. R और P के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं ?
(A) कोई नहीं (B) एक
(C) दो (D) तीन
(E) चार

87. निम्नलिखित में से कौन D की ओर उन्मुख है ?
(A) R (B) T
(C) Q (D) P
(E) S

88. निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सत्य है/हैं ?
1. P, G के सम्मुख है.
2. F और E के बीच एक व्यक्ति बैठा है.
3. R किसी एक छोर पर बैठा है.
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 1 और 3
(E) सभी सत्य हैं

89. निम्नलिखित पाँच जोड़ों में से चार एक समूह से सम्बन्धित एक निश्चित तरीके से समान हैं, निम्नलिखित में से कौनसा दूसरों से भिन्न है ?
(A) S–C (B) Q–F
(C) V–G (D) P–A
(E) R–C

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

90. यदि पंक्ति-1 के व्यक्तियों को बाएँ से वर्णानुक्रम में बैठाया जाए, तो कौन अपने पिछले स्थान पर रहेगा ?
(A) केवल B और F
(B) केवल F
(C) केवल A
(D) केवल B और E
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश—(प्रश्न 91 से 95 तक) दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर दीजिए.

सात व्यक्ति–K, L, M, N, O, P और Q का जन्म (दिए गए क्रम में नहीं) एक ही महीने की एक ही तारीख को, लेकिन अलग-अलग वर्ष में हुआ था.

1955, 1961, 1972, 1987, 1998, 2006, 2017 आयु गणना के लिए आधार वर्ष 2025 पर विचार कीजिए.

M की आयु एक संख्या का घन है. M और K के बीच 11 वर्ष का अन्तर है. K और P के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं. N, Q से 32 वर्ष बड़ा है. L की आयु एक संख्या का घन है. L और K के बीच आयु का अन्तर 10 वर्ष से अधिक है.

91. कितने व्यक्ति O से बड़े हैं ?
(A) एक (B) दो
(C) तीन (D) चार
(E) चार से अधिक

92. N और K के बीच आयु का अन्तर क्या है ?
(A) 51 वर्ष (B) 32 वर्ष
(C) 43 वर्ष (D) 17 वर्ष
(E) इनमें से कोई नहीं

93. निम्नलिखित में से किसका जन्म 1972 में हुआ था ?
(A) K (B) Q
(C) L (D) O
(E) P

94. निम्नलिखित पाँच में से चार एक निश्चित तरीके से समान हैं और एक समूह बनाते हैं. निम्नलिखित में से कौन समूह से सम्बन्धित नहीं है ?
(A) N (B) M
(C) Q (D) L
(E) P

95. वह व्यक्ति जो O से छोटा है, उसका जन्म किस वर्ष में हुआ था ?
(A) 1972 (B) 1987
(C) 2006 (D) 1998
(E) 2017

निर्देश—(प्रश्न 96 से 100 तक) निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए.

सात व्यक्ति–A, B, C, D, E, F और G एक गोलाकार मेज के चारों ओर केन्द्र की ओर मुख करके बैठे हैं. उनमें से प्रत्येक अलग-अलग शहरों–जयपुर, मेरठ, पुणे, आगरा, भोपाल, राँची और सूरत से हैं. नीचे दी गई जानकारी आवश्यक रूप से एक जैसी नहीं है. C, जयपुर से आए व्यक्ति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है. जयपुर और पुणे से आए व्यक्तियों के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं. G, पुणे से आए व्यक्ति के बाईं ओर से पाँचवें स्थान पर बैठा है और आगरा से आने वाले व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है. E आगरा से आने वाले व्यक्ति के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है. D, राँची से आने वाले A के दाएँ से चौथे स्थान पर बैठा है. F जयपुर से नहीं है. F और मेरठ से आने वाले व्यक्ति एक-दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं. G भोपाल से नहीं है.

96. मेरठ से सम्बन्धित व्यक्ति के दाएँ से चौथे स्थान पर कौन बैठा है ?
(A) वह व्यक्ति जो भोपाल से है
(B) वह व्यक्ति जो आगरा से है
(C) B
(D) G
(E) वह व्यक्ति जो पुणे से है

97. निम्नलिखित में से कौनसा संयोजन सही है ?
(A) E–जयपुर (B) F–मेरठ
(C) G–आगरा (D) D–पुणे
(E) C–भोपाल

98. A के सन्दर्भ में सूरत से सम्बन्धित व्यक्ति का स्थान क्या है ?
(A) दाईं ओर दूसरा
(B) बाएँ से चौथा
(C) दाईं ओर से पाँचवाँ
(D) बाएँ से पाँचवाँ
(E) दाईं ओर चौथा

99. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?
(A) B, D के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है
(B) आगरा का व्यक्ति E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है
(C) C, पुणे से आए व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है
(D) G सूरत से है
(E) A, G के ठीक दाएँ बैठा है

100. E और B के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति किस शहर से है ?
(A) आगरा (B) सूरत
(C) पुणे (D) भोपाल
(E) इनमें से कोई नहीं

उत्तर व्याख्या सहित

1. (B) 'Seminal' means strongly influencing later developments. It is a fitting description for a pivotal moment in human history.
2. (B) The sentence states that anthropologists believe our ancestors first controlled or utilized fire caused naturally by lightning or volcanoes. 'Harnessed' means to utilize or control a natural resource, which matches the context of early humans learning to control fire.
3. (E) The sentence discusses the 'accidental of techniques' which led to creating flames. 'Inception' means the beginning or start of something, fitting the context of the initial discovery and development of fire-making techniques.
4. (E) 'Obliterated' means destroyed completely. As wildfires are known for destruction, this word fits both contextually and descriptively.
5. (B) 'Pivotal' means of crucial importance in relation to the development or success of something else. The first intentional use of fire marked a pivotal moment in human evolution, indicating its critical role in human history.
6. (A) 'Manipulate' means to handle or control something with skill. Our ancestors developed increasingly sophisticated methods to manipulate this powerful element, referring to their growing ability to manage and use fire.
7. (B) When two subjects are joined by 'neither.....nor', the verb should agree with the subject closest to it. In this case, 'workers' is a plural subject, so

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

the plural verb 'have' should be used instead of 'has'.

8. (C) This sentence uses the third conditional structure, which describes a hypothetical situation in the past and its potential outcome. The correct structure requires the use of 'would have' in the result clause, not 'will have'. The correct phrasing is 'she would have cleared the entrance test'.

9. (D) The verb 'to be' is transitive and requires an object or a complement to complete its meaning in this context. The sentence ends abruptly with 'considered to be' without specifying what punctuality was considered to be. A correct sentence might end with 'considered to be a virtue' or simply 'considered important' or even 'was something he considered important'.

10. (D) The sentence describes actions completed in the past. The phrase 'before he reach the office' uses the simple present tense verb 'reach', which is incorrect in this context. It should be in the simple past tense, 'reached'.

11. (B) The error is in part (B) because when using the correlative conjunction 'neither... nor', the sentence structure after 'nor' should be parallel to the structure after 'neither'. The correct construction requires 'nor' to be immediately followed by the subject and verb to maintain parallelism, or, for emphasis, an inversion of the subject and auxiliary verb.

12. (E) The highlighted segment 'Were she to disclose the truth' is an example of an inverted conditional sentence, which is a grammatically correct and formal way of expressing a hypothetical condition.

13. (B) The sentence uses the subjunctive mood, which is required after expressions of necessity, importance, or urgency like 'It is essential that'. In the present subjunctive, the base form of the verb is used regardless of the subject. Thus, 'completes' should be 'complete'. The pronoun 'their' is acceptable as a gender-neutral singular pronoun in modern English when referring to 'every athlete'.

14. (A) The verb 'escape' is typically followed by a gerund (the –ing form of a verb) or a prepositional phrase, not an infinitive (to be arrested). The correct grammatical structure after 'escaped' is 'being arrested' to form a gerund phrase.

15. (B) The original phrasing 'came round the proposal' is an incorrect idiom; 'around to' is the correct prepositional phrase in this context.

16. (C) The passage discusses how nations, whether resource-rich or resource-poor, strengthen their position by prioritizing investments in human capital (education and healthcare). It implies that relying solely on natural resources is insufficient for long-term national strength.

17. (B) Better health reduces disease burden and absenteeism, directly contributing to long-term productivity.

18. (C) Statement (3) is not a contributing factor. In fact, the passage warns against 'high dependence on a single export oriented sector', stating it leads to fragile progress.

19. (B)

20. (A) The word 'glaring' typically means something very obvious or conspicuous, often in an unfavorable way.

21. (A) To 'stall' means to stop or delay a process or action.

22. (E) The sentence discusses countries intentionally directing their resource revenues into constructive sectors like education and healthcare. The correct word must reflect this purposeful allocation is 'channeling'. It means directing something toward a specific use or purpose.

23. (B) In the context of the passage, 'grim' describes a situation that is disturbing, depressing, or bleak a negative, serious condition where progress is hindered. So, the correct antonym would express positivity or hopefulness is 'Bright'.

24. (A) The sentence structure and meaning require a pair of words that logically complete the thought about the monk's teachings. 'Retain' fits the first blank as the teachings continue to hold onto their relevance, and 'inspire' fits the second blank as the purpose of such teachings is often to motivate or uplift seekers.

25. (A) The word 'abrupt' means sudden and unexpected, which fits the context of a decision made 'without full information'. This decision then 'jeopardized' the entire mission.

26. (C) A novel combining realism and fantasy is a 'blend' of genres. The word 'crafted' fits the context of something carefully made to challenge perceptions.

27. (B) The words 'foresees' and taken' fit the context of an environmental report predicting a future problem and the need for action.

28. (C) The complete sentence is "The school principal announced a new policy for improving student discipline".

29. (D) The complete sentence is "The new law had a significant effect on reducing pollution levels in the city".

30. (B) The complete sentence is "The teacher's question was designed to elicit thoughtful answers from the students".

31. (A) Over the past year, global prices of both coffee and orange juice have surged significantly due to climate-related disruptions.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

32. (C) Coffee-producing regions in Brazil faced severe droughts and unexpected frosts, leading to lower crop yields and higher prices.

33. (B) Meanwhile, orange juice prices spiked as Florida and Brazil, two major producers, battled diseases like citrus greening and hurricane damage.

34. (A) Coffee prices have shown signs of stabilization as new harvests approach, while orange juice supplies continue to struggle with long-term tree health issues.

35. (C) This comparative trend highlights how different agricultural vulnerabilities can cause varied price trajectories in global commodities.

36. (D) Restructured sentence is "The stock market closed higher today, driven by gains in the banking sector".

37. (C) Restructured sentence is "Heavy rainfall caused delays in several flights departing from the city airport".

38. (C) Restructured sentence is "The new policy aims to reduce traffic congestion and improve air quality in urban areas".

39. (E) The word 'counsel' is a noun meaning advice or guidance, especially from a professional, or a lawyer or group of lawyers engaged in a case. It can also be a verb meaning to give advice.

40. (B) The word 'gait' refers to a person's or animal's manner of walking.

प्रश्न 41 से 45 तक के लिए–

कुल जनसंख्या = 1200

$(12 + 2P + 5 + 8 + P + 15)\% = 100\%$

$3P + 40 = 100$

$3P = 60$

$P = 20$

शहर A में जनसंख्या

$$= \frac{1200 \times (2P \boxtimes 5)}{100}$$

$= 12 \times 45 = 540$

शहर B में जनसंख्या

$$= \frac{1200 \times 8}{100} = 96$$

शहर C में जनसंख्या

$$= \frac{1200 \times P}{100}$$

$= 12 \times 20$

$= 240$

शहर D में जनसंख्या

$$= \frac{1200 \times 15}{100} = 180$$

शहर E में जनसंख्या

$$= \frac{1200 \times 12}{100} = 144$$

41. (A) शहर F में पुरुष जनसंख्या

$$= \frac{180 \times 15}{100} = 270$$

शहर F में महिला जनसंख्या

$$= \left(\frac{96 \boxtimes 144}{2}\right) \times \frac{80}{100}$$

$$= \frac{120 \times 80}{100} = 96$$

∴शहर F की कुल जनसंख्या

$= 270 + 96$

$= 366$

अभीष्ट प्रतिशत

$$= \frac{366}{240} \times 100$$

$= 152{\cdot}5\%$

42. (D) अभीष्ट अन्तर

$= 96 + 240 - 144$

$= 192$

43. (E) पुरुष : महिला : बच्चे

2 : 5

$1 \times 5 : 1 \times 5$

2 : 5 : 5

शहर C में बच्चों की संख्या

$$= \frac{240}{12} \times 5$$

$= 100$

अभीष्ट अनुपात = 100 : 144

= 25 : 36

44. (B) 45. (B)

प्रश्न 46 से 49 तक के लिए–

पेय पदार्थ पसन्द करने वाले लोगों की कुल संख्या = 100

तीनों पेय पदार्थ पसन्द करने वाले लोगों की संख्या = 16

केवल कॉफी और दूध दोनों पसन्द करने वाले लोगों की संख्या = 20

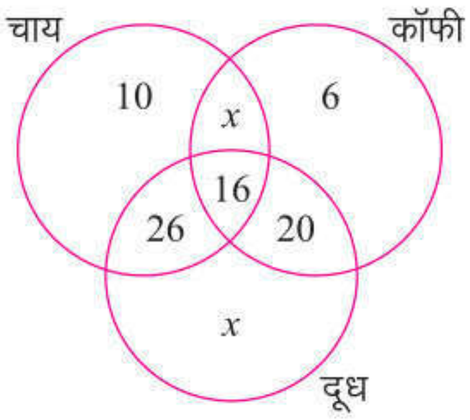
केवल चाय पसन्द करने वाले लोगों की संख्या = 10

केवल कॉफी पसन्द करने वाले लोगों की संख्या = 6

केवल दूध और चाय दोनों पसन्द करने वालों की संख्या

$$= \frac{20 \times 130}{100} = 26$$

केवल दूध पसन्द करने वाले लोगों की संख्या = केवल चाय और कॉफी दोनों पसन्द करने वाले लोग = x (माना)



$16 + 20 + 26 + 10 + 6 + 2x$

$= 100$

$2x = 100 - 78$

$2x = 22$

$x = 11$

46. (A) केवल एक पेय पदार्थ पसन्द करने वाले व्यक्तियों की संख्या

$= 10 + 6 + 11$

$= 27$

47. (B) कॉफी पसन्द करने वाले लोग

$= 11 + 6 + 20 + 16$

$= 53$

अभीष्ट प्रतिशत $= \frac{53}{16} \times 100$

$= 331{\cdot}25\%$

48. (D) अभीष्ट अनुपात

$= 26 + 20 + 11 : 6$

$= 57 : 6 = 19 : 2$

49. (E) दूध पसन्द करने वाले लोग

$= 11 + 26 + 20 + 16$

$= 73$

चाय पसन्द करने वाले लोग

$= 10 + 11 + 26 + 16$

$= 63$

अभीष्ट अन्तर = 73 – 63 = 10

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

प्रश्न 50 से 55 तक के लिए–

स्नातक कर्मचारी > स्नातकोत्तर कर्मचारी

कम्पनी	कुल कर्मचारी (स्नातक + स्नातकोत्तर)	स्नातक	स्नातकोत्तर
A →	220	112	108
B →	196	99	97
C →	224	130	94
D →	200	145	55
E →	204	150	54
कुल →	**1044**	**636**	**408**

50. (A) B और D में स्नातक कर्मचारियों की औसत संख्या

$$= \frac{99+145}{2} = 122$$

A और E में स्नातकोत्तर कर्मचारियों की औसत संख्या

$$= \frac{108+54}{2} = 81$$

अभीष्ट अन्तर = 122 – 81 = 41

51. (E)

52. (D) कम्पनी X में कुल कर्मचारी

$$= \frac{220+224+204}{3}$$

= 216

कम्पनी X में स्नातकोत्तर कर्मचारियों की संख्या

= 216 – 112 = 104

अभीष्ट अनुपात

= 104 : 150

= 52 : 75

53. (E) अभीष्ट अन्तर

= 636 – 408

= 228

54. (D) कम्पनी C में स्नातक पुरुषों की संख्या

= 130 – 50

= 80

कम्पनी C में स्नातकोत्तर महिलाओं की संख्या = 80 – 20

= 60

कम्पनी C में स्नातकोत्तर पुरुषों की संख्या = 94 – 60 = 34

$$\text{कमी \%} = \frac{(55-34)}{55}\times 100$$

$$= \frac{21}{55}\times 100$$

= 38·18%

55. (E) कम्पनी F में स्नातक कर्मचारी

= 99 + 121 = 220

कम्पनी F में कुल कर्मचारी

$$= \frac{112\times 225}{100} = 252$$

कम्पनी F में कुल स्नातकोत्तर कर्मचारी

= 252 – 220 = 32

56. (D)

57. (D) A और B को मिलकर कार्य करने में लगा समय

$$= \frac{A\times B}{A+B}$$

$$2T = \frac{10\times 5T}{10+5T}$$

$$2T(10+5T) = 10\times 5T$$

$$10+5T = 25$$

$$5T = 15$$

$$T = 3$$

58. (D) व्यक्ति का मासिक वेतन

= ₹ 25,000

SIP में निवेश के बाद शेष वेतन

= 25000 – 10250

= ₹ 14,750

प्रश्नानुसार,

$$\frac{25000\times(12+7+4x)}{100} = 14750$$

$$19+4x = 59$$

$$4x = 40$$

$$x = 10$$

59. (D) I. $x^2 - 20x + 91 = 0$

$$x^2 - 13x - 7x + 91 = 0$$

$$x(x-13) - 7(x-13) = 0$$

$$(x-13)(x-7) = 0$$

$$x = 13, 7$$

II. $y^2 - 28y + 195 = 0$

$$y^2 - 13y - 15y + 195 = 0$$

$$y(y-13) - 15(y-13) = 0$$

$$(y-13)(y-15) = 0$$

$$y = 13, 15$$

$$x \le y$$

60. (B) 61. (E)

62. (D) Y की वर्तमान आयु = 28 वर्ष

	X	:	Y
4 वर्ष बाद–	7	:	8

8 इकाई = 28 + 4

$$\therefore \quad 7 \text{ इकाई} = \frac{32}{8}\times 7 = 28 \text{ वर्ष}$$

Z की वर्तमान आयु

$$= \frac{(28-4)\times 125}{100}$$

$$= \frac{24\times 5}{4} = 30 \text{ वर्ष}$$

अतः 6 वर्ष पहले Z की आयु

= 30 – 6 = 24 वर्ष

63. (C)

64. (C) लाभ = निवेश × समय

$$\text{समय} = \frac{\text{लाभ}}{\text{निवेश}}$$

कुल लाभ = ₹ 5,100

A का लाभ = ₹ 2,700

B का लाभ = ₹ 2,400

	A	:	B
पूँजी →	3	:	4
लाभ →	9	:	8
समय →	x	:	y (माना)

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{2}$$

1 इकाई = 3 महीने

A का निवेश समय

= 3 × 3 = 9 महीने

65. (B)

66. (E) साधारण ब्याज

$$= \frac{\text{मूलधन}\times\text{दर}\times\text{समय}}{100}$$

$$2160 = \frac{x\times 12\times 4}{100}$$

x = ₹ 4,500

योजना B में निवेश राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज

$$= \frac{5000\times 21}{100} = ₹\ 1{,}050$$

67. (E) प्रश्नानुसार, 1410

$$= 40\times x + 18\times 25$$

$$1410 = 40x + 450$$

$$40x = 960$$

$$x = 24$$

अतः $2{\cdot}5x = 2{\cdot}5\times 24 = 60$

68. (B) माना वृत्त P की त्रिज्या = r

तो वृत्त Q की त्रिज्या = $4r$

प्रश्नानुसार,

$$2\pi 4r - 2\pi r = 132$$

$$2\pi(4r-r) = 132$$

$$2\times\frac{22}{7}\times 3r = 132$$

r = 7 सेमी

वृत्त Q की त्रिज्या

= 7 × 4 = 28 सेमी

वृत्त Q का क्षेत्रफल

$$= \frac{22}{7}\times 28\times 28$$

= 2464 सेमी^{2}

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

69. (B) $35\% = \frac{7}{20}$

$$\frac{MP}{CP} = \frac{27}{20}$$

20% छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य

$$= \frac{27 \times 80}{100} = 21{\cdot}6$$

1·6 इकाई = ₹ 96

1 इकाई = ₹ 60

15% छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य

$$= \frac{27 \times 85}{100}$$

$$= 22{\cdot}95$$

लाभ = विक्रय मूल्य – क्रय मूल्य

= 22·95 – 20 = 2·95

2·95 इकाई = 2·95 × 60

= ₹ 177

70. (B) गोले की त्रिज्या = बेलन की त्रिज्या

$$\frac{\text{बेलन का आयतन}}{\text{गोले का आयतन}} = \frac{3}{1}$$

$$\frac{\pi r^2 h}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{3}{1}$$

$$\frac{h}{r} = \frac{4}{1}$$

$$h = 4r$$

$$\frac{\text{बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल}}{\text{गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल}}$$

$$= \frac{2\pi r(r \boxtimes h)}{4\pi r^2}$$

$$= \frac{r \boxtimes 4r}{2r} = \frac{5}{2}$$

प्रश्न 71 से 75 तक के लिए–

बक्से
B
H
C
F
I
E
A
G
D

71. (E) 72. (C) 73. (A) 74. (A)
75. (B)

प्रश्न 76 से 78 तक के लिए–

76. (B)



निष्कर्ष– I. (×)

II. (√)

77. (E)



निष्कर्ष– I. (√)

II. (√)

78. (A)

निष्कर्ष– I. (√)

II. (×)

79. (B) N O S T A L G I A

80. (B) प्रश्नानुसार,

सार्थक शब्द—CABIN

बाएँ छोर से चौथा अक्षर—I

प्रश्न 81 से 85 तक के लिए–

महीने	गतिविधि	व्यक्ति
जनवरी	पढ़ना	P
मार्च	नृत्य	Q
अप्रैल	योग	S
जून	लम्बी पैदल यात्रा	U
जुलाई	कैंपिंग	T
अगस्त	ध्यान	V
नवम्बर	साइकिल चलाना	R

81. (A) 82. (E) 83. (E) 84. (C)
85. (D)

प्रश्न 86 से 90 तक के लिए–



86. (D) 87. (E) 88. (C) 89. (A)

90. (B) प्रश्न से–

C G B E A F B
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
A B C D E F G

प्रश्न 91 से 95 तक के लिए–

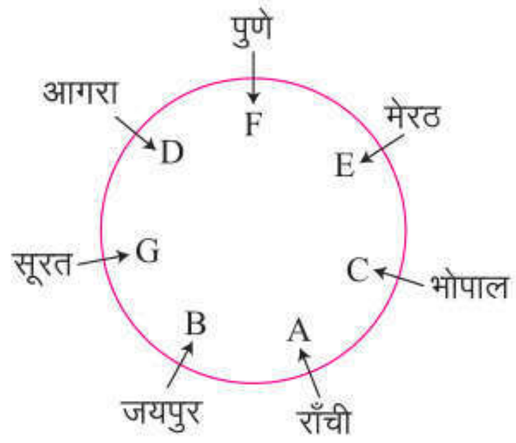
वर्ष	उम्र	व्यक्ति
1955	70	N
1961	64	M
1972	53	K
1987	38	Q
1998	27	L
2006	19	O
2017	8	P

91. (E)
92. (D) अभीष्ट अन्तर = 70 – 53

= 17 वर्ष

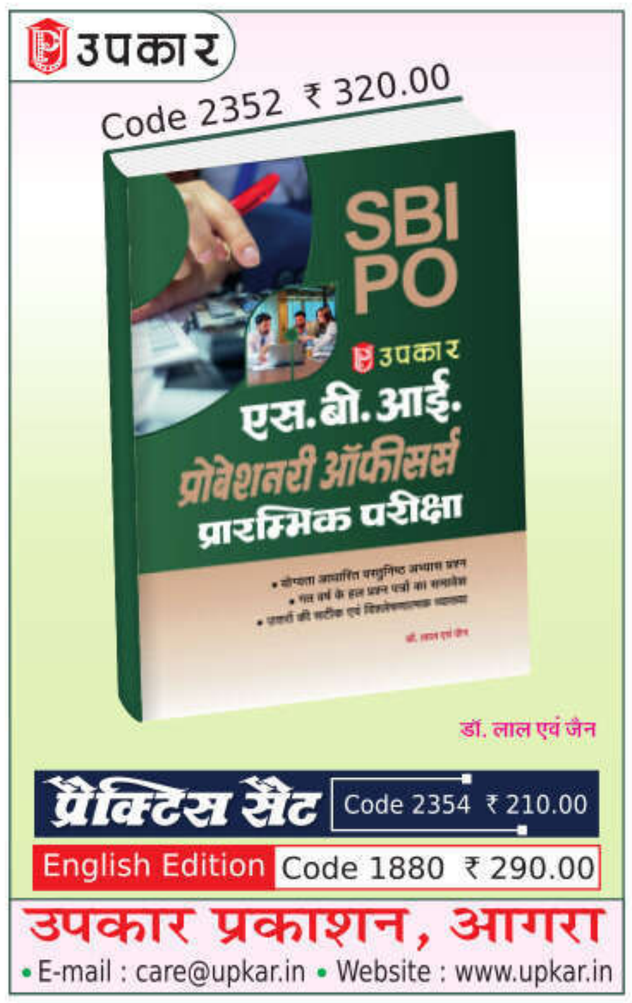
93. (A) 94. (D)
95. (E) O से छोटा अर्थात् P (जन्म का वर्ष 2017)

प्रश्न 96 से 100 तक के लिए–



96. (C) 97. (E) 98. (C) 99. (D)
100. (A)

●●●



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

सामान्य अध्ययन-I

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
   I. आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती हैं.
   II. विगत दो आम चुनाव से लोक सभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त है.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/कौनसे सही है/हैं ?
   (A) कथन I
   (B) कथन II
   (C) I और II दोनों
   (D) न तो I और न ही II

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
   I. पंचायती राज स्थानीय स्तर पर, एक प्रकार से त्रिस्तरीय जैविक सम्बन्धों की अभिशासन संरचना है.
   II. स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंततः खेल खत्म हो गया है.
   III. 'तृणमूल लोकतंत्र' का सम्बन्ध लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण से हैं.

   उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित में से कौनसा एक सही है ?
   (A) कथन II और कथन III दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं
   (B) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, तथा उसमें से केवल एक, कथन I की व्याख्या करता है
   (C) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है, तथा वह कथन I की व्याख्या करता है
   (D) न तो कथन II और न ही कथन III सही है

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
   I. राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता सर्वप्रथम 1993 में मिली.
   II. संसदीय प्रक्रिया में 'शून्यकाल' को केवल औपचारिक मान्यता प्राप्त है.
   III. मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/कौनसे सही है/हैं ?
   (A) I और II
   (B) केवल III
   (C) I और III
   (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

4. भारतीय संविधान के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
   I. राज्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों के लिए विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है.
   II. प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है.
   III. एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है.

   उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भों में कौनसा एक सही है ?
   (A) केवल I (B) I और III
   (C) केवल III (D) I, II और III

5. 'झण्डा समिति' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
   I. तदर्थ झण्डा समिति में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 7 थी.
   II. कराची अधिवेशन में गठित झण्डा समिति (1931) एवं तदर्थ झण्डा समिति (1947) दोनों ही समितियों में के.एम. मुंशी इसके सदस्य रहे हैं.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/कौनसे सही है/हैं ?
   (A) कथन I
   (B) कथन II
   (C) I और II दोनों
   (D) न तो I और न ही II

6. 'लोकपाल' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
   I. संसद में पहला लोकपाल विधेयक पाँचवीं लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था.
   II. केन्द्रीय सर्तकता आयोग (CVC) को लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों, पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट लोकपाल को देनी होगी.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/कौनसे सही है/हैं ?
   (A) कथन I
   (B) कथन II
   (C) I और II दोनों
   (D) न तो I और न ही II

7. भारतीय संविधान संशोधन एवं उनके प्रावधानों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

संविधान संशोधन		प्रमुख प्रावधान
I. 96वाँ संशोधन	:	संविधान की 8वीं अनुसूची में 'उड़िया' के स्थान पर 'ओड़िया' किया गया
II. 87वाँ संशोधन	:	परिसीमन में जन-संख्या का आधार 1991 ई. के स्थान पर 2001 ई. कर दिया गया
III. 88वाँ संशोधन	:	सेवाओं पर कर का प्रावधान
IV. 61वाँ संशोधन	:	मतदान की आयु में परिवर्तन

   उपर्युक्त में कितने युग्म सही हैं ?
   (A) केवल एक (B) केवल दो
   (C) केवल तीन (D) सभी चार

8. 'मौलिक अधिकारों' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
   I. ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तक समावेशी एवं सार्थक पहुँच, जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है.
   II. जया ठाकुर *बनाम* भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद-21 के तहत् मौलिक अधिकार घोषित किया है.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/कौनसे सही है/हैं ?
   (A) कथन I
   (B) कथन II
   (C) I और II दोनों
   (D) न तो I और न ही II

9. संसदीय समितियों के सन्दर्भ में अग्रलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
   (A) संसदीय समितियों की चर्चाएँ 'बन्द दरवाजे' के भीतर होती है और उसके

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

सदस्य अपने दल के सिद्धान्तों से बँधे नहीं होते हैं

(B) स्थायी समितियाँ अनवरत प्रकार की होती है

(C) अस्थायी समितियों का गठन किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है

(D) उपर्युक्त सभी सही हैं

10. 'राष्ट्रीय दल' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

I. चार राज्यों में लोक सभा या विधान-सभा चुनावों में कम-से-कम 6% वैध वोट प्राप्त करना और चार लोक सभा सीटें जीतना.

II. कम-से-कम तीन अलग-अलग राज्यों से लोक सभा की कम-से-कम 2% सीटें जीतना.

III. पाँच या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना.

IV. मान्यता प्रदान करने की समीक्षा लगातार तीन चुनावों के बाद की जाती है.

V. वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 है.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए—

(A) केवल II, III और IV

(B) केवल I और II

(C) केवल III, IV और V

(D) केवल IV और V

11. 'केन्द्रशासित प्रदेश' के सन्दर्भ में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए—

	केन्द्रशासित प्रदेश	राष्ट्रपति के प्रतिनिधि	सम्बन्धित उच्च न्यायालय के अधीन
I.	लक्षद्वीप	उपराज्यपाल	केरल उच्च न्यायालय
II.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	प्रशासक	उड़ीसा उच्च न्यायालय के अधीन
III.	चंडीगढ़	प्रशासक	पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन

उपर्युक्त में से कितनी पंक्तियों में सूचना सही सुमेलित है ?

(A) केवल एक (B) केवल दो

(C) सभी तीन (D) किसी में नहीं

12. 'सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

I. राष्ट्रपति की नजर में एक 'प्रतिष्ठित न्यायविद' सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, किन्तु उच्च न्यायालय में 'प्रतिष्ठित न्यायविद' के न्यायाधीश बनने का कोई प्रावधान नहीं है.

II. एक अतिरिक्त न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उच्च न्यायालय में पद धारण नहीं कर सकता है.

उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में, निम्न-लिखित में कौनसा एक सही है ?

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की व्याख्या करता है

(B) कथन I और कथन II दोनों सही है, किन्तु कथन II, कथन I की व्याख्या नहीं करता है

(C) कथन I सही है, किन्तु कथन II सही नहीं है

(D) कथन I सही नहीं है, किन्तु कथन II सही है

13. संसद में दोहरी सदस्यता के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

I. यदि किसी सदन का कोई मौजूदा सदस्य दूसरे सदन में भी निर्वाचित हो जाता है, तो पहले सदन में उसकी सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी.

II. कोई व्यक्ति दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यदि वह दोनों से निर्वाचित हो जाता है, तो परिणाम घोषित होने के 21 दिनों के भीतर एक सीट से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी पहली चुनावी सीट रिक्त हो जाएगी.

उपर्युक्त कथनों में कौनसा/कौनसे सही है/हैं ?

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I और II दोनों

(D) न तो I और न ही II

14. भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए—

I. संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ—अनुसूची VIII.

II. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना.

III. संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में बढ़ोतरी.

उपर्युक्त में से किसके सम्बन्ध में प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ पारित होना आवश्यक है ?

(A) केवल I और II

(B) केवल II और III

(C) केवल II

(D) सभी तीनों

15. निम्नलिखित में कौनसा एक कथन सही नहीं है ?

(A) अन्तर्राज्यीय परिषद् की प्रथम बैठक तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह की अध्यक्षता में हुई थी

(B) मुख्य चुनाव आयुक्त वी. एस. रमादेवी के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को (9) क की स्थित प्रदान की

(C) 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायती राज्य अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है

(D) राज्य सभा के प्रथम उपसभापति श्री एस.वी. कृष्णामूर्ति राव थे

16. राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय सम्बन्धी पहले अग्रिम अनुमान के सम्बन्ध में विचार कीजिए—

I. स्थिर मूल्यों पर 2025-26 में सकल मूल्य संवर्द्धन में 7·3 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान.

II. 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर ₹ 1,21,968 व प्रचलित मूल्यों पर ₹ 2,19,575 अनुमानित.

दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I और II दोनों

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

17. राज्यों की निर्यात तैयारियों के सम्बन्ध में वर्ष 2024 के निर्यात तैयारी सूचकांक के सन्दर्भ में विचार कीजिए—

I. इसे केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी किया गया है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

II. यह सूचकांक राज्यों को तीन वर्गों अग्रणी, चुनौती देने वाला और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है.
III. बड़े राज्यों में तमिलनाडु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है.
IV. छोटे राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान उत्तराखण्ड का है.

दिए गए उपर्युक्त कथनों में कितने सही नहीं है ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) केवल तीन (D) सभी चार

18. निम्नलिखित सूची-I का सूची-II से सही मिलान कीजिए—

सूची-I
(a) एनआईए के नए महानिदेशक
(b) आईटीबीपी के नए महानिदेशक
(c) बीएसएफ के नए महानिदेशक
(d) भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष

सूची-II
1. नितिन नबीन 2. प्रवीण कुमार
3. शत्रुजीत सिंह 4. राकेश अग्रवाल

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	2	3	4
(B)	4	3	2	1
(C)	3	2	1	4
(D)	4	2	3	1

19. गोल्डन ग्लोब अवॉर्डस 2026 के सम्बन्ध में सही सुमेलित नहीं है ?
(A) सर्वश्रेष्ठ फिल्म (ड्रामा) — हैमनेट
(B) सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (ड्रामा) —वैगनर मौरा
(C) सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (ड्रामा) — जेसी बकली
(D) सर्वश्रेष्ठ गैर-अंग्रेजी फिल्म — सिनर्स

20. गैर-हिन्दी भारतीय भाषाओं के लिए 'सेमोझी इलाकिया विरुधु' नामक साहित्यिक पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा देने की घोषणा की गई है ?
(A) केरल (B) कर्नाटक
(C) तमिलनाडु (D) तेलंगाना

21. पद्म पुरस्कार के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
I. पद्म पुरस्कारों के तहत् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री सम्मिलित है.
II. पद्म पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति इसे एक उपाधि की तरह अपने नाम के साथ लगा सकता है.
III. पद्म पुरस्कार को उल्लंघन की स्थिति में वापस लिया जा सकता है.
IV. पद्म पुरस्कारों के तहत् ₹ 5 लाख की विजेता राशि प्रदान की जाती है.

दिए गए उपर्युक्त कथनों में कितने सही हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) केवल तीन (D) सभी चार

22. 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की थीम रखी गई थी ?
(A) वन्दे मातरम् : राष्ट्र गौरव का शताब्दी समारोह
(B) वन्दे मातरम् के 150 वर्ष
(C) वन्दे मातरम् : राष्ट्र मातरम्
(D) वन्दे मातरम् और गणतंत्र दिवस

23. गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झाँकियों के पुरस्कारों (नागरिक पसन्द) के सम्बन्ध में सही सुमेलन है ?
(A) तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता — भारतीय नौसेना
(B) केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों की सर्वश्रेष्ठ झाँकी — संस्कृति मंत्रालय
(C) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ झाँकी — गुजरात
(D) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की द्वितीय सर्वश्रेष्ठ झाँकी — जम्मू और कश्मीर

24. 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना' किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है ?
(A) उत्तर प्रदेश (B) राजस्थान
(C) गुजरात (D) बिहार

25. जर्मनी के चांसलर फ्रेड्रिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान किन प्रमुख समझौता/ समझौते ज्ञापनों पर सहमति बनी ?
I. भारत में जर्मन विश्वविद्यालयों के परिसर खोलने की अनुमति.
II. भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए जर्मनी से होकर वीजा मुफ्त पारगमन.
III. सेमीकंडक्टर्स व दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति.

कूट :
(A) केवल I
(B) केवल II और III
(C) केवल III
(D) I, II और III

26. जनवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष 5 पासपोर्टधारक देशों में जापान और द. कोरिया को संयुक्त रूप से कौनसी रैंक प्रदान की गई है ?
(A) प्रथम (B) द्वितीय
(C) तृतीय (D) चतुर्थ

27. प्रमुख पुस्तक और लेखकों के सम्बन्ध में सही सुमेलित नहीं है ?
(A) घोस्ट आई—अमिताव घोष
(B) मिडनाइट ट्रेन—मैट हेग
(C) द हॉर्ट ऑफ इंडिया—मार्क टुली
(D) बिमाँड पर्दा—सलमान रुश्दी

28. 1 जनवरी, 2026 से कौनसा देश यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप मे अपनाने वाला 21वाँ राष्ट्र है ?
(A) ऑस्ट्रिया (B) बुल्गारिया
(C) स्पेन (D) माल्टा

29. 3-5 फरवरी, 2026 के बीच आयोजित 'विश्व सरकार शिखर सम्मेलन' का विषय रखा गया था ?
(A) भविष्य की सरकारों से सहयोग
(B) भविष्य की सरकारों को आकार देना
(C) सरकारों के बीच सहयोग
(D) भविष्य की रणनीति और मंथन

30. 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सही नहीं है—
(A) आयोग ने अपनी सिफारिशों में ऊर्ध्वाधर हस्तान्तरण को बरकरार रखा है
(B) विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत रखा है
(C) क्षैतिज हस्तान्तरण के तहत् सर्वाधिक हिस्सा जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को दिया गया है
(D) जनसंख्या (आधार 2011 जन-गणना) के आधार पर 17·50 प्रतिशत क्षैतिज हस्तान्तरण राज्यों के लिए निर्धारित है

31. यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय काहिरा (मिस्र) में है. इसमें मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की सभी अरब सरकारें शामिल हैं. इसकी स्थापना 22 मार्च, 1945 को हुई थी. यह कथन किस संगठन के सम्बन्ध में सही है ?
(A) विश्व बैंक (B) डब्ल्यूएचओ
(C) अरब लीग (D) ब्रिक्स

32. आर्थिक समीक्षा 2025-26 के सन्दर्भ में कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
I. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7·4% रहने की सम्भावना है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

II. वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6·8 से 7·2% रहने का अनुमान है.
III. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को 135·4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रवासी धनराशि प्राप्त हुई, जो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है.

कूट :
(A) केवल I
(B) केवल II और III
(C) केवल I ओर III
(D) I, II और III

33. विकसित भारत–जी राम जी अधि-नियम, 2025 के सन्दर्भ में सही है–
I. इसका पूरा नाम विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटी अधिनियम है.
II. यह ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने का प्रावधान करता हैं.

कूट :
(A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II (D) न तो I, न ही II

34. अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक कमजोर लोगों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा तथा कृषि आधारित आजीविका को बहाल करने के लिए 100 मिलियन डॉलर की सहायता पहल को लागू किया है/हैं ?
I. न्यू डेवलपमेंट बैंक
II. विश्व बैंक
III. खाद्य एवं कृषि संगठन
IV. एशियाई विकास बैंक

कूट :
(A) केवल I और III
(B) केवल II और IV
(C) केवल III और IV
(D) I, II, III और IV

35. हाल ही में समाचार की सुर्खियों में रहा 'स्कारबोरो शोल क्षेत्र' किन 2 देशों के बीच एक विवादित क्षेत्र रहा है ?
(A) चीन और जापान
(B) चीन और रूस
(C) चीन और फिलिपींस
(D) चीन और वियतनाम

36. भारत के किस पहाड़ी क्षेत्र में रैट होल के माध्यम से कोयला के अवैध खनन के दौरान विस्फोट होने से कम-से-कम 18 लोगों की मृत्यु हो गई है ?
(A) पूर्वी जयंतिया हिल्स
(B) शेवरॉय पहाड़िया
(C) मिशमी पहाड़िया
(D) नल्लामाला पहाड़िया

37. केन्द्रीय बजट 2026-27 में भारत के किन राज्यों में समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है ?
I. ओडिशा II. केरल
III. आन्ध्र प्रदेश IV. तमिलनाडु

कूट :
(A) केवल I और II
(B) केवल III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

38. केन्द्रीय बजट 2026-27 में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का प्रस्ताव किया गया है ?
(A) राष्ट्रीय साइबर योजना
(B) वस्तु विस्तार एवं रोजगार योजना
(C) महात्मा गाँधी ग्राम स्वराज्य योजना
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

39. केन्द्रीय बजट 2026-27 में वीबी–जी राम जी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ?
(A) ₹ 63,500 करोड़
(B) ₹ 95,692 करोड़
(C) ₹ 20,000 करोड़
(D) ₹ 22,000 करोड़

40. विजय हजारे ट्रॉफी (2025-26) का खिताब किसने जीता है ?
(A) विदर्भ (B) सौराष्ट्र
(C) झारखण्ड (D) मुम्बई

41. सेबी के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
I. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) एक गैर-सांविधिक निकाय है.
II. सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है.
III. कमोडिटी एक्सचेंज सेबी के विनियमकारी दायरे में आते हैं.
IV. सेबी के आदेशों के विरुद्ध प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी जा सकती है.

सही कूट है–
(A) केवल I एवं II
(B) केवल II एवं III
(C) केवल I एवं III
(D) केवल II एवं IV

42. 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
I. केन्द्र सरकार के विभाज्यनीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत होगा.
II. क्षैतिजिक वितरण के लिए निर्धारित की गई कसौटियों में सकल घरेलू उत्पाद में राज्य के योगदान को पहली बार शामिल करते हुए 10 प्रतिशत भार दिया गया है.
III. राज्यों के राजस्व घाटे को पाटने के लिए दिए जाने वाले अनुदान की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है.
IV. क्षेत्र-विशिष्ट तथा राज्य विशिष्ट अनुदान की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है.

सही कूट है–
(A) केवल I एवं II
(B) केवल I एवं III
(C) केवल III एवं IV
(D) I, II, III, IV सभी

43. नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इण्डिया इण्डेक्स 2023-24 के सन्दर्भ में सम्पोषणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई पहलों के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–
I. अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली (लक्ष्य 3) : सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण अभियान 2.0.
II. गुणवत्ता युक्त शिक्षा (लक्ष्य 4) : मध्यान भोजन योजना (पीएम पोषण) (PM POSHAN).
III. लैंगिक समानता (लक्ष्य 5) : सुकन्या समृद्धि खाता.
IV. वहन करने योग्य (लक्ष्य 7) : पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) स्वच्छ ऊर्जा.

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) केवल तीन (D) सभी चार

44. विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणाओं के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं है ?
(A) जीवन चक्र परिकल्पना–फ्रैंको मोदगिलियानी
(B) अधिशेष श्रम तथा अधिशेष मूल्य–कार्ल मार्क्स

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

(C) अदृश्य हाथ—एडम स्मिथ
(D) तरलता जाल—मिल्टन फ्रीड मैन

45. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए—
I. नीति आयोग—थिंक टैंक
II. वित्त आयोग—संवैधानिक निकाय
III. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड—विनियामक निकाय
IV. भारतीय रिजर्व बैंक—बैंकों का बैंक
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) केवल तीन (D) सभी चार

46. ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation TWIST) के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
I. यह एक अपरम्परागत मौद्रिक नीति उपकरण है.
II. इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दीर्घकालीन ब्याज दरों में कमी लाकर दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2019 में प्रयुक्त किया गया था.
III. इसके अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करके उतने ही मूल्य की प्रतिभूतियों की बिक्री करता है.
IV. ऑपरेशन ट्विस्ट का प्रयोग सर्वप्रथम बैंक ऑफ इंग्लैण्ड द्वारा 2022 में किया.
सही कूट है—
(A) केवल II
(B) केवल I एवं III
(C) केवल I, II, III
(D) केवल IV

47. निम्नलिखित में से कौनसे कोष/निधि का उल्लेख भारतीय संविधान में है ?
I. कंसोलिडेटेड सिंकिंग फण्ड
II. भारत की संचित निधि
III. गारन्टी रीडेम्पशन निधि
IV. भारत की आकस्मिकता निधि
सही कूट है—
(A) केवल I एवं II
(B) केवल II एवं III
(C) केवल II एवं IV
(D) केवल I एवं IV

48. बैंकिंग सुधारों से सम्बन्धित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए—
I. बिमल जालान समिति
II. नचिकेत मोर समिति
III. नरसिंहम समिति
IV. पी.जे. नायक समिति
गठन किए जाने के बढ़ते क्रम में उपर्युक्त समितियों का सही क्रम कौनसा है ?
(A) I, II, III, IV
(B) II, III, IV, I
(C) III, II, IV, I
(D) IV, III, II, I

49. निम्नलिखित में से कौनसा मुद्रा बाजार (Money Market) का उपकरण नहीं है ?
I. कोषागार हुण्डी
II. डिबेन्चर
III. कॉमर्शियल पेपर
IV. सर्टीफिकेट ऑफ डिपोजिट
सही कूट है—
(A) केवल II
(B) केवल II एवं III
(C) केवल II एवं IV
(D) केवल I, II, III

50. विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर समझौता के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है ?
(A) अम्बर बॉक्स (B) श्वेत बॉक्स
(C) ग्रीन बॉक्स (D) ब्लू बॉक्स

51. निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित है ?
I. नक्शा (NAKSHA) — शहरी भू-अभिलेख
II. उलपिन (ULPIN) — भू-आधार
III. एनजीडीआरएस (NGDRS) — एक राष्ट्र एक पंजीयन
सही कूट है—
(A) केवल I
(B) केवल II एवं III
(C) I, II, III सभी
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

52. राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (एन.एम.एम.) के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?
I. इसे वर्ष 2026-27 के केन्द्रीय बजट में घोषित किया गया.
II. इस मिशन का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 2023 में 12·9% से बढ़ाकर 2035 तक 25% करना है.
III. इस मिशन का लक्ष्य सकल मूल्य वर्धन में एकीकरण को गहरा करके व्यापारिक निर्यात को बढ़ाकर 2035 तक 1·2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करना है.
सही कूट है—
(A) केवल I एवं II
(B) केवल II एवं III
(C) केवल I एवं III
(D) I, II, III सभी

53. निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए—
I. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना (सुमन)
II. समग्र शिक्षा अभियान
III. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
IV. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
प्रारम्भ किए जाने/मंजूरी प्रदान किए जाने की तिथि के बढ़ते क्रम में उपर्युक्त योजनाओं का सही क्रम कौनसा है ?
(A) I, II, III, IV
(B) IV, III, II, I
(C) III, II, I, IV
(D) II, III, I, IV

54. शहरी चुनौती निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है ?
(A) 2025-26 से 2030-31 के बीच शहरी क्षेत्र में ₹ 4 लाख करोड़ का निवेश
(B) शहरी निकायों की परियोजना लागत का 25% केन्द्रीय सहायता के रूप में, 50% बाजारी ऋणों से तथा शेष निकाय के स्वयं के स्रोतों से या राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त
(C) निजी क्षेत्र की कोई सहभागिता नहीं
(D) शहरी शासन बाजार एवं वित्तीय प्रणाली, परिचालनात्मक दक्षता तथा शहरी नियोजन पर विशेष बल

55. नवीन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?
I. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024-25 कर दिया गया है.
II. व्यय भार परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 से व्युत्पन्न किए गए हैं.
III. नए सूचकांक में वस्तुओं की संख्या 259 से बढ़ाकर 308 तथा सेवाओं की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है.
IV. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण मकान किराए को पहली बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल किया गया है.
सही कूट है—
(A) केवल I, II, III
(B) केवल II, III, IV
(C) केवल I, III, IV
(D) I, II, III, IV सभी

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

56. 'ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक-7' रिपोर्ट के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. यह रिपोर्ट 'ए फ्यूचर वी चूज' शीर्षक के साथ केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-7) के दौरान जारी की गई.
2. रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1990 से उत्सर्जन में वार्षिक 2·5% की वृद्धि दर्ज की गई है.
3. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वर्तमान मार्ग पर चलने से 2030 के दशक तक तापमान में 1·5°C की वृद्धि हो सकती है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

57. 'समुद्री मत्स्यन गणना (MFC) 2025' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. यह समुद्री मत्स्यन गणना का पाँचवाँ संस्करण है, जो पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगा.
2. इस गणना का मुख्य नारा 'स्मार्ट गणना, स्मार्टर मत्स्यन' रखा गया है.
3. इसमें केवल भारत के मुख्य तटीय राज्यों को शामिल किया गया है, जबकि द्वीप समूहों (अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप) को इससे बाहर रखा गया है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

58. 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. इस सर्वेक्षण में 130 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शहरों को वायु गुणवत्ता सुधार प्रयासों के आधार पर रैंकिंग दी गई है.
2. 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है.
3. 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में ओडिशा का 'अंगुल' शहर प्रथम स्थान पर रहा है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

59. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की मार्च 2025 में हुई बैठक और प्रमुख घोषणाओं के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस बोर्ड की यह 7वीं बैठक गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई थी.
2. एशियाई शेर जनसंख्या अनुमान का 16वाँ चक्र वर्ष 2025 में शुरू किया गया है, जिसके अनुसार शेरों की आबादी बढ़कर 891 हो गई है.
3. भारत में 'चीता पुनः प्रस्तुति कार्यक्रम' के विस्तार के लिए मध्य प्रदेश के गाँधीसागर अभयारण्य और गुजरात के बन्नी घास के मैदानों को नए स्थलों के रूप में घोषित किया गया है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

60. 'नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट-2025' के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन की अनुमान रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कुल 6,327 डॉल्फिन होने का अनुमान है.
2. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल गंगा डॉल्फिन ही पाई जाती हैं, सिंधु डॉल्फिन की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है.
3. गंगा डॉल्फिन की सर्वाधिक आबादी बिहार राज्य में पाई गई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?

(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

61. 'वैश्विक वन संसाधन आकलन (GFRA) 2025' रिपोर्ट के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा जारी की गई है.
2. रिपोर्ट के अनुसार, विश्व का कुल वन क्षेत्र वैश्विक भूमि का लगभग 32% है, जिसमें से अधिकांश वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं.
3. रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया के आधे से अधिक वनों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

62. 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023' के मुख्य निष्कर्षों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25·17% है.
2. वर्ष 2021 की तुलना में कुल वन आवरण में होने वाली वृद्धि, वृक्ष आवरण में हुई वृद्धि से अधिक है.
3. भारत के 8 राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों में उनका वन आवरण 75% से अधिक है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

63. 'प्राइमेट्स इन पेरिल : द वर्ल्ड्स 25 मोस्ट एंडेंजर्ड प्राइमेट्स 2023-2025' रिपोर्ट के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. यह रिपोर्ट द्विवार्षिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के प्राइमेट विशेषज्ञ समूह और इंटरनेशनल प्राइमेटोलॉजिकल सोसाइटी के संयुक्त प्रयासों से जारी की जाती है.
2. रिपोर्ट के अनुसार, तपानुली ओरंगुटान मुख्य रूप से अफ्रीकी महाद्वीप के कैमरून और नाइजीरिया क्षेत्र में पाया जाता है.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

3. यह रिपोर्ट दुनिया के चार प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे लुप्तप्रायः प्राइमेट्स की पहचान करती है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

64. ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी रसायनों के सन्दर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए–

1. मिथाइल क्लोरोफॉर्म
2. हैलोन
3. मिथाइल ब्रोमाइड
4. कार्बन टेट्राक्लोराइड
5. हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन

उपर्युक्त में से कौनसे तत्व ओजोन को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों की श्रेणी में आते हैं ?

(A) केवल 1, 2, 4 और 5
(B) केवल 1, 2, 3 और 5
(C) केवल 2, 3, 4 और 5
(D) उपर्युक्त सभी

65. केल्प वनों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए–

1. ये जलमग्न पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो समुद्री स्तनधारियों, मछलियों और अकशेरुकी जीवों के लिए निवास स्थान और पोषण के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं.
2. ये वन कार्बन सोखने और तटीय अपरदन को रोकने जैसी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवाएँ प्रदान करते हैं.
3. ब्रायोजोआ की उपस्थिति इन वनों की वृद्धि और उत्पादकता के लिए अत्यधिक सहायक मानी जाती है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सत्य हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

66. महासागरों में ऑक्सीजन की कमी के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. मानवजनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के परिणामस्वरूप विश्व के महासागरों में ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्रों में होने वाली अधिकतम कमी को 'महासागरीय ऑक्सीजनहीनता' कहा जाता है.
2. गर्म पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होती है.
3. समुद्र के जिन क्षेत्रों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उन्हें ऑक्सीजन रहित जल कहा जाता है.

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं ?

(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीनों
(D) कोई नहीं

67. प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर, निम्नलिखित में से कौनसा पारिस्थितिकी तंत्र कार्बन के अवशोषण और भण्डारण में सर्वाधिक सक्षम है ?

(A) घास के मैदान
(B) वनस्पति रहित मृदा
(C) परिपक्व उष्णकटिबंधीय वन
(D) खारे पानी का दलदल

68. 'ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2024-25' के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. इन नियमों को केन्द्र सरकार द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), 2023 के ढाँचे के भीतर भारत के घरेलू कार्बन बाजार को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है.
2. इन नियमों का मुख्य लक्ष्य उत्सर्जन के पूर्ण परिमाण के बजाय, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन तीव्रता के सम्बन्ध में अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित करना है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

69. एक 'आयु-लिंग पिरामिड' का विश्लेषण करके इनमें से किन सांख्यिकीय संकेतकों का पता लगाया जा सकता है ?

1. आबादी के भीतर अलग-अलग आयु वर्गों का विस्तृत बँटवारा.
2. विशिष्ट आयु श्रेणियों के आधार पर स्त्री-पुरुष अनुपात.
3. प्रति वर्ग किमी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की सघनता.
4. किसी विशिष्ट प्रजाति की प्रजनन दर और भविष्य में उनके अस्तित्व की निरन्तरता का पूर्वानुमान.

सही विकल्प का चयन कीजिए–

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) उपर्युक्त सभी

70. महासागरीय धाराओं के उद्भव और व्यवहार के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए–

1. सागर की ऊपरी सतह की धाराएँ मुख्य रूप से प्रचलित पवनों द्वारा संचालित होती हैं और उनकी दिशा काफी हद तक वायु प्रवाह के अनुरूप होती है.
2. जल के घनत्व में अन्तर, जोकि तापमान और लवणता के उतार-चढ़ाव से पैदा होता है, गहरे समुद्र की धाराओं को गति देने वाला एक प्रमुख कारक है.
3. चक्रवात और तीव्र तूफानों जैसी अल्पकालिक वायुमण्डलीय घटनाएँ भी अस्थायी लेकिन शक्तिशाली समुद्री धाराओं को उत्पन्न करने में सक्षम हैं.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सत्य है/हैं ?

(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

71. सिंधु नदी तंत्र की विशेषताओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है ?

(A) सतलुज नदी का स्रोत मानसरोवर के निकट राक्षस ताल झील है और यह शिपकी ला दर्रे के माध्यम से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है

(B) झेलम नदी कश्मीर घाटी में स्थित वुलर झील से प्रवाहित होते हुए आगे चलकर पाकिस्तान की ओर निकल जाती है

(C) यदि जल प्रवाह की मात्रा को आधार माना जाए, तो चिनाब सिंधु की सबसे विशाल सहायक नदी है

(D) ब्यास नदी का सम्पूर्ण प्रवाह क्षेत्र केवल पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर स्थित है, जहाँ यह चिनाब में विलीन हो जाती है

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

72. विषुवतीय वर्षावन बायोम की जलवायु सम्बन्धी विशेषताओं के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. इस क्षेत्र में वार्षिक तापांतर अत्यन्त न्यून होता है, अर्थात् पूरे वर्ष तापमान लगभग एकसमान बना रहता है.
2. यहाँ दैनिक तापान्तर, वार्षिक तापान्तर की तुलना में अधिक स्पष्ट और प्रभावी होता है.
3. यहाँ होने वाली वर्षा मुख्य रूप से संवहनीय प्रकृति की होती है, जो प्रायः प्रतिदिन दोपहर के बाद गरज के साथ होती है.

उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं ?

(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) सभी तीनों (D) कोई भी नहीं

73. 'ग्रेट ग्रीन वॉल' पहल के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. यह पहल मूल रूप से 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा शुरू की गई थी.
2. इसका प्राथमिक लक्ष्य अफ्रीका के साहेल और सहारा क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना है.
3. इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 250 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को बहाल करना है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

74. बित्रा द्वीप के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. यह लक्षद्वीप द्वीपसमूह का सबसे छोटा और सबसे कम आबादी वाला बसा हुआ द्वीप है.
2. भौगोलिक रूप से, यह एक 'एटोल' का उदाहरण है, जो मूंगा चट्टानों से निर्मित है.
3. यह अरब सागर में स्थित है और प्रशासनिक रूप से कवरत्ती के साथ निकटता साझा करता है.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2 और 3

75. माउंट कंचनजंगा (खांगचेंदजंगा) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है, जो पूर्वी हिमालय में भारत (सिक्किम) और नेपाल की सीमा पर स्थित है.
2. जेमू ग्लेशियर, जो एशिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है, इसी पर्वत क्षेत्र में स्थित है.
3. यह पर्वत शृंखला तीस्ता और तमूर जैसी प्रमुख नदियों के उद्गम स्रोत के रूप में कार्य करती है.
4. सांस्कृतिक रूप से, इसे स्वदेशी लेपचा और बौद्ध समुदायों द्वारा एक पवित्र पर्वत और संरक्षक देवताओं का निवास माना जाता है.

उपर्युक्त में से कौनसे कथन सही हैं ?

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4

76. **अभिकथन (A) :** मोल्टबुक जैसे प्लेटफॉर्म 'एजेंटिक एआई' के स्वायत्त व्यवहार और उनके बीच होने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रयोग के रूप में उभरे हैं.

कारण (R) : इन प्लेटफॉर्म्स पर मानव भागीदारी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जिससे एआई एजेंट बिना किसी मानवीय निर्देश या प्रॉम्प्ट के पूरी तरह स्वतंत्र होकर नई विचारधाराएँ और विश्वास प्रणालियाँ विकसित कर रहे हैं.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए—

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है
(D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है

77. सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. यह दवा का वह हिस्सा है, जो इच्छित चिकित्सीय प्रभाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है.
2. किण्वन-आधारित एपीआई का उत्पादन सूक्ष्मजीवों की खेती के माध्यम से किया जाता है और ये आमतौर पर रासायनिक-संश्लेषण एपीआई की तुलना में अधिक जटिल होते हैं.
3. भारत वर्तमान में अपनी कुल एपीआई आवश्यकताओं का लगभग 70% चीन से आयात करता है.
4. पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन प्राकृतिक/निकासी आधारित एपीआई के उदाहरण हैं.

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) केवल तीन (D) सभी चार

78. हाल ही में चर्चा में रहे 'कौशल रथ' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. यह 'युवा एआई फॉर ऑल' कार्यक्रम के तहत् एक मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जागरूकता इकाई है.
2. इसका प्राथमिक उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञों को उन्नत क्वांटम कम्प्यूटिंग में प्रशिक्षित करना है.
3. इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आइसेक्ट के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है.
4. यह इकाई इंटरनेट सक्षम सिस्टम और ऑडियो-विजुअल टूल से युक्त एक चलते-फिरते कम्प्यूटर लैब के रूप में कार्य करती है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

79. बहु-दवा प्रतिरोधी क्षय रोग (एमडी-आर/आरआर-टीबी) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. एमडीआर-टीबी मुख्य रूप से आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन दवाओं के प्रति प्रतिरोध के कारण होता है.
2. आमतौर पर 6 महीने के उपचार पुराने उपचारों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी हैं.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

3. प्रतिरोधी क्षय रोग का अर्थ मुख्यतः रिफैम्पिसिन के प्रति प्रतिरोध है और इसे कभी भी एमडीआर-टीबी की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

80. नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप (एनएलएसटी) के सन्दर्भ में निम्न-लिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. यह 2-मीटर व्यास वाली एक सौर वेधशाला है, जिसे लद्दाख के पेंगोंग त्सो के पास मेराक में स्थापित किया जाएगा.
2. यह टेलीस्कोप मुख्य रूप से एक्स-रे और पराबैंगनी तरंगदैर्ध्य में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है.
3. इसका मुख्य उद्देश्य सौर गतिशीलता और अंतरिक्ष-मौसम प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

81. रजोनिवृत्ति और महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. रजोनिवृत्ति के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में गिरावट के कारण ऑस्टियोपोरोसिस (अस्थि-सुषिरता) और हृदय रोगों का जोखिम बढ़ जाता है.
2. रजोनिवृत्ति के लक्षणों में केवल शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं; मानसिक स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रत्यक्ष जैविक प्रभाव नहीं पड़ता है.
3. 'पेरिमेनोपॉज' वह संक्रमण काल है, जो रजोनिवृत्ति से पहले होता है और इसमें मासिक धर्म चक्र अनियमित हो सकता है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

82. 'टेरावेव' संचार नेटवर्क के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. यह ब्लू ओरिजिन द्वारा घोषित एक 'मल्टी-ऑर्बिट' उपग्रह समूह है, जिसमें निम्न पृथ्वी कक्षा और मध्यम पृथ्वी कक्षा दोनों के उपग्रह शामिल होंगे.
2. टेरावेव का प्राथमिक लक्ष्य सामान्य उपभोक्ताओं को कम लागत वाला ब्रॉड बैण्ड उपलब्ध कराना है, जो इसे सीधे स्टारलिंक का प्रतिस्पर्धी बनाता है.
3. यह नेटवर्क उपग्रहों के बीच डेटा स्थानान्तरित करने के लिए 'ऑप्टिकल लेजर लिंक' का उपयोग करता है, जिससे 6 टेराबिट प्रति सेकण्ड तक की गति सम्भव है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

83. 'उन्नत रसायन विज्ञान सेल' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. यह ऐसी नई पीढ़ी की भण्डारण प्रौद्योगिकियाँ हैं, जो विद्युत् ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं.
2. सभी लिथियम-आयन बैटरी को उनकी निर्माण प्रक्रिया के कारण अनिवार्य रूप से 'एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
3. भारत सरकार की 'उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन' योजना के तहत् केवल उन्हीं निर्माता इकाइयों को प्रोत्साहन मिलता है, जो एक निश्चित सीमा से अधिक 'ऊर्जा घनत्व' और 'चक्रीय काल' प्राप्त करते हैं.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

84. 'जैव-सुरक्षा स्तर-4' (बीएसएल-4) प्रयोगशालाओं और गाँधीनगर (गुजरात) में हाल ही में स्थापित सुविधा के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. बीएसएल-4 प्रयोगशालाएँ उन घातक और विदेशी एजेंटों के लिए डिजाइन की गई हैं, जिनसे प्रयोगशाला संक्रमण का उच्च जोखिम होता है और जिनके लिए कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं हो सकता है.
2. गाँधीनगर में स्थित नई बीएसएल-4 सुविधा भारत की पहली ऐसी प्रयोगशाला है, जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और नियंत्रित है.
3. इन प्रयोगशालाओं में 'पॉजिटिव प्रेशर सूट' और एयरलॉक सिस्टम का उपयोग अनिवार्य है, ताकि शोधकर्ताओं और बाहरी वातावरण के बीच पूर्ण अलगाव सुनिश्चित किया जा सके.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

85. चुनावों में उपयोग की जाने वाली 'अमिट स्याही' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. भारत में इस स्याही का निर्माण विशेष रूप से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की एक प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है.
2. इस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो त्वचा के सम्पर्क में आने पर सिल्वर क्लोराइड में परिवर्तित होकर एक स्थायी गहरा निशान बनाता है.
3. भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1951-52 के पहले आम चुनावों में किया गया था ताकि दोहरा मतदान रोका जा सके.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

86. अलबरूनी की किताब-उल-हिन्द के सन्दर्भ में, अग्रलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

1. अलबरूनी की पुस्तक, किताब-उल-हिन्द, फारसी में लिखी गई है.
2. यह पुस्तक 80 अध्यायों में बटी हुई है.
3. आमतौर पर (हालाँकि, हमेशा नहीं), अलबरूनी ने हर अध्याय में एक खास ढाँचा अपनाया है, जिसकी शुरुआत एक प्रश्न से होती थी, उसके बाद संस्कृति, परम्पराओं पर आधारित वर्णन होता था और आखिर में दूसरी संस्कृतियों के साथ तुलना की जाती है.

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

87. हम्पी के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. हम्पी के खण्डहरों को सन् 1800 ई.में कर्नल कॉलिन मैकेंजी नाम का एक इंजीनियर और पुरातत्ववेत्ता दुनिया के सामने लाया था.
2. सन् 1856 से, फोटोग्राफरों ने स्मारकों को रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिससे विद्वानों को उनका अध्ययन करने में मदद मिली.
3. 1836 ई. की शुरुआत में ही, शिलालेख विशेषज्ञों ने हम्पी के मन्दिरों में पाए गए कई दर्जन शिलालेखों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था.

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) 1, 2 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 1 और 3

88. अबुल फजल की 'आईन-ए-अकबरी' के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. यह 1588 ई. में, सम्राट के शासनकाल के 42वें वर्ष में, 5 बार संशोधन के बाद पूरी हुई थी.
2. आईन-ए-अकबरी को शाही नियमों के संग्रह और मुगल साम्राज्य के गजेटियर के रूप में जाना जाता है.
3. 'आईन-ए-अकबरी' 5 किताबों (दफ्तरों) से मिलकर बनी है.

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

89. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए—

राजवंश	राजधानी
1. कुतुबशाही	— गोलकुंडा
2. निजामशाही	— अहमदनगर
3. आदिलशाही	— बीदर

उपर्युक्त दिए गए युग्मों में से कौनसे सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

90. मुगल दरबार में जेसुइट मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. पहला जेसुइट मिशन 1580 ई. में फतेहपुर सीकरी में मुगल दरबार में पहुँचा और लगभग 2 वर्ष मुगल दरबार में रहा.
2. 1591 ई. और 1595 ई. में लाहौर में मुगल दरबार में दो और जेसुइट मिशन आए.
3. सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट्स मिशन के सदस्यों को अकबर के सिंहासन के बहुत नजदीक स्थान दिया जाता था.

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 1, 2 और 3

91. अमर-नायक प्रणाली के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. अमर-नायक प्रणाली चोल साम्राज्य की एक प्रमुख सैन्य-प्रशासनिक व्यवस्था थी.
2. अमर-नायक सैन्य कमांडर थे, जिन्हें राजा द्वारा राजस्व संग्रह और शासन के लिए क्षेत्र ('अमरम') दिए जाते थे.
3. वे उस क्षेत्र के किसानों, कारीगरों और व्यापारियों से राज्य के लिए कर एकत्र करते थे. इसके एवज में राज्य द्वारा उन्हें राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होता था.

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

92. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए—

सूची-I (संस्था)
(a) इंडियन एसोसिएशन
(b) मद्रास महाजन सभा
(c) बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन
(d) पूना सार्वजनिक सभा

सूची-II (स्थापना वर्ष)
1. 1884 2. 1885
3. 1867 4. 1876

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	1	2	3
(B)	1	4	3	2
(C)	4	2	1	3
(D)	1	3	4	2

93. भारत के मुख्य पेंटिंग स्कूलों के बारे में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए—

सूची-I (पुस्तक)
(a) माध्यमिक सूत्र
(b) महाविभाषा-I
(c) देवी चंद्रगुप्तम-I
(d) शिशुपाल वध

सूची-II (लेखक)
1. विशाखदत्त
2. नागार्जुन
3. वसुमित्र
4. माघ

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	3	1	4
(B)	1	2	3	4
(C)	3	1	4	2
(D)	2	1	4	3

94. निम्नलिखित में से कौनसा प्राचीन हड़प्पाकालीन नगर अपनी उन्नत जल-प्रबंधन एवं जल-संचयन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ वर्षाजल के संचयन और नियमन हेतु परस्पर जुड़े जलाशयों, नालों तथा संरचनाओं का सुव्यवस्थित निर्माण किया गया था ?
(A) धोलावीरा
(B) मोहनजोदड़ो

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

(C) रंगपुर
(D) लोथल

95. 1937 के प्रान्तीय चुनावों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. वर्ष 1937 में प्रान्तीय विधान सभाओं के लिए पहली बार चुनाव आयोजित किए गए थे और केवल लगभग 20-22 प्रतिशत जनसंख्या को ही मताधिकार प्राप्त था.
2. कांग्रेस ने इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 11 में से 5 प्रान्तों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया तथा 7 प्रान्तों में अपनी सरकारें बनाईं.
3. मुस्लिम लीग उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रान्त (NWFP) में एक भी सीट जीतने में असफल रही तथा पंजाब में आरक्षित 84 सीटों में से केवल 2 और सिंध में 33 में से केवल 3 सीटें ही प्राप्त कर सकी.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 2
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

96. 'पाकिस्तान प्रस्ताव' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. 23 अप्रैल, 1942 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की माँग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया.
2. इस अस्पष्ट प्रस्ताव में विभाजन या 'पाकिस्तान' शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था.
3. पंजाब के प्रीमियर एवं यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकन्दर हयात खान, जिन्होंने इस प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था, ने 1 मार्च, 1941 को पंजाब विधान सभा में अपने भाषण में पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 2 और 3
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

97. ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक काल में 'होम चार्जेस (Home Charges)' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. भारत से सम्बन्धित प्रशासनिक व्ययों के लिए इंग्लैण्ड में भुगतान किया जाता था.
2. भारत के सार्वजनिक ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज इन व्ययों का हिस्सा था.
3. रेल और सिंचाई परियोजनाओं में निवेशित पूँजी पर सुनिश्चित लाभांश भी इसमें सम्मिलित था.
4. ईस्ट इंडिया कम्पनी के शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभांश 'होम चार्जेस' का हिस्सा नहीं थे.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4

98. नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए—

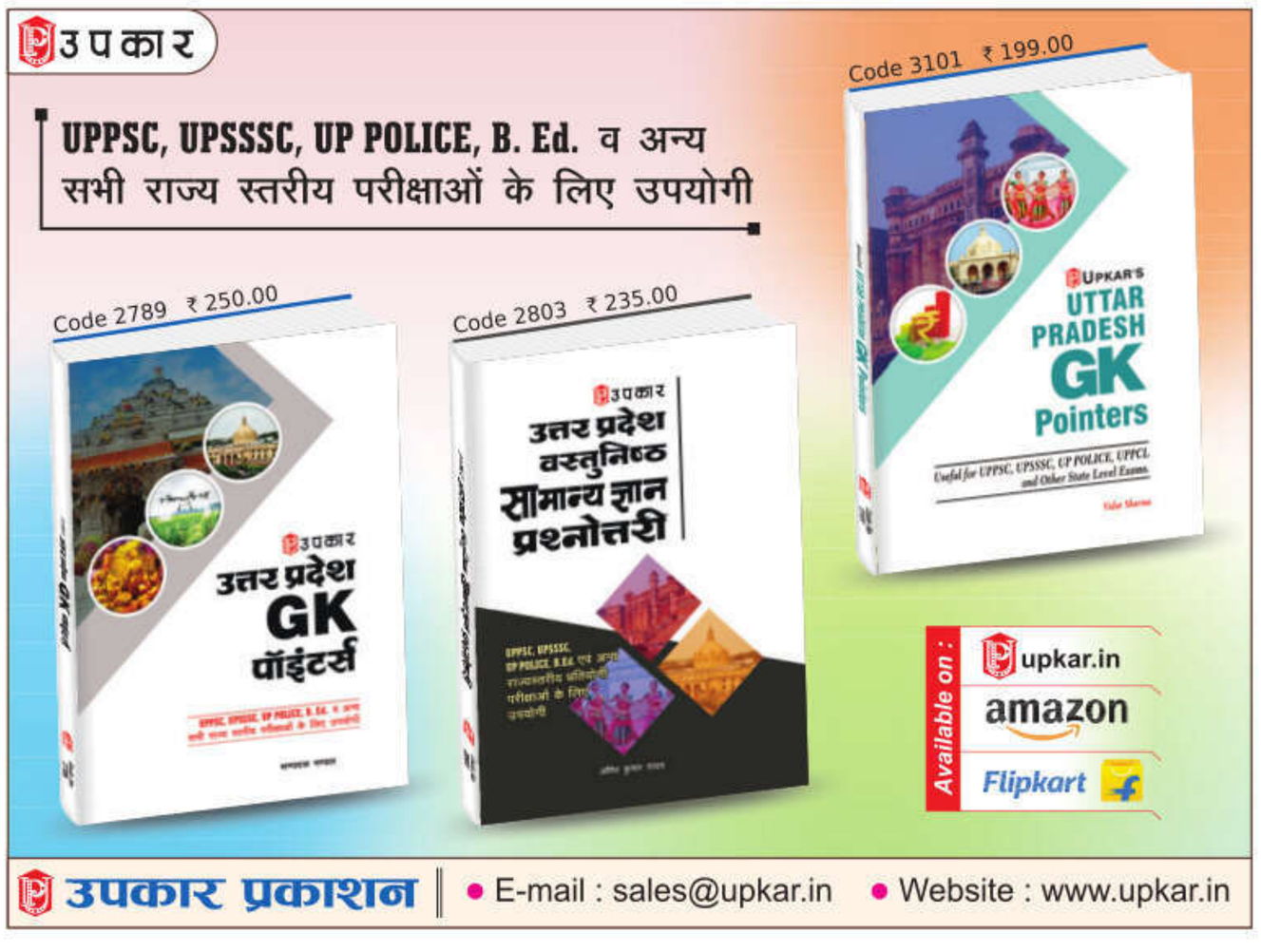
समाचार-पत्र / पत्रिका	संस्थापक / सम्पादक
1. सरस्वती	गणेश शंकर विद्यार्थी
2. हंस	मुंशी प्रेमचन्द
3. द मदरलैण्ड	मजहर-उल-हक

उपर्युक्त दिए गए युग्मों में से कौनसे सुमेलित हैं ?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4

99. निम्नलिखित में से कौनसा बंगाल में लागू स्थायी बन्दोबस्त का सकारात्मक परिणाम नहीं माना जा सकता ?
(A) इसने औपनिवेशिक सरकार को भूमि-राजस्व का स्थिर और पूर्वानुमेय स्रोत प्रदान किया
(B) प्रशासन के लिए बार-बार राजस्व पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता समाप्त हो गई
(C) इसने ऐसे जमींदार वर्ग का निर्माण किया जो राजनीतिक रूप से ब्रिटिश शासन का समर्थक था
(D) इसने कृषकों को मध्यस्थों के शोषण से सुरक्षा प्रदान की

100. औपनिवेशिक भारत में निम्नलिखित वित्तीय घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए—
1. इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना
2. भारतीय मुद्रा पर फाउलर समिति की नियुक्ति
3. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
4. भारतीय वित्त एवं मुद्रा पर रॉयल आयोग (चेम्बरलेन आयोग) का गठन

सही उत्तर का चयन कीजिए—
(A) 2, 4, 1, 3
(B) 4, 2, 1, 3
(C) 2, 4, 3, 1
(D) 4, 1, 2, 3



PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

Centre	Subject	Subject Code	Booklet Series	Roll Number
		⓪ ⓪ ① ① ② ② ③ ③ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑦ ⑦ ⑧ ⑧ ⑨ ⑨	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ① ① ① ① ① ① ① ② ② ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨

DIRECTIONS :

Use Black Ball Point Pen Only

Example

Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

Booklet Series to be coded by Invigilator with Black Ball Point Pen

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

Signature of Invigilator

1 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	26 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	51 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	76 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
2 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	27 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	52 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	77 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
3 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	28 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	53 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	78 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
4 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	29 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	54 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	79 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
5 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	30 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	55 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	80 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
6 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	31 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	56 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	81 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
7 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	32 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	57 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	82 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
8 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	33 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	58 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	83 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
9 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	34 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	59 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	84 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
10 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	35 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	60 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	85 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
11 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	36 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	61 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	86 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
12 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	37 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	62 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	87 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
13 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	38 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	63 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	88 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
14 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	39 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	64 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	89 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
15 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	40 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	65 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	90 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
16 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	41 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	66 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	91 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
17 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	42 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	67 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	92 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
18 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	43 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	68 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	93 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
19 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	44 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	69 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	94 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
20 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	45 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	70 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	95 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
21 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	46 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	71 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	96 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
22 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	47 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	72 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	97 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
23 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	48 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	73 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	98 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
24 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	49 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	74 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	99 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
25 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	50 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	75 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	100 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

उत्तर व्याख्या सहित

1. (A)
- लोक सभा में विपक्ष के नेता से तात्पर्य लोक सभा के उस सदस्य से है, जो उस समय सदन में सरकार के विपक्षी दल का नेता होता है और उसे लोक सभा अध्यक्ष द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त होती है.
- 16वीं एवं 17वीं लोक सभा में नेता विपक्ष का पद खाली था. विपक्षी दल के पास कुल सीटों का कम-से-कम 10% (यानी 543 में 55) होना अनिवार्य है.

2. (B)
3. (B)
- राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार वर्ष 1985 में मिलीं.
- संसदीय प्रक्रिया में 'शून्यकाल शब्द' को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है.
- राज्य सभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व (सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच) तथा लोक सभा में यह पूर्ववत् प्रश्नकाल के बाद (दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक) है.

4. (D)
5. (D)
- तदर्थ झण्डा समिति में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 6 थी.
- कराची अधिवेशन में गठित झण्डा समिति (1931) एवं तदर्थ झण्डा समिति (1947) दोनों ही समितियों में अबुल कलाम आजाद सदस्य रहे हैं.

6. (B)
- संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 (चौथी लोक सभा में प्रस्तुत) किया गया.
- वर्ष 1969 में लोक सभा में पारित हुआ, किन्तु राज्य सभा में लम्बित रहने की स्थिति में, चौथी लोक सभा के विघटित होने के बाद यह विधेयक व्यपगत हो गया.

7. (D)
- संविधान संशोधन, भारतीय संविधान के जीवंत दस्तावेज होने का प्रमाण है.
- भारतीय संविधान के भाग XX के अनुच्छेद-368 में संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रावधान किए गए हैं.

8. (C)
- भारतीय संविधान के भाग III के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित है.
- मौलिक अधिकार, अमेरिकी संविधान के 'Bill of right' से प्रेरित है.

9. (D)

10. (B)
- राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित दल को चार या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए.
- मान्यता प्रदान करने की समीक्षा लगातार दो चुनावों के बाद की जाती है.
- वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 हैं.

11. (A)
- केन्द्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप में कार्यपालिका का प्रमुख (राष्ट्रपति का प्रतिनिधि) प्रशासक होता है तथा यह केन्द्रशासित प्रदेश, केरल उच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्र में है.
- केन्द्रशासित प्रदेश, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में कार्यपालिका का प्रमुख (राष्ट्रपति का प्रतिनिधि) उपराज्यपाल होता है तथा यह केन्द्रशासित प्रदेश, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्र में रखा गया है.

12. (B) 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्रेरणा लेकर, भारतीय संविधान ने तीन स्तरीय ढाँचे के साथ एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है.
- सर्वोच्च न्यायालय
- उच्च न्यायालय
- अधीनस्थ न्यायालय

	निर्णायकों के निर्णय के आधार पर	नागरिकों की पसन्द के आधार पर
तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता	भारतीय नौसेना	असम रेजीमेन्ट
केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सर्वश्रेष्ठ झाँकी	संस्कृति मंत्रालय	स्कूली शिक्षा और संस्कृति विभाग
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सर्वश्रेष्ठ झाँकी	महाराष्ट्र(प्रथम),जम्मू-कश्मीर (द्वितीय), केरल (तृतीय)	गुजरात (प्रथम), उत्तर प्रदेश (द्वितीय), राजस्थान (तृतीय)

13. (A) यदि कोई व्यक्ति दो संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है और वह दोनों से निर्वाचित हो जाता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के 14 दिन के भीतर इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी.

14. (A)

15. (B)
- मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को (9) क की स्थित, प्रदान की.
- 9(क) की स्थित, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा.

16. (C)

17. (B)
- राज्यों की निर्यात तैयारियों के सम्बन्ध में निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है. वर्ष 2024 के लिए जारी यह सूचकांक इसका चौथा संस्करण है. इसका पहला संस्करण 26 अगस्त, 2020 को जारी किया गया था.
- निर्यात तैयारी सूचकांक में 17 बड़े राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम, तमिलनाडु दूसरा व गुजरात ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है.

18. (B) 19. (D) 20. (C)

21. (B) कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं आदि के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 131 पद्म पुरस्कारों [पद्म विभूषण (5), पद्म भूषण (13), पद्म श्री (113)] की 77वें गणतंत्र दिवस पर घोषणा की गई.

22. (B)

23. (C) सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झाँकियों के पुरस्कार-2026

24. (B) राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत् दुग्ध बेचने पर ₹ 5 प्रति लीटर अनुदान सीधे लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में प्रदान किया जाता है.

25. (D) 26. (B) 27. (D) 28. (B)

29. (B) यह सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है.

30. (C) 31. (C) 32. (D) 33. (C)

34. (C)

35. (C) विवादित क्षेत्र 'स्कारबोरो शोल' दक्षिण चीन सागर में अवस्थित है.

36. (A) रैट होल माइनिंग, कोयला को निकालने की एक विधि है. इसमें संकीर्ण

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

क्षैतिज परतों से कोयला निकाला जाता है.

37. (D) 38. (C) 39. (B)

40. (A) 18 जनवरी, 2026 को बेंगलुरु में खेले गए खिताबी मुकाबले में विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर खिताब जीता. विदर्भ ने पहली बार ही इस ट्रॉफी को जीता है.

41. (B) सेबी का गठन भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा 12 अप्रैल, 1988 को एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था. बाद में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 जो 30 जनवरी, 1992 से प्रभावी है के द्वारा सेबी एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है.

42. (D) 43. (D)

44. (D) ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा अपने ब्याज के तरलता पसन्दगी सिद्धान्त की व्याख्या में 'तरलता जाल' की अवधारणा प्रस्तुत की. तरलता जाल उस स्थिति की व्याख्या करता है, जब ब्याज की दर बहुत नीची हो जाने पर लोग नकदी मुद्रा को ब्याज दर पर उठाकर अपने पास रखना अधिक पसन्द करते हैं.

45. (D)

46. (C) ऑपरेशन ट्विस्ट का प्रयोग सर्वप्रथम सं.रा. अमेरिका में वर्ष 1991 में किया गया.

47. (C) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की समेकित/संचित निधि तथा अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख है, जबकि राज्य सरकारों की ओर से कंसोलिडेटेड सिंकिंग फण्ड तथा गारंटी रीडेम्पशन निधि का प्रबन्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है.

48. (C) नरसिंहम समिति (1991 एवं 1998), नचिकेत मोर समिति (2013) पी.जे. नायक समिति (2014), बिमल जालान समिति (2018).

49. (A) इक्विटी शेयर, डिबेन्चर्स, बॉण्डस आदि पूँजी बाजार के उपकरण हैं.

50. (B) कृषि पर समझौते के अन्तर्गत सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र को दी जा रहीं सब्सिडी को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है—

(i) **ग्रीन बॉक्स सब्सिडी :** ऐसी सब्सिडी जो व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती या सीमित मात्रा में डालती हैं.

(ii) **अम्बर बॉक्स सब्सिडी :** ऐसी सब्सिडी जो उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि करने के लिए दी जाती हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है.

(iii) **ब्लू बॉक्स सब्सिडी :** ये अम्बर बॉक्स सब्सिडी का ही एक हल्का स्वरूप है, जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों की तीव्रता को कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है.

51. (C)

52. (B) राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन वर्ष 2025-26 के केन्द्रीय बजट में घोषित किया गया था.

53. (C) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी, 2015 को लॉन्च की गई, समग्र शिक्षा अभियान 24 मई, 2018 को शुरू किया गया, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना (सुमन) 10 अक्टूबर, 2018 को लॉन्च की गई. प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को 16 जुलाई, 2025 को मंजूरी प्रदान की गई.

54. (C) संरचनात्मक जोखिम साझेदारी फ्रेमवर्क तथा सेवाएँ प्रदान करने के मानकों के द्वारा निजी क्षेत्र की सहभागिता.

55. (B) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (समग्र, ग्रामीण एवं शहरी) का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है.

56. (C)

- इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 से उत्सर्जन में वार्षिक वृद्धि 1·5% रही है, न कि 2·5%.

57. (A)

- यह गणना 13 तटीय राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में आयोजित की जा रही है, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप भी शामिल हैं. इसमें लगभग 5,000 गाँवों के 12 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा.

  यह जनगणना मत्स्य पालन विभाग द्वारा वित्त पोषित है. आईसीएआर-सीएमएफआरआई (केन्द्रीय समुद्री मत्स्यन अनुसंधान संस्थान) नोडल एजेंसी है. भारतीय मत्स्यन सर्वेक्षण परिचालन भागीदार है.

58. (A)

- 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में मध्य प्रदेश का देवास पहले स्थान पर रहा. अंगुल (ओडिशा) इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा.

59. (D) 60. (A)

61. (B)

- वैश्विक वन संसाधन आकलन (GFRA) रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी की जाती है, न कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा.

62. (C)

- 2021 से कुल 1,445 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें वृक्ष आवरण (1,289 वर्ग किमी) में वृद्धि, वन आवरण (156 वर्ग किमी) की तुलना में बहुत अधिक है.

63. (C)

- तपानुली ओरंगुटान इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पाया जाता है, जबकि क्रॉस रिवर गोरिल्ला कैमरून और नाइजीरिया में पाया जाता है.

64. (D)

65. (A)

- ब्रायोजोआ वास्तव में केल्प वनों के लिए एक खतरा है. ये छोटे, काई जैसे जीव होते हैं, जो केल्प की पत्तियों पर एक परत की तरह फैल जाते हैं. इससे केल्प भारी हो जाते हैं और समुद्र के तल में डूबकर नष्ट होने लगते हैं.

66. (A)

67. (D)

- खारे पानी के दलदल महत्वपूर्ण तटीय 'ब्लू कार्बन' पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं. ये क्षेत्र अपने बायोमास (जमीन के ऊपर और नीचे) और अपनी गहरी मिट्टी (तलछट) में कार्बन को अत्यधिक उच्च दर पर जमा करने के लिए जाने जाते हैं.

68. (A)

- इन नियमों का प्राथमिक उद्देश्य संस्थाओं को 'उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य' (उत्पादन की प्रति इकाई उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैस की मात्रा) प्रदान करना है, न कि कुल उत्सर्जन पर सीधा प्रतिबन्ध लगाना. जो संस्थाएँ इन निर्धारित लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करेंगी (अर्थात् कम उत्सर्जन करेंगी), उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट (CCC) जारी किए जाएंगे, जिन्हें बाजार में बेचा जा सकेगा.

69. (B)

- जनसंख्या पिरामिड, जिसे 'आयु-लिंग पिरामिड' भी कहा जाता है, एक चित्रात्मक चित्रण है, जो किसी जनसंख्या (आमतौर पर किसी देश या विश्व के क्षेत्र की) में विभिन्न आयु समूहों के वितरण को दर्शाता है.

70. (D)

71. (D)

- ब्यास नदी सिंधु प्रणाली की एकमात्र प्रमुख नदी है, जो अपना पूरा सफर (उद्गम से संगम तक) भारत में ही तय करती है. यह हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलती है और पंजाब के हरिके

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

में सतलुज नदी से मिल जाती है. यह पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती.

72. (C) 73. (A)

74. (D) बित्रा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 0·105 वर्ग किमी है और यहाँ की जनसंख्या भी सबसे कम है. यह एक एटोल (प्रवाल वलय) है, जो मूंगा द्वीपों की एक विशेषता है. यह अरब सागर में लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है और इसकी राजधानी कवरत्ती इससे कुछ दूरी पर स्थित है. बित्रा एक महत्वपूर्ण समुद्री जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जहाँ मूंगा चट्टानें, रंगीन मछलियाँ और समुद्री कछुए पाए जाते हैं.

75. (D)

76. (C)

- कारण (R) गलत है—मोल्टबुक पर इंसानों को पोस्ट करने या कमेंट करने की अनुमति नहीं है (वे केवल देख सकते हैं), लेकिन यह कहना गलत है कि एआई एजेंट 'बिना किसी मानवीय निर्देश' के काम कर रहे हैं. वास्तव में, इन बॉट्स को इंसानों द्वारा ही बनाया और 'प्रॉम्ट' किया जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि बॉट्स द्वारा विकसित की गई 'विश्वास प्रणालियाँ' या 'विचार-धाराएँ' अक्सर उनके शुरुआती मानवीय निर्देशों का ही परिणाम होती हैं, न कि पूर्णतः स्वतंत्र चेतना का.

77. (C)

- पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन रासायनिक-संश्लेषण एपीआई के उदाहरण हैं, न कि प्राकृतिक. प्राकृतिक एपीआई के उदाहरण मॉर्फिन और क्विनिन हैं, जिन्हें पौधों या जानवरों से निकाला जाता है.

78. (C)

- 'कौशल रथ' का उद्देश्य शहरी विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना नहीं, बल्कि अर्द्ध-शहरी और वंचित क्षेत्रों के छात्रों, युवाओं और शिक्षकों तक एआई शिक्षा की पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना है. यह 'फाउण्डेशनल एआई' और 'जेनरेटिव एआई' पर केन्द्रित है, न कि विशेष रूप से क्वांटम कम्प्यूटिंग पर.

79. (B)

- आरआर-टीबी विशेष रूप से रिफैम्पिसिन प्रतिरोध को दर्शाता है, लेकिन उपचार के उद्देश्य से इसे अक्सर एमडीआर/आरआर-टीबी के रूप में एक साथ समूहबद्ध किया जाता है.

80. (C)

- एनएलएसटी विद्युत् चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्यमान और निकट-अवरक्त तरंगदैर्ध्य में संचालित होगा, न कि एक्स-रे में.

81. (C)

- रजोनिवृत्ति केवल एक शारीरिक बदलाव नहीं है. हार्मोनल असन्तुलन का सीधा प्रभाव मस्तिष्क के उन रसायनों पर पड़ता है, जो मनोदशा को नियंत्रित करते हैं. इसके परिणामस्वरूप चिन्ता, अवसाद और गम्भीर मूड स्विंग्स जैसे मनोवैज्ञानिक लक्षण देखे जाते हैं.

82. (B)

- टेरावेव का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं के बजाय एंटरप्राइज, सरकारों और डेटा सेन्टरों के लिए उच्च क्षमता वाले डेटा बैकबोन प्रदान करना है.

83. (C)

- कथन 2 गलत है—सभी लिथियम-आयन बैटरी एसीसी नहीं होती हैं. एसीसी का वर्गीकरण केवल तभी होता है जब वे विशिष्ट 'प्रदर्शन मानकों' को पूरा करती हैं. सामान्य लिथियम-आयन बैटरी जो पुराने मापदण्डों पर आधारित हैं, उन्हें एसीसी की श्रेणी में नहीं रखा जाता. एसीसी में लिथियम-आयन के अलावा सोडियम-आयन, सॉलिड-स्टेट बैटरी और अन्य उभरती हुई रसायन विज्ञान तकनीकें भी शामिल हो सकती हैं.

84. (D) 85. (B) 86. (D) 87. (B)

88. (B)

- आईन-ए-अकबरी, सम्राट अकबर के आदेश पर अबुल फजल द्वारा लिखा गया ग्रन्थ है. यह 1598 में पूरा हुआ था.

89. (A)

राजवंश	राजधानी
• कुतुबशाही	– गोलकुंडा
• निजामशाही	– अहमदनगर
• आदिलशाही	– बीजापुर
• इमादशाही	– बीदर

90. (D)

91. (C) अमर-नायक प्रणाली विजय नगर साम्राज्य की एक प्रमुख सैन्य-प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली के समान थी. इसमें राजा (राय) द्वारा सैन्य कमांडरों (अमर-नायक) को राजस्व संग्रह और शासन के लिए क्षेत्र ('अमरम') आवंटित किए जाते थे. ये नायक निर्धारित सेना रखते थे और राजस्व का एक हिस्सा केन्द्रीय खजाने में भेजते थे, जो साम्राज्य की शक्ति और सुरक्षा का मुख्य आधार था.

92. (A)

93. (A)

(a) माध्यमिक सूत्र — नागार्जुन
(b) महाविभाषा-I — वसुमित्र
(c) देवी चंद्रगुप्तम-I — विशाखदत्त
(d) शिशुपाल वध — माघ

94. (A) धोलावीरा, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगरीय केन्द्र था. यह विशेष रूप से अपनी उन्नत जल-संरक्षण एवं जल-प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें वर्षाजल के संचयन और संरक्षण हेतु परस्पर जुड़े जलाशयों, नालों तथा बाँधों का निर्माण किया गया था. यह सुविकसित जल-प्रबंधन व्यवस्था उन्नत नगरीय अभियान्त्रिकी का परिचायक है. इन्हीं विशेषताओं के कारण धोलावीरा को सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक वैज्ञानिक रूप से नियोजित नगरों में से एक माना जाता है.

95. (B) 1937 में प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनाव अवश्य हुए, परन्तु मताधिकार केवल लगभग 10-12 प्रतिशत जनसंख्या तक सीमित था, अतः कथन 1 गलत है. कांग्रेस ने 5 प्रान्तों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 प्रान्तों में सरकारें बनाई, इसलिए कथन 2 सही है. मुस्लिम लीग का प्रदर्शन कमजोर रहा; NWFP में वह कोई सीट नहीं जीत सकी और पंजाब व सिंध में भी सीमित सफलता मिली, अतः कथन 3 सही है.

96. (A)

97. (A) 'होम चार्जेस (Home Charges)' वे व्यय थे जो इंग्लैण्ड में किए जाते थे, परन्तु उनका भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाता था और यह आर्थिक निकासी (Drain of Wealth) का महत्वपूर्ण साधन था. इनमें प्रशासनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज तथा रेल व सिंचाई निवेश पर सुनिश्चित प्रतिफल शामिल थे. ईस्ट इंडिया कम्पनी के शेयरधारकों को दिए गए लाभांश भी इस निकासी का हिस्सा थे, इसलिए कथन 4 गलत है.

98. (D) 99. (D)

100. (A) फाउलर समिति (1898) ने मुद्रा प्रणाली की समीक्षा की. चेम्बरलेन आयोग (1913) ने वित्तीय व्यवस्थाओं पर विचार किया. 1921 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया.

●●●

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



उद्योग, व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता

1. विभिन्न राज्यों की राजकोषीय सुदृढ़ता के आकलन के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (Fiscal Health Index) निम्नलिखित में से किसके द्वारा मार्च 2026 में जारी किए गए हैं ?
(A) भारतीय रिजर्व बैंक
(B) वित्त मंत्रालय
(C) नीति आयोग
(D) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्

2. मार्च 2026 में विभिन्न राज्यों के लिए जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर किस राज्य की राजकोषीय स्थिति अच्छी बताई गई है ?
(A) गुजरात (B) महाराष्ट्र
(C) पंजाब (D) ओडिशा

3. उपर्युक्त राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांकों के आधार पर सबसे खराब राजकोषीय सुदृढ़ता किस राज्य की आकलित की गई है ?
(A) झारखण्ड (B) छत्तीसगढ़
(C) पंजाब (D) ओडिशा

4. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत् पात्र लाभार्थियों को सालाना कितने रुपए तक कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ?
(A) ₹ 50 हजार (B) ₹ 1·0 लाख
(C) ₹ 2·5 लाख (D) ₹ 5·0 लाख

5. केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नई 'भव्य' योजना का सम्बन्ध किससे है ?
(A) औद्योगिक विकास
(B) कृषिगत विकास
(C) मत्स्यिकी क्षेत्र विकास
(D) खनन विकास

6. स्वीडन स्थित एक थिंक टैंक 'सीपरी' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र कौनसा है ?
(A) अमेरिका (B) रूस
(C) इजरायल (D) फ्रांस

7. उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र कौनसा है ?
(A) भारत (B) यूक्रेन
(C) ईरान (D) उत्तर कोरिया

8. निम्नलिखित में से किस दिन को 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है ?
(A) 15 जनवरी (B) 15 फरवरी
(C) 15 मार्च (D) 15 अप्रैल

9. फसल वर्ष 2025-26 में देश में गेहूँ का उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रहा है. यह उत्पादन लगभग कितना अनुमानित है ?
(A) 60 मिलियन टन
(B) 120 मिलियन टन
(C) 180 मिलियन टन
(D) 240 मिलियन टन

10. देश में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है ?
(A) पंजाब (B) हरियाणा
(C) मध्य प्रदेश (D) उत्तर प्रदेश

11. कर्मचारियों की भविष्य निधि जमाओं पर वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत सालाना की ब्याज की संस्तुति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 'बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज' द्वारा की गई है ?
(A) 6·25 प्रतिशत
(B) 7·25 प्रतिशत
(C) 8·25 प्रतिशत
(D) 9·25 प्रतिशत

12. भारत के एक प्रतिष्ठित उद्यमी एन. चन्द्रशेखरन को ब्रिटेन के सम्राट ने नाइटहुड के मानद सम्मान से मार्च 2026 में सम्मानित किया है. एन. चन्द्रशेखरन भारत के किस उद्योग ग्रुप से सम्बन्धित हैं ?
(A) रिलायंस ग्रुप (B) अडानी ग्रुप
(C) वेदांत ग्रुप (D) टाटा ग्रुप

13. वरिष्ठ बैंकर अतानु चक्रवर्ती ने हाल ही में निजी क्षेत्र के किस बैंक की चेयरमैनशिप से त्यागपत्र मार्च 2026 में दिया है ?
(A) आईसीआईसीआई बैंक
(B) यस बैंक
(C) एक्सिस बैंक
(D) एचडीएफसी बैंक

14. वरिष्ठ बैंकर विनय टोंस निजी क्षेत्र के यस बैंक के प्रबन्ध निदेशक सह-सीईओ अप्रैल 2026 में बनाए गए हैं. इस नियुक्ति से पूर्व विनय टोंस किस बैंक में प्रबन्ध निदेशक थे ?
(A) आईसीआईसीआई बैंक
(B) एक्सिस बैंक
(C) भारतीय स्टेट बैंक
(D) एचडीएफसी बैंक

15. फरवरी 2026 के अंत में भारत में विद्युत् उत्पादन की स्थापित क्षमता ने किस बिन्दु को पार किया था, जिससे भारत को विद्युत् उत्पादन मामले में अब आत्मनिर्भर कहा गया था ?
(A) 225 गीगावाट
(B) 325 गीगावाट
(C) 425 गीगावाट
(D) 525 गीगावाट

16. एनएसओ द्वारा फरवरी 2026 में जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों में भारत में 2025-26 में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है ?
(A) 6·6 प्रतिशत (B) 7·6 प्रतिशत
(C) 8·6 प्रतिशत (D) 7·0 प्रतिशत

17. स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए किस वर्ष को अब आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया है ?
(A) 2012 (B) 2012-13
(C) 2022-23 (D) 2024

18. एनएसओ के फरवरी 2026 के ताजा आकलन में 2025-26 में प्रचलित मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था ?
(A) 20 प्रतिशत (B) 30 प्रतिशत
(C) 40 प्रतिशत (D) 50 प्रतिशत

19. एशियाई विकास बैंक (ADB) का मुख्यालय कहाँ स्थित है ?
(A) नई दिल्ली (B) मुम्बई
(C) बैंकॉक (D) मनीला

20. फरवरी 2026 के अंत में भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष अब तक के सर्वोच्च स्तर पर थे (2025-26 के अंत तक की स्थिति). यह कोष उस समय लगभग कितने थे ?
(A) 628 अरब डॉलर
(B) 728 अरब डॉलर
(C) 828 अरब डॉलर
(D) 928 अरब डॉलर

उत्तरमाला

1. (C)	2. (D)	3. (C)	4. (D)
5. (A)	6. (A)	7. (B)	8. (C)
9. (B)	10. (D)	11. (C)	12. (D)
13. (D)	14. (C)	15. (D)	16. (B)
17. (C)	18. (A)	19. (D)	20. (B)

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित में से किस राज्य ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर पाबन्दी लगाए जाने का प्रस्ताव किया है ?
I. आंध्र प्रदेश II. गोवा
III. बिहार IV. कर्नाटक
सही कूट है–
(A) केवल I एवं II
(B) केवल II एवं III
(C) केवल I एवं IV
(D) केवल II एवं IV

2. निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 जीती ?
(A) कर्नाटक
(B) जम्मू-कश्मीर
(C) पश्चिम बंगाल
(D) उत्तराखण्ड

3. पुरुषों की भारतीय टीम ने किस देश को पराजित कर आईसीसी T-20 विश्व कप 2026 जीता ?
(A) द. अफ्रीका (B) इंग्लैण्ड
(C) न्यूजीलैण्ड (D) वेस्टइण्डीज

4. निम्नलिखित में से किसे आईसीसी (पुरुष) T-20 विश्व कप 2026 टूर्नामेन्ट में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेन्ट' के खिताब से नवाजा गया ?
(A) विल जैक्स (इंग्लैण्ड)
(B) रचिन रविन्द्र (न्यूजीलैण्ड)
(C) संजू सैमसन (भारत)
(D) टिम सीफर्ट (न्यूजीलैण्ड)

5. 98वें ऑस्कर 2026 (अकादमी पुरस्कारों) में पॉल थॉमस एण्डरसन को निम्नलिखित में से कौनसा पुरस्कार प्राप्त हुआ ?
I. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (वन बैटल ऑफ्टर अनदर)
II. सर्वश्रेष्ठ फिल्म (वन बैटल ऑफ्टर अनदर)
III. सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित पटकथा (वन बैटल ऑफ्टर अनदर)
उपर्युक्त में से सही है–
(A) केवल I एवं II
(B) केवल I
(C) केवल III
(D) I, II, III सभी

6. 98वें ऑस्कर 2026 पुरस्कारों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं है ?
(A) सर्वश्रेष्ठ फिल्म–सिनर्स
(B) सर्वश्रेष्ठ अभिनेता–माइकल बी. जॉर्डन
(C) सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री–जेसी बकले
(D) सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म–सेंटीमेंटल वैल्यू

7. मध्य-पूर्व में चल रहे इजरायल-अमेरिका-ईरान युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने सप्ताह में केवल 4 दिन काम करने का आदेश जारी किया है ?
(A) नेपाल (B) बांग्लादेश
(C) श्रीलंका (D) पाकिस्तान

8. भारतीय रिजर्व बैंक के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
I. भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन की संस्था 'सेन्ट्रल बैंक' की ओर से 'इनीशिएटिव ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
II. भारतीय रिजर्व बैंक को 'इनीशिएटिव ऑफ द ईयर' सम्मान उसके द्वारा लॉन्च किए गए 'बैंक डॉट इन' (bank.in) डोमेन के लिए प्रदान किया गया.
III. भारत विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने अपनी बैंकिंग प्रणाली के एक समर्पित और विशेष इंटरनेट डोमेन को अनिवार्य किया है.
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) उपर्युक्त से कोई नहीं

9. गैर-संचारी रोगों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है ?
(A) विश्व में होने वाली 75% मृत्यु गैर-संचारी रोगों के कारण होती है
(B) भारत में 40-50 प्रतिशत मृत्यु गैर-संचारी रोगों के कारण होती है
(C) भारत को प्रायः 'विश्व की मधुमेह राजधानी' कहा जाता है
(D) भारत में लगभग प्रत्येक चार वयस्कों में से एक व्यक्ति उच्च रक्तचाप से प्रभावित है

10. समाचारों की सुर्खियों में रहे 'प्रहार' (PRAHAAR) का सम्बन्ध निम्नलिखित में से किससे है ?
(A) समग्र आतंकवाद-रोधी नीति से
(B) कलवरी क्लास पनडुब्बी से
(C) सार्वभौमिक टीकाकरण से
(D) गैर-संचारी रोगों की रोकथाम से

11. वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 के बीच मक्का का उत्पादन 8·77% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर (CAGR) से बढ़ा, जबकि मक्का के अन्तर्गत क्षेत्रफल में 6·68% की वृद्धि दर्ज की गई. इस सकारात्मक वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है ?
(A) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् मक्का के वितरण में वृद्धि
(B) एथेनॉल के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में मक्का का बढ़ता उपयोग
(C) कुक्कुट चारा के रूप में मक्का का उपयोग
(D) शहरी नागरिकों के बीच गेहूँ के स्थान पर मक्का के उपयोग में वृद्धि

12. कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?
I. यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ.
II. इस तंत्र के अन्तर्गत लौह एवं इस्पात तथा उर्वरकों जैसे अधिक कार्बन-गहन उत्पादों के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर कार्बन शुल्क लागू होता है.
III. भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात में लगभग 90% हिस्सा लौह एवं इस्पात का है, जो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के दायरे में आता है.
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

13. निम्नलिखित में से किस पहल का सम्बन्ध स्वास्थ्य क्षेत्र से है ?
I. SAHI
II. AI-BODH
सही कूट है–
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

14. 'टेंडर ईयर्स डॉक्ट्रिन' के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
I. टेंडर ईयर्स डॉक्ट्रिन पारिवारिक विधि और अभिरक्षा सम्बन्धी न्यायशास्त्र का एक प्रमुख कॉमन कानून सिद्धान्त है.
II. इस सिद्धान्त का सार तत्व यह है कि आमतौर पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अभिरक्षा सामान्य तौर पर माता को दी जानी चाहिए जब तक कि उसे अयोग्य सिद्ध न कर दिया जाए.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

III. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह अभिधारित किया है कि अवयस्क बच्चों के कल्याण एवं उनके सर्वोत्तम हितों को 'टेंडर ईयर्स डॉक्ट्रिन' के अनुप्रयोग से ऊपर हो.

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

15. सामाजिक विकास आयोग क्या है ?
(A) यूरोपीय संघ का एक उप-निकाय
(B) संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक-सामाजिक परिषद् की एक कार्यात्मक समिति
(C) भारत में कार्यरत एक परामर्शदात्री निकाय
(D) विश्व बैंक में कार्यरत एक परामर्श-दात्री निकाय

16. अभी हाल ही में किस राज्य सभा सदस्य द्वारा राज्य सभा में निजी विधेयक (प्राइवेट मेम्बर बिल) प्रस्तुत किया गया ?
I. धनंजय भीमराव महादिक (भाजपा)
II. श्रीमती रेणुका चौधरी (कांग्रेस)
सही कूट है—
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

17. निम्नलिखित में से किस सांसद द्वारा लोक सभा में निजी विधेयक (Private Member Bill) पेश किया गया ?
I. शशि थरूर (कांग्रेस)
II. कृष्णप्रसाद तेन्नेती (तेलुगुदेशम पार्टी)
III. राजीव प्रताप रूडी (भाजपा)
IV. सुप्रिया सुले (एनसीपी-एससीपी)
उपर्युक्त में से सही है—
(A) केवल I एवं II
(B) केवल III एवं IV
(C) केवल I, II, III
(D) I, II, III, IV सभी

18. "प्रशिक्षुता पारितंत्र का पुनरुद्धार : अन्तर्दृष्टि, चुनौतियाँ, सिफारिशें एवं सर्वोत्तम प्रथाएँ" रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी की गई ?
(A) भारतीय रिजर्व बैंक
(B) नीति आयोग
(C) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
(D) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

19. 'वोमेन, बिजनेस एण्ड लॉ 2026' रिपोर्ट किस निकाय द्वारा जारी की गई ?
(A) विश्व बैंक
(B) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय
(C) नीति आयोग
(D) यू.एन. वोमेन

20. निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं है ?
(A) पीएम राहत—सड़क दुर्घटना पीड़ित सहायता
(B) संकल्प—आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास
(C) पीएम पोषण—तपेदिक रोगियों को पोषण सहायता
(D) प्रसाद—पर्यटन स्थलों का विकास

21. 13 फरवरी, 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए 'सेवा तीर्थ' परिसर की नक्काशीदार पत्थर की अधिष्ठान पट्टी निम्नलिखित में से किस मन्दिर की आधार-शिल्प सज्जा से प्रेरित है ?
(A) सूर्य मन्दिर, मोधेरो (गुजरात)
(B) चेन्नकेशव मन्दिर, बेलूर (कर्नाटक)
(C) दिलवाड़ा मन्दिर, आबू पर्वत (राजस्थान)
(D) बृहदेश्वरार मन्दिर, तंजावुर (तमिल-नाडु)

22. 'लोसर उत्सव 2026' का आयोजन कहाँ किया गया ?
(A) गंगटोक (सिक्किम)
(B) ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)
(C) धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)
(D) मैक्लॉडगंज (हिमाचल प्रदेश)

23. निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित है ?
I. हेरथ पोश्ते—कश्मीरी पंडितों की आस्था और परम्परा का उत्सव
II. थाई पूसम—थाइलैण्ड का प्रमुख त्योहार
सही कूट है—
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

24. समाचारों की सुर्खियों में रही तुलबुल नौवहन बैराज परियोजना किस राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र में स्थित है ?
(A) हिमाचल प्रदेश
(B) लद्दाख
(C) जम्मू-कश्मीर
(D) अरुणाचल प्रदेश

25. फरवरी 2026 में प्रारम्भ की गई सावल-कोट परियोजना किस नदी पर स्थित है ?
(A) चिनाब (B) सतलुज
(C) झेलम (D) किशनगंगा

26. निम्नलिखित में से कौनसा देश पैक्स सिलिका पहल का सदस्य नहीं है ?
(A) भारत
(B) पाकिस्तान
(C) द. कोरिया
(D) संयुक्त अरब अमीरात

27. प्रोजेक्ट वॉल्ट (Project Vault) के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है ?
(A) यह 12 अरब डॉलर की सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली परियोजना है
(B) इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों एवं दुर्लभ मृदा तत्वों के राष्ट्रीय भण्डारण से सम्बन्धित है
(C) इस परियोजनान्तर्गत रक्षा प्रणालियों विद्युत् वाहनों, बैटरियों, सेमीकण्डक्टरों आदि में प्रयुक्त होने वाले कोबाल्ट तथा गैलियम जैसे खनिजों का संग्रहण किया जाना है
(D) यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस तथा जर्मनी इस परियोजना से जुड़े हैं

28. 'आर्कटिक सेंट्री' मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
I. यह सं. रा. अमेरिका द्वारा प्रारम्भ किया गया एक अति महत्वाकांक्षी मिशन है.
II. इस मिशन का उद्देश्य आर्कटिक एवं उच्च उत्तरी क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को सुदृढ़ करना है.
सही कूट है—
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

29. अभी हाल ही निम्नलिखित में से किन देशों के बीच वन एवं जैव विविधता संरक्षण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ?
(A) भारत एवं नेपाल
(B) नेपाल एवं भूटान
(C) भारत एवं बांग्लादेश
(D) भारत एवं भूटान

30. 2 फरवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार, भारत में रामसर आर्द्रभूमियों की संख्या कितनी है ?
(A) 96 (B) 97
(C) 98 (D) 99

31. किस राज्य के वन विभाग द्वारा उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य में 6 'हॉर्न-बिल रेस्टोरेंटस' स्थापित करने की पहल प्रारम्भ की है ?
(A) बिहार (B) उत्तर प्रदेश
(C) छत्तीसगढ़ (D) मध्य प्रदेश

32. निम्नलिखित में से किसे 'बायो-वॉरियर' (Bio-Warrior) कहा गया है ?
I. नामालीकास्टिस सोलेनोटोग्नाथा (Namalycastis Solenoto-gnetha)
II. नेरिस धृतियाई (Nereis dhritiae)
सही कूट है—
(A) केवल I
(B) केवल II

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

33. चींटियों की किस प्रजाति को आर्मीआंट्स भी कहा जाता है ?
I. एनीक्टेस चिन्तूरेंसिस
II. एनीक्टस लंकामल्लोंसिस
सही कूट है–
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

34. भारत में नव विकसित Td वैक्सीन निम्न-लिखित में से किस रोग की रोकथाम में कारगर है ?
I. टेटनस
II. वयस्क डिफ्थीरिया
सही कूट है–
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

35. निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कृत्रिम मेधा के लिए 3A फ्रेमवर्क को अपनाए जाने की पहल प्रारम्भ की गई है ?
(A) शिक्षा
(B) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
(C) वित्तीय समावेश
(D) महिला सशक्तिकरण

36. 'स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, 2026 निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी की गई है ?
(A) भारतीय वन संस्थान
(B) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
(C) ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान
(D) विश्व बैंक

37. निम्नलिखित में से किस कारण से जीवों एवं पदार्थों के प्राकृतिक रंग विलुप्त होते जा रहे हैं ?
I. गर्म होते समुद्रों में शैवालों का अत्यधिक प्रसार
II. कोरल ब्लीचिंग
III. जंगली वनस्पतियों में क्लोरोफिल की कमी होना
सही कूट है–
(A) केवल I एवं II
(B) केवल II एवं III
(C) I, II, III सभी
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

38. रैट-होल खनन के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?
I. रैट-होल खनन मेघालय एवं पूर्वोत्तर भारत में कोयला खनन की एक अवैध एवं जोखिम भरी तकनीक है.
II. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रैट-होल खनन पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के बावजूद यह अभी भी प्रचलित है.
III. पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों में एक अवैध रैट-होल खान में हुए विस्फोट से 5 फरवरी, 2026 को कम-से-कम 30 लोग मारे गए.
सही कूट है–
(A) केवल I एवं II
(B) केवल II
(C) केवल II एवं III
(D) I, II, III सभी

39. माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
I. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक हालिया निर्णय में माहवारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान की है.
II. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक स्कूल (सरकारी एवं निजी) को वेंडिंग मशीनों के माध्यम से नि:शुल्क ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनेटरी नैपकिन लड़कियों को उपलब्ध कराने होंगे.
सही कूट है–
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

40. मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा (Mother Tongue-Based Multi-lingual Education–MTB-MLE) का उल्लेख अभी हाल ही में किस रिपोर्ट में प्रमुखता से किया गया है ?
(A) शिक्षा महिलाएँ, बच्चे, युवा एवं खेल पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट
(B) यूनेस्को की स्टेट ऑफ दी एजूकेशन रिपोर्ट
(C) नीति आयोग की एक रिपोर्ट
(D) 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट

1. (C) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 6 मार्च, 2026 को वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाए जाने का प्रस्ताव किया. ऐसा करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बना. आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, एन. चन्द्रबाबू नायडू ने भी विधान सभा में घोषणा की कि सरकार 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर पाबन्दी लगाने पर विचार कर रही है.
2. (B) असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जम्मू-कश्मीर की टीम ने हुबली (कर्नाटक) में 24-28 फरवरी, 2026 में खेले गए फाइनल में कर्नाटक को पहली पारी की बढ़त के आधार पर पराजित कर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती.
3. (C) विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम–नरेन्द्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेले गए आईसीसी T-20 विश्व कप 2026 के फाइनल मैच (8 मार्च, 2026) में भारत ने 96 रनों से न्यूजीलैण्ड को पराजित कर T-20 विश्व कप 2026 जीता. इससे पूर्व भारत ने 2007 में आईसीसी टी-20 विश्व कप का पहला टूर्नामेन्ट तथा 2024 का टूर्नामेन्ट जीता था.
4. (C) 5. (D)
6. (A) सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पॉल थॉमस एण्डरसन द्वारा निर्देशित वन बैटल ऑफ्टर अनदर को प्राप्त हुआ.
7. (C) श्रीलंका सरकार ने 16 मार्च, 2026 को सरकारी संस्थानों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में सप्ताह में केवल चार दिन काम करने के आदेश जारी किए हैं. इस प्रकार अब श्रीलंका में केवल सोमवार, मंगलवार, गुरुवार तथा शुक्रवार को कामकाज होगा. बुधवार, शनिवार तथा रविवार को कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा. यह निर्णय ऊर्जा की खपत को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है.
8. (C)
9. (B) हृदय रोग, मधुमेह, उच्चरक्त चाप, कैंसर और दीर्घकालिक श्वसन रोग प्रमुख गैर-संचारी रोग हैं. भारत में लगभग 60-65 प्रतिशत मृत्यु गैर-संचारी रोगों के कारण होती है.
10. (A) 'प्रहार' (PRAHAAR) भारत की पहली समग्र आतंकवादी रोधी नीति का अनावरण 23 फरवरी, 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा किया गया. P–Prevention (निवारण), R–Response (प्रतिक्रिया), A–Aggregation (एकीकरण), H–Human Rights (मानवाधिकार), A–Attenciation (क्षीणन), A–Alignment (सामंजस्य), R–Recovery (बहाली) इसके सात स्तम्भ हैं.
11. (B) 12. (C)
13. (C) (SAHI–Strategy for Artificial Intelligence in Healthcare for India) एक राष्ट्रीय मार्गदर्शक रूपरेखा है जिसे भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में कृत्रिम मेधा के सुरक्षित, नैतिक, साक्ष्य-आधारित और समावेशी उपयोग को सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है. AI-BODH : Artificial Intelligence Benchmarking open data Platform for Health को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है. इसका उद्देश्य एक ऐसा गोपनीयता संरक्षित मंच उपलब्ध कराना है, जहाँ मूल डेटा को सार्वजनिक या साझा किए बिना कृत्रिम मेधा मॉडलों को वास्तविक स्वास्थ्य आँकड़ों के आधार पर परखे जा सकें.

14. (C) टेंडर ईयर्स डॉक्ट्रिन का अनुप्रयोग उसी दशा तक प्रासंगिक है, जब तक कि वह प्रश्नगत बच्चे के हित के अनुरूप हो.

15. (B) 4 फरवरी, 2026 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में अपने अधिकार-आधारित, समावेशी एवं जनकेन्द्रित विकास दृष्टिकोण को प्रमुखता से प्रस्तुत किया.

16. (C) भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभा सदस्य धनंजय भीमराव महादिक द्वारा कोल्हापुरी लेदर क्राफ्ट (संरक्षण एवं जीवनयापन सुरक्षा) विधेयक, 2026 तथा कांग्रेस की राज्य सभा सदस्य श्रीमती रेणुका चौधरी द्वारा क्लाइमेट रेजीलिएंट एग्रीकल्चर एण्ड फार्मर्स प्रोटेक्शन विधेयक 2025, निजी विधेयक के रूप में राज्य सभा में प्रस्तुत किए गए.

17. (D) कांग्रेसी सांसद शशि थरूर द्वारा वैवाहिक बलात्कार को अपराध माने जाने सम्बन्धी भारतीय न्याय संहिता में संशोधन हेतु विधेयक दिसम्बर 2025 में लोक सभा में पेश किया गया. कृष्णप्रसाद तेन्नेती ने बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2025; राजीव प्रताप रूडी ने रेप्टाइल बाइट (प्रीवेशन एण्ड ट्रीटमेन्ट) तथा रेप्टाइल कंजरवेशन विधेयक, 2025 तथा सुप्रिया सुले ने पितृत्व एवं पितृत्व लाभ विधेयक 2025 दिसम्बर 2025 में लोक सभा में प्राइवेट मेम्बर विधेयक पेश किए.

18. (B) 19. (A)

20. (C) पीएम पोषण (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman–PM POSHAN) शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व में चलाई गई मिड-डे-मील योजना का परिवर्तित एवं संवर्धित रूप है, जिसमें सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूल में बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चों को गर्म, पौष्टिक भोजन कराया जाता है.

21. (B) विजयनारायण मन्दिर के नाम से भी विख्यात चेन्नकेशव मन्दिर का निर्माण कर्नाटक के बेलूर (प्राचीन नाम बेलापुर) में यगाची नदी के तट पर होयसल राजवंश के राजा विष्णुवर्धन द्वारा 1117 ईस्वी में कराया गया था.

22. (D) 'फायर हॉर्स वर्ष' के आरम्भ होने के प्रतीक स्वरूप लोसर उत्सव हिमाचल प्रदेश के मैक्लॉडगंज में 18-20 फरवरी, 2026 को आयोजित किया गया. यह तिब्बती बौद्ध समुदाय का पर्व है.

23. (A) थाई पूसम 'थाई' माह (तमिल पंचांग का एक माह) की पूर्णिमा को 'पूसम' नक्षत्र में मनाया जाता है. इस वर्ष यह 1 फरवरी, 2026 को तमिलनाडु, श्रीलंका, सिंगापुर एवं मलेशिया के तमिल परिवारों में हर्षोल्लास से मनाया गया.

24. (C) जम्मू-कश्मीर में बुलर झील के निकास बिन्दु पर स्थित एक नेवीगेशन लॉक-सह-नियंत्रण संरचना को बुलर बैराज कहा जाता है. इसे जम्मू-कश्मीर सरकार नौवहन परियोजना के रूप में विकसित कर रही है. इस परियोजना का एक उद्देश्य झेलम नदी में जल का न्यूनतम स्तर बनाए रखना भी है.

25. (A) 1856 मेगावाट क्षमता वाली नदी प्रवाह आधारित जलविद्युत् परियोजना संघ शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में फरवरी 2026 में प्रारम्भ की गई.

26. (B) संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में दिसम्बर 2025 में प्रारम्भ की गई 'पैक्स सिलिका' पहल में मूल रूप से सं.रा. अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, द. कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैण्डस, इजरायल, ऑस्ट्रेलिया, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे. 20 फरवरी, 2026 को भारत भी इस पहल में शामिल हो गया. यह पहल महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर और कृत्रिम मेधा प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित आपूर्ति शृंखलाओं के सुदृढ़ीकरण पर केन्द्रित है.

27. (D)

28. (B) आर्कटिक सेन्ट्री (Arctic Sentry) उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) द्वारा फरवरी 2026 में प्रारम्भ' की गई एक पहल है जिसमें आर्कटिक एवं उच्च उत्तरी क्षेत्र में वायुसेना, नौसेना तथा थल सेना की तैनाती को अधिक समन्वित रूप प्रदान करना है.

29. (A) 25 फरवरी, 2026 को भारत एवं नेपाल के बीच वनों, वन्य जीवों पर्यावरण, जैव विविधता, संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इस पहल का एक उद्देश्य हाथी, गंगा डॉल्फिन, गैंडा, हिम तेन्दुआ, बाघ तथा गिद्धों के संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान करना है.

30. (C) 2 फरवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार, भारत में रामसर आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 98 है जिनके अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्रफल 1360805·63 हेक्टेयर है.

31. (C) इस पहल का उद्देश्य दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल के लिए स्थायी अधिवास उपलब्ध कराना है.

32. (C) फरवरी 2026 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले के दीघा और बांकीपुर के प्रदूषित तटीय क्षेत्रों में समुद्री कृमि (Marine Worm) की दो नई प्रजातियाँ नामालीकास्टिस सोलेनोटोग्नाथा तथा नेरिस धृतियाई खोजी गई है, जो विषैले रसायनों, ऑक्सीजन के निम्न-स्तर, अधिक लवणीय जल तथा प्रदूषित अधिवासों में भी जीवित रहने में सक्षम है.

33. (C) फरवरी 2026 में श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य (आंध्र प्रदेश) में चींटियों की दो नई प्रजातियों—एनीक्टस चिन्तरेंसिस तथा एनीक्टस लंकामल्लेंसिस की खोज की गई. ये दोनों वन पारि-स्थितिक तंत्र में शीर्ष परभक्षी प्रजाति की भूमिका निभाती है.

34. (C) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में स्वदेशी रूप से विनिर्मित Td वैक्सीन टेटेनस तथा एडल्ट डिफ्थीरिया (वयस्क गलघोंटू) में कारगर हुई है.

35. (A) 3A फ्रेमवर्क शैक्षणिक संस्थानों में वर्षों से प्रचलित रटने वाली पद्धति को सुधार करते हुए कृत्रिम मेधा के अनुकूल शिक्षण पद्धति अपनाने पर केन्द्रित है. 3A से तात्पर्य A–Adoption (अपनाना); A–Absorption (आत्मसात् करना) तथा A–Application (अनुप्रयोग) से है.

36. (B)

37. (C) सतत् रूप से जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्रों में शैवाल (Algae) का प्रसार बढ़ने से समुद्रों तथा महासागरों का रंग हरा होता जा रहा है. समुद्र की सतह पर शैवाल के छा जाने से सूर्य का प्रकाश पानी में गहराई तक नहीं जा पाता. इससे सामुद्रिक वनस्पतियों का नैसर्गिक विकास बाधित होता है. कोरल ब्लीचिंग तथा समुद्री तापमान में वृद्धि हो जाने से मूँगे अपने भीतर रहने वाले रंगीन शैवाल को बाहर निकाल देते हैं जिसके कारण वे सफेद होते जाते हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण क्लोरोफिल की कमी हो जाने से जंगलों का रंग भूरा होता जा रहा है.

38. (D)

39. (C) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने डॉ. जया ठाकुर *बनाम* भारत सरकार वाद में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को मौलिक अधिकार माना तथा स्कूलों में निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन वितरण के आदेश पारित किए.

40. (B) ●●●

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



आर्थिक घटनाचक्र : वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राष्ट्रीय आय लेखों का आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित करके क्या किया गया है ?
(A) 2021-22 (B) 2022-23
(C) 2023-24 (D) 2024-25

2. द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर कितनी रह सकती है ?
(A) 7·2 प्रतिशत (B) 7·3 प्रतिशत
(C) 7·6 प्रतिशत (D) 7·8 प्रतिशत

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 (द्वि.अ.अनु.) में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की नॉमीनल विकास दर कितनी अनुमानित है ?
(A) 9·2 % (B) 8·8 %
(C) 8·7 % (D) 8·6 %

4. राष्ट्रीय आय लेखों की नई शृंखला आधार वर्ष 2022-23) में वर्ष 2025-26 में स्थिर कीमतों पर विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिशत हिस्से के सन्दर्भ में सूची-I (क्षेत्र) एवं सूची-II (जीवीए में हिस्सा % में) पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए–

सूची-I (क्षेत्र)
(a) कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र
(b) उद्योग
(c) विनिर्माण
(d) वित्तीय स्थावर सम्पदा एवं पेशेवर सेवाएँ

सूची-II (औसत भार % में)
1. 16·25% 2. 19·74%
3. 26·06% 4. 27·61%

सही कूट है–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	4	1	3
(B)	4	2	3	1
(C)	1	2	3	4
(D)	4	3	2	1

5. वित्त वर्ष 2025-26 के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सर्वाधिक खराब प्रदर्शन का अनुमान लगाया गया है ?
(A) कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र
(B) खनन एवं उत्खनन
(C) विद्युत्, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवाएँ
(D) निर्माण

6. वित्त वर्ष 2025-26 में नॉमीनल सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) में सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र का है ?
(A) कृषि, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्यिकी
(B) विनिर्माण
(C) वित्तीय, स्थावर सम्पदा, सूचना प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाएँ एवं निवास-स्थलों का स्वामित्व
(D) लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएँ

7. वित्त वर्ष 2025-26 (द्वि.अ.अनु.) में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सकल मूल्य वृद्धि की वास्तविक वृद्धि दर सर्वाधिक रही है ?
(A) विनिर्माण
(B) व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से सम्बन्धित सेवाएँ
(C) वित्तीय, स्थावर सम्पदा एवं पेशेवर सेवाएँ
(D) निर्माण

8. सकल घरेलू उत्पाद की नवीन शृंखला (आधार वर्ष 2022-23) में वित्त वर्ष 2025-26 (द्वि.अ.अनु.) के आँकड़ों में सर्वाधिक चौंका देने वाला कथन निम्नलिखित में से कौनसा है ?
(A) वास्तविक प्रति व्यक्ति आय प्रथम अग्रिम अनुमानों की तुलना में द्वितीय अग्रिम अनुमानों में अधिक है
(B) नॉमीनल प्रति व्यक्ति आय प्रथम अग्रिम अनुमानों की तुलना में द्वितीय अग्रिम अनुमानों में कम है
(C) नई शृंखला में नॉमीनल जीडीपी वृद्धि को पहले अग्रिम अनुमान की तुलना में कम कर दिया जाना
(D) कम नॉमीनल जीडीपी की वजह से वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4·5% के स्तर पर रहा है

9. भारत में महिला श्रम की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही हैं ?
I. वर्ष 2024 में भारत में महिला श्रम सहभागिता दर मात्र 32 थी.
II. भारतीय श्रम बल में लगभग 78 प्रतिशत महिलाएँ असुरक्षित रोजगार में हैं.
III. असुरक्षित रोजगार में प्रायः औपचारिक अनुबन्ध, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, उचित कार्य दशाएँ और श्रम संघों में प्रतिनिधित्व नहीं होता.
सही कूट है–
(A) केवल एक कथन सही है
(B) केवल दो कथन सही हैं
(C) तीनों ही कथन सही हैं
(D) कोई भी कथन सही नहीं है

10. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर कितनी निर्धारित की है ?
(A) 7·25% (B) 8·25%
(C) 8·50% (D) 8·75%

11. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
I. विश्व में भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है.
II. भारत विश्व में चौथा सबसे अधिक तेल परिशोधन करने वाला देश है.
III. भारत विश्व में पेट्रोलियम उत्पादों का पाँचवाँ सबसे बड़ा निर्यातक देश है.
सही कूट है–
(A) केवल I एवं II
(B) केवल II एवं III
(C) केवल I एवं III
(D) I, II, III सभी

12. भारत की किस नदी पर 'नदी प्रकाश स्तम्भों' का निर्माण किया जा रहा है ?
(A) गंगा (B) ब्रह्मपुत्र
(C) महानदी (D) गोदावरी

13. ज्ञान भारतम मिशन के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
I. ज्ञान भारतम मिशन संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है जिसकी घोषणा केन्द्रीय बजट 2026-27 में की गई.
II. ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य भारत की विशाल पाण्डुलिपि विरासत को

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

उजागर करना और उसकी रक्षा करते हुए उसे संरक्षित करना है.

सही कूट है—
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

14. जल जीवन मिशन के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?
I. "2030 तक सभी के लिए सुरक्षित और किफायती पेय जल की व्यापक और समान उपलब्धता" संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य 6·1 का भाग है.
II. भारत के लगभग 19·36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15·82 करोड़ (81·71%) परिवारों को नल से जलापूर्ति की जा रही है.
III. 10 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा गोवा राज्यों में 100 प्रतिशत परिवारों को नल से जलापूर्ति की जा रही है.

उपर्युक्त में से सही है—
(A) केवल I
(B) केवल II एवं III
(C) केवल I एवं III
(D) I, II, III सभी

15. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक (2025-26) रिपोर्ट जारी की गई है. यह सूचकांक किसके सहयोग से तैयार किया गया है ?
(A) राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केन्द्र (NRSC-ISRO)
(B) ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, नई दिल्ली (TERI)
(C) भारतीय वन संस्थान, देहरादून (IIF)
(D) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

16. नेपाल के प्रतिनिधि सभा के चुनावों में किस राजनीतिक दल ने दो-तिहाई बहुमत से बड़ी जीत हासिल की ?
(A) नेपाली कांग्रेस
(B) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनीफाइड मार्क्सिस्ट–लेनिनिस्ट)
(C) राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी
(D) श्रम शक्ति पार्टी

17. नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) 2026 के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?
I. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 वर्ष 2024-25 में राज्यों के राजकोषीय निष्पादन पर आधारित है.
II. इस सूचकांक में राजकोषीय दृष्टि से सुदृढ़ स्थिति वाले 10 शीर्ष राज्यों में ओडिशा पहले स्थान पर है.
III. राजकोषीय स्वास्थ्य रैंकिंग में पंजाब, प. बंगाल तथा केरल निचले पायदानों पर हैं.
IV. उच्च रैंक पाने वाले राज्यों में सुदृढ़ राजकोषीय अनुशासन तथा बेहतर संसाधन सृजन दर्शाया है, जबकि नीची रैंक वाले राज्यों में गैर-विकासात्मक व्यय बहुत ऊँचा है तथा राजकोषीय सम्पोषणीयता कमजोर है.

सही कूट है—
(A) केवल I, II, III
(B) केवल II, III, IV
(C) केवल I, III, IV
(D) I, II, III, IV सभी

18. सं. रा. अमेरिका द्वारा अभी हाल ही लिए गए किस निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव भारत से सं.रा. अमेरिका को किए जाने वाले निर्यातों पर पड़ सकता है ?
I. व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत् निर्यातकों के क्षमता अतिरेक की जाँच करना.
II. निर्यात की जाने वाली मदों के उत्पादन में 'बलात् श्रम' के उपयोग की जाँच करना.

सही कूट है—
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

19. सं.रा. अमेरिकी प्रशासन द्वारा अपने 15 व्यापार साझीदार देशों के विरुद्ध व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 के तहत् 'क्षमता अतिरेक' की जाँच के आदेश दिए हैं. यदि कोई देश इस क्षमता अतिरेक में संलिप्त पाया जाता है, तो अमेरिकी प्रशासन उस देश के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर सकता है ?
I. क्षमता अतिरेक वाली इकाई के उत्पाद पर प्रशुल्क लगाना.
II. क्षमता अतिरेक वाली इकाई के उत्पाद के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना.
III. व्यापार समझौता रियायतों को निलम्बित कर देना.
IV. सम्बन्धित देश को बाध्य करना कि वह सं. रा. अमेरिका को होने वाली क्षति की भरपाई करे.

उपर्युक्त में से कितने उपाय किए जा सकते हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) केवल तीन (D) सभी चार

20. विश्व व्यापार संगठन के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
I. मंत्रिस्तरीय कॉन्फ्रेंस विश्व व्यापार संगठन का निर्णय करने वाला सर्वोच्च निकाय है.
II. विश्व व्यापार संगठन का 14वाँ मंत्रिस्तरीय कॉन्फ्रेंस याउंदे (कैमरून) में 26-29 मार्च, 2026 को आयोजित हुआ.

सही कूट है—
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

21. भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई '24 स्पीड पोस्ट' पहले चरण में निम्नलिखित में से किन शहरों में प्रारम्भ की गई है ?
I. दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ.
II. दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई.
III. कोलकता, बेंगलुरु, हैदराबाद.
IV. दिल्ली, अमृतसर, पटना

सही कूट है—
(A) केवल I एवं II
(B) केवल II एवं III
(C) केवल I एवं IV
(D) केवल II एवं IV

22. सामान्य तौर पर मृदा में निम्नलिखित में से कौनसे पोषक तत्व पाए जाते हैं ?
I. नाइट्रोजन
II. फॉस्फोरस
III. पोटैशियम
IV. जस्ता
V. लौह
VI. बोरॉन

सही कूट है—
(A) केवल I, II, III, IV
(B) केवल I, II, III, V
(C) केवल I, II, V, VI
(D) I, II, III, IV, V एवं VI

23. वर्ष 2024-25 में भारत में दूध का उत्पादन कितना अनुमानित है ?
(A) 222 मिलियन टन
(B) 231 मिलियन टन

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

(C) 239 मिलियन टन
(D) 248 मिलियन टन

24. 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार, भारत में अखिल भारतीय विद्युत् उत्पादन क्षमता के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?
I. देश में अखिल भारतीय विद्युत् उत्पादन क्षमता 520·5 GW है.
II. देश में 52·30 प्रतिशत विद्युत् उत्पादन क्षमता कुल गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है.
सही कूट है—
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

25. निम्नलिखित में किस स्थिति में केन्द्रीय बैंक कठोर मौद्रिक नीति अपनाते हैं ?
I. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि.
II. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि.
III. राजकोषीय घाटे में वृद्धि.
IV. चालू खाते घाटे में वृद्धि.
उपर्युक्त में से सही है—
(A) केवल II
(B) केवल I एवं II
(C) केवल II एवं III
(D) I, II, III, IV सभी

26. समाचारों की सुर्खियों में रहे मोनोजाइट के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
I. मोनोजाइट एक समुद्री रेत खनिज है.
II. मोनाोजाइट में दुर्लभ खनिज तत्व तथा थोरियम दोनों पाए जाते हैं.
III. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत् मोनोजाइट को 'प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस' के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
IV. भारत में मोनोजाइट का खनन, ढुलाई, प्रसंस्करण और भण्डारण कड़ाई के साथ विनियमन के दायरे में आता है.
सही कूट है—
(A) केवल I एवं II
(B) केवल I एवं III
(C) केवल II एवं III
(D) I, II, III, IV सभी

27. समुद्री रेत खनिजों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
I. समुद्री रेत खनिजों का विनियमन 'खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के दायरे में आता है.
II. ओडिशा में गोपालपुर, केरल में कोच्चि-तिरुवनंतपुर गलियारे तथा आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम-श्रीकाकुलम गलियारे की पहचान दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए की गई है.
सही कूट है—
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

28. समाचारों की सुर्खियों में रहे प्रेस नोट-3 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
I. प्रेस नोट-3 कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान वर्ष 2020 में भारतीय कम्पनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया था.
II. प्रेस नोट-3 के प्रावधानों के तहत् भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के निवेशक को भारत में निवेश के लिए केवल सरकारी मंजूरी वाले मार्ग से निवेश अनुमन्य रहा है.
III. 5 मार्च, 2026 को संशोधित प्रेस नोट-3 के अनुसार, सरकार ने जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के निवेशकों को 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत 'ऑटोमैटिक रूट' (सरकारी अनुमति के बिना) से निवेश करने की अनुमति दी गई है.
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल I एवं II
(B) केवल II एवं III
(C) I, II, III सभी
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

29. फसल वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) में भारत में बागवानी उत्पादन कितना अनुमानित है ?
(A) 370·85 मिलियन टन
(B) 365·26 मिलियन टन
(C) 358·39 मिलियन टन
(D) 349·20 मिलियन टन

30. फसल वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) के लिए जारी बागवानी फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमानों के सन्दर्भ में सूची-I (प्रमुख फल) तथा सूची-II (2025-26 में अनुमानित उत्पादन) पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए—

सूची-I (प्रमुख फल)

(a) केला (b) आम
(c) सेब (d) अमरूद

सूची-II (उत्पादन मिलियन टन)

1. 2·79 2. 5·52
3. 23·45 4. 39·62

सही कूट है—

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	3	2	1
(B)	4	3	1	2
(C)	3	4	1	2
(D)	3	4	2	1

31. बागवानी फसलों के लिए वर्ष 2025-26 (प्रथम अग्रिम अनुमान) में वर्ष 2024-25 की तुलना में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक कमी (% में) आई है ?
(A) आम (B) टमाटर
(C) प्याज (D) आलू

32. निम्नलिखित में से कौनसी वित्तीय समावेशन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा कारगर पहल है ?
(A) अटल पेंशन योजना
(B) प्रधानमंत्री जनधन योजना
(C) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
(D) स्टैण्ड अप इण्डिया योजना

33. विश्व बैंक द्वारा वैश्विक स्तर पर निर्धनता के आकलन (जून 2025) हेतु निम्नलिखित में से कौनसी निर्धनता रेखा अब प्रचलन में नहीं है ?
(A) 2·15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति
(B) 3·00 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति
(C) 4·20 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति
(D) 8·30 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति

34. भारत के सन्दर्भ में विश्व बैंक द्वारा आकलित चरम निर्धनता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
I. वर्ष 2022 में भारत की 5·3% जनसंख्या अन्तर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा (3·00 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति) द्वारा मापित चरम निर्धनता में रह रही थी.
II. वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा सीधे कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू नहीं किया जा रहा है.
उपर्युक्त में से कौनसा कथन सही है ?
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

35. क्षैतिजिक वितरण निर्धारण के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा अग्रलिखित में

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

से किस कसौटी को पहली बार प्रयुक्त किया है जिसे 15वें वित्त आयोग ने प्रयुक्त नहीं किया था ?
(A) आय से दूरी
(B) जीडीपी में योगदान
(C) कर एवं राजकोषीय प्रयास
(D) जनसंख्या नियंत्रण प्रयास

36. I. 16वें वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार के करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% के स्तर पर ही बनाए रखा है.
II. 41% के इस हिस्से में राज्यों के व्यक्तिगत हिस्से के निर्धारण के लिए अपनाई गई कसौटी में कर एवं राजकोषीय निष्पादन को 10% भारांकन प्रदान किया गया है.
उपर्युक्त में से कौनसा कथन सही है ?
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

37. केन्द्रीय बजट 2026-27 में जेंडर बजट के रूप में आबंटित धनराशि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है ?
(A) 8·86% (B) 9·37%
(C) 10·59% (D) 12·65%

38. भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों के योगदान के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित है ?
I. सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी : 31·1%.
II. विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में भागीदारी : 35·4%.
III. कुल निर्यात में भागीदारी : 48·58%.
सही कूट है—
(A) केवल I एवं II
(B) केवल II एवं III
(C) केवल III
(D) I, II, III सभी

39. ग्रेट निकोबार मेगा-अवसंरचना में शामिल हैं—
I. अन्तर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेन्ट बन्दरगाह का विकास.
II. एकीकृत टाउनशिप का विकास.
III. दोहरे उपयोग वाला नागरिक-सह-सैन्य हवाई अड्डे का विकास.
IV. 450 MVA क्षमता के हाइब्रिड पॉवर प्लाण्ट की स्थापना.
सही कूट है—
(A) केवल I एवं II
(B) केवल I एवं III
(C) केवल III एवं IV
(D) I, II, III, IV सभी

40. भारतीय कृषि के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
I. वर्ष 2025-26 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 370·85 मिलियन टन अनुमानित है (द्वितीय अग्रिम अनुमान).
II. वर्ष 2025-26 में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 348·66 मिलियन टन अनुमानित है. (द्वितीय अग्रिम अनुमान).
उपर्युक्त में से सही है—
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

उत्तर व्याख्या सहित

1. (B) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय आय लेखों के आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 2012 से बदलकर 2024 तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है.
2. (C) 3. (D) 4. (A)
5. (C) वित्त वर्ष 2025-26 के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों (2022-23) पर सकल मूल्यवर्द्धन (GVA) की सबसे नीची विकास दर विद्युत्, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवाओं (मात्र 1·5%) रहने का अनुमान लगाया गया है. इसके बाद कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र (2·4%), खनन एवं उत्खनन (4·1%) तथा निर्माण (7·1%) का स्थान है.
6. (C) वित्त वर्ष 2025-26 के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, नाममात्र (नॉमीनला) सकल मूल्य वृद्धि में सर्वाधिक हिस्सा वित्तीय, स्थावर सम्पदा, सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर सेवाएँ एवं निवास स्थलों का स्वामित्व (27%) का है, उसके बाद कृषि पशुधन, वानिकी एवं मत्स्यिकी (18%), विनिर्माण (15%) तथा लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएँ (13%) का स्थान है.
7. (A) जीडीपी की नई शृंखला (आधार वर्ष 2022-23) में वित्त वर्ष 2025-26 (IIAE) में सकल मूल्य वृद्धि की सर्वाधिक वास्तविक वृद्धि दर विनिर्माण क्षेत्रक (11·5%) ने दर्ज की है. इससे कम व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से सम्बन्धित सेवाएँ (10·1%), वित्तीय, स्थावर सम्पदा तथा पेशेवर सेवाएँ (9·9%) तथा निर्माण (7·1%) का स्थान रहा है.
8. (C) 9. (C)
10. (B) कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर वर्ष 2022-23 में 8·15% थी, जिसे बढ़ाकर 2023-24 में 8·25% कर दिया गया था. वर्ष 2024-25 एवं अब वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर को इसी स्तर पर रखा गया है.
11. (D)
12. (B) केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ब्रह्मपुत्र नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-2) पर बोगीबील (डिब्रूगढ़ जनपद), पांडू (कामरूप (मेट्रो) जनपद), सिलघाट (नागांव जनपद) [सभी ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर] तथा विश्वनाथ घाट (विश्वनाथ जनपद) उत्तरी तट पर चार नदी प्रकाश स्तम्भ का निर्माण कराने जा रहा है.
13. (B) केन्द्रीय बजट 2025-26 के दौरान घोषित ज्ञान भारतम मिशन संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है.
14. (D)
15. (A) राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पौधारोपण का मात्रात्मक आकलन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक 2025-26 पर अपनी तरह की पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की. यह रिपोर्ट भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केन्द्र के समन्वय से जारी की गई है. हरित आवरण का आकलन उच्च-रिजॉल्यूशन उपग्रह सेंसरों द्वारा पता लगाए गए क्लोरोफिल की मात्रा से प्राप्त किया गया है.
16. (C) काठमांडू के मेयर बालेन्द्रशाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रतिनिधि सभा के 165 स्थानों में से 125 सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया समानुपातिक प्रणाली के तहत् मिलने वाली 57 सीटों के साथ इस दल के प्रतिनिधियों की संख्या 182 हो जाएगी. 275 सदस्यीय सदन में यह लगभग 66% है. नेपाल में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू होने के बाद से यह पहला चुनाव है जिसमें किसी एक ही दल को स्पष्ट बहुमत मिला है.
17. (B) राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 वर्ष 2023-24 में राज्यों के राजकोषीय निष्पादन पर आधारित है.
18. (C) सं. रा. अमेरिकी प्रशासन ने अपने 15 व्यापार साझीदार देशों के विरुद्ध इस बात की गहन जाँच किए जाने के आदेश जारी किए हैं कि उन देशों की निर्यातक इकाइयों में कहीं क्षमता

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

अतिरेक की स्थिति तो नहीं है. इसी के साथ-साथ अपने व्यापार साझीदार 59 देशों तथा यूरोपीय संघ के विरुद्ध यह भी जाँच कराई जा रही है कि उनके उत्पादों के उत्पादन में कहीं 'बलात्' श्रम का उपयोग तो नहीं किया जा रहा है.

19. (D)

20. (C) 14वाँ विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC 14) 26-29 मार्च, 2026 को याउंदे (कैमरून) में आयोजित किया गया. विश्व व्यापार संगठन की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में, इस सम्मेलन में सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों ने विश्व व्यापार संगठन प्रणाली में सुधारों, कृषि नीतियों, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल व्यापार नियमों पर गहन चर्चा की.

21. (B) भारतीय डाक विभाग द्वारा 17 मार्च, 2026 को '24 स्पीड पोस्ट' सेवा दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु तथा हैदराबाद में प्रारम्भ की गई. इस सेवा के तहत् ओटीपी आधारित सुरक्षित वितरण, एसएमएस अलर्ट के साथ एण्ड-टू-एण्ड ट्रैकिंग, व्यावसायिक ग्राहकों के लिए बीएनपीएल सुविधा, बल्क बुकिंग के लिए निःशुल्क पिकअप तथा केन्द्रीयकृत बिलिंग के साथ तत्काल और समयबद्ध शिपमेन्ट के लिए अगले दिन वितरण की गारन्टी दी गई है. इसके साथ ही '24 स्पीड पोस्ट' तथा '48 स्पीड पोस्ट सेवाएँ समर्पित प्रोसेसिंग विन्डो और प्राथमिकता वाले हवाई परिवहन के माध्यम से सुनिश्चित D + 1 और D + 2 वितरण समय-सीमा प्रदान करेंगी.

22. (D) भारत के मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण ने 1 : 50,000 और 1 : 10,000 के विभिन्न पैमाने पर मृदा डेटाबेस तैयार किया गया है जिससे पता चला है कि भारत की मृदा में पोटैशियम पर्याप्त मात्रा में है, जबकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है. बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा राज्यों में मृदा में जस्ता की कमी पाई जाती है, जबकि मृदा में लौह की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है.

23. (D)

24. (C) 31 जनवरी, 2026 को अखिल भारतीय विद्युत् स्थापित क्षमता 520·5 GW है जिसमें से 47·70% (248·542 GW) जीवाश्म ईंधन स्रोतों से तथा 52·30% (271·969 GW) गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है.

25. (D) 26. (D)

27. (B) भारत में समुद्री रेत खनिजों का खनन का विनियमन परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 'परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 के द्वारा किया जाता है.

28. (C) उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग द्वारा 5 मार्च, 2026 को जारी प्रेस नोट-2 (2026 शृंखला) के द्वारा प्रेस नोट-3(2020) में संशोधन करके भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों–चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान के निवेशकों को भारत में 10 प्रतिशत तक विदेशी निवेश 'ओटोमैटिक रूट' से (सरकार की पूर्वानुमति के बिना) करने (गैर-नियंत्रक हिस्सेदारी रखने) की अनुमति प्रदान की है, जिसमें सेक्टर विशिष्ट निवेश की उच्चतम सीमा लागू होगी. (जिस कम्पनी में इस प्रकार का निवेश आएगा उन्हें उद्योग विभाग को विस्तार से बताना होगा).

29. (A) फसल वर्ष 2025-26 (जुलाई 2025–जून 2026) के लिए जारी बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 370·85 मिलियन टन होने का अनुमान है जो वर्ष 2024-25 के अन्तिम अनुमानों (370·74 मिलियन टन से मामूली ही अधिक है.

30. (B)

31. (C) आम का उत्पादन 2024-25 में 23·14 मिलियन टन से प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में 23·45 मिलियन टन; टमाटर का 20·60 मिलियन टन से 10·2% बढ़कर 22·70 मिलियन टन, प्याज का उत्पादन 30·77 मिलियन टन से 11·2% कम होकर 27·31 मिलियन टन तथा आलू का उत्पादन 58·57 मिलियन टन से 0·2% कम होकर 58·45 मिलियन टन होना अनुमानित है.

32. (B) समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से बैंकिंग, ऋण और बीमा तक पहुँच प्रदान करने के लिए सरकार ने अगस्त 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेश मिशन नामक प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की ताकि प्रत्येक बैंक रहित परिवार को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जा सकें. इस पहल का आधार सिद्धान्त है—बैंक रहितों को बैंकिंग, असुरक्षितों को सुरक्षा और वित्त रहितों को वित्त. इस योजनान्तर्गत 25 फरवरी, 2026 तक कुल 57·78 करोड़ जनधन खातों में ₹ 2,94,702 करोड़ जमा है. 32·21 करोड़ खाते (55·8%) महिलाओं के है.

33. (A) विश्व बैंक द्वारा जून 2025 में 2021 में क्रय-शक्ति समता के रूप में निर्धनता रेखाओं को संशोधित किया गया है. वर्तमान में 3·00 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा माना गया है. नीची-मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धनता रेखा 4·20 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है, जबकि उच्च-मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धनता रेखा 8·30 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है.

34. (C) विश्व बैंक के एक आकलन के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में प्रत्येक 20 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चरम निर्धनता (3·00 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) में जीवन यापन कर रहा था (5·3%), जबकि 4 में से एक व्यक्ति नीची-मध्यम आय देशों के लिए निरूपित निर्धनता (4·2 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) (23·9%) में जीवन-यापन कर रहा था. उच्च-मध्यम आय वाले देशों के लिए निरूपित निर्धनता (8·30 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति) की दृष्टि से भारत की 82·1% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे रह रही थी. विश्व बैंक की सभी निर्धनता रेखाएँ 2021 की क्रय-शक्ति क्षमता पर आधारित हैं.

35. (B) सोलहवें वित्त आयोग ने क्षैतिजिक वितरण हेतु जो कसौटी निर्धारित की हैं. उसमें आय से दूरी को 42·5% भारांकन, जनसंख्या (2011) को 17·5% भारांकन, क्षेत्रफल को 10% भारांकन, वन क्षेत्र को 10% भारांकन, जीडीपी में योगदान को 10% भारांकन प्रदान किया है.

36. (A) क्षैतिजिक वितरण के लिए 15वें वित्त आयोग ने जो कसौटी निर्धारित की थी उसमें कर एवं राजकोषीय प्रयास को 2·5% भारांकन प्रदान किया गया था, जबकि 16वें वित्त आयोग ने इस पर विचार नहीं किया है वरन् जीडीपी में योगदान को पहली बार 10% भारांकन प्रदान किया है.

37. (B) 38. (D) 39. (D)

40. (D) वर्ष 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, बागवानी उत्पाद 370·85 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि खाद्यान्नों के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, खरीफ की फसलों का कुल उत्पादन 174·14 मिलियन टन तथा रबी की फसलों का कुल उत्पादन 174·51 मिलियन टन (कुल 348·66 मिलियन टन) अनुमानित है.

●●●

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



कि नींद में अचानक बोलने या बड़बड़ाने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी में 'स्लीप टॉकर' व मेडिकल भाषा में 'सोम्निलोकी' कहा जाता हैं ?

☞

- 'स्लीप टॉकिंग' अथवा 'सोम्निलोकी' (Somniloquy) एक प्रकार का 'पैरा-सोमनिया' या नींद सम्बन्धी विकार है.
- सामान्यतः सोते समय मस्तिष्क का एक सुरक्षा तंत्र हमारी माँसपेशियों और बोलने की क्रिया को नियंत्रित रखता है, ताकि हम नींद में आने वाले सपनों पर शारीरिक प्रतिक्रिया न दें, लेकिन जब यह तंत्र पूरी तरह प्रभावी नहीं होता, तो व्यक्ति नींद में ही बोलने या चलने लगता है.
- इसके मुख्य कारणों में तनाव, चिंता, दिनभर का मानसिक दबाव, नींद की कमी, अनियमित जीवनशैली, बुखार, शराब का अधिक सेवन या स्लीप एपनिया जैसी स्थितियाँ शामिल हैं.
- चिकित्सकों के अनुसार, सोम्निलोकी अपने आप में कोई गम्भीर बीमारी नहीं है, लेकिन यदि इसके साथ 'स्लीपवॉकिंग' (नींद में चलना) या अन्य हरकतें जैसे— हाथ-पैर चलाना जुड़ जाएँ, तो यह किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत हो सकता है.
- नींद में चलना मस्तिष्क के जागने और सोने की अवस्थाओं के बीच पैदा हुए असंतुलन का परिणाम होता है. चूँकि इसका कोई विशिष्ट डॉक्टरी इलाज नहीं है, इसलिए जीवनशैली में बदलाव ही सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है. इसके लिए एक निश्चित 'स्लीप हा. इजीन' अपनाना, सोने-जागने का समय तय करना, तनाव प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना और दोपहर के बाद कैफीन या सोने से पहले मोबाइल के इस्तेमाल से बचना जरूरी है.

कि आकाश हमारी पृथ्वी से नीला दिखाई देता है. क्या यह रंग भविष्य में बदल सकता है ?

☞

- आकाश का नीला दिखाई देना भौतिक विज्ञान की एक अद्‌भुत प्रक्रिया है, जिसे 'रेली स्कैटरिंग' (यह नाम 1870 के दशक में इस सिद्धान्त को विकसित करने वाले ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रेली के नाम पर पर पड़ा है) कहा जाता है.
- सूर्य से आने वाला प्रकाश दिखने में सफेद होता है, लेकिन असल में यह सात रंगों—लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी का मिश्रण है.
- जब यह प्रकाश पृथ्वी के वायुमण्डल में प्रवेश करता है, तो वहाँ मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसों के अणु और सूक्ष्म धूल कण इसे सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं.
- नीले रंग की तरंगदैर्ध्य (Wave-length) लाल और नारंगी जैसे अन्य रंगों की तुलना में छोटी होती है, जिसके कारण यह वायुमण्डल के कणों से टकराकर सबसे अधिक और प्रभावी ढंग से बिखरती है. यही बिखरा हुआ नीला प्रकाश जब हमारी आँखों तक पहुँचता है, तो हमें पूरा आकाश नीला दिखाई देता है. हालाँकि, बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य नीले से भी छोटी होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में नीले रंग की मात्रा अधिक होती है और हमारी आँखें नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए हमें आकाश नीला ही नजर आता है.
- सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यही आकाश लाल या नारंगी दिखाई देने लगता है, क्योंकि उस समय सूर्य क्षितिज के नीचे होता है और प्रकाश को वायुमण्डल की एक लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है.
- इस लम्बी यात्रा के दौरान नीला प्रकाश पूरी तरह बिखर कर लुप्त हो जाता है, जबकि लम्बी तरंगदैर्ध्य वाला लाल और नारंगी प्रकाश बिना अधिक बिखरे हम तक पहुँचता है.
- पृथ्वी के इस नीले आकाश की विशेषता इसके वायुमण्डल की संरचना में निहित है.
- उल्लेखनीय है कि पृथ्वी के इतिहास में आकाश का रंग हमेशा से ऐसा नहीं था. लगभग 4 अरब वर्ष पहले, जब वायु-मण्डल में मीथेन की अधिकता थी, तब आकाश नारंगी धुँध जैसा दिखता होगा.
- करीब 2·4 अरब वर्ष पहले 'ग्रेट ऑक्सिडेशन इवेंट' के दौरान जब साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया, तब धीरे-धीरे मीथेन की परत साफ हुई और आधुनिक नीला आकाश अस्तित्व में आया.
- भविष्य में, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण वायुमण्डल में जल-वाष्प या एरोसोल के बढ़ने से आकाश का रंग धुँधला या सफेद हो सकता है.
- खगोलीय दृष्टिकोण से देखें तो करीब 1 अरब वर्ष बाद जब सूर्य की चमक बढ़ेगी, तो बढ़ते तापमान के कारण वायु-मण्डल के बदलने से यह नीला रंग फीका पड़कर सफेद या पीला भी हो सकता है.

कि जीपीएस स्पूफिंग विमानों के नेविगेशन सिस्टम पर एक तरह का साइबर हमला है ?

☞

- दिल्ली के इंदिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1-7 नवम्बर, 2025 के बीच जीपीएस स्पूफिंग की गम्भीर घटना घटी थी, जिसे विशेषज्ञों ने 'उच्च श्रेणी का मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर' करार दिया था. इस घटना में लगभग 60 समुद्री मील के दायरे में विमानों का नेविगेशन सिस्टम प्रभावित हुआ, जिससे 800 से अधिक उड़ानों पर असर पड़ा था.
- उल्लेखनीय है कि जीपीएस स्पूफिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें अपराधी रेडियो ट्रांसमीटर का उपयोग करके नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजते हैं. ये नकली सिग्नल असली संकेतों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, जिसके कारण विमान का जीपीएस रिसीवर इन्हें ही सच मानकर लॉक कर लेता है.
- इसके परिणामस्वरूप, पायलट को स्क्रीन पर गलत लोकेशन, ऊँचाई, मौसम और रनवे का डेटा दिखने लगता है.

अन्य ग्रहों पर आकाश का रंग क्या है ?

☞

- **बुध** – किसी तरह का वायुमण्डल नहीं अतः आकाश का रंग काला.
- **शुक्र** – सल्फ्यूरिक एसिड की अधिकता के कारण पीला-संतरी रंग.
- **मंगल** – वायुमण्डल में धूल कण आकाश को लाल या पीला रंग प्रदान करते हैं.
- **बृहस्पति** – यहाँ आकाश हल्के नीले रंग का दिखाई देता है.
- **शनि** – वायुमण्डल में अमोनिया आकाश को पीली रंगत देता है.
- **यूरेनस या वरुण** – वायुमण्डल में मौजूद मीथेन के कारण नीला-हरा रंग होता है.
- **नेपच्यून या अरुण** – यूरेनस जैसा ही वायुमण्डल का रंग.

●●●

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



प्रश्न–प्राचीन भारतीय साहित्य में प्रयुक्त 'पुर', 'दुर्ग', 'निगम' और 'नगर' शब्दों के अर्थगत विकास और उनकी विशेषताओं का सोदाहरण वर्णन कीजिए.

उत्तर–प्रारम्भिक वैदिक काल में 'पुर' शब्द का अर्थ आज के 'नगर' जैसा नहीं था. उस समय इसका उपयोग अस्थायी शरण स्थलों, पशुओं के बाड़ों या मिट्टी की कच्ची किलेबंदी वाली बस्तियों के लिए किया जाता था, समय के साथ, इसका अर्थ परिवर्तित हुआ और यह राजा एवं उनके परिजनों के निवास स्थान के रूप में पहचाना जाने लगा.

- इसी क्रम में 'दुर्ग' शब्द का प्रयोग राजा की उस घेरेबंद राजधानी के लिए होता था, जो सुरक्षा की दृष्टि से अभेद्य हो. यह घेरेबंदी न केवल बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करती थी, बल्कि शासकों को नगर के निवासियों और उनके कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने में भी सक्षम बनाती थी.
- पाली साहित्य में 'निगम' शब्द का विशेष महत्व है. यह मूलतः एक 'बाजार वाले कस्बे' (Market Town) को सम्बोधित करता था. विद्वानों का मानना है कि निगमों का विकास उन गाँवों से हुआ, जिन्होंने विशिष्ट उत्पादों जैसे–लकड़ी के सामान, बर्तन या नमक निर्माण में विशेषज्ञता हासिल कर ली थी. यहाँ सिक्के मिलने के प्रमाण इसकी व्यापारिक प्रधानता को सिद्ध करते हैं. कई बार यह दस्तकारों और कारीगरों की सघन बस्ती के लिए भी प्रयुक्त होता था.
- साहित्य में कस्बे के लिए सबसे सामान्य शब्द 'नगर' है, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम तैत्तिरीय आरण्यक (7वीं-6वीं शताब्दी ई.पू.) में मिलता है. जब किसी नगर में 'पुर' की राजनीतिक शक्ति और 'निगम' की व्यापारिक कुशलता का समन्वय हो जाता था, तो उसे 'महानगर' कहा जाता था. बौद्ध ग्रंथों में छह प्रमुख महानगरों (1. राजगृह 2. चम्पा 3. काशी 4. श्रावस्ती 5. साकेत 6. कौशाम्बी) का उल्लेख मिलता है. ये महानगर मुख्य रूप से मध्य गंगा घाटी में स्थित थे और धर्म, राजनीति तथा व्यापार के प्रमुख केन्द्र थे. इसके अतिरिक्त 'पाटन' और 'स्थानीय' जैसे शब्दों का प्रयोग भी विभिन्न श्रेणियों के शहरों के लिए किया जाता था.

प्रश्न–मौर्य साम्राज्य की प्रांतीय शासन व्यवस्था के प्रमुख अंगों और उनमें केन्द्र एवं स्थानीय नियंत्रण के संतुलन की व्याख्या कीजिए.

उत्तर–मौर्य साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बाँटा गया था, जिसका संचालन मुख्य रूप से 'कुमार' (राजकुमार) द्वारा किया जाता था, जो वायसराय के रूप में कार्य करते थे. उदाहरणस्वरूप, सम्राट बनने से पूर्व अशोक ने तक्षशिला और उज्जैयनी के कुमार के रूप में अनुभव प्राप्त किया था. अशोक के अभिलेखों के अनुसार, मौर्य साम्राज्य की चार प्रमुख प्रांतीय राजधानियाँ थीं–पूर्व में तोशाली; पश्चिम में उज्जैन; दक्षिण में सुवर्णगिरि और उत्तर में तक्षशिला.

- कुमार की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद् और महामात्र (महामात्य) होते थे. रोचक तथ्य यह है कि मंत्रिपरिषद् का राजा से सीधा सम्पर्क होता था, जिससे वे कुमार की गतिविधियों पर अंकुश लगा सकते थे. वरिष्ठ अधिकारियों को 'महामात्र' कहा जाता था, जो न्याय, सीमा सुरक्षा और धम्म (धम्म महामात्र) जैसे विशिष्ट कार्यों का सम्पादन करते थे.
- प्रशासन में स्थानीय निवासियों को भी स्थान दिया जाता था. जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, चन्द्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त (एक वैश्य) और अशोक के समय तुशास्य जूनागढ़ के गवर्नर थे. हालाँकि, 'अमात्य' जैसे उच्च अधिकारियों के मनमाने व्यवहार के कारण कभी-कभी जन-विद्रोह भी होते थे, जैसा बिंदुसार और अशोक के काल में तक्षशिला में देखा गया.

प्रश्न–कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परिचय देते हुए इसके प्राकृतिक स्त्रोतों का उल्लेख कीजिए.

उत्तर–कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों से प्राप्त किए जाते हैं. किसी पौधे के ठोस पदार्थ का 70% से अधिक भाग इन्हीं से बना होता है. हमारे भोजन में प्रयुक्त भिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं.

कार्बोहाइड्रेटों के प्राकृतिक स्रोत

कार्बोहाइड्रेट का नाम	स्रोत
ग्लूकोस	अंगूर
फ्रक्टोस	शहद
सुक्रोस	गन्ना
लैक्टोस	दूध
स्टार्च	अनाज, जैसे–मक्का
सेलूलोज	पादप कोशिका भित्ति

प्रश्न–सूफी संतों के आध्यात्मिक दर्शन, उनके संगठनात्मक ढाँचे (सिलसिला) और उलेमा वर्ग से उनके बुनियादी मतभेदों को स्पष्ट कीजिए.

उत्तर–सूफीवाद मध्यकालीन इस्लाम के भीतर एक ऐसी रहस्यवादी और उदार लहर थी, जिसने औपचारिक धार्मिक कट्टरता के स्थान पर 'ईश्वर के प्रति प्रेम' को सर्वोपरि माना. सूफी संत उन उलेमाओं के विरोधी थे, जो धर्म की केवल कठोर और शाब्दिक व्याख्या करते थे और सत्ता के लालच में 'धर्म भ्रष्ट शासकों' की सेवा में लगे थे. सूफियों का मुख्य उद्देश्य राजनैतिक पतन से दूर रहकर मानवीय सेवा और आध्यात्मिक शुद्धि के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना था.

- इनका संगठनात्मक ढाँचा अत्यंत सुव्यवस्थित था. सूफी विभिन्न 'सिलसिलों' या श्रेणियों में संगठित थे. प्रत्येक सिलसिले का केन्द्र 'खानकाह' (मठ) होता था, जहाँ 'पीर' (गुरु या शेख) अपने शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे. पीर द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में 'वली अहद' को नामित करने की परम्परा थी, जिससे सिलसिले की निरन्तरता बनी रहती थी.
- उपासना की दृष्टि से इन्होंने उलेमाओं के बाहरी आडम्बरों को नकार कर 'ध्यान' और 'समां' (आध्यात्मिक संगीत) को अपनाया. समां का उद्देश्य संगीत के माध्यम से रहस्यमय भावातिरेक पैदा करना था, ताकि भक्त का ईश्वर से सीधा जुड़ाव हो सके. यद्यपि वे कुरान के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थे, लेकिन उनका मार्ग समावेशी और प्रेमपूर्ण था, जो बसरा जैसे केन्द्रों से फैलकर पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ.

●●●

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

प्रथम पुरस्कृत निबन्ध

"अमेरिकी कूटनीति जनित नव-उपनिवेशवाद से आसन्न संकट"

—बहादुर सिंह रावत 'चंचल'

क्या कारण था कि जिस अमेरिका ने उपनिवेशवाद से लड़कर अपनी स्वतंत्रता एवं जीवन मूल्यों की स्थापना की, वही अमेरिका शीतयुद्ध कालीन वैचारिक रुग्णता से ग्रसित होकर उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्षों के खिलाफ खड़ा हो गया.

अमेरिका 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार था. अमेरिकी क्रांति का प्रादुर्भाव ही इंग्लैण्ड और उसके उपनिवेशों के मध्य आर्थिक हितों के संघर्ष के कारण हुआ था. यद्यपि इस संघर्ष में राजनीतिक और सामाजिक कारक भी शामिल थे, तथापि आर्थिक कारकों ने ही इस संघर्ष को बल दिया.

ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों का आर्थिक शोषण विभिन्न कानूनों, यथा-नौ संचालन कानून, व्यापारिक अधिनियम, औद्योगिक अधिनियम आदि के द्वारा किया जा रहा था. इसी आर्थिक शोषण के विरोध में अमेरिकी जनता ने उपनिवेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और 4 जुलाई, 1776 ई. को अमेरिकी नेताओं ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया.

यह विडम्बना ही कही जाएगी कि जिस देश ने औपनिवेशिक देश के विरुद्ध लड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी, वह अपनी स्वतंत्रता के लगभग 200 वर्षों बाद एक ऐसी नीति अपना लेता है, जो शीतयुद्ध काल की पूँजीवादी और समाजवादी वैचारिक रुग्णता से ग्रसित थी और इसी रुग्ण नीति को साकार करने के लिए अमेरिका ने तृतीय विश्व के देशों, जो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष कर रहे थे, को विभिन्न प्रकार के आर्थिक और राजनीतिक दबाव के द्वारा सीमित करने का प्रयास किया.

इस क्रम में 'मार्शल प्लान' जिसके अन्तर्गत अमेरिका ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को वृहद स्तर पर आर्थिक सहायता प्रदान की. 'नाटो' जो अमेरिकी नेतृत्व में पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन था, के द्वारा अमेरिका ने तृतीय विश्व के देशों में पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत नव-साम्राज्यवाद को फैलाने का प्रयास किया.

इसके अतिरिक्त गाम्बिया, बुरुण्डी, रवांडा आदि अफ्रीकी राष्ट्रों ने तानाशाही को समर्थन दिया, वहीं वियतनाम और कोरियायी प्रायद्वीप में भी पूँजीवाद और साम्यवाद के द्वन्द्व ने अस्थायित्व को बढ़ाया. इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस देश ने एक ऐसी शोषणकारी विचारधारा (उपनिवेशवाद) के विरुद्ध लड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की, वही देश कालान्तर में वैचारिकता के आधार पर परोक्ष रूप से उपनिवेशवाद का समर्थक हो गया.

अमेरिकी कूटनीति से प्रेरित नव-उपनिवेशवाद (Neocolonialism) एक ऐसा सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष रूप है, जिसमें प्रत्यक्ष सैन्य कब्जे के बजाय आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दबाव के माध्यम से विकासशील देशों पर नियंत्रण कायम किया जाता है. यह **विकास, सहायता** और **स्वतंत्र व्यापार** के आवरण में विकासशील राष्ट्रों की सम्प्रभुता के लिए एक आसन्न संकट पैदा करता है.

अमेरिकी उपनिवेशवाद के प्रमुख आयाम और संकट—

(i) आर्थिक साम्राज्यवाद और ऋण का जाल—अमेरिकी और उससे जुड़ी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ (यथा—आईएमएफ, विश्व बैंक) विकासशील देशों को भारी ऋण देते हैं. यह ऋण अक्सर ऐसी शर्तों के साथ आता है जो प्राप्तकर्ता देश की घरेलू अर्थव्यवस्था को अमेरिकी MNGs (बहुराष्ट्रीय कम्पनियों) के लिए खोल देते हैं, जिससे स्थानीय उद्योग नष्ट हो जाते हैं.

(ii) Predotory (शिकारी) कूटनीति—आलोचकों के अनुसार 'अमेरिका फर्स्ट' (America First) की नीति के तहत् अमेरिकी कूटनीति अपने सहयोगियों को सुरक्षा की गारंटी के बदले भारी वित्तीय भुगतान करने के लिए मजबूर करती है, जो उनके रणनीतिक संसाधनों का दोहन करती है.

(iii) सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभुत्व—पश्चिमी संस्कृति, विचारधारा और उपभोगवादी जीवनशैली को थोपकर यह विकासशील देशों की स्थानीय संस्कृति और पहचान को कमजोर कर रहा है, जिससे उन्हें सांस्कृतिक रूप से निर्भर बना दिया जाता है.

(iv) लोकतंत्र की आड़ में हस्तक्षेप—कभी-कभी 'लोकतंत्र' या मानवाधिकारों के प्रसार के नाम पर विकासशील देशों की सम्प्रभुता का हनन किया जाता है और उन सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है, जो अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं काम करती हैं.

आसन्न संकट—

(i) सम्प्रभुता का नुकसान—विकासशील राष्ट्र सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से वे अपनी आर्थिक और विदेश नीति के लिए अमेरिकी निर्णयों पर निर्भर हो जाते हैं.

(ii) स्थायी अविकास—इस नीति से देश के भीतर आर्थिक असमानता, सामाजिक अशांति और संघर्ष बढ़ते हैं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय निगम केवल मुनाफा कमाने पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, न कि स्थानीय विकास पर.

(iii) लोकतंत्र का क्षरण—विकासशील देशों में अक्सर ऐसे शासकों को समर्थन दिया जाता है, जो स्थानीय जनता की बजाय अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देते हैं.

(iv) संसाधनों का दोहन—कांगो जैसे देशों में खनिजों (कोबाल्ट), लिथियम के लिए जारी होड़ इस बात का प्रमाण है कि कैसे विकसित राष्ट्र विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं.

यह नव-औपनिवेशिक व्यवस्था न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भी विकासशील देशों के लिए एक गम्भीर और तत्काल संकट हैं.

'डावोस' की बर्फीली पहाड़ियों में हर वर्ष दुनिया के ताकतवर लोग 'वैश्विक सहयोग' की भाषा बोलते हैं, लेकिन इस बार उस भाषा के पीछे छिपी लालच शक्ति साफ दिखाई दी. मंच पर शांति, नियम और साझेदारी की बातें थीं, जबकि समानान्तर रूप से दुनिया को यह सन्देश भी दिया जा रहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति फिर से ताकत के व्याकरण में लौट रही हैं. यही वह क्षण था जब नव-उपनिवेशवाद का मुखौटा उतरा और यह स्वीकारोक्ति सामने आई कि दुनिया नियमों से नहीं, बल्कि 'डर' और 'दबाव' से चलाई जा रही है.

इसी मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का ग्रीनलैण्ड को लेकर दिया गया बयान इस बदलती विश्व मानसिकता का सबसे सटीक प्रतीक बन गया. औपचारिक रूप से कहा कि वे कोई सैन्य बल इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही यूरोप पर कोई टैरिफ लगाएंगे, लेकिन उसी साँस में उन्होंने अमेरिकी बम बर्षकों, मिसाइल क्षमताओं और आर्कटिक में अमेरिकी सैन्य वर्चस्व की चर्चा भी कर दी. यह कोई कूटनीतिक असावधानी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित प्रदर्शन था. एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन, जो शब्दों में नहीं, संकेतों में धमकी देता है. डेनमार्क और पूरे यूरोप के लिए सन्देश स्पष्ट था कि **"सहमति न हो भी, तो अमेरिका के पास विकल्प मौजूद है".**

यह वही मानसिकता है जिसने कभी औपनिवेशिक युग को जन्म दिया था. फर्क

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

सिर्फ इतना है कि आज उपनिवेश झंडों और सेनाओं से नहीं, बल्कि रणनीतिक भू-भाग संसाधनों, टेक्नोलॉजी और सैन्य संकेतों के जरिए तय किए जा रहे हैं. ग्रीनलैण्ड पर ट्रम्प की जिद, दरअसल बर्फ की जमीन से अधिक उस सोच का विस्तार है, जिसमें भूगोल फिर से भाग्य लिखने लगा है और ताकत नैतिकता पर भारी पड़ रही है. ट्रम्प का बयान केवल ग्रीनलैण्ड के लिए ही नहीं था—यह पूरे यूरोप को उसकी रणनीतिक निर्भरता को आईना दिखाने जैसा था.

विडम्बना देखिए, वर्ष 1945 के बाद 'हिरोशिमा' और नागासाकी' राख से मानवता ने सबक लेने का दावा किया था, तब वाशिंगटन और लंदन ने एक ऐसी दुनिया का सपना गढ़ा था जहाँ राष्ट्रों का आचरण 'पाशविक शक्ति' से नहीं, बल्कि संस्थाओं और कानूनों से संचालित होगा. संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और बाद में विश्व व्यापार संगठन—ये सभी उसी उदारवादी अन्तर्राष्ट्रीयता के स्तम्भ थे. वादा किया गया था कि अब 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' नहीं चलेगी बल्कि नियम आधारित विश्व व्यवस्था होगी. पर 2026 में यह भ्रम पूरी तरह टूटता दिखा. अब 2026 के मध्य में ही खड़ी दुनिया एक नितांत भिन्न, अधिक क्रूर और अस्थिर यथार्थ में प्रवेश कर चुकी है.

ट्रम्प का दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनना और उनका आक्रामक कार्यकाल इस 'उपनिवेशवाद' प्रक्रिया का कोई आकस्मिक परिणाम नहीं है. यह उस गहरे संरचनात्मक क्षरण का प्रतीक है जिसे विद्वान दशकों से **'पश्चिमी प्रभुत्व का अंत' और 'इतिहास की वापसी'** कह रहे हैं. ट्रम्प की 'अमेरिका प्रथम' नीति ने कूटनीति के उन रेशमी धागों को एक ही झटके में तोड़ दिया है, जिन्होंने दशकों से दुनिया को बाँध रखा था. इनके स्थान पर 'लेन-देन आधारित अराजकता' का जन्म हुआ है. यह अराजकता केवल राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, यह एक नए प्रकार के 'नव-उपनिवेशवाद' की प्रस्तावना है, जहाँ 19वीं सदी का उपनिवेशवाद भौगोलिक सीमाओं को रौंदता था, तोपों और जहाजों से संचालित होता था, वहीं 21वीं सदी का यह नया 'उपनिवेशवाद'—'डेटा आपूर्ति' श्रृंखला, तकनीकी एकाधिकार और बर्फीले महाद्वीपों के माध्यम से राष्ट्रों की सम्प्रभुता का गला घोंट रहा है.

1990 के दशक में वैश्वीकरण को एक 'परोपकारी शक्ति' के रूप में पेश किया गया था. यह कहा गया कि "उठती हुई लहरें सभी नावों को ऊपर उठाती हैं," लेकिन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने यह सिद्ध कर दिया कि आर्थिक परस्पर निर्भरता एक दोधारी तलवार है. जब पश्चिमी बैंक डूबे तो उसकी सजा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने भुगती. जब व्यापारिक नियमों का उपयोग विकासशील देशों की नीतिगत स्वायत्तता को छीनने के लिए किया जाने लगा तो नियम आधारित व्यवस्था के प्रति मोह भंग होना स्वाभाविक था. आज व्यापारिक संधियाँ विकास का साधन कम और नियंत्रण का औजार अधिक बन गई हैं. आज जो अविश्वास दिख रहा है, वह इसी ऐतिहासिक धोखे का ही तो परिणाम हैं.

यदि नियम आधारित विश्व व्यवस्था एक जर्जर इमारत थी, जिसकी दीवारों में दरार पड़ चुकी थी, तो डोनाल्ड ट्रम्प वह बुल्डोजर है जिसने इस नींव को हिलाकर रख दिया है. ट्रम्प की वैश्विक दृष्टि 'यथार्थवाद' के उस क्रूर संस्करण पर आधारित है, जहाँ कोई स्थायी मित्र नहीं होता, केवल स्थायी उसके हित होते हैं. उनकी नीतियों ने दुनिया को यह कड़वा सच याद दिला दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 'प्रेमपत्र' लिखने की कला नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा है.

पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलना, ईरान परमाणु सौदे को एक तरफ तोड़ना और विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय को पंगु बनाना ये ट्रम्प के वे कदम हैं जिन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया कि अमेरिका अब उन नियमों को नहीं मानेगा जिन्हें उसने खुद बनाया था. यह 'अराजकता विश्व व्यवस्था' की शुरुआत है. यह एक ऐसी दुनिया है, जहाँ 'बहुपक्षवाद' मर चुका है और द्विपक्षीय दादागिरी का बोलबाला है. जब अधिनायक ही नियमों को तोड़ने लगें तो दुनिया 'मत्स्यन्याय' यानी जंगल के कानून की ओर लौटने लगती है, जहाँ केवल वहीं सुरक्षित है जिसके पास नुकीले दाँत हैं और मजबूत जबड़े हैं. ट्रम्प का सन्देश स्पष्ट है— **"हम नियम नहीं बनाएंगे—हम परिणाम तय करेंगे."**

यदि नव-उपनिवेशवाद का एक चेहरा वाशिंगटन और ब्रुशेल्स के बीच की तनातनी है, तो उसका दूसरा और अधिक भयावह चेहरा बर्फीले उत्तर में विशेषकर ग्रीनलैण्ड और आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई दे रहा है. इतिहास गवाह है कि साम्राज्यों की भूख कभी मिटती नहीं, वह केवल अपना भोजन बदलती है. वर्ष 2019 में जब डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैण्ड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था, तो वैश्विक मीडिया ने इसे एक रीयल स्टेट्स मुगल का मजाक समझकर उड़ा दिया था, लेकिन सामरिक दृष्टि रखने वालों के लिए यह एक गम्भीर खतरे की घंटी थी. यह प्रस्ताव 21वीं सदी में 19वीं सदी की उस औपनिवेशिक मानसिकता की वापसी थी, जो भूगोल को राष्ट्र, संस्कृति या लोगों का घर नहीं, बल्कि केवल एक परिसम्पत्ति मानती है, जिसका सौदा किया जा सकता है.

आज की शब्दावली में जिसे 'तकनीकी सामंतवाद' कहा जा रहा है, वह वास्तव में 'नव-उपनिवेशवाद' का डिजिटल चेहरा है. यह उपनिवेशवाद का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि यह जमीन पर कब्जा नहीं करता, बल्कि दिमागों पर कब्जा करता है. औपनिवेशिक काल में अफ्रीका और एशिया से कच्चा माल (कपास, मसाले, खनिज) लूटा जाता था और उन्हें महँगे उत्पादों में बेचा जाता था. आज 'डेटा' वह नया सोना है जिसे लूटा जा रहा है. विकासशील देशों के नागरिकों का 'डेटा', उनकी पसंद, उनकी राजनीतिक विचारधारा, उनका वित्तीय व्यवहार, उनकी बायो-मैट्रिक्स, उनके डर और उनकी इच्छाएँ—युक्त रूप से इन वैश्विक कम्पनियों द्वारा संकलित किया जाता है.

नव-उपनिवेशवाद का एक और घातक पक्ष 'तकनीकी रंगभेद' है. महाशक्तियाँ विशेष रूप से अमेरिका और चीन अब ऐसी उन्नत तकनीकों पर एकाधिकार कर रही हैं जिन्हें वे शेष विश्व के साथ साझा नहीं करना चाहतीं. वे एक ऊँची दीवार खड़ी कर रहे हैं जिसके भीतर भविष्य की तकनीक है और बाहर केवल उपभोक्ता.

नव-उपनिवेशवाद की सबसे विचलित करने वाली ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व विशेषता यह है कि अब राज्य की शक्ति का एकाधिकार निजी हाथों में जा रहा है. अतीत में राजा युद्ध का निर्णय लेते थे, अब एक तकनीकी सीईओ यह तय कर सकता है कि 'ड्रोन' उड़ेंगे या नहीं. यह निजी उपनिवेशवाद का वह युग है, जहाँ देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन और संचार के लिए किसी निजी कम्पनी के नियमों और शर्तों के मोहताज हैं. यदि इन निजी कुबेरों का हित किसी शत्रु देश के साथ मेल खाता है, तो वे एक सम्प्रभु राष्ट्र की रक्षात्मक क्षमता को पलभर में पंगु बना सकते हैं.

ट्रम्प का अमेरिका अब संयम नहीं, बल्कि दबदबे को अपनी विदेश नीति का आधार बना चुका है.

अन्त में, यह कूटनीति वैश्विक दक्षिण में सम्प्रभुता के क्षरण, विकास के अवसरों की कमी और स्थानीय उद्योगों के पतन का कारण बन रही है. 2026 में यह नव-औपनिवेशिक प्रणाली अपने विरोधाभाषों के कारण एक गम्भीर संरचनात्मक संकट से गुजर रही है, जिसमें डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती मिल रही है.

अमेरिकी कूटनीति का यह 'अदृश्य शासन' सीधे तौर पर सैन्य आक्रमण न करते हुए भी राष्ट्रों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अपनी दासता में जकड़ने का एक नया और अधिक खतरनाक तरीका है. ●●●

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दी मासिक

निबन्ध प्रतियोगिता क्रमांक-560 का परिणाम

विषय : "अमेरिकी कूटनीति जनित नव-उपनिवेशवाद से आसन्न संकट."

प्रथम– बहादुर सिंह रावत 'चंचल'
C/o धर्मकाँटा अनाज मण्डी
सुन्हेरा रोड सबलगढ़
जिला–मुरैना (मध्य प्रदेश)
पिन–476 229

द्वितीय– संजय प्रसाद (अध्यापक)
ग्राम–रिसौद, पो.–चाकन्द
जिला–गयाजी (बिहार)
पिन–804 404

तृतीय– उमेश चन्द्र जोशी
गोमती नगर
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
पिन–226 010

अन्य प्रशंसनीय प्रयास

1. प्रियंका कुमारी
ग्राम + पोस्ट–बकसण्डा
जिला–नवादा (बिहार)
पिन–805 126
2. आशीष अम्बर
ग्राम + पो.–रमनीरामपुर छतवन
जिला–दरभंगा (बिहार)
पिन–847 337
3. प्रभाष पाठक
सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी
जिला सांख्यिकी कार्यालय, अररिया
(बिहार)
पिन–854 311



प्रथम



द्वितीय



तृतीय

➥ उपर्युक्त प्रशंसित निबन्ध प्रतियोगियों में से प्रत्येक को उपकार प्रकाशन की ₹ 300 मूल्य की वांछित पुस्तक/पुस्तकें भेंटस्वरूप प्रदान की जाएंगी. **कृपया अपनी पसन्द की पुस्तक अलग से प्रकाशक के नाम पत्र द्वारा सूचित करें.** यदि ₹ 300 से अधिक मूल्य की पुस्तक की माँग की गई है, तो उसके मूल्य में से ₹ 300 पुरस्कारस्वरूप कम कर दिए जाएंगे.

वाद-विवाद प्रतियोगिता

विषय–"मध्य-पूर्व का संघर्ष तृतीय विश्वयुद्ध की आहट है."

अन्तिम तिथि–15 मई, 2026
शब्द संख्या–अधिकतम 750 शब्द (पक्ष/विपक्ष)
पुरस्कार योजना–पक्ष/विपक्ष के प्रथम दो लेख.
विशेष–पक्ष/विपक्ष के प्रथम लेख पत्रिका में प्रकाशित होंगे.
कृपया अपनी प्रविष्टि पर अपना पूरा पता फोन नं. सहित अवश्य लिखें.
प्रथम पुरस्कृत पक्ष/विपक्ष अभ्यर्थी को पुरस्कारस्वरूप ₹ 500/- प्रदान किए जाएंगे.
कॉपीराइट अधिकार प्रकाशक का होगा. अन्य लेख वापस नहीं किए जाएंगे.
(कृपया लिफाफे पर निम्नलिखित कूपन को अवश्य चिपकाएं)

वाद-विवाद प्रतियोगिता क्रमांक–225 (पक्ष/विपक्ष/दोनों पक्ष)

वाद-विवाद प्रतियोगिता क्रमांक–224 का परिणाम

विषय–"देश की एकता और अखण्डता के सन्दर्भ में हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए."

विजेता

पक्ष में : डॉ. नियाज अहमद अंसारी
सहायक प्राध्यापक : राजनीति विज्ञान
एवं व्यक्तित्व विकास, शासकीय आदर्श महाविद्यालय
उमरिया (मध्य प्रदेश), पिन–484 661

विपक्ष में : प्रभाष पाठक, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी,
जिला सांख्यिकी कार्यालय,
अररिया (बिहार)
पिन–854 311

☞ उपर्युक्त प्रशंसित वाद-विवाद प्रतियोगितयों में से प्रत्येक को उपकार प्रकाशन की ₹ 500 मूल्य तक की वांछित पुस्तक/पुस्तकें भेंट स्वरूप प्रदान की जाएंगी. **कृपया अपनी पसन्द की पुस्तक अलग से प्रकाशक के नाम पत्र द्वारा सूचित करें.** यदि ₹ 500 से अधिक मूल्य की पुस्तक की माँग की गई, तो उसके मूल्य में से ₹ 500 पुरस्कारस्वरूप कम कर दिए जाएंगे.

निबन्ध प्रतियोगिता

विषय–''क्षमा सबसे मधुर प्रतिरोध''.

अन्तिम तिथि–28 मई, 2026.

शब्द संख्या–लगभग 2000 शब्द.

1. अपना निबन्ध स्वहस्तलिखित, ई-मेल, whatsapp अथवा अन्य किसी भी माध्यम से प्रतियोगिता दर्पण को भेजें. e-mail : care@pdgroup.in, whatsapp : 9634167776
2. निबन्ध के साथ प्रतियोगी अपना पासपोर्ट आकार का फोटो अवश्य भेजें. प्रथम तीन स्थान पाने वाले प्रतिभागियों के फोटो को पत्रिका में सम्मान दिया जाता है. प्रथम तीन निबन्धों पर क्रमशः ₹ 2000, ₹ 1500 व ₹ 1000 चेक के माध्यम से व प्रमाण-पत्र पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे. अन्य 5 अनुशंसित निबन्धों को आकर्षक प्रमाण-पत्र व उपकार प्रकाशन की ₹ 300 मूल्य तक की वांछित पुस्तक पुरस्कारस्वरूप दी जाएगी.
3. प्रत्येक प्रविष्टि पर अपना नाम English में लिखें, जिस नाम से आपका बैंक खाता हो. बैंक का नाम, खाता नम्बर व बैंक का IFSC कोड भी अवश्य लिखें.

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें



विषय : "देश की एकता और अखण्डता के सन्दर्भ में हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए."

–डॉ. नियाज अहमद अंसारी

पक्ष में :

आज हिन्दी को भारत में सैद्धान्तिक रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुए लगभग 7 दशक हो चुके हैं, लेकिन इसे अब तक अपेक्षित महत्व व सुरक्षित भविष्य नहीं मिल पाया है. 1950 में स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया गया तो देश में हिन्दी भाषा-भाषियों की विपुल संख्या के दृष्टिगत देश की एकता व अखण्डता को बनाए रखने हेतु देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया. कलान्तर में, दक्षिण भारत व अन्य क्षेत्रों में भाषा विवाद के कारण हिन्दी राष्ट्रभाषा का विरोध करने वालों को कूटनीतिक सफलताएँ भी मिली है. दूसरा संविधान के लागू होने से 15 वर्ष तक के लिए अंग्रेजी को सरकारी कामकाज हेतु राजभाषा बना लिया गया. इसका प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव राष्ट्रभाषा बनने की प्रबल उत्तराधिकारी हिन्दी पर पड़ता रहा है.

अब यह उपयुक्त है कि भारत की स्वतंत्रता की 2047 में 100वीं वर्षगाँठ मनाने से पहले हम भारतवासियों ने देश की एकता व अखण्डता को बनाए एवं विकसित भारत-2047 अभियान को सफल बनाने हेतु हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में सैद्धान्तिक कलेवर से बाहर निकालकर व्यावहारिक धरातल पर आसीन करना होगा, अन्यथा हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं कहलाएंगे, जैसा कि **राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी कहते हैं, "कोई देश सच्चे अर्थ में तब तक स्वतंत्र नहीं है, जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता."** इसी प्रकार राष्ट्रभाषा हिन्दी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए हमारे **राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त** को भी अपनी काव्यकृति **'भारत-भारती'** में लिखना पड़ा है–

"है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं,

हम निज विचार जता सकें जिससे परस्पर सब कहीं–

इस योग्य हिन्दी है तदपि अब तक न निज पद पा सकी,

राष्ट्रभाषा बिना भावैकता अब तक न हममें आ सकी ॥"

अतः निम्नवत् तर्कों के आधार पर सिद्ध हो जाता है कि देश की एकता एवं अखण्डता को सुरक्षित बनाए एवं विकसित भारत-2047 अभियान के दृष्टिगत भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को सभी भारतीय दिल से स्वीकारें. इसके विकास में वे यथासम्भव अपना-अपना योगदान भी सुनिश्चित करें–

1. विश्व में शायद ही ऐसा कोई राष्ट्र हो, जहाँ उसकी अपनी राष्ट्रभाषा न हो और उसे पर्याप्त सम्मान न मिला हो, परन्तु दुर्भाग्यवश भारत में ऐसी ही विकट स्थिति बनी हुई है. गुलामी की जंजीरे कटने के बाद भी अधिकतर भारतीय अंग्रेजों की अंग्रेजी को बन्दर के मृत बच्चे की तरह गले लगाए हुए हैं. **मुंशी प्रेमचन्द ने सही कहा है, "जिसकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं, वहाँ कोई राष्ट्र भी नहीं."**

2. भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगभग एक सदी तक हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में सतत् विकास हुआ, अंग्रेजों एवं अंग्रेज समर्थक भारतीयों द्वारा हिन्दी की उपेक्षा की गई तो **भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, गोपालकृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, रबीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गाँधी, सुभाषचन्द्र बोस, सी. राजगोपालाचारी, मदनमोहन मालवीय** आदि सैंकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हिन्दी की अस्मिता हेतु हर स्तर पर संघर्ष किया. अब हम भारतीयों को इस दिशा में अपने कर्तव्य निर्वहन की नितांत आवश्यकता है.

3. भारतेन्दु युग (1850-1900) के साहित्यकारों ने तो जहाँ हिन्दी को जन-जन की भाषा बनाने हेतु साहित्य-सृजन किया. वहाँ द्विवेदी युग (1900-20) में हिन्दी का परिमार्जन हुआ. स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा महात्मा गाँधी ने तो राष्ट्र को एकजुट रखने वाली हिन्दी की अनिवार्यता प्रतिपादित की. उनके लिए तो हिन्दी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न बन गया था. स्वतंत्रता संग्राम के अन्तिम चरण में तो गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्र के दर्जनों नेताओं व साहित्यकारों ने राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत रचनायों से भारतीय के हृदय में राष्ट्रवाद का अलख जगाया. इन्होंने राष्ट्रीय एकता कायम रखने हेतु हिन्दी, उर्दू, अरबी, फारसी, मराठी, पंजाबी आदि के शब्दों को मिलाकर एक **'हिन्दुस्तानी'** भाषा के विकास की बात कही थी, क्योंकि कुछ स्वार्थी तत्वों ने हिन्दी पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाना शुरू कर दिया था.

4. संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रपति ने तीन आदेश क्रमशः 1952, 1955 तथा 1960 में जारी किए. 1960 में महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के लिए ज्ञान, विज्ञान के शब्द, सूचियाँ तैयार करने का काम **'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय'** को सौंपा गया. बाद में 1961 में **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग** की स्थापना की गई. 1963 में ससंद ने राष्ट्रभाषा एक्ट और 1975 में राजभाषा विभाग बनाया गया. हालाँकि, इन सुधारों के बावजूद अभी इसके भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सकने हेतु पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं जिन पर कार्य करना कठिन अवश्य है, किन्तु असम्भव नहीं.

5. शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करके हिन्दी को सच्चे अर्थों में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है. प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा, माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रभाषा एवं उच्च शिक्षा राष्ट्रभाषा हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में ही देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, तभी भारत अपनी संस्कृति, भाषा, साहित्य आदि सुरक्षित रख सकेगा.

जैसा कि **यूनेस्को** की एक रिपोर्ट में लिखा गया है, **"विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति न केवल अपना व्यक्तित्व खो देता है, बल्कि वह दूसरों का नकलची और गुलाम मानसिकता का व्यक्ति बन जाता है."**

निष्कर्ष–आज के विश्व में जिस प्रकार अंग्रेजी की जरूरत एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में अनिवार्य है, उसी प्रकार भारत में राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी की आवश्यकता बनी हुई है. अतः इसे सरकारी तंत्र व समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा हृदय से राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए. इसके लिए बुद्धजीवियों की तरफ से आधुनिक युग के अनुरूप ज्ञान-विज्ञान, व्यापार-वाणिज्य आदि के अनुकूल बनाया जा सकता है. कम्प्यूटर, इंटरनेट, ई-मेल, मोबाइल आदि संचार साधनों पर हिन्दी के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

भारतीय संघ की राजभाषा व राष्ट्रभाषा हिन्दी ही हो सकती है, कोई विदेशी या अन्य भाषा नहीं. वास्तव में हिन्दी के अत्यधिक प्रयोग से ही हमारा वास्तविक विकास सम्भव है, जिस प्रकार **चीन** ने चीनी और **रूस** ने रूसी को राष्ट्रभाषा बनाकर विकसित देश का दर्जा प्राप्त किया हुआ है. राष्ट्रीयता की सद्भावना से ओत-प्रोत और सच्ची निष्ठा पर आधारित हो. अब हिन्दी के प्रयोग में क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को अधिक संख्या में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे गैर-हिन्दी भाषाओं को भी राष्ट्रभाषा पर गर्व हो.

उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण भारत के लोग भले ही हिन्दी बोल न पाते हों, लेकिन

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

वे हिन्दी को समझ लेते हैं. हमें राष्ट्रभाषा हिन्दी के सरलीकरण हेतु मोबाइल फोन, हिन्दी वर्णमाला के की-बोर्ड, पाठ्य पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि का विकास एवं भरपूर प्रचार-प्रसार करना होगा. जैसाकि **भारतेन्दु हरिश्चन्द्र** ने हम सभी भारतवासियों से इस कर्तव्य की अपेक्षा की है—

चाहो जो साँचहु निज कल्याण,
तौ मिलि सब भारत संतान।
जपौ निरन्तर एक जबान,
हिन्दी, हिन्दू हिन्दुस्तान॥

विपक्ष में : —प्रभाष पाठक

भारत विविधताओं का देश है. यहाँ सैकड़ों भाषाएँ और हजारों बोलियाँ बोली जाती हैं, जो इस देश की आत्मा का हिस्सा हैं. भारत की भाषायी विविधता पर किए गए ऐतिहासिक, संवैधानिक और समाज भाषावैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि 'राष्ट्रभाषा' का प्रश्न केवल भाषा का नहीं, बल्कि पहचान, संघीय संरचना, सांस्कृतिक समानता और लोकतांत्रिक सन्तुलन का प्रश्न है. ऐसे में जब यह तर्क दिया जाता है कि देश की एकता और अखण्डता के लिए हिन्दी को ही एकमात्र राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो यह विचार तर्कसंगत और न्यायसंगत दोनों दृष्टियों से गम्भीर प्रश्न खड़े करता है.

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भारतीय संविधान ने हिन्दी को 'राष्ट्रभाषा' का दर्जा कभी नहीं दिया. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिन्दी संघ की 'राजभाषा' है, न कि 'राष्ट्रभाषा'. इसके साथ ही संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है. इसका अर्थ यह है कि संविधान निर्माताओं ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है और किसी एक भाषा को सर्वोपरि बनाना न्यायसंगत नहीं होगा. जो लोग हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की माँग करते हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से यह संवैधानिक भावना के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं.

यह तर्क कि एक भाषा से ही एकता आती है, ऐतिहासिक रूप से भ्रामक है. स्विट्जरलैण्ड में चार आधिकारिक भाषाएँ हैं, फिर भी वह विश्व के सबसे एकजुट और स्थिर राष्ट्रों में से एक है. इसके विपरीत, पाकिस्तान ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित किया और बांग्लाभाषी पूर्वी पाकिस्तान को उपेक्षित किया. परिणाम 1971 में देश का विभाजन था. भारत की सभी भाषाएँ सदियों पुरानी साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्पराओं से समृद्ध हैं. इन्हें किसी एक भाषा की छाया तले दबाना उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने जैसा होगा, जो एकता नहीं, बल्कि असन्तोष और विखण्डन को जन्म देगा.

जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार हिन्दी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या लगभग 43-44% है. इसका अर्थ यह है कि भारत की आधी से अधिक जनसंख्या हिन्दी भाषी नहीं है. दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में हिन्दी की जड़ें अत्यन्त कमजोर हैं. यदि हिन्दी को एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तो इन करोड़ों लोगों को अपनी मातृभाषा में नहीं, बल्कि एक अपरिचित भाषा में सरकारी कामकाज, शिक्षा और न्याय प्राप्त करना होगा.

एक ऐसे देश में जहाँ भाषा पहचान और अस्मिता से गहराई से जुड़ी हो, किसी एक भाषा को थोपना समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है. यदि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाकर उसे प्रशासन, न्यायपालिका और प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम बना दिया जाए, तो इसके दूरगामी आर्थिक परिणाम होंगे. गैर-हिन्दीभाषी राज्यों के छात्रों को दोहरा बोझ उठाना पड़ेगा. इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर होगी और हिन्दीभाषी राज्यों के अभ्यर्थियों को स्वाभाविक लाभ मिलेगा. यह क्षेत्रीय असमानता को और गहरा करेगा. तमिलनाडु में 1965 का भाषा आन्दोलन इसका ज्वलंत उदाहरण है.

भारत एक संघीय गणराज्य है, जहाँ राज्यों को अपनी भाषा, संस्कृति और प्रशासन के मामलों में स्वायत्तता प्राप्त है. भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन इसी सिद्धान्त पर हुआ था. हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना और उसे राज्यों पर थोपना संघवाद की आत्मा के विरुद्ध है. यह राज्यों को केन्द्र के अधीनस्थ बनाने का सांस्कृतिक उपकरण बन सकता है, जो अन्ततः क्षेत्रीय असंतोष और पृथकतावादी भावनाओं को बल देगा. पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील है. नगालैण्ड, मिजोरम, मेघालय जैसे राज्यों में अंग्रेजी अधिक व्यावहारिक भाषा है. वहाँ के लोगों की सांस्कृतिक और जातीय पृष्ठभूमि हिन्दी बोलने वाले उत्तर भारत से बिल्कुल भिन्न है. उन पर हिन्दी थोपना उन्हें भारतीय मुख्यधारा के करीब नहीं लाएगा, बल्कि दूर करेगा.

यह सोचना कि एक राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता की गारन्टी है, एक सरलीकृत और भ्रामक विचार है. राष्ट्रीय एकता का आधार भाषा नहीं, बल्कि लोकतंत्र, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व जैसे साझा संवैधानिक मूल्य होते हैं. भारतीय क्रिकेट टीम जीतती है, तो पूरा देश चाहे वह तमिलनाडु हो या पंजाब एक साथ जश्न मनाता है और इसमें भाषा की कोई भूमिका नहीं होती. भारतीय सेना में हर भाषा के सैनिक कंधे-से-कंधा मिलाकर लड़ते हैं. एकता किसी भाषा को थोपने से नहीं, बल्कि हर भाषा-भाषी नागरिक को यह अनुभव करवाने से आती है कि इस देश में उसकी पहचान, उसकी भाषा और उसकी संस्कृति का सम्मान है. यूनेस्को बार-बार यह चेतावनी दे चुका है कि भाषाओं का विलोप मानवता की सबसे बड़ी सांस्कृतिक त्रासदियों में से एक है. जब एक भाषा मरती है, तो उसके साथ एक पूरी जीवनदृष्टि, एक ज्ञान-परम्परा और एक अनूठी सांस्कृतिक स्मृति भी समाप्त हो जाती है. इसके साथ ही वैश्वीकरण के इस युग में अंग्रेजी भारत को वैश्विक बाजार, विज्ञान और तकनीक में प्रतिस्पर्धी बनाता है. हिन्दी को स्वैच्छिक रूप से सीखने और बोलने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन उसे अनिवार्य राष्ट्रभाषा बनाकर अन्य भाषाओं को दोयम दर्जे पर धकेलना न तो व्यावहारिक है, न न्यायसंगत.

निष्कर्षतः यह कहना समीचीन होगा कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाकर अन्य भाषाओं को गौण करना न तो संवैधानिक दृष्टि से उचित है, न ऐतिहासिक दृष्टि से बुद्धिमानी और न ही व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव है. भारत की वास्तविक शक्ति उसकी बहुभाषिकता में है. देश को एक सूत्र में बाँधने के लिए हमें एक भाषा नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समावेशी नीति चाहिए, जो हर भाषा का, हर संस्कृति का, हर नागरिक का सम्मान करे.

●●●



यह पत्रिका राहुल जैन द्वारा 2/11-ए स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-2 से प्रतियोगिता दर्पण के लिए प्रकाशित एवं राहुल जैन द्वारा सम्पादित तथा थॉमसन प्रेस (इण्डिया) लिमिटेड 18/35, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद—121 007 (हरियाणा) द्वारा मुद्रित

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

प्रतियोगिता दर्पण

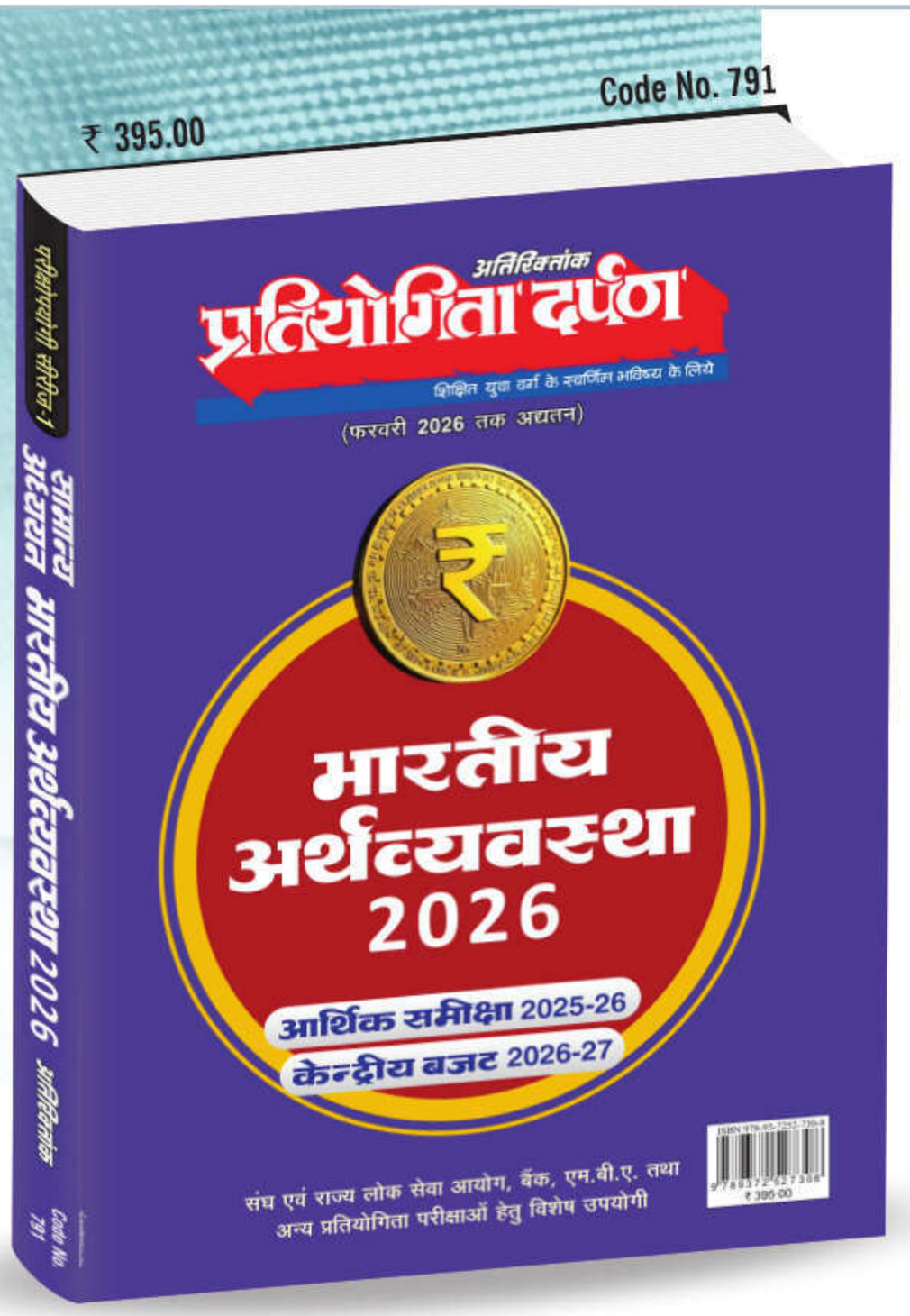
Fresh Arrivals

(फरवरी 2026 तक अद्यतन)

☑ आर्थिक समीक्षा : 2025-26

☑ केन्द्रीय बजट : 2026-27

और भी बहुत कुछ

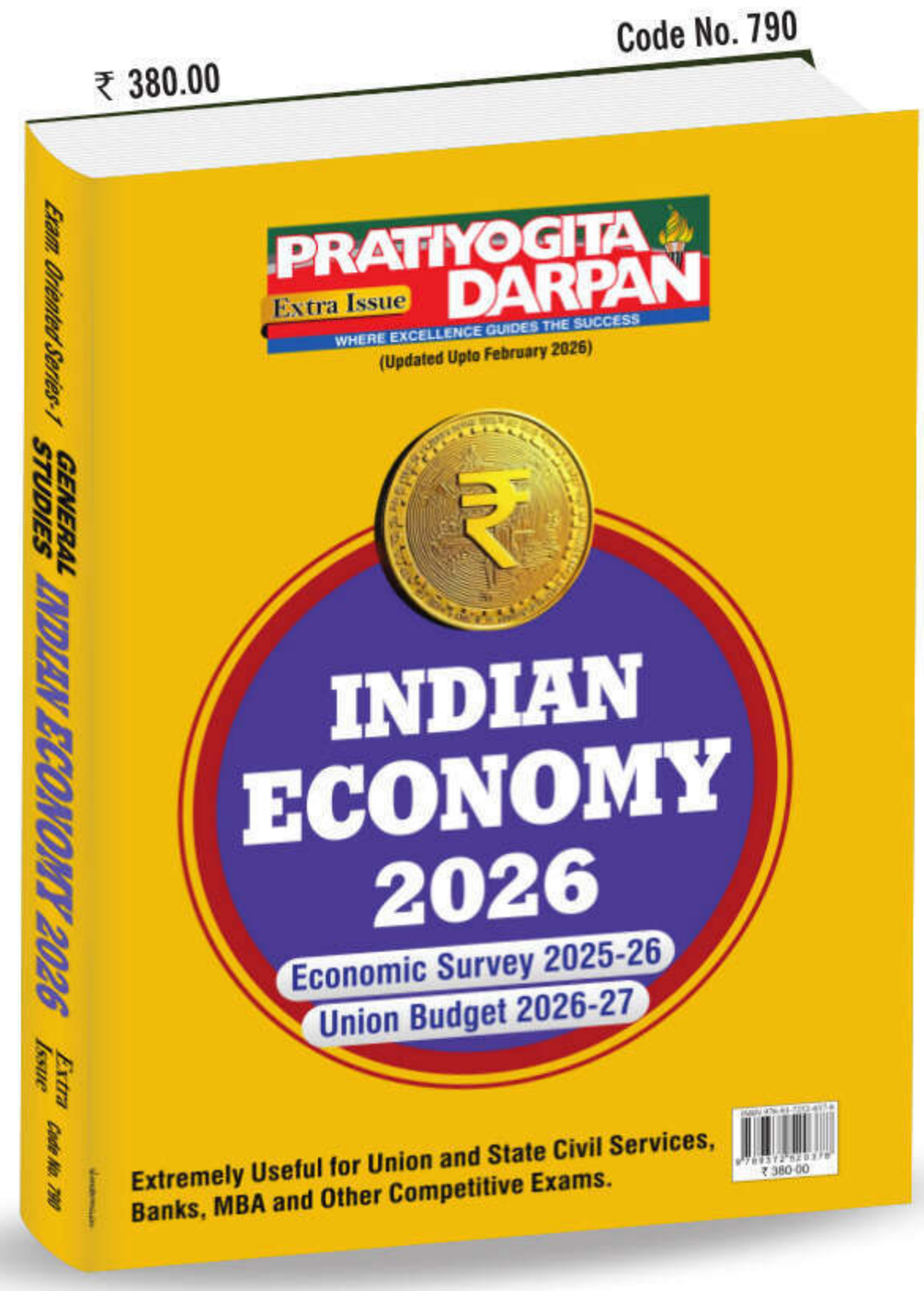


(Updated Upto February 2026)

☑ Economic Survey 2025-26

☑ Union Budget 2026-27

and much more



Available on :

pdgroup.in amazon Flipkart

प्रतियोगिता दर्पण

- E-mail : sales@pdgroup.in
- Website : www.pdgroup.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

Posting Date : 6, 7 & 8 Apr., 2026 (Agra-2)
Publishing Date : 6 Apr., 2026 Postal Regd. No. AGRA-047/2024-26

RNI No. 38696/79

दृष्टि The Vision

Drishti IAS

IAS GS फाउंडेशन कोर्स

हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम

ऑफलाइन व लाइव ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- **1200+ घंटों की** 500+ कक्षाएँ
- **निशुल्क** पुस्तकें + प्रिंटेड नोट्स
- **संशय निवारण** की सुविधा
- **कक्षाओं को असीमित** बार देखने की सुविधा

स्टेट PCS कोर्सेज़

हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम

ऑफलाइन व लाइव ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- **UPPCS** फाउंडेशन कोर्स
- **MPPSC** फाउंडेशन कोर्स
- **RAS** फाउंडेशन कोर्स
- **BPSC** फाउंडेशन कोर्स
- **HCS** फाउंडेशन कोर्स
- **UKPSC** प्रिलिम्स और मेन्स कोर्स
- **PPSC** फाउंडेशन कोर्स
- **APSC** फाउंडेशन कोर्स
- **WBPSC** फाउंडेशन कोर्स
- **JPSC** फाउंडेशन कोर्स
- **OPSC** फाउंडेशन कोर्स
- **JKPSC** प्रिलिम्स और मेन्स कोर्स

IAS प्रिलिम्स GS कोर्स 2026

हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- 400+ घंटों की कक्षाएँ
- ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़
- 18 महीनों की कोर्स वैधता
- संशय निवारण की सुविधा

IAS प्रिलिम्स (CSAT) कोर्स 2026

हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- 100+ घंटों की कक्षाएँ
- ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़
- 18 महीनों की कोर्स वैधता
- CSAT स्टडी मटीरियल

IAS प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2026

हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

पैकेज:
- I (53 टेस्ट्स)
- II (28 टेस्ट्स)
- III (25 टेस्ट्स)
- IV (34 टेस्ट्स)
- V (20 टेस्ट्स)
- VI (12 टेस्ट्स)

UPPCS प्रिलिम्स 2026 कोर्स

हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- 200+ कक्षाएँ
- ऑनलाइन मॉक टेस्ट्स
- 1 वर्ष की कोर्स वैधता
- संशय निवारण की सुविधा

72nd BPSC प्रिलिम्स कोर्स

हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- 200+ घंटों की कक्षाएँ
- संशय निवारण की सुविधा
- 1 वर्ष की कोर्स वैधता
- ऑनलाइन मॉक टेस्ट्स

टीचिंग एग्ज़ाम्स कोर्सेज़

हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- NTA/UGC-NET कोर्स
- Asst.Prof. कोर्सेज़ (BPSC. UPPCS, RPSC, MPPSC)
- BPSC TRE कोर्सेज़
- महापैक्स (Teaching, UGC, BPSC TRE)

ज्यूडिशियरी कोर्सेज़

हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- ज्यूडिशियरी फाउंडेशन कोर्स
- MP ADPO प्रिलिम्स कोर्स
- बिहार APO कोर्स
- बिहार ज्यूडिशियरी

SSC एग्ज़ाम्स कोर्सेज़

हिंग्लिश माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- SSC महापैक कोर्स
- लक्ष्य बैच – SSC CHSL 2026
- CGL फाउंडेशन कोर्स
- लक्ष्य कॉम्बो बैच (SSC CGL + CHSL 2026)

एडमिशन आरंभ

87501 87501

अभी डाउनलोड करें
Drishti Learning App
विंडोज़ पर भी उपलब्ध

अभी स्कैन करें

करोल बाग: 21, पूसा रोड, करोल बाग
नोएडा: C-171/2, सेक्टर - 15, नोएडा
प्रयागराज: ताशकंद मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
जयपुर: हर्ष टावर 2, टोंक रोड, जयपुर
लखनऊ: बलिंगटन चौराहा, मार्ग, लखनऊ
इंदौर: 12, AB रोड, भंवरकुआँ, इंदौर
राँची: क्रिस्टल हाइट्स, लालपुर चौक, राँची
पटना: शाही लेन, एस.पी. वर्मा रोड, पटना

ebooks.pdgroup.in